

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय अर्थशास्त्र

(प्रश्नोत्तर रूप में)

लेखक

रघुवीर सिंह जैन एम ए, एम कॉम

भूतपूर्व अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, जेंट कालिङ्ग, बड़ौदा

पूर्णतया सशोधित ६ वा सस्करण

प्रकाशक

रस्तोगी एण्ड कम्पनी

मुद्रक तथा प्रकाशक, मेरठ

[मूल्य छ रुपये]

प्रकाशक
रस्तोगी एण्ड कम्पनी
मेरठ

प्रथम मस्करण	१६१३
द्वितीय मस्करण	१६५४
तृतीय मस्करण	१६५५
चतुर्थ मस्करण	१६५६
पञ्चम मस्करण	१६५७
षष्ठम मस्करण	१६५७
सप्तम मस्करण	१६५७
अष्टम मस्करण	१६५८
नवम मस्करण	१६६०

मुद्रक—
पीताम्बर शरण रस्तोगी
शिक्षा प्रसन्न मेरठ



नवम संस्करण की भूमिका

“भारतीय अर्थशास्त्र” का नवम परिवर्द्धित तथा सशोधित संस्करण आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ा हर्ष है। पुस्तक का अष्टम संस्करण अल्प काल में ही समाप्त हो गया और फिर भी माग बनी रही इसके लिये मैं अपने सहयोगी अध्यापकों तथा प्रिय छात्रों का हृदय से आभारी हूँ। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि पुस्तक विद्यार्थियों को उपयोगी सिद्ध हो सकी। जितने भी सुभाव मेरे पास आय हैं उनका पुस्तक में यथोचित टग से समावेश किया गया है।

प्रस्तुत संस्करण की विषय सामग्री प्रायः नव रूप से जुटाई गई है तथा बिल्कुल ताजे आँकड़े दिये गये हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कारण अगले पाँच वर्षों में देश की अर्थ व्यवस्था में जो परिवर्तन होना की सम्भावना है उनका यथास्थान उल्लेख किया गया है तथा तीसरी योजना की रूप रेखा भी दी गई है। प्रश्न सरया भी बढ़ा दी गई है और पुस्तक का कलेवर भी बढ गया है। फिर भी मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभ उठा सकें।

अन्त में मैं पुनः अपने प्रिय छात्रों तथा विद्वान अध्यापकों का धन्यवाद देना अपना कर्तव्य समझता हूँ जिन्होंने पुस्तक को अपनाकर मेरा उत्साह बढ़ाया है।

सुभावों के लिये मेरा निमन्त्रण है।

कलकत्ता
१५-६-५६ }

बिनात
रघुवीर सिंह जैन

विषय-सूची

प्रश्न सं०

पृष्ठ सं०

अध्याय १ भौगोलिक पृष्ठ भूमिका

१	भारतीय अर्थ व्यवस्था का मुख्य लक्षण	१
२	भारतवर्ष की भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थितियों का देश की आर्थिक उन्नति पर प्रभाव ।	३
३	प्राकृतिक साधन तथा उनकी उन्नति ।	८
४	भारतवर्ष के खनिज पदार्थ तथा उनका औद्योगिक उन्नति पर प्रभाव	१०
५	भारतवर्ष में जल शक्ति के साधन	२१
६	भारतवर्ष की वन सम्पत्ति	३१
७	भारत एक घनवान देश परन्तु इसके निवासी निर्धन	४०

अध्याय २ भारतीय जनसंख्या

८	भारतवर्ष के विभिन्न भागों पर जनसंख्या का घनत्व	७३
९	भारतवर्ष में जनसंख्या की अधिकता की समस्या	४५
१०	भारतीय जनसंख्या के परिवार वितरण का आर्थिक महत्व	५४

अध्याय ३ सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाएँ

११	भारतवर्ष की सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाएँ तथा उनका आर्थिक जीवन पर प्रभाव	५६
----	---	----

अध्याय ४ भारत के आर्थिक जीवन में परिवर्तन

१२	उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में भारतवर्ष की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति	६३
१३	१८५७ ई० के उपरान्त भारत की कृषि	६७

अध्याय ५ भारतीय कृषि

१४	भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व—कृषि की मुख्य समस्याएँ तथा उनके सुधार के लिये सुझाव	६८
१५	भारतीय कृषक के लिये खेती व्यवसाय व्यापार न होकर जीवन का एक ढङ्ग है	७६
१६	भारतवर्ष की मुख्य फसलें तथा उनका भौगोलिक वितरण	७८
१७	भारत की अनन्व भागों में विभाजित तथा बिखरी हुई भूमि के कारण, आर्थिक प्रभाव तथा सुधार के ढङ्ग	८५
१८	भारत की विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ, मिट्टी के ढटाव की समस्याएँ एवं ठीक करने के सुझाव	१००
१९	भारतवर्ष में सिंचाई के साधन । उत्पादक तथा रसात्मक नहरों का अभिप्राय, भारत के विभिन्न राज्यों में सिंचाई ढाँचों का सापेक्षिक महत्व । युद्ध के पश्चात् की योजनाएँ	१०६
२०	खाद समस्या	११५
२१	पशु समस्या	११८
२२	फसल की विज्ञान	१२६

२३	ग्रामो के भूमिहीन रजदूरो की राजगार की समस्या तथा उसके उपचार	१३१
२४	भारत में आप किमको पसन्द करेंगे—(i) पूँजीवादी खेती की उन्नति, (ii) सामूहिक खेती, (iii) महकारी खेती, (iv) कृषक स्वामित्व । कारण दीजिये	१३५
२५	सामूहिक विवास योजना	१४२
२६	भूमिदान बज	१५४

✓ अध्याय ६ भारत की खाद्य समस्या तथा अकाल ✓

२७	भारत की खाद्य समस्या—कमी को पूरा करने के लिये किये गये प्रयत्न तथा आपके सुझाव	१६१
२८	'अधिन अन्न उर्जाओं' आन्दोलन	१७०
२९	अकाल	१७५

अध्याय ७ भारत में भूमि अधिकार-पद्धति तथा जमींदारी-उन्मूलन

३०	भारत के विभिन्न भागों में भूमि अधिकार की प्रथा	१८०
३१	स्थायी तथा अस्थायी बन्दोबस्त के लाभ व हानियाँ	१८६
३२	लगान कानून का उद्देश्य ३ F की प्राप्ति है	१८९
३३	भारत में जमींदारी उन्मूलन की समस्या, जमींदार को क्षतिपूर्ति, जमींदारी प्रथा के बाद भूमि का बन्दोबस्त	१९५
३४	वर्तमान भूमि नीति	२०२
३५	उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधारक एक्ट की मुख्य विशेषताएँ	२०५

अध्याय ८ ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था तथा ऋण

३६	ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था	२११
३७	ग्रामीण ऋण	२१९

अध्याय ९ कृषि पदार्थों का मूल्य

३८	कृषि पदार्थों के मूल्य को स्थिर करने का समर्थन	२२४
----	--	-----

अध्याय १० सरकार की कृषि सम्बन्धी नीति

३९	सरकार की भारतीय कृषि के प्रति नीति	२२८
----	------------------------------------	-----

अध्याय ११ भारत में सहकारी आन्दोलन

४०	रेफीसन तथा गुल्ज डेलिश सहकारी समितियों के मुख्य भेद	२३३
४१	१९०४ ई० से भारत में सहकारी आन्दोलन की उन्नति तथा कार्य पद्धति तथा उस समय से अब तक क्या परिवर्तन हुये हैं	२३५
४२	भारत में सहकारी आन्दोलन की स्वरूपा	२३९
४३	उत्तर प्रदेश में ग्रामीण साख सहकारिता का पुन संगठन	२४८
४४	बहु उद्देश्य समिति	२४९
४५	भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन के लाभ व दोष. उन दोषों को दूर करने के उपाय	२५२
४६	भारत में सहकारिता स्टोर आन्दोलन की वर्तमान स्थिति, तथा उसे लोकप्रिय बनाने के सुझाव	२५९

४७	भारतीय कृषि, भूमिवन्धक बँक तथा उनकी कम उन्नति के कारण	२६१
४८	रिजर्व बैंक तथा सहकारी आन्दोलन	२६४

अध्याय १२ कुटीर उद्योग

२४६	१६ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीय कुटीर उद्योगों के पतन के कारण	२६८
५०	भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योगों का महत्व—कुटीर उद्योग संगठन को उन्नत करने के सुभाव, सरकार की सहायता	२७१

अध्याय १३ बड़े पैमाने के उद्योग

५१	भारत के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण, भारत को औद्योगिक उन्नति से लाभ	२८१
५२	भारत की वर्तमान औद्योगिक अर्थ व्यवस्था—भविष्य में उसकी उन्नति के सुभाव	२८५
५३	औद्योगिक वित्त निगम का विधान तथा कार्य	२८०
५४	भारतीय उद्योगों की उन्नति में विदेशी पूँजी	२८८
५५	भारत सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति	२९६
५६	भारत सरकार की वर्तमान अर्थ-नीति तथा उसका भारतीय उद्योगों की उन्नति पर प्रभाव	३०२
५७	भारतीय उद्योगों का राष्ट्रीयकरण—दोष व हानियाँ	३०५
५८	बीमे का राष्ट्रीयकरण	३०८
५९	भारत के लोहे और फौलाद के उद्योग का विकास तथा उसकी वर्तमान समस्याएँ	३११
६०	भारतवर्ष में सूती कपड़े के उद्योग का विकास व उन्नति और उसकी मुख्य समस्याएँ	३१५
६१	भारतवर्ष के कोयले के उद्योग की उन्नति और वर्तमान स्थिति	३२१
६२	भारतीय चीनी उद्योग का विकास, उन्नति तथा उसकी प्रमुख समस्याएँ	३२६
६३	भारतीय जूट उद्योग—वर्तमान स्थिति तथा मुख्य समस्याएँ	३३३
६४	भारतीय कागज उद्योग	३३८
६५	भारतीय सीमेन्ट उद्योग	३४१
६६	भारत में भारी व कुटीर उद्योगों को उन्नत करने की आवश्यकता	३४४

अध्याय १४ औद्योगिक श्रम

६७	भारतवर्ष के मजदूर सघ आन्दोलन का विकास—मुख्य बाधाएँ तथा भारतीय श्रम समस्या पर उसका प्रभाव	३४७
६८	भारतीय फैक्टरी एक्ट	३५०
६९	श्रम हितकारी कार्य	३५५
७०	औद्योगिक श्रम के लिये सामाजिक बीमे की आवश्यकता	३५८
७१	श्रम की कार्य कुशलता किन बातों पर निर्भर है, भारत में वह कहाँ तक उपलब्ध है	३६६
७२	भारत में औद्योगिक सघर्ष के कारण तथा औद्योगिक शान्ति के लिये किये गये प्रयत्न	३७१

अध्याय १५ भारत में यातायात के साधन

७३	भारत में रेलों के विकास का इतिहास	३७८
७४	भारत में रेल यातायात के लाभ व हानियाँ	३८४
७५	रेलों का (अ) दस्तकारी, (ब) खेती तथा (स) उद्योग-धन्धों पर क्या प्रभाव पड़ा	३८५
७६	रेलों के विजलीकरण के लाभ	३८८
७७	भारत में सड़क यातायात का महत्व तथा स्थिति, इनके पिछड़े रहने के कारण तथा उन्नत करने के सुझाव	३९०
७८	गवर्नमेण्ट राइवेज V/S प्राइवेट मोटर बस्मनी	३९७
७९	रेल रोड संधर्ष तथा उसके उपाय	३९८
८०	आन्तरिक जल यातायात	४०२
८१	भारत में जहाजी यातायात के पिछड़े रहने के कारण, उन्नत करने के प्रयत्न तथा सुझाव	४०६
८२	भारतीय वायु यातायात का संक्षिप्त इतिहास	४११

अध्याय १६ भारतवर्ष का विदेशी व्यापार

८३	१९ वीं शताब्दी के मध्य के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार में प्रगति—निकट भविष्य में भारत के विदेशी व्यापार की रूपरेखा	४१५
----	---	-----

अध्याय १७ भारतीय मुद्रा तथा विनिमय

८४	१९२५ से ३८ तक भारतीय मुद्रा प्रणाली	४२७
८५	१९३९ से ४५ के बीच भारतीय मुद्रा प्रणाली	४३२
८६	१९४६ में भारतीय मुद्रा प्रणाली	४३४
८७	पौण्ड पावना—इसकी उत्पत्ति—इसका उपयोग	४३८
८८	रुपये के अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है ? भारतीय रुपये पर प्रभाव—भारतीय रुपये के पुनर्मूल्यन का गुण-दोष	४३८
८९	भारत में विदेशी विनिमय संकेत	४४२

अध्याय १८ भारतीय बैंकिंग

९०	भारतीय व्यापारिक बैंक का कार्य—उसका गुण-दोष, उनको उन्नत करने का सुझाव	४४७
९१	विदेशी विनिमय बैंक	४५१
९२	इम्पीरियल बैंक का विधान तथा काम में परिवर्तन—स्टेट बैंक क्यों बनाया गया	४५५
९३	रिजर्व बैंक की काम पद्धति	४५८
९४	भारत की वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था का मुख्य दोष तथा उसका सुधार का उपाय	४५७
९५	बैंकिंग कम्पनीज एक्ट १९४९ की मुख्य धाराएँ	४७०

अध्याय १९ भारतीय अर्थ-व्यवस्था

९६	भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की आय तथा व्यय का
----	--

	मुख्य मद, पंचवर्षीय योजना की वित्त व्यवस्था	४७४
६७	केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के आर्थिक सम्बन्ध, राज्यों की आय और उनकी आवश्यकताएँ	४८२
६८	भारत का सार्वजनिक ऋण	४८६
६९	भारत में नगरपालिका तथा जिला बोर्डों की आय-व्यय के मुख्य मद । उनकी आय बढ़ाने के साधन	४९८

अध्याय २०

आर्थिक योजना तथा राष्ट्रीय आय

१००	पंचवर्षीय योजना	५०४
१०१	द्वितीय पंचवर्षीय योजना	५१३
१०२	तृतीय पंचवर्षीय योजना	५२१
१०३	राष्ट्रीय आय	५२५



घास-फूस के सहारे पशु पाले जाते हैं। पर किम स्थान पर किस प्रकार के पशु पाले जाएं यह इस बात पर निर्भर है कि वहाँ पर कितनी वर्षा होती है तथा कितनी घास उगती है। यदि किसी स्थान पर अधिक वर्षा होने के कारण लम्बी घास उत्पन्न होती है तो वहाँ पर भेड़, बकरियाँ पाली जाती हैं।

जलवायु के पश्चात् पशुओं का आर्थिक उन्नति पर प्रभाव पड़ता है। हमारे देश में पंजाब तथा काश्मीर में भेड़ बकरियाँ पाली जाती हैं जिसके कारण वहाँ ऊनी कपड़े के कारखाने हैं। इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश आदि में गाय, बैल आदि पाले जाते हैं जिसके कारण कानपुर आदि म्यानों में चमड़े का काम खूब होता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रदेश से बरोडो रुपय का चमड़ा व खालें विदेशों को भेजी जाती हैं। चमड़े के उद्योग के अतिरिक्त इस प्रदेश में दुग्ध उद्योग भी खूब होता है। यह बात अवश्य है कि पशुओं की खराब नसल के कारण हम इतना दुध नहीं पाते जिससे कि उसको आस्ट्रेलिया आदि देशों के समान विदेशों को भेज सकें परन्तु यह बात सत्य है कि सारे गंगा-यमुना के प्रदेशों में स्थान-स्थान पर दुध का काम होता है।

इन सबके अतिरिक्त देश के खनिज पदार्थों का भी आर्थिक उन्नति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। वह देश जहाँ पर खनिज पदार्थों पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं, औद्योगिक होता है और वहाँ के लोग बहुत समृद्धि पाली होते हैं। पर जहाँ खनिज पदार्थों की कमी है वहाँ के लोग कम उन्नत होते हैं, जैसे इंग्लैंड तथा अमेरिका खनिज पदार्थों के कारण ही आज दुनिया के बड़े-बड़े देशों में हैं और भारतवर्ष खनिज पदार्थों की कमी के कारण बहुत पिछड़ा हुआ है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी देश की प्राकृतिक परिस्थितियों का उस देश की उन्नति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण ही भारतवर्ष एक खेतीहर देश है। इसी कारण गंगा, यमुना के मैदान में अन्न जननक्षय है तथा वह बहुत उन्नत है और दक्षिण का पठार तथा हिमालय प्रदेश बहुत पिछड़े हुए हैं।

सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव

किसी देश की सामाजिक रचना भी उस देश की आर्थिक उन्नति पर बहुत और प्रभाव डालती है। देशों में किस प्रकार से लोग अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करते हैं, किस धर्म के मानने वाले हैं, किस प्रकार के उत्तराधिकार के नियम हैं, उस प्रकार से घरेलू जीवन व्यतीत करते हैं, यह सभी बातें देश की आर्थिक उन्नति पर ऊपर प्रभाव डालती हैं। भारतवर्ष को ही लीजिये, भारतवर्ष के लोग अधिकतर 'हिन्दू' हैं, वे अहिंसा में विश्वास करते हैं तथा उनका विचार है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं को नहीं बढ़ाना चाहिये। इस कारण वह मछली, माँस आदि कम खाते हैं, जिसके कारण देश में अन्न सकट रहता है और अपने खेतों में हठी तथा मछली की

अच्छी खाद देना पसन्द नहीं करते। कम इच्छायें होने के कारण वे कम धन एकत्र करते हैं और नई-नई चीजों की खोज भी कम करते हैं।

इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में जाति-पाति का भेद बहुत पाया जाता है जिससे आर्थिक उन्नति में बहुत बाधाये उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त इस देश में लोग अधिकतर एक परिवार के रूप में रहने हैं। इस देश के परिवारों में इङ्ग्लैंड देश के परिवारों की भाँति किसी व्यक्ति की स्त्री, बच्चे आदि ही नहीं होने वरन् माँ बाप दादा, परदादा आदि बहुत से लोग होते हैं। इस सामूहिक परिवारिक प्रथा के कारण भी देश में कई प्रकार के लाभ तथा हानियाँ होती हैं, जैसे एक साथ रहने तथा कमाने के कारण परिवार के कुछ लोगों को अधिक काम करना पड़ता है और कुछ लोग निवृत्त हो जाते हैं। इस कारण धन एकत्र करने में बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है और यह बात देश की आर्थिक उन्नति में बहुत बाधक है। पर इस परिवारिक प्रथा के टूटने के कारण बृद्ध, बच्चे तथा अबलाएँ निराश्रित रह गई तथा भूमि का बंटवारा हो जाने पर छोटे-छोटे खेत हो गये हैं। इसके अतिरिक्त देश के उत्तराधिकार के नियमों का भी देश की आर्थिक उन्नति पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इस देश में कुछ ऐसे सामाजिक नियम हैं जिनके कारण दादाइलाही भूमि पर पिता के सब सड़कों का अधिकार होता है। समाज के इस नियम के कारण यहाँ पर बंटवारा होते-होते एक कृषक के पास भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े रह गये हैं, जिनमें खेती करना बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है। इस देश की पर्दे की प्रथा के कारण स्त्री समाज का श्रम देश के कुछ काम नहीं आता और इससे देश को बहुत हानि होती है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि देश की सामाजिक परिस्थितियाँ भी देश की आर्थिक उन्नति पर बड़ा प्रभाव डालती हैं।

Q 3 Give an idea of the natural resources of India Have they been Properly developed? If not what suggestions would you offer for the purpose?

प्रश्न ३—भारतवर्ष के प्राकृतिक साधनों पर प्रकाश डालिये। क्या उनका उचित ढंग से विकास हुआ? यदि नहीं, तो उन्नति के लिये सुझाव दीजिये।

भारतवर्ष एक बहुत विस्तृत देश है। विभाजन के पश्चात् इसका क्षेत्रफल जम्मू-काश्मीर सहित १२,६६,६०० वर्ग मील रह गया और इस देश की जनसंख्या १६५८ में ३६७५ करोड़ थी। यह देश ग्रेट ब्रिटेन का १३ गुना है और इसमें फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, डेनमार्क आस्ट्रिया, हंगरी, स्वीटजरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, रूमानिया समा सकते हैं। इसकी जनसंख्या भी संसार की कुल जनसंख्या की $\frac{1}{4}$ है। इतने विस्तृत देश में भगवान ने हर प्रकार की सामग्री मनुष्य के लिये रख छोड़ी है। यहाँ पर पहाड़, मैदान, पठार आदि सभी प्रकार की भूमि पाई जाती है जिसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की फसलें सुविधा के

साथ उगाई जा सकती हैं। देश की जलवायु मानसूनी है जो फसलें उगाने के लिये बहुत उपयोगी है। जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर बहुत से वन मिलते हैं, जिनमें बांस, चीड़, देवदार, फर, आम्रनूस आदि की बहुत उपयोगी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। बांस कागज बनाने तथा दूसरे कामों में आता है। दूसरे प्रकार की लकड़ियाँ भी फर्नीचर बनाने जलाने तथा अन्य दूसरे कई कामों में काम आती हैं। इस देश में लगभग १,८०, १५६ वर्गमील पर वन है। उनमें से बहुत कम वन काम में लाये गये हैं। इन वनों की ओर भी सरकार का ध्यान अभी हाल ही में गया है। ये वन हिमालय पर्वत व उसकी तराई, पश्चिमी घाट तथा मध्य प्रदेश के इलाके में पाए जाते हैं। मैदानों में जितने वन थे वे सब काटकर साफ कर दिये गये हैं और उनमें बहुत प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती हैं, जैसे चावल, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, गन्ना, कपास, जूट, दालें आदि। जिन स्थानों में वर्षा अधिक होती है वहाँ पर फसलें उगाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती पर जहाँ पर वर्षा कम होती है वहाँ पर सिंचाई के सहारे बहुत सी फसलें उत्पन्न की जाती हैं। यह बात सत्य है कि भारतवर्ष में आजकल अन्न की कमी है पर यह अन्न की कमी केवल प्राकृतिक कारणों से नहीं बल्कि और भी बहुत सी बातों के कारण है।

भारतवर्ष खनिज पदार्थों से भी भरपूर है, यहाँ पर बहुत कोयला मिलता है जो बङ्गाल, बिहार-उड़ीसा, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, राजपूताना आदि में मिलता है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में ६,००० करोड़ टन कोयला है। भारत में अच्छी प्रकार का कच्चा लोहा भी खूब मिलता है, जो बङ्गाल, बिहार, उड़ीसा तथा मद्रास राज्य में पाया जाता है। मैसूर में भी बहुत सा अच्छा लोहा पाया जाता है। भारतवर्ष में मैंगनीज बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके प्रमुख स्थान मध्य प्रदेश, मद्रास, बम्बई, मैसूर, बिहार व उड़ीसा में हैं। भारतवर्ष में सोना भी पाया जाता है। यह सोना दुनिया की सोने की उत्पत्ति का ३ प्रतिशत है। भारतवर्ष में दुनिया के सब देशों से अधिक अभ्रक मिलता है। यह अभ्रक बिहार में हजारी बाग के स्थान पर और आंध्र में नैलोर स्थान पर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष में अन्य कई प्रकार की धातुएँ पाई जाती हैं जो कि देश के लिये बहुत उपयोगी हैं।

इस देश में पशुओं की भी कमी नहीं है। यहाँ के पशुओं की संख्या तीस करोड़ के लगभग है। यह पशु कई प्रकार के हैं। इनमें कुछ दूध देने वाले हैं जैसे गाय, भैंस, कुछ बोझा ढोने वाले हैं, जैसे बैल, भैंसे, गधे, घोड़े, ऊँट आदि। कुछ मांस तथा ऊन देने वाले हैं, जैसे भेड़, बकरी आदि। ये पशु देश के लिये कई प्रकार से लाभदायक हैं, जैसे इनसे बहुत सी खाद मिलती है जो देश भी कृषि के लिये अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त इन पशुओं से चमड़ा तथा खालें भी प्राप्त होती हैं जिनसे देश की हर वर्ष बहुत सी आय होती है।

इस देश में कई प्रकार के शक्ति के साधन भी पाये जाते हैं। जिनमें लकड़ी

कोयला, मिट्टी का तेल, यहाँ पर कम मात्रा में पाया जाता है। इसके क्षेत्र केवल आसाम में हैं। इस कारण मिट्टी का तेल यहाँ पर दूसरे देशों से मँगाना पड़ता है। अतः यहाँ पर शक्ति का एक बहुत बड़ा साधन जल-शक्ति है। इस शक्ति का अनुमान चार करोड़ किलोवाट लगाया जाता है। परन्तु इसमें से १६५६-५७ तक केवल ३६ लाख किलोवाट के लगभग उपयोग में लाई गई है। इसलिये भविष्य में भारतवर्ष पर्याप्त मात्रा में विजली शक्ति के ऊपर निर्भर रह सकता है। भारतवर्ष में बिजली शक्ति उत्पन्न करने के लिये बहुत प्रकार की योजनाएँ चल रही हैं जिनसे अगले पाँच दस वर्षों में बहुत सी बिजली उत्पन्न होने की आशा है। बिजली के अतिरिक्त शक्ति का एक दूसरा साधन भी है। इस देश में बहुत गन्ना पैदा होता है जिससे चीनी बनाई जाती है। चीनी बनाने में जो शीरा बचा रहता है उसको अभी बहुत कम उपयोग में लाया गया है। यदि इस शीरे को काम में लाया जाय तो इससे पर्याप्त मात्रा में अल्कोहल बनाया जा सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवर्ष में सभी प्रकार के प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं पर यह देश निधन है। यहाँ के लोगों की वार्षिक आय दुनिया के प्रायः सब देशों के मनुष्यों से कम है। यहाँ के तीन चौथाई से अधिक लोगो को दो समय खाना भी नहीं मिलता और जो खाना मिलता है उसमें शरीर को बलवान बनाने की बहुत कम शक्ति है। लोगो के पास पहनने के लिये बहुत कम कपड़ा है। बहुत से मनुष्य तो नये ही रहकर अपना जीवन काट देते हैं। यहाँ के लोगो के पास रहने के लिये ठीक प्रकार के मकान भी नहीं हैं और बहुतो के पास तो मकान ही नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवर्ष एक निधन देश है यद्यपि वह साधनों की दृष्टि से बहुत धनवान है। ऐसा क्यों है? इसके निम्नलिखित कारण हैं—

(१) १५ अगस्त १९४७ ई० के पूर्व तक हमारा देश अङ्गरेजो का दास था। अङ्गरेज लोग इस देश की आर्थिक उन्नति में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं रखते थे। यही कारण है कि अगरेजो के डेढ़ सौ वर्ष के शासन-काल में हमारा देश बहुत कम आर्थिक उन्नति कर पाया।

(२) हमारे देश में पूँजी की बड़ी कमी है। हाल ही में जो पूँजी थी वह भी जर्मनी बही जाती थी। पूँजी की कमी के कारण किसी प्रकार की भी आर्थिक उन्नति कैसे हो सकती थी।

(३) हमारे देश में कुशल श्रम (Skilled labour) की बड़ी कमी है। बिना कुशल श्रम के खेती तथा उद्योग-धन्धो की उन्नति कैसे हो सकती थी।

(४) हमारे देश में अभी तक भी साख सस्थाओं जैसे बैंक, बीमा कम्पनियाँ आदि की बड़ी कमी है। बिना साख सस्थाओं की उन्नति के न तो व्यापार ही और न उद्योग धन्धे व खेती ही उन्नत हो सकी।

(५) हमारे देश में यातायात के साधनों की बहुत कम उन्नति हुई है। यहाँ पर लगभग ३४८८६ मील लम्बी रेल व १,२७,००० मील पक्की सड़कें हैं। गांवों में कच्ची सड़कें ही पाई जाती हैं। आवागमन के साधनों की उन्नति न होने के कारण हमारे देश के व्यापार तथा उद्योग धन्धों की उन्नति न हो सकी क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आवागमन के साधनों के उन्नत होने पर ही कच्चा माल औद्योगिक केन्द्रों तक ही जा सकता है तथा पक्का माल उन स्थानों पर पहुँचाया जा सकता है जहाँ उसकी मांग होती है। इनकी उन्नति पर ही हर प्रकार का माल विदेशों को भेजा जा सकता है।

(६) सन् १९२३ ई० से पूर्व तक हमारा देश अवाध व्यापार (Free Trade) की नीति को अपनाये हुए था। सन् १९२३ ई० के पश्चात् भी हमारे देश को विवेकात्मक सुरक्षण (Discrimination Protection) ही दिया गया। अवाध व्यापार की नीति के कारण हमारे देश के उद्योग धन्धों को विदेशी उद्योग प्रजा से प्रतियोगिता करनी पड़ी और इस प्रतियोगिता के कारण यहाँ के उद्योग पनप न पाये।

(७) हमारे देश की सरकारी माल मोल लेने की नीति (Stores Purchase Policy) भी हमारी उन्नति के मार्ग में एक बाधा रही है। प्रतिवर्ष अरब सरकार करोड़ों रुपये का माल इङ्ग्लैण्ड से खरीदती थी। यदि यह इस माल को भारत से ही खरीदती तो यहाँ के बहुत से छोट बड़ उद्योग धन्धे उन्नति कर जाते।

(८) हमारे देश में आधारभूत उद्योग (Basic or Key Industries) का तो प्रायः अभाव ही है। इसलिये हमका हर प्रकार की मशीनों के लिये विदेशों का मुँह ताकना पड़ता है। विदेशों से मशीन आन में समय तथा धन अधिक खर्च होता है। बहुधा विदेशी लोग हमका माल भेजते ही नहीं। इसने फलस्वरूप प्राकृतिक साधनों के उन्नत करने में बाधा पड़ना स्वाभाविक ही है।

इन सब बातों के कारण हमारे देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग न हो सका। भविष्य में हमसे चाहिये कि इन सब साधनों का पूरा पूरा प्रयाग किया जाय। ऐसा करने के लिये हमको कुछ निम्नलिखित बातें करनी पड़ेंगी।

(१) हमको समस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित एक योजना बनानी पड़गी। पंच-वर्षीय योजना इस ओर एक ऐसा प्रयत्न है।

(२) सरकार को सुरक्षण नीति का आधार देश का हित बनाना पड़गा जिसमें कि सब प्रकार के उद्योग देश के हित में यहाँ उन्नत हो सकें। द्वितीय वित्त आयोग (Fiscal Commission) की सिफारिश के अनुसार इस बात को भी मान लिया गया है।

(३) सरकार का चाहिये कि वह अपनी आवश्यकता का प्रायः सभी सामान देश से ही खरीदे जिससे यहाँ के सब प्रकार के उद्योग धन्धे पनप सकें तथा देश के प्राकृतिक साधनों का उपयोग हो सके।

(४) देश में कुशल श्रम की पूर्ति बढ़ाने के लिये सरकार को बहुत से टेक्नीकल स्कूल खोलने चाहियें ।

(५) पूँजी की कमी को विदेशों से ऋण लेकर पूरा किया जा सकता है ।

(६) देश में आधारभूत उद्योगों के उन्नत करने की भी आवश्यकता है ।

(७) बिना आवागमन के साधनों की उन्नति के भी हम अपने प्राकृतिक साधनों का उपयोग न कर सकेंगे । इसलिये उनको उन्नत करना चाहिये ।

(८) देश में बैंक आदि भी खोलने चाहिये । बैंकों की गाँवों में विशेष आवश्यकता है ।

इन सब बातों के पूरा करने से हम यह आशा करते हैं कि हम अपने प्राकृतिक साधनों का पूरा-पूरा उपयोग कर सकेंगे ।

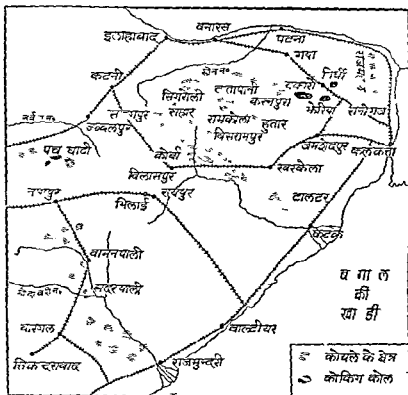
Q. 4 Give a short account of India's mineral wealth and discuss its bearing upon our future industrial development

प्रश्न ४—भारतवर्ष के खनिज पदार्थों का संक्षिप्त विवरण दीजिये और बताइये कि देश की भविष्य की औद्योगिक उन्नति पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है ?

उत्तर—भारतवर्ष खनिज पदार्थों की दृष्टि से एक बहुत धनी देश है परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि उनको पूर्णरूप से तथा वैज्ञानिक रीति से उन्नत किया जाये । सन् १८८० ई० तक उन खानों के खोदने का यहाँ पर कोई विशेष प्रबन्ध न था । इस कारण इन धातुओं से इस देश को कोई विशेष लाभ न पहुँच सका । जब से इस देश के लोगों का ध्यान खानें खोदने की ओर गया है तब से उनको यह विश्वास हो गया है कि यद्यपि इस देश के खनिज पदार्थ दुनिया में सबसे अधिक नहीं हैं तो भी इस देश के बहुत से उद्योग-धंधे चलाने के लिये वे पर्याप्त मात्रा में हैं । सन् १९१८ में नियुक्त औद्योगिक आयोग की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष में खनिज सम्पत्ति पर्याप्त मात्रा में है, जिसके द्वारा यहाँ के मूल उद्योग-धन्धों को सरलता से चलाया जा सकता है । हाँ, वे उद्योग जो निकल, बडम आदि पर निर्भर हैं उनके लिए अवश्य ही हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना होगा । भारतवर्ष में निम्नलिखित खनिज पदार्थ पाये जाते हैं—

कोयला (Coal)—संसार के कोयला उत्पन्न करने वाले देशों में भारत का सातवाँ स्थान है । इस देश में कोयले का अपार भण्डार है । इस भण्डार का अनुमान विभिन्न रूप से किया गया है । सन् १९५० में Geological Survey of India द्वारा किये गये अनुमान के अनुसार कोयले का भण्डार ३०,००० मिलियन टन है परन्तु १९५२ ई० में डा० सी० एस० फाक्स द्वारा किये गये अनुमान के अनुसार कोयले का भण्डार १००० फीट की गहराई तक ६०,००० मिलियन टन है । इसके अतिरिक्त बिहार के करनपुर क्षेत्र व आसाम, जम्मू व काश्मीर तथा दक्षिणी अरकाट

मे कोयले का बहुत बड़ा भण्डार बताया जाता है परन्तु यह सब घटिया प्रकार का है। परन्तु इसमें से २००० मिलियन टन ही कारखानों के काम आने वाला है। यद्यपि भारत में इतना अधिक कोयला है तो भी यह अमरीका तथा ग्रेट ब्रिटेन की अपेक्षा बहुत कम है। अमेरिका के भण्डार का अनुमान २६,७०,००० मिलियन टन तथा ग्रेट ब्रिटेन का १,७६,००० मिलियन टन है।



इस समय देश में ८०० कोयले की खानें हैं जिनमें से ७०० बगाल और बिहार में हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारे देश का कोयले का उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है। सन् १९३१ में हमारा वार्षिक उत्पादन केवल ०२ करोड़ टन था परन्तु १९५४ में यह बढ़ कर ३६८ करोड़ टन तथा १९५५ में ३८२ करोड़ टन, १९५६ में ३८७ करोड़ टन, १९५७ में ४३५ करोड़ टन तथा १९५८ में ४६१ करोड़ टन हो गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसकी उत्पत्ति ६ करोड़ टन तक बढ़ने की आशा है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष से २३ करोड़ टन अधिक होगी। इसमें ४५ करोड़ टन निजी क्षेत्र तथा शेष सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किया जायेगा।

देश में उत्पन्न होने वाले कुल कोयले का $\frac{2}{3}$ रेलों द्वारा, १० प्रतिशत लोहे व इस्पात के उद्योग द्वारा तथा ७-७ प्रतिशत जहाजों, निर्यात तथा विजली उत्पन्न करने के काम आता है।

भारतवर्ष में अधिकतर कोयला रानीगंज व झिरिया की खानों से प्राप्त होता है। १९५६ ई० में भारत की कोयले की उत्पत्ति लगभग ४ करोड़ टन थी जिसमें से २ करोड़ टन केवल बिहार में प्राप्त हुआ था। इस क्षेत्र के बाहर कोयले के प्रमुख क्षेत्र, हैदराबाद में मिंगरनी और सुन्नी में है। मध्य प्रदेश, आसाम, पंजाब, राजपूताना आदि में भी कुछ कोयला खानों से खोदा जाता है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास भी कोयले का भण्डार बताया जाता है जो क्षेत्र में लगभग १६ बर्ग मील है। परन्तु ऐसा अनुमान है कि यह उत्तर प्रदेश तथा पंजाब की कोयले की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। भारतवर्ष में जितना कोयला निकलता है उसका ५५ प्रतिशत बिहार से, २८ प्रतिशत बंगाल से, ६ प्रतिशत मध्य प्रदेश से, ५ प्रतिशत पूर्वी राज्य एजेन्सी से, ४ प्रतिशत हैदराबाद से, १ प्रतिशत आसाम से, $\frac{2}{3}$ प्रतिशत के लगभग पंजाब, उड़ीसा, राजपूताना से प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवर्ष में सभी स्थानों पर कोयले का समान बंटवारा नहीं है, इस कारण वह अभी तक उद्योग-धन्धे के लिये लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि भारतवर्ष का कोयला विदेशी कोयले की अपेक्षा खराब है। तीसरी बात यह है कि भारतवर्ष में कोयला कम मात्रा में है। सन् १९३७ में भारतीय कोयला समिति ने यह अनुमान लगाया था कि भारत में अच्छा कोयला १२२ वर्ष तक तथा साधारण कोयला ६२ वर्ष तक चलेगा। एक दूसरे विशेषज्ञ ने अभी हाल ही में कहा है कि भारतवर्ष में अच्छे कोयले का अभाव इसी शताब्दी के अन्त तक हो जायेगा। इस कारण भारतवर्ष उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिये बहुत समय तक कोयले पर निर्भर नहीं रह सकता। आजकल भारतवर्ष में कोयला खोदने का ढङ्ग बड़ा असन्तोषजनक है। बहुत सा कोयला खोदने में नष्ट कर दिया जाता है। यह कहा जा सकता है कि टैक्नीकल दृष्टि से कोयले का उद्योग अभी तक अवन्त अवस्था में है। चौथी बात यह है कि भारतवर्ष में अच्छे कोयले को रेलों द्वारा भाप बनाने में नष्ट किया जा रहा है और उसको धातु कार्यों के लिये बहुत कम काम में लाया जाता है।

अब इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि कोयले को ठीक प्रकार खोदा जाये तथा उसको अधिक से अधिक लाभदायक चीजों पर खर्च किया जाय। योजना आयोग की सिफारिश है कि अच्छे कोयले को केवल लोहे और फौलाद के उद्योग को बढ़ाने के काम में ही लाया जाये और भाप बनाने के काम में दूसरे प्रकार का कोयला काम में लाया जाए। इसके अतिरिक्त आयोग का यह भी सुझाव है कि भारतवर्ष के कोयले के साधनों का ठीक प्रकार से पता लगाया जाए, उसका उचित वर्गीकरण किया जाए जिससे कि हर श्रेणी का कोयला ठीक प्रकार से काम में लाया जा सके, कोयले का उचित ढङ्ग से बँटवारा किया जाए, ग्याङ्गार कोयले (Cooking Coal) का उत्पादन

बड़ाया जाए। इसके अतिरिक्त आरोग्य का यह भी मुद्दा है कि निम्नलिखित बातों के लिए कानून पास किए जाएँ—

- (१) उचित उपयोग, (२) नई उपकरणों के स्वामित्व पर एक सामूहिक उपकरण,
- (३) कोयला बोर्ड की स्थापना।

इन मुद्दों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने १९५२ में 'कोयला खान सुरक्षा एक्ट' पास किया। इसके अन्तर्गत सरकार को कोयले के उचित उपयोग तथा उमकी सुरक्षा के लिए कार्य करने की शक्ति दी गई है। इनके अतिरिक्त सरकार को यह भी अधिकार दिया गया है कि के कोयले पर उपकरण लगाए। एक कोयला बोर्ड की स्थापना भी की गई। १ जूलाई १९५३ से कोयले के क्षेत्रीय (Regional) बंटवारे की योजना भी बनाई गई है। मई १९५६ की एक सूचना के अनुसार विश्वस्तनीय सूची से पता लगा है कि भारत सरकार ने कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत एक कम्पनी स्थापित करने का निश्चय किया है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले का उत्पादन तथा बंटवारा करेगी। सरकार दूर-दूर की खानों को खोदने के लिये सहायक कम्पनियाँ भी बनाने की बात सोच रही है।

१९५५ ई० में भारत सरकार ने कोयले की खानों का एकीकरण करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी जिसने मुद्दा दिया है कि वे खाने जो कि १०,००० टन वार्षिक से कम कोयला उत्पन्न कर रही हैं उनका एकीकरण कर दिया जाए। यद्यपि इस कार्य को करने के लिए स्वयं इच्छा को प्रोत्साहन दिया जायगा परन्तु फिर भी कुछ कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़ सकती है।

३० अप्रैल १९५६ ई० के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में भारत सरकार ने कहा है कि भविष्य में सब नई खाने सरकार द्वारा खोदी जाएँगी। यही कारण है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल की २२ मिलियन टन की छूट में से १० मिलियन टन केवल सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त होगी। सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले की खानों को चलाने के लिए एक राष्ट्रीय कोयला विकास प्रमोटल की स्थापना की गई है।

लोहा (Iron)—यदि कोई देश अपनी औद्योगिक उन्नति के लिए किसी दूसरे देश का दास नहीं रहना चाहता तो उसे यन्त्रादि बनाने वाली धातुओं में स्वावलम्बी होना अनिवार्य है। इस दृष्टि से लोहे का बहुत महत्व है। यह अभी ठीक प्रकार म नही कहा जा सकता कि भारत में लोहे का प्रयोग कब से आरम्भ हुआ। परन्तु फिर भी यह कहा जा सकता है कि वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग जानते थे। ईसा से ३२६ ई० पूर्व जब सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया तब यहाँ के निवासी लोहे का उतना ही उपयोग जानते थे जितना कि यूनान के लोग। दिल्ली के पास लोहे का खम्बा ४१५ ई० में चन्द्रगुप्त द्वितीय की विजय की यादगार में गाड़ा गया था।

यह नहीं कहा जा सकता कि भारत का उद्योग कैसे समाप्त हो गया। हो सकता है कि यह इसलिए नष्ट गया हो क्योंकि यहाँ के लोहारों ने वैज्ञानिक रीति से काम नहीं किया।

धातु मिलती हैं जिसमें २० से ३० प्रतिशत तक लोहा निकलता है। भारत में आज-कल सबसे अधिक लोहा बंगाल, बिहार और उड़ीसा से प्राप्त किया जाता है। सिहभूमि, ब्योझर, बोनाई, मयूरगंज, बंगाल, मैसूर में लोहा अनन्त राशि में भरा पड़ा है। भारतीय खनिज सम्पत्ति विभाग (Indian Mineral Resources Bureau) का अनुमान है कि मद्रास राज्य के सलीम और नेलोर जिलों में लोहे की अनन्त राशि भरी पड़ी है। सौभाग्यवश लोहे की खानें कोयले की खानों के समीप हैं जिससे लोहा गलाने में काफी सुविधा मिलती है। जबकि संयुक्तराष्ट्र अमेरिका की कोयले और लोहे की खानों में १२०० मील का अन्तर है और भारत में यह अन्तर २०० मील से अधिक नहीं है। इस कारण यातायात का खर्च बहुत कम हो जाता है। १९५६ में ४०४८ हजार टन, १९५७ में ४६२० हजार टन तथा १९५८ में ६००० हजार टन कच्चा लोहा उत्पन्न किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कच्चे लोहे की उत्पत्ति का बिन्दु १२५ मिलियन टन रखा गया है। अभी तक भारत में सस्तरा का १ प्रतिशत, फास का ६० तथा अमेरिका का २० कच्चा लोहा उत्पन्न होता है। योजना आयोग की गले हुए लोहे तथा फौलाद की उत्पत्ति बढ़ाने की योजना के लिये भारतवर्ष को १३ लाख टन कच्चा लोहा, १५ टन कोयला ३० हजार टन मैंगनीज की धातु तथा तीन लाख टन चूने की ओर आवश्यकता है।

मैंगनीज (Manganese)—यह एक बहुत मूल्यवान धातु है और फौलाद बनाने के काम आता है। यह भारी रासायनिक विद्युत और कांच के उद्योग धन्यो के काम में भी आता है। भारतवर्ष में यह धातु बहुत पाई जाती है। इस विषय में सही आकड़े तो प्राप्त नहीं हैं फिर भी मैंगनीज के भण्डार का अनुपात १५० और २०० करोड़ टन के बीच में है। इसमें लगभग ५० प्रतिशत धातु निकलती है। इससे खराब धातु के भण्डार का अनुमान इससे लगभग तीन गुना है। १९३८ में इसकी उत्पत्ति ६,६७,६२६ टन थी जो सारी की सारी विदेशों को भेजने के काम में आती है। भारतवर्ष के लोहे और फौलाद के उद्योग द्वारा इतना बहुत कम भाग काम में लाया जाता है। १९५५ की उत्पत्ति १५,७०,००० टन थी इसमें से ४४३ प्रतिशत मध्य प्रदेश में, २५५ प्रतिशत उड़ीसा में, १२ प्रतिशत बम्बई में, ७२ प्रतिशत मैसूर में, ७१ प्रतिशत आंध्र में तथा शेष बिहार, राजस्थान तथा मध्य भारत में उत्पन्न हुआ। परन्तु १९५६ ई० में यह उत्पत्ति बढ़ कर १६८७,००० टन हो गई। १९५७ में उत्पत्ति घट कर १५,७४,००० टन रह गई। १९५८ की उत्पत्ति केवल १२ लाख टन थी। परन्तु १९५३ ई० में भारत में सबसे अधिक उत्पत्ति हुई जो कि १६००,००० टन थी। यह उत्पत्ति सस्तरा की १७ प्रतिशत थी। परन्तु द्वितीय योजना का ध्येय बिन्दु ३५ लाख टन है।

भारतवर्ष में उत्पन्न की जाने वाली धातु में से बहुत सी विदेशों को भेजी जाती है। वास्तव में हमारे लिये विदेशी विनिमय को प्राप्त कराने का यह बड़ा साधन है। १९५३-५४ में भारत में से १५६८००० टन धातु का निर्यात किया

गया। योजना कमीशन का निर्यात का बिन्दु १५००,००० टन तथा निर्यात प्रोत्साहन समिति का ध्येय बिन्दु १५ लाख से २० लाख टन के बीच में है। परन्तु १९५३-५४ के पश्चात् हमारी निर्यात कम हो रही है। यहाँ तक कि १९५६-५७ में हमारी निर्यात ८७५००० टन थी। १९५७-५८ में इससे कम धातु का निर्यात किया गया। इसका कारण यह नहीं कि हमारी धातु की प्रति इकाई कीमत बढ़ गई है। वस्तु में भाड़ा, सरकारी चुङ्गी आदि के कम होने से एक मैंगनीज की इकाई का मूल्य जो पहले अमेरिका में १७५ डालर था वह घट कर १२५ डालर रह गया। यह बात भी नहीं है कि विदेशों में मैंगनीज की माँग कम हो गई है। कम होने की अपेक्षा वह बढ़ गई है। तो फिर हमारी निर्यात के कम होने का क्या कारण है? इसका कारण स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का आना है। विदेशी लोग एक सरकारी एकाधिकारी कारपोरेशन से माल खरीदना पसन्द नहीं करते। इसके अतिरिक्त दूसरे कुछ देश इस धातु का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। इन देशों में धातु निकालने का नया ढङ्ग होने के कारण लागत भारत से कम है। इस कारण आवश्यकता इस बात की है कि भारत के निर्यात को बढ़ाया जाये। इसके लिये सरकार को चाहिए कि खान के मालिकों को सबकी सब धातु निर्यात करने का अधिकार दे। इसके अतिरिक्त सरकार को चाहिये कि वह नीचे तथा मध्यम श्रेणी की धातु पर से निर्यात कर हटा दे। इसके अतिरिक्त इस बात की आवश्यकता है कि विदेशियों से १०-२० वर्ष के अग्रिम सौदे किये जाये क्योंकि इस धातु के मूल्य में बड़ परिवर्तन होने रहते हैं। इसके अतिरिक्त खोदने की लागत में भी कमी करने की आवश्यकता है।

सोना (Gold) — भारतवर्ष में सोना बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह मैसूर रियासत के कौलार नदी क्षेत्र में मिलता है। इस क्षेत्र में कुल उत्पत्ति का ९९ प्रतिशत उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद में हट्टी और मद्रास में अनन्तपुर आदि स्थानों पर भी सोना मिलता है। भारतवर्ष में १९५७ में १७९१९६ ओंस सोना उत्पन्न किया गया। थोड़ा बहुत सोना रेत आदि को साफ करके भी प्राप्त किया जाता है।

मिट्टी का तेल (Petroleum) — भारतवर्ष में मिट्टी का तेल नाम मात्र की ही निकलता है। इरान व पाकिस्तान के भारतवर्ष से अलग होने के पूर्व इस देश को बाहर से बहुत कम मिट्टी का तेल मगवाना पड़ता था। परन्तु इन दोनों देशों के अलग होने के पश्चात् इस देश को अधिकतर तेल विदेशों से मगवाना पड़ता है। भारतवर्ष अपनी आवश्यकता का १० प्रतिशत से भी कम तेल पैदा करता है शेष विदेशों से मगता है। १९५५ में कुल शक्ति का ४६ प्रतिशत गोबर व लकड़ी से, ३४ प्रतिशत मनुष्य तथा पशु शक्ति से तथा केवल २० प्रतिशत कोयला, बिजली व तेल से प्राप्त हुआ। भारतवर्ष में मिट्टी के तेल के क्षेत्र आसाम में डिगबाई है। आजकल ६५—७० मिलियन गैलन मिट्टी का तेल प्राप्त होता है। देश की आवश्यकता को देखते हुए यह मात्रा बहुत कम है। परन्तु अब ऐसा विश्वास किया जाता है

कि उत्तरी भारत के मैदानों में बहुत सा तेल है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस बात का विशेष प्रयत्न किया जाएगा कि देश में तेल के साधनों की उन्नति हो तथा नये तेल के क्षेत्रों का पता लगाया जाए। पश्चिमी बंगाल में आजकल खोज की जा रही है। आसाम में अभी नये तेल के कुओं का पता लगाया गया है। राजस्थान के जैसलमेर के स्थानों पर भी खोज का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस कार्य को पञ्जाब 'ज्वालामुखी', होजियारपुर, जम्मू, आसाम तथा गंगा घाटी में बरेली व शाहजहापुर में बढाने की योजना है। पिछले दो वर्षों में भारत में तेल की खोज जोरों से की गई है। १९५६ ई० में सरकार ने एक Oil and Natural Gas Commission की स्थापना की है जो कि तेल के पता लगाने, उसकी खोदकर निकालने तथा साफ करने का कार्य करेगा। इस और रुमानिया के सिल्वरलै की सहायता से यह कमीशन अब ज्वालामुखी में खोज का कार्य कर रहा है। इस खोज के फलस्वरूप ज्वालामुखी में बहुत से तेल का पता लगाया गया है। इसी प्रकार आसाम तेल कम्पनी ने भी महारकेटिया, भीरू तथा हगरीजम में बहुत से तेल का पता लगाया है। भारत सरकार तथा बर्मा आयल कम्पनी ने अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके फलस्वरूप एक कम्पनी का निर्माण होगा जो कि उत्तरी आसाम में तेल निकालने का कार्य करेगी। यह कम्पनी न केवल तेल के उत्पादन का कार्य करेगी बल्कि बिना साफ किए हुए तेल को बरोनी (Barauni) (जो बिहार में है) एवं तेल के मलों के द्वारा पहुंचाने का कार्य करेगी।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार यह प्रयत्न भी कर रही है कि देश में मिट्टी का तेल साफ करने के कारखाने स्थापित किये जायें। भारत में एक ऐसा कारखाना १८६६ से डिपघोर्ड में कार्य कर रहा है। स्वतन्त्रता के पश्चात् Burmah Shell तथा Standard Vacuum Refineries जो दोनों बम्बई के पास हैं, स्थापित की गई हैं। इन कारखानों की शक्ति क्रमशः २० तथा १२५ मिलियन टन की है। एक तीसरा कारखाना Caltax Refinery विशाखापटनम में है। इसकी शक्ति ६७५ मिलियन टन की है। सरकार अब सरकारी तेल के साफ करने के कारखाने बनाने की योजना बना रही है। इनमें एक आसाम में होणा तथा दूसरा बिहार में।

भारत में अब तेल की मांग बढ़ती जा रही है। १९४८-५५ के बीच यह दुगुनी हो गई और यह आशा की जाती है कि यह ८ प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ेगा। इस कारण तेल की उत्पाति बढ़ाने की बड़ी आवश्यकता है। यदि हमारे देश में मिट्टी के तेल की उत्पत्ति बढ़ गई तो हम अपने विदेशी निर्यात के साधनों को बहुत हद तक बचा सकेंगे क्योंकि पिछले कई वर्षों में हमारी आयात लगभग २१ करोड़ रुपये वार्षिक की रही है।

—क्रोमाइट (Chromite)—यह युद्ध के काम आता है। इससे क्रोमियम का गमक भी तैयार किया जाता है जो चमड़ा रङ्गने के काम आता है। भारतवर्ष में अभी

तक इस धातु का उपयोग बहुत कम किया जाता है परन्तु जैसे-जैसे इस देश की औद्योगिक उन्नति होती जायेगी वैसे ही वैसे इस धातु का उपयोग मोटर और हवाई जहाज बनाने में होना जाएगा।

भारतवर्ष में यह धातु बिहार, मैसूर, बम्बई, मद्रास और उड़ीसा में पाई जाती है। पहले यह धातु अधिकतर निर्यात की जाती थी परन्तु १९५१ से अच्छी धातु का निर्यात बिल्कुल बन्द कर दिया गया है। १९५४ में इसकी उत्पत्ति ४५५०७ टन थी जो बढ़कर १९५५ में ८९३४९ टन होगई। १९५५ में ४८८०० टन का निर्यात किया गया। भारत में इस धातु के भण्डार का अनुमान १३२ लाख टन है।

बाक्साइट (Bauxite)—यह अल्यूमीनियम के धन्धे में काम आती है। यह बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई तथा काश्मीर में पाई जाती है। इसके भण्डार का अनुमान २५ करोड़ टन है जिसमें से अच्छी प्रकार की धातु ३५ करोड़ टन के लगभग है।

इसकी औसत उत्पत्ति १९४०-४४ के बीच में १५,००० टन वार्षिक थी। परन्तु १९५१ में यह ६७,००० टन से भी अधिक हो गई। १९५५ में उत्पत्ति बढ़ कर ८१,७७२ टन हो गई।

भारत में इस समय अल्यूमीनियम बनाने के दो कारखाने हैं जो ७५०० टन वार्षिक उत्पत्ति करते हैं। परन्तु यह उत्पत्ति देश की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अनुमान लगाया गया है कि इसकी मांग १९६०-६१ तक ४०,००० टन वार्षिक हो जायेगी। इस मांग को पूरा करने के लिये वर्तमान प्लान्ट की उत्पादन-शक्ति को तिगुना किया गया है तथा १०,००० टन और १५,००० टन के दो और नये प्लान्ट बनाये जा रहे हैं।

यद्यपि भारत में अच्छी प्रकार का बाक्साइट पर्याप्त मात्रा में बनाने की लागत बहुत अधिक है परन्तु आशा की जाती है कि बिजली की शक्ति के उन्नत होने पर इसकी लागत घट जायेगी तथा भारत ससार के अल्यूमीनियम उत्पन्न करने वाले सबसे प्रमुख देशों में गिना जायेगा।

जिप्सम (Gypsum)—यह अभी तक सीमेंट और पेरिस प्लास्टर की कच्ची धातु के रूप में काम में लाया गया है। परन्तु जब से सिंदरी की खाद की फैक्टरी बन गई है तब से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। सिंदरी में इस समय ५२८,००० टन जिप्सम काम में लाया जा रहा है परन्तु यह मांग बढ़कर ७००,००० टन होने की आशा है। इसके अतिरिक्त अल्वाई की खाद की फैक्टरी में ४३००० टन वार्षिक जिप्सम काम में लाया जाता है। सब सीमेंट के कारखानों की वार्षिक मांग २५०,००० टन है।

भारत में जिप्सम के क्षेत्र मुख्यतः राजस्थान के जोधपुर तथा बीकानेर जिले में हैं और यहाँ ३० फीट की गहराई तक १२० मिलियन टन का भण्डार

बताया जाता है। इसमें से ४० मिलियन टन जोधपुर डिबिजन में तथा ८० मिलियन टनबीकानेर डिबिजन में है। इसके अतिरिक्त जिप्सम का भंडार सौराष्ट्र तथा कच्छ में भी पाया जाता है। Geological Survey of India के अनुसार रतन में ३७७६००० टन, भाटिया में १७५००० टन तथा बीरपुर में ३६००० टन जिप्सम का भंडार है। इसके अतिरिक्त मद्रास राज्य के विचनापोली जिले में भी जिप्सम का भण्डार है। इस प्रकार भारत का कुल भण्डार २०० मिलियन टन के लगभग है। १९६०-६१ तक इसकी माँग १.६७ मिलियन टन होने की आशा है। भारत में १९५५ ई० में ६८६६०५ टन जिप्सम उत्पन्न किया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १८६ लाख टन जिप्सम प्राप्त करने की योजना है।

अभ्रक (Mica)—यह एक बहुत उपयोगी धातु है और बहुत सी चीजें बनाने के काम में आता है। विशेषकर विद्युत तथा दहकती हुई भट्टियों में यह काम में लाया जाता है। यह धातु भारतवर्ष में दुनिया के सब देशों से अधिक उत्पन्न होती है। भारतवर्ष में ससार के कुल भण्डार का आधा भण्डार है और भारतवर्ष सभार की ७० से ८० प्रतिशत आवश्यकता को पूरी करता है। इसके मुख्य स्थान बिहार में हजारीबाग व आँध्र में नैलोर है। इसके अतिरिक्त यह सलीम तथा मालाबार जिलों, ट्रावनकोर, अजमेर, मारवाड़ और राजपूताना में भी पाया जाता है। भारत की उत्पत्ति का लगभग ७५ प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है। भारतवर्ष में १९५७ में ६०७ लाख हण्डवेंट तथा १९५८ में ६,३६०४० लाख टन अभ्रक उत्पन्न किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अभ्रक के उत्पादन का ध्येय २००,००० हण्डवेंट रखा गया है।

भारतवर्ष में यद्यपि अभ्रक की उत्पत्ति बढ़ गई है तो भी खान खोदने का काम पुराना है। बहुत सा अभ्रक खोदने में नष्ट कर दिया जाता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में अभ्रक के उद्योग को उन्नत करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये गए हैं—

(१) बिहार और मद्रास के भंडारों का फिर से नक्शा बनाना तथा राजस्थान में विस्तार पूर्वक भौतिक कार्य (Geological work), (२) अभ्रक के गुण के अनुसार उसका वर्गीकरण करने के लिये अनुसन्धान, (३) छोटे-छोटे उत्पादकों की सहकारी समिति बनाई जाना, (४) इस बात की खोज करना कि क्या अभ्रक को बेचने के लिए केन्द्रीय विप्री बोर्ड बन सकता है अथवा नहीं।

यहां यह बात बता देनी आवश्यक है कि १९५२ के पश्चात् से अभ्रक के निर्यात में कमी होती जा रही है जिसके कारण इस उद्योग पर संकट आ गया है। हाल ही में सरकार ने अभ्रक के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये एक Export Promotion Council बनाई है।

ताँबा (Copper)—भारतवर्ष में ताँबा बिहार में ८० मील लम्बी पेट्री में पाया जाता है। १९५८ में भारत में ४११,००० टन ताँबा उत्पन्न हुआ।

शोरा (Salt-petre)—इसकी बहुत से उद्योगों के लिये बहुत माँग है, जैसे यह शीशा बनाने के काम में आता है और अन्न को कीड़ों से बचाने के लिये भी काम में आता है। यह अधिकतर, बिहार, उत्तर प्रदेश व पंजाब में पाया जाता है। एक समय था कि भारतवर्ष का शोरे की पूर्ति पर एकाधिकार था। परन्तु भारतीय सरकार की प्रशुल्क नीति (Traiff Policy) तथा दूसरे कारणों से भारतवर्ष में इस उद्योग का पतन हो गया। १९१४-१८ में भारतवर्ष से ४,४०,००० हण्डबैट शोरा बाहर को जाता था, परन्तु १९४१-४२ में १,७७,००० हण्डबैट ही भेजा गया था तथा १९५५ में ६०,००० हण्डबैट की उत्पत्ति में से केवल २२२८ हण्डबैट ही विदेशों को भेजा गया। आजकल अधिकतर शोरा बाहर को भेजा जाता है परन्तु यदि हम उसको खाद के रूप में काम में लायें तो हमें बहुत लाभ हो सकता है।

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष में अनेकों बहुमूल्य धातुयें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। इनके अतिरिक्त भारत में आधारभूत उद्योगों के लिये पर्याप्त मात्रा में लोहा और कोयला है। भारतवर्ष में अल्यूमीनियम की कच्ची धातु, घिसने वाली धातु तथा चूना पर्याप्त मात्रा में हैं। टिटैनियम, थोरियम तथा अभ्रक भी पर्याप्त मात्रा में हैं। परन्तु खेद की बात है कि इन खनिज पदार्थों का अधिकांश भाग कच्चे रूप में विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। हम अभ्रक के टुकड़ों से माइकानाइट, मोनोजाइट से सीरियम तथा इलमेनाइट से श्वेत टिटैनियम तैयार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हमारे उद्योग धन्ये विकसित हो जायें तो हम ४३ विभिन्न प्रकार के कच्चे खनिज पदार्थों का अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। वावसाइट, क्रोमाइट, जिप्सम, चूना, टिटैनियम, टंगस्टन तथा बैनडियम का हम अपने उद्योगों में अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार हमारे प्राकृतिक साधन हमारे देश के औद्योगिक विकास के लिये पर्याप्त हैं। कुछ ऐसी भी धातु हैं जो हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं जैसे पेट्रोल, ताँबा, टीन, शीशा, गिल्ट आदि। इनकी हम विदेशों से मगाकर अपना काम चला सकते हैं।

आशा है कि हमारी सरकार इस ओर ध्यान देगी। अभी हाल ही में भूगर्भ विभाग को अधिक सुसज्जित करने की ओर सरकार ने क्रियात्मक कदम उठाया है जिसके द्वारा भारत की खनिज सम्पत्ति का और भी पता लगाया जा सकेगा तथा देश का औद्योगिक और आर्थिक विकास किया जा सकेगा। १९४८ में दिल्ली में खनिज सूचना विभाग का निर्माण किया गया है। यह विभाग खनिज पदार्थ सम्बन्धी प्रयोग करके औद्योगिकों को खनिज सम्पत्ति सम्पत्ती नामको से जड़ित परामर्श देगा।

१९४९ ई० में खान और खनिज व्यवस्था तथा विकास विधेयक (Mines and Metal Regulations and Development Act) पास किया गया। इससे द्वारा अब दुर्लभ खनिज पदार्थों की खानों का ठेका देते समय राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की सलाह लेनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त देश में खानों की स्थिति

का, उनमें मिलने वाले पदार्थों का तथा उनकी किस्म का पता लगाने के लिये भूगर्भ विभाग (Geological Department) की स्थापना की गई।

१९५० ई० में राष्ट्रीय ईंधन विज्ञान शाला (National Fuel Research Laboratory) की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शोधन विज्ञान-शाला (National Metallurgical Laboratory) तथा केन्द्रीय ग्लान तथा सिरामिक विज्ञान-शाला (Central Glass and Ceramic Research Institute) की स्थापना भी की गई है। इस प्रकार यह आशा की जाती है कि निम्न भविष्य में हम अपने खनिज पदार्थों को देश के हित के लिये अधिकाधिक काम में लाने लगे।

Q 5 Discuss the importance of water power in India. What are the existing water power resources in this country? What are the principal features of the multipurpose hydel projects undertaken by the government and envisage their prospects.

प्रश्न—भारतवर्ष की जल-विद्युत शक्ति के विषय में ध्याय क्या जानते हैं? देश की वर्तमान विद्युत शक्ति के साधन बताइये तथा कुछ उद्देश्य विद्युत-शक्ति की जो योजनाएँ सरकार ने चलाई हैं उनके विषय में विस्तारपूर्वक लिखिये।

विजली का महत्व—भारतवर्ष में शक्ति के साधनों में जल शक्ति का एक प्रमुख स्थान है। इस देश में शक्ति के दूसरे साधन जैसे कोयला मिट्टी का तेल आदि बहुत कम मात्रा में पाये जाते हैं। इस कारण भविष्य में भारतवर्ष विद्युत शक्ति के ऊपर ही निर्भर रह सकता है। इस शक्ति के द्वारा सभी प्रकार के लोगों की आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं। एक परिवार को ही लीजिये। परिवार में विजली से कई प्रकार के काम लिये जा सकते हैं, जैसे खाना पकाना, पानी गरम करना, रोशनी करना, गरमी के दिनों में पंखा चलाना, जाड़ों में हीटर जलाना आदि। विजली मनोरंजन का साधन भी, है क्योंकि इससे रेडियो आदि चलाये जाते हैं। यह व्यापार के लिये भी बहुत उपयोगी है क्योंकि इसके द्वारा टेलीफोन, तार, बेतार का तार आदि दूर के स्थानों तक भेजे जा सकते हैं। यह देश की कृषि के लिये भी बहुत उपयोगी है क्योंकि इससे ट्यूबवेल बनाकर सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जा सकते हैं। यह छोट-छोटे उद्योग धन्धों के लिये अत्यन्त आवश्यक है। जापान, स्विटजरलैंड आदि देशों में विजली के द्वारा बहुत प्रकार के छोटे उद्योग धन्धे चलाये जाते हैं और इन्हीं के कारण ये देश बहुत समृद्धिवाली हो गए हैं। यदि हमारे देश में भी सस्ती विजली की शक्ति उत्पन्न होन लगे और वह समस्त छोट छोट गावों तक फैल जाए तो हमारे देश में बहुत से उद्योग धन्धे चाबू हो जायें। देश के उन लोगों के समय का सदुपयोग हो जाये तथा उनकी धन भी प्राप्त हो

जायेगा जिनके पास वर्ष के बारह महीनों में से केवल कुछ ही महीने काम रहता है, जैसे किसान । यह देश के बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है । क्योंकि इसकी सहायता से यह उद्योग धन्धे बड़ी सुगमता से चलाए जा सकते हैं । इसके सिवाए हमारे देश में कोयला कुछ थोड़े से स्थानों में केन्द्रित है, इस कारण देश में बड़े-बड़े उद्योग केवल उन्हीं स्थानों में चलाये जा सकते हैं, जो कोयले के क्षेत्रों के निकट हैं । ऐसा करने में उद्योग-धन्धों के अधिक केन्द्रीकरण का भय है । यदि देश में सस्ती बिजली हो तो उससे उद्योग-धन्धों का विकेन्द्रीकरण (Decentralization) होना सम्भव हो जाएगा और औद्योगिक क्षेत्रों में जो आजकल अधिक जनसङ्ख्या की समस्या तथा दूसरी प्रकार की समस्याएँ पाई जाती हैं उनका स्वयं ही हल हो जाएगा । इस लाभ के अतिरिक्त बड़े-बड़े उद्योग धन्धों को यह भी लाभ होगा कि उनको कारखाने चलाने में शक्ति के ऊपर जो व्यय करना पड़ता है उस व्यय में भी कमी हो जायेगी क्योंकि बिजली शक्ति अन्य शक्तियों की अपेक्षा सस्ती होती है । इसके सिवाय बिजली से देश की आवागमन की समस्या भी बहुत सुलझ सकती है । बिजली की गाड़िया, ट्राम्वे कार और दूसरी प्रकार के आवागमन के साधन बड़ी आसानी से चलाये जा सकते हैं । बिजली का प्रयोग रसायन-शालाओं में बहुत से अनुसन्धान करने के लिये भी किया जा सकता है । बिजली अस्पतालों में भी बहुत सी बीमारियों को अच्छा करने के काम में भी लाई जाती है । बिजली से दुग्ध उद्योग तथा बागवानी भी उन्नत की जा सकती है । दूध को बिजली की मशीनों से निवाला जा सकता है तथा उसको सुरक्षित भी रखा जा सकता है, इसी प्रकार पौधों को भी बिजली से आवश्यकतानुसार गर्मी पहुँचा कर फूला फलाया जा सकता है । मुर्गी पालने के उद्योग को भी बिजली से उन्नत किया जा सकता है क्योंकि बिजली से आवश्यकतानुसार अण्डे सेकर बच्चे निकाले जा सकते हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि जीवन के प्राय सभी क्षेत्रों में बिजली का एक प्रमुख स्थान है, यदि हमारे देश में बिजली की शक्ति उन्नत हो जाये तो उसको बहुत लाभ हो ।

भारतवर्ष, में जन-शक्ति के साधन—भारतवर्ष में बिजली की शक्ति का अनुमान ३.५ करोड़ किलोवाट लगाया जाता है । परन्तु इसमें भी १८५६-५७ तक केवल ३६ ६ लाख किलोवाट शक्ति में लाई जाने के लिये मशीनें लगाई गई हैं । दूसरी योजना काल के अन्तिम वर्ष तक बिजली का उत्पादन का ध्येय ६८ लाख किलोवाट रखा गया है । इसका कारण यह है कि बिजली की शक्ति उत्पन्न करने के लिये जो कारखाने लगाये जाते हैं उनमें बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है । दूसरे गरमी के दिनों में यहाँ की नदियों में बहुत कम पानी रह जाता है और बहुत सी नदियाँ तो सूख जाती हैं । ऐसी स्थिति में दो ही बातें सम्भव हैं या तो कारखाने गरमी के दिनों में बन्द हो जाये या बड़े बच्चे-बाँध बनाकर गर्मी के लिये पानी एकत्र किया जाये । तीसरा कारण यह भी है कि बिजली उत्पन्न करने

के लिये जिन मशीनों की आवश्यकता होती है उनको बाहर से मगाना पड़ता है और बाहर से आने में मशीनों के लिये वर्षों चाहियें, इस कारण कोई काम शीघ्रता से आरम्भ नहीं किया जा सकता। इन सब बाधाओं के कारण ही हमारे देश में बहुत कम बिजली उत्पन्न होती है।

हमारे देश में प्रति व्यक्ति बिजली का प्रयोग केवल ३५ किलोवाट घंटे (KWh) वार्षिक है। इसकी अपेक्षा इंग्लैंड तथा कनाडा में यह खर्च क्रमशः २००० तथा ५४५० KWh है। नार्वे में तो यह ७२५० KWh है। उत्पत्ति की दृष्टि से भी भारत को अभी बहुत रास्ता तय करना है। इसका पता नीचे की तालिका से लगता है—

देश	बिजली की शक्ति के साधनों का अनुमान (मिलियन KW)	वास्तविक उत्पात (मिलियन KW)
१—ब्रिटेन	५	४
२—नार्वे	७५	२६
३—फ्रांस	४५	४५
४—संयुक्त राष्ट्र	१००	१५
५—रूस	६०	१७
६—भारत	३५	०.६
७—समाप्त	५००	१३

भारत में अभी तक बिजली की शक्ति की बहुत कम उन्नति हुई है। बिजली की शक्ति की उन्नति की दृष्टि से हम भारत को ६ क्षेत्रों में बांट सकते हैं—बम्बई, बंगाल, बिहार, मद्रास, मैसूर, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब।

बम्बई—इस क्षेत्र में बिजली की शक्ति की उन्नति का ध्येय टाटा को है। अभी हाल ही में सरकार ने भी बहुत कुछ प्रयत्न किया है। टाटा का सबसे पहला कारखाना १९१७ ई० में खोपोली में जो बम्बई से ४५ मील है स्थापित हुआ। दूसरे दो स्टेशन १९२५ तथा १९२७ में स्थापित किये गए। अभी हाल में सरकार ने भी ५४००० किलोवाट शक्ति उत्पन्न करने के लिये मशीनें लगाई हैं।

टाटा के अतिरिक्त अहमदाबाद में भी एक बड़ी योजना है जहाँ कि ६० मिलों में से प्रत्येक की माँग १००० किलोवाट है। यहाँ की कोयना (Koyna) योजना जब पूरी हो जायेगी तो उससे २,४०,००० KW बिजली उत्पन्न होन लगेगी।

मैसूर—यहाँ पर बहुत सी नदियाँ हैं जिन से बहुत सी बिजली उत्पन्न की जाती है। यहाँ की सब योजनायें सरकारी हैं। मैसूर राज्य की कावेरी योजना दक्षिणी भारत में सबसे बड़ी है। यह १९०२ ई० में चालू हुई। इसकी वर्तमान शक्ति ४२००० किलोवाट है। इससे कोलार की सोने की खानों तथा दूसरे स्थानों

को बिजली दी जाती है। इस योजना के अतिरिक्त मैसूर में शिमला योजना (१७००० KW) तथा जोगपाल योजना (१२००० KW) हैं।

मद्रास—इस राज्य में अभी तक बिजली की बहुत कम उन्नति हुई है। परन्तु १९१४ ई० से इस राज्य में पांच बिजली की योजनाएँ उन्नत हुई हैं। पैकारा, मेटयूर, पायानासाम, नैयर तथा पेरियार योजनाएँ हैं। पैकारा योजना १९३० में प्रारम्भ हुई। इससे ७०,००० KW बिजली उत्पन्न होगी। यह बाँध ३,००० फीट ऊँचा है। मेटयूर योजना १९३७ में चालू की गई। इसकी बिजली उत्पन्न करने की शक्ति ४०,००० KW है। पायानासाम योजना में यम्बरापारनी नदी का जल काम में लाया गया है। यह योजना १९५२ में शुरू हुई। इसकी निर्मित शक्ति १८,००० KW है। नैयर योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूरी की गई है। यह पैकारा स्टेशन के नीचे का पानी काम में लाती है। इसकी उत्पन्न करने की शक्ति ३६,००० KW है। पेरियार योजना की शक्ति १,०५,००० KW है। यह केरल राज्य की पेरियार झील का पानी काम में लाती है। यह योजना १९५८-५९ में पूरी होने की आशा है। इसके अतिरिक्त मद्रास तथा मदुराई में दो भाप के स्टेशन हैं जिनकी अन्तिम शक्ति एक मिलियन किलोवाट से भी अधिक होगी।

पंजाब—बिजली की शक्ति उत्पन्न करने का कार्य इस राज्य में १९२६ ई० से हुआ। ऊल (Uhl) नदी का पानी इसके लिये काम में लाया गया। इसकी अन्तिम शक्ति १,२०,००० KW है जिसमें से ४८,००० KW १९३३ ई० से काम में लाई जा रही है। यह मण्डी योजना कहलाती है। इसके अतिरिक्त इस राज्य में भाखड़ा नामक योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई। इसके कई स्थानों से बिजली उत्पन्न करके लोगों को दी जा रही है।

उत्तर प्रदेश—इस राज्य की सबसे प्रसिद्ध योजना गंगा की योजना है। इस में गंगा की नहर पर ८ स्थानों में सरने बनाकर बिजली उत्पन्न की गई है। इसका वर्तमान शक्ति ७६,००० KW है। इस क्षेत्र में बिजली से बिजली के कुएँ बनाकर सिंचाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त शारदा नदी की योजना अभी हाल ही में पूरी की गई है। इसकी निर्मित शक्ति ४८,००० KW है, इसके अतिरिक्त रिहार्ड योजना रिहार्ड नदी पर पीपरी गांव के पास तैयार की जा रही है। पावर हाऊस में ६ शक्ति उत्पन्न करने वाले मेट होंगे जो ४०,००० KW के होंगे।

पश्चिमी बंगाल व बिहार—पश्चिमी बंगाल में कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाय कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जिसने अपना काम १८९७ ई० से आरम्भ किया। आरम्भ में इसकी बिजली उत्पन्न करने की शक्ति केवल १,००० KW थी परन्तु १९५६ ई० तक इसने इसको बढ़ा कर ४ लाख KW करली।

यहाँ की दूसरी योजना दामोदर घाटी योजना है जो कि बहु उद्देश्य है और बंगाल, बिहार तथा केन्द्र की सहायता से पूरी होगी। इस योजना के अन्तर्गत

तलैया तथा बोकारो परवती १८५३ से कार्य कर रहे हैं। तलैया पावर स्टेशन है तथा इसकी शक्ति ४००० KW है। बोकारो स्टेशन कोनार नदी पर बोकारो के पास है जो बिहार में है। इसमें ५०,००० KW की शक्ति के तीन स्टेशन हैं तथा इतना ही शक्ति का एक चौथा बनाने की योजना है। कोनार, मैथोन तथा पचत हिल नामक तीन और बाँध बनाने की योजना है। कोनार की उत्पादन शक्ति ४०००० KW है। यह ५०० फीट की ऊँचाई से बाँध करेगा। मैथोन स्टेशन भूमि के नीचे बाँधकर के समीप बनाया जाएगा। यह बंगाल बिहार की सीमा के समीप है। इसकी शक्ति ६०००० KW है। पचत हिल दामोदर पर बंगाल बिहार की सीमा पर है। इसकी शक्ति ४०००० KW है।



उड़ीसा—यहाँ हीराकुड बाँध महानदी पर बनाया गया है। अभी तक इसमें ७२,००० KW की दो यूनिट तथा २४००० KW की शक्ति की दो यूनिट हैं। इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा, बिहार का कुछ भाग तथा मध्य प्रदेश

की आवश्यकता पूरी होगी। अन्त में इस योजना, दामोदर योजना तथा मच्छकुण्ड में सम्बन्ध स्थापित किया जाएगा।

आंध्र—यह राज्य १९५३ से बना है। अभी तक यहाँ पर कोयले की खानों से २६०५० KW तथा डीजल स्टेशनों से १०,००० KW बिजली उत्पन्न की जा रही है। अधिकतर बिजली मैसूर तथा मद्रास राज्य से मोव ली जाती है। यहाँ की मच्छकुण्ड योजना आंध्र तथा उड़ीसा की एक सामूहिक योजना है। यहाँ का जलपत स्टेशन अन्त में १०२००० KW बिजली उत्पन्न कर सकेगा। तुंगभद्रा योजना जो कि मद्रास तथा हैदराबाद की सामूहिक योजना है इस राज्य को भी लाभ पहुँचाएगी।

बहु उद्देश्य बिजली की योजनाओं की विशेषता—जैसा ऊपर कहा गया है कि हमारे देश में अभी तक बिजली उत्पन्न करने के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र पड़ा है इस कारण भारतीय सरकार ने अमेरिका की टेनिसी घाटी की योजना (Tennessee Valley Authority) के अनुसार नदियों में बहने वाले पानी का सदुपयोग करने के लिए बहु-उद्देश्य नदियों की योजनाएँ (Multi-purpose river-projects) तैयार की हैं जिनसे बाढ़ के रोकने, वन लगाने, मछली पकड़ने, मिचाई करने के अतिरिक्त बिजली भी पैदा की जाएगी। इस प्रकार की बहुत सी योजनाएँ इस समय चल रही हैं। जितनी योजनाएँ इस समय देश में चल रही हैं उनके पूरा होने तक ७६५ करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है। इसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ६४६ करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। योजना के अन्तिम वर्ष में इन योजनाओं से १६ मिलियन एकड़ अतिरिक्त भूमि सींची जाने की आशा थी व १५ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न किए जाने का अनुमान है परन्तु प्रथम योजना काल में केवल ११ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न की जा सकी। इसमें मिचाई सम्बन्धी लाभ इस प्रकार होने की आशा है—१९७ मिलियन एकड़ भूमि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, २१ मिलियन एकड़ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिसमें ६० लाख एकड़ उन योजनाओं से होगी जो कि प्रथम योजना काल की होगी तथा ३० लाख एकड़ नई योजनाओं से होगी तथा शेष उसके पश्चात्। शक्ति सम्बन्धी लाभ में से ३४ मिलियन किलोवाट प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, ३५ मिलियन किलोवाट द्वितीय योजना के अन्तर्गत तथा शेष उसके बाद होगा। दूसरी योजना में कुल ४२ बिजली व भाप उत्पन्न करने वाली योजनाएँ चालू की जाएँगी।

(१) हीरा कुंड बाँध—उड़ीसा राज्य में महानदी के विनाशकारी कार्यों को रोकने के लिये यह बाँध बनाया गया है। महानदी का उद्गम मध्यप्रदेश के रामपुर जिले में है, इसकी लम्बाई ५३३ मील है। इसमें हर साल ७ करोड़ ४० लाख एकड़ फुट पानी बहता है और साल भर का औसत विकास १ लाख बीघे है। इस जलराशि का मुश्किल से २० वा भाग काम आता है। शेष बङ्गाल की खाड़ी में बह कर चला जाता है। उड़ीसा की भूमि को उचित मात्रा में पानी मिलने पर वहाँ की उपज दुगुनी तिगुनी बढ़ सकती है।

महानदी को नियन्त्रण में लाने के लिये सबसे पहले १९२७ ई० में प्रयत्न किया गया। १९४५ में यह समस्या केन्द्रीय सिंचन तथा नौका नयन आयोग को सौंपी गई।

महानदी पर हीराकुड, टीकापारा और नारज तीन बांध बनाने की योजना है। १९४८ में सबसे पहले हीराकुड बांध पर काम शुरू हुआ। इस बांध की लम्बाई १५,७४८ फुट होगी। इसके दोनों ओर लगभग १३ मील लम्बे बांध होंगे। इन बांध से सिंचाई, बिजली नौका नयन सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

इस योजना के दो भाग हैं। पहले भाग से मुख्य बांध दोनों ओर के बांधों, बिजली घर (१,२३,००० किलोवाट) ४०० मील लम्बी तार की लाइनों और ८ छोटे बिजली घरों का निर्माण शामिल है। इस पर ७० करोड़ ७८ लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है जिसमें से दिसम्बर १९५६ तक ५३.७६ करोड़ ४० खर्च किये गये। योजना के दोनों भागों पर १ अरब रुपये खर्च होगा।

बांध बनाकर तीन नहरें निकालने की योजना है। तीनों नहरों और उनकी शाखाओं से २.५ मिलियन एकड़ भूमि में सिंचाई होगी और इससे ४५ लाख टन गन्ना पैदा हो सकेगा।

अक्टूबर १९५८ तक २,४१,९८३ एकड़ भूमि को पानी की सुविधा प्रदान की गई। नहर के पानी का बटवारा करने के लिये नहर की शाखाय आदि सितम्बर १९५८ तक पूरी हो जायेंगी। चारों बिजली घरों से बिजली प्राप्त होनी शुरू हो गई है। इस बिजली को अब राजगपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री, हरकेला के इस्पात के कारखाने, जोदा के फेरोमगनीज के प्लान्ट, ब्रजराजनगर की कागज की मिल और चौदवार के टैक्सटाइल तथा दूसरे उद्योगों को बिजली दी जा रही है। हीराकुण्ड से नटक, पुरी, मम्बलपुर, सुन्दरगढ़, बारागढ़ तथा दूसरे अन्य शहरों को बिजली प्रदान की जा रही है।

डेल्टा की सिंचाई के लिए भी एक योजना स्वीकार की जा चुकी है। इसका कार्य १९६० में पूरा हो जायेगा। इस योजना पर १४.९२ करोड़ रुपये खर्च होंगे तथा १५७ लाख एकड़ पर प्रतिवर्ष सिंचाई होगी।

बिजली की अधिक मांग को पूरा करने के लिये दूसरे भाग के बनाने की भी मजूरी हो चुकी है। इस पर १४.३२ करोड़ रुपये खर्च होंगे इसके पूरा होने पर कुल निमित शक्ति १०९,००० KW हो जायगी। इसके अतिरिक्त डेल्टा की सिंचाई के लिये १४.९२ करोड़ रुपये की एक योजना बनाई गई है जिससे १८७ लाख एकड़ पर सिंचाई होगी।

अभी हाल ही में भारत सरकार यह सोच रही है कि हीराकुण्ड बांध व हरकेला धरमल पावर स्टेशन को एक दूसरे से सम्बन्धित कर दिया जाये जिससे कि हीराकुण्ड बांध का बिजली हरकेला पावर स्टेशन को प्राप्त हो सके। इस योजना का

अनुसार दोनो स्थानों की बिजली एक जगह एकत्र करके उसको आवश्यकतानुसार बाटा जायगा। इसके फल स्वरूप हीराकुण्ड के पानी का बिजली के उत्पन्न करने के लिये अधिक सदुपयोग हो सकेगा तथा मुख्य बाध पर ६ बिजली उत्पन्न करने वाली इकाईया का बनाना सम्भव हो सकेगा। ऐसा करने से रूरकेला के इस्पात, अल्यूमीनियम तथा खाद के उद्योगों को ही लाभ न हो सकेगा वरन् इस क्षेत्र में रेलों का बिजलीकरण भी सम्भव हो सकेगा। इसके कारण रूरकेला के इस्पात के कारखाने में जो शक्ति उत्पन्न होगी वह हीराकुण्ड बांध को प्राप्त हो सकेगी। इसके कारण रूरकेला में जो २५००० KW उत्पन्न करने वाला स्टेशन, अचानक पड़ने वाली आवश्यकता के लिए बनाया जाने वाला था उसकी आवश्यकता न पड़ेगी। इस योजना के फलस्वरूप हीराकुण्ड बांध से रूरकेला के इस्पात के कारखाने को दिन के कुछ घण्टों में जो शक्ति प्राप्त होगी वह शेष घण्टों में लौटा दी जायगी। इस प्रकार इस योजना से उड़ीसा को बड़ा लाभ होगा।

(२) दामोदर घाटी योजना—इस योजना के अनुसार दामोदर नदी पर एक बांध बनाने की योजना है। दामोदर नदी में प्रतिवर्ष भयंकर बाढ़ आती है जिसके कारण बंगाल, बिहार राज्य के एक बहुत बड़े भाग की तबाही व बर्बादी हो जाती है। लोगों को इस तबाही व बर्बादी से बचाने व इस विनाशकारी नदी को लाभदायक बनाने के लिये ही वह बांध बनाया जा रहा है।

इस बांध के बनाने में कई वर्ष लगेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में केवल चार बांध बनाये जायेंगे जिनसे १,०४,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न की जायगी। दुर्गापुर में एक ऐसा बांध बनाया जायगा जिससे न केवल सिंचाई ही होगी वरन् यह नौका वहन के काम भी आयेगा। बोकारा थर्मल स्टेशन भी बनाया जायेगा जिससे १½ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी।

ऊपर जिन चार बांधों का वर्णन किया गया है उनमें से तलवा बांध १९५५ में पूरा हो चुका है। यह बांध २४,००० एकड़ भूमि को खरीफ में तथा ७५,००० एकड़ भूमि को रबी में सिंचेगा। इसके अतिरिक्त इस बांध से बोदारमा तथा हजारी बाग की अबरक की खानों को बिजली पहुँचाई जायेगी। इसकी निर्मित शक्ति १½ लाख किलोवाट है परन्तु अन्त में यह बढ़ा कर २,२५,००० KW कर दी जायेगी।

दूसरा कोनर बांध मई १९५४ में पूरा हो चुका है। यह बोकारा थर्मल प्लांट को ठण्डा करने के लिये पानी ही प्रदान नहीं करता वरन् इससे १,०४,००० एकड़ भूमि भी सिंची जायेगी। अन्त में बांध के नीचे बिजली उत्पन्न करने के लिये एक प्लांट बनाने की योजना है जिसकी उत्पादन शक्ति ४०,००० किलोवाट होगी।

तीसरे मंथोन बांध से सिंचाई करने व बाढ़ को रोकने का कार्य किया जायेगा। यह ११ लाख एकड़ फुट पानी एकत्र करेगा तथा इसके समीप एक बिजली

घर बनाया जायेगा। जिसकी उत्पादन शक्ति ६०,००० किलोवाट होगी। इसको १९५७ ई० में पूरा किया गया।

चौथा बांध पचत हिल है। यह इन चारों में सबसे बड़ा है। इसका मुख्य कार्य बाढ़ को रोकना है। यह २२ लाख एक्ड फीट पानी एक्क करेगा तथा इसके समीप एक बिजली घर बनाया जायेगा जिसकी शक्ति ४०,००० किलोवाट होगी। इसको १९५८ ई० में कार्य में लाया जायेगा।

दुर्गापुर बांध पश्चिमी बंगाल में है। यह १०४ लाख एक्ड से भी अधिक भूमि सींचेगा। इसकी १५५० मील नहर में से ८५ मील लम्बी नहर में नाव चलेगी। इस प्रकार कलकत्ता और कोयले की खानों के बीच एक दूसरे रास्ते का निर्माण हो जायेगा। दुर्गापुर बांध का उद्घाटन उप-राष्ट्रपति द्वारा ६ अगस्त १९५५ को किया गया। नहरें जून १९५६ ई० में पूरी हो जायेंगी।

(३) कोसी योजना—यह योजना उत्तर बिहार, नेपाल के लिये है। इसमें एक बांध नेपाल में और दूसरा नेपाल-बिहार की सीमा पर बनाया जायेगा। इससे पहले बांध नेपाल की दस लाख एक्ड भूमि को सींचेगा और उससे एक लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी और दूसरा बांध जो दुनिया में सबसे ऊँचा होगा बिहार की १३-६७ लाख एक्ड भूमि को सींच सकेगा। इसको लागत ४४७६ करोड़ रुपये होगी।

(४) भाखड़ा नागल योजना—यह योजना पंजाब, पेप्पू तथा राजस्थान के लिये है। इसमें ३६,००,००० एक्ड से भी अधिक भूमि सींची जाने की आशा है और पूरा होने पर ३,६५००० किलोवाट बिजली की शक्ति उत्पन्न होगी। इस पर १७० करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है। नागल नहर का उद्घाटन ८ जून १९५४ को हो चुका है तथा गणवाल पावर हाउस भी २ जनवरी १९५५ से चालू हो गया है और दूसरा कोटला पावर हाउस ३० जून १९५६ ई० को पूरा हुआ। १९५७-५८ में राजस्थान व पंजाब में इस योजना से क्रमशः १५ लाख एक्ड भूमि पर सिंचाई हुई।

(५) तुझभद्रा योजना—इस योजना से आन्ध्र मैसूर तथा हैदराबाद को लाभ पहुँचेगा। इससे ८२ लाख एक्ड भूमि पर सिंचाई हो सकेगी और १,६५,००० किलोवाट बिजली भी उत्पन्न होगी। इस पर ६०७६ करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है।

(६) कोकरापारा योजना—इस योजना द्वारा सरकार ताप्ती नदी को उन्नत कर रही है। इसके द्वारा सूरत की ६,५२,००० एक्ड भूमि पर सिंचाई होगी। बांध जून १९५३ में चालू हो चुका है तथा नहरें १९६३ में पूरी हो जायेंगी।

(७) रिहद बांध योजना—यह एक बहुउद्देश्य योजना है। यह योजना दक्षिणी मिर्जापुर जिले के पीपरी स्थान पर चालू की गई है। प्रारम्भ में इस योजना पर ३५ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान था परन्तु अब यह बढ़ा कर ४६०५

करोड़ ६० करोड़ दिया गया है। इस बाध से लगभग १६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जायेगी जो कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बिहार के एक भाग पर भी होगी। इसके अतिरिक्त इस बाध की बिजली उत्पन्न करने की शक्ति २.५ लाख किलोवाट होगी। यह सिंचाई, रोशनी, रेलगाड़ियों आदि के काम में लाई जाएगी।

इन योजनाओं के अतिरिक्त और भी बहुत सी योजनाएँ हैं जो कि बहुत सी राज्य सरकारें अपने हाथ में लिए हुए हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सी नदी घाटी योजनाएँ चल रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य १५-२० वर्ष में सिंचित क्षेत्र को दुगुना कर देना है। इसके अतिरिक्त इन योजनाओं के द्वारा बहुत सी बिजली भी उत्पन्न होगी। यही नहीं बहुत सी उन नदियों को जो आजकल बाढ़ के द्वारा बहुत से क्षेत्रों में तबाही पैदा कर देती हैं, रोककर मनुष्य के लिए उपयोगी बनाया जायगा। इसके अतिरिक्त कुछ बांधों में नावें चलाने का काम भी किया जायगा।

इस प्रकार ये योजनाएँ न केवल खेती के लिए ही उपयोगी हैं बल्कि उद्योग धर्मों के लिए भी हैं। खेती को ये पानी पहुँचाकर बहुत सा अन्न पैदा करने में सहायता देगी। ऐसा करने से हमारे देश में अन्न का सकट शीघ्र ही दूर हो जाएगा। उद्योगों को इससे प्रत्यक्ष व परोक्ष लाभ होगा। प्रत्यक्ष लाभ तो यह होगा कि इनकी बिजली की सहायता से चलाया जायगा। सस्ती शक्ति प्राप्त होने पर इसका लाभ बढ़ जायगा। बड़े उद्योगों के अतिरिक्त छोटे उद्योगों के लिए तो बिजली का महत्व बहुत अधिक है। बिजली के आने पर देश के छोटे-छोटे गाँवों में छोटे-छोटे उद्योग उन्नत हो जायेंगे। इससे देश को बहुत लाभ होगा। इसके अतिरिक्त यदि बिजली में रेलें भी चलने लगीं तो बहुत सा कोयला बच जायगा जो इस्पात बनाने के काम आ सकेगा। परोक्ष लाभ यह होगा कि खेती के उन्नत होने पर कच्चा माल अधिक मात्रा में तथा सस्ता मिलेगा। इस प्रकार देश को बड़ा लाभ होगा।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिजली की शक्ति की उन्नति—प्रथम पंचवर्षीय योजना में बिजली का उपयोग १४ यूनिट से बढ़ कर २५ यूनिट प्रति व्यक्ति हो गया है। १९४१ ई० के शुरू में केवल ३६७८ गावों व कस्बों में बिजली पहुँची हुई थी परन्तु प्रथम योजना के अन्त में वह संख्या बढ़ कर ६५०० गाँव व कस्बों में हो गई। द्वितीय योजना में बिजली का खर्च २५ यूनिट से बढ़ कर ५० यूनिट होने की आशा है। बिजली की उत्पन्न शक्ति जो प्रथम योजना से पहले ६६ मिलियन किलोवाट घंटे थीं प्रथम योजना के अन्त में बढ़कर ११ मिलियन किलोवाट घंटे तथा दूसरी योजना के अन्त में १२ मिलियन किलोवाट घंटे होने की आशा है अर्थात् १९५५-५६ में जहाँ हमारी निर्मित शक्ति ३४ मिलियन किलोवाट थी वहाँ १९६०-६१ में यह ६६ मिलियन किलोवाट होने की आशा है।

गाँवों में छोटे-छोटे उद्योग धर्मों फैलाने तथा भूमि के नीचे के पानी को खेती के काम में लाने के लिये यह आवश्यक है कि छोटे गावों व कस्बों में बिजली पहुँचाई

जाने । प्रथम योजना के अन्त तक २०,००० और उससे ऊपर वाली आबादी के पस्को में से २५ प्रतिशत में बिजली पहुँचाई जा चुकी है । दूसरी योजना में ५००० से २०,००० तक की आबादी के गावों व ग्रहों में बिजली पहुँचाने की योजना है । इस योजना के अन्त तक ७५०० अतिरिक्त गावों व कस्बों में पहुँच जायगा ।

दूसरी योजना में विभिन्न राज्यों में बिजली की अतिरिक्त शक्ति कि नोटाट हम प्रकार बटने की आशा है—

आन्ध्र	१४०,३००
आसाम	२१,५००
बिहार	२०५,०००
बम्बई	४०५,०००
मध्य प्रदेश	१८३,०००
मद्रास	२८७,०००
उड़ीसा	२४७,०००
पंजाब	५४८,०००
उत्तर प्रदेश	३००,०००
पश्चिमी बंगाल	२४१,५००
जम्मू काश्मीर	११,०००
मध्य भारत	५६,०००
मैसूर	४०,६००
राजस्थान	७२,८००
तेलंगाना	५०,०००
द्रावणक्षीर कोचीन	१६१,०००

Q 6 What different type of forests are found in India ? Indicate their importance to the economy of the country. Mention measures adopted for their improvement. Have you any suggestions to offer ?

प्रश्न ६—भारतवर्ष में किस प्रकार के वन पाये जाते हैं ? देश की अर्थ-व्यवस्था में उसके वनों का महत्व बताइये । उनको उन्नत करने के लिये क्या कार्य किया गया है ? क्या आप कोई सुझाव देंगे ?

उत्तर—वनों के प्रकार—भारतवर्ष एक बहुत बड़ा महाद्वीप है । इसमें कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती है । यहाँ पर निम्नलिखित पाँच प्रकार के वन पाये जाते हैं —

(१) सदाबहार वन (Evergreen forests)—यह वन उन प्रदेशों में पाये जाते हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है जैसे पूर्वी हिमालय तथा आसाम प्रदेश तथा पश्चिमी घाट के प्रदेश में। इन वनों की वर्ष भर पानी मिलता रहता है इसलिये ये सदा हरे भरे रहते हैं। इन वनों के वृक्ष बहुत लम्बे और छतरीनुमा होते हैं। इनके नीचे अनेक प्रकार की बेले उग आती हैं। इन वनों में मुख्यतया बाँस, बेंत, महोगनी आदि के पेड़ पाये जाते हैं।

(२) चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन (Deciduous or Monsoon forests)—इन वनों के प्रदेश वे हैं जहाँ ४०" से ८०" तक वर्षा होती है। दक्षिणी पठार का भीतरी भाग इन वनों का प्रधान क्षेत्र है। ये वन सदाबहार के समान घन के नहीं हात और इनमें उगने वाले वृक्ष अधिक लम्बे भी नहीं होते। गर्म के दिनों में जब पानी भाप बनकर उड़ने लगता है तो वे पेड़ अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। इन वनों में साल, सगौन, हल्दू, शीशम, चन्दन, सेमल आदि लकड़ियाँ पाई जाती हैं।

(३) शुष्क वन (Dry forests)—ये वन उन स्थानों पर मिलते हैं जहाँ ४०" से कम वर्षा होती है। इन वन प्रदेशों में काँटेदार वृक्ष व कटीली झाड़ियाँ उगती हैं। ये वृक्ष छोट छोटे होते हैं परन्तु इन पेड़ों व झाड़ियों की जड़ लम्बी होती हैं। इनकी छाल मोटी व कड़ी होती है। वहाँ, कीकर, बकुल, खजेडा आदि वृक्ष उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के वन राजस्थान, गुजरात, मध्यभारत तथा दक्षिणी पंजाब में मिलते हैं। वास्तव में इनको वन नहीं कह सकते क्योंकि वनों का दृश्य नहीं दिखाई नहीं पड़ता। इधर-उधर केवल पेड़ व झाड़ियाँ ही दिखाई पड़ती हैं।

(४) पर्वतीय वन (Mountain forests)—हिमालय पर्वत पर विशेष प्रकार के वन पाये जाते हैं। ये वन किसी एक प्रकार के नहीं होते। पर्वत की तलहटी से १६००० फीट की ऊँचाई तक तापक्रम की भिन्नता के अनुसार प्रायः वे सभी प्रकार के वन मिलते हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव प्रदेशों तक भूमण्डल पर मिलते हैं। इन वनों में देवदार, पाइन, स्प्रूस, सनोवर, बलूत आदि की लकड़ियाँ पाई जाती हैं।

(५) समुद्र-तट वन (Tidal forests)—इन वनों का विस्तार नदियों के डेल्टाई प्रदेश में है। गङ्गा के वन इनमें विशेष महत्वपूर्ण हैं। यहाँ सुन्दरी नामक वृक्ष प्रचुरता से मिलता है। इसलिये इन वनों को सुन्दर वन कहते हैं। इसके अतिरिक्त ये वन महानदी, गोदावरी, कावेरी आदि के डेल्टा प्रदेशों में भी मिलते हैं। इन वनों में पाई जाने वाली लकड़ी जलाने के काम आती है और छाल चमड़ा रंगने के काम आती है। इनसे नावे भी बनाई जाती हैं।

वनों का क्षेत्रफल (Forest areas)—भारतवर्ष १९४१-४२ में २,८०,१५९ मील भूमि पर वन थे। यह कुल देश के क्षेत्रफल का २२.११ प्रतिशत है। परन्तु १२ मई १९५२ ई० के वन नीति प्रस्ताव (Forest Policy Resolution) में

सुझाव दिया गया है कि भारतवर्ष को कुन क्षेत्रफल के $\frac{1}{3}$ पर वन उगाने का ध्येय अपने सामने रखना चाहिये ।

विभाजन (Distribution)—भारत के वनों का विभाजन ठीक प्रकार का नहीं है । उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्र के १६.४ प्रतिशत पर, पंजाब के ११ प्रतिशत पर बिहार के १४.८ प्रतिशत पर, उड़ीसा के १३.७ प्रतिशत पर, मद्रास के २६.६ प्रतिशत पर, बङ्गाल के ५२.२ प्रतिशत पर, आसाम के ३६ प्रतिशत पर और मध्य प्रदेश के ४७.७ प्रतिशत पर वन पाये जाते हैं ।

उपज (Productivity)—भारत के वन न केवल क्षेत्र में कम हैं वरन् उनसे उपज भी कम मिलती है । जहाँ भारत में प्रतिवर्ष प्रति एकड़ २.५ घन फीट लकड़ी प्राप्त होती है वहाँ फ्रांस में ५६.८ घन फीट, जापान में ३७ घन फीट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में १८ घन फीट लकड़ी प्राप्त होती है ।

वनों का आर्थिक महत्व—

वन किसी देश की बहुमूल्य सम्पत्ति होते हैं । उनसे जलाने की लकड़ी मिलती है । वे पशुओं के लिये चारा प्रदान करते हैं । वे बहुत से उद्योग-धन्धों के लिये कच्चा मान जैसे लकड़ी, बाँस आदि प्रदान करते हैं । वे भूमि की उबरी शक्ति को कायम रखने हैं तथा मिट्टी को कटने से बचाते हैं । इसे प्रकार हम वनों के लाभों को दो भागों में बाँट सकते हैं—(१) प्रत्यक्ष लाभ (Direct advantages) तथा (२) अप्रत्यक्ष लाभ (Indirect advantages) ।

(१) **प्रत्यक्ष लाभ**—वनों से हमको कई प्रकार की उपयोगी वस्तुएँ प्राप्त होती हैं । इनमें से जलाने की लकड़ी मुख्य है । जलाने की लकड़ी की वर्तमान उत्पत्ति (१९५४-५५ में) का अनुमान ३०८,३४६ हजार घन फीट है । इसका मूल्य ३ करोड़ ५६ लाख ६१ हजार २० था । इस प्रकार भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष लकड़ी का उपयोग आधे मन (००२ टन) से भी कम है । इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रति व्यक्ति उपभाग एक टन के लगभग है । लकड़ी का अभाव गङ्गा सिंध के मैदानों में अधिक है जिसके कारण यहाँ गोबर जलाने की आदत पड़ गई । परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है क्योंकि गोबर हमारे देश में खाद के रूप में काम में लाया जाता है । Inspector General of forests ने कुछ वर्ष पूर्व अनुमान लगाया था कि भारत में २५० मिलियन टन गोबर की खाद प्रतिवर्ष जलाई जाती है । Imperial Council of Agricultural Research के अनुमान के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष ५५० मिलियन टन गोबर की खाद जलाई जाती है । लकड़ी की पूर्ति बढ़ाने के लिए पञ्चवर्षीय योजना में दो सुझाव दिये गये हैं । पहला, गाँवों में पड़ लगाना जो सामूहिक विकास योजना (Community Development Plan) के अन्तर्गत हो रहा है । दूसरा कोयले के उपभोग को बढ़ाना । १९५५-५६ तक गाँव में दस लाख टन कोयले का उपभोग बढ़ाने की योजना थी ।

वनो का दूसरा लाभ यह है कि उनसे हमको इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। युद्ध काल में इमारती लकड़ी की उत्पत्ति बहुत बढ़ गई थी परन्तु अब वह काम हो रही है। लकड़ी की आयात सहित हमारे देश में इमारती लकड़ी की पूर्ति लगभग २१ लाख टन है। इसमें से ७३ प्रतिशत नागरिकों के काम में आती है और शेष सरकार के। हमारे देश में फौलाद की कमी के कारण पंचवर्षीय योजना में सुझाव दिया गया है कि बिजली, टेलीफोन तथा नार के खम्बे फौलाद के स्थान पर लकड़ी के होने चाहिये। हमारे देश में इस प्रकार के ५०,००० खम्बे अष्टमान से तथा २०,००० सुन्दर वन तथा महानदी क्षेत्र से प्राप्त हो सकते हैं। १९५४-५५ में भारत में १०७,०५४ हजार घन फीट इमारती लकड़ी प्राप्त हुई जिसका मूल्य १५ करोड़ ८२ लाख ८० हजार ६० था।

वनो का तीसरा लाभ यह है कि इनसे कई उद्योगों के लिये कच्चा माल प्राप्त होता है। इन उद्योगों में से दियासलाई कागज पर्नोचर आदि के उद्योग मुख्य हैं। १९५४-५५ में कागज व दियासलाई की लकड़ी १२२८ हजार घन फीट प्राप्त हुई जिसका मूल्य १३ लाख ८७ हजार ६० था।

वनो का चौथा लाभ यह है कि इनसे बहुत सी उपयोगी वस्तुएँ जैसे लाख, चमड़ा रंगने का सामान, गोद, कत्था, जड़ी बूटियाँ, तारपीन का तेल आदि प्राप्त होती हैं। इन वस्तुओं की वार्षिक आय (१९५४-५५ में) ७७४ लाख रुपये के लगभग थी। इनमें से लाख और हर्षा तो विदेशों को भी भेजी जाती है। १९५०-५१ में भारतवर्ष से ११ करोड़ रुपये का लाख तथा १ करोड़ रुपये का हर्षा विदेशों को भेजा गया। वनो का पाँचवा लाभ यह है कि इनसे पशुओं के चराने का चारा प्राप्त होता है। इस प्रकार राज्यों को ६५ लाख रुपये वार्षिक की आय प्राप्त होती है। इनसे १ करोड़ ३० लाख गाय बैलें, ३६ लाख भैंसें तथा ६० लाख दूसरे पशुओं को चारा प्राप्त होता है। परन्तु हमारे वनों में पशुओं के चराने पर कोई नियन्त्रण न होने के कारण बहुत सा चारा खराब हो जाता है। इसलिये पंचवर्षीय योजना में सुझाव दिया गया है कि किसानों को अपने उत्तरे ही पशुओं को निशुल्क चराने का आज्ञा देनी चाहिये जो खेती तथा घरेलू काम के लिये आवश्यक है।

(२) अप्रत्यक्ष लाभ—वनो के बहुत से अप्रत्यक्ष लाभ भी हैं। वनों के कारण वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। वन पानी के बादलों को अपनी ओर खींचते हैं और उससे वर्षा बढ़ जाती है। सिन्धु में नील नदी के डेल्टे में केवल ६ रोज वर्षा का औसत था। परन्तु जब से वहाँ करोड़ों की सख्या में पेड़ लगे हैं तब से वर्षा के औसत दिन बढ़कर ४० हो गये हैं।

इसका दूसरा लाभ यह है कि पेड़ बरसात के दिनों में काफी पानी सोख लेते हैं। यह पानी भूमि में पहुँचकर भूमि के नीचे बहने वाली पानी की धारा में मिल जाता है और पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। इसके कारण कुओं में ऊपर ह

पानी निकल आता है। ऐसा न होने पर किसानों को सिंचाई करने में बड़ी कठिनाई होती है।

वन पृथ्वी की मिट्टी के कटने को रोकते हैं। जब बरसात में पानी बहुत वेग से बहने लगता है तो पड़ उसके प्रभाव को रोक देते हैं। बहुत सी मिट्टी इनके आस-पास जमा हो जाती है। मिट्टी के कटने को रोकने का मुख्य उपाय पेड़ लगाना ही है।

वन बाढ़ की भीषणता को भी बहुत कम कर देते हैं। यदि पहाड़ों पर वन न हो तो पानी बड़े वेग से बहता हुआ आए और अपने साथ बहुत से बड़े-बड़े पत्थरों को भी लुटका लाए जिसके कारण बहुत से आदमी मर सकते हैं तथा बहुत सा सामान नष्ट हो सकता है। चीन ने जब से अपने पहाड़ी वनों को साफ किया है तभी से वहाँ बाढ़ की भयङ्करता बहुत बढ गई है।

पेड़ अपनी जड़ों में बहुत सा पानी एकत्र किये रहते हैं और इस पानी को धीरे-धीरे निकालत रहते हैं। इस कारण प्रतिदिन की हवा में नमी रहती है। गर्मी में इसके कारण अच्छा मौसम रहता है। पड़ हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी हैं। वह हवा को साफ करते हैं और इस प्रकार हमको बहुत ना लाभ पहुंचाते हैं। वन देश की सुन्दरता को भी बढाते हैं।

सरकारी नीति (Government Policy)—

१८५७ ई० के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के पूर्व भारतवर्ष में वनों को बिना सोचे-समझे काटा जाता था जिसके कारण देश को बड़ी हानि हो रही थी। परन्तु इसके पश्चात् सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और सरकार ने प्रान्तीय तथा केन्द्रीय वन विभाग स्थापित किये। १८८३ ई० में वनों के महानिरीक्षक की नियुक्ति की गई। १८९४ ई० में सरकार ने वनों की निम्नलिखित चार श्रेणियों में विभाजित किया—

(१) वे वन जिनका रखना जलवायु तथा भौतिक वाग्यों से आवश्यक है। इन पर सरकारी नियन्त्रण होता है। इस प्रकार के वन वर्षों के लिये उपयोगी हैं। खाद आदि की रोक-थाम के लिये भी ये उपयोगी हैं। इनको सुरक्षित वन (Reserved forest) कहते हैं। १९५४-५५ में इन वनों के नीचे १,३८,०५६ वर्ग मील का क्षेत्र था।

(२) वे वन जिनमें बहुमूल्य लकड़ी प्राप्त होती है जैसे टीन, साल, देवदार आदि। सरकार इन पर इतना अधिक नियन्त्रण तो नहीं करती जितना कि वह पहले प्रकार के वनों पर करती है परन्तु फिर भी इन वनों पर सरकार का कुछ न कुछ नियन्त्रण अवश्य रहना है। इनमें लोगों को पैसे देकर पशु चराने तथा लकड़ी काटने की आज्ञा मिल जाती है। इन वनों को रक्षित वन (Protected Forests) कहते हैं। सन् १९५४-५५ में भारत में ६२६०४ वर्ग मील पर इस प्रकार के वन थे।

(३) वे जंगल जो केवल पशुओं को चराने के लिए आवश्यक है। वास्तव में इन्हें जंगल नहीं कहा जा सकता। इनको श्रेणी रहित (Unclassed) कहा जाता है। १९५४-५५ में इन वनों के नीचे ८०२३६ वर्ग मील का भाग था।

सरकार ने इन वनों की रक्षा के लिए वन विभाग (Forest Department) स्थापित किया है। इस विभाग के दो मुख्य कार्य हैं—(१) वनों को अत्यधिक शोषण से बचाना, (२) वनों की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करना। १९०६ ई० में वन अन्वेषण-शाला (Forest Research Institute) खोली गई जिसने खोज की है कि सदाई व भाभर घास के अतिरिक्त बाँस से भी बागज तैयार हो सकता है। इस अन्वेषण शाला ने यह भी पता लगाया है कि लकड़ी तथा बाँस को कीड़ों से कैसे बचाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने अभी पिछले कई वर्षों से वन महोत्सव मनाना आरम्भ किया है। प्रतिवर्ष १ जूलाई से ८ जूलाई तक सारे देश में पेड़ लगाये जाते हैं। उनमें जनता, सरकार तथा स्थानीय स्वशासन सभी भाग लेते हैं। इस प्रकार देश में वनों को बढ़ाने का प्रयत्न बराबर किया जा रहा है।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वन नीति—

पंचवर्षीय योजना में बताया गया है कि हमारे देश में जलाने की लकड़ी का बड़ा अभाव है और यह विशेषतः गंगा सिन्ध के मैदान में है। इसलिए वनों को योजना अनुसार बढ़ाना आवश्यक है। इसके लिए बेकार पड़ी भूमि की नाप तोल करनी आवश्यक है और उस पर उचित ढंग से वन उगाना आवश्यक है। इसी बीच में केन्द्रीय वन बोर्ड को यह बताना चाहिए कि प्रत्येक राज्य में वनों के नीचे कितना क्षेत्रफल होना चाहिए। योजना में बताया गया है कि वन उसी समय काटने की आज्ञा देनी चाहिए जब कि वे आवश्यकता से अधिक हो या काटे गए क्षेत्र के बराबर क्षेत्र पर वन लगाए जा सकें। योजना में सुझाव दिया गया है कि जमींदारी उन्मूलन के फलस्वरूप जो राज्य सरकारों के आधीन ४ करोड़ एकड़ भूमि आ गई है उसमें से अधिकतर पर से पेड़ गिरा दिये गए हैं। इस भूमि पर पेड़ उगाए जा सकते हैं। योजना में सुझाव दिया गया है कि अल्पकाल में तीन प्रकार से वनों का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है—(१) मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए वन लगाकर (२) अधिक क्षेत्र पर पेड़ लगाकर तथा (३) गाव में बाग लगा कर।

वनों के प्रबन्ध में केन्द्र और राज्यों की नीतियों में सामंजस्य नहीं पाया जाता। इस कमी को पूरा करने के लिए इस योजना में सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकार को प्रतिवर्ष अपनी योजना वनों के महा निरीक्षक (Inspector General of Forests) के पास भेज देनी चाहिए। समय-समय पर राज्यों के वन अधिकारियों का सम्मेलन बुलाना चाहिए जिससे कि प्रत्येक राज्य की कठिनाई दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

इस योजना के अनुसार विभिन्न राज्यों में वनों के विक्रम के लिये प्राथमिकता प्रदान करने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—

(१) जिन देशों में बड़ी-बड़ी रियल्टी का बिन्दु हुआ है अथवा जमींदारी जग्मूलन के कारण निजी वन सरकार के पास आ गए हैं उन वनों के प्रबन्ध को और अधिक मजबूत बनाना ।

(२) युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक काटे गए वनों का फिर से लगाना ।

(३) जिस स्थान पर अधिक मिट्टी कट गई है वहाँ पेड़ लगाना ।

(४) वनों में यातायात की सुविधा करना ।

(५) गांव में बाग लगाना ।

(६) लकड़ी की पूर्ति बढ़ाने के लिए काम में न आने वाली लकड़ियों का रासायनिक ढंग से शोषण ।

ऊपर की प्राथमिकताओं के आधार पर वन-विक्रम योजना में निम्नलिखित ढङ्ग से व्यय करने की योजना—

वन विकास	६११ ३ लाख रु०
प्रबन्ध	२४२ ४ लाख रु०
वन-उद्योग	४२ ५ लाख रु०
शिक्षा तथा ट्रेनिङ्ग	३३ ३ लाख रु०
अनुसन्धान	१० ० लाख रु०
कुल व्यय	६५२ ५ लाख रु०

इस योजना काल में विभिन्न राज्यों में जो कार्य किया उनके पल्लवरूप ७५,००० एकड़ भूमि पर हरी परत प्रदान की गई तथा ३,००० एकड़ प्रति वर्ष दर पर विदासलाई की लकड़ी के पेड़ लगाए गए । ३००० मील लम्बी वन सड़क बनाई गई तथा २० लाख एकड़ वन निजी अधिकार से लेकर सरकारी अधिकार में लाए गये ।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना और वन—

इस योजना में वनों के लिये २४ ७२ करोड़ रुपये रखे गए हैं । इस योजना में ३ ८० लाख एकड़ पर के पतित हुए वनों को फिर से उन्नत किया जाएगा, ५०,००० एकड़ पर टीक आदि व्यापारिक पेड़ लगाये जायेंगे, १३००० एकड़ पर नीला गोड तथा अन्य पेड़ लगाने जायेंगे तथा दूसरे २००० एकड़ पर जड़ी बूटियाँ लगाई जायेंगी । ५०,००० एकड़ पर विदासलाई की लकड़ी उगाई जायगी । नहरों तथा सड़कों, गाँव की बेकार भूमि आदि पर भी पेड़ लगाने की योजना है । इस योजना में वनों की सड़कों को उन्नत करने तथा इमारती लकड़ी को अच्छे ढंग से प्राप्त करने की भी योजना है । इनके अतिरिक्त लकड़ी को ठीक समय उगाने व

पकने के लिये प्लान्ट लगाये जायेंगे तथा वनों का सर्वे करने के लिये एक संस्था की स्थापना की जायेगी। दक्षिणी भारत के लिये एक वन रिमर्च की स्थापना की जायगी।

उन्नति के सुझाव—

भारतीय सरकार ने सर्वप्रथम १८६४ ई० में अपनी वन-नीति को घोषित किया जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जलवायु को ठीक रखने के लिये वनों की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। यह भी घोषित किया गया कि यद्यपि कृषि वनों से अधिक आवश्यक है तो भी कृषि करने के लिये वनों के क्षेत्र को एक निश्चित सीमा से कम नहीं करना चाहिए। इनके स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा करके वृद्ध धन प्राप्त करना चाहिए।

यद्यपि वन-नीति (Forest Policy) घोषित किए इतना समय हो गया है तो भी इस देश में वन लगाने की ओर सरकार की रुचि कभी नहीं हुई। सरकार ने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि वनों के लिये कम से कम कितना क्षेत्रफल होना आवश्यक है। दूसरे उसने कभी यह नहीं सोचा कि देश के उस क्षेत्र-फल पर जहां आज वन नहीं है कितने वन लगाये जा सकते हैं। यही नहीं सरकार ने कभी वनों की रक्षा के लिये कोई ध्यान नहीं दिया। देश के २,८०,१५६ वर्गमील में से केवल २,५६,५६० वर्ग मीन वन सरकार के अधिकार में हैं और शेष वनों पर जनता का नियन्त्रण है। वह वन जो कि सरकार के अधिकार में है सबके सब वन विभाग के अधिकार में नहीं है वरन् उनमें से ८६,०१६ वर्ग मील पर ही वन विभाग का अधिकार है। जिस क्षेत्र पर वन-विभाग का अधिकार है उसमें से केवल ६५,७७३ अथवा कुल वनों के क्षेत्रफल का ४०% सुरक्षित भाग है और सुरक्षित भागों में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वनों की रक्षा के हेतु नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश के लगभग तीन चौथाई वनों पर सरकार का विशेष नियन्त्रण नहीं है। इसके सिवाय हमारे देश में वनों का ऊपर बताई हुई तीनों श्रेणियों में इस प्रकार विभाजन किया गया है कि उसके कारण न तो वन विभाग भूमि को कटने ही से बचा सकता है और न बाढ़ को रोक सकता है। उदाहरणार्थ बम्बई राज्य में वनों का विभाजन इस प्रकार से है कि यदि आधी पहाड़ी सुरक्षित है तो आधी जनता के लिये खुली है। इस कारण वन-विभाग कोई इस प्रकार की योजना नहीं बना सकता कि जिससे मिट्टी न बटे और न ही बाढ़ कोई हानि पहुंचा सके।

इसलिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार की वन-नीति को समाप्त किया जाय। सरकार को चाहिये कि वह इस प्रकार की नीति बनाये जिससे कि मिट्टी कटने तथा बाढ़ की समस्या ठीक प्रकार से हल हो सके। ऐसा करने में यह सम्भव है कि जनता के अधिकारों को कम करना पड़े। पर इसकी कोई चिन्ता न करनी चाहिए।

एक बात और बताने योग्य है वह है यह, कि आजकल वन-विभाग राज्य

इन मजदूरों की वार्षिक आय का औसत २०४ रुपये है। अधिकतर मजदूरों की इससे कम ही है। इतनी कम आय होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इस प्रकार खेती पर लगे हुये लगभग २५ करोड़ लोगो मे से अधिकतर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इससे अधिक लोगो के खेती पर लगे होने के कारण ही देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग ४५ प्रतिशत खेती से ही प्राप्त होता है। जहाँ भारत में खेती पर इतने लोग लगे हुए हैं वहाँ इंग्लैंड और अमरीका में इसकी अपेक्षा बहुत कम लोग लगे हुये हैं। जहाँ भारत के १००० व्यक्तियों में से ७०६ खेती, पन्ध्र, वन तथा मछली पकड़ने में लगे हुए हैं वहाँ संयुक्त राष्ट्र अमरीका में केवल १२८ तथा ग्रेट ब्रिटेन में केवल ५६ इस कार्य में लगे हुए हैं।

इसके विपरीत भारत में बहुत कम लोग उद्योगों तथा दूसरे कार्यों में लगे भिरे हैं। जहाँ हर १००० व्यक्तियों में से भारत के केवल १५२ व्यक्ति ही खानो, उद्योगों तथा वाणिज्य में लगे हुये हैं वहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ४५६ तथा ग्रेट ब्रिटेन में ५५५ व्यक्ति लगे हुए हैं। यही नहीं, दूसरे उद्योगों तथा सेवाओं में भी भारत के बहुत कम लोग लगे हुये हैं। इनमें लग हुये लोगो का अनुमान प्रति १००० में से १४१ है। इनके विपरीत यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ४१६ तथा ग्रेट ब्रिटेन में ३६५ है। इन सबके कारण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन में सतुलित अर्थ-व्यवस्था है, अर्थात् इन दोनों देशों में लगभग आधे लोग खेती आदि तथा आधे दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं। इस कारण यदि इन देशों में खेती खराब हो जाए तो भी देश की विशेष ज्विन्ता नहीं होती परन्तु हमारे देश में ऐसा होने पर सारी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाती है। यही कारण है कि हमारे देश में इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि देश के बहुत से लोगो को खेती से हटाकर छोटे-बड़े उद्योगों में लगा दिया जाय। परन्तु ऐसा करना बहुत काल तक सम्भव न हो सकेगा क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया गया है कि १९७५-७६ में भी खेती पर लगभग ६० प्रतिशत लोग लगे रहेंगे।

खेती पर इतनी अधिक निर्भरता के कारण हमारे देश के खेत बहुत छोटे-छोटे हैं जिनके कारण हमारे देश की प्रति एकड़ उपज मसार के दूसरे देशों से कम है। इस कारण देश में बेरोजगारी व गरीबी पाई जाती है। इन दोनों बातों के कारण हमारे देश के लोगो का जीवन-स्तर बहुत नीचा है। यही गरीबी हमारे लिए अभि-प्राप्त बनी हुई है और हमारी उन्नति के बहुत से माग बन्द किए हुए हैं।

Q 11 What are the different social and religious institutions that are found in India and how do they affect the economic life of the people ?

प्रश्न ११—भारतवर्ष में कौन-कौन सी सामाजिक तथा धार्मिक संस्थायें पाई जाती हैं और वह लोगों के आर्थिक जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं ?

भारतवर्ष में कई प्रकार की धार्मिक तथा सामाजिक संस्थायें पाई जाती हैं, जो इस देश के लोगों के आर्थिक स्थिति के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। उनमें मुख्य-मुख्य ये हैं—

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| (१) जाति प्रथा | (२) सामूहिक परिवार प्रथा, |
| (३) उत्तराधिकार के नियम, | (४) पदा प्रथा । |

जाति प्रथा (Cast System)—एक जाति कुछ ऐसे परिवारों का समूह होती है जिनका एक ही वंश और पेशा होता है तथा जो एक ही प्रकार से रीति-रिवाजों का पालन करते हैं और जो अपने को एक महापुरुष की सत्तान बताते हैं। एक जाति के लोग एक से ही सामाजिक नियमों का पालन करने के कारण एक दूसरे से सम्बन्धित होते हैं। ये समय-समय पर उत्सवों के रूप में एक स्थान पर एकत्र होते हैं और इस प्रकार से अपने सामाजिक सम्बन्धों को अधिक मजबूत बनाते हैं। जाति-पाँति की प्रथा हमारे यहाँ इतनी मजबूत है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से न खाने-पीने के सम्बन्ध रखते हैं और न एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों से विवाह आदि करते हैं। भारतवर्ष में इस प्रकार की जातियाँ तथा उप-जातियाँ दो हजार से कम नहीं हैं। पर उनमें से चार मुख्य हैं—ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र।

जाति प्रथा के लाभ—जाति-पाँति प्रथा में चाहे आज भले ही अशुभ आ गये हों तो भी पुराने समय में इससे बहुत से लाभ थे। एक जाति के लोग अपने आपको एक बड़े परिवार का घटक समझते थे। उनमें आपस में बड़ा प्रेम था। वे एक दूसरे के सुख-दुख के साथी होते थे। यदि जाति के किसी घटक पर कोई आपत्ति आती थी तो वे सब मिलकर उसका सामना करते थे और इस प्रकार से जाति के लोगों की रक्षा होती थी। जाति के लोग मिल-जुलकर अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध भी करते थे। यदि जाति की कोई स्त्री विधवा हो जाती थी या कोई मनुष्य अपने पीछे कुछ बच्चे छोड़कर मर जाता था तो जाति वाले ही उनकी

रक्षा करते थे। यदि जाति के कुछ घटकों में आपस में कुछ झगडा हो जाता था तो निपटारा वे स्वयं अदालत में जाये बिना ही कर लेते थे।

आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा का बडा महत्व था। एक जाति के लोग साधारणतया एक ही पेशे वाले होते थे। यह पेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था इसलिए हर पेशे के लोगों की कार्यक्षमता बहुत अधिक होती थी। उस समय किसी आदमी को अपने लडके को अपने पेशे की शिक्षा देने के लिये कहीं भेजने की आवश्यकता न थी। अपने परिवार में रहकर ही लडका अपने पेशे के सब भेदों को समझ जाता था। यह बात उस समय इसलिये आवश्यक थी कि उस समय शिक्षा का अभाव था। जाति प्रथा के अभाव में लडके अपने पेशे की शिक्षा पाने से वंचित रह जाते।

जाति प्रथा बनाम गिल्ड—भारत की पेशेवर जातियों की तुलना योरोप की गिल्डों से की गई है। गिल्ड के समान वह अपने सदस्यों को शिक्षा देती थी, उनमें अच्छी भावनायें फैला करती थी। उनके झगडों का निपटारा करती थी, उनकी मजदूरी और काम पर नियन्त्रण करती थी और आपत्ति बाल में उनकी सहायता करती थी। परन्तु जाति और गिल्ड में बहुत से अन्तर थे।

गिल्ड स्वयं इच्छा से बनाये संगठन होते थे परन्तु जाति इस प्रकार के संगठन नहीं होते थे।

(२) गिल्ड के सदस्यों के ऊपर विवाह सम्बन्धी कोई भी रखावट न थी गिल्ड का सदस्य अपनी इच्छानुसार किसी से भी शादी कर सकता था। परन्तु एक जाति का आदमी अपनी ही जाति की लडकी से शादी कर सकता था।

(३) गिल्ड के सदस्यों का आपसी सम्बन्ध पेशे के आधार पर था परन्तु जाति के लिये पेशे का होना आवश्यक बात नहीं।

जाति प्रथा के दोष—प्रारम्भ में चाहे इस प्रथा से कुले भी लाभ हुआ हो पर आजकल यह मानना पड़ेगा कि यह प्रथा भारतवर्ष की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक उन्नति में बहुत बाधक है। जाति-पाति के भेद-भाव के कारण लोगों में इतना बैर और वैमनस्य बढ गया है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को सहन ही नहीं कर सकते। इसके कारण यह देश राजनीति दृष्टि से बहुत दुर्बल हो गया है। इसी दुष्परिमाण के कारण हम देश का विभाजन हुआ और आगे भी और बहुत सी बातें हो सकती हैं। दक्षिणी भारत में हुये ब्राह्मणों तथा गैर ब्राह्मणों के झगडों की निन्दा करते हुये प० नेहरू ने हाल ही में कहा था कि जाति प्रथा ने भूतकाल में भारतवर्ष की एकता को कमजोर तथा नष्ट किया और यदि यह बहुत दिनों तक चलती रही तो भारत विलुप्त भी उन्नति नहीं करेगा। जाति प्रजातन्त्र तथा समाजवाद के विरुद्ध है। जाति-पाति की प्रथा के कारण आर्थिक क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होनी है। इस प्रथा के

कारण लोगों के पेशे प्रायः निश्चित से हो गये हैं, जैसे ब्राह्मण विद्या सिखाने का कार्य करते हैं, क्षत्री रक्षा का, वश्य वाणिज्य का और शूद्र सेवा का। इनसे यह हानि होती है कि यदि एक जाति का आदमी कोई ऐसा पेशा करना चाहे जिसकी दूसरी जाति के लोग करते हैं तो वह बहुधा ऐसा नहीं कर सकता जैसे एक दान्न का लडका यदि जूने बनाने या लुहार का कार्य करना चाहे तो उस जाति के लोग उसको उस काम के करने के लिये मना करेंगे। इसी कारण लोगों की बुद्धि का विकास उस दिशा में नहीं होने पाता जिसमें होना चाहिये। इससे देश की आर्थिक दृष्टि में बहुत हानि होती है। जाति-पाति के भेद भाव के कारण ही लोगों का खाना पीना तथा वस्त्र आदि भी निश्चित से हो गये हैं। इस कारण सब चीजों की माग देश की हर एक जाति की ओर नहीं आती वरन् वह एक वर्ग विशेष से आती है। इसी कारण यहाँ पर बड़े-बड़े उद्योग धन्धे नहीं होने पाते। पुराने समय में जाति-पाति के भेद-भाव के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं जाना चाहते थे। इस कारण किसी स्थान पर तो श्रम की बहुत अधिकता रहती थी और किसी स्थान पर बहुत कमी। पुराने समय में पूजा भी श्रम के साथ ही उधर-उधर आती जाती थी इसलिये पूजा भी किसी स्थान पर कम और किसी पर अधिक रहती थी। इस प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि हमारे देश का शूद्र वर्ग जिसकी सख्या दस बारह करोड़ से कम नहीं है अपने आप को सदा ही पतित समझता है और अपने आपको ऊँचा उठाने के सब मार्ग बन्द समझता है।

जाति प्रथा का पतन—यद्यपि भारत के कोटि-कोटि निवासियों के लिये आज भी जाति प्रथा अत्यन्त महत्वपूर्ण है तब भी वे लोग जो कि पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में हैं उनका दृष्टिकोण बदल गया है आजकल के शिक्षित लोग व्यक्तिवाद की भावना में हैं उनका दृष्टिकोण बदल गया है आजकल के शिक्षित लोग व्यक्तिवाद की भावना से प्रभावित हैं। इसलिये जाति के बन्धन ढीले पड़ते जा रहे हैं। आजकल के शिक्षित लोग भिन्न-भिन्न जाति के लोगों के साथ खाने पीने में कोई सन्देह नहीं करते। अन्तर्जातीय विवाह भी होने शुरू हो गये हैं। बहुत से युवक भविष्य में उन्नति की इच्छा से अपने पैतृक कार्य को छोड़कर अन्य कार्यों को कर रहे हैं। आवागमन के साधनों की उन्नति होने से गावों की पृथक्ता सम्पन्न हो रही है, व्यापार और उद्योगों की उन्नति हो रही है। इसलिये युवक वर्ग वही पेशा करता है जो लाभप्रद होता है। रेल और मोटरो द्वारा यात्रा करते समय कोई किसी की जाति नहीं पूछता। ब्राह्मण और शूद्र बराबर-बराबर बैठते हैं। स्कूलों में भी सब जातियों के लड़के लड़कियाँ एक ही साथ बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इन सब बातों के कारण भी जाति प्रथा का पतन होता जा रहा है। इन सबके अतिरिक्त महात्मा गांधी के अप्रसृश्यता को दूर करने के आन्दोलन और उनके ऐतिहासिक पूना उपवास ने भी भारत की जाति प्रथा के पतन में बड़ी सहायता पहुँचाई है। जब से भारत स्वतन्त्र हुआ है तब से सब जातियों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त

हो गये हैं। इसलिए कोई भी आदमी जो राजनीति में जाना चाहता है वह किसी दूसरी जाति के लोगों से अधिकाधिक सम्पर्क में जाना चाहता है जिससे कि वह उनका मन प्राप्त कर सके। आजकल बाह्य एर छूट के पान जाने में कोई सकोच नहीं करता। वह उसकी गले लगाने का प्रयत्न करता है। इस कारण जाति प्रथा की भूतकाल की दृढ़ता कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती। इस प्रकार हम देखते हैं कि आजकल जाति प्रथा के बन्धन ढीले होते जा रहे हैं।

(२) सामूहिक परिवार प्रथा (Joint Family System)—यह भारतवर्ष की दूसरी विशेष संस्था है। सामूहिक परिवार में पारंपारिक दशों की भाँति पति पत्नी तथा बच्चे ही नहीं होते बल्कि इन देश में परिवार का रूप बहुत बड़ा होता है। यहाँ पर दादा, परदादा, पुन, पिता-माता, दादी, परदादी, भाई भावज, स्त्री बच्चे आदि सब एक साथ रहते हैं। उनका भोजन एक साथ पकन है। परिवार के कमाने वाले व्यक्ति अपनी सब कमाई परिवार कर्ता को दे देते हैं और वह ही उन धन का व्यय करता है। इस प्रकार परिवार के लोगों में बहुत ही प्रेम होता है।

लाभ—सामूहिक परिवार प्रथा के बहुत से लाभ हैं। इनमें सबकी सब सम्पत्ति एक ही साथ रहती है। इस कारण जब तक सामूहिक परिवार प्रथा हमारे देश में रही तब तक इन देश में भूमि का बंटवारा नहीं हुआ और छोट छोट खेतों की जो समस्या हमारे देश के सामने आजकल है वह नहीं थी। पर सामूहिक परिवार के टूटने से यह समस्या भयंकर रूप से हमारे सम्मुख आ खड़ी हुई। सामूहिक परिवार का एक लाभ यह भी है कि सारे परिवार का भोजन एक ही साथ पकना है। इस कारण धन के उपयोग में बड़ी कमी हो जाती है। सामूहिक परिवार में रोगी, दुर्बल, अशक्तों को इतर उतर नहीं भटकना पड़ता, उनको घर ही में आश्रय मिल जाता है। यह बात हमारे देश के लिये बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड आदि देशों की भाँति सरकार की ओर से ऐसे लोगों का कोई प्रबन्ध नहीं होता। इनका एक बहुत बड़ा लाभ यह भी है कि इससे परिवार के लोगों में प्रेम, भ्रातृभाव आशा मानन की आदत आदि कई अच्छे गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसका एक यह भी लाभ है कि इसके कारण उचित प्रकार का श्रम विभाजन हो जाता है। परिवार के कमजोर आदमियों को हल्का काम करने को दिया जाता है और ताकतवर आदमी भारी काम कर लेते हैं।

दोष—पर जहाँ पर सामूहिक परिवार के इतने गुण हैं वहाँ पर वह दोष युक्त भी है। इस प्रथा के कारण परिवार के कुछ लोग सदा ही आलसी बने रहते हैं वह कुछ काम नहीं करते और दूसरी की कमाई पर रहते हैं। दूसरे, इस प्रथा के कारण पूँजी का संचय भी कठिन हो जाता है क्योंकि आपस की खर्च करने की होड़ के कारण परिवार का हर एक घटक अधिकसे अधिक खर्च करना चाहता है। इस प्रथा के कारण ही लोगों में घर का मोह इतना अधिक हो जाता है कि वे इतर उधर नहीं जाना चाहते। इससे कई स्थानों पर श्रमिकों की कमी हो जाती है

और देश की उत्पत्ति को हानि होती है। अन्त में इसके कारण, परिवार के लोगों को काम करने का कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता। परिवार का एक आदमी जब यह देखता है कि वह तो खूब काम करना है और दूसरा काम नहीं करता परन्तु दोनों एकसा ही जीवन व्यतीत करते हैं तो वह भी काम करना छोड़ देता है। इससे बड़ी हानि होती है।

सामूहिक परिवार प्रथा के पतन के कारण—परन्तु आजकल सामूहिक परिवार का पतन हो रहा है। इसका कारण यह है कि हमारे देश के लोगों पर पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने के कारण उनमें व्यक्तिगत भावना प्रबल हो रही है। इसलिये कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में उस भारी बोझ को जो कि उस व्यक्तिगत सुख भोग तथा महत्वाकांक्षा में बाधक होता है, उठाना नहीं चाहता। आवागमन के साधनों की उन्नति के कारण युवक रोजगार की खोज में इधर-उधर जाने में सकोच नहीं करते। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बहुत से मजदूर बम्बई के कारखानों तथा आसाम के चाय के बागों में काम करते हैं तथा बङ्गाल और मद्रास के लोग दिल्ली, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में कार्य करते हैं। पारिवारिक पेशों के नष्ट हो जाने के कारण भी यह असम्भव हो गया कि एक परिवार के सब व्यक्ति एक ही स्थान पर ही रहे। उनकी रोजगार की तलाश में इधर-उधर जाना ही पड़ता है। अग्रजी न्यायालयों की स्थापना ने भी सामूहिक परिवार के पतन में सहायता पहुँचाई है क्योंकि इनके द्वारा परिवार की सम्पत्ति का बटवारा सरलता से सम्भव हो गया है। इस प्रथा के समाप्त होने का एक यह भी कारण है कि अब परिवार के घटकों में एक-दूसरे के साथ प्रेम नहीं रहा और न ही वे एक-दूसरे के लिये बलिदान करने को तैयार हैं। उनमें आपस में बहुत झगड़े रहने हैं। इन सब बातों के कारण अब सामूहिक परिवार बड़ी तेजी से टूटते जा रहे हैं।

(३) उत्तराधिकार के नियम (Laws of Inheritance and Succession)—

भारतवर्ष में उत्तराधिकार के दो नियम हैं—

(१) मिताक्षरा (Mitakshara), (२) दाय भाग (Dayabag)

(१) मिताक्षरा—यह नियम बंगाल को छोड़कर शेष सारे भारतवर्ष में लागू होता है। इस नियम के अन्तर्गत परिवार की दादाइलाही सम्पत्ति पर पिता और पुत्रों का अधिकार समान होता है। यद्यपि पिता सम्पत्ति की देख-रेख करता है तो भी कोई भी लड़का अपने पिता के जीवित रहते हुये भी सम्पत्ति का बटवारा कर सकता है। इस प्रकार इस नियम के अनुसार पिता और पुत्रों के बीच भी सम्पत्ति का बटवारा हो सकता है। यदि पिता के जीवन काल में सम्पत्ति का बटवारा नहीं हुआ तो उसकी मृत्यु के पश्चात् सम्पत्ति पर स्वयं ही पुत्रों का अधिकार हा जाता है। यदि कोई पिता सम्पत्ति को बेचना चाहे तो वह अपने पुत्रों की इच्छा के बिना उसको बेच नहीं सकता है।

(३) दाय भाग नियम—यह नियम बगल में चालू है। इसके अन्तर्गत परिवार की सम्पत्ति पर परिवार के कर्ता का पूरा अधिकार होना है। वह उस सम्पत्ति की देख-रेख करता है। यदि वह ठीक समझे तो वह इसको बिना पुत्रों की इच्छा के बेच भी सकता है। इस प्रकार इस नियम के अनुसार सम्पत्ति का वटवारा केवल पिता की मृत्यु के पश्चात् भाइयों में ही होता है।

इन दोनों ही नियमों के अन्तर्गत लड़कों को सम्पत्ति का कोई भी भाग नहीं दिया जाता। परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १९५६ ई० के अनुसार अब सम्पत्ति का वटवारा केवल लड़कों में ही न होगा बल्कि लड़कियों, विधवाओं, गौं, मरे हुए लड़के के लड़के, लड़की, मरी हुई लड़की की लड़की, मरे हुए लड़के की विधवा, में भी बाँटी जायगी। इनमें से कोई न होने पर सम्पत्ति का वटवारा कुछ और में जो कि द्वितीय श्रेणी में रखे गए हैं किया जायगा।

(४) मुस्लिम नियम—मुसलमानों के यहाँ सम्पत्ति केवल लड़कों में ही नहीं बाँटी जाती बल्कि लड़कियों को भी सम्पत्ति का कुछ भाग दिया जाता है।

हानि—उत्तराधिकार के इन नियमों के कारण देश की कृषि को एक बहुत बड़ी हानि हुई। इन नियमों के कारण देश की भूमि धीरे-धीरे छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट गई और आज यह स्थिति है कि देश में दूर-दूर तथा छोटे-छोटे खेत पाए जाते हैं जिनके ऊपर लाभप्रद खेती ही ही नहीं सकती। यही कारण है कि हमारे देश में प्रति एकड़ में ससार के सब देशों से कम अन्न उत्पन्न होता है।

इसके अतिरिक्त इन नियमों के कारण हर एक व्यक्ति को सम्पत्ति का एक छोटा सा भाग मिलता है। इसलिए पूँजी का संचय नहीं हो सकता और न ही बड़े बड़े उद्योग चलाए जा सकते हैं।

लाभ—इन नियमों का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे परिवार के सब लड़कों को जीवन के प्रारम्भ में ही कुछ न कुछ सम्पत्ति मिल जाती है और इससे देश के अन्दर एक शक्तिशाली मध्यम वर्ग का निर्माण हो जाता है। इसका एक लाभ यह भी है कि इससे सारे समाज में सम्पत्ति का वटवारा समान हो जाता है।

पर उत्तराधिकार के इन नियमों से जो लाभ हैं वह दोषों की अपेक्षा बहुत कम महत्व रखते हैं। हम यह कह सकते हैं कि इन नियमों से देश की आर्थिक उन्नति को बहुत क्षति पहुँची है।

(५) पर्दा प्रथा (Purdah System)—इस देश में पर्दे का रिवाज मुगलों के काल से आरम्भ हुआ। इस प्रथा के कारण देश को बहुत हानि हुई। इसके कारण इस देश का स्त्री समाज सदा ही घर की चारों दीवारों के भीतर बन्द रहता है। इसके कारण स्त्रियों का स्वास्थ्य खराब रहता है। इसी के कारण स्त्री जाति को शिक्षा प्राप्त करने का कम अवसर प्राप्त होता है। इसलिए इन स्त्रियों में जो सन्तान उत्पन्न होती है वह निर्बल तथा कम बुद्धि वाली होती है। इसी के कारण

स्त्री जाति जिसकी सख्या आधे के लगभग है घर के बाहर कोई धर्म नहीं कर सकती और वह धर्म देश के लिए कोई काम नहीं आता ।

(६) भारतीय धर्म (Indian Religion)—कुछ लोगो का विश्वास है कि भारतवर्ष में धर्म के कारण बहुत ही आर्थिक हानि हुई है । पर हम इस मत में विल्कुल भी सहमत नहीं हैं । भारतीय धर्म, धर्म सिद्धान्त पर आधारित है । फिर यह धर्म मनुष्य को निकम्मा कैसे बना सकता है ? फिर यदि हम इतिहास को देखें तो हमको पता लगेगा कि भारतवासियों ने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ही उन्नति की थी । वे कला-कौशल, गायन-विद्या आदि में बहुत ही निपुण थे । वे अपने ही देश के जहाजों में बैठ कर दूर-दूर के देशों में गए और वहां पर अपने बड़े-बड़े राज्य स्थापित किए । फिर हम यह कैसे कहें कि धर्म भारतवासियों की उन्नति के मार्ग में बाधक है । हाँ भारतीय धर्म लोगों पर इस दान का जोर देता है कि अपनी इच्छाओं का क्षेत्र सीमित रखो, अधिक धन एकत्र मत करो । अपना ही नहीं बरन् सारे समाज का हित सोचो । जहां तक इन बातों का सम्बन्ध है वे सब बहुत ही उत्तम बातें हैं । इन बातों से देश की आर्थिक उन्नति में कोई बाधा नहीं पड़ सकती, इसके विपरीत, इन आदर्शों का बड़ा पालन करने से वर्तमान काल की बहुत सी समस्याएँ सुलझ जाएँगी । इस कारण हम कह सकते हैं कि भारतीय धर्म भारतवर्ष की उन्नति में बाधक नहीं है, सहायक है ।

यदि हम भारतवर्ष के पिछड़े हुए होने के कारण तलाश करें तो वह हम को भारतीय धर्म में नहीं बरन् दूसरी बातों में मिलेगा, जैसे हमारे देश की जलवायु इस प्रकार की है कि उसमें बुखार, मलेरिया, प्लेग आदि कई प्रकार के रोग हो जाते हैं । इन रोगों का जो भी आदमी शिकार होता है वह या तो मर जाता है या इतना कमजोर हो जाता है कि वह भविष्य में कोई काम नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त हमारे देश में समय-समय पर बड़े भयंकर अकाल पड़ते रहते हैं जिनमें मनुष्यों को भोजन भी प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार की कठिनाइयों के कारण ही भारतवर्ष के लोग निराशावादी हो गए और वे भाग्य पर विश्वास करने लगे । इसके अतिरिक्त अंग्रेजी राज्य की स्थापना से पहले हमारे देश में बड़ी लूटमार, चोरी, डाके पड़ते थे । कोई भी मनुष्य अपनी जान व माल की सुरक्षित नहीं समझता था । ऐसी स्थिति में भारत के लोग किस प्रकार बड़े-बड़े उद्योग चला सकते थे तथा किस प्रकार पूँजी का संचय इस देश में हो सकता था । इन बातों के अतिरिक्त हमारे पतन का एक कारण और भी है और वह है सूअरूत । इस कारण हमारे देश के लगभग ३० लोग यह भावना रखते हैं कि वे जीवन में कभी भी उन्नति नहीं करेंगे । इन सब बातों के कारण ही हमारे देश का आर्थिक विकास रुक गया । परन्तु हमारे लिए निराश होने का कोई कारण नहीं है क्योंकि आधुनिक विज्ञान की उन्नति से पहले योरोप के देश भी कुछ ऐसी ही बातों के कारण उन्नति नहीं कर रहे थे । परन्तु विज्ञान की उन्नति के होने ही उन्होंने बड़ी उन्नति की ।

भारत के आर्थिक जीवन में परिवर्तन

Q 12

Q 12 Give an idea of the social and economic conditions in India at the beginning of the 19th century. What changes were brought about by the economic method and commercial policy of the East India Company.

प्रश्न १२—१९वीं शताब्दी के आरम्भ में भारतवर्ष की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति कैसी थी? ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आर्थिक ढङ्गों तथा उसकी व्यापारिक नीति से उसमें क्या परिवर्तन हुये?

१९वीं शताब्दी के आरम्भ में हमारा देश सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में था। परन्तु इस देश में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का राज्य स्थापित होने के पश्चात् देश की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। आधुनिक भारत उसी की देन है।

सामाजिक अवस्था—१९वीं शताब्दी के आरम्भ में भारतवर्ष की सामाजिक व्यवस्था में तीन मुख्य बातें पाई जाती थी—

- (१) आत्म निर्भर गांव (Self Sufficient Villages)
- (२) जाति प्रथा (Caste System)
- (३) सामूहिक परिवार प्रथा (Joint Family System)

गांव के लोग सादा जीवन व्यतीत करते थे। उनकी आवश्यकतायें बहुत कम थीं। गांव में किसानों के सिवाय बडई, कुम्हार, धोबी, लुहार, मुनार, आदि भी रहते थे। इन सब लोगों में आपस के बहुत कुछ अच्छे सम्बन्ध थे। वे एक दूसरे का कार्य बिना कुछ लिये दिये करते थे। हाँ, हर वर्ष या छ माह पीछे उन्हें कुछ अन्न तथा और दूसरी वस्तुएँ फसलाने के रूप में मिल जाती थी। उनमें आपस में कोई झगडा नहीं होता था और यदि होता था तो उसका निपटारा गांव में ही कर दिया जाता था। ये लोग प्रायः सामूहिक परिवार में रहते थे जिसमें बाप-दादा से लेकर बेटे पोते तक एक साथ रहते थे। ये सब लोग बहुत से धर्मों के मानने वाले थे उनमें कोई विशेष धार्मिक विरोध नहीं था। इस प्रकार गांव के लोग सुख के साथ अपना जीवन बिताते थे। इनकी आवश्यकतायें कम होती थीं और जितनी थी उनके पूरा करने के लिये गांव में साधन पाये जाते थे इस प्रकार उनका आस-पास के महरो या गांवों से कोई सम्बन्ध न था। इस प्रकार लोगों का जीवन सीधा सादा और शान्त था।

आर्थिक व्यवस्था—उन समय की आर्थिक व्यवस्था आजकल से प्रायः भिन्न ही थी। जैसा ऊपर कहा गया है गाँव प्रायः आम निर्भर थे। हर एक गाँव में धन, पूँजी तथा योग्यता आदि गाँव के लोगों में ही प्राप्त हो जाती थी। गाँव के लोग तीन भागों में बंट हुये थे—

(१) किसान, (२) गाँव के अफसर, (३) गाँव के कारीगर और श्रमिक। किसान लोग या तो किसानकार थे या वे स्वयं भूमि के स्वामी थे। दोनों ही प्रकार के लोग सुली खेती करते थे। किसान लोग अपनी तथा अपने परिवार की सहायता से खेती किया करते थे। कभी-कभी वे मजदूरों को मजदूरी पर भी बुला लेते थे। उनके पास अपनी स्वयं की पूँजी होती थी। यदि कुछ अधिक पूँजी की आवश्यकता होती थी तो वे गाँव के जमींदार या गाँव के मराजिन से कृण के रूप में ले लेते थे। गाँव में जो चीजें उत्पन्न होती थी वे गाँव में ही खच दी जाती थी।

गाँव के अफसरों में गाँव का पटेल (जो रयतवारी गाँवों में पाया जाता था), गाँव का पटवारी या गाँव का चौकीदार होता था। पटवारी खेती सम्बन्धी कार्य करता था और चौकीदार रक्षा का कार्य करता था। गाँव के अन्दर पंचायतें बनी हुई रहती थी। ये पंचायतें गाँव के सब झगड़ों का निपटारा करती थी तथा गाँव की शिक्षा तथा सफाई का प्रबन्ध करती थी। इस कारण गाँव के लोगों को आजकल की तरह बचहरी में नहीं जाना पड़ता था।

गाँव के दस्तकारों में बजई, लुहार, कुम्हार, नाई, मोची, घोड़ी, सुनार, लेनी आदि सम्मिलित थे। बड़े बड़े गाँवों में जुलाहे भी होते थे। वे सब लोग कोई मजदूरी नहीं लेते थे वरन् उनकी साल भर या छ महीने पीछे अपन यजमानों ने पसलाने के रूप में कुछ न कुछ मिल जाना था। इसी से उनका जीवन चंचल था। दस्तकार लोग काम सीखने के लिये कहीं बाहर नहीं जाते थे, वरन् अपने घर में अपने हर माता पिता से काम सीख लेते थे। काम घन्घे छोट-छोटे होने के कारण श्रम विभाजन (Division of Labour) का कोई स्थान न था। जाने जाने के मार्गों की कमी होने के कारण बाहर की प्रतियोगिता (Competition) का कोई भय नहीं था।

गाँव के अतिरिक्त कुछ छोटे-छोटे शहर भी पाये जाते थे। शहर या तो राजाओं की राजधानी होते थे या तीर्थ स्थान होते थे। कुछ व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गये थे। इस प्रकार शहर उद्योग धर्मों के कारण महत्वपूर्ण नहीं थे, पर इन शहरों में बहुत सी चीजों के कारखाने पाए जाते थे जैसे बनारस में ताँबे पीतल के बरतन बनते थे। ये बरतन मग़ा जी के पवित्र जल भरने के लिये बनाये जाते थे। वे शहर जो राजधानी थे उनमें कपड़ा तथा जरी का काम खूब होता था। इनमें लकड़ी तथा पत्थर के ऊपर खुदाई का काम भी होता था। ये सब चीजें हाथ से बनती थी, पर होती थी बहुत सुन्दर। टाँके की मलमल उसका एक उदाहरण है। काश्मीर में बहुत अच्छी प्रकार के शाल दुगाले बनते थे। इन दोनों

चीजों के लिये भारतवर्ष ससार में प्रसिद्ध हो गया था। दस्तकार लोग महाजनो से सामान लेकर उनके लिये सामान बनाने थे और उन्हीं को बेंच देते थे इस प्रकार शहर अपनी दस्तकारी के लिये प्रसिद्ध थे। उस समय में व्यापार कम होने के कारण व्यापारिक नगर बहुत कम थे। व्यापारिक नगर अधिकतर नदियों के तट पर बसे थे क्योंकि उस समय का व्यापार नावों द्वारा होता था।

गाँवों व शहरों के जीवन में काफी भिन्नता थी। शहरों में गाँवों की अपेक्षा अधिक जनसंख्या थी। शहर के लोग बाहर से आए हुये अनाज तथा दूसरी चीजों पर निर्भर रहते थे। वहाँ पर लाग बहुत प्रकार के कारोबार करते थे। दस्तकारियों की व्यवस्था भी गाँवों में कुछ अच्छी थी। बाजार गाँवों की अपेक्षा बड़े होते थे। गाँवों की अपेक्षा यहाँ द्रव्य का अधिक उपयोग किया जाता था। हुडी आदि में भी काम लिया जाता था।

उस समय में आवागमन के साधनों का तो मानो लोप ही था। न तो आजकल के समान रेलगाड़ी, मोटर, हवाई जहाज आदि ही थे और न सड़कें ही थी। सड़कें बच्ची थी जो वर्षा ऋतु में प्रायः बन्द हो जाती थी। आज जाने के साधन केवल रेलगाड़ी, गधे, ऊँट ही थे। ये सब साधन बहुत धीमे तथा उनसे यात्रा करने में जान व माल का भय सदा बना रहता था। आवागमन के साधनों की कमी के कारण देश के एक भाग का देश दूसरे भाग से कोई सम्बन्ध न था। हा कुछ बनजारे तथा अनाज के व्यापारी इधर उधर व्यापार करते थे। इन्हीं के द्वारा एक स्थान की आवश्यकता से अधिक वस्तुएँ दूसरे स्थान पर जाती थी ऐसी अवस्था में यदि व्यापार उन्नत न हो तथा एक स्थान तथा दूसरे स्थान के भावों में पृथ्वी आकाश का अन्तर हो तो कोई आश्चर्य नहीं। १८३३ ई० के भयंकर अकाल में गेहूँ का भाव आगरे में १३½ सेर था। पर उसी समय खान देश में गेहूँ ३१ सेर विक रहा था। अकाल के समय एक और हानि भी होती थी। अकाल के समय एक स्थान को दूसरे स्थान से कोई सहायता नहीं मिल सकती थी।

उस समय द्रव्य का संचालन बहुत कम था। शहरों में द्रव्य से कुछ काम लिया जाता था पर गाँव के प्रायः सभी मोटे वस्तु परिवर्तन से तय होते थे। मजदूरों की मजदूरी भी वस्तुओं के रूप में ही दी जाती थी। आजकल के ममान वेतन व लगान प्रतिपोगिता द्वारा निश्चित नहीं होते थे बल्कि वे रीति-रिवाज तथा मनुष्य के जीवन स्तर द्वारा निश्चित होते थे।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा की हुई बदल—जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारतवर्ष में आई तब देश की यह स्थिति थी। बहुत समय तक तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी देशी अथवा विदेशी धर्मियों से लड़ती रही पर जब अन्त में उसने उन गवर्नेटों के विजय प्राप्त कर ली तब उसने अपने शासन की व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये बहुत से नये-नये परिवर्तन जो इंग्लैण्ड तथा दूसरे देशों में हो रहे थे इस देश में भी किये।

(१) आवागमन के साधनों की उन्नति—सबसे पहली चीज जो बताने योग्य है वह है आवागमन के साधनों की उन्नति करना। इस देश में १८५० ई० के पश्चात् रले आरम्भ हुई। रेलों के बनाने से इस देश के एक स्थान का सम्बन्ध दूसरे स्थान से होने लगा। इससे व्यापार की उन्नति हुई। देश के जो खेत पहले केवल गाँव के लिये ही अन्न उत्पन्न करने लगे थे वे अब दूर-दूर के शहरों तथा देशों के लिये भी उत्पन्न करने लगे। इसके विपरीत दूर-दूर के देशों का पक्का माल यहाँ पर आने लगा। इस पक्के माल के आने से हमारे देश के उद्योग-धन्धे धीरे-धीरे नष्ट होने लगे और वह लोग जो पहले धन्धों में लगे हुये थे वे भी खेती करने की ओर झुकने लगे। इस प्रकार थोड़े ही समय में हमारा देश कच्चे माल का निर्यातकर्ता तथा पक्के माल का आयातकर्ता हो गया। पर रेलों के बनने से इस देश को यह लाभ भी हुआ कि एक स्थान की सभ्यता दूसरे स्थान पर फैलने लगी। अकाल के समय अकाल पीड़ित क्षेत्रों की सहायता करना बहुत ही सरल हो गया।

(२) औद्योगीकरण—ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस देश में बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ खोली जिनसे कि इस देश में लोहे, कपड़े, जूट, दियामलाई आदि के उद्योग धन्धों की उन्नति हुई। यदि अङ्गरेज लोग यहाँ अपनी पूँजी लगाकर कारखाने न खोलते तो शायद हमारे देश में बड़े-बड़े उद्योग-धन्धे उन्नत होने में बहुत समय लग जाता।

(३) सिचाई का प्रबन्ध—खेती की उन्नति के लिये देश में करोड़ों रुपये लगाकर बड़ी-बड़ी नहरें बनाई गईं। यद्यपि ऐसा करने में अङ्गरेजों का अपना स्वार्थ था क्योंकि वे अपनी मिलों से लिये कच्चा माल चाहते थे तो भी हम कह सकते हैं कि इन नहरों से इस देश का भी बहुत लाभ हुआ। नहरें बनने से अकाल का डर कम हो गया। देश में पहले से अधिक अन्न तथा दूसरा सामान उत्पन्न होने लगा।

(४) साख सस्याओं की उन्नति—देश में बैंक तथा बीमा कम्पनियाँ भी खुली। इसके अतिरिक्त ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने १८३३ ई० में सारे देश के लिये एक ही मुद्रा प्रणाली स्थापित की। इससे देश के व्यापार तथा कृषि की बहुत उन्नति हुई।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपने स्वार्थ के हेतु तथा व्यापार व उद्योग-धन्धों की उन्नति करने के लिये इस देश में कुछ सुधार किये पर हमको यह बात माननी पड़ेगी कि इन सुधारों से देश को बहुत लाभ हुआ। यदि ये सुधार न किये जाते तो देश आर्थिक दृष्टि से कभी उन्नति न करता। परन्तु यह बात अवश्य कहनी पड़ेगी कि यदि अङ्गरेज इस देश से प्रेम करके इन सब सुधारों को ठीक ढङ्ग से करने तो देश और भी अधिक उन्नति कर जाता।

Q 13 How did the entry of India in the world markets affect agricultural conditions of the country after 1857. In what manner have these effects been harmful ?

प्रश्न १३—१८५७ ई० के पश्चात् भारतवर्ष के संसार के बाजारों में आने का उसकी कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा ? ये प्रभाव किस प्रकार हानिकारक सिद्ध हुए ?

उत्तर—१८५७ ई० से पहले भारतवर्ष में ऐसे गाँव थे जो आत्म-निर्भर थे और जिनका दूसरे स्थानों से कोई सम्बन्ध नहीं था । भारतीय औद्योगिक क्रांति ने उस समय के गाँवों की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया है, "पुराने समय में प्रत्येक गाँव अपने लिए अन्न ही उत्पन्न नहीं करता था बल्कि वह अपने साधनों द्वारा अथवा समीप के स्थानों से अपनी थोड़ी सी सीधी सादी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता था । गाँव के बड़े तथा उसके लिए अच्छा माल, उसकी शक्कर, उसके रंग, उसके खाने तथा जलाने का तेल, उसके घरेलू वर्तन और उसके खेती करने के औजार सभी या तो स्वयं कृषक बनाता था या गाँव के दस्तकार जो गाँव में समाज के घटक होते थे और जिनको पैदावार का एक भाग मिलता था उन औजारों को बनाते थे । उस समय किसान लोग या तो काश्तकार होते थे या वे स्वयं भूमि के स्वामी होते थे । दोनों ही प्रकार के कृषक खुली खेती करते थे । किसान लोग अपनी तथा अपने परिवार की सहायता से खेती करते थे । कभी-कभी वे आवश्यकता पड़ने पर कुछ श्रमिकों को भी नौकर रख लेते थे । उनके पास अपनी स्वयं की पूँजी होती थी । यदि कुछ अधिक पूँजी की आवश्यकता होती थी तो वे गाँव के महाजन अथवा जमींदार से ऋण ले लेते थे । अन्न केवल गाँव की आवश्यकता के लिए ही उत्पन्न किया जाता था वह बाहर नहीं भेजा जाता था । इस प्रकार उस समय खेती सीधे साधक से की जाती थी ।"

पर १८५७ ई० के पश्चात् इस देश में रेलों बननी आरम्भ हो गई । इसके अतिरिक्त १८६८ में स्वेज नहर के मार्ग का पता लग गया । इन दोनों कारणों से भारतवर्ष में यूरोप के देशों का सस्ता माल आने लगा, रेलों के द्वारा उस सामान के भीतरी भागों में बँटने में बहुत आसानी हो गई । इन सबका फल यह हुआ कि धीरे-धीरे यहाँ की हाथ से बनाई जाने वाली चीजों की उत्पत्ति प्रायः बन्द हो गई और जो लोग इन चीजों को बनाते थे वे भी खेती की ओर ही झुकने लगे । इसलिए भूमि, पर, गड़हे, गाली, जलकलप, पिछो, फिटल, चूड़े, लपेटे, 'एन' से, इस कारण से तथा दूसरे उत्तराधिकार के नियमों के कारण से इस देश की भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हो गए और खेती करना एक घाटे का पेशा हो गया । इसका एक दूसरा भी परिणाम हुआ । भारतवर्ष में बाहर से सस्ता मशीन का बना हुआ माल आने के कारण यहाँ पर उद्योग-धन्धों की उत्पत्ति न हो सकी और देश कच्चे माल का बाहर भेजने वाला तथा पक्के माल का मँगाने वाला बन गया । इस प्रकार हमारा देश कृषि प्रधान देश बन गया ।

ससार के बाजारों में घुसने के कारण गांव के वे लोग जो केवल गांव के लिए ही फसलें उगाते थे सारे ससार के लिए उगाने लगे। इसके अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के परिणाम निकले। इसका अच्छा परिणाम तो यह था कि इसके कारण हमारे देश के किसान अधिक धन कमाने की चिन्ता में अधिक अन्न व दूसरी चीजें गांव की आवश्यकता से भी अधिक उगाने लगे। दूसरे वे अन्न उगाने की अपेक्षा कपास, जूट, गन्ना आदि फसलें उगाने लगे जिससे कि वे अधिक धन कमा सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में घुसने का साधारणतया अच्छा ही प्रभाव होना चाहिए था। पर भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ यूरोप के देशों से विपरीत परिस्थिति थी। जब यूरोप के देशों ने व्यापार में उन्नति की तो उन्होंने छोटे-छोटे खेतों को बड़े-बड़े खेतों में बदल दिया और उन खेतों पर आधुनिक ढङ्ग की मशीनों से खेती की जिसके कारण उन देशों को किसी प्रकार की हानि न हुई। उल्टे इनको बड़े पैमाने की खेती (Large scale farming) करने का अवसर मिल गया। पर हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। हमारा देश जब ससार के बाजारों में घुसा तो यहाँ से छोटे-छोटे उद्योग धंधे प्रायः नष्ट हो गए और जो लोग इनमें लगे हुए थे वे खेती पर निर्भर रहने लगे। इसी प्रकार यहाँ पर बड़े-बड़े खेतों की अपेक्षा छोटे-छोटे खेत हो गए। इन खेतों पर यूरोप के देशों के समान आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया बरन् पुराने यन्त्रों से ही खेती होती रही। यही कारण है कि ससार के दूसरे देशों के समान हमारे देश में उत्पादन व्यय (Cost of production) घटने की अपेक्षा उल्टा बढ़ गया। किसानों को इससे बहुत हानि हुई। पर दूसरा कोई धन्धा न होने के कारण वे खेती ही करने रहे और हानि उठाते रहे। पर कब तक हानि उठाते। धीरे-धीरे उनकी ऋण लेना पड़ा। इससे उनकी भूमि भी उनके हाथ से जाने लगी। यह भूमि उन लोगों के हाथ में चली गई जो स्वयं खेती नहीं करते थे। इस कारण उन लोगों को खेती की उन्नति करने की कोई परवाह न थी, वे केवल लगान वसूल करने की ही चिन्ता रखते थे। इस प्रकार हमारे देश में बहुत सारे मध्य-जन (Middle men) हो गए जो कि तटस्थ जमींदार (Absentee landlord) थे। इन जमींदारों ने कभी भी खेती की उन्नति नहीं की पर वे तरह-तरह से किसानों का शोषण करते रहे। वे उनसे खूब लगान लेते थे। समय-समय पर नजराना व भेंट भी लेते थे और आवश्यकता पड़ने पर उनसे बेगार भी लेते थे। इस प्रकार हमारे देश के किसान, मध्य-जी, निर्धन रहे और उनको सामाजिक न्याय, आर्थिक दृष्टि से कभी भी ऊपर उठने का अवसर प्राप्त न हुआ। इस प्रकार कह सकते हैं कि भारतवर्ष के ससार के बाजार में घुसने का परिणाम अच्छे की अपेक्षा बुरा हुआ।

उत्पादन क्रमशः ५६० पौंड तथा ३१२ पौंड है। इसी प्रकार हमारी गन्ने की उपज क्यूबा का एक तिहाई, जावा का छठा तथा हवाई द्वीपों का सातवाँ भाग है। इसी कारण कांग्रेस के ६२ वें अधिवेशन की *Steering* समिति ने कहा है कि भारत में गन्ने का उत्पादन संसार में प्रायः सबसे कम है।

खेती की पिछड़ी दश के कारण—खेती की पिछड़ी हुई दशा के निम्नलिखित कारण हैं—

(१) वर्षा की कमी—वृषि वर्षा के ऊपर निर्भर है। यदि वर्षा हो जाए तो खूब अन्न व दूसरी फसलें उत्पन्न हो जाती हैं पर यदि वर्षा न हो तो सब जगह हाहाकार मच जाता है। भारतवर्ष के कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर वर्षा की कमी कभी प्रतीत नहीं होती जैसे बङ्गाल व बिहार, पर कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ पर वर्षा का होना निश्चित नहीं है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आदि। यही कारण है कि इन भागों में समय-समय पर अकाल पड़ा करते हैं।

(२) खेती करने का पुराना ढङ्ग—इस मशीन एवं वैज्ञानिक युग में भारतवर्ष में आज भी लकड़ी के हल तथा बेली से खेती की जाती है। यह हल केवल भूमि खुरच ही सकता है उसको खोद नहीं सकता। इस कारण पौधों की जड़ें भूमि से पूरी तरह खूराक नहीं खींच सकती और पौधे बहुत ही दुर्बल रह जाते हैं।

(३) खाद की कमी—इस देश में खेतों में ठीक प्रकार से खाद भी नहीं डाली जाती। यहाँ पर अधिकतर गोबर की खाद काम में आती है। यद्यपि इस देश के लिये यह बहुत ही उपयुक्त है तो भी यह ठीक प्रकार से न बनाए जाने के कारण खेती को अधिक लाभ नहीं पहुँचा सकती। बहुत सी खाद उपलो के रूप में जला दी जाती है गोबर के जलाने का अनुमान २५० मिलियन टन से लेकर ५५० मिलियन टन तक किया गया है। इसके अतिरिक्त हड्डी तथा मछली आदि की खाद यहाँ पर काम में नहीं लाई जाती।

(४) उत्तम बीज का न होना—इस देश के किसान बीज की ओर भी कोई विशेष ध्यान नहीं देते। वे अच्छा बुरा सभी प्रकार का बीज बो देते हैं। यह बीज किसान लोग अधिकतर गाव के बनिये से मोल लेते हैं। बीज अच्छा न होने के कारण फसल भी अच्छी नहीं होती।

(५) दुर्बल पशु—इस देश की कृषि का मुख्य सहारा बैल है। पर बैल चारे की कमी के कारण बहुत ही दुबल होता है। यह बहुत सी बीमारियों का शिकार रहता है। इस कारण वह नए-नए यन्त्रों को जो कि भारी होते हैं चलाने में असमर्थ है।

(६) तटस्थ जमींदारी—इस देश की ७० प्रतिशत जोती हुई भूमि पर जमींदारी प्रथा पाई जाती है। बाकी भाग जहाँ पर रैयतवारी या और दूसरी प्रथाएँ पाई जाती हैं वहाँ पर किसान की वही स्थिति है जैसी जमींदारी प्रदेशों में है। इस देश के जमींदार लगान वसूल करने की धुन में रहते हैं, वे खेती की ओर बिल्कुल

ध्यान नहीं देते। वे किसानों से खूब लगान वसूल करने हैं, उनसे नजराना व बेगार का काम लेने हैं तथा उनको कई प्रकार से कष्ट पहुँचाने हैं। मुबारो से पहले तो वे जब उनको चाहते थे भूमि से निकाल बाहर कर देते थे। इन सबके कारण किसानों को भूमि में कोई विशेष रुचि नहीं रहती। वह भूमि से बिना कुछ लगाये उससे अधिक से अधिक प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इसी कारण धीरे-धीरे भूमि की उपजाऊ शक्ति प्रायः नष्ट होगी चली गई।

(७) **बिक्री के दोष**—इस देश के किसान अपनी फसल को बेचकर उनका दाम प्राप्त नहीं कर सकते जितना कि उनको करना चाहिए। गेहूँ की बिक्री की रिपोर्ट में बताया गया है कि किसान को उस धन का जो कि उपभोक्ता देता है केवल ६० प्रतिशत मिलता है। इसी प्रकार चावल, कपास आदि को बेचकर भी उसको बहुत ही कम धन मिलता है। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर जाने-जाने के मार्ग खराब हैं, नियन्त्रित बाजार नहीं है बाट भी ठीक नहीं है। मण्डी का आड़ती किसान की ढरी में से बहुत सामान कई प्रकार के बहानों से निकाल लेता है। यहाँ पर फसल के रखने के लिए गोदाम भी नहीं है। इसलिए बहुत सी फसल को चूहे तथा दूसरे प्रकार के जीव जन्तु खा जाते हैं। इन सब बातों के होने हुए कोई अचम्भा नहीं है कि किसान को अपनी फसल को बेचकर बहुत कम धन प्राप्त होता है। यह तो रही मण्डी में बेचने की बात परन्तु यदि किसान गाँव के बगिये की अपनी फसल बेचता है, और वह अधिकतर ऐसा ही करता है, तो उसको बहुत ही कम धन प्राप्त होता है। बिक्री के दोषों के कारण किसान की आर्थिक स्थिति सुधरन नहीं पाती।

(८) **गाँव का महाजन**—गाँव का महाजन भी खेती की उन्नति में बहुत बाधक है। वह किसान को ऊँची दर पर ऋण देता है और उसके बदले किसान से सस्ते मूल्य पर फसल खरीद लेता है। फसल का एक बड़ा भाग तो ध्याज तथा मूलधन के चुकाने में ही चला जाता है, जो शेष बचता है वह किसान की वर्ष भर की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं होता। इस कारण उनको महाजन से दूसरे वर्ष भी ऋण लेना पड़ता है। दूसरे वर्ष फिर वही होता है। इस प्रकार किसान के तिर से कभी भी ऋण का भार नहीं उतरता। ऋण की अवधि समाप्त होने पर किसान की भूमि महाजन के हाथ में चली जाती है। इस प्रकार हमारे देश की भूमि महाजन के हाथ में चली जाती गई। ऋणग्रस्त होने के कारण किसान के पास खेती की उन्नति करने के लिये धन नहीं रहता।

(९) **लगान नीति**—श्री० आर० सी० दत्त जैसे लोगों का कहना है कि हमारे देश में लगान निरन्तर बढ़ता जा रहा है तथा वह बड़ी बड़ाई के वसूल किया जाता है जिसके कारण किसान को गाँव के महाजन से ऋण लेना पड़ता है तथा उसको अपनी फसल उस समय बेचना पड़ती है जबकि वस्तुओं का मूल्य बहुत नीचा

होता है। इसके कारण किसान मृणप्रस्त रहता है और वह खेती में उन्नति नहीं कर सकता।

(१०) कीड़ों द्वारा हानि—ऐसा अनुमान किया जाता कि कीड़ों के कारण हमारे देश की १० से २० प्रतिशत तक फसल खराब हो जाती है। परन्तु अभी तक ३५० मिलियन एकड़ में से ३ मिलियन एकड़ को ही कीड़ों से बचाने का प्रयत्न किया गया है।

इन दोषों को सुधारने का ढंग

(१) सिंचाई को प्रबन्ध करना—वर्षा की कमी को सिंचाई से पूरा किया जा सकता है। परन्तु अभी तक भारतवर्ष में कुल जोते गये क्षेत्र के केवल १८ प्रतिशत पर सिंचाई का प्रबन्ध है। इस देश में सरकार ने बहुत सी नहरें, कुएँ तथा तालाब बनाकर सिंचाई का प्रबन्ध किया है पर अब भी देश के बहुत से भाग ऐसे हैं जहाँ सिंचाई की बड़ी कमी है। ऐसे स्थानों पर सिंचाई का प्रबन्ध भी करना चाहिये। सरकार बहु-उद्देश्य योजनाएँ बनाकर इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न कर रही है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की सरकार ट्यूबवैल भी लगवा रही है। इस प्रकार प्रथम योजना काल में १६३ मिलियन एकड़ पर सिंचाई का प्रबन्ध किया गया। इसमें से १० मिलियन एकड़ पर छोटी सिंचाई की योजनाओं में सिंचाई हुई और शेष बड़ी योजनाओं से। प्रथम योजना काल में ५००० ट्यूबवैल भी लगाये गये। आशा है कि इन सब योजनाओं के पूरा होने पर देश में खेती के लिये पानी की इतनी कमी नहीं रहेगी।

(२) नये यन्त्रों से खेती करना—कृषि की उन्नति तभी हो सकती है जबकि नये-नये यन्त्रों से खेती की जाय। जहाँ पर इन यन्त्रों का प्रयोग किया गया है वहाँ बहुत अच्छा परिणाम निकला है। परन्तु एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिये कि नये रज्ज के यन्त्रों को हम तभी काम में ला सकते हैं जबकि हम बैलों की स्थिति को सुधारे। बिना ऐसा किये दुर्बल बैल इन यन्त्रों को न खींच सकेंगे और इन यन्त्रों पर खर्च किया हुआ धन बेकार हो जायेगा। १९२८ के कृषि कमीशन के मतानुसार आजकल हमको नये यन्त्रों का प्रयोग करने की अपेक्षा पुराने यन्त्रों को सुधारना चाहिये। हमारे देश में आजकल ट्रैक्टरों का प्रचार बढ़ता जा रहा है और देश में लगभग २०,००० ट्रैक्टर काम में लाये जा रहे हैं।

भारत में कृषि के आधुनिकरण का समर्थन करते हुए श्री पारितोषरे ने स्टेट्समैन के खाद्य तथा कृषि सप्लिमेन्ट में कहा है कि इङ्ग्लैंड अमेरिका आदि देशों के तर्जों के आधार पर कहा जा सकता है कि कृषि का यन्त्रीकरण करने से न केवल लागत खर्च घटता है वरन् उपज में भी काफी वृद्धि होती है। उन्होंने बताया है कि भारत में आधुनिक मशीनों के आर्थिक मूल्य को अधिकाधिक महसूस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत से आदमी यह कहते हैं कि मशीनों से खेती करने से पशुओं को खेती से हटाना पड़ेगा परन्तु ऐसा सोचना उचित नहीं

है क्योंकि आजकल पशु इतना गलना खा जाते हैं जो १० करोड़ लोगों को पर्याप्त होता। कुछ लोगों का कहना है कि भारत में पहले ही सस्ता श्रम पर्याप्त मात्रा में है जिसके कारण मशीनों में खेती करना लाभप्रद न होगा। इसके अतिरिक्त मशीनों के मगाने से बेरोजगारी और भी बढ़ जायगी। परन्तु उन्होंने बताया है कि इस बात का भी कोई भय नहीं है क्योंकि श्रम को पशु पालन, दुग्ध उद्योग, खाद के बनाने व वितरण करने, बतारों के बीच की खेती, डील के बनाने स्थानीय सिंचाई की उन्नति, खेतों की सड़कों के बनाने तथा उनको ठीक रखने आदि कार्यों में लगाया जा सकता है। आगे उन्होंने कहा है कि बहुत से आदमी कभी-कभी यह कहते हैं कि मशीनों का लगाना छोटे-छोटे खेतों पर लाभप्रद नहीं है। परन्तु उन्होंने कहा है कि उत्तरी आयरलैंड के तजर्बों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि छोटे खेतों पर भी मशीनें लगाई जा सकती हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि पिछले दस वर्षों में अक्सटर ट्रक्टर १५५% बढ़ गये हैं और उनमें से ८०% ५० एकड़ तथा उनसे नीचे के खेतों पर लगाये गये हैं। इनके लगाने से उत्पत्ति, न केवल मूल्य में बढ़ी है वरन् मात्रा में भी बढ़ी है। अन्त में उन्होंने कहा है कि हर प्रकार की बाधा होने लगे भी भारत के किसान यह महसूस करते जा रहे हैं कि उपज को बढ़ाने के लिये खेतों पर मशीनों का लगाना बहुत आवश्यक है। भारत में कृषि आत्म-निर्भरता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि खेतों पर मशीनें लगाई जायें।

(३) खाद का प्रबन्ध करना—यह आवश्यक है कि खाद को न जलाया जाय। परन्तु यह काम तभी हो सकता है जबकि वन विभाग गावों को सस्ती लकड़ी दे। यह भी आवश्यक है कि खाद उत्तम रीति से तैयार की जाय। खाद को गोबर मूत्र तथा कूड़ा करकट मिलाकर बनाना चाहिये। ऐसी खाद से चीन तथा जापान आदि देशों को बहुत लाभ पहुंचा है। इसके सिवाय किसानों को हड्डी, खली तथा हरी खाद भी काम में लानी चाहिये। खाद के बिना अधिक अन्न की उपज नहीं हो सकती। भारत में खाद का महत्व अब धूम्र अनुभव किया जा रहा है। इस कारण यहां सब प्रकार की खाद बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसमें रासायनिक खाद, कम्पोस्ट गोबर की खाद आदि पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

(४) अच्छे बीजों का प्रबन्ध करना—अच्छा बीज अच्छी सफल के लिये बहुत आवश्यक है। इससे करीब १०-१५ प्रतिशत अधिक अन्न उपजता है। अच्छे बीज का प्रबन्ध या तो कृषि विभागों को करना चाहिये या सरकारी समितियों द्वारा इसका प्रबन्ध कराना चाहिये। प्रबन्ध इस प्रकार का होना चाहिये कि प्रायः सभी किसानों को उत्तम बीज मिल जायें।

भारत में हाल ही तक बीजों के बढ़ाने व वितरण का कोई उचित प्रबन्ध न था। इस कारण द्वितीय योजना काल के लिये प्रत्येक सामूहिक योजना ढ्वाक के लिये एक बीज-गृह की स्थापना की सिफारिश की गई है।

इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये एक माडल स्कीम तैयार की गई है। इसके अन्तर्गत ४३२८ बीज-खेत स्थापित किये जायेंगे। प्रत्येक बीज-खेती २७ एकड़ की आवश्यकता पूरी करेगा। ऐसा अनुमान है कि दूसरी योजना के चौथे वर्ष में २१५ मिलियन एकड़ भूमि को शुद्ध बीज मिल सकेगा। इसके अतिरिक्त विकास ब्लाकों में पांच बीज गोदाम स्थापित किये जायेंगे जिनकी शक्ति २५०० मन होगी। बीज-खेतों तथा गोदामों पर खर्च का अनुमान १३०६८० लाख रुपये है जिसमें से ११५०५० लाख रु० केन्द्र खर्च करेगा तथा १५६३० लाख राज्य। राज्यों को दिये गये धन का ५२ प्रतिशत सहायक अनुदान के रूप में होगा तथा शेष ४८ प्रतिशत ऋण के रूप में। ऋण की आदायगी १५ वर्ष तक की जा सकेगी। १६५६-५७ तथा १६५७-५८ के लिये राज्य को सहायता निम्नलिखित ढङ्ग से दी गई—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	ऋण	सहायक अनुदान	कुल
१६५६-५७	६३७०	८२६२	१४६६२
१६५७-५८	२३४८४	१६५६३	४३०४७

१६५६-५७ के १४६६२ लाख रुपये में से १०५६० लाख रुपये की मजूरी दी जा चुकी है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में उन्नत बीजों की ओर खूब ध्यान दिया जा रहा है।

(५) पशुओं की उन्नति करना—देश के पशु तभी उन्नत हो सकते हैं जबकि उनको पर्याप्त मात्रा में चारा मिले तथा अच्छे बल उत्पन्न करने के लिये अच्छे साडों का प्रबंध हो। बैलों की बीमारी की चिकित्सा करने के लिये पशुओं के हस्पताल खोले जायें। बिना पशुओं के उन्नत किये हम उत्तम और नये ढङ्ग के यन्त्रों का प्रयोग भी नहीं कर सकते।

(६) जमींदारी प्रथा को समाप्त करना—बिना जमींदारी प्रथा को समाप्त किये देश के किसान कुछ भी उन्नति नहीं कर सकते। यह हर्ष का विषय है कि हमारे देश में प्रायः सभी राज्यों में यह प्रथा तोड़ी जा रही है। ऐसा होने पर आशा है कि देश के किसान भूमि के स्वामी होने के पश्चात् किसान भूमि में खूब परिश्रम करके अधिक से अधिक अन्न उपजाने का प्रयत्न करेगा और भूमि की उपज कम न होने देने का प्रयत्न करेगा।

(७) बहु-उद्देश्य सहाकारी समितियों को स्थापित करना—यदि देश में बहु-उद्देश्य समितियाँ स्थापित हो जायें तो उन किसानों को बहुत से लाभ होंगे। किसान महाजन के फदे में से निकल सकेगा और समितियों द्वारा उपज को बेचने के कारण किसान को उतना ही धन मिलेगा जितना कि उसको मिलना चाहिये

इसके अतिरिक्त इन समितियों से किसान की खाद, बीज, पन्तु, यन्त्र आदि मिलने का भी प्रबन्ध किया जा सकता है। देश के बड़े बड़े लोगों का मन है कि इन महकारी समितियों से बहुमुखी उत्पत्ति हो सकती है।

(८) खेती सम्बन्धी अनुसन्धान—इस समय सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से खेती का अनुसन्धान भी एक है। इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि देश के भौतिक, रासायनिक, जल तथा पन्तु साधनों पर खोज की जाय तथा यह देखा जाय कि उनको लघु तथा दीर्घकाल में कैसे काम में लाया जाय ऐसा करन से वैज्ञानिकों का सीधा सम्बन्ध खेती तथा उद्योगों से स्थापित हो जायगा जिनसे बहुत लाभ होगा।

इनके अतिरिक्त भी बहुत से और ढङ्ग बताय गए हैं जिनसे खेती की उपज बढ़ सकती है जैसे सामूहिक विकास योजना पर हुई राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मध्य सेशन में बताया कि सींचे जाने वाले क्षेत्रों में चक्रबन्दी करने तथा प्रत्येक गाँव में एक पचायत अथवा एक बहु-उद्देश्य समिति जो कि यह देखे कि प्रत्येक परिवार की उपज बढ़ाने की एक पूर्ण योजना है, स्थापित की जाय। परन्तु ५० नेहरू के विचार से सामूहिक विकास योजना को ठीक प्रकार नियन्त्रण में लाने तथा सींचे जाने वाले क्षेत्रों में गहन ढङ्ग (Intensive) खेती करन से उत्पादन बहुत बढ़ सकता है। कार्यक्रम के ६३ वें अजिवेशन की स्टीमरिंग समिति का विचार है कि मिट्टी को सुरक्षित रखने व गहन खेती करने से उपज को तीन-चार गुना बढ़ाया जा सकता है। इस हेतु उसने १२ बिन्दुओं का एक प्रोग्राम दिया है। हममें निम्नलिखित चीजें सम्मिलित हैं—

(१) बम्बे तथा नानियाँ बनाकर प्राण पानी के साधनों का पूर्ण उपयोग करना, (२) द्यूबवेल के पानी की दर प्रारम्भ में इतनी नीची रखी जाय जो कि किसान की शक्ति के अन्दर हो। पीछे इन दर को मापारण दर तक बढ़ाया जा सकता है, (३) पुराने तालाब व कुओं की मरम्मत करना, (४) लघु सिंचाई योजनाओं को तैयार करना, (५) मिट्टी को कटने से रोकना, बाँध बनाना तथा पड़ लगाना, (६) प्रत्येक सामूहिक विकास क्षेत्र में अच्छा बीज उत्पन्न करने के लिये एक क्षेत्र सुरक्षित रखना, (७) हरी खाद के उत्पादन तथा प्रयोग को प्रोत्साहन देना, रासायनिक खाद के अतिरिक्त कम्पोस्ट का प्रयोग करना, (८) प्रत्येक किसान तक पहुँच करके उसके उत्पादन का एक बिन्दु निश्चित करना, (९) स्वनापन्न करने को उन्नत करने के लिये नियन्त्रित प्रयत्न करना तथा तन्तुलित भोजन को प्रोत्साहन देना, (१०) कम अवधि वाली पसलों का उत्पादन ढंग से तथा एकदम हाथ में लेना, (११) उत्तर तथा खार लगी हुई भूमि को खेती के काम में लाना, (१२) गडों में पानी एकत्र होने के विरुद्ध कुछ कदम उठाना।

भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से प्रकाशित हुई एक पुस्तक 'सिंचाई, उन्नत बीज तथा भूमि प्राप्त करना' में बताया गया है कि उत्पादन को सिंचाई

उन्नत बीजों तथा बेकार भूमि को खेती को योग्य बनाने से उपज को खूब बढ़ाया जा सकता है।

यह अति आवश्यक है कि इन सब सुधारों को शीघ्रतापूर्वक किया जाये नहीं तो हमारे देश की आर्थिक उन्नति होने की बहुत कम सम्भावना है क्योंकि खेती के ऊपर ही हमारे देश के और दूसरे उद्योग-धन्धे आधारित हैं।

Q 15 *Samp* 'Farming to a cultivator is a mode of life rather than a business' Comment upon this statement.

प्रश्न १५— 'किसान के लिये खेती करना व्यापार की अपेक्षा जीवन का एक ढंग है।' इस कथन की प्रालोचना कीजिये।

उत्तर—मनुष्य व्यापार सदा लाभ के लिये करता है। जब तक उसको लाभ होता है वह व्यापार करता है परन्तु घाटा होने पर वह उसको छोड़ देता है, यदि उसको इस बात की पूर्ण आशा होती है कि वह भविष्य में व्यापार से लाभ न कमा सकेगा। यह बात सभी व्यवसायों के लिये सत्य है, चाहे वह खेती हो अथवा व्यापार या कोई उद्योग धन्धा।

ससार के अन्य देशों में कृषकों के लिये कृषि एक व्यवसाय है अर्थात् ये खेती इसलिये करते हैं कि उनको खेती करने से लाभ प्राप्त होता है अथवा लाभ प्राप्त करने की आशा होती है परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे देश में यह दशा नहीं है। यहाँ किसान खेती इसलिये नहीं करता कि वह उसके लिये लाभप्रद है बल्कि वह खेती इसलिये करता है कि उसके पास खेती के अनिश्चित और कोई कार्य करने को नहीं है। ऐसी परिस्थिति में किसान खेती करता रहता है फिर चाहे उसको लाभ हो अथवा हानि।

यदि हम भारतीय कृषि की ओर दृष्टि उठाकर देखें तो हमको पता चलेगा कि वह एक घाटे का सौदा है। किसान के खेत छोटे-छोटे तथा बिखरे हुये हैं। उसके बल दुर्बल तथा खेती के लिये अयोग्य है, उसके हल तथा कृषि सम्बन्धी दूसरे औजार पुराने हैं। उसको न ठीक प्रकार का बीज ही मिलता है और न ठीक प्रकार की खाद ही। खेती मानसून पर निर्भर होती है। यदि मानसून आता है तो खेती अच्छी हो जाती है और यदि वह फेल हो जाता है तो खेती एक दम चौपट हो जाती है। मानसून के अतिरिक्त कई प्रकार के कीड़े-मकौड़े जैसे टिड्डी, चूहे आदि भी फसल को खराब करते रहते हैं। कभी-कभी ओले तथा अधिक वर्षा के कारण भी फसल खराब हो जाती है। यही नहीं आवश्यकता पड़ने पर किसान को उचित व्याज की दर पर ऋण भी नहीं मिलता। किसान ऋण माँग के महाजन से प्राप्त करता है जो उससे बड़ी ऊँची व्याज की दर लेता है। इसके अतिरिक्त महाजन

उस ऋण के दबाव में किसान की फसल सस्ते भागदान बढ़ाने का प्रयत्न किया गया और मूलधन मिलकर इतना अधिक हो जाता है अन्तर बढ़ती जा रही है। कर सकता और उसको अपनी भूमि से हाथ धोकर बैठना ये स्तर पर पहुँच गई हमारे देश की बहुत सी भूमि उन लोगों के हाथ में चली गई २-५१ में पैदावार करते। हमारे देश के लगभग ७० प्रतिशत क्षेत्र पर जमींदारी प्रथा ५ लाख टन हो अब उसका अन्त हो रहा है। जिसके फलस्वरूप किसान की भूमि भी आती होती। वह भूमि को जमींदार से लगान पर लेता है। जो लगान किसान जमींदार देता है वह अत्यधिक लगान होता है। जमींदार अधिक लगान से ही सतुष्ट नह, हो जाता, वह किसान से समय-समय पर नजराना तथा बेगार भी लेता रहता है। यदि वह नहीं देता तो उससे भूमि छुड़ा लेता है। यही नहीं, किसान से लगान इतनी बड़ाई से वसूल किया जाता है कि बहुधा वह अपनी फसल को उचित मूल्य, उचित स्थान तथा उचित समय पर बेच भी नहीं पाता। उसको यह फसल गाँव के महाजन से सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है। जो लोग फसल को मण्डियों में भी बेचते हैं उनको भी अपने माल का ६० प्रतिशत से अधिक मूल्य नहीं मिल पाता। इन सब कठिनाइयों के होते हुए यदि खेती एक लाभप्रद व्यवसाय न हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि जब खेती एक लाभप्रद व्यवसाय नहीं है तो फिर किसान उसको करता क्यों है। इसका उत्तर बिल्कुल सीधा है और वह यह है कि उसके पास दूसरा कोई काम करने को नहीं है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से पूर्व हमारे देश के कुछ लोग खेती पर लगे हुये थे और कुछ कुटीर उद्योग धन्धों में। परन्तु औद्योगिक क्रांति के पश्चात् जब इंग्लैंड के कारखानों का सस्ता माल भारत में आने लगा तब हमारे कुटीर उद्योग धीरे-धीरे नष्ट होने लगे। कुटीर उद्योगों के नष्ट होने पर दस्तकार लोगों को यदि कारखानों में अपना और कहीं काम मिल जाता तो कोई हर्ज की बात न थी परन्तु ऐसा नहीं हुआ। दस्तकार बिना कुछ काम के रह गया और कोई काम न देखकर दस्तकारों ने खेती करनी आरम्भ कर दी। उसके पश्चात् जनसंख्या निरन्तर बढ़ती रही परन्तु व्यवसाय के साधन न बढ़े क्योंकि अङ्गरेज सरकार की यही नीति थी कि वह भारतवर्ष को एक कृषि प्रधान देश बनाये। व्यवसाय के साधन न बढ़ने के कारण अधिकाधिक लोग खेती की ओर भुक्कने लगे और आजकल यह स्थिति है कि हमारे देश के लगभग ७० प्रतिशत लोग खेती पर लगे हुये हैं। इनमें से अधिकतर लोग खेती पर इसलिये नहीं लगे हुये हैं कि वे खेती करना चाहते हैं वरन् इसलिये लगे हुये हैं कि उनके पास दूसरा कोई काम करने को नहीं है। इसलिये किसान निरन्तर खेती करते रहते हैं यद्यपि उनको खेती करना लाभप्रद नहीं है और उनके ऊपर ऋण भार निरन्तर बढ़ रहा है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व इस ऋण का अनुमान १८०० करोड़ रुपये के लगभग था। ऐसी परिस्थिति में यदि हम कृषि को एक व्यवसाय कहें तो उचित न होगा क्योंकि

व्यवसाय का उद्देश्य तो लाभ कमाना है। इसलिये हम उनको जीवन का एक ढङ्ग कह सकते हैं अर्थात् हम कह सकते हैं कि कृषि किसान के जीवन का अङ्ग है। हमारा किसान तरह-तरह की कठिनाइयाँ उठाता रहता है, तरह-तरह के अपमान सहता रहता है, आये दिन हानि उठाता रहता है तो भी वह खेती करना नहीं छोड़ता। अब तो स्थिति यह है कि यदि उसको कोई दूसरा काम भी मिले तो भी वह वेती की कठिनाई से ही छोड़ता है। इसी कारण हम खेती को व्यवसाय न कह कर किसान के जीवन का ढङ्ग कह सकते हैं।

Q 16 What are the important agricultural crops in India? Give their geographical distribution

प्रश्न १६—भारतवर्ष का मुख्य फसलें क्या हैं? उनका भौगोलिक विवरण दीजिये।

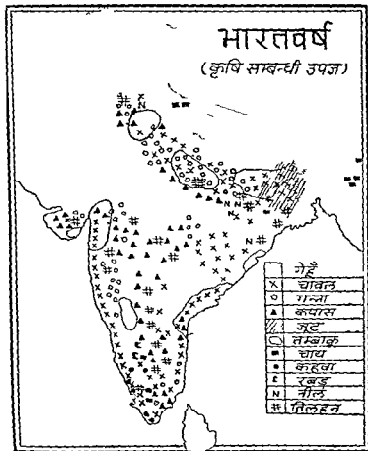
भारत के अधिकतर भाग की भूमि बहुत उपजाऊ तथा नर्म है। जलवायु गर्म है और वर्षा अधिक होती है। इस कारण उपज अच्छी होती है। उत्तरी भारत में तदा सर्दी तथा गर्मी दोनों ऋतुयें नियमानुसार होती हैं तथा दो फसलें उत्पन्न होती हैं। शीतकाल में गेहूँ, जौ, सरसो, तम्बाकू और पोस्त की फसल होती हैं। इनकी बोने के लिये थोड़े जल की आवश्यकता होती है। ग्रीष्म काल में चावल, गन्ना, नील तथा मक्का की खेती होती है। दक्षिणी भारत में जहाँ शीतकाल नहीं होता यहाँ समशीतोष्ण कटिबंध के अनाज नहीं बोये जाते। कृषि विभाग के निरीक्षण में भारत की कृषि में बहुत उन्नति हुई है। आजकल इस ओर ध्यान दिया जा रहा है कि उत्तम बीज प्राप्त हो सके और उत्तम यन्त्र काम में लाये जायें और कृषि के वैज्ञानिक साधनों से लाभ उठाया जाये और नई-नई फसलें बोई जायें।

खाद्य पदार्थ

चावल—यह भारतवर्ष की सबसे प्रसिद्ध उपज है। इसे बहुत गर्मी तथा जल की आवश्यकता है। क्योंकि चावल का पौधा कई दिन तक जल में डूबा रहना चाहिये इसलिये यह उन खेतों में उगता है जहाँ जल ठहर सके। यह बंगाल, बिहार, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदी के डेल्टाओं में, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में तथा पंजाब में जहाँ सिंचाई हो सकती है उगाया जाता है।

भारतवर्ष में जितने क्षेत्रफल पर खेती होती है उसके एक चौथाई भाग पर चावल की खेती होती है। परन्तु वहाँ पर दूसरे देशों की अपेक्षा प्रति एकड़ पर बहुत कम चावल उत्पन्न होता है। जैसे यदि भारत की धान की प्रति एकड़ उपज ८३२ पौण्ड थी तो वह मिश्र की २०३० पौण्ड, जापान की २४७४ पौण्ड, इटली की २६४० पौण्ड तथा स्पेन की २५०० पौण्ड थी। इस कारण प्रतिवर्ष बहुत सा चावल बाहर से मगाना पड़ता है। जब कभी चावल के बाहर के आने में कठिनाई होती है तो देश को एक बड़े भारी सकट का सामना करना पड़ता है।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत चावल का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप चावल की पैदावार निरन्तर बढ़ती जा रही है। १९५२-५३ में चावल की पैदावार २२५.३७ लाख टन के न्यून स्तर पर पहुँच गई और १९५३-५४ में पैदावार २७७.६९ लाख टन हो गई। १९५४-५५ में पैदावार घटकर २४८.०१ लाख टन हो गई। १९५६-५७ की उपज २८०-२९२ लाख टन है।



गई। परन्तु १९५७-५८ में पैदावार घटकर २३८.२१ लाख टन रह गई। यह बावल ७ करोड़ ६० लाख एकड़ पर बोना गया था। १९५३-५४ में कई राज्यों में बावल उगाए जापानी ढङ्ग अपनाया जिसके द्वारा प्रति एकड़ अनिदिक पैदावार १९५३-५४ में १३.३५ मन १९५४-५५ में १५.८० मन १९५५-५६ में १७.३४ मन हुई। परन्तु यह केवल ४ लाख एकड़ भूमि में बावल उगाते समय अपनाया गया है। १९५६-५७ तक २३.७४ लाख एकड़ भूमि पर जापानी ढङ्ग मैती की गई।

इस प्रयत्न का फल यह हुआ कि चावल का आयात अब प्रायः समाप्त हो गया। जबकि १९५१ और १९५२ में ७५ लाख टन से अधिक चावल विदेशों से मंगाया गया। १९५३ में केवल १४७४ लाख रुपये का चावल आयात हुआ। १९५४ में स्वदेशी पैदावार से ही देश की आवश्यकता की पूर्ति की गई और जो आयात हुआ भी वह केवल गोदामों के लिये हुआ। १९५८-५९ की आयात का अनुमान ५ लाख टन है।

गेहूँ—गेहूँ समशीतोष्ण कृटिवर्ध का पौधा है। इसे पक्के समय उष्ण तथा शुष्क वायु की आवश्यकता होती है, परन्तु आरम्भ से शीत की। वर्षा विशेषकर बुआई और उपज के समय थोड़े दिनों से अन्तर से होनी चाहिये। कड़ी चिपनी मिट्टी तथा बालू जो नदियाँ अपने साथ बहा लाती हैं इसके लिये बहुत अनुकूल हैं। यह प्रायः पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों में बोया जाता है। अत्यन्त गर्मी और अत्यन्त शीत इसके शत्रु हैं। बंगाल तथा दक्षिण में गेहूँ उत्पन्न नहीं होता। १९४७-४८ में इस देश में लगभग २ करोड़ एकड़ भूमि पर गेहूँ बोया गया था और उसमें ५५७ लाख टन की उपज हुई पर यह उपज भारतवर्ष की आवश्यकता के लिये पर्याप्त न थी। इस कारण विदेशों से भी बहुत सा गेहूँ मगाना पड़ा। परन्तु १९५३-५४ में २ करोड़ ६४ लाख एकड़ पर गेहूँ बोया जिससे ७८-९० लाख टन उगाया गया। १९५४-५५ में बोया गया क्षेत्र २ करोड़ ७८ लाख एकड़ हो गया तथा उपज बढ़कर ८९०० लाख टन हो गई। १९५६-५७ में बोया गया क्षेत्र ३ करोड़ ३६ लाख एकड़ हो गया तथा उपज ९३१४ लाख टन हो गई। १९५७-५८ में बोया गया क्षेत्र २ करोड़ ९६ लाख ५७ हजार एकड़ तथा उपज ७६५४ लाख टन रह गई।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गेहूँ की पैदावार भी बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप १९५६-५७ में पैदावार बढ़कर ९३१४ लाख टन हो गई। यह कुछ पूर्व की पैदावार से भी अधिक थी।

ज्वार बाजरा—ये शुष्क जलवायु में उत्पन्न होते हैं। इस कारण राजपूताना, पंजाब तथा दक्षिण में इनकी खेती होती है। भारत में १९५३-५४ में ७ करोड़ ४० लाख एकड़ भूमि पर ज्वार, बाजरा आदि की खेती हुई थी व उनसे १२,४२९ हजार टन अन्न प्राप्त हुआ था। १९५४-५५ में बोया गया क्षेत्र घट कर ७ करोड़ १२ लाख एकड़ रह गया परन्तु उपज बढ़कर १२,५१९ हजार टन हो गई। १९५६-५७ में ज्वार बाजरा ६ करोड़ ८२½ लाख एकड़ भूमि पर बोया गया तथा उससे १०,१३४ हजार टन उपज प्राप्त हुई। १९५७-५८ में बोया गया क्षेत्र ६ करोड़ ९८ लाख ६४ हजार एकड़ हो गया और उपज बढ़कर ११,६२१ हजार टन हो गई।

दालें—यह अधिकतर उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, बम्बई और मध्य प्रदेश में उत्पन्न होती हैं। इन सबमें चने का स्थान मुख्य है। १९५६-५७ में २,४२,६५ हजार

एकड़ पर चना बोया गया तथा उसने ६२६४ लाख टन चना उपजाया गया। १९५७-५८ में २२४०५ हजार एकड़ पर चना बोया गया तथा ४७५४ लाख टन प्राप्त हुआ। १९५६-५७ में दूसरी दालें ३३९५० एकड़ भूमि पर बोई गईं तथा उनकी उत्पत्ति ५२३९ लाख टन हुई। १९५७-५८ में अन्य दालें ३२०५० हजार एकड़ पर बोई गईं तथा ३४६२ लाख टन उपज मिली।

जौ—यह अधिकतर उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी पंजाब में उत्पन्न होता है। १९५३-५४ में इसकी खेती लगभग ८७१९ हजार एकड़ पर हुई और इससे ८९०५ लाख टन अन्न प्राप्त हुआ परन्तु १९५७-५८ में बोया गया क्षेत्र घटकर ७५३१ हजार एकड़ रह गया तथा उत्पत्ति घटकर केवल २१७५ लाख टन रह गई।

फव—यह ममरन भारत में उत्पन्न होने हैं परन्तु काश्मीर में बहुत अच्छे फल उत्पन्न होने हैं। इसके अतिरिक्त और भी भागों में फल उत्पन्न होने हैं। जैसे नागपुर में सतरे, इलाहाबाद में अमरूद आदि।

यहां पर बहुत प्रकार की साग भाजी भी उत्पन्न होती है। जैसे आलू, टमाटर, गोभी, भिन्डी, प्याज आदि। यह सब्जियाँ देश के प्रायः सभी भागों में उत्पन्न होती हैं।

अभी पिछले दिनों हमारे देश में अन्न की बहुत कमी थी। इस कारण इस बात के ऊपर अधिक जोर डाला जा रहा था कि देश में अन्न की कमी को सागभाजी द्वारा पूरा किया जाय।

गन्ना—भारतवर्ष वसंतर में सबसे अधिक गन्ना पैदा करने वाला देश है। यह उपजाऊ भूमि पर होता है और इसे ऊँचा तापक्रम और एकसा किन्तु काफी पानी चाहिये। सिंचाई के सहारे इसकी उत्पत्ति बढ़ जाती है। भारत में गन्ना उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा बङ्गाल में उत्पन्न होता है।

हमारे देश में जब से चीनी उद्योग को संरक्षण मिला है तब से गन्ने की उत्पत्ति बहुत बढ़ गई है। १९५०-५३ में हमारे देश में ४२७२ हजार एकड़ भूमि पर गन्ना बोया गया और ५०१९० हजार टन गन्ना उत्पन्न किया गया। परन्तु उस वर्ष चीनी व गुड़ आदि के भावों के गिरने के कारण अगले वर्षों में इसका उत्पादन बहुत कम हो गया तथा गन्ना कम क्षेत्र पर बोया गया। जैसे १९५३-५४ में बोया गया क्षेत्र गिर कर ३४८५ हजार एकड़ रह गया तथा उपज घट कर ४३७०९ हजार टन रह गयी। उसके पश्चात् चीनी तथा गुड़ का मूल्य वृद्धि से बढ़ाया गया क्षेत्र तथा उत्पत्ति फिर बढ़ने लग। इस प्रकार १९५५-५६ में गन्ना का क्षेत्र बढ़कर ४५६४ हजार एकड़ तथा उत्पत्ति ५९५९ लाख टन रह गई। १९५७-५८ में बोया गया क्षेत्र ५०२१ हजार एकड़ हो गया तथा उपज ६४४४२ हजार टन हो गई। १९६०-६१ के लिए दूसरी योजना में ७८ लाख टन का ध्येय रखा गया है।

अब विभिन्न राज्यों में गन्ने की उत्पत्ति करने का प्रयत्न किया जा रहा है। और १९५२-५३ तक गन्ने के कुल क्षेत्र का १० प्रतिशत उत्तर प्रदेश में, ५ प्रतिशत बिहार में, ३९४ प्रतिशत बम्बई में तथा ६५ प्रतिशत मद्रास में उन्नत गन्ने के अन्तर्गत बोया गया। दूसरी योजना में गन्ने की उत्पत्ति का ध्येय बिन्दु ७४ लाख टन है। १९५६-६० ई० के बीच भारत के समस्त राज्यों में १७ ३७ लाख एकड़ भूमि पर उन्नत खेती की जायगी।

रेशे वाली फसले

कपास—इसके लिये गर्म, नम तथा समान जलवायु की आवश्यकता है। परन्तु अधिक जल इसके लिए हानिकारक है। दक्षिण की काली मिट्टी में जिसमें नमी बहुत काल तक रह सकती है इसकी अच्छी उपज होती है। यह अधिकतर गुजरात, काठियावाड़ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब राज्यों में कई भागों में उत्पन्न होती है। पंजाब में नहरों के किनारे अमेरिकन कपास बोई जाती है।

भारतवर्ष में अच्छे प्रकार की कपास बहुत कम उत्पन्न होती है। यहाँ की कपास छोटे घागे वाली होती है, इस कारण अच्छे प्रकार की कपास विदेशों से मँगानी पड़ती है। जब सिंधु भारतवर्ष का एक अङ्ग था उस समय अच्छे प्रकार की कपास की इतनी कठिनाई न थी जितनी कि आजकल है। अब भारतवर्ष, अमेरिका, मिस्र तथा सूडान से अच्छी कपास मँगाता है। सन् १९५२-५३ में भारत में ३१८४ हजार गाँठें पैदा हुईं परन्तु १९५३-५४ में ३८४४ गाँठें हो गईं, और १९५७-५८ में वह बढ़कर ४७५३ हजार हो गईं। कपास की एक गाँठ ३८२ पौंड की होती है। १९५३-५४ में उसका क्षेत्रफल १७२ ६५ लाख एकड़ था, तथा १९५७-५८ में २०१-५८ लाख एकड़। दूसरी योजना का ध्येय बिन्दु ५५ लाख गाँठें है। परन्तु राज्यों के मन्त्रियों ने हाल ही में इसको बढ़ाकर ६५ लाख गाँठें कर दिया है।

जूट—इसके लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु तथा ऐसी भूमि की आवश्यकता है जिसमें प्रतिवर्ष नई मिट्टी बनती रहे। इसलिए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र के निचले भाग में अथवा आसाम व बङ्गाल में बहुत जूट उत्पन्न होता है।

विभाजन के पहले भारतवर्ष को जूट की पूर्ति (Supply) का एकाधिकार (Monopoly) था। पर विभाजन के पश्चात् लगभग ७० प्रतिशत भाग पाकिस्तान के अधिकार में चला गया। इस कारण यहाँ जूट की मिलों को जो कि सबकी सब भारतवर्ष में हैं बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जूट की २० ६ लाख गाँठें बढ़ाने की योजना थी परन्तु अभी तक इनमें सतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। जहाँ योजना के प्रथम वर्ष में उत्पादन १४ लाख गाँठें बढ़ गया था योजना के दूसरे वर्ष में इसमें लगभग कोई वृद्धि नहीं हुई और १९५३-५४ में जूट तथा मस्ता का क्षेत्रफल और

उत्पादन क्रमशः १६६१ हजार एकड़ तथा ४५५१ हजार गांठ कहे जाते हैं, अर्थात् १६५२-५३ की अपेक्षा १६५३-५४ में क्षेत्रफल में ३४२ प्रतिशत की और उत्पादन में ३२१ प्रतिशत की कमी हो गई है। १६५३ में खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय ने जूट की उन्नत करने तथा उत्पत्ति मूल्य बढ़ाने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त की। इसकी सिफारिश की मानकर ही सरकार ने योजना काल में निश्चित ५० लाख रु० के खर्च को बढ़ा कर ८० लाख रु० कर दिया। १६५५-५६ में क्षेत्र २३१० हजार एकड़ तथा उत्पत्ति ५३५१ लाख गांठ व १६५७-५८ में क्षेत्र २४८० हजार एकड़ तथा उपज ५२६६ गांठें थी। दूसरी योजना का ध्येय विन्दु ५० लाख गांठें हैं। परन्तु राज्य मन्त्रियों की बैठक में इस विन्दु को बढ़ा कर ५५ लाख गांठें कर दिया गया है। जूट की गांठ का वजन ४०० पौंड होता है।

रेशम—जो रेशम के कीड़ों से प्राप्त की जाती है, वह मैसूर, काश्मीर, बङ्गाल, मद्रास, आसाम और पूर्वी पंजाब में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर की उत्पन्न होती है जो बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है।

तिलहन

इनमें सरसो, तिल, अलसी, अरुण्ड तथा विनोले आदि सम्मिलित हैं। यह प्रायः सारे भारतवर्ष में उत्पन्न होते हैं और विशेषकर बङ्गाल, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में इनकी खेती अधिक होती है। सरसो अधिकतर पंजाब तथा अलसी बङ्गाल, बिहार और मध्य प्रदेश में होती है। तिल अधिकतर दक्षिण में होते हैं। मूंगफली भी दक्षिण में बहुत अधिक होती है। तेल निकालने के बीज यूरोप को भेजे जाते हैं, वहाँ इनका तेल, साबुन, रङ्ग, रोगन और वनस्पति की बनता है। तेल निकालने के बीज बाहर न भेजे जायें तो इससे देश को बहुत लाभ हो क्योंकि तेल निकालने में बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा तथा खली को खाद के रूप में काम में लाया जा सकेगा तथा तेल को बाहर भेजने से अधिक धन की प्राप्ति होगी।

पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत तेल निकालने वाले बीजों की दशा कुछ सुधरी है। मूंगफली का क्षेत्र जो १६५१ में १२१५१ हजार एकड़ था वह बढ़कर १६५४-५५ में १३६६३ हजार एकड़ हो गया तथा १६५७-५८ में केवल १४४५७ हजार एकड़ रह गया परन्तु इसकी उत्पत्ति निरन्तर घटती जा रही है जैसे यह १६५१ में ३१४२ हजार टन, १६५२ में २८८२ हजार टन थी। परन्तु १६५७-५८ में उत्पत्ति ४२७१ हजार टन हो गई। दूसरे तेल निकालने के बीजों की उत्पत्ति भी कम होनी जा रही है जैसे १६५१ में यह १६७२० हजार टन रह गई तथा क्षेत्र १८०० हजार एकड़ रह गया। परन्तु इन बीजों का क्षेत्र १६५६ में १६८०५ हजार एकड़ तथा पैदावार १६४६ हजार टन थी। दूसरी योजना में इसकी उत्पत्ति का ध्येय विन्दु ७० लाख टन है। परन्तु राज्य मन्त्रियों की सभा में इस ध्येय को ७६ लाख टन रखा गया है।

मादक पदार्थ

✓ **तम्बाकू**—इसके लिए आर्द्र गर्म जलवायु की आवश्यकता है। मद्रास, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा बङ्गाल में इसकी खेती होती है। भारतवर्ष में ससार का १७ प्रतिशत तम्बाकू उत्पन्न होता है। १९४५-४६ में भारतवर्ष में दस लाख एकड़ पर तम्बाकू बोया गया था और इससे ३,३५,००० टन तम्बाकू उत्पन्न हुआ परन्तु १९५३ में केवल ६१२ हजार एकड़ पर ही तम्बाकू बोया गया और उससे २६८ लाख टन तम्बाकू पैदा हुआ परन्तु १९५७-५८ ई० में इसका क्षेत्र ६२६ हजार एकड़ तथा उपज २५२ लाख टन हो गई। भारतवर्ष का तम्बाकू दूसरे देशों की अपेक्षा कुछ खराब है।

✓ **अफीम**—पोस्त की खेती भारत सरकार के आधीन है। इसे गर्म आर्द्र जलवायु तथा उपजाऊ भूमि चाहिए। पटना, गाजीपुर, बनारस के समीप के प्रान्त, पूर्वी राजपूताने में स्थित मालवा प्रान्त तथा मध्य प्रदेश की एजेन्सी में इसकी खेती होती है। सन् १९३६-४० में ६१३८ एकड़ पर अफीम बोई जाती थी।

चाय—इसकी गर्म तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता है। यह पर्वती ढालों पर उत्पन्न होती है जिससे कि इसकी जड़ों में जल एकत्र होकर जड़ों को हानि न पहुंचा सके। इसकी बारम्बार वर्षा की आवश्यकता रहती है जिससे नये पत्ते निकलते रहे। आसाम, दार्जिलिङ्ग, देहरादून तथा नीलगिरि की पहाड़ियों पर इसकी खेती अधिक होती है। हमारे देश के निर्मात में चाय का मुख्य स्थान है। यह इङ्ग्लैण्ड तथा अमेरिका को भेजी जाती है। हमारे देश में चाय की उत्पत्ति १९५१-५२ में ६४१ मिलियन पौड, १९५२ में ६७५ लाख पौड और १९५६-५७ में ६६८ लाख पौड थी। दूसरी योजना का ध्येय विन्दु ७०० लाख पौड है।

कहवा—इसके लिए आर्द्र तथा नम जलवायु की आवश्यकता है। परन्तु जिस स्थान पर इसे बोया जाय वह स्थान समुद्रतट से प्रायः तीन हजार फुट की ऊँचाई पर होना चाहिए। यह मसूर, द्रावनकोर, कोचीन तथा नीलगिरि पर्वत पर उत्पन्न नहीं होता है। पहले भारतवर्ष से बहुत सा कहवा विदेशों को भेजा जाता था पर अब यह स्थान ब्राजील ने ले लिया है। सन् १९५५ में कहवे का क्षेत्र २४० हजार एकड़ तथा उत्पत्ति ६८ लाख पौड थी।

विविध फसलें

खरड़—यह मुख्यतः दक्षिणी भारत में उत्पन्न होती है। इसके मुख्य स्थान द्रावनकोर, कोचीन, कुर्ग और मद्रास हैं। खरड़ की उत्पत्ति १९५३-५४ में ४५ मिलियन पौड के लगभग थी तथा यह १६९ हजार एकड़ पर बोई जाती है। परन्तु १९५६-५७ की उत्पत्ति ४९ लाख पौड हो गई और बोया गया क्षेत्र १८४ हजार एकड़ हो गया।

(३) भूमि का समान बंटवारा हानि—

नहीं होता, जैसे इङ्ग्लैंड में, उनमें सबसे बड़े लड़के को तो खूब जमीन—

परन्तु छोटे लड़के को कुछ नहीं मिलता। इस प्रकार सम्पत्ति का असमान बंटवारा हो जाता है। यह सामाजिक अन्याय नहीं तो क्या है। यह अन्याय खेतों को सब लड़कों में समान बांटने पर दूर हो जाता है। सब लड़कों की सम्पत्ति का कुछ न कुछ भाग मिल जाने के कारण वे साधनहीन नहीं रह जाते और अपने साधनों से वे अपने भविष्य के जीवन को चलाने में बड़ी सहायता पाते हैं। इस प्रकार देश में एक शक्तिशाली मध्यम वर्ग का जन्म हो जाता है जो किसी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है।

(४) कुछ फसलों के लिये छोटे खेत प्रावश्यक—कुछ फसलें, जैसे चावल, छोटे खेतों पर ही ठीक प्रकार से उगाई जा सकती हैं। मद्रास आर्थिक मण्डल का कहना है, “धान की खेती सारी भूमि पर एकसा धरातल प्राप्त करने के लिये सबसे अच्छी छोटे खेतों पर की जाती है और खेती की सुविधा के लिये एक व्यक्ति की भूमि बहुधा छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटी जाती है।”

(५) प्रो० श्रीमन्नारायण अग्रवाल विनोबा जी के भूमिदान यज्ञ का समर्थन करते हुये कहते हैं कि बड़े-बड़े खेतों की अपेक्षा छोटे-छोटे खेतों पर खेती करना अधिक लाभप्रद है। अपने विचार के समर्थन में उन्होंने बहुत से बड़े-बड़े लोगों के विचार दिये हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया है कि जापान के अच्छे-अच्छे गाँवों में २-४ एकड़ के खेत हैं। इसके पश्चात् उन्होंने बताया है कि चीन की नई सरकार बड़े-बड़े खेतों को सम्प्राप्त करके छोटे-छोटे खेत बनाकर भूमि का पुनर्बंटवारा कर रही है। यहाँ नहीं रूस में भी जहाँ बड़े-बड़े खेत पाये जाते हैं वहाँ पर भी किसानों को ३ एकड़ से लेकर २३ एकड़ तक निजी भूमि दी गई है। इन छोटे खेतों पर स्थानीय किसानों के परिश्रम से काम करता है और अपने परिवार के लिये पर्याप्त अन्न उत्पन्न करता है। इस प्रकार छोटे खेत किसी प्रकार भी खराब नहीं बहे जा सकते। रूस से देशों का भी यह अनुभव है कि छोटे खेतों की प्रति एकड़ उपज बड़े खेतों से अधिक होती है।

परन्तु यदि हम छोटे-छोटे तथा बिखरे खेतों की लाभ व हानियों की तुलना करें तो हमको पता चलेगा कि इसकी हानियाँ अधिक हैं और लाभ बहुत ही कम। कारण यह आवश्यक है कि इस स्थिति को सुधारा जाय।

सार के ढंग—

छोटे तथा छिटे खेतों की दुराई को कई प्रकार से ठीक किया जा सकता है। इससे निम्नलिखित मुख्य हैं—

(१) आर्थिक खेत (Economic Holdings) बनाना—आर्थिक खेतों की स्थापना कई प्रकार से की गई है। पर हमारे विचार में आर्थिक खेत वहाँ खन होते

हैं जो किसान तथा उसके परिवार को निरन्तर काम दे सकें तथा जिससे उसको इतनी आय प्राप्त हो जाय जिससे कि वह अपने परिवार को सुख से रख सके।

इस प्रकार के खेत कई प्रकार से बनाये जा सकते हैं। एक ढङ्ग तो यह है कि रूस के समान सरकार सारी भूमि पर अधिकार कर लें और फिर उस भूमि को सामूहिक ढङ्ग (Collective basis) से जोता जाय। दूसरा ढङ्ग यह है कि भूमि के स्वामी तो स्वयं किसान ही रहे पर वे सब मिलकर सहकारी खेती (Co-operative farming) करें। तीसरा ढङ्ग यह है कि बिखरे हुये खेतों की चक्करी (Consolidation) कर दी जाय।

पहले ढङ्ग को अपनाने में यह डर है कि इस देश में उसका बड़ा विरोध होगा। हमारे देश के लोग निजी सम्पत्ति (Private Property) के सदा ही इच्छुक रहे हैं। इस कारण वह कभी भी यह बात पसन्द न करेगे कि भूमि पर से उनका अधिकार छीना जाय। इसके अतिरिक्त, इस ढङ्ग को अपनाने में रूस का रक्तपात आँखों के सामने आ जाता है। इस कारण इस ढङ्ग को इस देश में नहीं अपनाया गया।

इस कारण हमारे देश में सहकारी खेती तथा चक्करी से ही इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है। परन्तु अभी तक इस कार्य में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई क्योंकि गांव के स्तर पर न तो कोई व्यवस्था है और न लोगों में काम करने का उत्साह। सहकारी खेती पर अभी हाल ही में बड़ा जोर दिया जा रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि योजना काल में इस प्रकार के पग उठाये जायेंगे जिससे कि देश में सहकारी खेती एक मजबूत नींव पर खड़ी हो सके। ऐसा करने से १० वर्ष में अधिकतर खेती सहकारी ढङ्ग से होने लगेगी। भूमि सुधार के लिये नियुक्त पैनल की एक विशेष समिति ने सुझाव दिया है कि वे भूमि जो कि राज्यों को उच्चतम सीमा नियुक्त करके प्राप्त हो अथवा गांव के पास की भूमि जो राज्यों को जमींदारी समाप्त करने पर प्राप्त हो उसको सहकारी ढङ्ग से खेती के काम में लाया जाय। भारत के कुछ विशेषज्ञों ने १९५६ ई० में चीनी की सहकारी खेती का अध्ययन भी किया है। इन विशेषज्ञों ने अपने बहुत से सुझाव दिये हैं जिनमें से एक यह भी है कि कृषि को मजबूत आधार पर रखने के लिये देश में मजबूत बहु-उद्देश्य सहकारी समितियों का निर्माण किया जाय।

दिसम्बर १९५८ में समस्त राज्यों में सहकारी कृषि समितियों की संख्या २०२० थी। हैदराबाद में सरकार ने इस प्रकार की समितियों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिये लगान में कमी, कृषि आय-कर में कमी, निशुल्क टैक्निकल सलाह, कम व्याज की दर पर ऋण आदि बहुत सी सुविधाएँ प्रदान करने के लिये कहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की खेती की उन्नति के लिये १३८५७ लाख रुपये रखे हैं।

विभिन्न राज्यों में इन समितियों की संख्या इस प्रकार थी—

राज्य	समितियाँ की संख्या	राज्य	समितियों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	३१	मनीपुर	३
आसाम	१७०	मैसूर	१००
बिहार	२७	उड़ीसा	२८
बम्बई	४०२	पंजाब	४७८
देहली	२२	राजस्थान	१०५
जम्मू व काश्मीर	७	त्रिपुरा	१२
केरल	५५	उत्तर प्रदेश	२५४
मध्य प्रदेश	१४०	पश्चिमी बङ्गाल	१४८
मद्रास	३७		

७ जून १९५८ ई० की एक सूचना के अनुसार राज्य सरकार १९५८-५९ में ५१३ तर्जों वाले सहकारी खेत चालू करगी। परन्तु राष्ट्रीय विकास समिति का बिन्दु इस वर्ष के लिये ६०० था। इस प्रकार यह प्राप्ति घटने बिन्दु से कम होगी। परन्तु सरकारी क्षेत्रों का कहना है कि सहकारी खेतों के निर्माण में हमका सट्टा को न देख कर उनके गुणात्मक प्रकार को देखना चाहिये। पिछले वर्षों में स्थापित सहकारी खेतों की योजना कमिशन द्वारा की गई जाँच से पता लगता है कि वर्तमान के १६०० खेतों में से केवल ५० वास्तविक अथवा किसी मात्रा में सफल बने जा सकते हैं। भविष्य में सरकारी तथा गैर-सरकारी संस्थाओं का यह प्रयत्न होगा कि केवल उन लोगों को सहकारी खेतों में सम्मिलित होने दिया जाय जो कि सहकारिता की टेक्नीक में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार यह आशा है कि भविष्य में इन सहकारी खेतों के निर्माण से सहकारी आन्दोलन में एक बड़ी बदल आ जायगी।

चक्रवर्ती का कार्य सबसे पहले पंजाब में १९२० में आरम्भ हुआ। यह कार्य बानून द्वारा तथा स्वयं इच्छा से किया गया है। ३१ दिसम्बर १९५७ तक ८५,८०,८७४ एकड़ भूमि पर चक्रवर्ती का कार्य पूरा हो चुका था तथा ५६,१७,४३८ एकड़ पर यह कार्य चल रहा था।

पंजाब के पश्चात् चक्रवर्ती का कार्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बरार आदि में भी हुआ। उत्तर प्रदेश में सहकारी तथा कानूनी दृष्टि से ही चक्रवर्ती का कार्य हुआ। १९५३ ई० में खेती की चक्रवर्ती से सम्बन्धित एक बानून पास किया गया इसमें १९५६ में कुछ मशौधन किया गया है। जिसके अनुसार चक्रवर्ती का कार्य एक पूर्व के जिले में तथा एक पश्चिम के जिले में आजमाया जायगा। इस प्रकार का कार्य अब २१ जिलों में किया जा रहा है। ३१ दिसम्बर १९५७ तक वह क्षेत्र जिस पर चक्रवर्ती का कार्य पूरा हो चुका था १३९८५९९ एकड़ था तथा ३७३५१२९ एकड़ पर यह कार्य चल रहा था।

जम्मू तथा काश्मीर		२२ ३/४ एकड़
मैसूर	हैदराबाद क्षेत्र	१८ से २७० एकड़
पंजाब	पेपसु क्षेत्र	३० स्टैंडर्ड एकड़ (उखड़े हुए लोगों के लिये ४० स्टैंडर्ड एकड़)
राजस्थान	अजमेर क्षेत्र	५० एकड़ (जहाँ भूमि मध्यस्थों पर है।)
पश्चिमी बंगाल		२५ एकड़
हिमाचल प्रदेश		चम्बा जिले में ३० एकड़ तथा दूसरे क्षेत्रों में १०५ २० लगान देने वाला क्षेत्र

पंजाब में सरकार ने इन बात का अधिकार दिया है कि जिन जमींदारों के पास ३० स्टैंडर्ड एकड़ से अधिक भूमि है उन पर किसानों को बना दिया जाय। केरल का Agrarian Relations Bill जो अब एक प्रचलन समिति के सामने है। विषय में प्राप्त की जाने वाली भूमि के लिये १५ से ३० एकड़ तक अधिकतम सीमा निर्दिष्ट करता है। (Madhya Pradesh Land Revenue Code Bill, १९५८ में प्राप्त की जाने वाली भूमि के लिए एक अधिकतम सीमा निर्दिष्ट करता है, परन्तु अधिकतम सीमा नियमों के अनुसार निर्दिष्ट होगी।)

खेतों की उच्चतम सीमा के दो पहलू हैं—(१) भविष्य में प्राप्त की जाने वाली भूमि की उच्चतम सीमा तथा (२) वर्तमान के खेतों की उच्चतम सीमा। भविष्य में प्राप्त की जाने वाली भूमि की उच्चतम सीमा निम्नलिखित राज्यों में निर्दिष्ट की जा चुकी है—

बिहार प्रदेश	राजधानी क्षेत्र	१८ से १५० एकड़
गुजरात	सुंदरानी जिले	५० एकड़
कर्नाटक	(भतपूर्व) कर्नाटक क्षेत्र	१० से ४८ एकड़
	मराठावाड़ा क्षेत्र	१० से १५० एकड़
	सौराष्ट्र क्षेत्र	२० से १२० एकड़
	विशुव तथा कच्छ क्षेत्र	सैन परिवार के लिये (क्षेत्र ट्रिग्नलन द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा)
जम्मू तथा काश्मीर		२२ ३/४ एकड़
मध्य प्रदेश	मध्य भारत क्षेत्र	५० एकड़
	राजस्थान क्षेत्र	३० से २० एकड़ तक (भूमि की श्रेणी के अनुसार)

मंसूर	बम्बई क्षेत्र	१२ से ४८ एकड़
	हैदराबाद क्षेत्र	१२ से १८० एकड़
पंजाब		३० स्टैण्डर्ड एकड़
राजस्थान	(अजमेर क्षेत्र सहित)	३० सीचे गये एकड़ अथवा २० शुष्क एकड़
उत्तर प्रदेश		४० एकड़
पश्चिमी बंगाल		२५ एकड़
दहली		३० स्टैण्डर्ड एकड़

मंसूर में वर्तमान तथा भविष्य में प्राप्त की जाने वाली भूमि के लिये ऐसी सीमा निश्चित की गई है जिसकी वार्षिक आय ३६०० रु० होगी। Andhra Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings Bill 1958 ऐसी उच्चतम सीमा निश्चित करना चाहता है जिससे कि वर्तमान के खेतों से ५४०० रुपये की वार्षिक आय प्राप्त हो सके तथा भविष्य में प्राप्त खेतों से ३६०० रुपये की वार्षिक आय प्राप्त हो सके। जम्मू तथा काश्मीर में वर्तमान के खेतों की उच्चतम सीमा के कानून को कार्यान्वित किया जा चुका है। पंजाब के पेपसू क्षेत्र तथा आसाम में नियम बन चुके हैं तथा भूमि के स्वामियों से इस बात के घोषणा पत्र लिये जा रहे हैं कि उनके पास कितनी भूमि है। पश्चिमी बंगाल में सरकार ने भूतपूर्व जमींदारों के फालतू भूमि पर अधिकार कर लिया है। यह भूमि एक-एक बरस के लिये बिना भूमि के मजदूरों को दी जाती है।

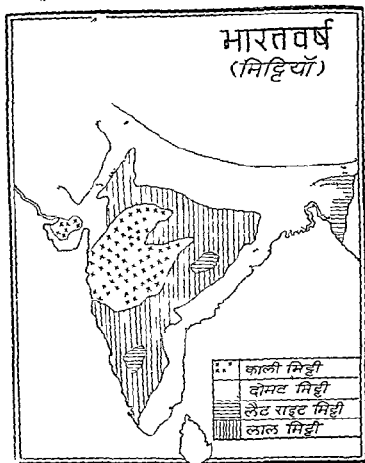
Q 18 What different types of soils are found in India ? Discuss the problem of soil erosion in the country and suggest remedies

प्रश्न १८—भारत में कौन सी भिन्न-भिन्न मिट्टियाँ पाई जाती हैं ? देश की मिट्टी के बटाव की समस्या का वर्णन कीजिये तथा ठीक करने के सुभाव कीजिये।

उत्तर—भारतवर्ष में निम्नलिखित प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं—

(१) दोमट मिट्टी (Alluvial Soil)—यह भारतवर्ष की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। यह मिट्टी गङ्गा सिंध के मैदान तथा समुद्र तट के मैदानों में पाई जाती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है। इसकी गहराई का अनुमान लगाना बड़ा कठिन है। खोदने पर कई सौ फुट गहराई तक यह मिट्टी पाई गई है। यह मिट्टी पौधों को उगाने के लिये बड़ी उपयुक्त है परन्तु इसमें नत्रजन (Nitrogen) की कमी है। यह मिट्टी पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बङ्गाल, आसाम,

उत्तरी राजस्थान और समुद्र तट के मैदानों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चावल, गन्ना तथा गेहूँ उगाए जाते हैं।



(२) काली मिट्टी (Black Soil) — यह मिट्टी लगभग दो लाख वर्ग मील में पाई जाती है। इसके क्षेत्र काठियावाड़ वरार हैदराबाद पश्चिमी मध्य प्रदेश बम्बई और मद्रास के कुछ भाग हैं। बरसात के दिनों में यह मिट्टी चिकनी व तिलविली हो जाती है और गर्मी के दिनों में इसमें बहुत सी दरारें पड़ जाती हैं। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। इसमें धातुओं की अधिक मात्रा होने के कारण इसका रंग काला होता है। यह मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयुक्त है। इस मिट्टी का मुख्य गुण यह है कि यह नमी को बहुत समय तक अपने अन्दर बनाए रखती है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड का मात्रा कम होता है परन्तु पोटैश और चूना अधिक होता है।

(३) लाल मिट्टी (Red Soil)—यह मिट्टी इमलिये लाल होती है क्योंकि इसमें लोहा मिला होता है। यह मद्रास, मैसूर, दक्षिण-पूर्व, बम्बई, हैदराबाद और मध्य प्रान्त के पूर्व में छोटा नागपुर, उड़ीसा और बङ्गाल के दक्षिण में पाई जाती है। इस मिट्टी का रङ्ग हर जगह एक सा नहीं होता। कहीं लाल, कहीं भूरा, कहीं पीला, कहीं खाकी और कहीं काला भी होता है। परन्तु क्योंकि इसका रङ्ग अधिकतर भागों में लाल होता है इसीलिये यह लाल मिट्टी कहलाती है। इस मिट्टी का क्षेत्रफल लगभग ८ लाख वर्ग मील है। यह मिट्टी छेददार होती है। ऊँचे भागों की मिट्टी हल्की, पतली तथा ककरीली होती है इसीलिये उपजाऊ नहीं होती। इस पर बाजरा पैदा हो जाता है। परन्तु जो मिट्टी मैदानों और घाटियों में पाई जाती है वह गहरी तथा बारीक कणों वाली होती है जिसमें कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस मिट्टी में लोहा, मैंगनेशियम तथा एल्युमीनियम का अंश अधिक होता है किन्तु नत्रजन, फास्फोरस, चूना, पोटेश तथा जीवाश्म कम होता है।

(४) लैटराइट मिट्टी (Laterite Soil)—इस मिट्टी का रङ्ग भी लाल या लाली में युक्त पीला होता है। यह मिट्टी मध्य भारत, आसाम तथा पश्चिमी व पूर्वी घाटों के पास पाई जाती है। ऊँचे भागों की मिट्टी ककरीली व छेददार होती है, पानी बहुत जल्द सोख लेती है। अनुपजाऊ होने के कारण कृषि के लिये उपयुक्त नहीं है। परन्तु निचले भागों की मिट्टी चिकनी अथवा दोमट होती है। यह अधिक समय तक नमी धारण कर सकती है इसलिये खेती के लिये उपयुक्त है। इस पर चाय की खेती खूब होती है तथा चावल उगाया जाता है। इस मिट्टी में अल्युमीनियम व लोहे का अंश अधिक होता है किन्तु चूना, मैंगनेशियम, फास्फोरस व नत्रजन कम होता है। सोडा, क्षार पदार्थ तथा पोटेश विलकुल नहीं होते।

भारतवर्ष में मिट्टी के कटाव की समस्या (Problem of Soil-erosion in India)

भारतवर्ष जैसे कृषि प्रधान देश के लिये मिट्टी का जो महत्त्व है उसके सम्बन्ध में कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है। अनुमान है कि एक इंच भूमि बनने में लगभग ३०० से १००० वर्ष लगते हैं। परन्तु जिस समय से मनुष्य ने भूमि को खेती के लिये उपयोगी बनाया है उसी समय से उसकी अज्ञानता के कारण मिट्टी के कटाव की समस्या उसके सामने आ गई है। मिट्टी के कटाव के कारण भूमि की ऊपरी परत हटा अथवा पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इस प्रकार ऊपरी परत की मिट्टी चले जाने के कारण जो मिट्टी बच रहती है वह खेती के लिये उपयुक्त नहीं रह जाती। क्योंकि ऊपर वाले परत की मिट्टी के वह गुण भी जो पौधों को उगाने के लिए आवश्यक हैं मिट्टी के साथ उड़कर अथवा बह कर चले जाते हैं। नीचे वाली मिट्टी पर खेती होने पर और भी अधिक मिट्टी का कटाव हो जाता है। आधुनिक काल में अधिकाधिक खेती होने के कारण यह समस्या

और भी उग्र रूप धारण कर रही है। बहुत से क्षेत्रों में मरुस्थल आगे बढ़ता रहता है और उसके रोकने का उचित समय पर ठीक साधन प्रयोग में लाये गये तो उसका बढ़ावा बढ़ता ही रहता है और दूसरे हरे-भरे क्षेत्रों में रेत लाकर वहाँ की पुरानी फसलों और वृक्षों के उत्पादन को नष्ट करके उसको बोरान बना देता है। हमारे देश में मथुरा व आगरे के जिलों के पास मरुस्थल आगे बढ़ रहा है।

मिट्टी का कटाव मनुष्य के लिये एक बड़ी भयङ्कर चीज है। इसके कारण बड़ी-बड़ी सभ्यताओं का नाश हो गया। डा० एच० एच० बेटन (Dr. H H Betten) का मत है कि 'मिट्टी के कटाव के कारण पुरानी सभ्यताओं का नाश हुआ गया है, जिनके टूटे-फूटे शहर अब उस निर्जन खण्डों में पड़े हुये हैं जो कभी समार के सबसे उपजाऊ क्षेत्र थे।' चीन का गोबी मरुस्थल, मिस्र का बड़ा मरुस्थल, भारत तथा वेनीलोन के खण्डर इस मीन एव जलूक सभ्यता के विनाश के प्रमाण हैं।

मिट्टी के कटाव के कारण (Factors responsible for soil erosion) -- मिट्टी के कटाव के बहुत से कारण हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं--

(१) हवा—जब तेज हवा अथवा आधी चमत्ती है तो वह अपने साथ मिट्टी के कण उड़ाकर ले जाती है। इस प्रकार मरुस्थल बढ़ता रहता है।

(२) पानी—पानी के द्वारा दो प्रकार का कटाव होता है—(अ) समतल तथा (अ) गहरा।

(अ) समतल कटाव—जिस भूमि में घात अथवा फसल उगी हुई नहीं होती उस पर जब पानी पड़ता है तो उस भूमि के कण पानी में मिलकर बहकर चले जाते हैं। इस प्रकार जीवाश्म तथा पौधों की खुराक के बहुमूल्य अंश पानी में बहकर भूमि की उर्वर शक्ति को कम कर देते हैं। समतल कटाव धीमे-धीरे होता है और इसका पता तब लगता है जबकि खेत से प्राप्त उपज घटती है। ऐसे कटाव को रोक-थाम करने के लिये खेतों की मेड़बन्दी करना सबसे सरल उपाय है। इसके अतिरिक्त ऐसी फसलें भी बोई जायें जो भूमि के कणों को अच्छी तरह पकड़ सकें और भूमि के कटाव को रोकें।

(आ) गहरा कटाव—वर्षा के समय पानी ऊँचे खेतों से नीचे की ओर बह कर सलता है जिसके साथ भूमि-कण भी अधिकांश मात्रा में होते हैं। जैसे-जैसे पानी बहकर आगे चलता है इसकी भूमि काटने तथा भूमि कणों को अपने साथ बहा ले जाने की शक्ति बढ़ जाती है। कुछ दूर बहकर यह पानी छोटी-छोटी नालियाँ बना लेता है जो निरन्तर बहती रहती हैं। अन्त में वे बड़े-बड़े नालों का रूप धारण कर लेती हैं। उस समय भूमि बहुत ऊबड़-खाबड़ हो जाती है। इसको गहरा कटाव कहते हैं। हमारे देश में आगरा व इटावे के जिलों में गहरे कटावों ने बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है। ये कटाव इतने बड़े-बड़े हैं कि उन्होंने छोटी-छोटी पहाड़ियों का रूप धारण कर लिया है। ऐसे गहरे कटावों को जहाँ पृथ्वी के बहुत ऊबड़-खाबड़ होने के कारण कोई फसल उत्पन्न नहीं हो सकती, कन्दरायुक्त बंजर भूमि

(रेवाइन) कहते हैं। समतल तथा गहरे दोनों कटावों में से समतल कटाव अधिक हानिकारक है क्योंकि इसका ज्ञान किसान को नहीं हो पाता।

मिट्टी के कटाव के कारण (Causes of soil erosion)—मिट्टी के कटाव के बहुत से कारण हैं जिसमें से कुछ नीचे दिये जाते हैं—

(१) पत्तों को असावधानी से काटना और काटने के पश्चात् वृक्ष न लगाना।

(२) घाम पतवार का बुरी तरह काटना तथा उसमें दूसरी घास न उगाना। इसके अतिरिक्त भेड़, बकरी तथा दूसरे घरेलू पशुओं को अनियमित रूप से चराना और चरागाहों की अच्छी प्रकार देखभाल न करना।

(३) अनियमित रूप से बार-बार फसल बोना और उसमें पूरी मात्रा में जीवाश्म और खाद का न डालना। ऐसा करने से भूमि के कणों की संगठन शक्ति कम हो जाती है और इसके कारण पानी सरलता से बह जाता है।

(४) ऊँचे-नीचे खेतों की ठीक प्रकार से मेड़ बन्दी न करना और पानी के निकास का ठीक प्रबंध न करना।

(५) जहाँ मरुस्थल बढ़ रहा हो वहाँ वृक्षों का न लगाना।

सबसे अधिक मिट्टी ढालू पहाड़ों के नीचे की भूमि को काटती है। हमारे देश में आसाम, उड़ीसा, आंध्र, छोटा नागपुर तथा मध्य प्रवेश में बहुत सी मिट्टी खेती की जोत को बदलते रहने के कारण कट गई है। केवल उड़ीसा में ही इस प्रकार की हानि का अनुमान १२,००० वर्ग मील है। परन्तु इसका सबसे अधिक प्रभाव मैदानों में पड़ता है। "उत्तरी भारत की मुलायम मिट्टी के क्षेत्रों में नदी व स्रोतों के कितारे अच्छी उपजाऊ मिट्टी की बड़ी हानि हो रही है और दरार वाली भूमि बिना रुकावट के बटती जा रही है।" हमारे देश में जमना नदी के दक्षिण में बुन्देलखण्ड में तथा मध्य भारत, बिहार, बम्बई, मद्रास तथा पंजाब के कुछ भागों में मिट्टी के कटने की समस्या बहुत भयङ्कर हो गई है। बंगाल और आसाम में जहाँ ७०" से २००" तक वर्षा होती है मिट्टी का कटाव जङ्गलों के कटने तथा भूमि की जोत की जल्दी बदलने के कारण होता रहता है। इसके अतिरिक्त हाल ही में छोटा नागपुर की पहाड़ियों के वन कट जाने के कारण बड़ी भयङ्कर बाढ़ आती है जिससे बहुत सी मिट्टी कट जाती है। इस प्रकार दरार वाली भूमि का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ३० लाख एकड़ तथा राजस्थान, विन्ध्य प्रदेश, बम्बई, सौराष्ट्र आदि में ३६ से ५० लाख एकड़ के बीच है।

पानी के अतिरिक्त हवा से भी मिट्टी कटती रहती है, समुद्र के किनारे हवा के कारण ही मरुस्थल देश के भीतर की ओर बढ़ रहा है।

इस प्रकार यह अनुमान लगाया गया है कि भारतवर्ष की लगभग दो करोड़ एकड़ भूमि मिट्टी के कटने के कारण बिल्कुल नष्ट हो गई और लगभग १० लाख एकड़ भूमि को अभी ठीक बनाना है इसलिए यह बिल्कुल आवश्यक है कि मिट्टी के

इस प्रकार कटने को एक दम रोका जाय नहीं तो हमको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ।

मिट्टी का कटाव रोकने के उपाय—

मिट्टी के कटाव को निम्नलिखित ढङ्ग से रोका जा सकता है—

(१) पेड़ लगाकर—वनो के लगाने से मिट्टी का ढीलापन जाता रहता है तथा नदियों की बाढ़ का वेग कम हो जाता है । इसके अतिरिक्त पेड़ों से गिरी हुई पत्तियों व टहनियों से भूमि की सतह ढक कर सुरक्षित हो जाती है । वन आधियों के वेग को कम करके हवा द्वारा की जाने वाली क्षति को भी रोक देते हैं ।

(२) बाँध बनाकर तथा डोल बनाकर—मिट्टी के कटने को रोकने के लिये बाध बनाए जाने चाहिये तथा खेतों के चारों ओर डोल बना देनी चाहिये । ऐसा करने से जब पानी मिट्टी को बहाकर ले जायगा तो वह मिट्टी बाध अथवा डोल से रुक जायेगी ।

(३) पशुओं के चराने की ठीक व्यवस्था करके—पशुओं के चराने की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि वनस्पति धीरे धीरे समाप्त हो । पशुओं को बिना सोचे समझे चराने के कारण वनस्पाति जल्दी समाप्त हो जाती है और मिट्टी कटनी आरम्भ हो जाती है ।

(४) ठीक प्रकार खेती करके—खेती को ठीक प्रकार करके भी मिट्टी के कटने को बहुत कुछ रोका जा सकता है । खेती की ठीक प्रकार जुताई वरके उनमें डोल बनानी चाहिये । ढलान की भूमि को वर्षा के पहले लम्बानुसार जोत देने से पानी भूमि में रुक जाता है तथा भूमि का कटाव नहीं होता ।

मिट्टी को बचाने का प्रयत्न—प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये ३ २५ करोड़ रुपये रखे गये थे पर द्वितीय योजना में इस कार्य के लिये २६ ८३ करोड़ रुपये रखे गये हैं । इसमें से ४ करोड़ रुपय तो केन्द्र खर्च करेगा और शेष राज्य सरकारें खर्च करेगी । इस धन में से ३ २४ करोड़ रुपये नदी योजना क्षेत्रों के लिये रखे गये हैं । जोने हुए तथा जोते जाने योग्य खेतों की मिट्टी के कटाव को रोकने के लिये १३ करोड़ रुपये रखे गये हैं । लोक रक्षा में इसके लिये एक River Board Bill भी पेश किया गया है जिसके द्वारा राज्य की सत्ताह के River-Board बनाये जायेंगे । उनके बन जाने के पश्चात् Soil Conservation Boards उनकी सलाह से अपने अपने क्षेत्र की योजनायें बनायेंगे । श्री कृष्णामचारी का मुताव है कि राज्यों को ऐसे कानून बनाने चाहियें जो कि सरकार को मिट्टी के बचाने के लिये योजना बनाने की शक्ति दें और भूमि जोतने वालों पर यह ज़िम्मेदारी हो कि वे मिट्टी को काटने से बचावें ।

Central Soil Conservation Board ने मिट्टी को बचाने के लिये कई स्थानों पर ट्रेनिंग का कार्य किया है जहाँ पर बहुत से आदमियों को ट्रेनिंग दी जा

चुकी है तथा बहुत से लोगो को ट्रेनिंग दी जा रही है। १९५६-५७ में बोर्ड ने देहरादून में एव Land use Survey and Planning Organisation की स्थापना की मजूरी दी है। इसकी शाखायें नागपुर तथा राची में होगी। बोर्ड ने जाधपुर में एक Desert Reclamation Scheme को चालू करने का निश्चय किया है। जिसके अन्तर्गत द्वितीय योजना काल में २५ लाख एकड़ मरुस्थली भूमि को प्राप्त किया जायेगा। एक ऐसी सस्था भी स्थापित की जायगी जो कि पहाड़ी जातियों में खेती को बदलते रहने के विरुद्ध प्रचार करेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी सरकार मिट्टी के कटाव को रोकने के लिये बहुत प्रयत्नशील है।

एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना हो चुकी है और राज्यों की सलाह से एव प्रोग्राम बनाने का प्रयत्न जारी है। इस कार्य के लिय किसानों के सहयोग की आवश्यकता है जो कि सामूहिक विकास योजना व राष्ट्रीय विस्तार मेवा के द्वारा प्राप्त हो सकता है। मरुस्थल को न बढ़ने देना इस योजना का एक मुख्य अङ्ग है।

Q 19 State the different forms of irrigation in India. What is meant by productive and protective works? Point out the relative importance of irrigation works in different states of India. Give post war schemes.

प्रश्न १९—भारत में सिंचाई के विभिन्न साधनों को बताइये। उत्पादक तथा रक्षात्मक नहरों का क्या अभिप्राय है? भारत के विभिन्न राज्यों में सिंचाई के ढंगों का सापेक्षिक महत्व बताइये। युद्ध पश्चात् की योजनाएं दीजिये।

भारतवर्ष में सिंचाई का महत्व—यह बात हर एक जानता है कि बिना पानी के भूमि से कुछ भी नहीं उगाया जा सकता। इसलिये जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं होती वहाँ पर खेती को दूसरे ढंग से पानी पहुँचाया जाता है।

भारतवर्ष की वार्षिक जल वर्षा लगभग ४५ इंच है। स्थान-स्थान पर इसमें बहुत घटत बढ़त होती रहती है। उदाहरण के लिये राजपूताने में केवल १० इंच वर्षा होती है जबकि बंगाल में ६० से ८० इंच तक होती है। यही नहीं वर्षा वर्ष के सब महीनों में एक सी नहीं होती। किसी महीने में अधिक होती है ता किसी में कम। जैसे लगभग ६० प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर तक होती है और शेष १० प्रतिशत शेष ८ मास में होती है। वर्षा के सम्बन्ध में यह भी बात बताने योग्य है कि वह अनिश्चित है कभी होती है और कभी नहीं भी होती है। इसी कारण भारतीय कृषि को मानसून का जुआ बताया गया है (Indian agriculture is gamble in the monsoon)।

ऐसी अवस्था में कृषि को वर्षा के ऊपर छोड़ना देश में आये दिन सकट

बुलाना है। इसी कारण सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है। जब से देश के अन्दर सिंचाई का प्रबन्ध हुआ है तब से देश में अकाल का भय बहुत कम हो गया है।

सिंचाई करने से एक दूसरा लाभ यह है कि इससे एक से अधिक फसलें उत्पन्न करने का अवसर प्राप्त हो जाता है और ठीक समय पर पानी पहुँचने के कारण प्रति एकड़ अधिक अन्न उत्पन्न होता है, उदाहरण के लिये उत्तर प्रदेश के जिन भागों में सिंचाई होती है उन भागों में एक एकड़ पर १५५० पौण्ड गेहूँ तथा जो पैदा होता है। परन्तु जिन भागों में सिंचाई का प्रबन्ध नहीं है उनमें केवल ७५० या ८०० पौण्ड ही उत्पन्न होता है। यही हाल दूसरी फसलों के साथ भी है।

कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो बिना सिंचाई के उत्पन्न ही नहीं हो सकती। जैसे सब्जों तथा फल को हर समय पानी चाहिए जो वर्षा से प्राप्त नहीं हो सकता।

यदि हमारे देश में सिंचाई का प्रबन्ध न होता तो आज हमारे देश के पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि भाग मरुस्थल में बदल जाने और देश में भीषण अकाल पड़ते हैं जिसमें न केवल जल घन की ही हानि होती बल्कि देश की सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था नष्ट-भ्रष्ट हो जाती।

इसलिये हम यह कह सकते हैं कि भारतवर्ष में सिंचाई की बड़ी आवश्यकता है। यह बात तब और भी अधिक सत्य में आ सकती है जबकि यह ध्याता जाय कि हमारे देश का मुख्य पेशा कृषि है और इसके ऊपर देश की ७० प्रतिशत जन-संख्या निर्भर है।

भारत में सिंचाई के साधन—

भारत में मुख्यतः तीन प्रकार के साधनों से सिंचाई होती है—

(१) कुएँ, (२) तालाब, (३) नहर।

कुएँ—हमारे देश में कुआँ सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। इनसे हमारे देश की कुल सींची हुई भूमि की लगभग ३० प्रतिशत भूमि सींची जाती है। कुओं की संख्या हमारे देश में २५ लाख से अधिक है और उनमें लगभग १०० करोड़ रुपये लगे हुये हैं। १९५५-५६ में इनसे हमारे देश की १६६ लाख एकड़ भूमि सींची गई।

कुएँ साधारणतया जन स्थानों पर पाये जाते हैं जहाँ मुतायम मिट्टी होती है तथा पानी बस गहराई पर मिल जाता है। वैसे तो सारे भारतवर्ष में ही कुओं द्वारा सिंचाई होती है परन्तु उत्तर प्रदेश में यह सबसे अधिक संख्या में पाये जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुओं की संख्या लगभग ११ लाख से भी अधिक है। दूसरा नम्बर मद्रास का जाता है जहाँ ६६ लाख कुएँ पाये जाते हैं। पूर्वी पंजाब, बम्बई, मध्य प्रदेश और राजपूताने का नम्बर इसके पश्चात् जाता है।

कुएँ नञ्चे और पक्के दोनों प्रकार के होते हैं। नञ्चे कुएँ लगभग ४० रुपये की लागत पर तैयार हो जाते हैं। परन्तु पक्के कुओं पर लगभग ३००० रुपये खर्च

होते हैं। ये कुए पशु, तेल, बिजली तथा ढेकली से चलते हैं। कच्चे कुए अधिकतर ढेकली से चलते हैं और सागभाजी वाले इनको बना लेते हैं।

उत्तर प्रदेश के नल कूप (Tube wells)—

उत्तर प्रदेश के नल कूपों को सिंचाई का एक प्रमुख साधन बनाया जा रहा है। इन कुओं से बिजली की शक्ति से पानी निकाला जाता है। यह कुए बहुत सी भूमि पर सिंचाई कर सकते हैं। सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे रही है। १९४६ के अन्त तक उत्तर प्रदेश में १८४७ नल कूप थे। परन्तु १९५२ के अन्त में इनकी संख्या बढ़कर २३९२ हो गई। १९५६ के अन्त तक उत्तर प्रदेश में ५००० नलकूप बन गये हैं। इन कुओं से अन्त में २ मिलियन अतिरिक्त भूमि सींची जायेगी तथा ३ लाख टन अतिरिक्त अन्न तथा दूसरी पसले उत्पन्न हो सकेंगी। Indo-American Technical Assistance Programme के अन्तर्गत भारत सरकार ने २९७६ ट्यूब वेल बनाये हैं तथा दूसरे २९५० ट्यूब वेलों पर कार्य चालू हो गया है।

उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बम्बई सरकार की भी ५०,००० कुए बनवाने की योजना है। यह कुए प्रतिवर्ष १०,००० की गति से बनाये जायेंगे। सरकार की ओर से ५०० रुपये अथवा लागत का २५ प्रतिशत, इन दोनों में से जो भी कम हो, कुए बनाने वालों को सहायता के रूप में दिया जायेगा। शेष लागत तत्काली ऋण के रूप में ३½ प्रतिशत व्याज की दर से सरकार की ओर से दी जायेगी। इसी प्रकार मद्रास में भी बिजली के कुए बनाने के लिये सरकार की ओर से सहायता दी जा रही है।

(२) तालाब—२९५५-५६ में हमारे देश के कुल सींचे हुये भाग के लगभग १९ प्रतिशत भाग अर्थात् १०९ लाख एकड़ पर तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। तालाब अधिकतर दक्षिणी भारत में पाये जाते हैं जहाँ पर बहुत सख्त मिट्टी है। इस प्रकार की मिट्टी में कुए खोदने बड़े कठिन हैं और वहाँ नहरें बनाना भी कठिन है क्योंकि वहाँ की भूमि सख्त है और वहाँ की नदियाँ बरसात में ही चलती हैं। यह तालाब अधिकतर मद्रास, मसूर, बम्बई, हैदराबाद, राजपूताना तथा मध्य भारत में पाये जाते हैं। वर्षा के पानी को इन तालाबों में रोक दिया जाता है और फिर इस पानी को नहाने, कपड़े धोने और पीने के काम में लाया जाता है। यह तालाब छोटे बड़े सभी प्रकार के होते हैं। मद्रास में ऐसे ४०,००० तालाब हैं। बहुत से तालाब बहुत बड़े हैं। इनमें बम्बई राज्य में, मे. फार्म (Erf), और जिल्हा, मे. जग. समुद्र शीलों ४५ वर्गमील हैं। मसूर राज्य का कृष्णा राज सागर और हैदराबाद का उस्मान सागर आदि बहुत बड़े तालाब और शीलों हैं।

(३) नहर—वर्तमान काल में नहरें हमारे देश की सिंचाई की मुख्य साधन हैं। यह अधिकतर सरकार ने बनाई हैं। १९५५-५६ में भारत में २३२ लाख एकड़ भूमि नहरों द्वारा सींची जा रही थी। कुल सींचे हुये भाग का ४१ प्रतिशत सरकारी

नहरो तथा केवल ५२ प्रतिशत निजी नहरो में सोचा जाता है। नहरे दो प्रकार की हैं—(१) बरसाती (Inundation), (२) सदा बहने वाली (Perennial)। बरसाती नहरें केवल बरसात में ही बहती हैं। इन नहरो में नदियों की बाढ़ का पानी आता है। पुराने समय में अधिकतर इसी प्रकार की नहरे थीं सदा बहने वाली नहरें हिमालय पहाड़ से निकले वाली नदियों से जिनमें सदा ही जल भरा रहता है, निकलती हैं। यह नहरे अङ्गरेजों के शासनकाल में बहुत बड़ी लागत लगा कर बनाई गई थी। इन नहरो से उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब, बिहार, उड़ीसा आदि राज्यों में सिंचाई होती है। जब ये नहरे बनीं तब से इन भागों में अकाल का भय बहुत कम हो गया है। इन दो प्रकार की नहरो के अतिरिक्त कुछ ऐसी नहरें भी हैं जो किसी स्थान पर पानी एकत्र करके उसमें से निराली जाती हैं। इस प्रकार की नहरें दक्षिण, मध्य प्रदेश तथा बुन्देखण्ड में पाई जाती हैं।

१९२१ से पूर्व नहरें तीन भागों में विभक्त थी—(१) उत्पादक (Productive) (२) रक्षात्मक (Protective) और (३) छोटी (Minor)।

(१) उत्पादक—ये नहरे थीं जिनसे बनने के १० वर्षों के भीतर इतनी आय प्राप्त हो जाये जो कि उनमें लगी हुई पूँजी पर व्याज तथा चानू खर्चों के बराबर हो। इस प्रकार की नहरे अधिकतर उत्तरी भारत तथा मद्रास में पाई जाती हैं। १९३५-३६ में इस प्रकार की नहरो में ११४ करोड़ रुपया लगा हुआ था और उनसे ७६१ प्रतिशत की आय मिल रही थी।

(२) रक्षात्मक—यह वह नहरें जो लाभ उत्पादन करने के हेतु नहीं बनाई जाती बरन् इसलिये बनाई जाती हैं जिससे कि अकाल का भय कम हो जाये। यह नहरें अकाल सहायता तथा बीमा कोष (Famine Relief and Insurance Fund) में से बनाई जाती हैं। १९३५-३६ में इस प्रकार की नहरें लगभग ३० लाख एकड़ भूमि को मीचती थीं और उनमें ३६ करोड़ रुपया लगा हुआ था। इस प्रकार की नहरें अधिकतर दक्षिण भारत में पाई जाती हैं।

(३) छोटी इनमें विविध प्रकार की छोटी-छोटी नहर सम्मिलित थीं। यह प्रतिवर्ष की सरकार की आम में से बनाई जाती हैं।

परन्तु १९२१ के पश्चात् इस प्रकार का विभाजन समाप्त कर दिया गया। आजकल सब नहरें या तो उत्पादक (Productive) हैं अथवा अनुत्पादक (Unproductive) हैं।

विभिन्न राज्यों की नहरे

पूर्वी पंजाब की नहरे

विभाजन से पूर्व पंजाब प्रान्त से नहरो की सबसे बड़ी व्यवस्था थी परन्तु उनमें से कई बड़ी बड़ी नहरें पाकिस्तान में चली गई हैं। अब पूर्वी पंजाब में अग्र-लिखित नहरें पाई जाती हैं।

(१) पश्चिमी यमुना नहर—यह नहर यमुना नदी से ताजवाला (जिला अम्बाला) स्थान पर निकाली गई। इससे पूर्वी पंजाब के करनाल व हिसार जिलों में सिंचाई होती है। राजस्थान व देहली के कुल भागों पर भी इसी से सिंचाई होती है। इस नहर की शाखाओं सहित लम्बाई लगभग २००० मील है जिनसे १०१८ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है।

(२) सरहिन्द नहर—यह सतलज से रोपड़ (जिला अम्बाला) स्थान से निकाली गई है। इसके द्वारा लुधियाना, फिरोजवादा, हिसार जिलों तथा पटियाली सभ की पटियाला, नाभा, जीद, मलरे कोटला व कलासिया रियासतों में सिंचाई होती है इस नहर की शाखाओं सहित लम्बाई २७३३ मील है १४८३ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाती है।

(३) अपर बारी दोआब नहर—यह नहर पठानकोट के निकट माधोपुर स्थान से रावी नदी से निकाली गई। इसके द्वारा गुरुदासपुर व अमृतसर जिलों में सिंचाई होती है। नहर के बनाए जाने से पूर्व इन भागों में जंगल थे जिनको साफ करके यहाँ खेती की जाती है। इससे ८२८ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होनी है।

(४) सतलज घाटी की नहर—यह नहर सतलज नदी पर फिरोजपुर स्थान से निकाली गई है। यह राजस्थान के बीकानेर राज्य में सिंचाई करती है।

उत्तर प्रदेश की नहरे

(१) ऊपरी गंगा नहर—यह नहर हरिद्वार से निकाली गई है। हरिद्वार से अलीगढ़ तक भूमि का ढाल अधिक होने के कारण कई स्थानों पर बाध लगाकर झरने बनाये गये हैं जिनसे विजली बनाने का काम लिया जाता है। यह १७२७ लाख एकड़ पर सिंचाई करती है।

(२) निचली गंगा की नहर—यह नहर हरिद्वार (जिला बुलन्दशहर) से गंगा नदी से निकाली गई है। इस नहर तथा इसकी शाखाओं की लम्बाई लगभग ५१२४ मील है और यह लगभग ११५२ लाख एकड़ भूमि को सींचती है। यह नहर कासगँज के पास ऊपरी नहर से मिल गई है जिससे ऊपरी नहर में पानी की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। परन्तु यह फिर उससे अलग होकर कानपुर व इटावा जिलों में सिंचाई करती है।

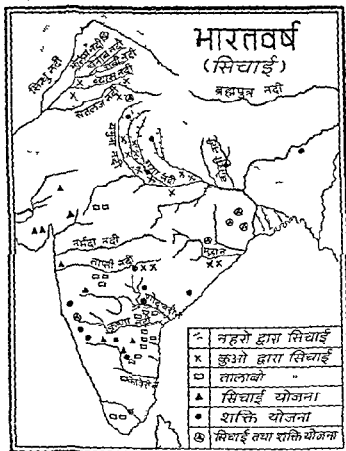
(३) पूर्वी जमुना नहर—यह नहर ताजवाला जिला (अम्बाला) पर जमुना नदी से निकाली गई है। इसकी लम्बाई ६०० मील है तथा यह ४ लाख एकड़ भूमि को सींचती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, राय, मेरठ जिलों में इसी नहर से सिंचाई होती है। अन्त में नहर दिल्ली के पास जमुना नदी से मिल जाती है। अभी हाल ही में इसको चौड़ा करके अधिक भूमि को सींचने की व्यवस्था की गई।

(४) आगरा नहर—यह नहर दिल्ली के दाईं ओर ११ मील नीचे ओखला स्थान से निकाली गई है। इसके द्वारा आगरा, मथुरा जिलों तथा भरतपुर रियासत

के कुछ भागों में सिंचाई की जाती है। यह लगभग १००० मील लम्बी है और लगभग ४४७ लाख एकड़ भूमि को सींचती है।

(५) शारदा नहर—यह बनवसा (बमदेव) स्थान में शारदा नदी में से निकाली गई है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। इसकी अनेक छोटी छोटी शाखाएँ हैं। इसमें मुख्यतः अवध व रुहेलखण्ड प्रदेश में सिंचाई होती है। इसके द्वारा लगभग १६७२ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होती है।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में बतवा नहर, केन नहर, घागरा नहर, घासन नहर, मान नहर आदि भी हैं।



मद्रास की नहरें

मद्रास के उत्तरी भाग में कुछ छोटी छोटी नहरें अकाल के समय मनुष्यों की सहायता करने की दृष्टि में बनाई गई हैं। पैरियर नहर प्रणाली इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली है। पैरियर नदी पहले अरब सागर में जाकर गिरती थी परन्तु

अब यह मधुरा जिले को पानी देती है। इसके द्वारा लगभग १ ४३ लाख एकड़ भूमि सींची जाती है। इस राज्य की दूसरी नहर कावेरी मेदूर प्रोजेक्ट है जिससे कावेरी डेल्टे में ३ ०१ लाख एकड़ पर सिंचाई होती है।

बम्बई की नहर

बम्बई राज्य में दो महाबूलों बांध हैं—

(१) भदारदारा बांध (Bhandardara Dam)—यह बांध भारत में सबसे बड़ा बांध है। यह गोदावरी की एक सहायक नदी का पानी लेता है और अहमदनगर जिले में ६० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई करता है।

(२) लायड बांध (Lloyd Dam)—यह कृष्णा नदी की एक सहायक नदी पर बनाया गया है और पूना तथा शोलानुर जिलों की सिंचाई करता है।

भारतवर्ष में सिंचाई के वर्तमान साधन व भविष्य की योजनाएँ—

भारतवर्ष में १८५५-५६ में ३१ ८२ करोड़ एकड़ पर खेती होती थी। इस क्षेत्र में से ५ ६२ करोड़ एकड़ भूमि पर सिंचाई होती थी। यह क्षेत्र कुल का १८ प्रतिशत के लगभग था। इसमें से लगभग २ ३१ करोड़ एकड़ भूमि पर नहरों से, १ ०६ करोड़ एकड़ पर तालाबों द्वारा, १ ६६ करोड़ एकड़ पर कुओं द्वारा तथा ५५ लाख एकड़ पर अन्य साधनों द्वारा सींची जाती थी। भारतवर्ष में संसार के सब देशों में अधिक क्षेत्र पर सिंचाई होती है। भारतवर्ष का सींचा हुआ क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र अमरीका का २ ३ गुना है। यह क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र अमरीका, रूस, जापान तथा इटली के कुल सींचे गये क्षेत्र से भी बड़ा है। परन्तु इन सब देशों का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से दस गुना है। परन्तु अभी तक भारतवर्ष में सिंचाई के लिये बहुत कुछ करना शेष है। अभी तक हमारे देश की नदियों का ५ ६ प्रतिशत पानी उपयोगी कामों में प्रयोग किया जाता है। शेष ८४४ प्रतिशत पानी समुद्र में बहकर चला जाता है। अब इस पानी को काम में लाने के लिये देश के भिन्न-भिन्न भागों में ३०० योजनाएँ चल रही हैं। जिन पर लगभग ७६५ करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है। इनमें से १२ को हम बड़ी योजनाएँ कह सकते हैं और शेष को छोटी बड़ी योजनाओं पर १० करोड़ रुपये से अधिक, मध्यम श्रेणी की योजनाओं पर २ करोड़ से १० करोड़ तक तथा छोटी योजनाओं पर २ करोड़ रुपये से कम खर्च होगा। यह योजनाएँ ५ से १० वर्ष तक पूरी होने की आशा है। इन योजनाओं से योजना के अन्तिम वर्ष में ८६ लाख एकड़ भूमि के सींचे जाने की आशा है। परन्तु जब यह योजनाएँ पूर्ण रूप से उन्नत हो जायेगी तब उनसे २ करोड़ २० लाख भूमि सींची जायेगी। इन योजनाओं से अप्रतिष्ठित ढाँचा से लाभ प्राप्त होने का आशा है—

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)	अतिरिक्त सिंचाई (एकड़ में)	अतिरिक्त संचित (किलोवाट में)
१९५१-५२	८५	६४६,०००	१८,०००
१९५२-५३	१२१	१,८६०,०००	२३६,०००
१९५३-५४	१२७	३,५५५,०००	७२४,०००
१९५४-५५	१०७	३,७४६,०००	८७५,०००
१९५५-५६	७८	८,५३३,०००	१०८२,०००
अन्त में		१६,८४२,०००	१,४६५,०००

जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल सींचा हुआ क्षेत्र ६७ मिलियन एकड़ होगा दूसरी योजना के अन्त तक वह ८८ मिलियन एकड़ होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की कुछ सिंचाई की योजनाएँ दूसरी योजना में भी चलती रहनी हैं। इनके अतिरिक्त कुछ नई योजनाएँ भी चालू की जायेंगी। दूसरी योजना में सिंचाई व बाढ़ नियन्त्रण के लिये ४८६ करोड़ रुपये रखे गये हैं।

इन योजनाओं में से कुछ निम्नलिखित हैं—

(१) भाबडा नगर योजना (पंजाब)

इस योजना के अन्तर्गत सतलज नदी पर भाबडा नामक गाँव में एक बाँध बनाया गया है। इससे ३६ लाख एकड़ भूमि सींचे जाने की आशा है तथा इससे १३ लाख टन अतिरिक्त गन्ना प्राप्त हो सकेगा। कुछ इलाकों में तो इससे सिंचाई भी होने लगी है। १९५७-५८ में इस नहर से पंजाब और राजस्थान में लगभग १५ लाख एकड़ पर सिंचाई हुई। ६६७ लाख एकड़ भूमि पर इस का अधिकार है। पूर्ण होने पर यह ३६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई करेगी।

(२) दामोदर घाटी योजना (बङ्गाल और बिहार)

बङ्गाल और बिहार की सरकारों ने मिलकर एक 'दामोदर घाटी की संयुक्त तथा बहु-उद्देश्य वाली उन्नतिकारी योजना' (Unified Multipurpose Damodar Valley Development Project) बनाई है। इस योजना के अन्तर्गत दामोदर नदी पर एक बाँध बनाया जाय वाला है जिससे बाढ़ रोकने, सिंचाई करने, बिजली पैदा करने आदि का काम लिया जायेगा। इस योजना से लगभग १० लाख एकड़ भूमि की पानी मिलेगा और दामोदर नदी में जो बाढ़ आती रहती है वह रुक जायेगी। १९५२-५३ में इससे ५ हजार एकड़ भूमि को पानी मिला। दामोदर घाटी के चार बाँध हैं जिनमें से तलैया बाँध का उद्घाटन प्रधान मन्त्री द्वारा २१ फरवरी १९५३ ई० को हो चुका है। इससे २४,००० एकड़ खरीफ तथा ७५,००० एकड़ रबी की फसल सींची जायेगी। इसका दूसरा बाँध कोनर बाँध है जिसका उद्घाटन मई १९५४ में हो चुका है। इससे १,०४,००० एकड़ भूमि सींची जायेगी। इसके तीसरे बाँध को १९५७ ई० में पूरा किया गया।

(३) हीराकुड योजना (उड़ीसा)

उड़ीसा राज्य में महानदी पर हीराकुड नामक योजना बनाई गई है। इससे अन्तर्गत टीका पारा, नरज और हीराकुण्ड नामक स्थानों पर महानदी पर बांध बांधने की योजना है। इससे लगभग २२ ½ लाख एकड़ भूमि सिंची जायेगी। इस योजना की काफी प्रगति हो चुकी है। १९५६ ई० में बारगड नहर से पानी छोड़ दिया गया है।

(४) कोसी योजना (बिहार और नेपाल)

इस योजना के अन्तर्गत एक बांध नेपाल में और दूसरा नेपाल और बिहार की सीमा पर बनाया जायेगा। इसमें पहला बांध नेपाल की १० लाख एकड़ भूमि को और दूसरा बांध बिहार की १३ ९७ लाख एकड़ भूमि को सिंचेगा।

(५) तुङ्गभद्रा योजना (आंध्र, मैसूर)

इस योजना में मैसूर, आंध्र व हैदराबाद की ८२ लाख एकड़ भूमि सिंची जायेगी और २१०,००० टन अतिरिक्त गन्ना प्राप्त हो सकेगा।

(६) ककरापारा योजना (बम्बई)

इस योजना से मूरत व बरोच की ६,५२,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी। यह जून १९३५ में चालू हो चुकी है। इससे १६०,००० टन अतिरिक्त गन्ना तथा १६००० टन अतिरिक्त कपास मिल सकेगी।

(७) पीपरी योजना (उत्तर प्रदेश व रीवा)

इस योजना से १९ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जाने की आशा है। इनके अतिरिक्त द्वितीय योजना काल में २० नई योजनाएँ चालू की जायगी जिनमें से केवल १८ पर ५ करोड़ रु० से अधिक खर्च होगा। इन सब पर ४५० करोड़ रु० खर्च होंगे जिसमें से लगभग आधा खर्च १९६०-६१ तक हो जायेगा।

बड़ी-बड़ी योजनाओं के अतिरिक्त योजना में बहुत सी छोटी छोटी योजनाय भी हैं। इनमें पुराने तालाबों व कुओं से बिजली के पम्पो द्वारा पानी निकालना, छोटे छोटे बांध अथवा बम्बे बनाना आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार ८२ मिलियन एकड़ पर इन योजनाओं द्वारा सिंचाई हो सकेगी। इनके अतिरिक्त छोटी-छोटी सहायक योजनाओं से ३ मिलियन एकड़ पर सिंचाई हो सकेगी। इन पर ३० करोड़ रु० खर्च होगा। इस प्रकार छोटी छोटी योजनाओं से ७७ करोड़ रु० खर्च करके ११२ मिलियन एकड़ पर सिंचाई हो सकेगी। इस प्रकार सब प्रकार की योजनाओं से १९७ मिलियन एकड़ पर सिंचाई करने की योजना है। इनसे ४२ मिलियन टन अतिरिक्त गन्ना प्राप्त हो सकेगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में १६३ मिलियन एकड़ भूमि पर सिंचाई का प्रवन्ध किया गया जिसमें से १० मिलियन एकड़ छोटी तथा ६३ मिलियन एकड़

बड़ी योजनाओं द्वारा हुआ। बड़ी व छोटी सभी प्रकार की योजनाओं की काफी प्रगति हुई है। बड़ी योजनाओं की प्रगति के विषय में हम पहले ही लिख चुके हैं। छोटी योजनाओं में १५६३४८ कुएँ बनाये गये। ६८४७२ कुओं की मरम्मत की गई, ३१३४ तालाब बनाये गये तथा ५७८८ की मरम्मत की गई, ३८४८५ रूट कुएँ बनाये गये, ३३८७२ बाँध तथा बम्ब्रे बनाये अथवा उन्नत किये गये, १८६२४ पम्प नदियों तथा बम्बों पर बनाये गये। इनके अतिरिक्त १४१२४ सिंचाई की दूसरी योजनाएँ भी पूरी की गई।

Q 20 Describe plans contemplated to meet the manurial deficiencies of our soil.

प्रश्न २०—हमारी मिट्टी की खाद सम्बन्धी कमी को पूरा करने की जो योजनाएँ विचार की गई हैं उनको बताइये।

उत्तर—यदि हम राष्ट्रीय आधार पर खेती की उत्पत्ति को बढ़ाना चाहें तो उसके लिये खाद का एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। खाद की आवश्यकता न केवल खाद्य पदार्थों के लिये ही होती है वरन् व्यापारिक फसल जैसे जूट, कपास आदि के लिये भी होती है। नदी योजनाओं के पूर्ण होने पर तो खाद की और भी अधिक आवश्यकता होगी क्योंकि बिना खाद के केवल पानी की सहायता से फसल नहीं उगाई जा सकती। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में आशा की जाती है कि देश में खाद की सहायता से २५ लाख टन अधिक गन्ना उत्पन्न हो सकेगा जो कि योजना-काल में अधिक उत्पन्न होने वाले गन्ने का २० प्रतिशत होगा। इसके अतिरिक्त यह भी बात है कि बहुत पुराने समय से प्रयोग में आने के कारण भारतवर्ष की मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपनी न्यूनतम सीमा पर पहुँच गई है। भूमि की इस खाई हुई शक्ति को प्राप्त करने के लिये हमको बहुत अधिक खाद की आवश्यकता है क्योंकि कहावत है कि जब तक भूमि रहेगी तब तक बीज का समय तथा फसल कमी समाप्त न होगी।

भूमि पर खेती करने से उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। इस कमी की पूर्ति के लिये ही खाद देने की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु सब स्थानों में एकसी खाद नहीं दी जा सकती क्योंकि सब स्थानों की मिट्टी में एक से ही पदार्थों की कमी नहीं होती। जिस मिट्टी में जिस-जिस प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार की उस मिट्टी में खाद देनी पड़ती है। भारतवर्ष की मिट्टी में (Nitrate), फोस्फेट (Phosphate), कार्बोनेट (Carbonates), सल्फेट (Sulphate), चूना (Calcium) तथा नमी (Humus) की कमी है। इसलिये भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि इन सब चीजों को भूमि

की उबंरा शक्ति को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि इन सब चीजों को भूमि को दिया जाये। खाद कई प्रकार की होती है जैसे, (१) गोबर की खाद, (२) मल-मूत्र की खाद, (३) हड्डी की खाद, (४) खनी की खाद, (५) हरी खाद, (६) मछलियों की खाद, (७) रासायनिक खाद आदि।

(१) गोबर की खाद—हमारे देश में सबसे अधिक गोबर की खाद काम में लाई जाती है। परन्तु यह खाद भी मात्रा में कम है। पश्चिमी बङ्गाल के हुगली तथा चौबीस परगने के क्षेत्र में किये गये एक अनुसन्धान से पता चला है प्रति एकड़ गोबर की खाद का औसत हुगली में १२४ मन तथा चौबीस परगने में ११४ मन है जबकि आवश्यकता फसल के अनुसार १०० मन से ४०० मन की है। यह खाद हमारी मिट्टी को नत्रजन (Nitrogen) तथा नमी प्रदान करती है। परन्तु हमारे देश में इस खाद को ठीक प्रकार तैयार नहीं किया जाता तथा बहुत सी खाद उपलो के रूप में नष्ट कर दी जाती है। उपलो के रूप में नष्ट की गई खाद का अनुमान २५० मिलियन टन से लेकर ५५० मिलियन टन तक है। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि जहाँ तक हो किसान को वन विभाग से सस्ती लकड़ी मिल जाय। इसके अतिरिक्त किसानों को बताया जाये कि खाद किस प्रकार तैयार की जा सकती है। अच्छी खाद तैयार करने के लिये किसानों को गोबर कई महीनों तक गड्ढों में रखना पड़ेगा। गड्ढों में रखने से गोबर ठीक प्रकार सड़ जाता है और उससे अच्छी खाद तैयार होती है।

(२) मल-मूत्र की खाद—गोबर के अतिरिक्त मनुष्य के मल-मूत्र से भी अच्छी खाद तैयार हो जाती है। इस खाद में नाइट्रट, पुटास और फामफेट बहुत अधिक मात्रा में होती है। परन्तु अभी तक इसका कोई विशेष उपयोग नहीं किया गया है। गाँव में तो इसका कोई उपयोग नहीं किया जाता और शहरों में भी यह बहुत कम काम में लाई जाती है। यदि गावों में सार्वजनिक शौच-कूप (Pit latrines) बना दिये जायें तो गाँव गन्दगी से भी बच सकता है और उससे अच्छी खाद भी मिल सकती है। बड़े बड़े शहरों में जहाँ नाल और नदियों का गन्दा पानी बहुत बड़ी मात्रा में एकत्र होता है। वहाँ वैज्ञानिक क्रियाओं द्वारा मल को दुर्गन्धरहित और सूखा बनाया जा सकता है। उसके उपयोग में किसान को कोई आपत्ति न होगी।

आजकल इस ढङ्ग से खाद तैयार करने का काम बड़े जोरों से चल रहा है। सामूहिक विकास योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना वाले क्षेत्रों में २४ लाख गड्ढे खोदे जा चुके हैं। इस कार्य के लिये छाटी हुई ३००० जगहों में से १७२६ जगहों में १९५३-५४ में खाद बनाने का काम चल रहा था और शहर में इस प्रकार १८५० लाख टन खाद तैयार की गई है।

खाद तैयार करने का जापानी ढङ्ग—आजकल हमारे देश में खाद तैयार करने के इस ढङ्ग पर बड़ा जोर दिया जा रहा है। इस ढङ्ग के अनुसार कूड़ा करकट,

सड़ी गली सब्जी व फल, हड्डियाँ, पखाना, गोबर, बीट आदि को एक जगह मिला दिया जाता है और उससे खाद तैयार की जाती है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि १००० जनसंख्या से अधिक वाले ४२२३ नगरों के सूड़े करकट से १ करोड़ मन् अच्छी खाद तैयार हो सकती है और उससे १½ या २ करोड़ टन गन्ना प्रतिवर्ष उत्पन्न हो सकता है।

१९५७-५८ में २२२ लाख टन कम्पोस्ट खाद तैयार की गई। १९५८-५९ का ध्येय बिन्दु २६४० लाख टन है। १९५७-५८ में १९२५ लाख टन कम्पोस्ट बाँटा गया। प्रमुख शहरों में १५३० लाख खाद के पानी का प्रयोग करने के लिये Sewage Utilization Schemes जारी रखी गई। स्थानीय खाद की कमी को दूर करने के लिये चार योजनाएँ कार्यान्वित की गई जिससे कि (१) राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में स्थानीय खाद के साधनों का अधिक अच्छा उपयोग हो सके (२) ग्राम पंचायतों में कम्पोस्ट खाद उत्पन्न की जा सके, (३) छोटे-छोटे गाँवों में पायलेट आधार पर नाईट-सॉयल तैयार हो सके, (४) हरी खाद के प्रयोग का प्रचार किया जाय। इस योजना के अन्तर्गत १५१९ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में तथा विभिन्न राज्यों में ७६२ पंचायतों में इस कार्य को पूरा करने की अनुमति दी गई। बहुत से राज्य सरकारों ने हरी खाद का प्रचार करने के लिये हरी खाद की बीज बाँटे। बिहार में नाईट-सॉयल तथा गाव की गन्दगी से कम्पोस्ट तैयार करने के लिये एक पायलेट प्रोजेक्ट तैयार किया गया।

(३) हड्डियों की खाद—हमारे देश में धार्मिक भावनाओं के कारण हड्डियों की खाद का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। यहाँ से प्रतिवर्ष बहुत सी हड्डियाँ तथा उनका चूरा विदेशों को भेजा जाता है। परन्तु यदि हड्डियों को खाद के रूप में लाया जाये तो देश को बहुत लाभ हो सकता है।

(४) खली की खाद—तेल निकालने के पश्चात् जो खली बचती है उसका भी खाद के रूप में काम में लाया जा सकता है। परन्तु अभी तक हमारे देश में खली की खाद का बहुत कम प्रयोग हुआ है। इसका पहना कारण यह है कि यह भारतीय किसान की गरीबी के कारण उसकी खर्च-शक्ति के बाहर है। दूसरे, हमारे देश से प्रतिवर्ष अधिकतर तेल निकालने के बीजों का निर्यात कर दिया जाता है। इसलिय खली की खाद यहाँ कम मिलती है। यदि हमारे देश से तेल निकालने के बीजों का निर्यात न किया जाय तो इससे बड़ा लाभ होगा।

(५) हरी खाद—उन स्थानों में जहाँ पानी आसानी से मिल सकता है अथवा जहाँ वर्षा शून्य होती है, हरी खाद का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ पसला, जैसे मूँग, अरहर, सनई, देवा आदि में नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होती है। यदि इन पसलों को उगाकर उनके कुछ बड़ा हो जाने पर खेत में हल चला दिया जाय तो बहुत अच्छी खाद मिल सकती है। परन्तु इसमें दो कठिनाइयाँ हैं। पहली, यह कि यह बहुत महंगी है और किसान अपनी निर्धनता के कारण उसको काम में नहीं ला

सकना । दूसरे, यह पानी बहुत चाहती है और हमारे देश में पहले ही पानी की कमी है इसलिये यह कम काम में लाई जाती है ।

(६) मछलियों की खाद—मछलियों का भी उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है । परन्तु इस प्रकार की खाद भारत के समुद्र-तट के मैदानों में ही प्रयोग की जा सकती है । समुद्र के दूर के मैदानों में इस खाद का प्रयोग नहीं हो सकता ।

(७) रासायनिक खाद—इनके अतिरिक्त सल्फेट ऑफ अमोनिया तथा नाइट्रेट का भी उपयोग खाद के रूप में किया जा सकता है । हमारे देश में इस प्रकार की खाद तैयार करने के दो कारखाने हैं । एक तो बिहार के सिदरी नगर में और दूसरा ट्रावनकोर में है । परन्तु यह खाद बहुत महंगी है । इसलिये इसका प्रयोग अभी तक हमारे देश में कम किया जाता है । १९५३ ई० में हमारे देश में ४३ लाख टन रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया । योजना में १९५५-५६ के लिये ६१ लाख टन का ध्येय रखा गया है । यह ध्येय पूरा हो चुका है । १९५६ में इस दश में ६७५,००० टन अमोनिया सल्फेट तथा १ लाख टन सुपर फास्फेट का उप-भाग किया जा रहा था । दूसरी योजना काल के लिये इनके उपभोग का ध्येय क्रमशः १८५ लाख टन तथा ७० लाख टन रखा गया है । यह अनुमान लगाया जाता है कि खाद के अधिक उपभोग के कारण देश में २५ लाख टन अतिरिक्त गन्ना उत्पन्न हो जायगा । खाद की इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये तीन नई फैक्ट्री खोली जायेंगी । यह नदल, रुकैला तथा नैवेली में स्थित होगी । दिसम्बर १९५७ ई० में श्री अजित प्रसाद खाद्य मन्त्री ने यह स्वीकार किया है कि इस देश में खाद की पूर्ति आवश्यकता में २५ प्रतिशत है तथा अगले वर्ष की कमी का अनुमान ४०% है । इस कमी का कारण यह बताया गया है कि विदेशी विनिमय की कमी के कारण इसका आयात नहीं किया जा सकता । १९५८-५९ में इस प्रकार की खाद की मांग ६ लाख टन थी परन्तु देश की पूर्ति ६०२ लाख टन थी जिसमें से ३३५ लाख टन सिदरी से ०६५ लाख टन देशी साधनों से तथा २०२ लाख टन का आयात किया गया ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में यद्यपि किसान नई प्रकार की अच्छी खाद काम में ला सकता है परन्तु वह उनमें से बहुत सी काम में नहीं ला सकता जैसे, खली, हरी तथा रासायनिक खाद तो वह महंगी होने के कारण काम में नहीं ला सकता । इसके अतिरिक्त ये खाद पानी बहुत चाहती है और हमारे देश में सिंचाई के साधनों की पहले ही कमी है । इसलिये ये खाद कम काम में लाई जाती है । हड्डी व मछली की खाद किसान धार्मिक भावनाओं के कारण काम में नहीं लाता । मल-मूत्र से भी खाद तैयार नहीं की जाती । इन सबके पश्चात् केवल गोबर की खाद ही बनती है । जिसको किसान काम में लाता है । परन्तु इसको ठीक प्रकार तैयार न कर सकने के कारण इससे इतना अधिक लाभ नहीं पहुँचता जितना कि

पहुँचना चाहिये। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि किसान को खाद तैयार करने का ढङ्ग बताया जाय और विशेषतः उसको जापानी ढङ्ग से खाद तैयार करने का ढङ्ग तथा उस खाद का लाभ बताया जाय। वन-विभाग को भी गावों में सस्ती लकड़ी बेचनी चाहिये जिससे कि किसान गोबर को उपलो के रूप में न जलाये। यह सब करने से हमारे देश में खाद की कमी दूर हो सकती है।

खाद जांच समिति की सिफारिश

ज्ञात हुआ है कि खाद जांच समिति ने देश में खाद के उत्पादन और नियंत्रण के लिये एक केन्द्रीय बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की है। समिति का मुझाव है कि देश की तमाम फ़ैक्टरियाँ, चाहे वे सरकारी हों अथवा सरकार से सहायता प्राप्त करती हों, बोर्ड के आधीन कार्य करें।

केन्द्रीय उत्पादक मन्त्री श्री के० सी० रेड्डी ने यहाँ बताया कि भाखड़ा नगर के खाद कारखाना बनाने के लिये विदेशी फर्मों के जो प्रस्ताव आये हैं उन पर विचार के लिये एफ़ टैक्निकल समिति नियुक्त की गई है जिसके अध्यक्ष डा० ए० नागराज राव हैं। इस कारखाने का लक्ष्य प्रतिवर्ष दो लाख टन अमोनियम नाइट्रेट तैयार करना होगा। रुरकेला (उड़ीसा) में भी एक फ़ैक्टरी स्थापित होगी जिससे ४,४२,००० टन नाइट्रोलाइम स्टोन उत्पन्न होगा।

ज्ञात हुआ है कि खाद जांच समिति ने यह भी सिफारिश की है कि दक्षिणी आरकोट में नैवेली नामक स्थान पर अथवा विजयवाड़ा में एक और फ़ैक्टरी खोनी जाय।

दो अन्य कारखाने ट्राम्बे व इटारसी में भी खोलने का मुझाव दिया गया है।

खाद से लाभ—रासायनिक खाद के प्रयोग से सभी प्रकार की फसलों को लाभ होता है। अनुभवों से पता लगा है कि अमोनियम सल्फ़ेट तथा सुपर फास्फ़ेट का प्रयोग धान उगाने में करने में क्रमशः २७ रु० तथा ११ रु० प्रति एकड़ का लाभ होता है। नवजन के प्रयोग से लाभ १०० प्रतिशत है। इसका प्रयोग पंजाब में करने से ५० रु० प्रति एकड़ का लाभ हुआ है। फास्फोरस का प्रयोग मध्यम काली भिट्ठी तथा लाल भिट्ठी से क्रमशः ५० रुपये तथा ३२ रुपये प्रति एकड़ का लाभ हुआ है।

Q. 21. 'The cattle problem is the crux of Indian agriculture.' Appraise the truth of this statement.

प्रश्न २१—'पशु समस्या भारतीय कृषि की पहेली है।' इस कथन को सत्यता का मूल्यांकन कीजिये।

पशुओं का महत्व—पशु भारतीय कृषक का सबसे बहुमूल्य धन है। एम० एल० डालिङ्ग ने ठीक ही कहा है "बिना उनके खेत बिना जुते पड़े रहते हैं, गोदाम और

खती खाली रहती है, खाने-पीने का आधा स्वाद जाता रहता है, क्योंकि एक माँस न खाने वाले देश में इससे खराब बात क्या हो सकती है कि लोगो को न दूध मिले, न मक्खन, न घी ?” भारतवर्ष में पशुओं का महत्व इस कथन से समझ में आ सकता है ।

वास्तव में भारतवर्ष में पशु किसान का एक मात्र सहारा है । बिना उसके वह कोई काम नहीं कर सकता । उसकी सहायता से वह अपने खेतों को जोतता है । उसी के द्वारा वह कुएँ से पानी निकालकर अपने खेतों को सींचता है । उसी की खाद को वह खेतों में देकर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है । उसी के द्वारा वह भत्से से गेहूँ को अलग करता है । उसी को गाड़ी में जोतकर वह शहर में अपनी फ़ैसल को बेचने के लिये ले जाता है । उसी को गाड़ी में जोतकर वह भाड़ा कमाता है उसी के द्वारा मक्खन, पनीर का उद्योग चलाकर अपनी आय को बढ़ाता है । उसी के दूध व घी से वह अपने खाने की कमी को पूरा करता है । इस प्रकार भारतीय कृषक के लिये पशु का वही महत्व है जो उसके लिये उसके हाथों और पैरों का है । बिना पशु के भारतीय किसान कुछ भी नहीं कर सकता ।

पशुओं से भारत की राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष १,००० करोड़ रुपये की वृद्धि होती है । कुल राष्ट्रीय आय का ३०० करोड़ रुपया दूध तथा उससे सम्बन्धित उद्योगों से, ४० करोड़ रुपया खालों व चमड़े से, २७० करोड़ रुपया खाद से, १६१ करोड़ रुपया सामान ढोने से तथा ३००-४०० करोड़ रुपये का क्षेत्र परिश्रम के रूप में प्राप्त होता है ।

पशुओं की होम दशा—परन्तु भारतवर्ष में पशुओं का इतना महत्व होते हुए भी उनकी दशा बड़ी खराब है । वे निर्बल और आधे भूखे रहते हैं । उनकी कार्य शक्ति बहुत कम है । गायों ने दूध तक देना छोड़ दिया है । बैल नाटे निर्बल तथा दुबले-पतले होते हैं । वे खेती के योग्य नहीं हैं । इसका कारण यह है कि भारतवर्ष में उनकी संख्या बहुत अधिक है । १९५६ की जनगणना के अनुसार हमारे देश में १५.८६ करोड़ गायें, बैल तथा ४ करोड़ ४६ लाख भैंसे थीं तथा पशुओं की कुल संख्या ३० करोड़ ६५ लाख थी । भारतवर्ष में पशुओं की संख्या संसार की $\frac{2}{3}$ तथा एशिया की $\frac{1}{2}$ है । ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारतवर्ष में प्रति १०० एकर बोये हुये क्षेत्र के पीछे ३७ पशु हैं । पश्चिमी बङ्गाल के हुगली तथा ३४ परगना क्षेत्रों में किये गये एक अनुसंधान से पता चला है कि हुगली जिले में पशुओं की संख्या के प्रति १०० एकर के पीछे ५८ है तथा २४ परगनों में ६० है । इसके विपरीत हालैंड में केवल ३८ और मिन्न में केवल २५ ही हैं ।

कृषि कमीशन ने बताया है कि पशुओं की गणना से पता चलता है किसी जिले में बैलों की संख्या उनकी माँग पर निर्भर होती है । किसी स्थान पर पशुओं को पालने की जितनी कम सुविधाएँ प्राप्त हैं उतने ही अधिक पशु वहाँ पर रखे जाते हैं । जैसे ही पशुओं की संख्या बढ़ती है वैसे ही पशुओं को चारा कम मिलता

है। चारे की कमी के कारण पशु कमजोर हो जाते हैं। पशुओं की कमजोरी के कारण और अधिक पशु रखने पड़ते हैं और पशुओं की अधिकता के कारण चारे की समस्या और भीषण हो जाती है। इस प्रकार एक कुचक्र (Vicious circle) बन जाता है।

पशुओं की होने दशा के कारण—पशुओं की हीन दशा के तीन कारण हैं—(१) चारे की कमी, (२) नस्ल का खराब होना तथा (३) पशुओं के रोग।

(१) चारे की कमी—भारतवर्ष में पशुओं को खिलाने के लिये चारे की बड़ी कमी है। यहाँ पर जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ती जाती है वैसे ही फसलें उगाने के लिये अधिक भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इसके फलस्वरूप चाराहो की कमी होती जाती है। चाराहो की कमी होने के कारण चारे की समस्या बढ़ती जाती है। चाराहो की कमी होने पर भी किसान ने पशुओं को पालने के ढङ्ग को नहीं बदला। वह दूध देने वाले पशुओं को केवल तभी तक पर्याप्त भोजन देता है जब तक कि वे दूध देते हैं, उसके पश्चात् वह उनको चरने के लिये छोड़ देता है। जब तक हमारे देश में चाराहो अधिक थी तब तक तो पशु अपना पट भर लेते थे परन्तु अब वे ऐसा नहीं कर सकते। देखने में आता है कि भारतवर्ष में दिसम्बर से लेकर जौलाई तक चारे की बहुत कमी रहती है। मार्च और जून के बीच में तो घास भी गर्मी के कारण सूख जाती है। इसलिये इस समय पशुओं को बहुत कम चारा मिल पाता है। वे इधर-उधर खाने की तलाश में घूमते रहते हैं और जो कुछ भी उनको इधर-उधर मिलता है उसी को खा जाते हैं। भूखे पशुओं को कपड़ा, कागज, गली-सड़ी चीजें तक खाते हुये देखा गया है। पशुओं की यह दशा वास्तव में बड़ी खराब है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

भारत में चारे की क्या स्थिति है इस का पता Indian Council of Agricultural Research द्वारा छापी गई एक पुस्तक 'Dairying in India' से लग सकता है। इसके पृष्ठ २ पर इस प्रकार लिखा है—पशुओं की एक पर्याप्त बड़ी सच्चा सिवाय वर्षा ऋतु के लघुकालीन समय के या तो कम चारा पाती है या रस भरा चारा पाती ही नहीं। प्राकृतिक घासों के बड़े-बड़े क्षेत्र या तो काम में लाये ही नहीं जाते या बुरी प्रकार से काम में लाये जाते हैं। सूखे चारों की स्थिति कुछ ठीक है परन्तु वे कम शक्ति प्रदान करने वाले होते हैं। साइलेज अथवा सुरक्षित हरे चारे की उपयोगिता जो कि गर्मी तथा कमी के समय काम में लाया जा सकता है, किसानों को भाव्य ही नहीं। खली, बिनीला, कोकर आदि चीजें लगभग दुर्लभ हैं। हरे चारे, सूखे चारे तथा खली आदि की वर्तमान पूर्ति पशुओं की पौष्टिक आवश्यकता का एक छोटा अंश ही प्रदान कर सकती है। नमक तथा दूसरी खनिज पदार्थों का उपयोग बहुत कम है। यह भी कहा जा सकता है कि पानी जो कि पशुओं का स्वास्थ्य तथा निरन्तर दूध प्राप्त करने के लिये आवश्यक है गर्मी के दिनों में प्राप्त नहीं होता।

कीटिङ्ग (Keating) ने ठीक ही कहा है 'भारतवर्ष में लोगों के सीखने के लिये शायद ही कोई ऐसा सबक इतना महत्वपूर्ण होगा जितना कि चारे की फसल उगाना, उचित रूप से उठाकर रखना तथा मितव्ययिता से प्रयोग में लाना ।

चारे की समस्या को दो प्रकार से सुलझाया जा सकता है—(अ) चरागाहों को बढ़ाकर, (ब) वर्तमान भूमि पर अधिक चारा उगाकर । कृषि विशेषज्ञों तथा कृषि कमिशन की राय है कि चरागाहों की भूमि को नहीं बढ़ाया जा सकता । इसलिये वर्तमान भूमि पर ही अधिक से अधिक चारा उत्पन्न करने के लिये हमको कई उपाय करने पड़ेंगे । पहले, गाँव के आस-पास बेकार भूमि पर घास उगाई जा सकती है । दूसरे, गाँव के चरागाहों पर ग्राम पंचायत का नियन्त्रण होना चाहिये जिससे कि पशुओं की नियन्त्रित चराई की जा सके । तीसरे, यदि ज्वार, बाजरा आदि का साइलेज बनाकर पशुओं को खिलाया जाये तो बहुत अच्छा होगा । चौथे, जहाँ सिंचाई का प्रबन्ध है वहाँ किसानों को चारे की फसल उगानी चाहिये । पाँचवें, रिजका और क्लोवर आदि घासों बिना किसी मुख्य फसल का त्याग किये जल्दी से उगाई जा सकती है । छठे, चारे की समस्या सुलझाने में वन-विभाग भी बहुत सहायता कर सकता है । वनों की घास काटकर रेलों द्वारा (यदि उनका भाड़ा सस्ता हो जाय) देश के उन भागों में भेजी जा सकती है जहाँ उसकी कमी है ।

(२) नस्ल का खराब होना—हमारे देश में पशुओं की नस्ल खराब है । इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर अच्छे साड़ों की कमी है । हमारे देश में यह रिवाज है कि जब किसी वृद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसके वंशज किसी बछड़े को साड़ बनाकर छोड़ देते हैं । पहले अच्छे बछड़े छोड़े जाते थे परन्तु अब उसकी नस्ल की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । इसके फलस्वरूप हमारे देश में लाखों साड़ ऐसे हैं जिनकी नस्ल खराब है तथा जो बहुत दुबले पतले हैं । जब इस प्रकार के साड़ों से बच्चे पैदा कराने का काम लिया जायेगा तो फिर नस्ल कैसे ठीक हो सकती है । क्योंकि हमारे देश में गाय को पवित्र माना जाता है इस कारण खराब गाय और साड़ों को भी नहीं मारा जाता । इसलिये उनकी नस्ल खराब है । परन्तु भैंसों के मारने के विषय में इस प्रकार की कोई पवित्र भावना नहीं है । इसलिये खराब पशुओं का वध होता रहता है । यही कारण है कि भैंसों की नस्ल गायों से अच्छी होती है और वे गायों से कई गुना दूध देती है ।

इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि साड़ों की नस्ल को सुधारा जाय । ऐसा करने के लिये हमको अच्छी नस्ल के साड़ों को छोड़ना पड़ेगा और खराब नस्ल के साड़ों को नपुंसक बनवाना पड़ेगा । इसके साथ साथ यह नियम भी बनाना पड़ेगा कि भविष्य में खराब नस्ल के साड़ न छोड़े जायें । नस्ल को सुधारने के लिये जिला थोर्डो, गोदालाओं तथा सहकारी नस्ल सुधार समितियों से भी सहायता ली जा सकती है ।

पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ६०० ऐसे प्रमुख ग्राम केन्द्र (Key Village Centres) खोलने की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक प्रमुख ग्राम केन्द्र ३-४ गावों के बीच में होगा जिसमें ३ वर्ष से अधिक आयु वाली लगभग ४०० गावें तथा ३ या ४ अच्छी नस्ल वाले साढ़ें होंगे। घूमने वाले अन्य साढ़ों को वहाँ से हटा दिया जायगा अथवा नपुंसक बना दिया जायेगा। प्रत्येक केन्द्र पर पशुओं की नस्ल दूधोत्पादन आदि का विस्तृत लेखा रखा जायगा। इनके अतिरिक्त १५० कृत्रिम प्रजनन केन्द्र (Artificial insemination centres) भी खोल जायेंगे। प्रथम योजना में देश में ५५५ प्रमुख ग्राम केन्द्र तथा १४६ कृत्रिम प्रजनन केन्द्र खोले गये। दूसरी योजना में १२५८ प्रमुख ग्राम केन्द्र तथा २४५ कृत्रिम प्रजनन केन्द्र तथा २५४ विस्तार केन्द्र खोलने की योजना है। इस योजना से २२००० उन्नत साढ़ें, ६५०,००० उन्नत बैल तथा १० लाख उन्नत गायें प्राप्त हो सकती हैं।

गो-सदन—भारत सरकार ने गो-सदन की योजना भी बनाई है। जहाँ प्रमुख ग्राम केन्द्र योजना का उद्देश्य वर्तमान पशुओं की दशा सुधारना तथा पशुओं की नस्ल को उन्नत करना है वहाँ गो-सदनों का उद्देश्य बूढ़े तथा बेकार जानवरों को अलग करना है। परन्तु इस ओर अधिक ध्यान नहीं हुआ। प्रथम योजना काल तक केवल २५ गो-सदन ही प्राप्त हुए थे। इस योजना के टोले चलने के कई कारण हैं—(१) अच्छे प्रकार के बड़े-बड़े भूमि के टुकड़ों का न मिलना। (२) जनता द्वारा सहयोग न दिया जाना। कुछ राज्यों द्वारा अपने हिस्से का धन न देना। दूसरी योजना में ६० गो-सदन खोलने की योजना है जिसमें ३० हजार पशु रख जायेंगे। १९५७-५८ तक २१ गो-सदन स्थापित किये गये तथा ७२ गो-शालाओं को गहन उन्नति के लिये छाटा गया।

(३) पशुओं के रोग—भारतवर्ष में प्रति वर्ष लाखों पशु रिडरपेस्ट, जहरवाद तथा मुँह और पंरी के रोगों से मरते हैं। इनमें रिडरपेस्ट सबसे अधिक भयंकर रोग है। रोगों के कारण पशु मरते ही नहीं हैं बल्कि जीवित बचने हैं वे बहुत दुर्बल हो जाते हैं और उसी वजह से मर जाते हैं। इस कारण किसान को अधिक पशु रखने पड़ते हैं।

पशुओं को रोग से बचाने के लिये आवश्यक है कि उनकी साफ-सुथरे स्थान पर बांधा जाय और उनकी सलाह का अच्छा पानी न पीने दिया जाय। इसके अतिरिक्त जब किसी पशु को दूध का रोग हो तो उस स्थान के सब पशुओं का टीका लगवा देना चाहिये। रोगों के कारण तथा उपचार के विषय में भारतीय पशु चिकित्सा संस्था Indian (Veterinary Research Institute) ने बहुत अधिक और उत्तम ढङ्गों की खोजें की हैं, किन्तु किसानों को अभी तक इनका लाभ नहीं पहुँचाया जा सका है। पंचवर्षीय योजना में पशुओं के रोगों को दूर करने के लिये केवल १५७ लाख रुपये का प्रबन्ध किया गया है। योजना के अनुसार ६४० पशु

चिकित्सालय खोले जायेंगे। अभी हाल ही में १७३ पशु चिकित्सालय की कमी को पूरा करने के लिये आजकल पंजाब और हैदराबाद के पशु चिकित्सालयों में दो पालिका चल रही हैं। दूसरी योजना काल में १६०० पशु चिकित्सालय खोले जायेंगे।

इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि पशुओं के बिना भारतीय कृषि सम्भव नहीं है तो भी पशुओं की हालत बड़ी खराब है और इस कारण पशु भारतीय कृषि की एक जटिल समस्या बन गये हैं। बिना पशुओं की उन्नति हुये हम भारतीय कृषि में उन्नति करने की बात सोच ही नहीं सकते। इसलिये पशुओं की उन्नति करना हमारा कर्तव्य है। यह उन्नति उनको पर्याप्त चारा देने, उनकी नस्ल सुधारकर तथा उनको रोगों से मुक्त करके की जा सकती है।

अभी हाल ही में सरकार पशुओं की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दे रही है। Indian Council of Agricultural Research के द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर विभिन्न नस्लों के पशुओं का वर्गीकरण किया गया है जिससे की अधिक महत्वपूर्ण नस्लों की शुद्धता बनी रहे। लोगों को विभिन्न प्रकार की नस्लें दिखाने के लिये अखिल भारतीय पशु प्रदर्शनी की जाती है। इसके अतिरिक्त और बहुत सी ऐसी प्रदर्शनियाँ भी की जाती हैं। आजकल सरकार की यह नीति है कि पशुओं की दूध देने की शक्ति को बढ़ाया जाय। भारतवर्ष में आजकल २०० पशु उत्पन्न करने वाले खेत हैं जिनमें से १३० सरकारी हैं। इन खेतों पर पशुओं की नस्ल को उन्नत करने का प्रयत्न किया जाता है। परन्तु अच्छी प्रकार के साड़ों की वार्षिक उत्पत्ति केवल १००० है जबकि आवश्यकता इससे कई गुनी है। परन्तु इस कमी को पूरा करने के लिये ही कृत्रिम प्रजनन केन्द्र खोले गये हैं। परन्तु इन सब प्रयत्नों के द्वारा भी कमी पूरी नहीं हुई है। आशा है सरकार इस ओर और अधिक ध्यान देगी।

Q-22 Mention the main defects in the Marketing of Agricultural products in India and state their evil effects what steps have been taken to remedy them ? Have you any suggestions to offer ?

प्रश्न २२—भारतवर्ष में खेती की फसल की बिक्री में क्या मुख्य दोष हैं और उसके क्या दुष्परिणाम हैं ? उनको दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ? क्या आपको कोई सुझाव देने हैं ?

फसल की बिक्री के दोष—जिस समय तक भारतवर्ष के गांवों का सम्बन्ध दूसरे देशों तथा विदेशों से नहीं हुआ था, फसल की बिक्री बड़े सीधे सादे ढङ्ग से हो जाती थी। पर जब से भारतवर्ष में आने जाने के मार्गों की उन्नति हुई और व्यापारिक फसलें उन्नत होने लगी, तब से फसल की बिक्री की एक समस्या भारतीय

कृषक के सामने उत्पन्न हुई। यह सत्य ही है कि उत्पत्ति करने का कार्य इतना कठिन नहीं है जितना कि उसको बेचने का। उचित रूप में फसल के बेचने में कई बातें बहुत आवश्यक हैं, जैसे जो बीज बेची जाय वह साफ और स्वच्छ होनी चाहिए और उसमें किसी प्रकार का भी मिलाव नहीं होना चाहिये। दूसरे बेचने वाले की आर्थिक स्थिति पर भी ठीक प्रकार की होनी चाहिये ताकि वह उस फसल को बेच सके जबकि उसको अच्छा मूल्य प्राप्त हो। तीसरे, आने जाने के मार्ग बहुत सुगम और तेज होने चाहिये जिससे कि कम से कम खर्च करके फसल दूर के स्थानों पर शीघ्रातिशीघ्र ले जाई जा सके। चौथे, जिन बाजारों में फसल बेची जाय उनके ऊपर ठीक प्रकार का नियन्त्रण हो। पाचवें, बेचने वाला व्यक्ति समझदार होना चाहिये जिससे कि उसको कोई धोखा न दे सके। यदि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम भारतवर्ष में फसल की बिक्री के वर्तमान दृष्ट को देखें तो हमको पता लगेगा कि हमारे देश से इनमें से कोई भी बात नहीं पाई जाती। इस कारण हमारे देश की फसल की बिक्री में अवगुण या दोष पाये जायें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

हमारे देश के कृषक अपनी फसल को गाँव के बनिये ही को जो बहुत कम किरानों को श्रृण भी देता है बेचते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पंजाब में कुच गेहूँ का ६० प्रतिशत, कुल कपास का ३५ प्रतिशत तथा कुल तिलहन का ७० प्रतिशत गाँव में ही बिकता है। उत्तर प्रदेश में ८० प्रतिशत गेहूँ, ९० प्रतिशत कपास तथा ७५ प्रतिशत तिलहन और बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल में ८ प्रतिशत तिलहन तथा ६० प्रतिशत जूट गाँव में ही बेचा जाता है। बनिया जिस समय श्रृण देता है उसी समय अगली फसल का भाव ठहरा लेता है। यदि भाव ऊँचे या नीचे होने हैं तो उसका लाभ किसान को नहीं पहुँचता। बनिया बाट भी ठीक नहीं रखता और बहुधा वह तोलने में भी बेईमानी कर जाता है। बेचारा किसान इन सबको सहन करता है क्योंकि वह ऋणग्रस्त होता है और बाजार की परिस्थिति से अनभिज्ञ होता है।

पर अब यह सवाल आता है कि किसान अपनी फसल मण्डी में क्यों नहीं ले जाता। इसके कई कारण हैं। पहला यह की किसान ऋणग्रस्त है, दूसरा यह कि किसान के पास मण्डी तक ले जाने के लिये गाड़ी भर सामान नहीं होता, तीसरा यह कि आने जाने के मार्ग सुगम नहीं हैं।

यदि किसान अपनी फसल को शहर की मण्डी में ही ले जाता है तब भी कोई विशेष लाभ नहीं होता, क्योंकि मण्डी की बिक्री में भी बहुत से दोष पाये जाते हैं। पहले, किसान को फसल को मण्डी तक ले जाने में कठिनाई पड़ेगी क्योंकि गाँव से मण्डी तक सड़क बहुधा कच्ची होती है और उनमें ऋण की गाड़ी को किसान के पतले-दुबले बैल बहुत कठिनाई से खींचते हैं। बरसात में तो जब यह सड़कें पानी से भर जाती हैं तो गाँव से मण्डी तक का रास्ता बिल्कुल बन्द सा हो जाता

गेहूँ के बेचने में किसान को केवल ६८५ प्रतिशत, चावल के बेचने में ७८८ प्रतिशत, चीनी के बेचने में ६५१७ प्रतिशत मिलता है। इस प्रकार किसान को अपने परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलता। उस फल में से बहुत सा भाग मध्यस्थ खा जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि किसान की आर्थिक अवस्था कभी सुधरने नहीं पाती। इसका प्रभाव न केवल किसान के जीवन-स्तर पर ही पड़ता है बल्कि खेती की उन्नति पर भी पड़ता है। किसान को इनका कम मिलने के कारण वह खेती की उन्नति के लिए न अच्छे बीज मोल ले सकता है, न अच्छा खाद, न अच्छे बँल और न ही वह खेती की स्थायी उन्नति कर सकता है।

दूसरे यह कि किसान को अपनी फसल प्रतिकूल स्थान पर, प्रतिकूल समय तथा प्रतिकूल भाव पर बेचनी पड़ती है। यह ता इसलिये कि किसान के पास फसल रखने के लिए कोई स्थान नहीं होता। दूसरे इसलिए है कि किसान की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह अनुकूल भाव की बात नहीं देख सकता क्योंकि उसको सिचाई व्यवस्था तथा लगान आदि देने पड़ते हैं। इस प्रकार किसान को भविष्य में भाव के बढ़ने से कोई लाभ नहीं होता।

तीसरे, यह कि किसान फसल बेचने में कुछ भी नहीं सीख सकता। न वह यह जानता है कि उपभोक्ता किस प्रकार की चीज पसन्द करते हैं और न यह कि कहा तथा किस प्रकार फसल बेचनी चाहिए।

चौथे, किसान को बनिय तथा आदमी की बड़मानी का शिकार होना पड़ता है।

पाचवें, यह कि किसान के पास फसल को रखने का उत्तम प्रबन्ध न होने के कारण उसकी बहुत सी फसल को कीड़े मकौड़ खा जाते हैं।

छठे, यह कि बिज्जी के इस ढङ्ग के कारण बहुत से मध्यम पैदा हो गए हैं जो सिवाय किसान का लूटने के कोई काम नहीं करने।

बिज्जी के ढङ्ग में सुधार—बिज्जी के इस ढङ्ग में दो प्रकार से सुधार हो सकते हैं। पहले यह कि नियन्त्रित बाजार (Regulated Markets) और दूसरे यह है कि सहकारी बिज्जी समितियाँ (Co-operative Marketing Societies) स्थापित की जायें। हमारे देश में इन दोनों ही ओर प्रयत्न किया गया है। अभी तक प्रयत्न आवश्यकता से बहुत कम है इस कारण किसान को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है।

नियन्त्रित बाजार—नियन्त्रित बाजार किसानों के लिये बहुत आवश्यक है। ऐसे बाजारों में किसानों का माल आसानी से बिक जाता है और उसको अपनी फसल का उचित मूल्य मिल जाता है। ऐसे बाजारों में किसान दुकानदारों की धोखे-बाजी से भी बच जाता है। ऐसे बाजारों में बिज्जी की देख-भाल करने के लिये इन्स्पेक्टर रखे जाते हैं। बाजारों का नियन्त्रण करने के लिये क्रेताओं और विक्रेताओं तथा बिज्जी के प्रतिनिधियों की समिति बनी होती है। इस प्रकार किसानों को ऐसे बाजारों से बड़ा लाभ होता है।

इस देश में नियन्त्रित बाजार स्थापित करने का प्रयत्न सबसे पहले बरार में हुआ। कृषि कमीशन (Agricultural Commission) ने यह सुझाव रखा कि इस प्रकार के बाजार सारे देश में स्थापित होने चाहियें। इसके पश्चात् बहुत से प्रांतों तथा रियासतों ने इस प्रकार के कानून बनाये। जैसे बम्बई में १९२७ ई० में (यह कानून सन् १९३० में बदल दिया गया), हैदराबाद रियासत में सन् १९३० में, मद्रास में १९३३, मध्य प्रदेश में १९३५ ई० में तथा पंजाब में १९३६ ई० में पास हुये। इस प्रकार प्रथम योजना से पहले ऐसे कानून ७ राज्यों में थे। योजना काल में ये कानून तीन और राज्यों में पास किये गये। पर इन कानूनों की यह विशेषता है कि यह किसी स्थान की एक या दो चीजों पर लागू होते हैं अन्य चीजों पर नहीं होते। जैसे बम्बई, बरार के कानून रुई के लिये लागू होते हैं, बङ्गाल का कानून जूट के लिये। दूसरे यह कि इनके ऊपर इतना बड़ा नियन्त्रण नहीं होता जितना कि होना चाहिये। इस कारण यह किसानों को इतना लाभ नहीं पहुँचा सकते जितना कि उनसे पहुँच सकता है। अभी तक १८०० बाजारों में ५५० नियन्त्रित बाजार हैं, तथा ५०० बाजारों की दूसरी योजना वान के अन्त तक नियन्त्रित करने की योजना है। हैदराबाद, मंसूर तथा पंजाब में तो प्रायः सारे महत्वपूर्ण थोक बाजार नियन्त्रित हैं।

सहकारी बिक्री—आजकल बहुत से लोगों का यह विचार है कि किसान की स्थिति अभी सुधर सकती है जबकि ऋण देने वाली सहकारी समितियाँ बिक्री भार भी अपने ऊपर ले। हमारे देश में सहकारी समितियों ने हाल ही में बहुत उन्नति की है। जैसे कि बम्बई की ६३ कपास सहकारी बिक्री समितियों ने सन् १९५१-५२ ई० में ३७४ लाख रुपये का माल बेचा तथा अन्ध ४४ ने फल व सब्जी को सहकारी आधार पर बेचने का प्रबन्ध किया। मद्रास की प्रायः सभी ऋण देने वाली समितियाँ बिक्री समितियों से सम्बन्धित कर दी गई हैं। सन् १९५२-५३ में मद्रास की बिक्री समितियों ने ४७ लाख रुपये का माल बेचा। उत्तर प्रदेश में बहुत सा गन्ना, धी, खाद्य-सामग्री तथा तिलहन सहकारी बिक्री समितियों द्वारा बेचे जाते हैं। १९५२-५३ में उत्तर प्रदेश की १०६ गन्ना समितियों ने चीनी मिलों की आवश्यकता का ६३ प्रतिशत उन्हें प्रदान किया। १९४७-४८ में भारतवर्ष में ३,७५१ ऐसी समितियाँ थी जिनकी सदस्यता २० लाख तथा पूँजी ५५ करोड़ रुपये थी।

दूसरी योजना काल में इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि सहकारी उन्नति से सम्बन्धित सभी बातों को एक साथ मिला दिया जाय। इस प्रकार साख, बिक्री, फसल की बाजार के लिये तैयार करना, फसल को गोदामों में एकत्र करना आदि-बातों का एक दूसरे से सम्बन्ध होगा। एक राष्ट्रीय विकास तथा गोदाम बोर्ड (National Co-operative Development and ware-housing Board) की स्थापना की जा चुकी है। एक केन्द्रीय गोदाम प्रमण्डल तथा १६ राज्य गोदाम प्रमण्डलों की स्थापना की जा चुकी है। इन सबके अन्तर्गत जो गोदाम स्थापित किये

जायेंगे उनमें २० लाख टन गुल्ला एकत्र किया जा सकेगा । इन गोदामों की रसीद के आधार पर किसानों के लघुकर्तृनी ऋण प्राप्त हो सकेंगे । द्वितीय योजना के पहले दो वर्षों में १९८३ गोदाम बनाने के लिये सहकारी बिक्री समितियों तथा कुछ बड़ी सहकारी समितियों को सहायता दी गई । १९५८-५९ में १ ५९ करोड़ की लागत के १०६० गोदाम बनाने की योजना है ।

सरकारी समितियों द्वारा फसल को बेचने से बहुत लाभ हैं—(१) इससे मध्य जन (Middle men) का लाभ बहुत कम हो जाता है । (२) इसके द्वारा किसान को अपनी फसल के ठीक दाम मिल जाते हैं । (३) किसान को भविष्य में होने वाले ऊँचे दाम का ठीक लाभ पहुँचता है । (४) फसल को बेचते समय किसान बहुत सी नवीन बातें सीखता है । (५) किसान को अधिक मात्रा में फसल बेचने का लाभ भी प्राप्त हो जाता है ।

सरकारी प्रयत्न—कृषि कमीशन तथा केन्द्रीय बैकिंग कमेटी के सुझाव के अनुसार भारतीय सरकार ने भी फसल की बिक्री की ओर ध्यान देना आरम्भ कर दिया है । उसने १९३४ में फसल की बिक्री के एक परामर्शदाता (Agriculture Marketing Adviser) को नियुक्त किया । उसको सहायता के लिये एक उप परामर्शदाता भी है इसके अतिरिक्त एक जाच का परिचालक (Director of Inspection), ६ ज्येष्ठ बिक्री अफसर (Senior Marketing Officer), २ सहायक जाँच परिचालक निरीक्षण अफसर (Supervising Officer) और १५ सहायक बिक्री अफसर भी नियुक्त किये गये हैं । इसी प्रकार बिक्री की व्यवस्था बहुत से राज्यों में भी पाई जाती है ।

इस सारी व्यवस्था द्वारा तीन प्रकार के काम किए जाते हैं—(१) अनुसंधान कार्य (Investigation), (२) उन्नति कार्य (Development), (३) श्रणीबद्ध करने के कार्य (Grading) । अनुसंधान के कार्य में मुख्य वस्तुओं की बिक्री की जाँच करना, नियन्त्रित बाजारों की समस्या के बारे में सोचना, आवागमन के साधनों की समस्या पर विचार करना आदि हैं । उन्नति का कार्य अधिकतर बिक्री की खाजक परिणाम पर निर्भर होगा । इसके द्वारा यह प्रयत्न किया जायगा कि किसान और व्यापारी को उपभोक्ता की आवश्यकता की दावत खबर दी जाय तथा उनमें इस बात का प्रचार किया जाय कि वह केवल स्टैंडर्ड श्रेणी (Standard Grade) की ही वस्तुएँ बेचें । श्रणीबद्ध करने का कार्य टेक्नीकल (Technical) है और उसके द्वारा तिलहन, फल, अन्न आदि वस्तुओं के भौतिक तथा रासायनिक गुण की जाँच की जाती है ।

बिक्री की इन व्यवस्था ने बहुत सा लाभदायक कार्य किया किया है । पिछले २५ वर्षों में ८८ वस्तुओं की बिक्री के ढङ्ग की जाँच की जा चुकी है । इनमें से मुख्य चावल, गेहूँ, मूँगफली, तम्बाकू, चना, फल, आलू, चीनी आदि हैं । ये सब रिपोर्ट हो चुकी है । इनसे बहुत सी उपयोगी बातों का पता चलता है । १९३७ ई०

में कृषि-उत्पन्न (श्रेणी तथा कृषि) एक्ट (Agricultural Produce Grading And Marketing act) पास किया गया। यह फल, तम्बाकू, बहवा, चावल, गुरा, गेहूँ, आटा, गुड़, तेल निकालने के बोज, वनस्पति घी, कपास, लाख, सन, खालें। व चमड़ा, ऊन, लकड़ी, अखरोट आदि पर लागू होता है। इन एक्ट के अन्तर्गत प्रति वर्ष कई करोड़ रुपये के सामान को श्रेणीबद्ध करके बेचा जाता है। यह कानून ३८ वस्तुओं पर लागू होता है और अभी तक ११७ वस्तुओं के ग्रेड स्टैंडर्ड्स किये जा चुके हैं। घी वेजीटेबिल आयल, मक्कन, चावल, आटा, गुड़, अण्डे, फल आदि के लिये ३८० ग्रेडिंग केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। मत्त, सिगरेट, तम्बाकू की पत्ती, ऊन, सन्दल की लकड़ी का तेल आदि को निर्यात करने से पूर्व Agmark की मोहर लगवानी आवश्यक है। इन चीजों की मांग विदेशी बाजारों में बढ़ती जा रही है। १९५७-५८ में २७.५३ करोड़ रु० का ऐसा माल विदेशों को निर्यात किया है तथा १९५८-५९ के पाच महीनों में १२.६५ करोड़ रु०।

दूसरी योजना में सिफारिश की गई है कि मिर्च, अदरक, हल्दी, वनस्पति, तेल, हाथ द्वारा निकाली गई मू गफली, खाल व चमड़ा आदि का निर्यात करने से पूर्व अनिवार्य रूप में ग्रेडिंग कर दिया जाय।

इसके अतिरिक्त १९३९ ई० में केन्द्रीय सरकार ने Standards of Weight Act पास किया जो कि १९५२ में लागू हो गया। इससे सभी स्थानों पर एक से बात हो जायेंगे। इस एक्ट पर अमल करने के लिये उत्तर प्रदेश, बम्बई, बिहार, पूर्वी पंजाब, हैदराबाद, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मैसूर आदि में अलग कानून हुए पर उन पर कोई अमल न किया गया और आज भी देश में बहुत प्रकार के बाट पाय जाने हैं। १९४८ ई० में Indian Standards Institute ने सारे देश के लिये मीट्रिक बाट (Metric weights) ग्रहण करने की सिफारिश की और बहुत सोच विचार के पश्चात् सरकार ने इस मुताबिक को मान लिया है तथा अक्तूबर १९५८ से देश के कुछ भागों में मीट्रिक बाटों का चलन आरम्भ हो गया है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने फरवरी १९५६ ई० में Central Co operation Development and Ware-housing Board की स्थापना के लिये लोक सभा में एक बिल पेश किया जिसका कार्य उत्पात्ति, विप्री फसल को गोदाम में रखने, खेती की फसल का आयात तथा निर्यात करने आदि की योजना बनाना तथा उसमें उन्नति करना होगा। इस योजना के अन्तर्गत १७०० प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ बनाई जायेंगी। इन समितियों की सदस्य १२००० बड़ी बड़ी प्रारम्भिक साख समितियाँ होंगी जो कि किसानों को खेती सम्बन्धी सामान बाटेगी तथा विप्री के लिये उनकी फसल एकत्र करेंगी। विप्री तथा साख समितियों के पास छोटे-छोटे गोदाम होंगे। दूसरी योजना काल में ६५७० ऐसे गोदाम बनाये जायेंगे। इनके अतिरिक्त १९६०-६१ तक ३५० लाइसेन्सुड गोदाम बनाने की भी योजना है।

इसके अतिरिक्त All India Radio, Delhi से हर रोज मुख्य-मुख्य

वस्तुओं का मूल्य घोषित किया जाता है, विदेशों में भारतीय ट्रेड कमिशनरों द्वारा भी भारतीय वस्तुओं का प्रचार किया जाता है। पर विदेशों में हमारे देश की वस्तुओं के बेचने में यह कठिनाई होती है कि हमारे देश की चीजों में मिन्याबट होती है तथा वे अच्छे प्रकार की नहीं होती।

सुझाव—अभी तक बिजली की उन्नति के बिना कार्य किया गया है वह आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम है। आवश्यकता इस बात की है कि इस कार्य को अधिक वेग से बढ़ाया जाये। नियन्त्रित बाजार जो अभी तक एक दो मुख्य स्थानीय वस्तुओं तक सीमित है उनको सभी पदार्थों की बिक्री के लिये लागू किया जाये। दूसरे, सहकारी बिजली समितियाँ अधिकाधिक खोली जायें तथा जहाँ तक सम्भव हो उनको ऋण देने वाली समितियों से जोड़ दिया जाये। तीसरे, सामान रखने के लिये सरकार को गोदाम बनाने चाहियें। इससे यह लाभ होगा कि किसान फसल को एकत्र करने में जो हानि होती है वह कम हो जायेगी और किसान को गोदाम की रसीद पर ऋण लेने में सुविधा हो जायगी। सरकार का हाल ही में इस ओर उठाया हुआ पग बहुत लाभदायक सिद्ध होगा।

Q-23 In what manner would you assure full employment for the landless labourers in our rural areas? Describe your schemes

प्रश्न २३—आप किस प्रकार अपने गाँवों के बिना भूमि के मजदूरों को पूर्ण रोजगार प्रदान कर सकते हैं? अपनी योजना बताइये।

बिना भूमि के मजदूर वे होते हैं जो भूमि पर आश्रित होते हैं परन्तु जिनके पास अपनी स्वयं कार्य की भूमि नहीं होती वरन् वे दूसरे लोगों के खेतों में मजदूरों के समान काम करते हैं। भारतवर्ष में ऐसे मजदूरों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है। १८८२ ई० में ऐसे मजदूरों की संख्या केवल ७५ लाख थी परन्तु १९२१ ई० में यह संख्या बढ़कर २ करोड़ १५ लाख और १९३१ ई० में ३ करोड़ ३० लाख हो गई। १९५१ की जनसंख्या के अनुसार कृषि मजदूर तथा उन पर निर्भर रहने वालों की संख्या ४९ करोड़ थी जो कि खेती पर निर्भर रहने वाली कुल जनसंख्या की २० प्रतिशत थी। परन्तु कृषि भग जाँच खोज के अनुसार ३० ४% ग्रामीण परिवार कृषि मजदूर हैं।

बिना भूमि के मजदूरों की संख्या में वृद्धि के कारण—भूमि के मजदूरों की संख्या में वृद्धि के कई कारण हैं। पहला, हमारे देश में जनसंख्या की निरन्तर वृद्धि हो रही है परन्तु उसके साथ उद्योग-धन्यो की वृद्धि नहीं हो रही है जिससे निवृत्ति हुई जनसंख्या को रोजगार मिल सके। इसलिये लोगों को खेती की ओर झुकना पड़ता है। दूसरे, हमारे देश के कुटीर उद्योग-धन्यो विदेशी माल की प्रति-योगिता के कारण नष्ट हो गये जिसके फलस्वरूप उन उद्योगों में लगे हुए दस्तकारों को किसी और स्थान पर कार्य न मिलने के कारण खेती की ओर झुकना पड़ा

क्योंकि उनमें से बहुतों के पास भूमि न थी इसलिये उनको मजदूरी के रूप में काम करना पड़ा। तीसरे, किसानों ने कुछ सामाजिक कुप्रथाओं के कारण गांव के महाजन से ऊँची व्याज दर पर ऋण लिया जिसके न चुका सकने के कारण उनकी भूमि उनके हाथों में से निकल गई और वे बिना भूमि के मजदूरी के रूप में काम करने लगे। डा० राधा कृष्ण मुखर्जी का कहना है कि 'प्रत्येक परिस्थिति जिसके कारण कि छोटे किसान की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है उसने खेत मजदूरों की संख्या में वृद्धि कर दी है।

बिना भूमि के मजदूरों की प्रति—भारतवर्ष में बिना भूमि के मजदूरों की प्रति के कई स्रोत हैं जैसे वे परिवार जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है, वे परिवार जिनके पास भूमि तो है परन्तु इतनी अपर्याप्त है कि उस पर परिवार के सब सदस्यों को पूरे वर्ष तक काम नहीं मिल सकता। गांव के सेवक तथा दस्तकार तथा कहीं-कहीं दामता का भी जीवन बिताने वाले मजदूर पाये जाते हैं। ये मजदूर अधिकतर वे होते हैं जो महाजनों से रुपया लिये हुए रहते हैं, परन्तु उसको चुका नहीं सकते।

बिना भूमि के मजदूरों की अवस्था—खेतों पर मजदूरों को निरन्तर काम नहीं मिलता। रोजगार की अवधि फसल के प्रकार तथा खेती करने की ढंग पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिये उत्तर पश्चिम के सींचे हुये भागों तथा उत्तर प्रदेश के गेहूँ के क्षेत्रों में मजदूरों को ६ मास तक काम मिल जाता है परन्तु पूर्व के उन भागों में जहाँ गेहूँ नहीं उगाया जाता मजदूरों को केवल ४ महीने ही काम मिलता है। कुल भारत का औसत २१८ दिन है जिसमें १८६ दिन वे खेती पर काम करते हैं तथा २६ दिन इधर-उधर का काम करते हैं। भारतवर्ष में वे मजदूर जो कि स्थायी रूप से कार्य करते हैं केवल १०-११ प्रतिशत हैं, शेष को कभी-कभी कार्य मिल जाता है।

भारत में बिना भूमि के मजदूरों की अवस्था बड़ी खराब है। कहीं-कहीं तो इनको दासता का जीवन बिताना पड़ता है। बहुत अधिक समय तक कार्य करने पर भी उनको बहुत कम मजदूरी मिलती है और इस पर भी मालिक की डाट-उपट सहन करनी पड़ती है। ऐसा अनुमान है कि १९४४-४५ तथा ४६ में बम्बई, पंजाब तथा मद्रास में इनकी मजदूरी १० आने और १ रुपये के बीच में थी और स्त्रियों की मजदूरी तो इससे भी कम थी। आजकल भी इनकी मजदूरी इस प्रकार है—

औसत दैनिक मजदूरी (आनों में)

क्षेत्र	पुरुष	स्त्री
उत्तरी भारत	१८८	१६८
पूर्वी भारत	१६६	१५७
दक्षिणी भारत	१६२	६८

पश्चिमी भारत	१८६	१२५
मध्य भारत	१२८	८२
उत्तरी पश्चिमी भारत	२२८	१५८
समस्त भारत	१७५	१०८

इस प्रकार के मजदूरों के परिवार की औसत वार्षिक आय ४८७ रुपये है तथा इन मजदूरों की प्रति व्यक्ति आय केवल १०४ रुपये है जबकि कुल भारत में प्रति व्यक्ति आय २६६ रुपये है ।

गाँवों में अन्न की कमी या मूल्य के बढ़ने का प्रभाव सबसे पहले इन मजदूरों पर पड़ता है । ये मजदूर पशु रखकर तथा उनका घी, दूध बेचकर अपनी आय बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं । प्रायः वे उन्हें खेतों के आस-पास चराते हैं और उसके बदले किसान की वेगार करते हैं । कभी-कभी उनको आस-पास के शहरों में भी कारखानों में काम मिल जाता है । इस प्रकार इन मजदूरों की अवस्था बहुत ही खराब है ।

उन्नति के सुझाव — बिना भूमि के मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए यह आवश्यक है कि खेती करने के ढङ्ग में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाय । खेती करने की कला को बदला जाय । सिंचाई की अधिक सुविधायें प्रदान की जायें । फसल की विज्ञान के ढङ्ग में परिवर्तन किया जाय । अधिक भूमि को खेती के लायक बनाया जाय । खेती में अच्छा बीज व खाद काम में लाई जाय । ऐसा करने से बहुत से लोगों को रोजगार मिल जायेगा ।

परन्तु खेती के उन्नत करने पर भी सब मजदूरों को रोजगार न मिल सकेगा । इसलिये यह आवश्यक है कि गाँवों में कुटीर उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन दिया जाय । इन उद्योगों के लिए हमारे देश में बहुत गुंजाइश है । इन उद्योगों में हमारे देश के बहुत से बेरोजगार मजदूर लग सकते हैं ।

खेत रहित मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिये यह भी आवश्यक है कि हमारे देश में प्रादेशिक उन्नति (Regional Development) की योजना अपनाई जाय । इस प्रकार की उन्नति से स्थान-स्थान पर बड़े-छोटे उद्योगों की उन्नति हो जायेगी और मजदूरों को रोजगार की तलाश में दूर के शहरों में नहीं जाना पड़ेगा ।

इसके अतिरिक्त स्थान-स्थान पर बिना भूमि के मजदूरों की सहकारी समितियाँ बनाई जायें और इन समितियों को दुग्धशालायें खोलने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय । इस प्रकार के कार्य के लिये भी हमारे देश में बहुत गुंजाइश है ।

बिना भूमि के मजदूरों को रोजगार दिलाने में विनोबा भावे का भूमिदान योजना बहुत सहायक सिद्ध हो सकती है । इस योजना के अनुसार उन लोगों की कुछ भूमि जिनके पास वह आवश्यकता से अधिक है दान में लेकर उन लोगों को दे दी जाती है जिनके पास भूमि नहीं है । आजकल हमारे देश में बहुत से लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित हो गया है और श्री जयप्रकाश नारायण जैसे बड़े-बड़े नेता इस

कार्य में लग गये हैं। परन्तु अभी बहुत मजिल तय करनी शेष है। इस योजना को हमारे देश प्रोत्साहन देना बहुत आवश्यक है।

इन सबके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि सरकार सड़कें, रेलें, नहरें, इमारतें आदि बनाने का कार्य अपने हाथ में ले। ऐसा करने से देश के बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मिल जायेगा।

इन सब बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने का प्रबन्ध किया जाय नहीं तो उनका शोषण किया जा सकता है। हमारे देश में ऐसा कानून १९४८ ई० में पार हो चुका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की मजदूरी सारे पंजाब, राजस्थान, अजमेर, कुर्ग, देहली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ तथा त्रिपुरा में निश्चित की जा चुकी है। दूसरे सात राज्यों में न्यूनतम मजदूरी कुछ निश्चित भागों में निश्चित की गई है। द्वितीय योजना में सुझाव दिया गया है कि न्यूनतम मजदूरी सब राज्यों के सब भागों में निश्चित कर देनी चाहिये। ६ जनवरी १९५५ ई० को उत्तर प्रदेश की सरकार ने वयस्क कृषि श्रमिकों के लिये १ रु० प्रतिदिन या २६ रु० प्रति मास तथा १८ वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये १० आने प्रतिदिन या १६/५० प्रति मास न्यूनतम वेतन निश्चित किया है। यह मुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बादा, बाराबंकी, जौनपुर, रायबरेली, फैजाबाद, हमीरपुर, बलिया, गाजीपुर और जालौन के जिलों में लागू होगा। इसका कारण यह है कि हमारे देश में विश्वासपात्र आकड़ों की कमी है तथा मजदूर असंगठित हैं। इसके अतिरिक्त कृषि सुधार समिति (Agrarian Reforms Committee) का यह भी सुझाव है कि इन मजदूरों के काम करने के घण्टे पुरुषों के लिये प्रतिदिन १२ तथा स्त्रियों के लिये १० रखे जायें। इस प्रकार के कार्यों से मजदूरों का शोषण न हो सकेगा।

पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये १५ करोड़ रुपये रखे गये हैं। योजना में इस समस्या को सुलझाने के लिय बड़े-छोटे सिंचाई के साधनों को उन्नत करना, बड़े पैमाने पर भूमि खेती के लिये प्राप्त करना, ग्रामीण उद्योगों की उन्नति तथा विकास करना आदि बताया गये हैं। इसके अतिरिक्त मिश्रित खेती (Mixed Farming) तथा सार्वजनिक निर्माण कार्य (Public Works Programme) के ऊपर विचार करने के लिये भी योजना में सुझाव दिया गया है। द्वितीय योजना में इस बात को माना गया है कि भूमि पर जनसंख्या के वर्तमान दबाव के कारण केवल थोड़े से मजदूरों को ही भूमि दी जा सकती है। परन्तु आर्थिक कारणों से ही नहीं बरन् सामाजिक नीति के कारण भी यह आवश्यक है कि देश की अर्थ व्यवस्था से उन लोगों को भी कुछ लाभ पहुँचाया जाय जो कि अभी तक सदा दुखी रहे हैं तथा जिनको सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है।

योजना में कहा गया है कि यह अच्छा होगा कि प्रत्येक राज्य में सरकारी तथा गैर सरकारी लोगों का एक विशेष बोर्ड बनाया जाय जो कि बिना भूमि के

मजदूरो सम्बन्धी योजनाओं की उन्नति की जाव कर सके तथा मजदूरो के फिर से वसताने की योजनाओं पर नसीहत कर सके। इसी प्रकार का एक बोट सारे भारत-वर्ष के लिये होना चाहिये जो कि नीति तथा व्यवस्था के प्रश्नों पर विचार करे तथा समय-समय पर मजदूरो को भूमि पर वसताने की योजनाओं की उन्नति की जाव करता रहे।

योजना में कहा गया है कि जहाँ तक हो सके वह भूमि जो कि खेतों की उच्चतम सीमा निश्चित करने के पश्चात् बचे भूदान आन्दोलन से प्राप्त हो, भूमि को खेती योग्य बनाकर प्राप्त हो, उसको भूमिहीन मजदूरो की दी जाय। परन्तु क्योंकि इस प्रकार पर्याप्त भूमि प्राप्त नहीं हो सकेगी। इस कारण इस सब कार्य से समस्या पूरे तौर पर नहीं सुलझ सकेगी। इसी कारण इस बात की आवश्यकता है कि इन भूमिहीन मजदूरो की सहायरी समितियाँ बनाई जायें तथा उनका निर्माण कार्य और कुटीर उद्योगों में लगाया जाय। योजना कमिशन ने इस बात पर जोर दिया है कि इन मजदूरो को घर बनाने में भूमि मुफ्त दी जाय तथा उनको न्यूनतम मजदूरी कानून के अन्तर्गत लाया जाय।

Q 24. What would you prefer—(a) The development of capitalistic farming, or (b) Collective farming, or (c) Co-operative farming or (d) Peasant proprietorship in India? Give reasons

प्रश्न २४—भारतवर्ष में आप किसको पसन्द करेंगे—(अ) पूँजीवादी खेती की उन्नति अथवा (आ) सामूहिक खेती अथवा (इ) सहकारी खेती अथवा (ई) कृषक स्वामित्व? कारण दीजिये।

भूमि स्वत्व (Land Tenures) के पश्चात् यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि खेती करने का ढङ्ग क्या हो क्योंकि इनके ऊपर ही यह बात निर्भर होती है कि हमको खेती की जिनमें उपज प्राप्त होती है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि भारतवर्ष छोटे-छोटे खेतों का देश है। भारतवर्ष में एक खेत का औसत क्षेत्रफल ५ एकड़ है। इसके विपरीत अमेरिका में एक खेत का औसत क्षेत्रफल १४५ एकड़, डेनमार्क में ४० एकड़, स्वीटन में २५ एकड़, जर्मनी में २१ एकड़ तथा इंग्लैंड में २० एकड़ है। इनके छोटे छोटे खेतों में आधुनिक कृषि यन्त्रों का प्रयोग होना असम्भव है। यही कारण है कि हमारी कृषि की अवस्था बड़ी खराब है। अब जबकि हमारे देश में जमींदारी उन्मूलन (Zamindari Abolition) हो रहा है तब हमारे सामने यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम अपने देश में किस प्रकार की खेती कर। नमार में आजकल अनेक प्रकार के कृषि संगठन चल रहे हैं जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं—

(अ) पूँजीवादी खेती—इस प्रकार की खेती अधिकतर इंग्लैंड और अमेरिका में की जाती है। भारतवर्ष में भी कम्पनी के शासन काल में अंग्रेजी मिलों के लिये कपास उगाने के खाते बड़े-बड़े खेत बनाने का प्रयत्न किया गया परन्तु राजनीतिक कारणों से इस विचार धारा को प्रोत्साहन न मिला। अन्त में १८५७ ई० के स्वतन्त्रता संग्राम के पश्चात् अंग्रेजी अफसरों को बड़े-बड़े खेत चाय, कहुवा, रबड़ उगाने के लिये दिये गये। पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा सिन्ध के सीचे हुए भागों में बड़े-बड़े खेत भारतीय तथा अंग्रेजी लोगों को दिये गये। अभी कुछ ही वर्ष पूर्व बम्बई सरकार ने ६,००० एकड़ का एक क्षेत्र एक चीनी सभा (Sugar syndicate) को पट्टे पर उठाया है। जब से चीनी के उद्योग की सरक्षण मिला है तब से दक्षिणी भारत में गन्ना उगाने वाले कई खेत स्थापित हो चुके हैं। कहीं-कहीं फल उगाने के लिये बड़े-बड़े खेत स्थापित किये गये हैं।

पूँजीवादी खेती दो प्रकार की हो सकती है।

(१) बड़े-बड़े खेत जिनके ऊपर एक व्यक्ति या एक सभा या एक मिथिन पूँजी कम्पनी खेती करती हो। ऐसे खेतों पर सब कार्यों के लिये मजदूर लगाये जाते हैं और खेतों की देखभाल करने के लिये बड़े-बड़े चतुर इन्जीनियर आदि लगाये जाते हैं। ऐसे खेतों पर रासायनिक खाद तथा आधुनिक मशीनें बहुत अधिक मात्रा में काम में लाई जाती हैं। इस प्रकार के खेत हमारे देश में दक्षिणी भारत में गन्ना तथा पहाड़ी भागों में चाय उगाने का काम में लाये जाते हैं।

(२) बड़े-बड़े खेत जिनके ऊपर किसी व्यक्ति अथवा कॉर्पोरेशन का अधिकार होता है परन्तु ऐसे खेतों को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित करके किसानों में बाँट दिया जाता है। इन किसानों के रहने के लिये मकान, खेतों में देने के लिये अच्छी खाद व बीज दिया जाता है तथा उनको अपनी फसल की बिक्री के लिये सुविधायें दी जाती हैं। किसानों के स्वास्थ्य तथा शिक्षा का साध भी पहुँचाया जाता है। सर डेनियल हेमिल्टन की गोसावा (बंगाल) की भूमि इस प्रकार की खेती का एक उदाहरण है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि बड़े-बड़े खेतों से छोटे-छोटे खेतों की अपेक्षा अधिक उपज प्राप्त होती है क्योंकि बड़े खेत वाले लोगों के पास हर प्रकार की सुविधायें होती हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के दृष्टिकोण से इस प्रकार की खेती बहुत अच्छी होती है। परन्तु अभी यह बात कहनी कठिन प्रतीत होती है कि इस प्रकार की खेती करने से हम अपने भूमि के साधनों का सदुपयोग कर सकें। इसके अतिरिक्त यदि किसानों से उनकी भूमि लेकर बड़े-बड़े खेतों के रूप में किसी पूँजीपति को दे दी जाय तो उनको उन खेतों पर अपने परिवारों सहित मजदूरों के रूप में कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार से कार्य करने में किसानों का शोषण होने का डर है। भारत में चाय के बागों पर इस प्रकार के शोषण से मजदूरों को बचाव के लिये कानून बनना पड़ा है। इस प्रकार की खेती से यह भी डर है कि इसके

कारण हजारों आदमी जो अब खेती पर लगे हुए हैं बेरोजगार हो जायेंगे। बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये यह आवश्यक है कि बड़े-बड़े खेतों के साथ उनसे सम्बन्धित उद्योगों को चलाया जाय। परन्तु यह कोई सरल कार्य नहीं है। इस प्रकार भारत की वर्तमान स्थिति में इस प्रकार की खेती उपयुक्त नहीं है।

(आ) सामूहिक खेती—इस प्रकार की खेती रूस में की जाती है। इस प्रकार की खेती को प्राप्त करने के लिये रूस के अन्दर बड़ी सख्ती से काम लिया गया। बहुत सा रक्त बहा। भारत में भी इस प्रकार की सरती करने की आवश्यकता करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत सम्पत्ति से लोगों को बड़ा प्रेम है। किसानों से इस प्रकार खेतों को प्राप्त करके खेतों का प्रबन्ध एक निर्वाचन समिति को, जो सरकार की आज्ञानुसार कार्य करती है, दे दिया जाता है। इस समिति की देख-रेख में किसानों को खेतों पर मजदूरों के रूप में कार्य करना पड़ता है। मजदूरों को कार्य अथवा पारिवारिक आवश्यकतानुसार मजदूरी दी जाती है। किसानों के इस प्रकार मजदूरों के रूप में कार्य करने से उनकी कार्य संचालन की सब शक्ति नष्ट हो जाती है। इसके अतिरिक्त रूस के उदाहरण को सामने रखने पर हमको पता चलता है कि इस प्रकार की खेती से उतना लाभ नहीं होता जितना कि उससे आशा की जाती है। नोम जस्नी (Naum Jasny) के अनुसार (जो कि जार सरकार तथा सोवियत सरकार के आधीन कृषि विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर चुका है), सामूहिक खेती के कारण १९२८ और १९३७-३८ के बीच की खेती पर आश्रित जनसंख्या की प्रति व्यक्ति आय १० प्रतिशत घट गई। इन सब बातों के कारण हम यह सकते हैं कि हमारे देश के लिये इस प्रकार की खेती उपयुक्त नहीं है। भारतवर्ष में सौराष्ट्र तथा भोपाल में ५-५ तथा त्रिपुरा और कुर्ग में १-१ सामूहिक कृषि समिति है।

(इ) सहकारी खेती—इस प्रकार की खेती में किसान आपस में मिलकर कार्य करते हैं—जैसे अपनी भूमि, पूँजी और पशुओं को एकत्र करके फार्म के ऊपर स्वयं अपने द्वारा निर्वाचित समिति की देख रेख में काम करते हैं। किसानों का खेतों पर व्यक्तिगत अधिकार होता है और इसके लिये उनको सामूहिक खेतों में उनकी भूमि के क्षेत्र के अनुसार लाभार्थ दिया जाता है। जो किसान खेत पर कार्य भी करते हैं उनको उनके काम की मजदूरी भी जाती है। इस प्रकार किसानों को लाभार्थ तथा मजदूरी मिलती है।

सहकारी खेती का उद्देश्य पूँजीवादी खेती के दोषों को दूर करते हुए उसके लाभों को समाप्त करना है। खेतों को इस प्रकार एकत्र करने से उन पर आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है तथा उनके लिये अच्छा बीज व खाद खरीदी जा सकती है। किसानों के उनके कार्य की मजदूरी मिल जाती है तथा लाभार्थ भी मिल जाता है। इस प्रकार उनका शोषण नहीं होता। उनको कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होती है।

भारतवर्ष के कुछ राज्यों में सहकारी खेती करने का प्रयत्न किया गया है । वम्बई में ३४६ सामूहिक खेती समितियाँ थी जिनके १०६६४ सदस्य थे । १६५६-५७ में १४ समितियाँ रजिस्टर्ड की गई । मद्रास में १६५३ में २६ उपनिवेशक समितियाँ थी जिनको पट्टे पर भूमि दी गई है । यह भूमि सदस्यों को एक योजना के अनुसार बाँटी गई है और उनको मजान के लिये भी भूमि दी गई है । सदस्य अपने उत्तराधिकार को भी नियुक्त करते हैं । सदस्य के उत्तराधिकारी के न होने पर भूमि समिति के पास चली जाती है । सरकार ने किसानों को कुछ बनाने बँल, खाद तथा औजार खरीदने के लिये ऋण भी दिया है । सदस्यों की फसल एक स्थान पर एकत्र करके बेच दी जाती है और इससे प्राप्त धन सदस्यों में बाँट दिया जाता है । इन समितियों को सफलता अवश्य मिली है । १९५६ में मद्रास राज्य में २ सहकारी समितियाँ स्थापित हुई तथा १९५७-५८ के लिये ५ और समितियाँ स्थापित करने की योजना थी विनोबा भावे से मिले हुए तामिलण्ड के २०० गाँवों में सहकारी खेती करने की बात सोची जा रही है । अभी हाल ही में इस प्रकार की खेती उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में भी की गई । परन्तु इस प्रकार के कार्य में कोई विशेष लफलता नहीं मिली है । इसका कारण यह है कि किसान लोग सहकारी खेती के लिये अपनी सबसे घटिया भूमि, कमजोर बँल आदि देने हैं तथा उस पर उस लगन में कार्य नहीं करते जिससे कि वे अपने खेतों पर करते हैं । कहीं ऐसा भी देखने में आया है कि सरकारी खेती में केवल एक उत्साही व्यक्ति के कारण सफलता प्राप्त हुई है और उस व्यक्ति के हटते ही इसके समाप्त होने की आशा है । आजकल उत्तर प्रदेश में २१६ ऐसी समितियाँ थी जो ५०६६२ एकड़ पर खेती करती थी । उत्तर प्रदेश में आजकल सहकारी अच्छी खेती, सहकारी के सामेदारी खेती, सहकारी किसान खेती तथा सहकारी सामूहिक खेती को आजमाया जा रहा है । दूसरी योजना में १०० समितियाँ बनाने की योजना है परन्तु उसमें से अभी तक १५ स्थापित हो चुकी हैं ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में सहकारी खेती ने कोई विशेष प्रगति नहीं की है । इसका कारण यह है कि अभी तक हमारे देश के लोगों में सहकारिता की भावना आई ही नहीं है और जब तक यह भावना जातृत हो हमें और प्रकार की खेती के ढङ्ग को अपनाना पड़ेगा योजना आयोग का मत है कि भारत की १६०० सहकारी खेती समितियों में से केवल ५० वास्तविक कही जा सकती है । परन्तु हमारा अन्तिम ध्येय सहकारी खेती ही होना चाहिए दूसरे प्रकार की खेती केवल एक अन्तर्कालीन पग ही समझना चाहिए ।

आर्थिक समीक्षा (२३ जुलाई १९५५) में श्री कलशनाथ काटजू सहकारी खेती की अवनाति के विषय में कहते हैं कि एक विस्तृत अर्थ में तो सहकारी खेती सभी कार्यान्वित हो सकती है, जय जमीन का एकीकरण कर दिया जाय । गिछने १८ वर्षों के भीतर मैंने इस मामले पर काफी सोच विचारा है और मुझे ऐसा प्रतीत

होता है कि इस प्रकार जमीनो के एकीकरण के मार्ग में जो बाधाएँ हैं, उन पर पार पाना असम्भव है ।

इनके कारण बताते हुए काटजू माहब कहते हैं कि किसानों में अपनी ही जमीन पर खेती करने की परम्परागत और चिरकाल भावना पाई जाती है । वे अपनी जमीन पर प्रथम परिश्रम करके अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं । विमान अपनी खेती-बाड़ी का काम स्वयं ही नहीं करता उसके बाल बच्चे और परिवार के लोग भी उसकी सहायता करते हैं । यदि उससे कहा जाय कि वह सम्मिलित खेती का ढङ्ग अपना ले तो वह उस बात को ब्यापि स्वीकार नहीं करेगा । 'परिवार के सभी सदस्य सम्मिलित जमीन पर मिल जुल कर काम करते हैं । किन्तु उममे यह आशा करना कि वह गाँव के सभी किसानों को एक समुक्त परिवार का मध्यम समझे' निरी कल्पना होगी ।

दूसरी बाधा यह बात निश्चिन करने में है कि दो व्यक्तियों के धर्म के बीच परस्पर समता किस प्रकार स्थापित की जाय ।

तीसरे इस प्रकार की खेती करने पर परिवार के बाल बच्चों का धर्म काम न आ सकेगा ।

श्री काटजू का मत है कि भारत के लिये बड़े पैमाने की खेती उनकी उचित नहीं है जितनी कि छोटे पैमाने की । उन्होंने कहा कि यदि भारतीय किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार ठीक समय पर अच्छा बीज, खाद और पानी मिलने लगे तो वह अपने धर्म में बल पर उनकी ही अच्छी फसल पैदा कर सकता है जितनी की दुनिया में किसी भी देश से किसान पैदा करते हैं । आपानी ढङ्गों में इस तथ्य की पुष्टि कर दी है ।

योजना कमिशन द्वारा स्थापित Re organisation Committee of Land Reforms Panel की रिपोर्ट—

इस समिति ने सुझाव दिया है कि खेतों की उच्चतम सीमा निश्चित करने के पश्चात् जो भूमि बचे तथा सरकार के पास जो बकार भूमि बकार (Waste land) पड़ी है उसको सहकारी खेतों के लिये एकत्र कर दी जाए । जिन किसानों की भूमि का जोतना सामर्थ्य नहीं है उनकी भूमि भी उसी में मिला दी जाय । इस प्रकार देश में तीन प्रकार के खेत हो जायेंगे—

(१) सहकारी खेत जिनमें सरकार के अतिरिक्त (Surplus), दूसरी भूमि तथा किसानों द्वारा स्वयं इच्छा से एकत्र किये हुए खेत होंगे ।

(२) वे खेत जो खेतों की न्यूनतम सीमा निश्चित करने पर बचें । इनकी पहले प्रकार की भूमि के साथ मिलाकर दानों को एक साथ सहकारी ढंग से जानन का प्रयत्न किया जायगा ।

(३) किसानों के खेत जो न्यूनतम सीमा से बड़े होंगे । इनकी किसान स्वयं देखभाल करेंगे परन्तु यहां भी यह प्रयत्न किया जायगा कि किसान स्वयं इच्छा से सहकारी खेतों में सम्मिलित हो जायें ।

समिति ने यह अभी तक निश्चित नहीं किया कि सहकारी खेतों का नियन्त्रण किस ढंग से हो। परन्तु सम्मिलित तीनों ढंगों में से एक अपनाया जा सकता है—

(१) सारे खेत को पारिवारिक यूनिटों में बांटना और उसको खेती करने के लिये छोटे-छोटे परिवारों में बाँट देना। परिवार सहकारी समिति को लगान देंगे।

(२) सारे खेत को जोतने, बोने तथा काटने के लिये एक इकाई मानना परन्तु सिचाई आदि के लिये उसको छोटी-छोटी इकाइयों में बाँट देना और उनको वर्ष प्रतिवर्ष परिवारों में बाँट देना।

(३) सारे खेत का सब कार्यों के लिये एक साथ नियन्त्रण करना तथा सदस्यों को समयानुसार अथवा कार्यानुसार मजदूरी देना।

समिति का सुझाव है कि सारे देश में एक बड़े पैमाने पर हर फसल के क्षेत्र में सहकारी खेती का एक योजनाबद्ध तजुर्वा किया जाये।

समिति का यह भी सुझाव है कि हर राज्य में एक छोटी समिति स्थापित की जाय जिसका चेयरमैन सहकारिता का मन्त्री हो। इसके सदस्य वे लोग हों जिनका सहकारी मिद्दान्त में विश्वास हो तथा जो अनुभवी हों। इस समिति की सहायता के लिये एक ऐसा अफसर हो जो कि सारे राज्य में सहकारी खेतों का संचालन करे।

सहकारी खेतों को बहुत प्रकार की छूट तथा सहायता देनी पड़ेगी जैसे उनको सरकार तथा सहकारी संस्थाओं से ऋण मिलना, खेती की स्वीकृत योजनाओं के लिये उनको औरो की अपेक्षा सरकार से पहले आर्थिक सहायता, बीज, खाद, खेती औजार मिलना, कुछ समय के लिये उनका लगान घटा देना तथा उनको कृषि आय कर से छूट देना आदि।

अभी १९५७ ई० के आरम्भ के महीनों में हमारे देश में इस बात पर बड़ा वादविवाद हुआ कि भारत में सहकारी खेती को अपनाया जाय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि योजना काल में मुख्य कार्य यह होगा कि कुछ ऐसे मुख्य पग उठाये जायें जिनसे कि सहकारी खेती की नींव दृढ़ हो जाये, जिनसे दस वर्ष या ऐसे ही समय में अधिकतर कृषि भूमि सहकारी आधार पर होने लगे। पंडित नेहरू सहकारी खेती का समर्थन इसलिये करते हैं क्योंकि इसके कारण किसान को टेक्नो-लॉजिकल लाभ प्राप्त होता है। परन्तु इस प्रकार की खेती का मुख्य विरोध चौधरी चरणसिंह द्वारा किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश के आय मन्त्री हैं। उनका कहना है कि सहकारी खेतों के कारण कुछ चुने हुये लोग अधिकतर लोगों की सादगी, ना-समझी, श्रद्धालुता तथा आलस्य का लाभ उठावेंगे। इस प्रकार हम एक प्रकार के मध्यस्थों को हटाकर उनके स्थानों पर उनसे भी सख्त मध्यस्थों को स्थापित कर देंगे। इसके अतिरिक्त चौधरी साहब का यह भी कहना है कि इस प्रकार की

खेती से उत्पादन कम हो जायेगा। इससे प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों को ठेस पहुँच जायेगी। इसके द्वारा तानाशाही स्थापित हो जायेगी तथा इसके होने पर खेती का मशीनीकरण उसके सब परिणामों सहित हो जायेगा।

(ई) कृषक स्वामित्व—इस प्रकार की खेती हमारे देश में रैयतवारी क्षेत्रों जैसे बम्बई, मद्रास आदि में पाई जाती है। इसमें किसानों का भूमि पर मौलसी अधिकार होता है और भूमि हस्तान्तरित भी की जा सकती है। पंजाब में भी इस प्रकार की खेती पाई जाती है। वहाँ पूरे गाँव पर ही मालगुजारी निर्धारित की जाती है और फिर उसका बटवारा किसानों में कर दिया जाता है। परन्तु जहाँ जहाँ भी ऐसी खेती की जाती है वहाँ भी किसानों की अवस्था खराब है। हम इस प्रकार की कृषक-स्वामित्व कृषि के समर्थक नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश में उस किसान को जो स्वयं भूमि को जोतना होता है भूमि का स्वामी माना जाय और वह सीधा सरकार को मालगुजारी दे। यदि वह भूमि स्वयं न जोते तो उसकी भूमि सरकार के आधीन चली जाये। इस प्रकार किसान भूमि का विश्वास भाजक (Trustee) रहे।

इस प्रकार की खेती हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति के लिये बहुत उपयुक्त जान पड़ती है। हमारे देश में किसानों को निजी सम्पत्ति से वञ्च मोह है। इस प्रकार की खेती से किसानों की निजी सम्पत्ति की भूख सतुष्ट हो जायेगी। इसके साथ-साथ भूमि पर अपना अधिकार होने के कारण किसान उस पर जो तोड़ कर काम करेगा और इसके कारण खेती की उन्नति होगी क्योंकि यह ठीक ही कहा गया है निजी सन्पत्ति का जादू (Magic of private property) मस्त्थल को भी उपवन में बदल देता है। इसके अतिरिक्त किसान की कार्य संचालन की बुद्धि (Initiative) पर भी कोई आघात न होगा। उसको अपनी इच्छानुसार कार्य करने का पूरा अवसर प्राप्त हो जायेगा। इस प्रकार की खेती के कारण किसान किसी का दास भी न रहेगा जैसे कि वह पूँजीवाद तथा सामूहिक खेती के अन्तर्गत रहेगा।

परन्तु इस प्रकार की खेती चालू करने से पहले हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ेगा—

(१) किसान की भूमि को ऋणों के भुगतान में न ली जाय।

(२) यदि किसान खेती स्वयं न करे तो भूमि सरकार के अधिकार में चली जाय।

(३) भूमि का हस्तान्तरण केवल उन लोगों को किया जा सके जो स्वयं खेती करते हों।

(४) किसान को भूमि लगान पर देने का अधिकार न दिया जाय।

(५) खेत का एक न्यूनतम क्षेत्र निश्चित कर देना चाहिए जिसका भविष्य में बटवारा न किया जा सके।

(६) किसान अपने लिये बीज, छाद, औजार आदि खरीदने तथा अपनी फसल को बेचने के लिये सहकारी समितियाँ बनाये ।

Q 25 The ideal of the Community Projects is to create the Welfare State where people and Government will in co operation promote the objective.

Discuss fully the various steps and activities proposed to implement the objective underlying the projects

प्रश्न २५—‘सामूहिक विकास योजना का उद्देश्य एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना है जहाँ जनता तथा सरकार उद्देश्य की पूर्ति के लिये सहयोग से कार्य करेंगे ।’

योजना में चित्ति उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जो पग उठाये तथा कार्य किये गये हैं उनको पूर्ण रूप से विवेचना कीजिये ।

उत्तर—सामूहिक विकास योजना का विचार भारतवर्ष के लिये नया नहीं है । यह विचार इतना पुराना है जितना कि वेद । वैदिक यज्ञ सारं समाज के हित के लिये दिये जाते थे और इन यज्ञों में समाज के सारे व्यक्ति किसी न किसी रूप में हाथ बटाते थे । चौथी शताब्दी पूर्व में भी मेगस्थनीज ने बताया कि भारतीय समाज सामूहिक जीवन बिताता था । जैन तथा बौद्धों के ग्रन्थों से पता चलता है कि भारतवर्ष के लोग मेल-जोल से अपना जीवन बिताने के अभ्यस्त थे ।

इस प्रकार सामूहिक विकास योजना भारत के लिये कोई नई वस्तु नहीं है । यह पुराने सामूहिक जीवन को फिर से चलाने का एक आधुनिक प्रयत्न है । इसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर लिये गये हैं । इस योजना में अलग-अलग गाँव में उन्नति करने का प्रयत्न न करके बहुत से गाँवों में एक साथ उन्नति करने का प्रयत्न किया गया है । यह योजना किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के करने के लिये ही चालू नहीं की गई है बल्कि यह समाज के जीवन के हर पहलु को लेकर चालू की गई है । इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत विद्या, सफाई, चिकित्सा, कृषि, उद्योग धंधे, सामाजिक कार्य आदि सभी चीजें आती हैं । इस प्रकार इस योजना में इस बात का प्रयत्न किया गया है कि गाँव के लोग आर्थिक तथा नैतिक दृष्टि से उन्नत हो जायें । परन्तु इस प्रकार की उन्नति वे स्वयं करें यह उनके ऊपर छोड़ी न जाय ।

उद्देश्य—१९५१ की जनगणना के अनुसार भारत की ८२५ प्रतिशत जनता ग्रामीण रहती है । इसलिये भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में यह आवश्यक है कि सरकार का ध्यान ग्रामीणों में रहने वाली इस जनता की ओर आकर्षित हो । पिछले दो वर्षों में ग्रामीणों में से पूँजी, योजना आदि सहयोगों की ओर चली जा रही है । इस प्रकार गाँवों में अज्ञानता, गरीबी, भूख आदि का साम्राज्य रहता है । भारत के स्वतंत्र

हो जाने के पश्चात् यह आवश्यक हो गया है कि लोगों की भूख को शान्त किया जाए, रोगों को समूल नष्ट कर दिया जाय तथा अज्ञानता को जड़ से उखाड़ फेंका जाय। इसके अतिरिक्त लोगों के लिये कुछ खाली समय की भी आवश्यकता है ताकि वे काम से थक जाने पर अपनी शक्ति बटोर सकें और समाज के दूसरे लोगों से मिल-जुल सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह आवश्यक है कि गाँव के लोगों के जीवन के हर पहलू को उन्नत किया जाय। सामूहिक विकास योजना द्वारा ऐसा ही प्रयत्न किया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शुरु ही से इस बात पर जोर दिया गया है कि सारे समाज की उन्नति हो और पिछड़े वर्गों पर रास ध्यान दिया जाय क्योंकि विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देहातो में ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें किसी वर्ग के साथ भेद भाव या अन्याय न हो। कार्यक्रम का उद्देश्य यह भी है कि देहात के लोगों को आत्मोन्नति के लिये प्रेरित किया जाय और इसके लिये जनता के संगठनों की स्थापना करायी जाय, ताकि देहात में ऐसे आदमी तैयार हो जो अपने लोगों की उन्नति के मार्ग पर ले चल। इस प्रकार सामूहिक विकास योजना का उद्देश्य अधिकाधिक लोगों का अधिकाधिक हिस्सा करना है। यही एक लोक हितकारी राज्य का उद्देश्य होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सामूहिक विकास योजना का उद्देश्य एक लोक हितकारी राज्य की स्थापना करना है। परन्तु बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के विपक्ष में अपना नोट देते समय श्री बी० जी० राव ने कहा है कि लोक हित कार्यों की अपेक्षा आर्थिक उन्नति कार्यो की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये।

सामूहिक विकास योजना के अन्तर्गत विकास के निम्नलिखित कार्य नियोज्य हैं—

- (१) कृषि तथा कृषि सम्बन्धी कार्य
- (२) यातायात
- (३) शिक्षा
- (४) स्वास्थ्य

- (५) प्रशिक्षा (Training)
- (६) सहायक रोजगार
- (७) मकान
- (८) सामाजिक कल्याण

(१) कृषि—इसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जायेंगे—परती तथा गई भूमि को खेती के योग्य बनाना, तालाब, नहरों, कुओं तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई की योजना बनाना जिससे कि योजना काल में कम से कम आधी भूमि पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जायें, उत्तम बीज तथा खाद का प्रवन्ध करना, फसल के बेचन तथा साख का प्रवन्ध करना, पशुओं के प्रजनन केन्द्रों का प्रवन्ध करना, देश के भीतर मछलियों के उद्योग को उत्तत करना, फलों तथा सब्जियों की काश्त की उन्नति करना, भूमि सम्बन्धी अनुसन्धान करना, यथा सम्भव प्रत्येक गाँव अथवा ग्राम समूह में बहुउद्देश्य सहकारी समिति की स्थापना करना जिसका सदस्य प्रत्येक परिवार का एक व्यक्ति अवश्य हो।

(२) यातायात—इसके अन्तर्गत सड़को का प्रवन्ध किया जायगा तथा

मोटर यातायान को प्रोगाहन दिया जायगा। इनके अतिरिक्त बेलगाड़ी आदि का भी प्रबन्ध किया जायगा।

(३) शिक्षा—इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक आवश्यक तथा निम्नलिखित शिक्षा का प्रबन्ध करना, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करना, सामाजिक शिक्षा तथा पुस्तकालयों का प्रबन्ध करना आदि हैं।

(४) स्वास्थ्य—इसके अन्तर्गत नफाई तथा चिकित्सा का प्रबन्ध, दाहशोका का प्रबन्ध करना आदि हैं।

(५) प्रशिक्षण—इसके अन्तर्गत दलबारी के स्तर को ऊँचा करने के लिये प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना, कृषकों को प्रशिक्षण देना, निरीक्षकों को प्रशिक्षण देना, प्रबन्धकों को प्रशिक्षण देना, स्वास्थ्य कार्यालयों को प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना आदि सम्मिलित हैं।

(६) सहायक रोजगार—इसके अन्तर्गत गृह तथा छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देना जाना है जिससे कि बेकार तथा अर्द्ध बेकार लोगों को काम मिल सके तथा इस प्रकार की योजना बनाना जिससे कि व्यापार सहायक उद्योग तथा लोक हित सेवाओं में मजदूरों का गमान बचाया हो जाय।

(७) मकान—इसके अन्तर्गत गाँवों में उत्तम प्रकार के मकान बनाने के विषय में प्रदर्शन तथा शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा जो गाँव धने वसे हैं उनमें नये स्थानों पर मकान बनाना आदि आते हैं।

(८) सामाजिक कल्याण—इसके अन्तर्गत दृश्य तथा श्रव्य (auto-visual) प्रणाली के अनुसार ग्रामों में मनोरंजन के साधनों का प्रचार किया जायगा। इसमें मनोरंजन गरायों, खेल-कूद आदि की व्यवस्था की जायेगी। इसी के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं की उत्पत्ति भी आती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सामूहिक विकास योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य अधिक ही नहीं हैं, बल्कि उनमें से प्रत्येक कार्य बड़ा व्यापक है। इतने बड़े कार्य को नरवार के लिये करना असम्भव है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस सब कार्य को करने के लिये ग्रामीण जनता का पुरा-पूरा सहयोग हो। यह सहयोग धन, धन, योग्यता आदि सभी चीजों के रूप में होगा। इतना बड़ा यह कार्य तभी सफल होगा जबकि गाँव के लोग यह निश्चित करेंगे कि उनकी किस चीज की आवश्यकता है तथा वह किस प्रकार प्राप्त की जा सकेगी। उनकी हिम्मत करके हाथ में पावड़ा लेना पड़ेगा तथा स्वयं तथा दूसरों के साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा। सरकार की सहायता उनके उस समय मिलेगी जबकि उनके बिना उनका काम न चलेगा। इस प्रकार सामूहिक विकास योजना जनता तथा सरकार के सहयोग द्वारा पूरी हो सकेगी—किसी एक से यह पूरी न हो सकेगी।

कार्यक्रम तथा सफलता—

इन सब उद्देश्यों को लेकर २ अक्टूबर १९५२ ई० से सामूहिक विकास

योजना का कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इसके अनुसार सारे देश को अनेक योजना क्षेत्रों में बाँटा गया है। प्रत्येक योजना क्षेत्र (Project Area) में लगभग ३०० गाँव होंगे जिनमें लगभग २ लाख आदमी तथा १ लाख ५० हजार एकड़ खेती योग्य भूमि होगी। प्रत्येक योजना क्षेत्र को तीन विकास खण्डों (Development Blocks) में बाँटा जायगा। प्रत्येक विकास खण्ड में लगभग १०० गाँव तथा २० से ६० हजार तक जनसंख्या होगी। प्रत्येक खण्ड को पाँच से दस ग्रामों के समूह में बाँटा जायगा। प्रत्येक ग्राम समूह एक ग्राम-स्तर कर्मचारी (Village Level Worker) का कार्य क्षेत्र होगा।

प्रत्येक विकास खण्ड में एक मण्डी इकाई होगी। विकास खण्ड के गाँवों के लिए मण्डी इकाई आर्थिक, सामाजिक तथा सामूहिक कार्यों का केन्द्र होगी तथा विकास खण्ड में यह ऐसे स्थान पर होगी जहाँ से यह कार्य अत्यन्त सफलतापूर्वक ढङ्ग में हो सके। मण्डी इकाई में साधारणतया एक औषधालय तथा स्वास्थ्य केन्द्र होगा जो गतिशील औषधालयों द्वारा गाँव में पहुँचेगा। औषधालय में एक डॉक्टर, स्वास्थ्य निरीक्षक तथा सफाई निरीक्षक कार्य करेंगे। मण्डी इकाई में यातायात सेवा के अंजार तथा सामान ठीक करने का केन्द्र, वस्तु के त्रय-विक्रय का केन्द्र, कृषि की उपज के लिये एक गोदाम तथा पशु सम्बन्धी केन्द्र होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ मनोरंजन तथा शिक्षा सम्बन्धी केन्द्र स्थापित किये जायंगे।

संगठन (Organisation)—यह कार्यक्रम भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों के सहयोग से किया जायगा।

केन्द्रीय संगठन—सामूहिक विकास कार्य की महत्ता व इसके बढ़ते हुए कार्य के कारण सितम्बर १९५६ ई० में इसके लिये एक अलग मन्त्रालय का निर्माण किया गया। यह मन्त्रालय इस प्रोग्राम के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। आधार-भूत नीति के मामले एक केन्द्रीय समिति को प्रस्तुत किये जाते हैं जिनका सभापति प्रधान मन्त्री तथा जिसके सदस्य योजना आयोग के सदस्य, खाद्य तथा कृषि तथा सामूहिक विकास योजना के मन्त्री होते हैं। इस कार्य से सम्बन्धित दूसरे मन्त्रालयों से जो सम्बन्ध स्थापित किया जाता है वह या तो विशेष समितियों के द्वारा या समय-समय पर विचार विमर्श के द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय संगठन के अन्तर्गत एक केन्द्रीय सचिव तथा सामूहिक योजना प्रबन्धक (Community Project Administrator) होंगे। सामूहिक योजना प्रबन्धक देश भर में सामूहिक योजना के नियोजन, निर्देशन तथा समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा तथा इस कार्य में विभिन्न राज्यों के उपयुक्त अधिकारियों से सलाह लेगा।

राज्य संगठन—प्रत्येक राज्य में राज्य-विकास समिति (State Development Committee) होगी जिसमें राज्य के मुख्य मन्त्री सभापति, विकास मन्त्री सदस्य तथा विकास कमिशनर सचिव होंगे। विकास कमिशनर पर ही राज्य में

इस योजना के कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व होगा। वह समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा। यही समिति राज्य में समस्त सामूहिक नियोजन का मार्ग दर्शन करेगी।

जिला सगठन—जिलाधीश जिला योजना अथवा विकास समिति का अध्यक्ष होगा। एक विकास अफसर जिसको जिला योजना अफसर कहा जायगा इस समिति का सचिव होगा। जिले में सब विकास विभागों के अध्यक्ष इस समिति के सदस्य रहेंगे। इससे अतिरिक्त जिला बोर्डों के अध्यक्ष तथा उपअध्यक्ष भी इस समिति में रहेंगे। जिलों में जहाँ आवश्यक होगा एक जिला विकास अधिकारी (District Development officer) नियुक्त किया जायगा। यह विकास कार्य का उत्तरदायी कार्य करेगा। यह अफसर अपने जिले के सामूहिक विकास कार्य का उत्तरदायी होगा।

सामूहिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये प्रमुख कर्मचारी योजना कार्यकारी अधिकारी (Project Executive Officer) होंगे। योजना को कार्यान्वित करने के लिये इन्हें पूर्वी पंजाब के नी रोखेरी नामक स्थान पर इस कार्य को विशेष शिक्षा दी गई थी। ये अपने क्षेत्र के सामूहिक कार्यक्रम के लिये उत्तरदायी होंगे। इनकी सहायता के लिये, कृषि, सहकारिता, पशु-पालन, कुटीर उद्योग आदि के विशेषज्ञ होंगे। अन्त में एक गाँव स्तर कार्यकर्ता (Village Level Worker) होता है जो कि बहुउद्देश्य व्यक्ति का कार्य करता है। यह व्यक्ति ५ से १० गाँवों में कार्य करता है। गाँव वालों का सहयोग प्राप्त करने के लिये भारत सेवक समाज की स्थापना की गई है। यह राजनीतिक दल नहीं है।

वित्त व्यवस्था—इस योजना को पूरा करने के लिये सरकार तथा जनता दोनों ही धन की व्यवस्था करेंगे। जनता का सहयोग श्रम व धन के रूप में होगा। जो धन सरकार खर्च करेगी उसके स्थायी खर्च का बटवारा केन्द्र और राज्यों में ३१ के अनुपात में होगा। तथा चालू खर्च को केन्द्र तथा राज्य बराबर-बराबर खर्च करेंगे। परन्तु तीन वर्ष पश्चात् सामूहिक खण्डों का कुल खर्च राज्य ही सहन करेंगे। परन्तु इस योजना को चलाने वाले कर्मचारियों का खर्च केन्द्रीय सरकार भी सहन करेगी। परन्तु किसी वर्ष में केन्द्र का हिस्सा ५० प्रतिशत अथवा ६ करोड़ रुपये (इन दोनों में जो कम हो) होगा। एक और सामूहिक क्षेत्र का खर्च ६५ लाख रुपये होगा जो तीन वर्ष में किया जायगा। इस वर्ष में से ६५३ लाख समुक्त राष्ट्र सहन करेगा। नगरों के एक क्षेत्र का खर्च ११ लाख होगा जिसमें से ७५ लाख समुक्त राष्ट्र अमेरिका का होगा। परन्तु साधनों की कमी के कारण एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र तथा एक सामूहिक विकास क्षेत्र का दूसरी योजना काल में तीन वर्ष का खर्च क्रमशः ४ लाख व १२ लाख रखा गया है। यदि सामूहिक विकास योजना क्षेत्र में जिसका कार्य सितम्बर १९५७ ई० में पूरा हो जाना चाहिये था कोई बचत हुई है तो उस धन को मार्च १९५६ तक खर्च करने का निश्चय किया

गया है। इस खर्च को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ही एक निश्चित योजना के अनुसार करेंगी। द्वितीय योजना काल के लिये यह नियन्त्रण किया गया है कि सामूहिक विकास योजना क्षेत्रों में कार्य के प्रति लोगों में दिलचस्पी बनाये रखने के लिये प्रत्येक क्षेत्र पर तीन वर्ष तक प्रतिवर्ष ३०,००० रुपये 'स्थानीय कार्य' तथा 'सामाजिक शिक्षा' के मद के अन्तर्गत खर्च किये जायेंगे। यह खर्च भी केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में एक निश्चित योजना के अनुसार किया जायेगा।

प्रथम योजना काल में ६६५ करोड़ रुपये खर्च करने का निश्चय किया गया था। परन्तु इसमें से वास्तविक खर्च का अनुमान ५२४ करोड़ था। इस प्रकार ४४१ करोड़ दूसरी योजना काल में खर्च होगा। दूसरी योजना में इस कार्य के लिये २०० करोड़ रुपये रखे गये हैं।

विदेशी सहायता—इस सब कार्य को पूरा करने के लिये भारत की संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने १९५२-५३ से १९५६-५७ तक १२,७७१,८६० डॉलर का सामान देने का वचन दिया। उसमें से १२,०१५ मिलियन डॉलर सामान भगाने का आर्डर दिया गया था। परन्तु उसमें से १५ सितम्बर १९५६ तक केवल ६७२३ मिलियन डॉलर का सामान आ पाया था। कुछ विशेषज्ञों की सेवाओं भी भारत तथा राज्य सरकारों को प्रदान की गई हैं।

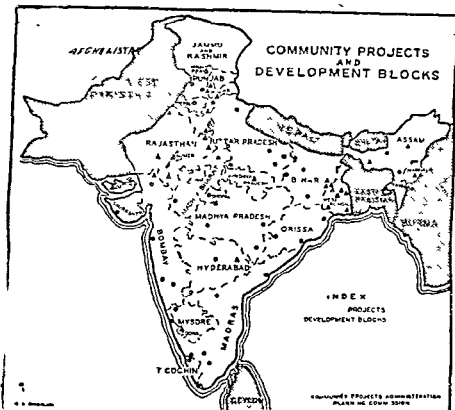
इसके अतिरिक्त भारत को प्रारम्भ से ही Ford Foundation से बड़ी सहायता प्राप्त हो रही है। वह योजना को चलाने वाले हजारों कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दे रहा है। इसने १५ पायलेट प्राजेक्टों को चलाने के लिये भी सहायता प्रदान की है। ये प्राजेक्ट गांव की उन्नति में सहायक होंगे।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा—(National Extension Service)

यह योजना २ अक्टूबर १९५३ से चालू की गई। इसके चालू करने की सिफारिश अधिख जन्म उपजाओ आच समिति तथा योजना आयोग ने की थी। इसके द्वारा १,२०,००० गांवों अर्थात् कुल जनसंख्या के एक चौथाई तक पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है। क्योंकि सामूहिक विकास योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उद्देश्य एक ही है इस कारण केन्द्र तथा राज्यों में इनको मिला दिया गया है। परन्तु जबकि सामूहिक विकास योजना केवल ३ वर्ष के लिये है राष्ट्रीय विस्तार सेवा स्थायी है। इस योजना के द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में तक सारे देश के लोगों तक पहुंचने का अवसर प्राप्त हो जायगा।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा का उद्देश्य गांव के लोगों को खेती तथा घरेलू विज्ञान के विषय में जानकारी कराना है। इसके अतिरिक्त खेती आदि में जो अन्यवेषण होंगे उनके विषय में भी उनकी जानकारी कराई जायगी। उनकी खेती करने के उन्नत ढंगों के विषय में भी जानकारी कराई जायगी। यदि किसी समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी तो उसके विषय में अन्येषण सस्थाओं को सूचित किया

जायगा। इनके अतिरिक्त किसानों को अवसर दिया जायेगा कि वे मिल-जुग कर एक-दूसरे से खेती सम्बन्धी बहुत सी बातें सीखें।



राष्ट्रीय विस्तार सेवा का आधारभूत सिद्धान्त यह है कि समाज के लोग स्वयं अपनी ओर ध्यान दें और यदि आवश्यकता पड़े तो सरकार उनको समाज सेवा तथा ऋण देकर सहायता करे। इसके द्वारा गाँव की सब समस्याएँ सहकारी सिद्धान्त पर सुलझाने का प्रयत्न किया जायेगा।

इस योजना की व्यवस्था सामूहिक विकास योजना के अनुसार ही है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस योजना पर १०१ करोड़ ₹० खर्च किये गये। केन्द्रीय सरकार ने स्थायी खर्च का ७५ प्रतिशत तथा बार-बार होने वाले खर्च का ५० प्रतिशत सहन किया। तेल राज्य की सरकारों ने खर्च किया। इस योजना को कोई विदेशी सहायता प्राप्त न हुई।

राष्ट्रीय विस्तार योजना द्वारा ३१ मार्च १९५७ तक निम्नलिखित कार्य किया गया—

अब तक सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों की जनता धन, सामग्री और श्रम के रूप में ६६ करोड़ ३१ लाख ८० दे चुकी है। सरकार ने ६० करोड़ ४ लाख रुपये खर्च किये हैं। इस प्रकार जन सहयोग का अनुपात सरकार के खर्च का ६० प्रतिशत होता है। इस समय देश के १,५८,०६६ गांवों में से २,३४,६१० गांवों के १३ करोड़ निवासी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हैं।

जन सहयोग दिलाने में पंचायतों ने बहुत भाग लिया है। वैसे तो सभी राज्य ज्यादा से ज्यादा पंचायतों को स्थापित और उन्हें साधन सम्पन्न बनाने में प्रयत्नशील हैं फिर भी सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना पर इन्हें जोर दिया गया है और विशेष ज्यादा अधिकार और आय के साधन सौंपे गये हैं।

अक्टूबर, १९५२ में कार्यक्रम के आरम्भ से पिछले वर्ष के अन्त तक सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में ३४,००० पंचायतें और अन्य निकाय कार्य में लगे। पहली पंचवर्षीय आयोजना की अवधि में पंचायतों की संख्या ८३,०८७ से बढ़कर १,१७,५६३ हो गई।

अधिकांश पंचायतों को स्कूलों के भवन बनाने और उनकी देखभाल करने गांव की गलियों को पक्की करने, सामुदायिक केन्द्र, पंचायतघर और कुएँ बनाने का काम सौंपा गया है। गांव की गलियों में राखनी, गांव में मफाई, जलाशय और मछली पालने के तालाबों को बनाना, वनों और बागों की देखभाल और पत्ती भूमि को खेती योग्य बनाने का काम भी पंचायतों के जिम्मे है।

पिछले कई वर्षों में (अर्थात् ३० सितम्बर १९५८ तक) सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में प्रौढ शिक्षणालयों की संख्या ८७,००० और वाचनालयों की संख्या ४५१०० हो गई। देहातों में ५,०७,००० शौचालय बनाये गये, १,८६,१५,००० गज लम्बी नालियाँ खोदी गईं, १,२६,००० कुएँ बनाये गये और ७=६०० मील कच्ची सड़के बनाई गईं तथा ६१,४०० मील लम्बी सड़क को उन्नत किया गया। इन सब कामों में पंचायतों और अन्य निकायों ने महत्वपूर्ण भाग लिया।

सहकारी संस्थाओं ने भी बहुत काम किया। वास्तव में कार्यक्रम की एक उल्लेखनीय सफलता यह है कि लोगों को विविध कामों के लिये सहकारी संस्थाएँ बनाने की प्रेरणा मिली। इससे खेती और उद्योग धन्धों की उन्नति हुई। नमून की पड़ताल से पता चलता है कि सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में अन्न की उपज २० से २५ प्रतिशत तक बढ़ी है। ३० सितम्बर १९५८ तक किसानों के खेतों पर ४८,५१,००० प्रदर्शन किये गये। १,५७,६८,००० मन उन्नत बीज तथा ३,६०,३६,००० मन रासायनिक खाद बाँटी गई, ११,७५,००० उन्नत औजार बाँटे गये। ५०,१५,००० कम्पोस्ट गड्डे छोड़े गये।

इसी बीच ४५८० प्रजनन केन्द्र चालू किये गये । १०५ मिलियन पशुओं को रिडरपेस्ट से बचाया गया । २२,००० साढ़ तथा ३१८,००० निडिया बाटी गई ।

लोगों को अपना अधिकतर काम सहकारी ढङ्ग से करने को प्रेरित करने के लिये प्रत्येक खंड में सहकारी विस्तार अधिकारी नियुक्त किये गये हैं । इन अधिकारियों को काम सिखाने के लिये ८ केन्द्र खोले गये हैं ।

३० सितम्बर १९५८ तक सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में १,२७,१२५ सहकारी संस्थाएँ खोली गई । सहकारी संस्थाओं के नये सदस्यों की संख्या ८७.८ लाख है ।

देहातो की कला और शिल्प को बढ़ावा देने के लिये २६४८ प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं । इन केन्द्रों में ६२,००० आदमियों को सिखाया और पुनरभ्यास कराया गया । लगभग ५,७८,००० लोगों को आंशिक रोजगार और १,७१,००० लोगों को पूरा रोजगार दिलाया गया । १९५६ के अन्त तक विकास कार्यक्रम से १,०३,७०,००० परिवारों को लाभ पहुंचा ।

विकास मण्डलों, ग्राम परिषदों, ग्राम सभाओं या ग्राम सभों जैसी संस्थाओं का काम भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहा । १९५६ के अन्त तक सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा और क्षेत्रों में इस प्रकार की ४८,००० संस्थाएँ स्थापित की गई । इसी अवधि में युवक सघ, किसान सघ, महिला समिति जैसे १,३८,००० जन संगठन बनाये गये ।

द्वितीय योजना का कार्यक्रम—सितम्बर १९५५ ई० में राष्ट्रीय विकास कौंसिल ने मंजूर किया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सारे देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को फैलाना चाहिये तथा कम से कम ४० प्रतिशत राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्रों (National Extension Blocks) को सामूहिक उन्नति क्षेत्रों (Community Development Blocks) में गहन उन्नति के लिये बदल देना चाहिये । इस प्रकार द्वितीय योजना में ३८०० अतिरिक्त राष्ट्र विस्तार क्षेत्रों में कार्य करना पड़ेगा तथा उनमें से कम से कम १९२० को सामूहिक उन्नति क्षेत्रों में बदलना पड़ेगा ।

इस कार्य में २६३ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है परन्तु योजना में केवल २०० करोड़ रुपये रखे गये हैं ।

प्रथम योजना में खेती, पशु-पालन, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, यातायात के क्षेत्रों में बहुत सा काम किया गया । द्वितीय योजना में इन सब क्षेत्रों में साधारण काम तो चलता रहेगा परन्तु इसके अतिरिक्त अप्रलिखित क्षेत्रों में विशेष कार्य किया जायगा—

(१) कुटीर उद्योगों की उन्नति जिससे कि गाँव के लोगों को रोजगार मिले ।

(२) सहकारी कार्यों की उन्नति ।

(३) स्त्रियों व बच्चों में काम फैलाना, तथा

(४) पिछड़ी जातियों में अधिक कार्य करना ।

आलोचनाएँ—योजना कमीशन ने इस कार्य की पड़ताल करके उसकी एक आलोचनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की है । इसमें इस कार्य की बहुत सी कमजोरियों को बताया है तथा उनको दूर करने के ढङ्ग भी बताये हैं । परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि कमीशन ने इस कार्य को विन्कुल बेकार माना है क्योंकि इस कार्य के फलस्वरूप प्रत्येक विकास क्षेत्र के गावों में कुछ न कुछ कार्य हुआ है । इस कार्य में विशेष उल्लेखनीय खेती करने का उन्नत ढङ्ग अपनाना तथा सिंचाई के लिये प्रबन्ध करना है ।

इस कार्य के होने के कारण गाव के लोग अब यह अनुभव करने लगे हैं कि सरकार न केवल शासन करने के लिये है बल्कि वह लोगों की सहायता करने के लिये भी है । परन्तु इस आशा के कारण ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं । उनमें से मुख्य यह है कि सरकार कहाँ तक लोगों की आशाओं को पूरा कर सकती है । इसी ओर योजना कमीशन की रिपोर्ट में हमारा ध्यान आकर्षित किया है ।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लोग अब सरकार से इतनी सहायता की आशा करते हैं कि वह सरकार के वर्तमान साधनों से पूरी नहीं हो सकती । इसके विपरीत लोगों में आत्म निर्भरता तथा स्वयं कार्य करने की इच्छा न तो व्यक्तिगत आधार पर और न सामूहिक आधार पर ही उत्पन्न हुई है । इस कारण जब तक सरकार गावों में अधिक धन खर्च नहीं करेगी तथा जब तक गाव के लोग आत्म-निर्भरता तथा स्वयं कार्य करने की भावना पैदा नहीं करेंगे, जब तक ग्रामीण भारत में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जिसके कारण बहुत सी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायेंगी ।

इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इस कार्य के संचालन में एक बड़ी कमी यह है कि इसका लाभ सब स्थानों पर समान नहीं पहुँचता । विकास क्षेत्रों के गावों में ही उन गावों को अधिक लाभ होता है जो कि पहुँच के अन्दर हैं परन्तु दूर के गावों को कम लाभ प्राप्त होता है । व्यक्तियों में किसानों तथा गैर किसानों के लाभ में अन्तर है तथा किसानों में भी उनकी अधिक लाभ प्राप्त होता है जिनके पास बड़े खेत हैं । इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह बात बड़ी चिन्ता का विषय है । इस चिन्ता का आधार न केवल यह है कि यह सामाजिक तथा क्षेत्रीय आधार पर अनुचित है बल्कि जैसे-जैसे लोगों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न होनी जाती है वैसे ही वैसे यह राजनीतिक दृष्टि से बड़ी कठिनाई उत्पन्न करेगा ।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लोगों के सामाजिक दृष्टिकोण में अभी तक कोई अन्तर नहीं आया है । इसका पता इस बात से लगता है कि लोग सामूहिक केन्द्रों, युवक वनवों तथा स्त्रियों के सङ्गठनों में भाग लेने के लिये तैयार नहीं हैं । लोग सहकारी समितियों तथा पंचायतों में भी कम भाग लेते हैं ।

इस रिपोर्ट में बड़े लोग की शिक्षा तथा कुटीर उद्योगों के विषय में भी भेद प्रगट किया गया है। इसके अनिश्चित रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सामूहिक विकास योजना के उद्देश्यों तथा उनकी तकनीक न तो पर्याप्त है और न समान। मलाहकार समितियों तथा पंचायतों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। सामूहिक विकास में उनके पश्चात् क्रिय जाने वाले बहुत कार्य के बीच वाले समय में पहला किया सब कार्य प्रायः समाप्त हो गया है।

इन रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि विकास का कार्य पंचायतों तथा महाकरी समितियों के द्वारा किया जाना चाहिये जिससे कि जनता इस कार्य में हाथ बटाती रहे तथा यह कार्य बहुत समय तक चलता रहे।

इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विकासवात्मक कार्य का शासनात्मक पहलू भी समझना आवश्यक है। इसमें सुझाव दिया गया है कि जिले के मुख्य शासन वक्ता का मुख्य कार्य विकास करना होना चाहिये और उनको मालगुजारी बमूल करन तथा ग्रान्ति स्थापित करने के लिए कुछ लोगों से महापना प्राप्त होनी चाहिये। इन क्रम का उल्टा करना ठीक नहीं है।

इन रिपोर्ट में ग्राम सेवक के कार्य के लिये भी सुझाव दिया गया है। इन रिपोर्ट में ग्रहण की भी एक व्यापक नीति की आवश्यकता बताई गई है जिसके कारण अधिक उन्नति सम्भव हो सके।

सुझाव—

अभी हाल ही में बलवन्त राम महता कमटी ने सामूहिक विकास योजना पर अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें कहा गया है कि सामूहिक विकास कार्य में लोग हितकारी कार्य (Welfare activities) में ध्यान देकर आर्थिक उन्नति के अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं (More demanding aspects of economic development) की ओर ध्यान देना चाहिये।

समिति का मत है कि सामूहिक विकास योजनाओं पर नियन्त्रण करने वाली मशीनरी का प्रजातान्त्रिक विवेकीकरण (Democratic decentralization) में ही वास्तविक ग्राम्य उन्नति हो सकती है। समिति का मत है कि नियन्त्रण का कार्य पंचायत समिति के हाथ में होना चाहिये जिसका कार्य क्षेत्र एक विकास क्षेत्र (Development block) जितना होना चाहिये। इस क्षेत्र की जनसंख्या ८०,००० से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह समिति गांव पंचायतों में से (Indirect elections) द्वारा बनानी चाहिए। इसमें जिले के जीवन के सभी अङ्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसका कार्य खेती, पशु सिंचाई कार्य आदि की उन्नति, प्रारम्भिक स्कूलों का नियन्त्रण तथा स्थानीय उद्योगों का प्रोत्साहन देना होगा समिति का कहना है कि राज्य सरकारों को चाहिये कि वे इन सब कार्यों को सभी अपन हाथ में लें जबकि पंचायत समिति इनको न कर सके। इस समिति के साधनों में भूमि कर की एक निश्चित कानूनी प्रतिज्ञा, व्यवसायों तथा व्यापार पर कर तथा अचल

सम्मति कर पर एक उपकर (Surcharge) सम्मिलित होंगे। समिति का यह भी चर्चा है कि पंचायत समिति में दो प्रकार के अफसर होंगे—ब्लॉक-स्तरीय (Block-level) तथा ग्राम स्तरीय (Village-level)। ये सब अफसर राज्य केडर (Cadre) से लिये जायेंगे। उनके वेतन, महंगाई, पेन्शन आदि की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। पंचायत समिति उनके आने जाने के खर्च को ही महन करेगी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वे विषय जो राज्यों के हाथ में हैं उनमें केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह केवल धन से राज्य सरकारों की सहायता करे तथा उच्चतम स्तर पर अनुसंधान के एकीकरण का कार्य करे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि जिन विषयों की जाँच राज्य के टेक्नीकल अफसरों ने कर ली है योजना में सम्मिलित करने अथवा केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिये उनकी जाँच फिर से केन्द्रीय सरकार के टेक्नीकल अफसरों द्वारा करानी अनावश्यक है। इसी प्रकार यदि योजना कमिशन द्वारा कोई योजना स्वीकार हो गई है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा फिर से उनकी जाँच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सामूहिक विकास क्षेत्रों में किस प्रकार खेती की उन्नति की जा सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि वे क्षेत्र जहाँ मिचाई की सुविधायें नहीं हैं उनमें मोट अनाज के उन्नत बीज बाँटे जायें। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा का कार्य द्वितीय योजना काल में पूरा होना कुछ बातों के कारण संभव नहीं। इस कारण इसके पूरा करने के समय को ३ वर्ष बढ़ा देना चाहिये।

यहाँ यह बात बताने योग्य है कि मुख्य मन्त्रियों ने जनवरी १९५८ की राष्ट्रीय उन्नति कौन्सिल (Standing Committee) की छोटी बैठक में बलबन्त राय महता कमेटी के इस सुझाव को सिद्धान्त में मान लिया है कि प्रत्येक विकास क्षेत्र में एक प्रजातांत्रिक सचवा स्थापित की जाय।

परन्तु ५ अप्रैल १९५८ को सामूहिक उन्नति मन्त्री श्री दे ने लोक सभा में स्वीकार किया कि यद्यपि सभी राज्यों ने महता समिति को सिद्धान्त में स्वीकार कर लिया था परन्तु फिर भी आन्ध्र और मद्रास को छोड़कर कहीं भी प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण को कार्यान्वित नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि कुछ प्रभावशाली तत्व इसको कार्यान्वित करने में बाधक हैं।

२३ अप्रैल १९५८ की एक बैठक में सामूहिक विकास की केन्द्रीय समिति ने योजना तथा उन्नति के कार्यों का शीघ्र ही विकेन्द्रीकरण करने की बात स्वीकार कर ली है। समिति ने सुझाव दिया है कि ब्लाक अथवा जिला-स्तर पर कानूनी संस्थाएँ स्थापित की जाएँ। जिनकी योजना तथा विकास की पूरी जिम्मेदारी हो। राज्यों से कहा जायेगा कि वे इस बात का आश्वासन दें कि अगले तीन वर्षों में ऐसी

सस्याये स्थापित कर दी जायेगी। इनके पूर्ण करने की अवधि को भी अक्टूबर १९६३ तक बढ़ा दिया गया है।

यह आवश्यक है कि समय-समय पर गाँवों की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति की जाच की जाय जिससे कि आर्थिक उन्नति का पता लग सके। यह भी आवश्यक है कि गांव के बेरोजगार अथवा कम समय रोजगार पाने वालों की जाच की जाय तथा यह भी देखा जाय कि कौन से कुटीर उद्योगों में लगाये जा सकते हैं। इस कार्य को ग्राम पंचायतों को करना चाहिये। लोगों के सहयोग को अधिकाधिक प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय तथा धूमखोरी को रोका जाय।

सामूहिक विकास योजना पर अपना विचार प्रगट करते हुये प० मेहरू ने कहा कि मेरे विचार में सामूहिक विकास प्रोग्राम तथा इनके द्वारा किया गया कार्य आश्चर्यजनक है। यह बहुत प्रशंसनीय है। परन्तु यह कहने के पश्चात् यह भी ठीक है कि सामूहिक विकास की उन्नति के कारण ही यह कुछ कठिनाइयों में पड़ गया है और ये कठिनाइयाँ आधारभूत तथा महत्वपूर्ण हैं। यदि यह आन्दोलन छोटे-छोटे कार्यकर्त्ताओं की ओर दौड़ेगा तो यह समाप्त हो जायेगा। यह ठीक है कि इससे फिर भी कुछ लाभ होगा परन्तु इस प्रोग्राम की आधारभूत कीमत चली जायगी। यह बात याद रखनी चाहिये कि गांव में छोटा सा कार्यकर्त्ता भी एक बड़ा अफसर बन जाता है।

Q. 26 Discuss the economic significance of Vinoba Bhave's 'Bhoomidan Yajna Movement'. Will it solve the problem of landless labourers?

प्रश्न २६—विनोबा भावे के 'भूदान यज्ञ आन्दोलन' का आर्थिक महत्व बतलाइये। क्या इसके बिना भूमि के मजदूरों की समस्या सुलझ जायेगी?

उत्तर—१९५५ की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष की जनसंख्या ३५७८ करोड़ है। जिसमें लगभग ४१ करोड़ ऐसे मजदूर हैं जिनके पास अपनी भूमि जोतने के लिये नहीं है इसके विपरीत भारत में लगभग ५६ लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास भूमि तो है परन्तु वे उसको स्वयं नहीं जोतते। भूमि दान यज्ञ के द्वारा आचार्य विनोबा भावे इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि गाँवों में मनोवैज्ञानिक जागरण हो अर्थात् उन लोगों से भूमि लेकर जिनके पास आवश्यकता से अधिक है उन लोगों को दे दी जाय जिनके पास वह बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार बिना भूमि के मजदूरों को कार्य दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस प्रकार विनोबा जी भारतीय संविधान की उस धारा को कार्यान्वित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनमें यह दिया हुआ है कि

सरकार को इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करने का अधिकार है जिससे कि वह एक अच्छा जीवन-स्तर चला सके ।

‘भूदान-यज्ञ’ आन्दोलन का विचार विनोबा जी के मस्तिष्क में उस समय आया जबकि वे हैदराबाद से पैदल लौट रहे थे । रास्ते में नालगोडा जिले के एक गाव में वे ठहरे । यहाँ प्रार्थना सभा में कुछ व्यक्तियों ने उनसे प्रार्थना की कि वे सरकार से कहकर उनको कुछ भूमि दिला दें । उन्होंने उनको ऐसा करने का वचन दिया परन्तु उसी क्षण उनके मन में विचार आया कि वे क्यों न जमींदारों से भूमि दान में लेकर इस प्रकार के भूमिहीन श्रमिकों को दिला दें । वस तभी उन्होंने पाँच करोड़ एकड़ भूमि दान में एकत्र करने का निश्चय किया जिससे कि वे बिना भूमि के मजदूर परिवार को कम से कम छ, सात एकड़ भूमि काम करने के लिये दें सकें । उसी दिन से विनोबा भावे सारे भारतवर्ष की पैदल यात्रा कर रहे हैं और अपनी प्रार्थना सभाओं में जमींदारों से अपील करते हैं कि वे अपनी भूमि, बिना भूमि के किसानों को दान में दें । इनकी अपील पर स्थान-स्थान पर उनको भूमि दान में दी गई है, इस प्रकार उन्होंने लाखों एकड़ भूमि दान के रूप में प्राप्त कर ली है ।

भूमिदान मंत्र वास्तव में एक नया प्रयोग है । जहाँ दूसरे देशों में जमींदारों से उनकी भूमि या तो बहुत सा धन क्षतिपूर्ति के रूप में लेकर प्राप्त की गई है या उनको विन्कुल नष्ट करके प्राप्त की गई है वहाँ विनोबा भावे अहिंसात्मक ढङ्ग से जमींदारों में भाई-चारे की भावना जागृत करके उनको बिना किसी क्षति-पूर्ति के प्राप्त कर रहे हैं । उनकी सफलता को देखकर देश के कुछ बड़े-बड़े राजनीतिक दलों ने भी इसका समर्थन किया है और कुछ लोग तो विनोबा जी के समान ही स्थान-स्थान पर घूमकर भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

भूमिदान आन्दोलन केवल भूमि का ही नहीं, सम्पूर्ण समाज को बदलने, सम्पूर्ण समाज के उदय सर्वोदय का आन्दोलन है किन्तु आरम्भ में भूमि क्यों ? इस-लिये कि भूमि उत्पत्ति के साधनों में मुख्य है और उत्पत्ति के साधन उत्पादक के हाथ में देना—स्वस्थ प्रजापती अर्थ-व्यवस्था का मूल है । भारत में ४३ करोड़ व्यक्ति सेतिहूर मजदूर हैं, जिनमें अछूत भी सम्मिलित हैं और जो आज भी उपेक्षित हैं । इतने बड़े वर्ग को सर्व प्रथम लेना उचित ही है । इसके अनिर्वित भूमि का विभाजन इतना विषम है कि करोड़ों के पास इतनी कम भूमि है कि उनकी स्थिति भूमिहीनों से किसी भी प्रकार श्रेष्ठ नहीं है । व्यक्तिगत स्वामित्व के कारण अधिकांश भूमि श्रम-हीन अनुत्पादक के हाथों में चली गई है । भूमि का सदुपयोग न होने के कारण उनका प्रभाव राष्ट्र की छात्र समस्या पर पड़ा है । बेकारी, जनमर्यादा वृद्धि, जन-स्वास्थ्य आदि के प्रश्न बहुत कुछ इसी से जुड़े हुए हैं । इसीलिये विनोबा जी ने सर्वोदय के पहले चरण के रूप में भूदान को लिया है । वे भूमि पर ईश्वर का या समाज का अधिकार मानते हैं । आकाश, प्रकाश वायु और वर्षा की भांति भूमि पर भी

भूदान के साथ सम्पत्ति दान का कार्य-क्रम भी चलाया जा रहा है। भूमि न दे सकने वाले लोग अपनी सम्पत्ति का छोटा भाग दे सकते हैं। सम्पत्ति के दृष्टी से ग़रीब ही रहेंगे परन्तु उनका विनियोग विनोबा या इस कार्य के लिये नियुक्त समिति करेगी। जिनके पास देने को न भूमि है न सम्पत्ति, वे अपना श्रम का समान के निर्माण कार्यों को दान दे सकते हैं। श्रम दान से पैसे के स्थान पर श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऊँच-नीच भावना का लोप होगा और आर्थिक समानता का मार्ग प्रगस्त होगा। श्रमदान से यदि मजदूर निर्माण-कार्य करने वाले अपनी बुद्धि का दान करेंगे तो शिक्षण, स्वास्थ्य चिकित्सा का रूप ही बदल जायेगा।

हमारे देश में इस यज्ञ के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। कुछ लोगों का विचार है कि इस यज्ञ के द्वारा भारत के बिना भूमि के किसानों की समस्या बहुत कुछ सुलझ जायेगी परन्तु दूसरे कुछ लोगों का विचार है कि इसके द्वारा खेत और अधिक छोटे हो जायेंगे और इस प्रकार देश की खेती अनाधिक हो जायेगी।

जो लोग भूमिदान यज्ञ का समर्थन करते हैं उनमें प्रो० श्रीमन्मारायण अग्रवाल भी एक हैं। अपने एक लेख में उन्होंने भूमिदान यज्ञ की बड़ी प्रशंसा की है। उनका विचार है कि बड़े-बड़े खेतों की अपेक्षा छोटे-छोटे खेतों पर खेती करना अधिक लाभप्रद है। अपने इस विचार के समर्थन में उन्होंने कई बड़े २ लोगों के विचार दिये हैं। यही नहीं, उन्होंने बताया कि जापान के अच्छे-अच्छे गाँवों में २५ एकर खेत है। आगे चलकर वे कहते हैं कि चीन की नई सरकार बड़े-बड़े खेतों को समाप्त करके छोटे-छोटे खेत बनाकर भूमि का पुनर्वितरण कर रही है। यही नहीं हम में भी जहाँ बड़े-बड़े खेत पाये जाते हैं वहाँ पर भी किसानों को २ एकर से लेकर २५ एकर तक निजी भूमि दे रखी है। इन सब छोटे-छोटे खेतों पर कृषि विमान बड़े परिश्रम से कार्य करके अपने परिवार की आवश्यकता के लिये अन्न उत्पन्न करता है। इन सब उदाहरणों को देखकर यह कहा जा सकता है कि खेती करना बड़े खेतों पर नहीं बल्कि छोटे खेतों पर लाभप्रद होता है। इस प्रकार यह कहना कि विनोबा के भूदान यज्ञ के कारण खेतों के छोटा होने का कारण खेती का पंजा अनाधिक हो जायेगा, ग़लत है। प्रो० अग्रवाल ने आगे चलकर बताया है कि छोटे पैमाने पर की गई खेती के स्तर को ऊँचा करने के लिये किसान अपनी सहकारी समितियाँ बना सकते हैं और सामूहिक रूप से बीज, खाद, सिंचाई, फसल की बिक्री आदि का प्रबन्ध कर सकते हैं। अन्त में प्रो० अग्रवाल कहते हैं, "बिना भूमि के श्रम की बेरोजगारी से दुटकारा दिलाने तथा उनकी भूमि की वास्तविक मूल्य को शान्त करने के लिये यह आवश्यक है कि भूमि का पुनर्वितरण एक बहुत बड़े पैमाने पर हो। आचार्य विनोबा का भूमिदान यज्ञ अमीर लोगों से गरीब लोगों को बिना किसी क्षतिपूर्ति के सद्भावना तथा महानुभूति के आधार पर भूमि को हस्तांतरित करने में आवश्यक आयुष्मण्डल उत्पन्न कर रहा है। इस प्रकार भूमि के

भारतीय कृषि

शान्त पुनर्वटवारे का वायुमण्डल ही देश को खूनी क्रान्ति से बचा सकता है। जिसमे सम्मिलित होने के लिये साम्यवादी सदा तत्पर रहते हैं।"

भूदान यज्ञ के विषय में श्री भगवानदास बेला लिखते हैं, 'यह पद्धति अहिंसक क्रान्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके पीछे विकेन्द्रीकरण और स्वावलम्बन की कल्पना है।'

भूदान यज्ञ के महत्व के विषय में श्री रामेश्वर दयालु ने लिखा है, 'भारत भूमि की यह विशेषता है कि यहाँ जब धर्म चक्र चलता है, तब जनता मन्त्रमुग्ध सी सर्वस्व अर्पण कर देती है। साथ ही हमें यह भी समझना चाहिये कि भूदान आन्दोलन से उत्पन्न जन शक्ति के प्रभाव से हमारी अर्थ रचना सर्वोदय की दिशा में प्रगति करेगी जिस अर्थ रचना में किसी के हाथ में अत्यधिक पूँजी नहीं एकत्र हो सकेगी क्योंकि प्राथमिक आवश्यकताओं के विषय में विकेन्द्रित स्वावलम्बी व्यवस्था होगी। रोप बड़े उद्योग, जो केन्द्रित रूप से ही चल सकते हैं उनके राष्ट्रीयकरण की सफलता व लिय जिस बातावरण शुद्धि की आवश्यकता है, वह भूमिदान-आन्दोलन में छिपी है।'

'इस आन्दोलन का प्रभाव न केवल आर्थिक क्षेत्र में अपितु राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में भी होगा। पक्षातीत राज्य-व्यवस्था का उद्घोष भारतीय राजनीति में होने लगा है। भूदान आन्दोलन उसके लाने का बातावरण निर्माण करेगा। इसी से समाज की जाति, वर्ण, स्त्री पुरुष आदि की असमानताय भी दूर होगी।'

जो लोग इस आन्दोलन का विरोध करते हैं उनका कहना है कि इसके द्वारा देश के पहले ही छोट छोटे खेत और भी छोट हो जायग। इस प्रकार खेती की उन्नति करना सम्भव न होगा। उनका यह भी कहना है कि इसके द्वारा वह भूमि जो आजकल जङ्गलों अथवा चरागाहों के नीचे है उस पर भी खेती होने लगगी और इस प्रकार भूमि के कटाव आदि की समस्या दूररूप धारण कर लेगी। उनका यह भी कहना है कि जो भूमि दान में दे दी जा रही है उनमें से अधिकतर खेती योग्य नहीं है। इसलिये यदि बकार भूमि को दान में दिया गया तो क्या लाभ? उनका यह भी कहना है कि विनोबा भावे ने भूमि को दान में लेकर उसका कोई उचित प्रयुक्त नहीं किया है। वे भूमि को दान में लेकर जिलाधीश को सीर देते हैं। उनका यह भी कहना है कि विनोबा जी भूमि लेने समय यह नहीं देखन कि भूमि झगड़े की तो नहीं है। इस प्रकार उनको जो भूमि मिली है उसमें से बहुत सी पगड़े की है।

इनमें से कुछ बात ठीक हो सकती है परन्तु उसके कारण हम इस आन्दोलन का विरोध नहीं करना चाहिये। यह हम मान सकते हैं कि कुछ भूमि झगड़ की हो सकती है कुछ खेती के अयोग्य हो सकती है, कुछ पर वन भी हो सकते हैं। परन्तु दान में मिली सब भूमि तो ऐसी नहीं है। जिस भाग में अच्छी भूमि दान में मिली है उस सीमा तक तो भूमिहीन किसानों को भूमि मिल जायेगी। इसके

अतिरिक्त हमें यह बात भी ध्यान रखनी चाहिये कि हमें यह न देखना चाहिये कि विनोबा भावे को अपने मिशन में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है वरन् हमें उस भावना की प्रशंसा करनी चाहिये जिसको लेकर यह आन्दोलन चलाया गया है तथा उस चामु मण्डल की भी प्रशंसा करनी चाहिये जो कि इस आन्दोलन द्वारा देश में उत्पन्न हो रहा है यदि इस आन्दोलन द्वारा देश के जमींदार अपनी भूमि दे सकते हैं तो इसके पश्चात् यह आशा भी की जा सकती है कि देश के पूँजीपति अपनी पूँजी के दान में देने लगेंगे तथा इसके पश्चात् दूसरे लोग भी अपनी सम्पत्ति का कुछ भाग अथवा अपना धर्म अथवा अपनी बुद्धि देशहित के लिये देने लगेंगे। ऐसा होने पर देश की काया पलट हो जायेगी। यदि हम इस आन्दोलन को इस दृष्टिकोण से देखें तो हम इसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते। हमें पूरी आशा है यदि इस आन्दोलन ने देशव्यापी रूप धारण कर लिया तो उससे देश के भूमिहीन किसानों की समस्या बहुत मुलज आयेगी।

भूमिदान यज्ञ आन्दोलन की प्रगति

अप्रैल १९५७ ई० में मसूरी में हुई छठी विवास कमिश्नरी की सभा में इस बात पर सहमति प्रगट की गई कि भूदान तथा ग्रामदान आन्दोलनों को अधिक से अधिक सहायता तथा प्रोत्साहन दिया जाय। प्रवर समिति का सुझाव था कि जिन राज्यों में इन आन्दोलनों के लिये आवश्यक कानून नहीं है वहाँ लोगों में इस प्रकार की भावना जाग्रत करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि सामूहिक विकास कार्य अधिक प्रभाव से चल। इस समिति का यह भी सुझाव है कि एक सरकारी मस्या निर्माण की जाय जो कि भूदान तथा ग्रामदान के कार्य में सहायता दे तथा भूमि का बटवारा करने में सहायता दे। परन्तु इस प्रकार सहकारी एजेंसी के कार्य पर सभा सदस्यों में मत भेद था। श्रीमन्नारायण अग्रवाल का मत था कि समाज को अपने हित के लिये ग्रामदान तथा भूदान आन्दोलनों की सहायता करनी चाहिये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को ग्रामदान इकाई को स्वीकार करना चाहिये तथा इसको आवश्यक सहायता देनी चाहिये। प० नेहरू ने कहा कि बिना सरकार की सहायता के भूदान आन्दोलन उस भूमि का क्या करेगा जो कि उसको प्राप्त होगी। सरकार ने हर पक्ष पर काय किया है। बहुत से राज्यों में कानून पास करके इस कार्य की सहायता की गई है।

जो आन्दोलन १८ अप्रैल १९५१ ई० को छोटे रूप में शुरू हुआ था वह अब सारे देश में फैल गया है। अब यह आन्दोलन ग्राम दान के रूप में विकसित हुआ है। ग्राम दान का अर्थ है 'सारे गांवों के दान।' इसका ध्येय यह है कि समस्त गांव की भूमि पर सारे ग्रामवासियों का सामूहिक अधिकार होना चाहिये।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में यह बात स्वीकार की गई है कि ग्राम दान गांवों के रूप में जो सफलता प्राप्त की गई है उसका सहकारी गांव की उन्नति पर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। सितम्बर १९५७ में पलवल (मैसूर राज्य) में हुई

अखिल भारत सर्व सेवा सभमि इस बात की डब्छा प्रगट की गई है कि सामूहिक विकास आन्दोलनो (Community Development Programme) तथा ग्रामदान आन्दोलन मे बडा गहरा सम्बन्ध होना चाहिये । मई १९५८ मे माउन्ट आबू मे हुई विकास कमिश्नरो की कान्फरेन्स मे यह निश्चय किया गया कि भूदान तथा ग्राम दान मे निकट सम्बन्ध होना चाहिये । भविष्य मे ग्राम दान वाले गावो मे ही सबसे पहले सामूहिक विकास का कार्य किया जायगा ।

आन्ध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई (सौराष्ट्र क्षेत्र), मध्य प्रदेश, मराठा, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, देहली हिमाचल प्रदेश मे भूदान के दान को प्राप्त करने तथा उसके बटवारे को सुविधाजनक बनाने के लिये कानून पान किये जा चुके हैं ।

१९५४-५५ से विभिन्न राज्यों ने इस आन्दोलन को जो आर्थिक सहायता प्रदान की है वह इस प्रकार है —

(हजार १० मे)

राज्य	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५८-५९
आन्ध्र प्रदेश	—	—	—	३०	२०
बिहार	—	३३०	१०००	१८६०	—
बम्बई					
१ विघटन	—	—	—	२००	—
२ सौराष्ट्र	४२	२५३	२५३	१६८	२१०
मध्य प्रदेश					
१ माउ प्रदेस	१००	१००	१००	३००	३००
२ मध्य भारत	—	१५०	३००	२००	२००
३ भोपाल	—	—	—	—	२५
पंजाब	—	—	—	५०	५०
राजस्थान	१०	१००	२५०	३००	—
उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	५००
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	५०	—

भारत सरकार भी इस आन्दोलन को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है । १९५६-५७ मे उसने ११-८२ लाख १० तथा १९५७-५८ मे १० लाख १० की आर्थिक सहायता उसने प्रदान की । इसके अनिश्चित वह सर्वमेवा मध्य द्वारा तैयार की गई स्कीम के लिये वह ६८ लाख १० और देगी । १९५७-५८ मे बिना भूमि के मजदूरो को भूमि पर सहायिता के आधार पर बसाने के लिये भी २५० लाख की मजदूरी दी गई है ।

अब तब प्राप्त आँकड़ों से ज्ञात हुआ है कि देश में जून मई १९५८ ई० तक आचार्य विनोबा भावे के भूदान यज्ञ में कुल ४४ लाख एकड़ जमीन दानस्वरूप प्राप्त हुई है और इसमें से ८ लाख एकड़ जमीन वितरित की जा चुकी है।

भूदान में बिहार का स्थान सर्व प्रथम रहा है जहाँ से २१ लाख १३ हजार ६३८ एकड़ जमीन प्राप्त हुई। बिहार से प्राप्त हुई इस जमीन में से २,८६२८६ एकड़ जमीन का वितरण भी हो चुका है।

भूदान के लिये अपने जीवन का दान करने वालों की कुल संख्या १,६४६ है जिनमें से १,०६८ जीवनदानी अकेले बिहार से हैं।

दूसरा नम्बर उत्तर प्रदेश का आता है जहाँ से भूदान में ५ लाख ८७ हजार ६३० एकड़ जमीन प्राप्त हो गई है। राजस्थान का नम्बर तीसरा है जहाँ ४ लाख २६ हजार ४८८ एकड़ जमीन मिली है। इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश में २,४१,९५० एकड़ भूमि प्राप्त हुई आसाम में २३,१९६ एकड़, बम्बई राज्य में गुजरात प्रदेश में ४७४८६ एकड़, महाराष्ट्र में ६४३६० एकड़ सौराष्ट्र में ३१२३७, विधर्व में ८६७७८ एकड़ मध्य प्रदेश में १,७८,८१६ एकड़, पंजाब में १९९२९ एकड़, मद्रास में ७०८२३ एकड़, उड़ीसा में ४,२४,६३५ एकड़।

ग्राम दान में ३१ दिसम्बर १९५८ तक ४५७०० गाँव प्राप्त हुये।

सम्पत्ति दान के २० मई १९५७ तक विनोबा जी को २ लाख ६७ हजार १४९ रुपये ७ आने दान में मिले हैं। जिसमें पेंसून और पंजाब से ६३ हजार ६४६ रुपये १३ आ० ३ पाई मिले हैं। यह दान अन्य सभी प्रान्तों में सर्व प्रथम है।



भारत की खाद्य-समस्या तथा अकाल

✓ Q. 27 Discuss about the food problem of India What has been done in recent years in India to meet food shortage in the country ? What more would you wish to be done in this respect ?

प्रश्न २७—भारतवर्ष की खाद्य-समस्या के विषय में लिखिये। हाल ही में अन्न की कमी को पूरा करने के लिये क्या किया गया है ? आप इस ओर और क्या करना चाहते हैं ?

खाद्य समस्या का अनुमान (An idea of the food problem)—१९४३ ई० के दशक के अकाल के पश्चात् भारत की खाद्य समस्या निरन्तर बिगड़ती चली गई। इसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि युद्ध से पूर्व हमारे देश में एक व्यक्ति प्रतिदिन १९१० कलोरी का उपभोग करता था परन्तु १९५१-५२ में वह केवल १९५० कलोरी का और १९५२-५३ में १६४० कलोरी का उपभोग करता था। परन्तु आजकल वह १७५० कलोरी का उपभोग करता है। इसके विपरीत १९५२-५३ में इंग्लैंड का एक आदमी ३०६०, संयुक्त राष्ट्र का ३११७ तथा डेन्मार्क का ३२५० कलोरी का उपभोग करता था। इस बीच में हमारे देश में प्रायः सभी चीजों का उपभोग कम हो गया है। इसका पता हमें नीचे की तालिका से चलता है।

वर्ष	उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष (किलोग्राम में)									
	खाद्य पदार्थ	दालें	चीनी	चर्बी	फल	सब्जी	मांस	अण्डे	मछली	दूध
१९३४-३८	१४३	२२	१४	३	२६	२५	३	०.४	१	६५
१९४८-५०	११०	२०	१३	३	२५	१६	२	०.१	२	४५

इस प्रकार हम देखते हैं कि हम पहले से मात्रा में कम भोजन ही नहीं करते वरन् भोजन गुण (Quality) में भी पहले से घट गया है। हमारे भोजन में चर्बी, प्रोटीन, विटामिन आदि आवश्यक पदार्थों की बड़ी कमी है। खाद्य पदार्थों की

कमी के कारण हमको बहुत सी विदेशी विनिमय खर्च करके विदेशो से गल्ला मगाना पड़ा। कई वर्षों तक गल्ले का आयात निरन्तर बढ़ता रहा, जैसे १९४८ में २८ लाख टन, १९४९ में ३७ लाख टन, १९५० में २१ लाख टन, १९५१ में ४७ लाख टन। इसके पश्चात् स्थिति में कुछ सुधार हुआ और इसके फलस्वरूप हमारे आयात घटते गये। इस प्रकार १९५२ में ३९ लाख टन, १९५३ में २०० लाख टन और १९५४ में ८ लाख टन गल्ला विदेशो से मगाया गया। १९५५ में भी लगभग ७ लाख टन गल्ला विदेशो से मगवाया गया। परन्तु इस वर्ष भारत ने एक लाख टन चावल का निर्यात भी किया। १९५६ की आयात १४ लाख टन थी, १९५७ की ३६ लाख टन तथा १९५८ की आयात लगभग ३२ लाख टन थी। १९५९ की आयात का अनुमान १५ लाख टन है।

भारतवर्ष की खाद्य की समस्या की ओर सबसे पहले १९१४ ई० की मूल्य-जाच समिति (Price Inquiry Committee) ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। उसने बताया था कि भारत में कृषि योग्य भूमि की अपेक्षा जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ रही है। परन्तु इससे पूर्व १८८० ई० के अकाल आयोग ने अनुमान लगाया कि भारत में ५० लाख टन गल्ला आवश्यकता से अधिक है। १८९८ ई० के आयोग का भी यही अनुमान था। इसका अभिप्राय यह है कि हमारे देश की खाद्य समस्या इस शताब्दी के प्रारम्भ से बिगड़ती जा रही है। एक अनुमान के अनुसार १९०१ और १९३१ ई० के बीच में हमारी जनसंख्या १७ प्रतिशत बढ़ी परन्तु इसी बीच में खाद्य सामग्री कुल १६ प्रतिशत बढ़ी। १९३० और १९४० के बीच में हमारी जनसंख्या १५२ प्रतिशत बढ़ी परन्तु खाद्य पदार्थ तथा दालों की उत्पत्ति ३९ प्रतिशत घट गई। १९३३ ई० में सर जान मेगा (Sir John Megaw) ने एक जाच के पश्चात् बताया था कि भारत में ३९ प्रतिशत लोगों को पर्याप्त भोजन ४१ प्रतिशत लोगों को कम भोजन तथा २० प्रतिशत लोगों को प्रायः भोजन मिलता ही नहीं। युद्धकाल तथा उसके पश्चात् की स्थिति के विषय में हम पहले ही बता चुके हैं कि वह युद्ध पूर्व के काल से भी खराब हो गई। अशोक महता समिति का अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में हमारे देश में २-३ मिलियन टन गल्ला आयात करने की आवश्यकता पड़ेगी।

खाद्य पदार्थों की कमी के कारण (Causes of the food deficit)—
भारतवर्ष में खाद्य पदार्थों की कमी के निम्नलिखित कारण हैं—

(१) हमारे देश में जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही खाद्य सामग्री उससे कम गति से बढ़ रही है। श्री० पी० के० वत्तल ने १९१३-१४ से १९३५-३६ के बीच के समय में हिसाब लगाकर बताया था कि हमारे देश में जनसंख्या १ प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ी। परन्तु खाद्य सामग्री ०.६५ प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ी। डा० ज्ञानचन्द्र ने भी बताया है कि हमारे देश में १९०० और १९३४ ई० के बीच में जनसंख्या की वृद्धि २१ प्रतिशत हुई परन्तु जोनी हुई भूमि में केवल ११ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(२) पिछले बहुत से वर्षों से हमारे देश में खाद्य पदार्थों के नीचे के क्षेत्र में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई परन्तु जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है जैसे १९२६-३० और १९३६-४० के बीच में खाद्य पदार्थों के बीच के क्षेत्र में केवल १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई परन्तु इस बीच में जनसंख्या में १५२ प्रतिशत वृद्धि हुई। इसका कारण यह है कि हमारे देश के विमान भूमि को खाद्य पदार्थों के उत्पादन से हटाकर कपास, जूट, गन्ने आदि की उत्पत्ति की ओर लगा रहे हैं।

(३) खाद्य सामग्री की कमी का एक कारण यह भी है कि अभी कुछ दशाब्दों से हमारे देश के किसान गेहूँ, चावल आदि पौष्टिक पदार्थों से अपना ध्यान हटाकर ज्वार, बाजरा, मक्का आदि कम पौष्टिक पदार्थों की ओर लगा रहे हैं। इसका पता नीचे की तालिका से चलता है—

खाद्य पदार्थ	१९१०-१५	१९१५-२०	१९२०-२५	१९२५-३०	१९३०-३५	१९३५-३८	१९१०-३८
चावल	१००	११४०	१०८४	१०७२	११०२	१०३०	३५
गेहूँ	१००	६६२	६३४	६३०	६७८	१०४२	४२
ज्वार	१००	१६७४	१६७०	२१०८	२०८८	२०६७	१०६७५
जौ	१००	२२४२	२०२६	१७२०	१७३०	१५७१	६७१
बाजरा	१००	११४०	१०५०	१२६०	१२५२	१२५१	२५०
मक्का	१००	११४०	१०६०	१०६०	११२०	१०५०	५०

उपरोक्त तालिका से विदित है कि १९१०-३८ के बीच में चावल व गेहूँ का उत्पादन तो बड़ा क्रमशः ३५ और ४२ प्रतिशत परन्तु ज्वार का १०६७ प्रतिशत, जौ का ६७१ प्रतिशत बाजरे का २५ प्रतिशत तथा मक्का का ५०%।

(४) १९३७ ई० में ब्रह्मा हमारे देश से अलग कर दिया गया जिसके फलस्वरूप हमारे देश में १३ लाख टन चावल की कमी हो गई।

(५) १९४७ ई० में देश के विभाजन पर हमारे देश को अविभाजित भारत की ८० प्रतिशत जनसंख्या तथा ७६ प्रतिशत खाद्यान्न की उपज का भाग मिला। इसी के कारण हमारे सींचे हुये भाग में भी कमी हो गई है। इसके अतिरिक्त हमारे देश को जूट तथा लम्बे रेशे वाली कपास उगाने वाले क्षेत्र का भी बहुत कम भाग मिला है जिसके फलस्वरूप हमारे देश में इन चीजों की कमी हो गई है। यदि पाकिस्तान इन चीजों को उचित मूल्य पर हमें बेचना रहता तो कोई कठिनाई उत्पन्न न होती परन्तु ऐसा नहीं हुआ। उसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन न करके अपने माल का मूल्य ४४ प्रतिशत बढ़ा दिया। इसी कारण हमको बहुत से क्षेत्रों पर कपास तथा जूट उगाना पड़ा। इसके फलस्वरूप खाद्य पदार्थों के अन्तर्गत जो धान या उसमें कमी पड़ गई।

(६) द्वितीय महायुद्ध में हमारे देश में बहुत सा अनाज विदेशों को भेजा गया तथा बहुत सा अनाज सरकार ने फौजों के लिये खरीद लिया । इसके अतिरिक्त हमारे देश में अमेरिका की सेनायें भी रही जिसके कारण गल्ले की मांग और भी बढ़ गई । इन सब बातों के कारण खाद्य सामग्री की ओर भी कमी हो गई ।

(७) प्रायः प्रतिवर्ष हमारे देश का बहुत सा अन्न वर्षा न होने, बाढ़ आने, धोले पड़ने तथा टिड्डी दल के आने से नष्ट हो जाता है । १९५५ में आसाम, बङ्गाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण करोड़ों रुपये की हानि हुई है ।

इन सब बातों के कारण हमारे देश में गल्ले की बड़ी कमी है । १९५१ ई० में जम्मू और काश्मीर को छोड़कर हमारे देश की जनसंख्या ३५ करोड़ ६८ लाख थी । यदि प्रति १०० व्यक्ति को ८६ बड़े व्यक्तियों के बराबर माना जाय तो हमारे देश की कुल संख्या लगभग ३०७ करोड़ बड़े व्यक्तियों के बराबर होती है । यदि बड़े आदमी को प्रतिशत २४ औंस भोजन दिया जाय तो हमारी जनसंख्या के लिये ४४ करोड़ टन गल्ला प्रतिवर्ष चाहिये । हमारे देश की कुछ वर्षों की उपज इस प्रकार थी—

(करोड़ टनो में)

वर्ष	चावल	गेहूँ	ज्वार, बाजरा	सब खाद्य पदार्थ
१९४६-५०	२२८	६५	१६२	४५५
१९५०-५१	२२१	६७	१४५	४४२
१९५१-५२	२२८	६२	१५४	४४४

इस प्रकार हमारे देश में प्रतिवर्ष खाद्य सामग्री की उपज लगभग ४४ करोड़ टन है । यदि इसमें से लगभग १० से १२½ प्रतिशत बीज बोने तथा नष्ट होने वाले भाग में निकाल दिया जाय तो हमारे देश के प्रतिवर्ष लोगों के उपयोग के लिये लगभग ३६ से ४० करोड़ तक गल्ला उपलब्ध होता है । इस प्रकार हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग ४०-५० लाख टन गल्ले की कमी पड़ती है । अशोक महता समिति के अनुसार गल्ले की कमी का अनुमान २०-३० लाख टन है ।

खाद्य समस्या को सुलझाने का प्रयत्न—बहुत समय तक तो सरकार ने खाद्य समस्या को सुलझाने का कोई प्रयत्न न किया, पर १९४२ ई० में जब खाद्य समस्या ने एक भीषण रूप धारण कर लिया तब सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ । अन्न की उत्पत्ति बढ़ाने के लिये सरकार ने उस वर्ष में एक 'अधिक अन्न उपजाओ योजना' (Grow-More Food Campaign) चालू की जिसके अन्तर्गत ८० लाख एकड़ भूमि अन्न उपजाने के काम में लाई गई । खाद्य समस्या की ओर अधिक ध्यान देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने एक नया खाद्य विभाग खोला । उसने खाद्य समस्या की जांच करने के लिये एक ग्रेगरी समिति (Gregory Committee) भी नियुक्त की । इस समिति ने यह बताया कि खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये विदेशों से अन्न मंगाना चाहिये, राशनिंग चालू करना चाहिये तथा

एक अन्न भण्डार बनाना चाहिये । अन्न भण्डार की सिकारिश अन्न नीति समिति (Foodgrains policy Committee) ने भी की । १९४३ ई० के अकाल के पश्चात् तो कमीशन नियुक्त किया गया था उसने इस बात के ऊपर जोर दिया कि जनता को अन्न देने का भार सरकार पर है । सरकार ने इस बात को माना और उसके पश्चात् सरकार ने लगातार विदेशों से अन्न मगाकर खाद्य समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया है । १९४८ ई० में सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास की अध्यक्षता में एक अन्न नीति की समिति नियुक्त हुई जिसने यह बताया कि अगले पाँच वर्षों में देश में एक करोड़ टन अन्न की कृद्धि होनी चाहिये । इस समिति ने वे ढङ्ग भी बताये जिनके द्वारा देश की खाद्य समस्या सुलझ सकती थी । उसने बताया कि इस देश में अधिक सिंचाई के साधन होने चाहिये । अधिक बेकार पड़ी हुई भूमि को जोतना चाहिये । खेतों को अधिक खाद देनी चाहिये अच्छे बीज का प्रबन्ध करना चाहिये और ५० करोड़ रुपये लगाकर एक Central Land Reclamation Organisation बनाना चाहिये ।

१९४७ के अन्न में महात्मा गांधी के जोर देने पर राशनिंग और कन्ट्रोल समाप्त कर दिया गया । परन्तु कुछ समय ही पश्चात् जब वस्तुओं का मूल्य बहुत ऊँचा हो गया तो सरकार ने पुनः राशनिंग चालू कर दिया । जिसके अनुसार प्रांतीय तथा केन्द्रीय सरकारों ने अन्न खरीदकर लाईसेन्सदार दुकानों के द्वारा जनता में बटवाया । सरकार ने अपनी योजना को सफल बनाने के लिये विदेशों से बहुत सा अन्न मगवाया । १९४८ ई० में २८ लाख टन, १९४९ ई० में ३७ लाख टन, १९५० ई० में ४० लाख टन व १९५१ ई० में ४७ लाख टन के लगभग अन्न विदेशों से मगवाया गया । परन्तु उसके पश्चात् से फसलों के अच्छा होने तथा कन्ट्रोल में दिनाई हो जाने के कारण गल्ले का आयात कम हो गया ।

१९४९ ई० में भारतीय सरकार ने इस बात की घोषणा कि की चाहे जो भी कुछ हो मार्च १९५१ ई० के पश्चात् भारतवर्ष अन्न पर एक दाना भी विदेशों से नहीं मगायेगा । किन्तु खेत का विषय है कि सरकार इस योजना में सफल न हो सकी और खाद्य पदार्थों में स्वावलम्बी हो जाने की तिथि को मार्च १९५२ तक के लिये बढ़ा दिया गया । पर सन् १९५२ में भी सरकार अपनी योजना में सफल न हो सकी । योजना कमीशन के मतानुसार भविष्य में कई वर्षों तक भारतवर्ष को तीस लाख टन गल्ला विदेशों से मगाना पड़ेगा । परन्तु पिछले दो वर्षों में फसल के अच्छा होने के कारण हमारा गल्ले का आयात तीस लाख टन न होकर २३ लाख टन तथा ६ लाख टन के लगभग हो गया । परन्तु १९५६ में फिर १४ लाख टन गल्ला विदेशों से मगाना पड़ा । १९५८-५९ में २५ लाख टन गल्ला विदेशों से मगवाया जायेगा । १९५९-६० का अनुमान १५ लाख टन है ।

केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने भी अन्न की उत्पत्ति बढ़ाने के लिये बहुत कार्य किये, जिनमें के ट्रयबुनल लगवाना, अच्छी खाद व बीज

देना, नई भूमि के ऊपर खेती करना आदि मुख्य है। हाव ही में केन्द्रीय सरकार अन्तर्राष्ट्रीय ऋण से ऋण लगी हुई भूमि को सुधारने के लिये एक करोड़ डालर ऋण लिया है। पानी की समस्या को सुलझाने के लिये बहुत सी बड़ी-बड़ी सिंचाई की योजनाएँ भी बनाई गई हैं। मसुदा राष्ट्र भी हमारे देश की खेती की उन्नति में बहुत सहायता पहुँचा रहा है और उसने पॉइंट ४ (Point 4) प्रोग्राम के अन्तर्गत भारतवर्ष को ५ करोड़ डालर की सहायता देने का वचन दिया। इस धन की सहायता से लोहे, फौलाद का प्रबन्ध, खाद का प्रबन्ध, टिड्डी का रोकना, समुद्र में मछलियों की उत्पत्ति बढ़ाना, दूधबैल चरवाना आदि काम किये जायेंगे। इस योजना में भारतवर्ष को अपना भी धन लगवाना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखने हैं कि हमारे देश में खाद्य समस्याओं को सुलझाने के लिये सरकार बहुत प्रबन्ध कर रही है।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत खाद्य नीति—इन सब प्रयत्नों के अतिरिक्त सरकार ने खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये पंचवर्षीय योजना में एक बड़ी धन राशि रखी गई है। ऐसी आशा की जाती है कि खेती सामूहिक विकास योजना (Community Development Projects) पर ३६०.४३ करोड़ रुपये तथा सिंचाई तक बिद्युत उत्पादन पर ५६१.४१ करोड़ रुपये व्यय होंगे और इससे १६५५-५६ तक लगभग ७६ लाख टन अधिक अन्न उत्पन्न होगा। परन्तु यह हर्ष का विषय है कि १६५०-५१ तथा १६५३-५४ के बीच हमारा खाद्यान्न ६५ लाख टन बढ़ गया है। द्वितीय योजना में १० मिलियन टन अधिक अन्न उपजाने की योजना है जिसकी सिंचाई, खाद, बीज नई भूमि को प्राप्त करके तथा भूमि की उन्नति करके प्राप्त किया जायगा।

खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये सरकार ने खाद्य-नियन्त्रणों को धीरे धीरे हटा दिया है और अब प्रायः सभी चीजों पर से नियन्त्रण हट गया है। नियन्त्रण हट जाने के कारण हमारी खाद्य समस्या की गम्भीरता बहुत कुछ कम हो गई है। दो वर्षों तो अनाज इतना पैदा हुआ कि गहूँ, चने आदि के भाव बहुत गिर गये और भविष्य में और गिरने की आशा थी। इन वस्तुओं के मूल्यों को गिरने से रोकने के लिये सरकार ने निश्चय किया कि वह दूसरी फसल के बाजार में आने ही में छरीदेगी जिससे कि गहूँ का मूल्य १० रुपये मन से नीचे न गिरे। परन्तु अभी कुछ दिनों से गन्ने के मूल्यों में फिर बड़ी वृद्धि होती जा रही है जिसके फलस्वरूप देश के मजदूरों व कर्मचारियों में बड़ी अशांति बढ़ती जा रही है। इसलिये भारत सरकार ने एक केन्द्रीय खाद्य जाच समिति की नियुक्ति की जिसके अध्यक्ष श्री अशोक मेहता थे। इस समिति ने खाद्य सामग्री के बढ़ते हुए मूल्यों की जाच करके अपनी रिपोर्ट दी है।

समिति ने सुझाव दिया है कि मूल्य सम्बन्धी नीति के निश्चित करने तथा इसको लागू करने के लिये एक प्रोग्राम बनाने के लिये एक उच्च-शक्ति मूल्य-स्थिरता

वाड (Hight power price stabilization Board) स्थापित किया जाये। इसी के साथ एक खाद्य-सामग्री स्थिरता संस्था (Foodgrains stabilization organisation) भी सम्बन्धित होगी जो कि मूल्यों को स्थिर रखने के लिए खाद्य पदार्थों के क्रय-विक्रय काय करेगी। समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि गैर सरकारी लोगों को एक केन्द्रिय खाद्य सलाहकार समिति स्थापित की जाय जा कि खाद्य मन्त्रालय तथा मूल स्थिरता बोर्ड को सहायता करे। इसमें कृषि, व्यापार, मजदूरी, उद्योगी, उपभोक्ताओं, बैंकिंग, सहकारी संस्थाओं, मुख्य मुख्य राजनीतिक दलों, अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि होंगे। समिति का मत है कि न तो पूर्ण मूल्य नियन्त्रण ही होना चाहिये और न पूर्ण स्वतन्त्र व्यापार ही होना चाहिये। समिति की राय में मूल्य नियन्त्रण व्यापार में बाधा बनकर खड़ा नहीं होना चाहिये वरन् उसको ठीक करने वाला होना चाहिये। ऐसा करने के लिये केवल खाद्य पदार्थों के मूल्यों की ओर ही ध्यान देना होगा वरन् कुछ ऐसी चीजों के मूल्यों की ओर भी ध्यान देना होगा जो गल्ले के मूल्य पर अपना प्रभाव डालती है। समिति ने कहा है कि पश्चिमी बङ्गाल के पूर्वी तथा उत्तरी जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में बाढ़, वर्षा की कमी आदि होने के कारण जो आपत्ति आती है उसको शीघ्र ही दूर किया जाय तथा उन पर शीघ्र कार्य किया जाय। समिति का यह भी सुझाव है कि थोक व्यापार का समाजीकरण किया जाय। इसके लिये प्रारम्भ में सरकार गल्ले की खरीद व बिक्री कर सकती है। बाजार में व्यापार करने वाले व्यापारियों को लाइसेंस लेना का कहा जाय। सरकार को चावल व गेहूँ का एक रिजर्व बनाना चाहिये तथा चावल व गेहूँ का आयात करना चाहिये। सरकार को यह प्रोत्साहन भी करना चाहिये कि लोग मोटा अनाज खायें। समिति ने सुझाव दिया है कि गल्ले का वितरण उचित मूल्यों की दुकानों अथवा राशन की दुकानों अथवा सहकारी समितियों द्वारा करना चाहिये। समिति ने गल्ले का उत्पादन बढ़ाने के भी कुछ सुझाव दिये हैं और उसके साथ साथ जनसंख्या के रोक-थाम पर भी जोर दिया है।

यहाँ यह बात बताने योग्य है कि समिति के सुझानों पर देश में बड़ा बाढ़ विवाद हुआ और सरकार भी पूर्णरूप से समिति के मत में महत्त्व नहीं है।

१९५६-६० में भारत सरकार ने निश्चय किया है कि वह गेहूँ व चावल में राज्य व्यापार (State Trading) करेगी। कृषि मन्त्रालय द्वारा प्रस्तुत रूप रेखा के अनुसार खाद्यान्नों के राज्य व्यापार योजना के दो अङ्ग हैं। एक अन्तरिम आयोजन और दूसरे अन्तिम रूप। अन्तरिम व्यवस्था में एक तो थोक व्यापारियों के द्वारा ही राज्य व्यापार होगा और अभी इसमें गेहूँ और चावल ही आते हैं। थोक व्यापारी लाइसेंस प्राप्त व्यापारी होंगे जो किसानों से निर्धारित मूल्य पर अनाज क्रय कर नियन्त्रित भावों पर बेचेंगे। यह क्रय-विक्रय का न लाभ न घाटा के आधार पर होगा। अन्तरिम माल में सहकारी संगठन ज्यों ज्यों संगठित होते जायेंगे वे अधिक थोक व्यापार अपने हाथ में लेते जायेंगे।

योजना के अन्तिम रूप में ग्राम-स्तर पर सहकारी समितियाँ अनाज एकत्र करेंगी तथा उसे हाट सहकारी समितियों को पहुँचा देगी जिससे उपभोक्ता अपनी आवश्यकतानुसार ख़य करेंगे।

इस योजना का विरोध कई बातों के कारण किया गया है। लोगों का कहना है कि सरकार के पास यह कार्य करने के लिये साधन नहीं हैं। इसके अतिरिक्त कई लाख व्यापारी जो गल्ले के काम में लगे हुए हैं वे बेकार हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त लोगों का यह भी कहना है कि गावों से उचित रूप में न तो गल्ले का संग्रह ही हो सकेगा और न ही उसका उचित वितरण।

ऐसा अनुमान है कि केन्द्रीय सरकार गेहूँ और चावल का २-३ मिलियन टन का एक बफर फूड स्टॉक (Buffer Food Stock) बनायेगी। यह गल्ला देश के भीतर से एकत्र किया जायगा तथा थोड़ा गल्ला विदेशों से भी आयात किया जायगा।

इसके अतिरिक्त सरकार सारे देश को कुछ क्षेत्रों में वाटना चाहती है। वे क्षेत्र जिनमें गल्ले की कोई कमी नहीं होती उनको उन क्षेत्रों से अलग रखा गया है जिनमें गल्ले की कमी होती है। इसके अतिरिक्त गल्ले में स्ट्रैबजी को समाप्त करने का प्रयत्न किया जायगा।

सरकार को क्या करना चाहिये—सरकार को खाद्य-समस्या को सुलझाने के लिये अभी कुछ करना बाकी है। हमारे देश में ठीक आँकड़ों की बहुत कमी है। बिना ठीक आँकड़ों के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। ठीक आँकड़ों को एकत्र करने के लिये सरकारी तथा गैर सरकारी सभी प्रकार की सरथाओं से काम लेना पड़ेगा।

सरकार को चाहिये कि वह खेती को अधिमान का पद दे। उसको चाहिये कि वह खेती के लिये अधिक धन खर्च करे और खेती की देख-भाल करने के लिये अधिक मनुष्यों को नियुक्त करे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में केन्द्रीय सरकार एक आदमी के पीछे ८० रुपया व्यय करती है। पर हमारी केन्द्रीय सरकार कुल एक आदमी व्यय करती है। हमारे देश में केन्द्रीय सरकार जितना सब मदों पर खर्च करती है उसमें से हर १०० रुपये के पीछे केवल १२ आने खेती पर खर्च होते हैं। राज्य सरकारें भी, जिनके ऊपर खेती की उन्नति करने का मुख्य भार है, १६४७-४८ में इस प्रकार से खर्च करती थीं—

आसाम कुल खर्च का १५ प्रतिशत, बिहार ४५ प्रतिशत, बम्बई ७ प्रतिशत मध्य प्रदेश ३२ प्रतिशत, मद्रास ४ प्रतिशत, पूर्वी पंजाब २२ प्रतिशत और उत्तर प्रदेश ३६ प्रतिशत।

भारतवर्ष में दूसरे देशों की अपेक्षा खेती की देख-भाल करने वाले व्यक्ति भी बहुत कम हैं। इस देश में भारतीय सरकार ने एक करोड़ व्यक्तियों के पीछे केवल ६ कृषि अफसर (Agricultural Officer) रखे हुये हैं। पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका

रित करना तथा उनको एक सूत्र में लाना हो। केन्द्रीय सरकार का कार्य केवल नीतियों को निर्धारित करना तथा उनको एक सूत्र में करना होना चाहिये।

इन समिति ने यह भी बताया कि दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन नृप केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को देन चाहियें तथा कम समय वाले ऋण सहकारी समितियों को देना चाहियें। इसने यह भी बताया कि छोटी छोटी सिंचाई की योजनाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हमारी खाद्य उत्पत्ति बढ़ाने की आशा है।

१९५१-५२ के पश्चात् से इस दृष्टि से जा कार्य किया गया है वह दो प्रकार का है—पहला कुए, तालाब छोट गांव, ट्यूब वेल आदि बनाना, कट्टर, बडिंग तथा प्रकार पड़ी हुई भूमि को साफ करके खेती के योग्य बनाना तथा दूसरा, खाद, बीज आदि बांटना। नीचे की तालिका से यह पता चलता है कि भारत सरकार, ने राज्य सरकारों को 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत १९५१ से ५६ तक कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की है।

योजना का नाम	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६
	वास्तविक करोड़ रु० में	वास्तविक करोड़ रु० में	वास्तविक करोड़ रु० में	वास्तविक करोड़ रु० में	स्वीकृत करोड़ रु० में
लघु सिंचाई	७४५	८०१	९८४	७९५	१०९९
भूमि प्राप्ति	२७५	६६०	२८४	३३३	३१८
खाद	१४५	१५८	६१५	७४४	९६५
बीज	०५५	०६१	०५३	०६५	१२२
अन्य	०९३	१०४	०७९	०७१	०९३
योग	१३०४	१४०४	२०१५	१९९८	२७९७

लघु सिंचाई—प्रथम योजना में यह अनुमान किया जाता है कि लगभग १ करोड़ एकड़ भूमि छोटी योजनाओं द्वारा तथा ६३ लाख एकड़ भूमि बड़ी योजनाओं द्वारा सींची गई। दूसरी योजना में सींचा हुआ भाग २१० करोड़ एकड़ बढ़ा दिया जायगा जिसमें से ६० लाख एकड़ छोटी योजनाओं से बढ़ेगा।

खाद—प्रथम योजना से पहले देश में अमोनियम सल्फेट का उपभोग २७५ लाख टन था। परन्तु योजना काल के प्रथम ३ वर्षों में इसका उपभोग बढ़कर ६१० लाख टन हो गया। दूसरी योजना में नवजन खाद का उपभोग १८ लाख टन हो जायगा। नई तरह की खाद का प्रचार बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

भूमि प्राप्ति करना—प्रथम योजना काल में केन्द्रीय टैंक्टर विभाग ने १७८४ लाख एकड़ भूमि तथा राज्य टैंक्टर विभागों ने १७ लाख एकड़ भूमि प्राप्त की। इसमें अतिरिक्त बहुत सा क्षेत्र किसानों ने स्वयं उन्नत किया। दूसरी योजना में १५ लाख एकड़ भूमि को प्राप्त किया जायगा तथा २० लाख एकड़ भूमि पर टैंक्टर विभागों द्वारा उन्नति की योजनाएँ चलाई जायगी।

उन्नत बीज—उन्नत बीजों का बटवारा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। यह कार्य अधिकतर सहकारी समितियों के द्वारा किया जा रहा है। दूसरी योजना में प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्र में एक या दो बीज गोदाम स्थापित किये जायेंगे।

जापानी ढंग की खेती—१९५५-५६ में १९५३ लाख एकड़ भूमि पर इस प्रकार की खेती हो रही थी। दूसरी योजना में इस क्षेत्र को बढ़ाकर ४० लाख एकड़ कर दिया जायगा।

Q 29 What were the causes of famines in India ? What measures were taken by the Government of India to meet the situation and with what effect ?

प्रश्न २९—भारतवर्ष में अकाल पड़ने के क्या कारण थे ? भारतवर्ष सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिये क्या किया और उसका क्या प्रभाव पड़ा ?

भारत में अकाल का इतिहास—भारत में बहुत पुराने समय से अकाल पड़ते आये हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इनका वर्णन आता है। मुसलमानों के समय में भी बहुत से भीषण अकाल पड़े पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में वे कुछ अधिक सख्ता में पड़े। १७७० ई० से १८५४ ई० तक बारह भयंकर अकाल पड़े। इनका कारण वर्षा की कमी तथा कम्पनी राज्य की अव्यवस्था थी। कम्पनी के पश्चात् जब भारतवर्ष ब्राउन के अधिकार में चला गया तब भी इस देश में बहुत से अकाल पड़े। एक अकाल उत्तरी भारतवर्ष में १८५० ई० में पड़ा जिसका कारण वर्षा न होना था। सरकार ने लोगों को सहायता के रूप में काम दिया और जो काम नहीं कर सकते थे उनको बिना काम लिये सहायता दी। इसके पश्चात् १८६६ ई० में एक दूसरा भयंकर अकाल पड़ा जिसमें उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बङ्गाल और बिहार आदि प्रांत अकालग्रस्त हो गये। इसमें उड़ीसा प्रदेश के लगभग दस हजार आदमी मर गये। एक दूसरा अकाल १८६८ में उत्तरी तथा मध्य भारत में पड़ा। यह अकाल अन्न, चारे और पानी की कमी के कारण पड़ा। इसके साथ ही साथ हैजे की बीमारी भी फैली। इसी कारण बहुत से आदमी इसमें मर गये। इसके पश्चात् एक अकाल १८७३ में पड़ा जिसने बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों पर अपना प्रभाव डाला। इसी के पश्चात् इससे भी एक भीषण अकाल १८७६ में मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश व पंजाब में पड़ा। इस अकाल में सरकार तटस्थ बंठी रही और उसने घोषणा की कि अकाल पीड़ित लोगों को बचाना उसके कर्तव्य से बाहर है। इसमें बहुत से आदमी मरे। इसके पश्चात् १८८८ में एक अकाल पड़ा जिसने सारे भारतवर्ष पर अपना प्रभाव डाला। परन्तु इस समय तक सरकार अपने कर्तव्य को जान गई थी और उसने बहुत बड़े पैमाने पर अकाल पीड़ितों की सहायता की। इस

काल में सरकार के सात करोड़ रुपये से अधिक खर्च हो गये । इसके दो साल पश्चात् ही १८९९ ई० में भी एक और भीषण अकाल पड़ा जिसने १,८९००० वर्गमील पर प्रभाव डाला और २८०,००,००० आदमी इसके शिकार हुये । इस अकाल में सरकार के दस करोड़ रुपये खर्च हुये । बीसवीं शताब्दी में अकाल बहुत ही कम पड़े । १९२९-३० में एक अकाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब में पड़ा । १९३६ में एक दूसरा अकाल बङ्गाल तथा भारत के दूसरे भागों में पड़ा । इसके कुछ समय पश्चात् १९४३ ई० में एक भीषण अकाल पड़ा जिसमें लगभग ३५ लाख आदमी मर गये । इसका कारण यह था कि ब्रह्मा के ऊपर जापान का अधिकार होने से इस देश में वहाँ का चावल आना बन्द हो गया । दूसरे इस देश से बहुत सा अन्न विदेशों को भी भेजा गया । तीसरे, कुछ प्राकृतिक विपदायें जैसे टिड्डी, बाढ़, तूफान आदि भी उस समय आई । चौथे, एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में गन्ना आना जाना बन्द हो गया । पाँचवें, आने-जाने की सुविधायें भी बहुत कम थी । छठे, कन्ट्रोल व राशनिंग भी कुछ गलत ढंग से लगाया गया । सातवें व्यापारी लोग जनता की विपत्ति की चिन्ता न करने हुये अधिक रुपया कमाने की चिन्ता में लगे हुये थे । अकाल इस देश से अभी तक भी नहीं गये । यहाँ पर १९४५ में लड़ाई के समाप्त होने के पश्चात् से ही अकाल की स्थिति हो गई । जिसका प्रभाव प्रायः सार भारतवर्ष पर हुआ । अभी हाल ही में बङ्गाल, मद्रास, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब के हिस्सर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अन्न और जल की बहुत कमी थी । राजस्थान और हिस्सर आदि प्रदेशों में तो चारे की भी बहुत कमी थी जिसके कारण संकड़ों पशु मर गये । बहुत से पशुओं को आस-पास के राज्यों में भेज दिया गया ।

अकाल के कारण—

इस प्रकार हम देखते हैं कि अकाल प्राकृतिक तथा आर्थिक कारणों से पड़ते हैं । प्राकृतिक कारणों से वर्षा की कमी या अधिकता, ओलों का पड़ना, टिड्डी दल का आना, बाढ़ से फसलों का नष्ट होना आदि बातें सम्मिलित हैं । आर्थिक कारणों में रोजगार का न होना, अन्न का ठीक बटवारा न होना, ऊँचे दामों का होना, आने जाने के मार्गों की कमी होने के कारण अन्न के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कठिनाई होना आदि सम्मिलित हैं ।

अकाल के प्रभाव—

समाज के ऊपर अकाल का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है । इससे बहुत से मनुष्य व पशु मर जाते हैं और जो बच जाते हैं वे इतने दुर्बल हो जाते हैं कि बहुत समय तक वे कोई काम करने योग्य नहीं रहते । इसके कारण देश का व्यापार प्रायः नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है और देश में पूँजी की भी बहुत कमी हो जाती है, चारों ओर आपत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं । ऐसे समय में लोगों का बहुत भारी नैतिक पतन भी हो जाता है । सरकार की आय भी घट जाती है और उल्टे उसको लोगों की सहायता

मे उतने ही व्यक्तियों के पीछे ४०८ कृषि अपसर हैं। इङ्ग्लैंड जैसे छोटे से देश में हमारे देश की अपेक्षा २० गुने कृषि अपसर हैं। हमारे देश में दूसरे देशों के समान इस बात की आवश्यकता है कि कृषि विभागों का कृषक के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अधिक से अधिक कृषि अपसर रखे जायें।

देश के अन्दर अधिक से अधिक सहकारी समितियाँ खाली जानी चाहियें। ये समितियाँ कृषक तथा सरकार के बीच अच्छा सम्बन्ध स्थापित कर सकती हैं। ये विदेशों से खेती के यन्त्र तथा खाद भी मंगा सकती हैं कृषकों को अच्छा बीज भी दे सकती हैं, उनका ऋण भी दे सकती हैं और इस प्रकार के व्यक्तियों को भी नौकर रख सकती हैं जो किसानों को कृषि सम्बन्धी शिक्षा दें। ये आकड़े भी एकत्र कर सकती हैं।

८ सितम्बर १९४८ ई० को कृषि मन्त्री सभा (Agricultural Ministers Conference) के सम्मुख भाषण करते हुए श्री जयराम दौलतराम ने कहा था कि मेरे विचार में अमेरिका तथा दूसरे देशों में कृषि की उन्नति इस कारण नहीं हुई कि उन देशों में बड़ी-बड़ी मशीनों से काम लिया गया बल्कि इस कारण हुई कि उन देशों में कृषि की उन्नति करने के लिए बहुत अधिक सत्या में मनुष्य लगे हुए हैं। भूतकाल में चाह हमारी जो भी योजनाएँ रही हो अबवा भविष्य के लिए हम चाह जो भी योजना बनायें हम उस समय तक सफल न होंगे जब तक कि हम अधिकाधिक सत्या में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करेंगे जो इन योजनाओं को हमारे देश के लाखों कृषकों तक पहुँचा सकें।

सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि खाद्य-सामग्री का बटवारा समस्त देश में ठीक रूप से हो। इस हनु देश के उन भागों को जहाँ खाद्य-सामग्री की अधिकता है उन भागों से जोड़ देना चाहिये जहाँ खाद्य-सामग्री की कमी है। सरकार को एक भण्डार भी बनाना चाहिये जिसमें हर समय अन्न रखा जाय जिसकी आवश्यकता के समय काम में लाया जा सके।

सरकार को यह भी देखना चाहिये कि यन्न को ठीक प्रकार से गोदामों में एकत्र किया जाय। ऐसा न करने से हमारे देश का लाखों मन अनाज हर वर्ष नष्ट हो जाता है।

यह भी आवश्यक है कि सरकार आगामी कुछ वर्षों के लिए कृषि वस्तुओं का अधिनतम व न्यूनतम मूल्य निश्चित करे। इस प्रकार गल्ले के एकत्र करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जायगी। इसके साथ साथ सरकार को यह भी देखना पड़ेगा कि निश्चित किये गये मूल्यों में अधिक व कम पर सौदे न हो अन्यथा मूल्य निश्चित करने से कोई लाभ न होगा केवल घूसखोरी को प्रोत्साहन मिलेगा।

इस बात का भी प्रयत्न करना चाहिये कि साख तथा दूसरी विकासात्मक सुविधाओं अथ-सहायता अनुदान आदि का सम्बन्ध सरकार द्वारा उन्नित मूल्य दुकानों के लिये निश्चित मूल्य पर खरीदे गये गल्ले से होना चाहिये।

ऐसा करने से इन दुकानों का देश की बाजारी मशीनरी में एक महत्वपूर्ण स्थान हो जायगा।

यह भी आवश्यक है कि गल्ले आदि के पीछे बैंक व्यापारियों को साख प्रदान न करें। यहाँ यह बताया जा सकता है कि रिजर्व बैंक कई बार धन को ऐसा न करने का आदेश दे चुका है परन्तु वह अभी सफल नहीं हुआ।

सरकार को यह भी देखना चाहिये कि गल्ले में कोई मट्टे वाले सीदे न करे क्योंकि भविष्य के मूल्यों के कारण ही व्यापारियों तथा स्टॉक करने वालों को माल एकत्र करने का प्रोत्साहन मिलता है।

सरकार को खेती की उच्चतम सीमा भी निश्चित कर देनी चाहिये और उसकी शीघ्र ही कार्यान्वित करना चाहिये। ऐसा करने से बड़े-बड़े उत्पादकों की गल्ले को एकत्र करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जायगी।

आशा है कि ये सब प्रयत्न करने से हमारे देश की खाद्य-समस्या अवश्य सुलझ जायगी।

Q 28 Analyse the causes of the meagre achievements of the 'Grow-More food campaign' in India

प्रश्न २८—भारतवर्ष में 'अधिक अन्न उपजाओ योजना' की कम सफलता के कारण लिखो।

उत्तर—'अधिक अन्न उपजाओ-योजना' इस देश में १९४३ ई० से चालू हुई। इसका उद्देश्य यह था कि देश की खाद्य समस्या सुलझ जाय। इस योजना की मुख्य विशेषतायें ये हैं—

(१) खाद्य सामग्री बढ़ाने के लिये नई तथा खाली पड़ी हुई भूमि को काम में लाया जाये। दो दो फसलें उत्पन्न की जाय। दूसरी फसलों से भूमि को हटा कर खाद्य सम्बन्धी फसलें उगाई जायें। नई भूमि को जोतने का प्रोत्साहन देने के लिये सरकार को चाहिये कि वह बिना व्याज के ऋण दे, बिना लगान पट्टे पर भूमि दे, लगान में छूट की जाय, मुफ्त सिंचाई का प्रबन्ध किया जाए अथवा सस्ते दामों पर इसका प्रबन्ध हो, कम मूल्य पर किनारों को बीज दिया जाए और लगान सम्बन्धी कानून में बदल की जाए।

(२) सिंचाई के लिये नहरें अथवा कुय बनाकर अधिक जल का प्रबन्ध किया जाये।

(३) खाद्य का अधिक उपयोग किया जाए।

(४) अच्छे बीज का भी प्रबन्ध हो।

इस योजना के अन्तर्गत प्रान्तों से यह कहा गया कि वे नई भूमि प्राप्त करें कुये बनायें, अच्छा बीज काम में लायें, हरी खाद तथा दूसरी प्रकार की खादों को

प्रयोग करें। उनसे यह भी कहा गया कि वे पशुओं की उन्नति की ओर भी ध्यान दे तथा विदेशों से ट्रैक्टर मँगवाये और खेती की उन्नति के लिये हर प्रकार के प्रयत्न करें।

यह योजना केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के सहयोग से चलाई गई। इसमें केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों का भाग ५०-५० था। योजना के पहले चार वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को ऋण व अनुदान के रूप में सहायता दी जिससे कि वे उत्पत्ति बढ़ा सकें। अब केन्द्रीय सरकार निश्चित प्रोग्राम के लिये सहायता प्रदान करती है। आजकल इस योजना के दो प्रकार के कार्यक्रम हैं—निर्माण कार्यक्रम तथा पूर्ति कार्यक्रम। पहले में कुआँ, तालाबों, छोटे-छोटे बाँधों, ट्यूबवells आदि का बनाना तथा उनकी मरम्मत सम्मिलित है। दूसरे में खाद व अच्छे बीजों का वितरण है।

१९५१-५२ से इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि इस योजना को विस्तृत बनाने के बदले गहन बनाया जाए। १९५०-५१ के पश्चात् पंचवर्षीय योजना चालू हो गई जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को अधिक अन्न उपजाओ योजना के लिये बहुत सा धन दिया है। इस योजना की नई नीति यह है—

- (१) स्थायी उन्नति की योजनाओं जैसे सिंचाई तथा भूमि की उन्नति की ओर अधिक ध्यान दिया जाए।
- (२) बड़े पैमाने पर ट्यूबवells बनाने का कार्य किया जाए।
- (३) उन क्षेत्रों में जहाँ पर्याप्त वर्षा अथवा सिंचाई के साधन हैं खाद व उन्नत बीज बाँटे जायें।
- (४) पशुओं, मछलियों तथा बागवानी की उन्नति में सहायता प्रदान करना।
- (५) हम सिद्धान्तों को मानना कि केन्द्र की सहायता धीरे-धीरे समाप्त कर दी जाये।

केन्द्रीय सरकार पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों को खेती की उन्नति के लिये जो सहायता प्रदान करती है वह अधिक अन्न उपजाओ योजना के लिए ही है। १९५१-५२ में केन्द्र ने छोटी सिंचाई की योजनाओं, भूमि प्राप्ति करने, खाद व बीजों के लिये १७ ३९ करोड़ रुपये की अनुमति दी। परन्तु उसमें से केवल ११ २९ करोड़ रुपया खर्च हुआ। १९५२-५३ में १९ ३५ करोड़ की अनुमति दी गई परन्तु १४ १६ करोड़ रुपया खर्च किया गया तथा १९५३-५४ में २१ ७४ करोड़ की अनुमति दी गई परन्तु खर्च का पता नहीं। १९५६-५७ के लिए २५ ६२ करोड़ रुपये राज्यों को देने के लिए रखे गये।

इस योजना के सम्बन्ध में यह कहावत चरितार्थ होती है—‘घोड़ा पहाड़ निकला चूहा’। इसकी हर तरफ बड़ी भूमिधाम मची। विज्ञापनों द्वारा जनता में इसका सूत्र प्रचार किया गया। इस प्रकार इस योजना पर सरकार ने करोड़ों रुपया व्यय किया पर फल कुछ भी न निकला। जितना प्रयत्न हुआ उतनी ही खाद्य

समस्या भयङ्कर होती चली गई और खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति बजाये बढ़ने के घट गई। यह बात नीचे दी हुई तालिका से अच्छी प्रकार समझ में आ सकती है।

वर्ष	क्षेत्रफल	उत्पत्ति दस लाख टनोमे	प्रति एकड़ उत्पत्ति पींडो मे
१९३६-३७ से १९३८-३९ का औसत	१५ ८८	४० ६	५७७
१९४२-४३	१६४०	४४०	६०३
१९४३-४४	१६६०	४५०	६१२
१९४४-४५	१८३०	४६०	२६४
१९४८-४९	१८६६	४४०	५३२
१९४९-५०	१९५६	४५६	५२५

इस प्रकार हम देखते हैं कि १९४३-४४ की अपेक्षा १९४९-५० में भी देश में खाद्य-सामग्री की उत्पत्ति में बहुत कमी थी।

इस बात की खोज करने के लिये रिजर्व बैंक तथा और दूसरी संस्थाओं ने बहुत प्रयत्न किया है। इनके मतानुसार इस योजना की सफलता के निम्नलिखित कारण हैं—

(१) देश के किसी भी भाग में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने से पूर्व जितने क्षेत्रफल पर खेती होती थी उनमें ५ प्रतिशत से अधिक कहीं भी वृद्धि नहीं हुई है।

(२) खाद्य पदार्थों पर कंट्रोल होने तथा तन्हाकू आदि पर न होने के कारण लोगों ने खाद्य पदार्थों को बोना बन्द कर दिया।

(३) जैसा कि ऊपर की तालिका दिखाया गया है, यद्यपि खाद्य-पदार्थों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई, तो भी प्रति एकड़ उत्पत्ति घटती चली गई।

बम्बई सरकार ने भी इस योजना की सफलता के कारण जानने का प्रयत्न किया। उसकी छान-बीन से पता चला कि इस राज्य में यह योजना निम्नलिखित कारणों से असफल हुई—

(१) सरकार के पास आवश्यकता की अपेक्षा साधन बहुत कम थे और जिनने भी ये उनका वितरण उत्तम रीति से नहीं हुआ।

(२) सरकार के पास योजना के लिये देखभाल करने वाले व्यक्ति बहुत कम थे। इसके फलस्वरूप जो साधन अन्न-उत्पत्ति के काम आने चाहिये थे वे दूसरी वस्तुओं के उत्पन्न करने में व्यय हो गये।

(३) इस योजना में दिखावट अधिक हुई और काम कम हुआ। सरकार ने यह प्रयत्न नहीं किया कि वर्तमान साधनों की अधिक उपयोगी बनाया जाय वरन् उसने यह प्रयत्न किया कि नये साधनों के प्रयोग द्वारा चकाचौंध करने वाले फल दिखाये जायें। उदाहरण के लिये पुराने कुओं की मरम्मत करने के बदले सरकार ने नये कुएँ बनवाये।

यता करने के लिये बहुत सा रुपया खर्च करना पड़ता है ।

भारत सरकार की अकाल सम्बन्धी नीति—भारतीय सरकार ने १८३६-३८ के अकाल के बाद एक कमिशन की नियुक्ति की जिसने यह बात बताई कि सरकार को चाहिये कि अकाल के समय जनता की सहायता करे । जो मनुष्य काम कर सकते हैं उनको काम दे, जो काम नहीं कर सकते उनको बिना कुछ लिये सहायता दे । अन्न के वितरण करने का कार्य जनता ही के हाथ में रहना चाहिये । यदि जनता सुचारु रूप से इस कार्य को न कर सके तो सरकार को स्वयं यह कार्य करना चाहिये । जो लोग खेती कर रहे हैं उनको ऋण दिया जाये और जिस अन्न में फसलें नष्ट हो गई हैं उस अन्न तक लगान में छूट करनी चाहिये ।

सरकार ने इन सब बातों को मान लिया और आगे के अकालों में इसी नीति से काम लिया गया । सरकार ने अकाल सम्बन्धी कानून बनाया और उसकी जांच १८६६-६७ वाले अकाल में की । अकाल में ४० लाख लोगों को सहायता दी गई और सरकार का ३½ करोड़ रुपया खर्च हुआ । इसमें से १½ करोड़ रुपया ऋण के रूप में लोगों को दिया गया और १½ करोड़ रुपयों की लगान में छूट की गई । १½ करोड़ रुपया दान के रूप में खर्च किया गया । फिर भी अकाल में अंग्रेजी भारत में ३½ लाख मनुष्य मर गये । १८६६ के अकाल कमिशन ने यह बात बताई कि अकाल पीड़ितों को बिना कुछ लिये सहायता देनी चाहिये और अलग-अलग स्थानों पर अकाल पीड़ितों की सहायता का प्रबन्ध करना चाहिये । १९०१ के अकाल कमिशन ने इन बातों की निफारिश की कि अकाल पड़ते ही शीघ्रतासे लगान की छूट कर देनी चाहिये और तत्काली ऋण लोगों को देना चाहिये । उसने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय कृषि की समस्याएँ सहकारी समितियों द्वारा सुलझ सकती हैं । उसने यह भी बताया कि अकाल को रोकने के लिये सिंचाई का प्रबन्ध होना चाहिये । सरकार ने इन सब बातों को मान लिया । १९०४ ई० में एक सहकारी नाबख्श समिति ऐक्ट पास किया गया जिसने किसानों को बहुत लाभ पहुंचा । इसके पश्चात् सरकार का ध्यान नहीं बनवाने की ओर भी लग गया और पचासो करोड़ रुपया खर्च करके सरकार ने देश के बहुत से भागों में नहरें बनाई ।

अकाल निवारण कोष (Famine Relief Fund)—

१८३६ ई० में अकाल से बचने के लिये सरकार ने एक योजना बनाई जिसके अनुसार हर वर्ष डेढ़ करोड़ रुपया एक कोष में इसलिये एकत्रित किया गया जिससे अकाल में बचने के लिये लगातार कुछ न कुछ काम होना रहे । इस कोष में १९१६ के ऐक्ट के अनुसार केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारें एक निश्चित धन राशि हर वर्ष जमा करती थी । इस कोष के अतिरिक्त एक ट्रस्ट फंड भी खोला गया जिसमें महाराजा जयपुर ने गन्दूह लाख रुपया दान किया । इसके पश्चात् भी इन ट्रस्ट में बहुत सा धन एकत्रित किया गया । इस ट्रस्ट का रुपया नूतन पर चड़ा हुआ है और

उसकी आय से सहायता देने का कार्य किया जाता है ।

अकाल सम्बन्धी नयी नीति—आजकल हर राज्य सरकार ने अकाल रक्षक कोष (Famine Insurance Fund) खोला हुआ है जिसमें हर वर्ष बजट में से कुछ न कुछ धन जमा किया है । आजकल सहायता पहुंचाने का कार्य निम्नलिखित ढंग से होता है ।

जिस समय अकाल पड़ने का डर होता है उस समय सरकार लोगों को सचेत कर देती है । सारे देश का नक्शा बनाकर उसको बहुत से सहायक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है । यदि वर्षा नहीं होती तो सरकार एकदम अकाल नीति घोषित करती है । जनता से सहायता की याचना की जाती है । लगान में छूट कर दी जाती है और कृषि के लिये ऋण दिया जाता है । बहुत से जाच घर (Test works) खोल दिये जाते हैं और यदि उनमें बहुत से आदमी आते हैं तो उन जाच घरों को सहायता घरों (Relief Works) में बदल दिया जाता है । जो मनुष्य कार्य कर सकते हैं । उनको काम दिया जाता है और जो कार्य नहीं कर सकते उनको बिना कुछ लिये सहायता पहुँचाई जाती है । बीमारी से बचने के लिये अस्पताल भी खोले जाते हैं । ये मनुष्य यहाँ पर उस समय तक रखे जाते हैं जब तक वर्षा नहीं होती । वर्षा होने पर उनको छोटे-छोटे सहायता घरों में जो अकाल पीड़ितों के गाँवों के पास होते हैं पहुँचा दिया जाता है और वहाँ पर उनको हल, बैल, बीज आदि मोल लेने के लिये ऋण दिया जाता है । जब पतझड़ ऋतु की फसल पककर तैयार हो जाती है तो बचे हुये सहायता केन्द्र भी बन्द कर दिये जाते हैं । इस प्रकार अकाल पीड़ितों की सहायता की जाती है ।

इस नीति से पहले भले ही कुछ अधिक लाभ न हुआ हो पर पिछले कई वर्षों से इससे देश को बहुत लाभ पहुँचा है । इसी नीति के कारण हिंसार, राजस्थान, मद्रास, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि में बहुत से लोग जो भूख और प्यास से मर जाते थे उनको बचा लिया गया है । अकाल से बचाने के लिये केन्द्रीय सरकार भी राज्य सरकारों को बहुत सा धन सहायता रूप में देती रहती है । अभी हाल ही में उसने राजस्थान को बहुत सा धन दिया है और उत्तर प्रदेश को भी बहुत से द्यूबबैल बनाने के लिये सहायता दी है । इस प्रकार केन्द्रीय और राज्य दोनों ही सरकारें अकाल पीड़ितों की सहायता करती हैं ।

अभी अप्रैल १९५८ ई० में बिहार में अकाल की स्थिति आ गई थी जिसने १६५ मिलियन लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डाला । इस स्थिति का मुख्य कारण वर्षा की कमी था । इस स्थिति का मुकाबला करने के लिये बिहार राज्य में १२७०० उचित मूल्य की दुकानें खोली गईं । सकट वाले क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का कार्य किया गया । इस कार्य में भारी मिट्टी का कार्य, हल्का कार्य तथा छोटे-छोटे सिंचाई के कार्य किये गये । इस कार्य में ३५ मिलियन लोग लगाये गये । इसके अतिरिक्त २६५००० आदमी कोसी बाध, जल माष तथा सार्वजनिक कार्य की

योजनाओं में लगाये गये। राज्य सरकार ने ८० लाख ६० जाँच कार्यों (Test Works) के लिये मजदूर, ७० लाख ६० तकावी तथा कृषि ऋण के रूप में मजदूर किये गये तथा १० लाख ६० भूमि की उन्नति के लिये ऋण के रूप में दिये गये। इसके अतिरिक्त १५ लाख ६० मुफ्त सहायता, ३६८ लाख रुपये सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य तथा दूध तथा अन्य खाद्य पदार्थों के लिये दिये गये।

उपयुक्त वितरण से यह बात समस्त में आ सकती है कि राज्य सरकारें किस प्रकार अकाल के समय लोगों की सहायता करती हैं।



Q (30) Give an account of the forms of land tenure in different parts of India and estimate their economic effects

प्रश्न ३०—भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में भूमि अधिकार की जो प्रथाएँ हैं उनका विवरण दीजिये और उनके आर्थिक प्रभाव का अनुमान लगाइये ।

भूमि अधिकार से उस प्रथा का बोध होता है जिसके द्वारा यह जाना जाता है कि खेती करने वाले काश्तकार को किन शर्तों व अधिकारों के अन्तर्गत भूमि जोतने बोनने के लिये दी गई है । भूमि अधिकार की समस्या एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है । यदि खेत का जोतने वाला स्वयं भूमि का स्वामी होता है तो भूमि अधिकार की कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं होती परन्तु जब किसान किसी दूसरे से भूमि जोतने बोनने के लिये लेता है तब भूमि अधिकार की समस्या का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है ।

भारतवर्ष में सदा से ही सरकार भूमि की सर्वोच्च स्वामी (Supreme landlord) रही है और इस नाते यह किसान में भूमि-कर लेती रही है । मनु ने बताया है कि सरकार को कुल उत्पत्ति का छठा भाग मालगुजारी के रूप में लेना चाहिये । हिन्दु राजाओं के शासनकाल में सरकार इसी दर से मालगुजारी लेती रही । उस समय मालगुजारी का प्रबन्ध कुटुम्ब के आधार पर होता था । प्रत्येक कुटुम्ब का प्रमुख गाँव की सभा का सदस्य होता था । गाँव का मुखिया इस सभा का अध्यक्ष होता था । दस गाँवों के मुखिया मिलकर एक दूसरी सभा बनाते थे जिसका अध्यक्ष चौधरी कहलाता था । दस चौधरी एक परगना सभा बनाते थे और दस परगनों की एक बड़ी सभा राजा के आधीन कार्य करती थी । मुखिया लोग अपने अपने गाँवों की मालगुजारी राजा से तय करके अपने गाँव के कुटुम्बों में बाँट देते थे । मुसलमानी शासनकाल के आरम्भ में भी यही प्रथा रही । परन्तु जब मुस्लिम शासन दृढ़ हो गया तब उन्होंने इस देश में जागीरदारी प्रथा प्रारम्भ की । परन्तु जागीरदारी प्रथा जमींदारी प्रथा से बहुत भिन्न थी । अकबर के शासनकाल में जागीरदारी के स्थान पर ठेकेदारी प्रथा चालू की गई । इसके अनुसार मालगुजारी बसूल करने का ठेका ठेकेदारों (Revenue Farmers) को दे दिया गया । ये निश्चित रकम या पैदावार सरकारी खजानों में जमा करते थे । टोडरमल ने भूमि का नया बन्दोबस्त करके नये तिर्रे से मालगुजारी निश्चित की । कुछ समय तक तो कार्य इस प्रकार होता रहा परन्तु जब मुगल सत्ता निर्बल पड़ने लगी तब बहाने से सूबेदार,

सरदार, ठेकेदार अपनी मनमानी करने लगे और धीरे-धीरे वे बड़े शक्तिशाली हो गये। जब अंग्रेजों के हाथ में बंगाल की मालगुजारी वसूल करने का अधिकार आया तब उन्होंने भूल से इन ठेकेदारों आदि को ही भूमि का स्वामी बना लिया और उसके इस अधिकार को स्वीकार किया। १७२३ ई० में लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल में इतरी मालगुजारी सदा के निचे निश्चित करके स्थायी बन्दोबस्त की नींव डाली। उसने उनको भूमि में हर प्रकार के अधिकार दे दिये। इस प्रकार भारतवर्ष में जमींदारी प्रथा का जन्म हो गया। बंगाल के पश्चात् स्थायी बन्दोबस्त वाली जमींदारी प्रथा को दक्षिण में भी पहुँचाने का प्रयत्न किया गया परन्तु वहाँ पर कुछ जमींदारी लोगों के विरोध के कारण यह प्रथा चालू न की जा सकी। इस प्रकार दक्षिणी मद्रास तथा बम्बई प्रान्तों में सरकार ने किसानों और अपने बीच में किसी मध्यजन (Middle man) के अधिकारों को स्वीकार न करके अपना सीधा सम्बन्ध किसानों से रखा। दूसरे शब्दों में इन प्रान्तों में सरकार ने रयतवारी प्रथा चलाई।

स्थायी बन्दोबस्त के दोष सरकार को कुछ ही समय बाद दिखाई देने लगे। इस कारण भारत के दूसरे प्रान्तों में जैसे सयुक्त्त प्रान्त, पंजाब, मध्यप्रदेश आदि में सरकार ने अस्थायी बन्दोबस्त किया। इन प्रदेशों में बन्दोबस्त को २० से ४० वर्षों में बदला जाता है। इन प्रदेशों में भूमि अधिकार की दृष्टि से दो प्रकार का प्रथायें पाई जाती हैं—(१) महालवारी तथा (२) मालगुजारी। इस प्रकार भारत में चार प्रकार की भूमि अधिकार प्रथायें पाई जाती हैं—(१) जमींदारी (२) रयतवारी (३) महालवारी तथा (४) मालगुजारी।

(१) जमींदारी—

इस पद्धति में सरकार और किसान के बीच में एक मध्यजन होता है जिसको जमींदारी कहते हैं। यह जमींदारी जमीन का मालिक होता है। वह स्वयं खेती नहीं करता बल्कि अपनी भूमि को किसानों को उठा देता है। ये किसान जमींदार को लगान देते हैं। लगान वसूल करके जमींदार सरकारी खजाने में उसका कुछ भाग मालगुजारी के रूप में जमा करता है। यदि किसी वर्ष किसान जमींदार को लगान नहीं देता तब भी जमींदार को सरकारी मालगुजारी तो देनी ही पड़ती है। इस प्रकार मालगुजारी देने की पूरी जिम्मेदारी जमींदार पर होती है। जमींदार अपनी जमीन का पूरी तरह मालिक होता है। यह किसान को किसी भी शर्त व अधिकारों के अन्तर्गत जर्माने दे सकता है। वह उनका साथ किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकता है। वह उनको भूमि पर अपनी इच्छानुसार रख व निकाल सकता है। सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इस प्रकार जमींदारी प्रथा में सरकार व किसान का कोई सम्बन्ध नहीं होता। यह प्रथा बंगाल, बिहार, उत्तरी मद्रास, बनारस और अवध तथा बम्बई और मध्यप्रदेश के कुछ भागों में पाई जाती है। अधिकांश बंगाल, उत्तरी मद्रास, बिहार और बनारस में सरकार और जमींदारों में स्थायी बन्दोबस्त है और शेष राज्या में अस्थायी बन्दोबस्त है।

जमींदारी प्रथा के लाभ—जिस समय बङ्गाल में जमींदारी प्रथा चालू की गई थी उस समय उससे निम्नलिखित लाभ होने की आशा थी—

(१) इसके द्वारा सरकार को एक निश्चित धन-राशि प्रतिवर्ष प्राप्त हो जायेगी ।

(२) इससे जमींदार वर्ग सदा ही सरकार का स्वामीभक्त रहेगा और इसके द्वारा अंग्रेजी राज्य की जहाँ इस देश में मजबूती के साथ जम जायेंगी ।

(३) इसके द्वारा जमींदार वर्ग उत्पन्न हो जायगा । यह वर्ग शिक्षित होगा पर इसके पास कुछ अधिक कार्य करने को न होगा । इस कारण यह वर्ग समाज का राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में मार्ग-प्रदर्शन कर सकेगा ।

(४) जमींदार अपने काश्तकारों को आवश्यकता पड़ने पर धन से सहायता पहुँचायेगा तथा भूमि की उन्नति में सहायक होगा ।

(५) श्री रमेशदास अपने 'भारत के आर्थिक इतिहास' (छठे संस्करण) में पृष्ठ ५८ पर जमींदारी प्रथा के लाभ बताते हुये कहते हैं कि जो लोग ध्यानपूर्वक चीजों का अध्ययन नहीं करते उन्होंने जमींदारों को भूमि के ऊपर एक भार बताया है, परन्तु गम्भीर आदमी जिन्होंने भारत के सामाजिक तथा आर्थिक इतिहास को ध्यानपूर्वक पढ़ा है एक दूसरा ही मत रखते हैं । उनका कहना है कि इस राजनीतिक लाभ के अतिरिक्त कि जमींदार एक विदेशी सरकार तथा किसानों के उस राष्ट्र के बीच जिसका सरकार में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था एक प्रभावशाली वर्ग के रूप में कार्य करते थे । यह भी लाभ था कि देश के इन लोगों का मत तथा प्रभाव जमींदारी प्रथा की गलतियों को ठीक करता तथा सरकार को लोगों के अधिक सम्पर्क में लाता था ।

जमींदारी प्रथा के दोष—परन्तु व्यवहार में इनमें से बहुत से लाभ न हो सके । यह बात तो सत्य है कि जमींदारी प्रथा के द्वारा सरकार को आय निश्चित हो गई और वे सरकार के स्वामीभक्त बन गये और उन्होंने कृषक वर्ग में नागरिक जागृति पैदा न होने दी परन्तु उनसे जिन आर्थिक लाभों के प्राप्त होने की आशा थी वे न हो सके । इसके विपरीत इस देश में जमींदार तटस्थ जमींदार (Absentee landlord) बन गये हैं । वे कभी भी अपने काश्तकारों की धन से सहायता नहीं करते और न वे कभी भूमि की उन्नति में कोई सहायता पहुँचाते हैं । उल्टे वे भूमि की उन्नति में बाधक हैं । वे मनचाहूँ खान किसान से वसूल करते हैं । उनसे बंगाल तथा नजराना लेते हैं । समय-समय पर वे बहुत सा धन अवकाश के रूप में भी लेते हैं । यदि बेचूँगा किसान न दे तो उसको भूमि से निकाल बाहर करते हैं । वे स्वयं कभी भी काश्तकार से नहीं मिलते बल्कि वे गुमास्ते रखते हैं जो काश्तकारों को हर प्रकार से सताते रहते हैं । इस प्रकार इस देश में स्थायी बन्दोबस्त करने से कोई लाभ नहीं हुआ उल्टे हानि ही हुई । किसान और सरकार का सीधा सम्बन्ध न होने के कारण किसान की आर्थिक स्थिति दिनो-दिन बिगड़ती जा रही है । साथ

ही साथ सरकार को भी बहुत आर्थिक हानि हुई है क्योंकि आजकल जमींदार लोग काश्तकारों से ले तो रहे हैं १६½ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष और सरकार को दे रहे हैं केवल ४ करोड़ । इस प्रकार जमींदारों की जेब में केवल बज्जाल में १२½ करोड़ रुपये चले जाते हैं । यदि ये सब रुपये सरकार को मिलते तो उसको विप्री कर इत्यादि न लगाने पड़ते और वह अधिक रुपया शिक्षा, कृषि, सड़क आदि पर व्यय कर सकती ।

इन सब दौधों ने जब बहुत उग्र रूप धारण कर लिया तब सरकार को हस्त-क्षेप करना पड़ा । उतने पहले कानून द्वारा काश्तकारों के अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया और अन्त में अब से हमारे देश में अपनी सरकार आई है तब से वह इस प्रथा को समाप्त करती जा रही है ।

(२) रयतवारी—

इसके अन्तर्गत काश्तकारों तथा सरकार के बीच में कोई जमींदार नहीं होता बरन् काश्तकार सीधे सरकार से भूमि लेते हैं । यहाँ पर मालगुजारी काश्तकार के पास जिस प्रकार की भूमि होती है वह उस पर क्या फसल उगाता है, उस भूमि को वर्षा तथा आवागमन के साधनों की कितनी सुविधा प्राप्त है, आदि को ध्यान में रख कर निश्चित की जाती है । इन सब बातों के हेर फेर होने के कारण मालगुजारी समय-समय पर घटती-बढ़ती रहती है । यह डङ्ग मद्रास, बम्बई, आसाम, बरार तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है ।

इस प्रकार इस प्रथा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

(१) इसमें सरकार व किसान के बीच में कोई मध्यजन नहीं होता । सब भूमि की अन्तिम मालिक सरकार होती है चाहे वह भूमि जोती हुई हो, चाहे वह बंकार पड़ी हो ।

(२) किसान को अपनी भूमि जोतने, हस्तांतरित करने तथा छोड़ने का पूरा अधिकार होता है ।

(३) प्रत्येक किसान सरकारी लगान के लिए अलग-अलग जिम्मेदार होता है ।

(४) लगान एक निश्चित समय के लिये निर्धारित किया जाता है और फिर उसमें परिस्थिति के अनुसार बदल कर ली जाती है ।

इस प्रथा के गुण—(१) इसका पहला गुण यह कहा जा सकता है कि इसमें सरकार और किसान के बीच में कोई मध्यजन नहीं होता बरन् किसान का सरकार से सीधा सम्बन्ध होता है । इस कारण सरकार किसानों की समय-समय पर होने वाली कठिनाइयों को समझकर उनके दूर करने का प्रयत्न कर सकती है ।

(२) जमींदारी प्रथा के स्थायी बन्दोबस्त के समान इस प्रथा में मालगुजारी सदा के लिये निश्चित नहीं होती बरन् लगभग २० वर्ष पश्चात् दोहराई जाती है । इस प्रकार भूमि पर होने वाली उन्नति का लाभ सरकार को पहुँच जाता है ।

(३) जमींदारी प्रथा के समान इस प्रथा में किसान को सताने वाला कोई

व्यक्ति नहीं होता। यहाँ जमींदारी प्रथा के समान किसी को नजराने, अवदाव आदि देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती।

(४) जिन भागों में यह प्रथा पाई जाता है उसमें चक्कन्दो, भूमि की उन्नति वड़े पैमाने पर खेती करने आदि का कार्य बड़ी सुगमता से किया जा सकता है।

इस प्रथा के दोष—(१) यद्यपि इस प्रथा में कहने के लिये तो सरकार और किसान का सीधा प्रबन्ध है परन्तु वास्तव में वहाँ भी जमींदारी प्रथा के समान, बहुत से मध्यजन आ गये हैं जो किसानों को खूब लूटते हैं। इस प्रकार देखने में यह प्रथा भले ही अच्छी दिखाई पड़ती हो पर वास्तव में ऐसी बात नहीं है।

(२) प्रत्येक व्यक्ति का लगान अलग निर्धारित करने के कारण ग्राम पंचायतों के कार्यों का अन्त हो गया।

(३) किसानों को भूमि हस्तांतरित करने की स्वतन्त्रता होने के कारण उनकी बहुत सी भूमि महाजनो के हाथों में चली गई है।

(४) मरहारी लगान केवल भूमि के क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जाता है और प्रतिवर्ष की कृषि उत्पादन की वृद्धि अथवा ह्रास का उसमें कोई ध्यान नहीं रखा जाता। सर जार्ज क्लार्क न लार्ड की प्रवर समिति के समक्ष गवाही देते हुए कहा कि रैपतवारी देश के लिय सबसे अधिक घातक है। रैपतवारी प्रान्तों में मालगुजारी नियन्त्रण करने का कार्य बन्दोबस्त अफसरों के अन्दाजे पर निर्भर होता है।

(५) जब भी बन्दोबस्त बदला जाता है तो साधारणतया लगान बढ़ाया ही जाता है, घटाया नहीं जाता। इस कारण खेती पर किसी प्रकार की रखाई उन्नति सम्भव नहीं।

इस प्रकार हम यह सकते हैं कि यद्यपि यह प्रथा देखने में बड़ी अच्छी मालूम पड़ती है परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है इसमें भी किसानों की स्थिति जमींदारी क्षेत्रों के किसानों की स्थिति से कोई अच्छी नहीं है।

(३) महालवारी—

इस प्रथा में गाँव की जमीन का मालिक कोई एक जमींदार नहीं होता बरन् गाँव के वे सब लोग मिलकर होते हैं जो गाँव की जमीन के किसी न किसी हिस्से के मालिक होन हैं। यदि कोई व्यक्ति खेती तो करता है परन्तु वह उसका मालिक नहीं होता बरन् वह किसी मालिक की जमीन लगान कर लेकर जोतता होता है तो वह सरकार की मालगुजारी देने का जिम्मेदार नहीं होता। गाँव में जो मालगुजारी देने के जिम्मेदार होते हैं वे साधारणतया एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। परिवार के टूटने पर उनमें आपस में भूमि का बंटवारा हो जाता है। इस कारण उनको सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से मालगुजारी के लिये जिम्मेदारी ठहरा दिया जाता है। यह प्रथा उन स्थानों पर भी पाई जाती है जहाँ ग्राम मल्का इतनी शक्तिशाली थी कि व्यक्तिगत रूप से सरकार और जमीन के मालिकों का

कोई भी सम्बन्ध न था और ग्राम सभा सभी हिस्सेदारों का प्रतिनिधित्व करती थी। ऐसी स्थिति में जब अङ्गरेजों ने इस प्रकार के गांवों में मालगुजारी प्रथा का नया संगठन किया तब उन्होंने सब हिस्सेदारों से सामूहिक रूप से इक्करानामा किया और हिस्सेदारों को सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से सरकार को मालगुजारी देने के लिये जिम्मेदार बना दिया। उन हिस्सेदारों में से सरकार एक को नम्बरदार नियुक्त कर देती है। यह नम्बरदार सब हिस्सेदारों से मालगुजारी वसूल करके सरकारी खजाने में जमा कर देता है। इस प्रकार यह प्रथा भी जमींदारी प्रथा के समान ही है। अन्तर केवल इतना है कि जमींदारी प्रदेशों में केवल एक आदमी मालगुजारी देने का जिम्मेदार होता है। परन्तु महालवारी में कई आदमियों के ऊपर यह भार होता है।

यह प्रथा उत्तर प्रदेश (बनारस और अवध को छोड़कर) पंजाब और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रथा में सारी भूमि की पैमायश करके उसको जोतों में बाँट दिया जाता है और सरकार लगान का लगभग आधा भाग मालगुजारी के रूप में लेती है।

(४) माल गुजारी—

मालगुजारी का यह ढङ्ग मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसमें मालगुजारी जो इसी प्रकार निश्चित की जाती है जिस प्रकार कि उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर एक अन्तर है। यहाँ पर मराठों के समय में जो लोग काश्तकार थे उन्हें को सरकार ने काश्तकार मान लिया है और उनको भूमि पर स्वामित्व का अधिकार भी दे दिया है। यहाँ पर बन्दोबस्त अफसर (Settlement officer) यह निश्चित करते हैं कि मालगुजारी सरकार को कितनी मालगुजारी देगा तथा वह काश्तकारों से कितना लगान लेगा। यह इसलिये किया जाता है जिससे कि मालगुजारी काश्तकारों को न लूट सके।

महालवारी तथा मालगुजारी प्रथाओं के गुण व दोष—ये दोनों प्रथाएँ जमींदारी प्रथा के समान ही हैं। इनमें जो लोग भूमि के स्वामी होते हैं वे स्वयं खेती नहीं करते बरन् वे किसानों को भूमि लगान पर उठा देते हैं और वे उसी प्रकार किसानों को सताते हैं जैसे जमींदार लोग उनको सताते हैं। श्री रमेशदत्त ने अपनी पुस्तक “भारत का आर्थिक इतिहास” में लिखा है कि श्री चिरोल्म जो अपने समय के सबसे योग्य बन्दोबस्त अफसरों में से एक था कहा है कि मैं नहीं जानता कि वह भूमि सम्बन्धी कौन सा अधिकार है जिसको कि मालगुजारी अथवा उसके साज्जीदार काम में नहीं लाते सिवाय इसके कि वे भूमि को बेच नहीं सकते और न उसको रहन रख सकते। वह अपने गाँव को हस्तान्तर नहीं कर सकता क्योंकि इसी सरकार ने अपनी सन्कुचित दृष्टि के कारण उसका यह अधिकार स्वीकार नहीं किया परन्तु जब भूमि उसके अधिकार में होती थी तो उसको आन्तरिक व्यवस्था पर पूर्ण अधिकार था। वह काश्तकारों को दमा सकता था उनको निकाल सकता

था, उनका लगान बढ़ा सकता था, भूमि पर बाग लगा सकता था, तालाब बना सकता था। इस प्रकार वह गाँव के प्रशासन में बड़ी अधिकार रखता था जो कि दूसरे स्थानों पर मालिकों का होने थे जिनका भूमि में निर्विवाद अधिकार स्वीकार कर लिया गया था परन्तु इन प्रदेशों में बन्दोबस्त ३०-४० वर्षों में बदला जाता है और उस समय सरकार मालगुजारी घटा बढ़ा सकती है। इस प्रकार स्थायी उन्नति का कुछ लाभ सरकार को सरकार को भी मिल जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में भूमि अधिकार की चाहे जो भी पद्धति पाई जाती हो उसी में किसानों का शोषण किया जाता है।

Q 31 Give merits and demerits of the Permanent and Temporary Settlement

प्रश्न ३१—स्थायी तथा अस्थायी बन्दोबस्त के लाभ व हानियाँ बनाइये।

बन्दोबस्त का अर्थ—बन्दोबस्त द्वारा राज्य भूमि की मालगुजारी निश्चित करता है। इसके अन्तर्गत तीन बातें होती हैं (१) भूमि की उत्पत्ति में राज्य का भाग निश्चित किया जाता है। (२) राज्य को जो व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मालगुजारी देगा उसको निश्चित कर दिया जाता है। (३) यह भी निश्चित किया जाता है कि जिन व्यक्तियों को भूमि दी गई है उनके उसमें क्या अधिकार होंगे।

बन्दोबस्त दो प्रकार का हो सकता है—

(१) स्थायी (२) अस्थायी।

(१) स्थायी बन्दोबस्त (Permanent Settlement)—

यह सबसे पहले बंगाल में १७६३ ई० में चालू किया गया। इसके अनुसार जमींदारी की मालगुजारी सदा के लिये निश्चिन हो गई है। जमींदारी जितना लगान काश्तकार में लेता है उसका १०/११ भाग सरकार को देता है और १/११ आग परिधम में रूप में रख लेता है। मालगुजारी में सरकार ने कोई वृद्धि नहीं की। इस कारण यद्यपि आजकल बंगाल के जमींदार अपने काश्तकारों से १६½ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष वसूल कर रहे हैं तथापि वह सरकार को मालगुजारी के रूप में ४ करोड़ रुपया ही देते हैं। जब तक सरकार का लगान मिलता रहता है उस समय तक जमींदार को किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता पर यदि किसी वर्ष जमींदार मालगुजारी न दे सके, चाहे उस वर्ष अकाल ही पड़ा हो तो उसकी भूमि नीलाम करके उससे मालगुजारी वसूल कर ली जाती है। यद्यपि सरकार लगान नहीं बढ़ाती तथा भी सरकार को यह अधिकार है कि वह व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिये कोई भी कानून चालू कर सकती है।

स्थायी बन्दोबस्त के उद्देश्य—स्थायी बन्दोबस्त निम्नलिखित उद्देश्य से इस देश में चालू किया गया था—

(१) इसके द्वारा सरकार को एक निश्चित धन राशि हर वर्ष प्राप्त हो जायगी।

(२) इससे जमींदार वर्ग सदा ही सरकार का स्वामी भक्त रहेगा और इसके द्वारा राज्य को जड़े इस देश में मजबूती के साथ जम जायगी।

(३) इसके द्वारा जमींदार वर्ग उत्पन्न हो जायगा। यह वर्ग निश्चित होगा पर इसके पास कुछ अधिक कार्य करने को न होगा। इस कारण यह वर्ग समाज का राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में मार्ग दर्शन कर सकेगा।

(४) जमींदार अपने कानूनी अधिकारों की आवश्यकता पड़ने पर धन से सहायता पहुँचायेगा तथा भूमि की उन्नति में सहायक होगा।

स्थायी बन्दोबस्त के लाभ—विलियम म्योर, उत्तर पश्चिम प्रान्त के लेफ्टी—नेन्ट गवर्नर तथा भारत के वित्त मन्त्री ने स्थायी बन्दोबस्त के लाभ को ६ श्रणियों में बाँटा है—

(१) समय-मसम पर बन्दोबस्त बदलने का खर्च कम हो जायेगा।

(२) बन्दोबस्त बदलने के झगड़ों से जनता मुक्त हो जायगी।

(३) अस्थायी बन्दोबस्त में बन्दोबस्त बदलने के कुछ समय पूर्व से जो भूमि की उन्नति शक्ति में ह्रास होता है वह स्थायी बन्दोबस्त में नहीं होता।

(४) स्थायी बन्दोबस्त के कारण लोगों को भूमि पर स्थायी उन्नति करने का प्रोत्साहन मिलता है और इसके कारण खुशहाली बढ़ेगी।

(५) भूमि का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जायेगा।

(६) लोगों में सतोष रहेगा।

सर जान लारेन्स भारत मन्त्री की कौंसिल के एक सदस्य ने स्थायी बन्दोबस्त से लाभ बताते हुए कहा, "मैं स्थायी बन्दोबस्त का समर्थन इसलिये करता हूँ। क्योंकि मेरा यह विश्वास है कि चाहे देश न हाल ही में कितनी उन्नति कर ली हो इसके माधन इससे भी अधिक तेजी से बढ़े यदि सरकारी माग को कम कर दिया गया।

स कार्य के द्वारा भूमि में रफ़ा लगाने को और भी प्रोत्साहन मिलेगा और माल-गुजारी में इससे भी अधिक स्थायीपन आ जायेगा। इसके द्वारा एक प्रगतिशीली मध्य वर्ग का निर्माण होगा। जाति और धर्म की भावनाओं का भारत के लोगों पर बड़ा प्रभाव है परन्तु उनको भूमि से और भी अधिक प्रेम है। उत्तरी भारत के

हजारों बंदाचित लाखों व्यक्ति जो कि भारत की सब जातियों में सबसे अधिक लड़ाकू हैं, ऐसे लोगों की सतान हैं जिन्होंने अपनी भूमि की रक्षा के लिये अपने धर्म को भी छोड़ दिया।"

टिप्पणी—कम्पनी की आशा थी कि उपर्युक्त उद्देश्य जमींदार उसी प्रकार का कर सकेंगे जिस प्रकार कि वे इंग्लैंड में पूरा कर रहे थे। परन्तु ऐसा नहीं हुआ।

इस देश में जमींदारी तत्त्व जमींदार (Absentee landlord) बन गये। उन्होंने कभी अपने काश्तकारों की धन से सहायता नहीं की और न उन्होंने कभी भूमि की उन्नति में कोई सहायता पहुंचाई। उल्टे वे भूमि की उन्नति में बाधक हो गए। वे मनचाहा लगान किसान से वसूल करते हैं। उनसे बेगार तथा नजराना लेते हैं। समय समय पर वे बहुत सा धन अवसाव के रूप में भी लेते हैं। यदि बेचारा किसान न दे तो उसको भूमि से निकाल बाहर करते हैं। वे स्वयं कभी भी काश्तकार से नहीं मिलते वरन् वे गुमास्ते रखते हैं जो काश्तकारों को हर प्रकार से सताते रहते हैं। इस प्रकार इस देश में स्थायी बन्दोबस्त करने से कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टे हानि ही हुई। किसान और सरकार का सीधा सम्बन्ध न होने के कारण किसान की आर्थिक स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती चली गई। साथ ही साथ सरकार को भी बहुत आर्थिक हानि हुई क्योंकि आजकल जमींदार लोग बंगाल में काश्तकारों से ले तो रहे हैं १६½ करोड़ रुपये प्रति वर्ष और सरकार को दे रहे हैं केवल ४ करोड़। इस प्रकार जमींदारों की जेब में केवल बंगाल से १२½ करोड़ रुपये चले जाते हैं। यदि यह सब रुपये सरकार को मिलते तो उसको बिक्री कर आदि न लगाने पड़त, और वह अधिक रुपया शिक्षा, कृषि, सड़क आदि पर व्यय कर सकती। इसी कारण बंगाल के फ्लाउड कमिशन ने बन्दोबस्त को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने की सिफारिश की है।

(२) अस्थायी बन्दोबस्त (Temporary Settlement)—

भारत में मालगुजारी का दूसरा ढङ्ग अस्थायी बन्दोबस्त है। इसके अन्तर्गत जमींदार के ऊपर मालगुजारी स्थायी बन्दोबस्त के समान सदा के लिये निश्चित नहीं की जाती वरन् वह एक निश्चित समय के लिये तय की जाती है। इस निश्चित समय के पश्चात् बन्दोबस्त बदला जाता है। उस समय फिर यह तय किया जाता है कि सरकार को कितनी मालगुजारी चाहिये तथा उसको कौन देगा। बन्दोबस्त बदलते समय बहुधा मालगुजारी बढ़ाई ही जाती है घटाई नहीं जाती। भूमि के मालिक भी बहुधा नहीं बदले जाते बल्कि वहीं रहत है। बन्दोबस्त बदलने का समय मध्य प्रदेश में २० से ३० वर्ष, मद्रास में ३० वर्ष और उत्तर प्रदेश में ४० वर्ष है। इस ढङ्ग के अन्तर्गत मालगुजारी तय करने में तीन बात करनी पड़ती है। पहले तो सारे गांव का नक्शा, मालगुजारी का लेखा तथा अधिकारों का लेखा तैयार करना पड़ता है। सारे गांव की भूमि की माप तोल की जाती है और उसकी डीलबन्दी कर दी जाती है। इसके पश्चात् यह देखा जाता है कि मिट्टी किस प्रकार की है। इसी के साथ साथ यह बात भी निश्चित कर दी जाती है कि मालगुजारी कौन जमा करेगा। इस लेखे में आवश्यकतानुसार बदल कर दी जाती है ताकि वह बिल्कुल ठीक रहे। इसके पश्चात् दूसरी बात मालगुजारी के धन का निश्चित करना है। तीसरे, यह भी निश्चित किया जाता है कि मालगुजारी कहाँ और किस प्रकार जमा की जायेगी।

भारत में भूमि अधिकार पद्धति तथा जमींदारी उन्मूलन [१८६]

अस्थायी बन्दोबस्त के लाभ—अस्थायी बन्दोबस्त के निम्नलिखित लाभ रहे जा सकते हैं—

(१) इस प्रकार के बन्दोबस्त में सरकार को भविष्य में होने वाली स्थायी उन्नति के लाभ का एक अंश प्राप्त हो जाता है।

(२) इस बन्दोबस्त में सरकार को किसान के साथ सम्बन्ध स्थापित करने का अवसर प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार वह उसकी बहुत सी शिकायतों को दूर कर सकती है।

(३) इस प्रकार के बन्दोबस्त में फसल के नष्ट होने पर मालगुजारी में छूट कर दी जाती है। इस छूट का लाभ जमींदार व किसान दोनों को पहुंचता है।

दोष—परन्तु इस प्रकार के बन्दोबस्त में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं—

(१) जब बन्दोबस्त बढ़ा जाता है तो गाँव का आर्थिक जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

(२) बन्दोबस्त के अस्थायी होने के कारण भूमि का अधिकारी भूमि पर स्थायी उन्नति नहीं करता क्योंकि उसको इन बात का विश्वास नहीं होता कि भविष्य में भी वह भूमि उसी के पास रहेगी।

(३) बन्दोबस्त होने के कुछ वर्ष पूर्व से ही भूमि पर किसी प्रकार की उन्नति नहीं की जाती जिससे कि लगान न बढ़ा दिया जाय।

(४) बन्दोबस्त के समय अफसर लोग पक्षपात से काम लेते हैं तथा किसानों को बताते हैं।

(५) बन्दोबस्त के समय भूमि उसी जादमी को दी जाती है, जो सबसे अधिक बोली बोल्ता है। इस प्रकार बहुत भूमि निचम्मे आदमियों के हाथों में चली जाती है।

Q 32 "Tenancy legislation in all the provinces where it has been enacted has generally aimed at granting the benefits of three F's to tenants" Explain these F's and illustrate with reference to recent tenancy legislation in the U P or in any other province in India, how the benefits of these F's have been conferred on the tenants ?

प्रश्न ३२—“उन सब प्रांतों में जहाँ कहीं भी लगान सम्बन्धी कानून पास हुये हैं उनका उद्देश्य किसानों को तीन ‘एफ’ का लाभ पहुँचाने का रहा है।” इन तीनों एफों का विवरण करो और उत्तर प्रदेश अथवा भारतवर्ष के और किसी प्रांत में हाल ही में पास हुए कानून की सहायता से यह बताइये कि कार्रवारों को किस प्रकार से इन तीनों एफों का लाभ प्रदान किया गया है।

जिस समय तक कृषक स्वयं भूमि का स्वामी होता है उस समय तक लगान की कोई समस्या नहीं होती परन्तु जब भूमि का स्वामी तथा उसका जीतने वाला

एक ही व्यक्ति नहीं होता तब बहुत सी समस्याएँ आकर उपस्थित हो जाती हैं। भूमि किसान को कितने समय के लिए दी जाती है, जमींदार किसान से क्या लगान लेता है, वह किसान के साथ कैसा व्यवहार करता है, आदि बातें भूमि की उपज तथा किसान की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। इस कारण सभी देशों में लगान सम्बन्धी कानून पास किये गए हैं जिससे जमींदार किसान के साथ बुरा बर्ताव न कर सकें।

लगान के कानूनों का उद्देश्य किसान को तीन एफो (Three F's) का लाभ देना होता है। ये तीन एफ Fixity of Tenure (निश्चित शर्तों व अधिकारों के अन्तर्गत जोतने व लिए भूमि देना), Fair Rents (उचित लगान) तथा Freedom of Transfer (हस्तांतर करने की स्वतन्त्रता) होते हैं। जब तक कृषक का उपयुक्त सुविधायें प्राप्त नहीं होंगी तब तक किसान भूमि की उन्नति में कोई दिलचस्पी नहीं लेगा। इस कारण किसी अच्छी लगान पद्धति में यही तीनों बातें होनी चाहियें। अब हम इनका संक्षिप्त वर्णन करेंगे।

Fixity of Tenure—किसान जिस भूमि को जोत वो रहा है उसका ऊपर उसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए। उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि उस भूमि में से उसको कोई बाहर नहीं निकालेगा। यदि उसको यह विश्वास नहीं होगा तो वह भूमि की उन्नति के लिए कुछ भी न करेगा। जब तक हमारे देश में किसान भूमि को राजा से लेते थे और उसी को लगान देते थे उस समय तक हमारे देश की भूमि में इतना अन्न उत्पन्न होता था कि यह विदेशों को भी गल्ला खिला सकती थी। परन्तु मुगलकाल के पश्चात् जब भारत पर अङ्गरेजों का आधिपत्य हुआ और उन्होंने यहाँ पर जमींदार वर्ग उत्पन्न किया तो किसान का यह विश्वास जाता रहा। बहुत समय तक जमींदार लोग किसान को भूमि पर से जब चाहते हटा देने थे। इस कारण किसानों ने भूमि में दिलचस्पी लेनी छोड़ दी और देश की भूमि की उपजाऊ शक्ति दिन प्रति दिन नष्ट होती चली गई। अन्त में सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा और सबसे पहले बङ्गाल में १८५८ ई० में एक कानून पास हुआ जिसके कारण बारह वर्ष लगातार भूमि जोतने वाले को भूमि में मौहसी हक (Occupancy right) प्राप्त हो जाते थे। जिस किसान को मौहसी हक प्राप्त हो जाता था उसको जमींदार भूमि से उसके जीवनकाल में बाहर नहीं निकाल सकना था। परन्तु हुआ क्या? जमींदार ने किसान को मौहसी हक प्राप्त करने का अवसर ही नहीं दिया। वह बारह वर्ष पूरे होने से पहले ही किसान से यह भूमि छुड़वा लेता था और उसको दूसरी भूमि दे देता था। इस कारण इस कानून को बङ्गाल में १८८५ ई० में बदल दिया गया। नये कानून में यह रखा गया कि जो किसान एक गांव की किसी भी भूमि को लगातार बारह वर्ष तक जोतना रहेगा उसको उस पर मौहसी हक प्राप्त हो जायेगा। आगरा में भी १८०१ ई० में एक ऐसा कानून पास किया गया जिससे कि जमींदार लोग पहले कानून को न तोड़ सकें।

इसी प्रकार का एक कानून अवध में भी १८८६ ई० में पास हुआ। इस कानून के अनुसार उन किसानों को मौहसी हक दिया गया जो पहले भूमि के स्वामी थे परन्तु जिनके अधिकार से भूमि चली गई थी। इसके अतिरिक्त कुछ कानूनी काश्तकार भी बनाये गए जिनको सात वर्ष तक भूमि से नहीं निकाला जा सकता था और न ही उनका लगान बढ़ाया जा सकता था। परन्तु इस कानून से किसानों की स्थिति में विशेष बदल न हुई। सात वर्ष समाप्त होने पर जमींदार किसान से भूमि भी छुड़वा लेने थे और उनका लगान भी बढ़ा देते थे। इस कारण १९२१ ई० में अवध में एक दूसरा कानून पास किया गया जिससे कि कानूनी काश्तकारों को मौहसी काश्तकार बना लिया गया। इन काश्तकारों को लगान ५ या १० वर्षों में बढ़ाया जा सकता था।

अवध व अतिरिक्त आगरा प्रान्त में भी १९०१ ई० में एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार १२ वर्ष तक लगातार भूमि जोड़ने वाले को मौहसी हक प्राप्त हो जाता था। इसमें यह भी रखा गया कि जो व्यक्ति १८५९ ई० वाले कानून को नहीं मानेगा उसको दण्ड दिया जायेगा। जब इस कानून से भी किसानों को विशेष लाभ न हुआ तो १९२६ ई० में एक दूसरा कानून पास किया गया जिससे हर ऐच्छिक काश्तकार (Tenant-at-will) को मौहसी हक प्राप्त हुआ। ये कारतार कानूनी काश्तकार (Statutory Tenants) कहलाये। इन काश्तकारों को जमींदार उनके जीवन काल में भूमि से बाहर नहीं निकाल सकता था और उनकी मृत्यु के पश्चात् भी किसान के उत्तराधिकारी पाँच वर्ष तक भूमि से नहीं निवाले जा सकते थे। मौहसी काश्तकार मौहसी ही रहे। गैर मौहसी काश्तकार (Non-occupancy tenants) अपना हक जमींदार से खरीद सकते थे। कानूनी काश्तकारों का लगान जमींदार बवल २० वर्ष के पश्चात् बढ़ा सकता था। परन्तु इस कानून से भी सीर के किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। इस कारण १९२९ ई० में अवध लगान कानून १९२१ ई० तथा आगरा लगान कानून सन् १९२६ ई० को मिलाकर यू० पी० लगान कानून (U P Tenancy Act) पास किया गया। इस कानून में भी १९४७ ई० में कुछ परिवर्तन किया गया। १९४७ ई० के पश्चात् उत्तर प्रदेश में वेदखली बिलकुल बन्द कर दी गई।

लगान सम्बन्धी मुद्दों के विषय में योजना में सुझाव दिया गया है कि किसान को भूमि स्वत्व की सुरक्षा (Security of tenure) होनी चाहिये। मालिक को स्वयं खेती करने के लिये थोड़ी सी भूमि प्राप्त करने की आज्ञा देनी चाहिए। परन्तु मालिक को भूमि देते समय यह देखना चाहिए कि किसान के जमीन न रह जाये। जिस खेती में किसानों को स्थायी अधिकार दिये हुए हैं उनमें किसान को अधिकार दिया जाने कि वह भावजा देकर उस खेत का स्वामित्व प्राप्त कर ले। योजना में यह भी कहा गया है कि यदि किसान स्वयं इच्छा से भी अपने खेत को छोड़ना चाहे तो भी इसकी मालिक के नाम में उस समय तक रजिस्टर न किया

जाए जब तक कि यह निर्णय न कर लिया जाए कि किसान वास्तव में भूमि को स्वयं इच्छा से छोड़ रहा है और उस पर स्वामी का कोई दबाव नहीं है। इसके अतिरिक्त मालिक के नाम में केवल उतनी भूमि ही रजिस्टर करनी चाहिये जितनी पर वह स्वयं खेती करेगा। उससे अधिक भूमि पर मालिक का अधिकार न होकर सरकार का अधिकार होना चाहिये। इस प्रकार धीरे धीरे हमारे किसानों को लगान के स्वामित्व का लाभ प्राप्त हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में सरकार और किसानों का सीधा सम्बन्ध हो गया है। सरकार जमींदारों को मावजा देकर उनकी भूमि प्राप्त करेगी।

Fair Rent—एक आदश लगान पद्धति में दूसरी बात यह होनी चाहिये कि वास्तविक से उचित लगान लिया जाये। यदि काश्तकार से अधिक लगान लिया जायगा तो उसके पास बहुत कम धन बचेगा। इस धन से न तो वह अपना तथा अपने परिवार का जीवन निर्वाह ही कर सकता है और न वह खेती की उन्नति ही कर सकता है।

हमारे देश में जब तक जमींदारों के ऊपर कोई कानूनी पाबन्दी न थी तब तक वे काश्तकारों से बहुत अधिक लगान लेते थे। यदि वे अधिक लगान देने से इन्कार करते थे तो उनका भूमि से निकाल दिया जाता था। जमींदार लोग अधिक लगान देने से सन्तुष्ट नहीं होते थे वरन् वे काश्तकारों को हर प्रकार से सताते थे। वे उनमें बगार लेते थे। उनसे शादी विवाह के अवसर पर नजराना लेते थे। जब बाप की मृत्यु के पश्चात् भूमि लड़के को दी जाती थी तब भी उससे नजराना लिया जाता था। यदि जमींदार हाथी रखता था तो काश्तकारों से हथियाना लिया जाता था। डा० राधा बमल मुखर्जी ने बताया है कि उड़ीसा में काश्तकारों पर ७२ भिन्न-भिन्न कर लगे हुये थे जिनमें बाल काटने तक का कर भी सम्मिलित था। ऐसी दशा में यदि काश्तकारों की स्थिति खराब हो तो कोई अचम्भा नहीं।

काश्तकारों को अधिक लगान से बचाने के लिये देश के भिन्न-भिन्न राज्यों में कानून पास किये गये। उदाहरण के लिये अवध प्रान्त में १९२१ ई० में जो कानून पास किया गया उसके अनुसार कानूनी काश्तकारों का लगान १० वर्ष से पहले नहीं बढ़ाया जा सकता था। इसी प्रकार १९२६ ई० के कानून के अनुसार कानूनी काश्तकारों का लगान २० वर्ष से पूर्व नहीं बढ़ाया जा सकता था। परन्तु इस कानून से गणराज्य का सत्त्व बन्ध नहीं हुआ। इस कारण १९३६ ई० के कानून में यह प्रवन्ध किया गया कि जो कोई भी जमींदार काश्तकार से नजराना लेगा उसको दण्ड दिया जाएगा। इस कानून के अनुसार किसी काश्तकार का लगान २० वर्ष से पहले नहीं बढ़ाया जा सकता। इस समय के पश्चात् भी यदि लगान बढ़ाया जाएगा तो वह भी बढ़ाया जा सकता था जबकि जमींदार ने भूमि पर कुछ उन्नति की हो तथा फसल का मूल्य बढ़ गया हो। योजना में कहा गया है कि किसानों द्वारा दिया गया लगान कुल उपज के $\frac{1}{3}$ से अधिक नहीं होना चाहिये।

Freedom of Transfer—आदर्श लगान के ढङ्ग में तीसरी बात यह होनी चाहिये कि काश्तकार को अपनी भूमि हस्तान्तर (Transfer) करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये। यदि काश्तकार को भूमि हस्तान्तर करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी तो उसकी साख (Credit) बढ़ जायगी और अपनी भूमि को बन्धक करके आवश्यकता पड़ने पर ऋण ले सकेगा। इस ऋण के द्वारा वह भूमि पर हर प्रकार की उन्नति कर सकता है।

हमारे देश में अधिकतर भाग में जमींदारी प्रथा थी। जिसमें भूमि का स्वामी जमींदार होता था। इस कारण काश्तकार को यह अधिकार नहीं था कि वह भूमि को हस्तान्तर कर सके। जिन भागों में रयतवादी प्रथा थी वहाँ पर भी अधिकतर काश्तकार ही भूमि को जोतते थे। इन काश्तकारों को भी भूमि हस्तान्तर करने का कोई अधिकार नहीं होता था। इस प्रकार देश के प्रायः सारे राज्यों में काश्तकार को भूमि हस्तान्तर करने का कोई अधिकार नहीं होता था। अब उत्तर प्रदेश में जबकि जमींदारी समाप्त हो गई है और काश्तकारों को भूमिधर के अधिकार प्राप्त हो गये हैं तो काश्तकारों को अब भूमि हस्तान्तर करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। पर सीरदार तथा दूसरी प्रकार के काश्तकारों को यह अधिकार अब भी प्राप्त नहीं है।

योजनाओं के अन्तर्गत भूमि-सुधार

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के भूमि सुधार के विषय में निम्नलिखित सुझाव थे—
(१) लगान में कमी, (२) भूमि-स्वत्व की निश्चयता, (३) किसानों को अपनी भूमि खरीदने का अधिकार देना। इस ओर अभी तक जो प्रयत्न किया गया है वह इस प्रकार है—

आंध्र प्रदेश

पहले के आंध्र क्षेत्र में उन किसानों को जो १ जून १९५६ ई० को भूमि पर अधिकार रखते थे चार वर्ष या कम से कम समय दिया गया है और जो उसके पश्चात् दाखिल किये गये हैं उनको छ वर्ष का कम से कम समय दिया गया है। सरकारी साधनों द्वारा सींचे गये क्षेत्रों का लगान कुल उपज का ५० प्रतिशत, सूखी भूमि में ४५ प्रतिशत तथा बैलिंग द्वारा सींचे गये भागों में २६ प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

आसाम

यदि कोई जमींदार स्वयं खेती करना चाहे तो वह अधिक से अधिक ३३ ई० एकड़ भूमि प्राप्त कर सकता है। शासकदारी में लगान है। (जहाँ जमींदार जोतने का खर्च बर्दाश्त करता है) से है तक हो सकेगा। स्थायी बन्दोबस्त वाले क्षेत्रों में किसान से उस रकम से १०० प्रतिशत से अधिक नहीं लिया जा सकता जितना कि जमींदार मालगुजारी देता है। अस्थायी बन्दोबस्त में ५० प्रतिशत से अधिक नहीं लिया जा सकता।

१. बिहार

मौलसी अधिकार १२ साल के लगातर अधिकार से प्राप्त किया जा सकता है। नकद लगान rental value के ५० प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता, यदि भूमि रजिस्टर्ड पट्टे के आधीन हो तथा दूसरी हालतों में २५ प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। वैसे लगान कुल उपज के $\frac{१}{१०}$ से अधिक नहीं हो सकता।

बम्बई

पहले बम्बई राज्य में एक जमींदार ५० प्रतिशत भूमि पर उस समय अधिकार प्राप्त कर सकता है जब कि उसकी खुद काश्त की भूमि तीन आर्थिक जोतों (१२ से ४८ एकड़) से कम होगी। दूसरे क्षेत्रों में भूमि पर किसान का अधिकार माना जायगा जब तक कि जमींदार के पास एक आर्थिक जोत (३ से १२ एकड़) से कम भूमि न हो। अधिकतम लगान कुल उपज का $\frac{१}{१०}$ अथवा मालगुजारी के पाँच गुने इन दोनों में जो कम हो से अधिक नहीं हो सकता।

जम्मू तथा काश्मीर

काश्मीर क्षेत्र में भूमि को खुदकाश्त के लिये तर भागों में २ एकड़ तक तथा सूखे भागों में ४ एकड़ तक प्राप्त किया जा सकता है। जम्मू में यह सीमा ४ तथा ६ एकड़ है। १२ $\frac{१}{२}$ एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले किसानों का लगान नम भागों में कुल उपज का $\frac{१}{१०}$ तथा सूखे भागों में $\frac{१}{१०}$ से अधिक नहीं हो सकता।

केरल

इस राज्य में किसानों को भूमि में नहीं निकाला जा सकता तथा जमींदार को भूमि प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

मध्य प्रदेश

इस राज्य में किसानों को पाँच वर्ष में तीन वर्ष भूमि जोतने पर मौलसी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। पहले विन्ध्य प्रदेश में किसानों को ७ वर्ष की सुरक्षा प्रदान की गई है। मध्यभारत तथा भोपाल क्षेत्रों में किसानों को भूमि से नहीं निकाला जा सकता।

मद्रास

इस राज्य में किसानों की बेदखली कुछ समय के लिये रोक दी गई है। कुछ हालतों में जमींदारों को भूमि प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। लगान सींचे हुये भागों में कुल उपज के ४० प्रतिशत से तथा अन्य हालतों में ३३ $\frac{१}{३}$ प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।

उड़ीसा

किसानों को ३० जून १९५६ तक बेदखल नहीं किया जा सकता। अधिकतम लगान कुल उपज के $\frac{१}{१०}$ से अधिक नहीं हो सकता।

पंजाब

इस राज्य में भी किसानों की लगान सम्बन्धी सुरक्षा प्रदान की गई है। लगान कुल उपज के $\frac{१}{१०}$ से अधिक नहीं हो सकता।

राजस्थान

किसान इतनी भूमि रख सकता है जो उसको १२०० रु० वार्षिक की वास्तविक आय प्रदान करती रहे। लगान शुल उपज के १/६ से अधिक नहीं हो सकता।

उत्तर प्रदेश

सब किसानों का सरकार से सीधा सम्बन्ध हो गया है।

पश्चिमी बंगाल

यहाँ भी जमींदारों को समाप्त करके किसानों को सरकार के सम्बन्ध में लाया गया है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में समय-समय पर कानून द्वारा काश्तकार को 'तीन एक' का लाभ पहुँचाने का प्रयत्न किया गया है। इसके कारण बाज्य देश के काश्तकार न तो भूमि से निकाले जा सकते हैं और न उन पर लगान ही बढ़ाया जा सकता है। बहुत स्थानों पर वे भूमि के स्वामी बन गये हैं।

Q 33 Discuss the problem of the abolition of zamindari in India. What compensation, if any, should be paid to the zamindar, and how? What system should replace zamindari?

प्रश्न ३३—भारतवर्ष में जमींदारी उन्मूलन की समस्या का वर्णन कीजिये। जमींदार को क्या और किस प्रकार क्षतिपूर्ति के रूप में मिलना चाहिये? जमींदारों प्रथा के पश्चात् भूमि का क्या बन्दोबस्त होना चाहिये?

उत्तर—भारतवर्ष में जमींदारी प्रथा का श्रीगणेश अंग्रेजी शासन से हुआ। उससे पहले भी इस देश में कुछ जमींदार थे पर वे भूमि के स्वामी न थे। उनका कार्य केवल लगान वसूल करना था। पर अंग्रेजों ने इस देश में ऐसे जमींदार उत्पन्न किये जो न केवल लगान वसूल करत थे वरन् भूमि के स्वामी भी थे। इससे पूर्व इस देश में भूमि का स्वामी बहुधा राजा ही होता था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इस देश में जमींदारी प्रथा की नींव दो कारणों से डाली। पहला कारण तो यह था कि वह अपने हिस्तेदारों को निश्चित घन लाभ राशि के रूप में हर वर्ष देना चाहती थी। दूसरा यह कि जिन प्रदेशों पर कम्पनी ने विजय पाई थी उनमें एक ऐसा वर्ग उत्पन्न करना चाहती थी जो सदा ही राज्य का हितैषी बना रहे। इन बातों के अतिरिक्त अंग्रेजों का यह भी विश्वास था कि बेकबूल, बेदूस तथा टरनिप टाउनशेण्ड के समान जमींदार लोग अपनी-अपनी भूमि पर ही रहेंगे और वहाँ रहकर वह खेती की उन्नति के लिये हर प्रकार का प्रयत्न करेंगे। वे यह समझते थे कि जमींदार अपने काश्तकारों की घन तथा बुद्धि से भी सहायता करेंगे।

पर यह सब नहीं हुआ। जमींदार लोगों ने अधिकतर अपनी भूमि से बहुत दूर शहरी में रहना पसन्द किया। भूमि की देखभाल करने के लिये गुमास्ते अथवा मुन्शी लोग नियुक्त किये गये। ये मुन्शी लोग ही काश्तकारों के सम्पर्क में आते थे जमींदार का लगान वसूल करके उसको दे देते थे। पर वे लोग काश्तकारों से बहुत बुरा बर्ताव करते थे उनसे घूस के रूप में बहुत सा धन वसूल करते थे। उनकी जमींदार से भूठी शिकायत करके उनको भूमि से निवृत्तवा देते थे। उनमें लगान भी सख्ती से वसूल करते थे। काश्तकार को यह सब सहन करना पड़ता था क्योंकि वे जमींदार के पास जाकर ये सब बातें नहीं कह सकते थे।

मुन्शी अथवा गुमाश्तों के बुरे बर्ताव के अतिरिक्त जमींदार लोग भी अपने काश्तकारों से कोई प्रेम नहीं रखते थे। उनसे अधिक से अधिक लगान लेते थे। वे इसी से ही सन्तुष्ट न थे वरन् वे उनसे समय-समय पर नजराने के रूप में बहुत सा धन वसूल करते थे। काश्तकारों को केवल नजराना ही नहीं देना पड़ता था वरन् उनके ऊपर कई प्रकार के कर लगे हुये थे। य कर बहुत प्रकार के थे। डा० राधा कर्मल मुकर्जी के मतानुसार उड़ीसा प्रान्त में इन प्रकार के ७२ कर काश्तकारों पर लगे हुये थे। इन करा में हथियाना तथा जमींदार के बाल बटवाने तक का शामिल था।

इन सब करों तथा ऊँचे लगान के कारण काश्तकार लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी। उनके पास अपने बच्चों के पालन-पोषण के लिये भी पर्याप्त मात्रा में धन नहीं बचता था। पर फिर भी वे इसी व्यवसाय को करते थे क्योंकि देश में उनके करने के लिये दूसरा कोई व्यवसाय नहीं था। अपनी निर्जनता के कारण काश्तकार लोग भूमि की उन्नति के लिये कुछ भी न कर सकन थे और जमींदार लोगों को सिवाय अपने लगान के भूमि में कोई रुचि नहीं थी इसी कारण भूमि की स्थिति दिनो-दिन विगड़ती चली गई और आजकल यह स्थिति आ गई है कि हमारी भूमि विदेशों की भूमि की अपेक्षा बहुत ही कम उत्पन्न कर सकती है।

जमींदारी प्रथा के कारण देश में भूमि का बटवारा भी ठीक नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में लगभग ३ या एक प्रतिशत जमींदारों के पास राज्य की ५० प्रतिशत भूमि है। बम्बई राज्य में ५० प्रतिशत छोटे-छोटे काश्तकारों के पास केवल १० प्रतिशत भूमि है जबकि १०-६३ प्रतिशत बड़े-बड़े जमींदारों के पास कुल भूमि का ५० प्रतिशत भाग है। यही अवस्था दूसरे राज्यों में भी है। इस प्रकार हमारे देश में ७% भूमि उन लोगों के अधिकार में है जो भूमि पर स्वयं खेती नहीं करते। इस प्रकार इस देश में भूमि रहित मजदूरों (Landless labourers) की संख्या दिनो दिन बढ़ती जा रही है। १८७२ ई० के गणना कमीशन (Census Commission) के अनुसार इस देश में एक भी भूमि रहित मजदूर नहीं था, पर १८८२ ई० में इनकी संख्या ७० लाख हो गई। १८३१ ई० में भूमि रहित मजदूर दो करोड़ से भी अधिक थे और आजकल इनकी संख्या ५ करोड़ के लगभग है। इन मजदूरों

को बहुत ही कम वेतन मिलता है। इन मजदूरों की स्थिति दास जैसी है यह सब जमींदारी प्रथा के कारण ही हुआ। अब हमारे देश में दो वर्गों के लोग हैं—एक शोषण करने वाले (Those who exploit) और दूसरे शोषित (exploited)। इन दोनों वर्गों में अभी तक शोषण करने वाला वर्ग ही बलशाली है। पर अब जमींदारों को प्रायः सभी राज्यों में समाप्त कर दिया गया है।

जमींदारी प्रथा के कारण राज्य कोष को भी बहुत हानि हुई। १७६३ ई० में जबकि बङ्गाल ने स्थायी बन्दोबस्त प्रारम्भ किया गया उस समय बङ्गाल सरकार को मालगुजारी के रूप में २,८५,८७,७३२ रु० मिलता था। उस समय जमींदार लोग वास्तुकारों से ३½ या ४ करोड़ रुपया लगान के रूप में लेते थे। १८०६ ई० में इस प्रान्त में केवल ४ करोड़ रुपया मालगुजारी के रूप में जमा किया जाता था पर जमींदार वास्तुकारों से १६ करोड़ रुपया वसूल करते थे। इस प्रकार सरकारी आय तो २,८५,८७,७३० रुपये से बढ़कर केवल ४ करोड़ रुपया हुई पर जमींदारों की आय ३ अथवा ४ करोड़ से बढ़कर १६ करोड़ हो गई। यदि यह प्रथा इस राज्य में न होती तो राज्य सरकार को ही यह सब लाभ होता। यह बात बङ्गाल तक ही सीमित नहीं है वरन् यह उत्तर में भी है जहाँ जमींदार लोगों की जेबों में लगभग ८ करोड़ रुपया प्रतिवर्ष चला जाता है। यही स्थिति दूसरे प्रान्तों में भी है। यदि यह सब धन सरकारी राजकोष में जाता तो आज देश की राज्य सरकारों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मनो पर व्यय करने के लिये बहुत सा धन होता।

जमींदारी प्रथा के इन दोषों के कारण कौंसिल सरकार ने राज्य सत्ता हाथ में लेते ही जमींदारी उन्मूलन एक्ट पास किये। इन एक्टों के द्वारा जमींदारी प्रथा प्रायः सभी राज्यों में समाप्त होती जा रही है।

प्रथम योजना का एक महत्वपूर्ण अंग जमींदारी प्रथा को समाप्त करना था। इन कार्य में बहुत कुछ प्रगति हो चुकी है। जमींदारों को समाप्त करने सम्बन्धी कानून प्रायः सभी जगह पास हो चुके हैं और इस प्रकार मध्यस्थ प्रायः सभी स्थानों पर समाप्त हो गये हैं। बिना जोती हुई भूमि सरकार ने अपने अधिकार में ले ली है तथा इसको ग्राम पंचायतों को सौंप दिया गया है। इस प्रकार देश की कुल बोई हुई भूमि का ४३ प्रतिशत जो पहले जमींदारों, जागीरदारों, इनामदारा के हाथों में थी वह अब घट कर केवल ५ प्रतिशत उनके अधिकार में रह गई है।

विभिन्न राज्यों में इस कार्य की प्रगति इस प्रकार है—

(१) आसाम में १८२ लाख एकड़ भूमि जो स्थायी बन्दोबस्त के अधीन थी उस पर जमींदारों के अधिकारों को समाप्त करने के लिये कानून पास हो चुका है। इसी प्रकार मेसूर, हिमाचल प्रदेश तथा देहली में भी इस प्रकार के कानून पास हो चुके हैं। राजस्थान में जागीरदारों को ४ करोड़ २० लगान के रूप में मिलते थे। उसमें से उन जागीरदारों की भूमि जिससे कि २,८६ करोड़ लगान प्राप्त होता था, उनसे प्राप्त की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी जमींदारी समाप्त करने

के लिये बहुत पहले कानून पास हो चुका है। १९५६ ई० में इस कानून के नाम पर राज्य की जमींदारी भी समाप्त कर दी गई है। अभी कुछ स्थानों पर जमींदारी को प्राप्त करने के लिये कानून पास करने शेष हैं। एक अनुदान के अनुसार इन सब प्रकार के मध्यस्थों के क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास अनुदान के रूप में ६२५ २५ करोड़ रु० देने हैं। इसका ६७ प्रतिशत केवल उत्तर प्रदेश तथा बिहार को देना है। अभी तक सब राज्यों में ६८ ८७ करोड़ रु० दिया गया है।

क्षति पूर्ति की समस्या—क्षति पूर्ति देने के प्रश्न पर इस देश में बहुत मत-भेद है। कुछ लोगो का कहना है कि जमींदारों को उनकी भूमि के बदले पूरा-पूरा बाजारी मूल्य मिलना चाहिये। इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जो यह कहते हैं कि जमींदारों को कुछ भी नहीं मिलना चाहिये। इन लोगो का विचार है कि जमींदारों ने अपनी भूमि या तो खरीदी ही नहीं और यदि उन्होंने खरीदी भी है तो उनको जमींदारी से इतना धन प्राप्त हो चुका है कि उनको एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिये। पर ये दोनों ही विचार गलत मालूम पड़ते हैं। यदि सरकार जमींदारों को उनकी भूमि का पूरा बाजारी मूल्य दे तो यह उनके लिये असम्भव होगा। दूसरे, जमींदार लोग भी इतनी क्षति-पूर्ति पाने का कोई हक्क नहीं रखते। यदि सरकार जमींदारों को भूमि के बदले कुछ न दे तो यह भी ठीक न होगा क्योंकि हमारे विधान की ३१ वी धारा में यह बात स्पष्ट रूप से दी हुई है कि जब सरकार कोई भी सम्पत्ति जनता से लेगी तो उसके बदले क्षति-पूर्ति देगी। यदि ऐसा है तो सरकार जमींदारों से ही भूमि बिना कुछ दिये कैसे ले सकती है क्योंकि सरकार एक प्रकार की तथा दूसरे प्रकार की सम्पत्ति में कोई भेद-भाव नहीं कर सकती। यह तो रही वैधानिक बात, न्याय की दृष्टि से भी जमींदारों को कुछ न कुछ मिलना ही चाहिये। यह कहना कि सब ही जमींदारों को भूमि या तो दान में मिल गई है या छल-कपट से मिली है या पुरस्कार के रूप में मिली है सरासर गलत है। बहुत से जमींदार ऐसे भी हैं जिन्होंने भूमि को न्याय से कमाये हुये धन से खरीदा है। ऐसी दशा में इन जमींदारों को कुछ भी क्षति पूर्ति न देना बिल्कुल अन्याय है और यह बात भी जानना बड़ा बटिन है कि किस जमींदार ने किस ढङ्ग से भूमि खरीदी है। इस कारण यह बात ठीक ही जान पड़ती है कि जमींदारों को क्षति-पूर्ति के रूप में कुछ न कुछ मिलना ही चाहिये।

क्षति-पूर्ति के प्रश्न पर हमारी राज्य सरकारों में कोई मत-भेद नहीं है। वे सभी जमींदारों को कुछ न कुछ देना चाहती हैं पर उसके क्षतिपूर्ति आकने के ढङ्ग भिन्न-भिन्न हैं, उदाहरण के लिये आसाम, बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में क्षति-पूर्ति का धन वास्तविक आय (Net Income), उत्तर प्रदेश में वास्तविक सम्पत्ति (Net assets) तथा मद्रास में आधारभूत वार्षिक आय (Basic annual sum) से हिसाब निश्चित किया जायगा। पर यह ध्यान रहे कि उत्तर प्रदेश में वास्तविक सम्पत्ति उसी अर्थ में काम में लाई गई है जिस अर्थ में कि दूसरे प्रदेश

में वास्तविक आय काम में लाई गई है। वास्तविक आय लगान में से जमींदार के सब ढर्चें जैसे मातंगुजारी, कृषि आयकर भूमि के रखने के कारण जो जमींदार को खर्च करना पड़ता है, आदि घटाकर निकाली जाती है। इन प्रकार वास्तविक आय या वास्तविक सम्पत्ति निकालकर सरकार इस धन का कुछ गुना जमींदारों को देगी। उत्तर प्रदेश में क्षतिपूर्ति वास्तविक आय की आठ गुनी तथा राजस्थान व मध्य प्रदेश के कुछ भागों में सात गुनी है। मध्यभारत में जमींदारी उन्मूलन के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति आठ गुनी है तथा जागीर उन्मूलन कानून के मातहत सात गुनी है। अन्य राज्यों में जानाम में क्षतिपूर्ति दुगुनी से लेकर १५ गुनी तक, बिहार में तीन गुनी से २० गुनी तक, मद्रास में १२½ गुनी से ३० गुनी तक तथा मध्यप्रदेश में विलीन हुए प्रदेशों में दुगुनी से दस गुनी तक है। कम आमदनी वाली जमींदारियों पर क्षतिपूर्ति अधिक है तथा अधिक आय वाली जमींदारियों पर कम है।

उड़ीसा पश्चिमी बंगाल और भूपाल में क्षतिपूर्ति का कुछ अलग हिसाब है। भारत में विभिन्न राज्यों को जमींदारों तथा ग्रन्थ भूमि अधिकारियों को समाप्त करने के लगभग ३७० ४ करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में तथा ८६६ करोड़ रुपये पुनर्वास अनुदानों के रूप में देने पड़ेंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश को उपरोक्त बड़ी रकमों में से लगभग ७० प्रतिशत का भुगतान करना पड़ेगा।

क्षतिपूर्ति का धन निश्चिन करने के पश्चात् दूसरी बात जो सामने आती है वह है कि इस धन को जमींदारों को किस प्रकार दिया जाय। यह बात तो स्पष्ट ही है कि राज्य सरकार इतना धन खर्चे पैसे के रूप में नहीं दे सकती क्योंकि उनके कोष में इतना धन है ही नहीं। दूसरे, यह सब धन वह केन्द्रीय सरकार तथा जनता से श्रृण के रूप में नहीं ले सकती क्योंकि केन्द्रीय सरकार के पास इतना धन देने के लिये है ही नहीं। जनता से भी बहुत सा धन पंचवर्षीय योजना के लिये लिपा जा चुका है। यदि प्राप्त हो भी जाय तो भी केन्द्रीय सरकार उनको ऐसा न करने देगी क्योंकि उसको इसके पश्चात् जनता से श्रृण लेने में बड़ी कठिनाई होगी रिजर्व बैंक ने भी इसकी सहायता करने से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार राज्य सरकारों के लिये वह सब धन एक दम देना असम्भव सा प्रतीत होता है। इन कारण प्रायः सभी राज्य यह धन छोटे-छोटे जमींदारों को इन्ध के रूप में तथा बड़े-बड़े जमींदारों को इकरारनामों (Bonds) के रूप में देगी इन इकरारनामों का समय अवग-अलग राज्यों में अलग-अलग है जैसे उत्तर प्रदेश में ४० वर्ष उड़ीसा में ३० वर्ष आदि। इन पर जो ब्याज की दर दी जायेगी वह भी भिन्न भिन्न है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह निश्चित किया कि वह जमींदारों को धन तथा इकरारनामों के रूप में क्षतिपूर्ति देगी। इसके लिये उसने १९४७ ई० में जमींदारी उन्मूलन कोष (Zamindari Abolition) चालू किया। इस कोष में जो कोई कारनकार अपने लगान का १० गुना जमा कर देता है। उनको भूमिधर बना दिया जाता है भूमिधर को भूमि पर पूर्ण अधिकार होता है। इस कोष के कारण उत्तर प्रदेश में

५६ ७३ करोड़ रु० जमींदारों को दिया जा चुका है। यदि यह बात दूसरे राज्यों में भी हो तो बहुत लाभ होगा। क्योंकि जमींदारों को केवल इकरारनामों के रूप में देने से उसको इस समय कोई लाभ न होगा। इसलिये उनको कुछ धन तथा शेष धन के बदले इकरारनामों मिलने चाहिये।

जमींदारी उन्मूलन से प्रभावित जागीरदारों और जमींदारों की सख्या मद्रास में ३६०००, सौराष्ट्र में ४६०००, मध्यप्रदेश में ११ लाख तथा उत्तर प्रदेश में २ लाख है।

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भूमि की व्यवस्था

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है और वह है कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भूमि की क्या व्यवस्था होनी चाहिये। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् चार प्रकार से खेती की जा सकती है—

(१) सरकारी खेती (State farming), (२) सामूहिक खेती (Collective farming), (३) सहकारी खेती (Cooperative) और (४) किसान खेती (Peasant farming)।

(१) सरकारी खेती—सरकारी खेती करने में यह लाभ है कि इससे हमारे देशके छोटे-छोटे खेत बड़े हो जायेंगे और इन पर आधुनिक यन्त्रों द्वारा खेती हो सकेगी। इससे देश की खूब उपज बढ़ेगी परन्तु इससे लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होगी। इससे किसानों को अपने आप स्वयं इच्छा से कार्य करने का भी कभी अवसर प्राप्त न होगा। वे मजदूरों के रूप में खेती पर कार्य करेंगे। दूसरे सरकारी उद्योगों में निजी लाभ के लिये स्थान न होने के कारण काम करने वाले कम से कम कार्य करने का प्रयत्न करते हैं। तीसरे, सरकार के पास खेती का संचालन करने के लिये उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। चौथ, खेती जैसे उद्योग में इतना खर्चा लगाने के लिये भी सरकार के पास धन नहीं है। इस कारण सरकारी खेती करना उपयुक्त नहीं है।

(२) सामूहिक खेती—इस प्रकार की खेती रूस में होती है। वहां पर लगभग ६४ प्रतिशत जोती हुई भूमि पर इस प्रकार की खेती होती है। इस खेती में किसान अपनी भूमि को एक जगह एकत्र कर लेते हैं। उनके यन्त्र तथा पशु आदि भी सामूहिक ही होते हैं। खेती करने से जो लाभ होता है वह सब में बांट दिया जाता है। रूस में किसानों को सरकार की ओर से आदश मिलता है कि वे कितनी भूमि पर क्या फसल उगायें। इस प्रकार किसान वहां पर काम करने में स्वतन्त्र नहीं है। हमारे देश में इस प्रकार की खेती भी उपयुक्त नहीं है। इस देश के लोगों को निजी सम्पत्ति से बड़ा प्रेम है। इस कारण वे अपनी भूमि को एक स्थान पर इकट्ठा नहीं करेंगे। दूसरे, खेती के इस ढंग से रूस का वह सब खतपात जो वहां पर हुआ आखों के सामने आ जाता है। तीसरे, रूस का ही अनुभव यह

बताता है कि वहां पर यद्यपि कुले उपज में वृद्धि हुई है तो भी प्रति एकड़ उपयुक्त नहीं होगी।

(३) सहकारी खेती—इस प्रकार की खेती में किसान लोग अपनी खेती को एक स्थान पर एकत्र कर लेते हैं और सब मिलकर खेती करते हैं। खेती करने में सभी साझी मेलजोल से काम करते हैं। इस प्रकार की खेती में हिस के समान सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। खेती से जो प्राप्त होता है उसको सब आपस में बांट लेते हैं। इस प्रकार की खेती बहुत लाभदायक है। जहां पर भी यह छोट प्रकार से की गई है वहां पर फल बहुत अच्छा निकला है। हमारे देश में बम्बई, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से खेती की जा रही है। इस प्रकार की खेती प्रारम्भिक दश में है। इस कारण हम यह नहीं कह सकते कि इस प्रकार की खेती हमारे देश की जनमानस स्थिति के उपयुक्त है या नहीं। यह भी देखने में आया है कि जहां कहीं भी इस प्रकार की खेती सफल सिद्ध हुई है, वे ऐसे स्थान हैं जहां पर किसानों की सरकार ने भूमि जोतने के लिये दी है। जहां कहीं किसानों के खेतों को एकत्र करके सहकारी खेती करने का प्रश्न आता है वहां पर सफलता नहीं मिली क्योंकि किसान अपनी भूमि को एकत्र करने को तैयार नहीं हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की खेती को धीरे-धीरे चालू किया जा सकता है, एक दम नहीं। दूसरी योजना में यह ध्येय रखा गया है कि योजना काल में ऐसे पग उठाये जायें जिससे कि दस वर्ष में अधिकतर भूमि पर सहकारी खेती होने लगे। कांग्रेस के नामपुर अधिवेशन के स्वीकृत प्रस्ताव में कहा गया है कि हमारा लक्ष्य और मनसब समुक्त सहकारी खेती है। लेकिन अगले तीन वर्षों तक हम अपना प्रयास सेवा सहकारी समितियों पर ही केन्द्रित करना चाहिये।

(४) किसान खेती—इसमें किसान स्वयं भूमि के स्वामी होते हैं। वे स्वयं खेती करते हैं। इस प्रकार की खेती हमारे देश के लोगों के लिये बहुत उपयुक्त प्रतीत होती है क्योंकि इस देश के लोग निजी सम्पत्ति के बहुत प्रेमी हैं। चौधरी चरणसिंह जी इस प्रकार की खेती को ही देश के लिये उपयुक्त बताते हैं। इस कारण इस खेती को ही इस देश में चालू किया जा सकता है। पर ऐसा करने में थोड़ी सी सावधानी से काम लेना पड़ेगा। सरकार को चाहिये कि वह किसानों के ऊपर ऋण के बदले भूमि को देवने तथा रहन रहने के ऊपर कड़ा बन्धन लगा दे। उसको यह भी चाहिये कि वह यह पाबन्दी लगा दे कि जिस समय किसान भूमि देवना चाहे ता उसको खरीदने का पहला अधिकार सरकार को होगा। किसानों पर भी पाबन्दी लगनी चाहिए कि किसान लोग भूमि को केवल उन्हीं लोगों को हस्तांतर करें जो स्वयं खेती करते हैं। खेती को लगान पर देने की भी पाबन्दी होनी चाहिए। यदि यह सब सावधानी की जायेंगी तो इस प्रकार की खेती से हमारे देश को लाभ

हो सकता है। जैसे-जैसे देश में सहकारी समितियों का प्रचार बढ़ता जायेगा वैसे ही वैसे उस ढङ्ग से खेती करनी चाहिये क्योंकि सहकारी खेती से बहुत प्रकार के लाभ होते हैं जो किसान की खेती से नहीं होते।

यहाँ सब बात बताने योग्य है कि योजना के लिये जो मन्त्री मण्डल की स्थायी कांग्रेस कमेटी (The Standing Committee on planning of the Congress party in Parliament) है वह भी इस समय सहकारी खेती के विरुद्ध है। उसका कहना है कि भूमि की भूख को पहले व्यक्तिगत किसान की खेती करके सन्तुष्ट करना चाहिये। इसके पश्चात् किसानों को बताया जाय कि उनको आपस के लाभ के लिये मुख्य-मुख्य खेती के कार्यों जैसे जोतना, बोना, फसल काटना, फसल बेचना तथा खेती के लिये सामान मोल लेना आदि के लिये सहकारी समितियाँ चाहियें। यही बात इस समय दिखाई पड़ती है।

—

Q 34 Discuss the changes that have been brought about in India's land policy in recent years

प्रश्न ३४—अभी हाल ही में हुई भारतीय भूमि नीति में जो बदल हुई हैं उसका उल्लेख कीजिये।

अङ्गरेजी के शासन काल में इस दश में जमींदारी प्रथा की नींव पड़ती जिसमें मध्यस्थों के अधिकार को स्वीकार करके सरकार ने असली खेत जोतने वालों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। इसके कारण किसानों की जो दुर्दशा हुई उसके कारण अङ्गरेजी सरकार को भी कानून बनाने के लिये मजबूर होना पड़ा। परन्तु अङ्गरेजी शासन काल में जो कानून बनाये गये उनसे किसानों को कोई विशेष लाभ न हुआ। इसी कारण कांग्रेस सरकार ने प्रान्तों में राज्य सत्ता सम्भालते ही अपना ध्यान इस ओर आकर्षित किया। १९४७-५० के बीच सरकार ने कई प्रकार से इस विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया। इस बीच कांग्रेस ग्राम सुधारक समिति (Congress Agrarian Reforms Committee) की रिपोर्ट उल्लेखनीय है।

अप्रैल १९५१ ई० में प्रथम पंचवर्षीय योजना का सूत्रपात हुआ और सारे देश के लिये भूमि सुधार की एक योजना तैयार की गई। परन्तु इससे पहले भी बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तथा पेंप्सू में मध्यजनों के अधिकारों को समाप्त करने के लिये कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई थी। परन्तु उत्तर प्रदेश तथा बिहार में जमींदारों पर सरकार को जमींदारी अधिकार समाप्त करने के अधिकार को चुनौती देने के कारण कानून कुछ समय तक लागू न किया जा सका।

▼

योजना कमीशन के भूमि सुधार के विषय में निम्नलिखित सुझाव थे—

(१) खेती करने वाले तथा सरकार के बीच से मध्यस्थों को समाप्त करना।

(२) लगान सम्बन्धी ऐसे कानून पास करना जो लगान को कम करें और किसानों को भूमि पर एक निश्चित मुयावजा देने के पश्चात् स्थायी अधिकार प्राप्त करने का अवसर दें परन्तु यदि जमींदार स्वयं खेती करने के लिये भूमि प्राप्त करना चाहे तो उसको इस कार्य के लिये भूमि प्राप्त करने का अधिकार देना ।

(३) एक सेन की उच्चतम सीमा निश्चित करना ।

(४) चक्रवर्ती व भूमि का भविष्य में बटवारा रोक कर खेती का सुधार करना तथा सहकारी ग्राम प्रबन्ध व सहकारी खेती की उन्नति करना ।

योजना कमिशन के सुझावों के फलस्वरूप भारत सरकार ने मई १९५३ में भूमि सुधार के लिये एक केन्द्रीय समिति नियुक्त की जिसका कार्य राज्य सरकारों व भूमि सुधार के प्रस्तावों पर विचार करके योजना कमिशन की भूमि सुधार विम का मार्ग-दर्शन करना होगा ।

प्रथम योजना के चालू होने के पश्चात् या तो राज्यों में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने वाले कानून पास हो चुके हैं या होने वाले हैं । जम्मू व काश्मीर को छोड़कर दोष सभी राज्यों में जमींदारों को उनका अधिकार प्राप्त करने के लिय क्षति-पूर्ति दी जायगी । क्षति-पूर्ति देने के पश्चात् जब भूमि सरकार के हाथ में आ जायगी तब उसकी आय में अवश्य वृद्धि होगी ।

प्रथम योजना में भूमि सुधार के लिय निम्नलिखित मुयाव दिया गया है—

(१) लगान को कम करना, (३) भूमि स्वत्व (Tenure) सम्बन्धी निश्चितता, (२) किसानों को अपनी भूमि खरीदने का अधिकार देना ।

वहुत से राज्यों ने अधिकतम लगान निश्चित कर दिये हैं जो कि योजना कमिशन द्वारा बनाई हुई सीमा से अधिक नहीं है । इस कानून आध, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बङ्गाल, जम्मू, काश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेंसू, ट्रावनकोर, कोचीन तथा भोपाल में पास किये जा चुके हैं । उत्तर प्रदेश तथा दहली में ऐसे कानून पास हो चुके हैं जिनके द्वारा मौजुदा किसानों को भूमि रखने तथा उनकी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है । इन राज्यों में किसानों को उनकी भूमि से नहीं निकाला जा सकता ।

बम्बई, पंजाब, हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश, पेंसू, सौराष्ट्र तथा कच्छ में जमींदारों को स्वयं खेती करने के लिय भूमि प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है । पंजाब में केवल वहीं किसान भूमि को खरीद सकते हैं जो उसको लगातार १२ वर्ष से जोत रहे हैं । मध्य प्रदेश, मद्रास तथा मैसूर में किसानों को भूमि प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है ।

वहुत से राज्यों में खेती की उच्चतम सीमा भी निश्चित हो चुकी है जैसे जम्मू काश्मीर में २२½ एकड़, उत्तर प्रदेश में १२½ एकड़, बिहार में ५ आदमियों के परिवार के लिये ३० एकड़ तथा छोटा नागपुर के पहाड़ी जिले के लिये ४५ एकड़, हैदराबाद में एक पयल उगाने वाली नम भूमि के लिये ७ में ६ एकड़ तक, चाक

मिट्टी वाली भूमि के लिये ३० से ६० एकड़ तक, बाली मिट्टी व लेटराइट मिट्टी के लिये २१ से ३६ एकड़ तक, सौराष्ट्र में आर्थिक खेत की तीन गुनी, दिल्ली में ३० स्टेण्डर्ड एकड़ ।

वर्तमान स्थिति—खेती करने के ढङ्गों पर अब भी सामाजिक रिवाजों व ढंगों का बड़ा प्रभाव है । खेती साधारणतया छोटे-छोटे खेतों में व्यक्तिगत रूप से की जाती है । ग्राम सुधार दो बातों को ध्यान में रखकर किया है—

(१) अधिक उत्पत्ति प्राप्त करना तथा (२) सामाजिक न्याय लाना । राज्यों द्वारा किये गये सुधारों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में बाँटा जा सकता है—

(१) मध्यस्थों का अन्त ।

(२) भूमि स्वत्व सम्बन्धी कानून, (अ) लगान की फसल के $\frac{1}{2}$ तथा $\frac{1}{3}$ के बराबर करने, (आ) काश्तकार को भूमि में स्थायी अधिकार देने व जमींदार को अपने स्वयं के जोतने के लिये एक निश्चित मात्रा में भूमि प्राप्त करने, (इ) काश्तवार को जमींदार में एक मामूली मुआवजा देकर भूमि प्राप्त करने का अधिकार देने के लिये बनाये गये हैं ।

(३) खेत की उच्चतम सीमा निश्चित करना ।

(४) खेती का पुनर्गठन करना जिसमें चक्कबन्दी करना । खेती का बटवारा रोकना तथा सहकारी ग्राम व्यवस्था तथा सहकारी खेती करना आदि सम्मिलित हैं ।

इस प्रकार सारे राज्यों में अब जमींदारी प्रथा का अन्त हो गया है और इस प्रकार किसानों को सरकार के सम्पर्क में लाया गया है । बहुत से राज्यों में लगान घटा दिया गया है । यद्यपि किसानों को लगान सम्बन्धी मामलों में निश्चितता प्राप्त हो चुकी है तो भी अभी तक उनको भूमि का मालिक नहीं बनाया जा सका । इस सम्बन्ध में जो बठिनाई है वह यह है कि खेतों के आकार व उनके बटवारे सम्बन्धी सही आँकड़े न होने के कारण छोटे मालिकों व किसानों के अधिकारों में कैसे एकता लाई जाय । परन्तु अब क्योंकि १९ राज्यों के खेतों के आकार सम्बन्धी आँकड़े (Rural Credit Survey तथा National Sample Survey) प्राप्त हो चुके हैं इस कारण शायद हालत कुछ सुधर जायगी । किसानों को अब खेतों में नहीं निकाला जा सकता ।

इस प्रकार वर्तमान भूमि नीति का मुख्य उद्देश्य छोटे छोटे किसान मालिकों का निर्माण करना, उनको भूमि स्वतन्त्र सम्बन्धी स्थायी अधिकार देना, खेतों का अधिकतम आकार निश्चित करना, सहकारी खेती को प्रोत्साहन देना तथा लगान में कमी करना है ।

मई १९५५ ई० में योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में भूमि सुधार के मामले से हुई प्रगति की जांच करने तथा द्वितीय योजना के लिये भूमि सुधार नीति निर्धारण करने के लिये सुझाव देने के लिये एक पैनल की

नियुक्ति की। इस पेनल ने बहुत से मामलों की जाँच की जिनमें भूमि सुधार, खेती का पुनर्गठन, खेतों की चकबन्दी, उनका प्रबन्ध, कानून, सहकारी खेती, भूदान आदि मुख्य हैं। नगान सुधार समिति की रिपोर्ट ६ मार्च १९५६ को दी गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भूमि के स्वामित्व का आधार उत्तराधिकार न होकर श्रम होना चाहिये। इस प्रकार 'जोतने वाले को भूमि' मिलन का सिद्धान्त स्वीकार किया गया है।

द्वितीय योजना काल में भूमि सुधार के दो उद्देश्य हैं—पहला, कृषि उत्पत्ति के मार्ग में से ऐसी बाधाएँ दूर करना जो कि देश से कृषि प्रधान होने के कारण आती हैं और दूसरे इस प्रकार की हालतें निर्माण करना जिससे कि शीघ्रातिशीघ्र उच्च श्रेणी की वायकुशलता तथा उत्पादनशीलता वाली ग्रामीण अव्यवस्था का देश में निर्माण हो सके। केन्द्रीय प्रश्न एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की उन्नति के लिये बहुत स सुझाव दिये गए हैं जिनमें खेतों की चकबन्दी, खेती का नियन्त्रण, सहकारी खेती आदि मुख्य हैं।

Q 35 Explain the main features of the U P Zamindari Abolition and Land Reforms Act

प्रश्न ३५—उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधारक एक्ट को मुख्य विशेषतायें समझाइये।

१ जूलाई १९५० ई० को रात के ठीक १२ बजे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अग्राधारण गजट द्वारा यह घोषणा की कि आज से सारी भूमि को स्वामी सरकार हो गई है। यह घोषणा दोल पीटकर राज्य के प्रत्येक गांव में पटवारिया द्वारा भी की गई। इस अवसर को मनाव के लिये प्रभात फरिया निकाली गई तथा मिठाइयाँ बाँटी गई।

उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन तथा सुधारक एक्ट में ३१४ धाराएँ हैं। प्रारम्भ में यह राज्य की ४१३ करोड़ एकड़ भूमि में से केवल ३९० करोड़ एकड़ भूमि पर लागू होगा। यह बनारस, टीहरी गढ़वाल तथा रामपुर रियासतों पर सरकारी जायदादों पर, कुमायू प्रदेश के अधिक भाग पर, दहरादून जिले के जानसार बाबर परगने पर, मिर्जापुर जिले में केमपुर पहाड़ी के दक्षिणी भाग पर, बनारस जिले के परगना कसदार राजा स्थान पर। म्मुनिस्सिल, टाऊन एरिया, कैंटोनमेंट तथा नोटिफाइड एरिया के अन्तर्गत जितना क्षेत्र है उस पर लागू नहीं होता। इन स्थानों के लिये एक अलग कानून बनाया जायगा। परन्तु १९५५ तथा १९५६ ई० में इन सब में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिये भी कानून पास कर दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश की विधान सभा (Assembly) ने २ अगस्त १९४६ ई० को

एक प्रस्ताव पास किया जिसमें उसने यह निश्चय किया कि इस राज्य में जमींदारी प्रथा का अन्त होना चाहिये। जमींदारी उन्मूलन की योजना तैयार करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का भी निश्चय किया गया। जमींदारी उन्मूलन समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त १९४८ ई० में पेश की। ७ जौलाई १९४९ ई० को सबसे पहले विधान सभा में जमींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधारक बिल पेश किया गया। इस बिल के पास होने में काफी समय लगा क्योंकि जमींदार लोगो ने इसमें बहुत से रोड़े अटकाये। यद्यपि दोनों सभाओं से पार होकर इस बिल को राष्ट्रपति की अनुमति २४ जनवरी १९५१ ई० को मिल गई थी तो भी इसके ऊपर कार्य न हो सका क्योंकि जमींदार लोगो ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध एक मुकदमा चालू किया जिसमें कि उन्होंने सरकार को जमींदारों की भूमि इस प्रकार से लेने की चुनौती दी। पर वे इलाहाबाद हाईकोर्ट तथा सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से हारे और अन्त में १ जौलाई १९५२ ई० को सरकार ने सब भूमि को अपने अधिकार में लेने की घोषणा की। इसके फलस्वरूप मध्यस्थों के सभी हित जिनमें जोती, बोई जाने वाली जमीन, बाग की जमीन, बजर भूमि, वन मीनाश्रय हाट, बाजार आदि सम्मिलित थे बिना किसी प्रवन्ध के राज्य सरकार में निहित हो गये।

इस ऐक्ट के दो भाग हैं। पहले भाग में पुरानी पद्धति को नष्ट करने तथा दूसरे भाग में नई पद्धति को जन्म देने का वर्णन है।

पहले भाग में जमींदारी प्राप्त करने जमींदारों को क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासन प्रदान करने आदि का वर्णन है।

क्षतिपूर्ति—इस ऐक्ट के अनुसार जमींदारों की भूमि जमींदारों को खालिस सम्पत्ति (Net assets) का ८ गुना देकर प्राप्त की जायेगी। छोटे-छोटे जमींदारों (जिनकी सध्या बहुत अधिक है) को क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त पुनर्वास के लिये भी खालिस सम्पत्ति के एक गुने से लेकर २० गुने तक देने की योजना है। सबसे कम पुनर्वासन का धन उन जमींदारों को दिया जायेगा जिनकी खालिस सम्पत्ति सबसे अधिक होगी। जैसे-जैसे खालिस सम्पत्ति घटती जायेगी वैसे ही वैसे पुनर्वासन धन की मात्रा घटती जायेगी। इस प्रकार उस जमींदार को जिसकी खालिस सम्पत्ति सब से कम होगी २० गुना पुनर्वासन धन के रूप में मिलेगा।

यह बात निश्चित करने के लिए कि किसको क्या धन क्षतिपूर्ति के रूप में मिलना चाहिए क्षतिपूर्ति अफसर (Compensation officers) नियुक्त किये गए हैं। क्षतिपूर्ति हर एक सम्पत्ति पर अलग-अलग निश्चित की जायेगी। परन्तु पुनर्वासन सहायता धन जमींदार की आर्थिक स्थिति पर निर्भर होगा। सबसे छोटे जमींदार को सबसे अधिक पुनर्वासन धन मिलेगा। जो भूमि वक्फ तथा ट्रस्ट के आधीन हैं उन को भी सरकार अपने अधिकार में ले लेगी। परन्तु इनमें से जिन भूमियों की आय व्यक्तिगत लाभ के लिये व्यय होती है उन पर क्षतिपूर्ति का धन उसी प्रकार दिया

जायेगा जिस प्रकार कि दूसरे जमींदारों को । परन्तु जिन भूमियों का धन दान देने तथा जनता की भलाई के काम में खर्च होता है उन पर और सम्पत्तियों के समान क्षतिपूर्ति मिलने के अतिरिक्त वार्षिक सहायता (Annuity) भी इतनी मात्रा में दी जायेगी जितनी कि उनसे आजकल वार्षिक आय प्राप्त होती है ।

जिस समय सरकार किसी भूमि को अपने अधिकार में लेगी उस समय सरकार को क्षतिपूर्ति देनी होगी । जब तक सरकार क्षतिपूर्ति का धन जमींदार को न देगी उस समय तक सरकार को उस धन के ऊपर २½ प्रतिशत का व्याज देना पड़ेगा । परन्तु यदि सरकार को ली हुई भूमि का धन निश्चित करने में ६ महीने में अधिक लगेंगे तो सरकार जमींदार को अन्तर्कालीन क्षतिपूर्ति (Interim Compensation) देगी । १९५७ के अन्त तक अन्तर्कालीन क्षतिपूर्ति के रूप में ५६ ७३ करोड़ रुपये दिये गए ।

सरकार को क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वासन के रूप में लगभग १७६ करोड़ रुपये देना पड़ेगा । अन्तर्कालीन क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति इकरारनामों (Bonds) के रूप में दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न प्रकार के किसानों के लिए भूमि प्राप्त करने की दर में अभी हाल ही में बदल करने की घोषणा की है जो इस प्रकार है—उन भूमिधरों को जो भूमि प्राप्त करने की घोषणा के छपने के पूर्व भूमिधर हुये hereditary rates पर किये गए मूल्यांकन का ५० गुना अथवा मालगुजारी का ८० गुना, इन दोनों में जो भी अधिक हो, दिया जायगा ।

सीरदारों को hereditary rates पर किये गए मूल्यांकन का २० गुना दिया जाएगा । यदि भूमिधर अथवा सीरदारों द्वारा दी गई मालगुजारी hereditary rates पर किये गए मूल्यांकन से कम है तो मूल्यांकन तथा मालगुजारी के अन्तर का २० गुना क्षतिपूर्ति के धन में जोड़ दिया जायेगा ।

गाँव समाज अथवा स्थानीय सत्था के आसामी को उनके द्वारा दिये गए अथवा दिये जाने वाले ५ वर्ष के लगान के बराबर क्षतिपूर्ति दी जायेगी । दूसरे आसामियों को hereditary rates पर किये गए मूल्यांकन का ५ गुना क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा । अग्रवासियों को hereditary rates पर किये गए मूल्यांकन का ७½ गुना क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जायेगा । आसामी अथवा अधिवासी को जो क्षतिपूर्ति दी जाएगी वह उसके भूमि के स्वामी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति में से कम कर दिया जायेगा ।

जमींदारी उन्मूलन कोष (Z A fund)—जमींदारी उन्मूलन बिल के पास होने से पहले ही सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कोष बिल पास किया । इस बिल के अनुसार कोई भी काश्तकार जो अपने लगान का १० गुना जमींदारी उन्मूलन कोष में जमा कर देगा उसको भूमिधर बना दिया जायेगा । भूमिधर को भूमि में पूरा-पूरा अधिकार होगा । अभी तक यह निश्चित नहीं किया गया कि इस धन को किस

प्रकार खर्च किया जायेगा। पर यह सम्भावना है कि इसको एक सिंकिंग फण्ड (Sinking fund) में रक्खा जाये, जिसमें कि प्रतिवर्ष ३ करोड़ रुपया जो सरकार को जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् मालगुजारी के रूप में आजकल से अधिक प्राप्त होगा जमा किया जाये और इस धन से ४० वर्ष पीछे इकरारनामों का धन उनके स्वामियों को दिया जाये।

भूमि की नई पद्धति

भूमि की नई पद्धति का वर्णन इस ऐक्ट के दूसरे भाग में किया गया है। इस नई पद्धति को हम तीन भागों में बांट सकते हैं—(१) ग्राम जातियों (Village communities) अथवा ग्राम समाज की स्थापना, (२) मालगुजारी प्रथा (Land Tenures), (३) सहकारी खेती की उन्नति।

(१) ग्राम जाति अथवा ग्राम समाज—एक ग्राम जाति में ग्राम के काश्तकार तथा ग्राम के निवासी सम्मिलित होंगे। ग्राम समाज के आधीन ग्राम की सामूहिक भूमि (Common Land), ग्राम की सीमा के भीतर के वन, सब वृक्ष जो किसी खेत में न हों, जनता के कुएँ, तालाब, आने जाने के मार्ग, घाट, मछली, हाट तथा बाजार होंगे। ग्राम समाज एक ग्राम पंचायत नियुक्त करेगी जिसका कार्य यह होगा कि वह, वे सब काम करे जो कानून उस पर सौंपे। इस ग्राम पंचायत का कार्य ग्राम की देख-भाल करना तथा ग्राम समाज का जो भूमि सौंपी गई उसका प्रबन्ध तथा देख-भाल करना होगा। इसका यह भी कर्तव्य होगा कि वह खेती तथा कुटीर उद्योग धन्धों की उन्नति करने में सहायक हो। सरकार यदि चाहे तो वह पंचायत द्वारा मालगुजारी भी वसूल करा सकती है। गांव पंचायत एक कमेटी नियुक्त करेगी जिसका कर्तव्य यह होगा कि वह खाली पड़ी हुई भूमि तथा दूसरी भूमि का प्रबन्ध करेगी।

(२) मालगुजारी प्रथा—इस ऐक्ट के अनुसार इन राज्य में दो प्रकार के बड़े-बड़े काश्तकार तथा दो प्रकार के छोटे काश्तकार होंगे। बड़े काश्तकारों को भूमिधर तथा सीरदार और छोटे काश्तकारों को आसामी तथा अधिवासी कहेंगे।

भूमिधर—भूमिधारी का अधिकार उस सब भूमि में होगा—(१) जो जमींदार की सीर, खुद काश्त अथवा कुज की है, (२) अवध में स्थायी पट्टे की भूमि जिस पर काश्तकार या तो स्वयं खेती करता हो या उस पर उसका कुज हो, (३) जिम भूमि का काश्तकार निश्चित लगान देता हो अथवा उस पर वह कोई लगान न देता हो, (४) मौरूसी काश्तकार अथवा उस काश्तकार की भूमि जिसमें उसको उत्तराधिकार का अधिकार है और जिस पर वह स्थायी लगान देता हो अथवा कोई लगान ही नहीं देता अथवा धारा १७ में दिये पट्टा दामी अथवा इस्तमरारी काश्तकार की भूमि जिसको बेचकर उसको हस्तांतर करने का अधिकार हो।

इन सब के अतिरिक्त वे सब काश्तकार जो सीरदार होंगे उनको यह अधिकार होगा कि वे अपने लगान का १० गुना भूमि उन्मूलन कोष में जमा करके भूमिधर बन सकते हैं ।

भूमिधर को अपनी भूमि में स्थायी पीढ़ी पर चलने वाला तथा हस्तांतरण-शील अधिकार (Permanent heritable and transferable right) होगा । वह अपनी भूमि को इच्छानुसार किसी भी काम में ला सकेगा । ये बेदखल नहीं किया जा सकेगा । भूमिधर को भविष्य में कोई लगान न देना पड़ेगा । वह केवल मालगुजारी देगा जो कि वर्तमान लगान की आधी होगी । इस प्रकार वह ४० वर्ष तक आधा लगान देगा । इसके पश्चात् उसको जो मालगुजारी देनी पड़ेगी वह तब तक बन्दोबस्त पर निर्भर होगी ।

सीरदार—सीरदार का अधिकार हर एक मौल्मी काश्तकार (Occupancy tenant) को होगा । इस प्रकार हर एक काश्तकार जिसके पास की अवधि में विशेष शर्तों पर भूमि है, भूतपूर्व मालिक काश्तकार (Ex proprietary tenant), मौल्मी काश्तकार, उत्तराधिकार का अधिकारी रखने वाला काश्तकार, विशेष लगान की दर देने वाला काश्तकार तथा कुंज रखने वाला काश्तकार सीरदार बन जायेगा ।

सीरदार को भूमि में स्थायी तथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले अधिकार होंगे । परन्तु वह भूमि को अपनी इच्छानुसार हर एक काम में नहीं ला सकेगा । वह अपनी भूमि पर केवल खेती बागवानी अथवा पशुपालन का कार्य ही कर सकेगा ।

आसामी—आसामी का अधिकार निम्नलिखित वास्तकारों का होगा—(१) कुंज वाली भूमि के काश्तकार अथवा उप-काश्तकार को, (२) उस मनुष्य को जिसके पास किसी काश्तकार ने अपनी भूमि रहन रखी हो, (३) चरागाहों अथवा नदी के पानी के नीचे की भूमि अथवा वह भूमि जो वन लगाने के लिये रख छोड़ी गई हो अथवा नदिया की वह भूमि जिस पर कभी कभी खेती होती है, के काश्तकार को, (४) उन मनुष्यों को जिनके पास भूमिधर अथवा सीरदार से एकट के अनुसार भूमि पीछे आई हो ।

आसामी को अपनी भूमि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले अधिकार तो होंगे परन्तु उसके अधिकार भूमि में स्थायी न होंगे ।

अधिवासी—अधिवासी सीर के काश्तकार अथवा उप-काश्तकार होंगे । इन काश्तकारों को एकट के चारू होने के पश्चात् पाँच वर्ष तक भूमि रखने का अधिकार होगा । पाँच वर्ष पश्चात् वे भूमि के लगान का १५ गुना जमींदारी उन्मूलन कोष में जमा करके भूमिधर बन सकते हैं ।

भविष्य में भूमिधर तथा सीरदार तो मालगुजारी देंगे और आसामी तथा अधिवासी लगान देंगे ।

इस एकट में इस बात का भी प्रबन्ध किया गया है कि किसी काश्तकार के

वर्ग इसलिये खेती नहीं करता क्योंकि उसको इस वान का विश्वास नहीं होता कि उसको अपनी फसल का उचित मूल्य भी मिल सकेगा या नहीं। यदि पदार्थों का मूल्य स्थिर कर दिया जाये तो यह वर्ग अपने उत्पादन व्यय का हिसाब लगा कर अपने लाभ को निकाल सकेगा और यदि उसको लाभ दिखाई देगा तो यह वर्ग अवश्य इस कार्य में लग जायगा। इसके कारण कृषि उद्योग की अवस्था उन्नति होगी।

यदि अभी कृषि पदार्थों के मूल्य को स्थिर न किया गया तो भविष्य में वे घिर जायेंगे। इसके कारण किसानों का ऋण भार भविष्य में बढ़ जायगा। १९३०-३४ के बीच होने वाली मन्दी के कारण भारत का प्राचीन भार कई अरब रुपया बढ़ गया था।

यदि कृषि पदार्थों के मूल्यों को स्थिर करने के कारण कृषि की उन्नति होगी तो इसके कारण हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ जायगी। देश में व्यापार की उन्नति होगी। सरकार व रेलों की आय बढ़ जायगी। इस प्रकार इसके कारण बहुत लाभ होने की आशा है।

इसके विपरीत जो लोग कहते हैं कि कृषि पदार्थों के मूल्यों को स्थिर नहीं करना चाहिये उनका कहना है कि यदि मूल्य स्थिर किये गये तो वे ऊँची सीमा पर स्थिर किये जायेंगे और यदि ऐसा हो गया तो उससे कई प्रकार की हानि होगी। पहली, यह कि इसके कारण उपभोक्ता का खर्च बढ़ा हुआ रहेगा और उसको कभी भी चैन न मिल सकेगा। दूसरी यह कि इसके कारण पक्के माल का मूल्य अधिक रहेगा और उसके कारण पक्के माल का मूल्य भी अधिक हो जायगा। पक्के माल का मूल्य अधिक न होने के कारण हमारे माल की विदेशों में माँग घट जायगी और विदेशी माल की माँग हमारे देश में बढ़ जायगी। इसके कारण देश के उद्योगों की अवस्था उन्नति होगी। तीसरी, यह कि इसके कारण मजदूरों का जीवन-स्तर बढ़ जाने के कारण उनकी मजदूरी बढ़ जायगी और इसके कारण भी पक्के माल का मूल्य बढ़ जायगा और उसका प्रभाव हमारे देश के पक्के माल के निर्यात पर पड़ेगा।

यदि हम कृषि वस्तुओं के मूल्यों की स्थिरता के पक्ष व विपक्ष के तर्कों को देखें तो हम यह कह सकते हैं कि मूल्यों की स्थिरता से हमको लाभ अधिक होगा और हानि कम। पर यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि मूल्यों को सोच समझ कर स्थिर किया जाय तथा उसमें समय-समय पर परिवर्तन करने की गुञ्जायश छोटी जाय। मूल्य स्थिर करते समय हमको केवल किसान के हितों को ही नहीं देखना चाहिये बरन् उपभोक्ताओं तथा उद्योग-धन्य के हितों को भी देखना पड़ेगा। ऐसी बात ध्यान में रखने से हमको कोई विशेष हानि न होगी। इसके अनिश्चित यह बात भी है कि यदि हमको मूल्य स्थिर करने से थोड़ी हानि हो भी गई तो हमको उसको सहन करना चाहिये। इसका कारण यह है कि हमारा कृषि उद्योग बली

खराब हालत में है और उसको उन्नत करना बड़ा आवश्यक है। एक बार इस उद्योग के उन्नत होने पर हम कृषि मूल्यों को स्वतन्त्र छोड़ सकते हैं।

यहाँ यह बात बताने योग्य है कि अशोक महता कमेटी ने कहा है कि मूल्य के ढाँचे को स्थिर नहीं किया जा सकता। जब तक कि मूल्य इस प्रकार घटते-बढ़ते हैं कि उनके कारण लागत व कुछ लाभ प्राप्त होता रहता है तब तक उनमें परिवर्तन कोई चिन्ता का विषय नहीं। परन्तु जब मूल्यों में इतना परिवर्तन हो जाता है कि उसके कारण लागत और आय तथा मूल्य में बहुत अन्तर हो जाता है तब वे चिन्ता का विषय बन जाते हैं। मूल्यों में इतना अधिक परिवर्तन दूर करना चाहिये। इस बात को प्राप्त करने के लिये कमेटी ने सुझाव दिया है कि एक एक उच्च शक्ति मूल्य स्थिरता बोर्ड स्थापित किया जाय जिसका कर्तव्य यह हो कि वह मूल्य स्थिरता की सामान्य नीति को निश्चित करे तथा उसको समय-समय पर लागू करने के लिए कदम उठाये।

परन्तु सरकार ने पूरे तौर पर इस सुझाव को नहीं माना है क्योंकि मूल्य निश्चित करने का कार्य आर्थिक नीति का एक मुख्य अङ्ग है जिसको एक सरदार के बाहर एक कानूनी सस्था के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। परन्तु जून १९५८ की एक सूचना के अनुसार सरकार केन्द्रीय अर्थ-मन्त्रालयों के सभा सचिवों की एक समिति को यह कार्य सौंपी कि वह देश के मूल्य-स्तर की दिशा की जानकारी करे तथा उसको स्थिर करने का सुझाव दे।

एशिया तथा सुदूर पूर्व के देशों के लिये कृषि मूल्यों तथा आयों से सम्बन्धित हुई F. A. O. केन्द्र की एक बैठक इस निर्णय पर पहुँची कि किसानों को एक न्यूनतम मूल्य का विश्वास दिलाने की अपेक्षा यह प्रयत्न करना चाहिये कि मूल्यों में कम से कम सीमाओं के बीच परिवर्तन हो। मूल्यों में बहुत अधिक स्थिरता को दूर करना चाहिये जिससे कि उत्पादन का माग के साथ सामञ्जस्य स्थापित हो जाय। परन्तु यह आवश्यक है कि फसल कटने के पश्चात् जो मूल्यों में बहुत अधिक कमी आ जाती है उसको दूर किया जाए तथा उन क्षेत्रों पर निगाह रखी जाय जहाँ मूल्य बहुत ऊँचे तथा नीचे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि फसल की बिक्री के ढङ्ग को उन्नत किया जाय जिससे कि किसानों को अधिक लाभ हो। यह भी आवश्यक है कि उन सब कारणों को ध्यान में रखा जाय जो कि मूल्य पर प्रभाव डालते हैं तथा उन पर एक-एक करके विचार किया जाय। यह भी आवश्यक है कि फसल बोनस से बहुत पहले ही मूल्य सम्बन्धी निणय की घोषणा कर दी जाय जिससे कि उसका फसल के ऊपर अधिक से अधिक प्रभाव पड़े और उससे किसान को अधिक से अधिक उत्पत्ति करने का प्रोत्साहन मिले।

यह हर्ष का विषय है कि हमारी सरकार इस ओर निरन्तर कदम उठा रही है। उसने गन्ने के मूल्यों को स्थिर कर दिया है। उसका प्रयत्न है कि रूई व पटसन के मूल्य एक न्यूनतम सीमा से नीचे न गिरे। अभी हाल ही में जब गेहूँ के दाम गिरते

लगे तो केन्द्रीय सरकार ने घोषित किया कि वह स्वयं गेहूँ को खरीदेगी जिससे कि गेहूँ का मूल्य १० रु० मन से कम न हो। अभी अगस्त १९५७ ई० में खाद्य मन्त्री श्री अजीत प्रसाद जैन ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को एक सुझाव भेजा है कि खाद्य पदार्थों के मूल्य वर्तमान स्तर पर स्थिर कर देने चाहियें। ऐसा करने से किसानों को बड़ा लाभ होगा। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में भी यह बात स्वीकार की गई है किसानों को उचित लाभ का विश्वास दिलाने के लिये प्रत्येक फसल का न्यूनतम भाव फसल बोन से उचित समय पहले ही निश्चित कर देना चाहिये और जहाँ कहीं आवश्यक हो फसल को सीधे किसान से खरीदनी चाहिये। किसानों को लाभ होने से सारे देश को लाभ होगा क्योंकि हमारे देश में लगभग ७० प्रतिशत व्यक्ति किसान ही हैं।



Q 39 State in broad outline the policy of the state towards Indian agriculture from the middle of the nineteenth century upto the present day

प्रश्न ३९—१९ वीं शताब्दी के मध्य से आज तक सरकार की जो नीति भारतीय कृषि के लिए रही हो उसकी विस्तारपूर्वक रूपरेखा लिखिये ।

उत्तर—स्वतन्त्रता से पूर्व इस देश की शासनगत्ता अंग्रेज लोगों के हाथ में थी । अंग्रेजों को इस देश की आर्थिक उन्नति करने में कोई रुचि नहीं थी । उनका उद्देश्य इस देश में एक मजबूत राज्य स्थापित करना था । इसी से उन्होंने इस देश में कुछ सुधार जैसे विद्या का प्रचार, सती प्रथा रोकना आदि किये । इसी कारण उन्होंने दूसरी आर्थिक समस्याओं की ओर बहुत कम ध्यान दिया ।

देश की आर्थिक समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान १८७० ई० के पश्चात् आकर्षित हुआ जबकि देश में बहुत से भूषण अकाल पड़े । १८८० ई० में अकाल कमीशन (Famine Commission) ने इस बात पर ज़ार दिया कि हर प्रान्त में कृषि विभाग (Agricultural Department) खोला जाये जो एक डाइरेक्टर के आधीन हो । इस विभाग का कार्य कृषि सम्बन्धी सूचनायें एकत्रित करना है जिससे कि वह आने वाले अकाल की बाबत सरकार को पहिले ही सूचित कर दे, कृषि में इसलिए उन्नति करना जिससे कि अकाल फिर न पड़े तथा अकाल के समय अकाल पीड़ितों की सहायता करना है । सरकार ने इस सुझाव के अनुसार १८८२ ई० में प्रान्तीय कृषि विभाग खोले । इनका कार्य हर गांव से कृषि सम्बन्धी सूचनायें तथा आकड़े एकत्रित करना था । एक नया शाही कृषि विभाग (Imperial Department of Agriculture) भी खोला गया ।

१८८६ ई० में डा० वालकर (Voelcker) को जो कि शाही कृषि सोसायटी का कृषि रसायनी सलाहकार था इस देश में भेजा गया । उसका कार्य यह था कि वह बताये कि इस देश में कृषि के ऊपर कैसे कृषि रसायन लागू की जा सकती है । उसने सारे देश का भ्रमण किया और तब अपनी रिपोर्ट दी । इस रिपोर्ट में उसने बताया कि भारतीय कृषि न तो प्रारम्भिक दशा में है और न पिछड़ी हुई में । देश के बहुत से भागों में खेती इतने उत्तम ढङ्ग से की जा रही है कि उसमें कुछ उन्नति करने की आवश्यकता ही नहीं है और जहाँ कहीं भी कृषि की बुरी दशा है वहाँ पर यह इसलिए नहीं है कि लोग खेती करना नहीं जानते बल्कि इसलिए है कि वहाँ पर

खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधायें नहीं हैं। उसने खेती को उन्नत करने के लिए बहुत से सुझाव रखे।

१८६० ई० में डा० बालकर के सामने ही कृषि सभा हुई। जिसमें डा० बालकर के कहने से भारतीय सरकार ने जे० डब्लू० लीडर को कृषि रसायनज्ञ (Agricultural chemist) नियुक्त किया। दूसरे क्षेत्रों में भी कृषि उन्नत करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। इस कारण १९०१ ई० में कृषि का एक इन्स्पेक्टर जनरल तथा एक माईकोलोजिस्ट नियुक्त किया गया। इसके पश्चात् १९०३ ई० में एक कृमिशास्त्रवेत्ता (Entomologist) भी नियुक्त किया गया। शिकागो के धी हेली फिप्स ने लाड कर्जन को ३०,००० पौंड का एक दान किया जो कि पूसा अनुसन्धान-शाला (Pusa Research Institute) खोलने के काम में लाया गया। १९०५ ई० में कृषि विभागों का फिर से संगठन किया गया और उनके आधीन अनुसन्धान शालाय (Research Institutes) तथा प्रयोगी खेत (Experimental farms) खोले गए। केन्द्रीय सरकार ने खेती की उन्नति के लिए २० लाख रुपये भी दिये। इसी बीच कृषकों को ऋण लेने में सुविधा देन के लिये सरकार ने १९०४ ई० में एक सहकारी समिति एक्ट पास किया जिसके आधीन देश में बहुत सी सहकारी समितियाँ खुल गईं। १९०६ ई० के पश्चात् इस देश में सिचाई की उन्नति के लिए भी बहुत कुछ कार्य किये गये।

१९१६ ई० के सुधारों के पश्चात् कृषि विभाग प्रान्तीय सरकारों के हाथ में चला गया। केन्द्रीय सरकार का कार्य केवल उन चीजों से सम्बन्ध रखता था जो अखिल भारतीय महत्व की हो।

१९२६ ई० में भारतीय कृषि की जाँच करने के लिये एक शाही कमीशन (Royal Commission) नियुक्त किया गया। इस कमीशन का कार्य भारतीय कृषि तथा ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति की उस समय की जाँच करना और ग्रामीण लोगों की आर्थिक उन्नति तथा कृषि की उन्नति के लिये सुझाव देना था। कमीशन की रिपोर्ट बहुत बड़ी है और इसमें कृषि आय (Land Revenue) तथा कृषि स्वत्व (Land Tenure) को छोड़कर करीब-करीब सभी कृषि समस्याओं का निदान करने के लिये सुझाव रखे गये हैं। इस कमीशन में यह सुझाव दिया कि एक शाही कृषि अनुसन्धान सभा (Imperial Council of Agricultural Research) की स्थापना की जाये जिसका कार्य भारत में कृषि अनुसन्धान को उन्नत करना, उसका मार्ग दर्शन करना तथा सम्बन्ध करना हो। इस सभा का कार्य कृषि तथा पशु सम्बन्धी सभी बातों की वास्तव सूचना एकत्र करके उनकी बतलाना है।

कमीशन की रिपोर्ट के पश्चात् इस देश में एक शाही कृषि अनुसन्धान सभा चालू की गई जिसको आजकल भारतीय कृषि अनुसन्धान सभा (Indian Council of Agricultural Research) कहते हैं। यह खेती सम्बन्धी अनुसन्धानों के लिये सहायता भी देता है। इसका कार्य समय-समय पर योग्य लोग देखते रहते हैं।

१९२६ ई० के पश्चात् जब मूल्य गिरने लगे तो खेती को बड़ी हानि हुई। कृषि पदार्थों के दाम सबसे पहले तथा सबसे अधिक गिरे। इससे भारतीय किसानों की तथा भारतीय कृषि की दशा बहुत बिगड़ गई। इस समय भारतीय सरकार ने दूसरे देशों की सरकारों के समान कृषक की सहायता करने के लिये कुछ भी नहीं किया। इस कारण किसानों के ऊपर ऋण का भार बहुत अधिक बढ़ गया। इसी बीच में सरकार ने १९३४ ई० में एक कृषि वस्तु विक्री-सलाहकार को नियुक्त किया और १९३५ ई० में रिजर्व बैंक के आधीन एक कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department) की स्थापना की जिसका कार्य कृषि को आर्थिक सहायता देना तथा सहकारिता के सम्बन्ध में पूरी जाँच पड़ताल करना है। प्रान्तीय सरकार ने कृषकों को महाजनो के पजे में से बचाने के लिये भी बहुत से कानून पास किये। इसके अतिरिक्त भूमि में किसानों के स्वत्व की रक्षा करने के लिये प्रान्तीय सरकार ने बहुत कुछ कार्य किये। जिसके फलस्वरूप आज बहुत से राज्यों में कृषक को भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता और न ही उससे नजराना आदि लिया जा सकता है। साथ-साथ राज्य सरकारों ने ग्राम सुधार की बहुत सी योजनाएँ भी बनाई क्योंकि ऐसा अनुभव किया गया है कि ग्राम सुधार की बड़ी योजनाओं के बिना, केवल खेती की उन्नति करना कठिन होगा।

द्वितीय महायुद्ध में कृषि पदार्थों के भाव बहुत ऊँचे हो गये। इसके कारण किसानों को बहुत लाभ हुआ। पर कंट्रोल के कारण उनको इतना लाभ न हो सका जितना कि होना चाहिये था।

जब से राष्ट्रीय सरकार आई है तब से उसने खेती की उन्नति की ओर काफी ध्यान दिया है। उसने जमींदारी का उन्मूलन किया है तथा खेती की उच्चतम तथा न्यूनतम सीमाएँ निश्चित की है। इसके अतिरिक्त वह खेती की चकबन्दी की ओर बड़ी तेजी से अग्रसर हो रही है। उसने उचित लगान निश्चित किये हैं तथा कानूनकारों को अनुचित अवकाश व नजरानों से बचाया है। उसने किसानों को जमीन खरीदने के लिये धन भी दिया है। इसके अतिरिक्त उसने बिना भूमि के किसानों को भूमि भी दी है।

सहकारी आन्दोलन की प्रगति के लिये उसने ऋण की विशेष सुविधाओं पर बल दिया है तथा सहकारी शिक्षा के प्रसार के लिये एक केन्द्रीय समिति भी नियुक्त की है। गाव के कार्यकर्त्ताओं के लिये भी शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया गया है।

सरकार ने बहुत सा धन खर्च करके बड़ी व छोटी सिंचाई की योजनाओं को चालू किया है। जहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना में बड़ी बड़ी सिंचाई की बहु उद्देश्य योजनाओं पर सरकार ६६१ करोड़ तथा कृषि तथा सामूहिक विकास योजना पर ३५७ करोड़ रुपये तथा छोटी छोटी योजनाओं जैसे ट्यूबवैल पर ४५ करोड़ रुपये खर्च करने जा रही थी वहाँ दूसरी योजना में वह सिंचाई तथा शक्ति योजनाओं पर ८६० करोड़ तथा कृषि सामूहिक विकास पर १६८ करोड़ रु० खर्च करेगी।

सरकार 'अधिक जल उपआओ योजना' तथा सामूहिक विकास योजना के अन्तर्गत भी सिंचाई का प्रबन्ध कर रही है।

प्रथम योजनाकाल में केन्द्रीय ट्रैक्टर सस्य में ११८६ लाख एकड़ भूमि तथा राज्य ट्रैक्टर सस्य में १७ लाख एकड़ भूमि को खेती के योग्य बनाया है। संग्रहण २५ लाख एकड़ भूमि को कटर बर्निशिंग, मिट्टी की सुरक्षा, नालियों आदि के द्वारा लाभ पहुँचा है। प्रथम योजनाकाल में ६३ लाख एकड़ भूमि को सिंचाई का प्रदत्त करके खेती के योग्य बनाया गया।

संयुक्त राष्ट्र टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत २०११ ट्यूबवैल बनाए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बम्बई में भी ट्यूबवैल बनाये जा रहे हैं। सरकार सरकारी समितियों को सहायता प्रदान कर रही है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में ११००, बिहार में १५० तथा पंजाब में ३००, बम्बई (गुजरात क्षेत्र) में ४००, बम्बई (सीराष्ट्र क्षेत्र) में ७०, पश्चिमी बंगाल में १२५, मद्रास में २७८ ट्यूबवैल बनाये जाने वाले हैं।

बड़ी-बड़ी योजनाओं के अन्तर्गत १५-२० वर्ष में १५ करोड़ एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकेगी।

सरकार मनु-गुन आदि से खाद बनाने का भी बड़ा प्रयत्न कर रही है। सामूहिक विकास योजनाओं वाले क्षेत्रों में १९१७-१८ में २२२ लाख टन कम्पोस्ट खाद तैयार की गई तथा १९१८-१९ का ध्येय २६४० लाख टन है। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में नालियों का पानी सिंचाई के काम में लाने की योजना है तथा बहो-बहो पशु बपशालाओं का खून भी खेती के काम में लाने की योजना है। इनसे अतिरिक्त १९१८-१९ में खासपनिक खाद का उपभोग ९ लाख टन हो गया।

राज्यों में उन्नत बीजों के बाँटने का भी प्रयत्न हो रहा है। योजना के पहले तीन वर्षों में धान, गेहूँ तथा दूसरे खाद्य-पदार्थों का २ लाख टन उन्नत बीज बाँटा गया। वह बीज खाद्य पदार्थों के नीचे के कुछ क्षेत्रों का ८५ प्रतिशत था। अब सरकार उन्नत बीज बाँटने की ओर बड़ी तेजी से ध्यान दे रही है। आशा है कि दूसरी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र में एक या दो बीज गोदाम स्थापित हो जायेंगे।

सरकार पौधों की रक्षा के लिये पौधा सुरक्षा सस्य बना रही है, तथा उसमें इस सम्बन्ध में कई प्रकार की मशीनें भी खरीदी हैं। इसके अतिरिक्त दिवियों का रोकने के साधनों का भी आधुनिकरण कर दिया गया है।

सरकार मिट्टी के कटने को भी रोकने का प्रयत्न कर रही है और केन्द्रीय सरकार ने १९१३ में एक केन्द्रीय मिट्टी सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की है जिसका कार्य मिट्टी की सुरक्षा के लिये अन्वेषण करना, राज्यों तथा नदी घाटी सस्यों को मिट्टी की सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं को बनाने में सहायता प्रदान करना, अपसरो

की टैक्नोक्ल प्रशिक्षा का प्रबन्ध करना तथा राज्यों और नदी घाटी अधिकारियों के लिये आर्थिक सहायता की सिफारिश करना है। इस बोर्ड ने अभी तक कच्छ महस्थान को रोमने का प्रयत्न किया है तथा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पैड लगाय गये हैं। १७ राज्यों में ऐसे बोर्ड स्थापित हो चुके हैं।

१९५१ में खाद्य पदार्थों के नीचे २३९५९ मिलियन एक्ड भूमि थी जो १९५७-५८ में बढ़कर २९७ ३७ मिलियन एक्ड हो गई।

द्वितीय योजना काल के लिये सरकार का यह प्रयत्न है कि वह किसानों को महकारा समितियों के द्वारा ऋण की अधिकाधिक सुविधाय प्रदान करे। सरकार किसानों की फसल एक्त्र करन के लिये गोदाम भी बनायगी तथा इनकी रसीद के आधार पर किसानों को ऋण भी दिया जायगा। इस कार्य के लिय सरकार न दूसरी योजना के लिये ४० करोड रुपये रखे हैं।

अभी हाल ही में सरकार न फसलों को उन्नत करने का प्रचार किया है। रबी की फसल के लिय यह प्रचार ९ राज्यों में किया गया। इस प्रचार के अन्तर्गत सरकार किसानों को समय पर उन्नत बीज व खाद देगी, बीज को कीड़ों से बचाने का प्रयत्न करेगी, सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी, उन्नत औजार प्रदान करेगी तथा ऋण देगी। इसके अतिरिक्त बहुत सी लाभदायक सूचनायें भी किसानों को दी गई तथा सामूहिक इनाम (community prizes) भी दिय गये। इसके अतिरिक्त किसानों को यह भी दिखाया गया कि उन्नत रीति से खेती करने से किस प्रकार लाभ होता है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सरकार खेती की उन्नति के लिये हर प्रकार से प्रयत्नशील है। प्रथम योजना में खेती को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। दूसरी योजना में यह स्थान उद्योग धन्धों को दिया गया है परन्तु फिर भी कृषि के महत्व को स्वीकार किया गया है।



Q 40 Distinguish clearly the principal characteristics of the Raiffeisen and the Schulz-Delitzsch types of co-operative societies

प्रश्न ४०—रेफीसन तथा शुल्ज डेलिश् सहकारी समितियों की मुख्य बातों के भेद स्पष्टतया बताइये ।

सहकारिता का अर्थ—सहकारिता न पूँजीवाद है और न साम्यवाद, यह इन दोनों के बीच एक ऐसा प्रयत्न है जिसमें पूँजीवाद के सब दुर्गुण दूर करते हुये समाजवाद के सब गुणों का प्राप्ति करने का प्रयत्न किया गया है । सहकारिता आन्दोलन निर्धन तथा असहाय व्यक्तियों के लिये होता है । इनमें वे सब लोग जो आर्थिक दृष्टि में कमजोर हो अथवा जिनको पूँजीपतियों द्वारा लूटे जाने की आशङ्का हो एक साथ मिल जाते हैं और कुछ धन एकत्र करते हैं । इस धन से तथा सगठन के बल पर प्राप्ति कृषि द्वारा वे अपनी आर्थिक, नैतिक तथा सामाजिक उन्नति करते हैं, और इस प्रकार अपनी योग्यतानुसार अपना पूर्ण विकास करते हैं ।

सहकारी आन्दोलन का जन्म जर्मनी में रेफीसन तथा शुल्ज डेलिश् द्वारा हुआ । रेफीसन ने अपना कार्य ग्रामों तथा शुल्ज डेलिश् ने अपना कार्य शहरों में प्रारम्भ किया । क्योंकि ग्राम तथा शहर के सामाजिक सगठन में अन्तर होता है इस कारण एक में नियम दोनों प्रकार के व्यक्तियों पर लागू नहीं हो सकते । इस कारण हम देखते हैं कि दोनों प्रकार की सहकारी समितियों के सिद्धान्तों में बहुत अन्तर है ।

रेफीसन के सिद्धान्त—

रेफीसन (Raiffeisen) पद्धति के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

(१) इस प्रकार की समिति का कार्यक्षेत्र बहुत छोटा होता है—एक गाँव, एक व्यवसाय अथवा एक जाति, जिससे कि सब सदस्य पूर्ण रूप से एक दूसरे से परिचित हो ।

(२) इस प्रकार की समिति में कोई हिस्से (Shares) नहीं हों और यदि होने हैं तो बहुत कम जिससे कि लोग लाभान्वित (Dividend) के कारण समिति में सम्मिलित न हो और इस प्रकार निर्धन लोगों का शोषण न हो सके ।

(३) इनके सदस्यों का दायित्व अपरिमित (Unlimited liability) होता है जिससे कि समिति की साख बट जाए और सदस्य समिति के कार्य में अधिक दिलचस्पी से भाग लें ।

(४) ये समितिप्रां बहुधा अपने ही सदस्यों को ऋण देती हैं और वह भी उत्पत्ति के कामों के लिये। इन कामों में बीज, हल, बैल आदि आते हैं।

(५) ये कुछ अधिक समय के लिये ऋण देती हैं और अपने सदस्यों को बिस्ती में ऋण लौटाने की सुविधा देती हैं। इसका कारण यह है कि किसान लोग फसल के पश्चात् ही ऋण लौटा सकते हैं। खेती में कम लाभ होने के कारण वे सब ऋण एक साथ नहीं लौटा सकते। इसलिये किसानों का होना आवश्यक है।

(६) इनका एक स्थायी द्रव्य कोष (Reserve fund) होता है जिसमें लाभ नहीं बांट जाता। यह इसलिये किया जाता है जिससे कि सहकारी समितियाँ अधिकाधिक अपने साधनों पर निर्भर रह सकें।

(७) ये अपने सदस्यों को लाभान्वित नहीं देती वरन् अपने लाभ को स्थायी कोष में एकत्र करती रहती हैं। यह इसलिये किया जाता है जिससे कि धनी लोग लाभ के कारण इन समितियों में न जुस जायें।

(८) इनके सब सदस्य बिना वेतन काम करते हैं। केवल मनी-कॉपाइमश (Secretary-treasure) को ही वेतन मिलता है।

(९) ये अपने सदस्यों के नैतिक उत्थान का भी प्रयत्न करती हैं।

मुल्ज डेलिश के सिद्धान्त—इसके विपरीत मुल्ज डेलिश सहकारी समितियों के सिद्धान्त ये हैं—

(१) इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि दस्तकार किसानों के समान पान-पान नहीं रहते। वे फैले रहते हैं।

(२) शेयर पूंजी (Share Capital) पर अधिक जोर दिया जाता है।

(३) सदस्यों का दायित्व परिमित होता है क्योंकि वे दूर-दूर रहने के कारण एक दूसरे के विषय में नहीं जान सकते। परिमित दायित्व के कारण उनको ऐसी परिस्थिति में अधिक हानि हो सकती है।

(४) ये थोड़े समय के लिये ऋण देती हैं क्योंकि दस्तकार लोग थोड़े समय में अपना सामान बनाकर तथा उसको बेचकर रुपया लौटा सकते हैं।

(५) इनका स्थायी कोष बहुत कम होता है क्योंकि ये लाभ को अपने सदस्यों को लाभान्वित के रूप में बांट देती हैं।

(६) पदाधिकारियों को वेतन दिया जाता है।

(७) ये सदस्यों की नैतिक उन्नति की अपेक्षा भौतिक उन्नति पर अधिक जोर देती हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों प्रकार की समितियों में बहुत बड़ा अन्तर है।

Q 41 Describe briefly the growth and working of the co-operative movement in India since 1904. What changes have been brought about in the working of the movement since then ?

प्रश्न ४१—१९०४ से भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन की उन्नति तथा कार्य पद्धति संक्षेप में लिखिये। उस समय से इसकी कार्य पद्धति में क्या-क्या परिवर्तन हुये ?

उत्तर—भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन एक मुख्य सदेश लिये हुये है। यह ग्रामीण तथा शहरी समस्याओं का निदान करने के लिये बहुत उपयुक्त मार्ग है। जिस देश में लोगो ने उत्तम रीति से इसको अपनाया है वहाँ पर इससे लोगो की सभी आर्थिक समस्याएँ प्रायः सुधर गई हैं। इसलिये हमारा विश्वास है कि सहकारिता से ही हमारे देश की आर्थिक उन्नति हो सकती है और किसी दूसरे ढङ्ग से नहीं।

१९०४ का कानून—इस देश में सहकारी समितियाँ सबसे पहले १९०४ ई० के सरकार साख्य समिति कानून (Co-operative Credit Societies Act) के अन्तर्गत चालू हुई। इससे पूर्व भी मद्रास आदि स्थानों पर निधि आदि खोलकर इस बात का प्रयत्न किया गया था कि लोगो की आर्थिक समस्या सुलझ जाये। पर ऐसे प्रयत्न उत्तम रीति से नहीं किये गए थे। इसी कारण हम यह कह सकते हैं कि सहकारिता का प्रारम्भ इस देश में १९०४ के पश्चात् ही हुआ। इस कानून के अनुसार केवल साख्य समितियाँ ही स्थापित हो सकती थीं। भारतवर्ष में ग्रामीण जनता की अधिकता के कारण ग्रामीण सहकारी समितियों पर अधिक जोर डाला गया। समितियों को दो श्रेणियों में बाटा गया—ग्राम तथा नगर। जिन समितियों में कम से कम दूँ सदस्य किसान होत थे वे ग्राम समितियाँ कहलाती थीं और शेष सब नगर समितियाँ। ग्राम समितियों के सदस्यों का उत्तरदायित्व अपरिमित होता था और नगर समितियों का उत्तरदायित्व समितियों की इच्छानुसार परिमित अथवा अपरिमित हो सकता था। सरकार अपनी इच्छानुसार इन समितियों का हिसाब अपने अफसरों से निःशुल्क जचवा सकती थी तथा इनके काम की देखभाल के लिये इन्स्पेक्टर नियुक्त कर सकती थी। सरकार ने इन समितियों को कर से बरी किया हुआ था तथा उनसे कोई रजिस्ट्री की फीस भी नहीं ली जाती थी। ग्राम समितियाँ तो पूर्णरूप से रेपीसन के विधान्त पर चलन वाली थी तथा नगर समितियाँ शुल्क विलिस के सिद्धान्त पर।

इस कानून के पाम हा जाने के पश्चात् सहकारी समितियाँ वेग से इस देश में बढ़ने लगी। १९०६-७ में इन समितियों की संख्या केवल ८४३ थी और उनके सदस्यों की संख्या १००,८४४ थी तथा उनकी कार्यशील पूँजी २३,७१,६८३ रुपये थी। १९११-१२ ई० में समितियों की संख्या बढ़कर ८,१७७, सदस्यों की संख्या ४०३,३१८ तथा कार्यशील पूँजी ३३५,७५,१६२ रुपये हो गई।

१९०४ के कानून के दोष—परन्तु थोड़े ही दिनों पश्चात् इस कानून के कुछ दोष दृष्टिगोचर होने लगे । इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि इसके अनुसार ग्राम तथा नगर समितियों का वर्गीकरण किया गया वह दोषपूर्ण तथा असुविधाजनक था । दूसरे, इस कानून में साख समितियों के अतिरिक्त और दूसरे प्रकार की समितियाँ बनाने का कोई प्रबन्ध न था । तीसरे, उच्च श्रेणी की समितियाँ बनाने का भी प्रबन्ध न था । चौथे, पंजाब तथा मद्रास आदि प्रान्तों में जहाँ शेर पूजा का अधिक महत्व था अपरिमित उत्तरदायित्व तथा लाभांश देने के ऊपर रोक लगा देने के कारण बहुत ही असुविधा हुई । १९०४ ई० के कानून के इन दोषों को दूर करने के लिये सरकार ने १९१२ ई० में एक दूसरा कानून पार किया ।

१९१२ का कानून—

१९१२ ई० में कानून में गैर साख वाली सहकारी समितियों जैसे त्रय-विक्रय उत्पादन, बीमा, घर आदि की अनुमति दी गई । दूसरे, सहकारी समितियों को पूजा की सहायता देने तथा इनके निरीक्षण आदि के लिये नवीन सधों की व्यवस्था की गई । इनमें (१) संघ (Unions) जिनके सदस्य प्रारम्भिक समितियाँ थीं और जिनका कार्य आपसी नियन्त्रण तथा हिसाब जाँचना था । (२) केन्द्रीय बैंक, जिनके सदस्य प्रारम्भिक समितियाँ तथा कुछ और व्यक्ति थे । (३) प्रान्तीय बैंक जिनके सदस्य कुछ बड़े व्यक्ति थे, सम्मिलित थे । इस कानून में यह आज्ञा दी गई थी कि मद्रास, पंजाब प्रान्तों में जहाँ शेर पूजा का बहुत महत्व था, अपरिमित दायित्व वाली समितियाँ भी लाभांश दे सकती थीं । सभी समितियों का इस बात की आज्ञा दी गई कि वे अपने लाभ का चौथाई भाग स्थायी द्रव्य कोष (Reserve fund) में हस्तांतरित करने के पश्चात् लाभ का १० प्रतिशत दान, विद्या आदि कार्य के लिये व्यय कर सकती थीं । इस कानून में ग्राम तथा नगर समितियों के बदले परिमित तथा अपरिमित दायित्व वाली समितियाँ बनाई गईं । इस कानून के अनुसार इन समितियों का दायित्व जिनके सदस्य दूसरी रजिस्टर्ड समितियाँ थीं, परिमित था तथा जिनका उद्देश्य किसानों को ऋण देना था उनका अपरिमित था । इनके अतिरिक्त और जो समितियाँ थीं उनका दायित्व उनकी इच्छा पर निर्भर था । इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में परिस्थिति के कारण रेफीसन का सिद्धान्त दृढता के साथ लागू न किया जा सका ।

इस कानून के पास हो जाने से इस देश में सहकारिता के आन्दोलन को बहुत प्रोत्साहन मिला । इसके पश्चात् समितियों की संख्या उनके सदस्यों की संख्या तथा उनकी कार्यशील पूँजी में बहुत वृद्धि हुई । पर यह वृद्धि सब प्रान्तों में एक ही नहीं थी । रयतवारी प्रान्तों में जैसे बम्बई, मद्रास आदि में इस आन्दोलन ने बहुत उन्नति की । पर जमींदारी प्रान्तों में अभी तक यह आन्दोलन बहुत कम लोगों तक पहुँचा है ।

मैक्लेगन समिति—

१९१४ ई० में सरकार ने इस आन्दोलन की जाँच करने के लिये मैक्लेगन समिति (MacLagan Committee) नियुक्त की। इस समिति ने जाँच के पश्चात् यह बताया कि इस आन्दोलन में कई दोष हैं और उनको दूर करना अत्यावश्यक है। मैक्लेगन समिति ने जो दोष बताये वह यह थे—सदस्यों का निरक्षर होना, प्रबन्ध करने वालों की स्वार्थपरता, पक्षपात, सरकार का आवश्यकता से अधिक हस्तक्षेप जिसके कारण सदस्य सहकारी समितियों को 'सरकारी बैंक' समझते हैं, आदि-आदि।

१९१६ के सुधारों के पश्चात्—१९१८ ई० के सुधारों के पश्चात् सहकारिता प्रान्तीय सरकारों के आधीन चली गई। इसके पश्चात् प्रान्तीय सरकारों ने आवश्यकतानुसार अपने नए कानून पास करके इस आन्दोलन की उन्नति की। बम्बई में नवम्बर पहले इस प्रकार का कानून १९२५ ई० में पास किया गया। यह कानून १९१२ ई० के कानून पर आधारित था। बम्बई के पश्चात् मद्रास, बिहार तथा उड़ीसा प्रान्तों ने भी अपने-अपने कानून पास किये। कुछ प्रान्तों ने जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा मद्रास ने जाँच समितियाँ (Enquiry Committees) नियुक्त की जिससे कि वे इस आन्दोलन की प्रगति की जाँच कर सकें। इन समितियों की तथा शाही कृषि कमीशन तथा प्रान्तीय और केन्द्रीय बैंक जाँच समितियों की रिपोर्ट बहुत ही लाभदायक है। इस बीच में १९१८ में मन्दी (Depression) आ गई और इसके साथ ही साथ भारत के सहकारी आन्दोलन के दुर्दिन आ गये। इस समय बहुत से प्रान्तों ने जाँच समितियाँ बैठाई और उनके वह अनुसार सहकारी आन्दोलन का पुनर्निर्माण किया गया। इसके पश्चात् समितियों की संख्या बढ़ाने की ओर ध्यान न देकर उनको सुधारने की ओर ध्यान दिया गया। इस काल में आन्दोलन पर सरकारी हस्तक्षेप और अधिक बढ़ गया। इस बीच में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई जिसके कारण इस आन्दोलन को बहुत ही लाभ पहुँचा। इस बैंक का कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department) कृषि साख की समस्याओं का अध्ययन करता है और जिन लोगों को साख अथवा सहकारिता में हाँच होती है उनको इस विभाग की बहुत सी उपयोगी सूचनाएँ मिल सकती हैं। यह विभाग समय समय पर अपनी रिपोर्ट छापता रहता है जिसमें सहकारी आन्दोलन की उन्नति का पूर्ण विवरण होता है।

द्वितीय महायुद्ध—द्वितीय महायुद्ध में सभी वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गये। इस कारण सहकारी समितियों के सदस्यों की आर्थिक स्थिति बहुत कुछ सुधर गई। इनके पक्षस्वरूप समितियों का जाग्रण उनके सदस्यों पर था वह बहुत कुछ अंशों में चुका दिया गया और इन समितियों की स्थिति भी बहुत कुछ सुधर गई। महायुद्ध में मध्यजनों (Middle men) से अपने आपको बचाने के लिये बहुत से उपभोक्ताओं ने उपभोक्ता सहकारी समितियों की स्थापना की। इसके अतिरिक्त

और प्रकार की गैर साख समितियाँ भी स्थापित हुईं। इसके फलस्वरूप बहुत से लोगो तक यह आन्दोलन पहुँच गया। युद्ध से पहले हर ४-५ गाव के पीछे एक समिति थी। पर १९४५-४६ ई० में हर ३८ गावों के पीछे एक समिति हो गई। युद्ध से पूर्व केवल ६२ प्रतिशत लोग इस आन्दोलन से लाभ उठाते थे पर १९४५-४६ ई० में १०६ प्रतिशत लोग लाभ उठाते थे। सन् १९४६ में सहकारी योजना समिति (Co-operative Planning Committee) ने कुछ सुझाव पेश किये जिनके अनुसार प्रतिवर्ष लगभग २१६०० सहकारी समितियों की वृद्धि होगी। इस समिति ने यह भी सुझाव दिया कि ये समितियाँ बहु-उद्देश्य होनी चाहियें तथा ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे कि अगले १० वर्ष में ५० प्रतिशत गाव तथा ३० प्रतिशत ग्रामीण जनता इस आन्दोलन से लाभ उठाने लगे। १९५१ ई० में रिजर्व बैंक ने एक समिति नियुक्त की जिसने ग्रामीण अर्थ व्यवस्था की जाँच करके १९५४ ई० में अपनी रिपोर्ट दी। इसने सहकारी आन्दोलन के ढाँचे तथा उसकी कार्य-पद्धति पर प्रभाव डालने वाले बहुत से सुझाव दिए हैं। इसने सबसे पहले बताया कि देश में राज्य के सहयोग से सहकारी आन्दोलन चलना चाहिये। द्वितीय योजना में इस प्रकार के सहकारी सहयोग को स्वीकार किया गया है।

आन्दोलन के कार्य करने के ढंग में समय-समय पर हुये परिवर्तन—

सहकारी समितियाँ इस देश में १९०४ से चालू की गईं। १९०४ के अधिनियम के अनुसार केवल साख समितियाँ ही स्थापित की जा सकती थीं। समितियों को नगर तथा ग्राम समितियों में बाँटा गया था। ग्राम समितियाँ रेफीसन के सिद्धांत पर तथा नगर समितियाँ चुल्ज डेलिश के सिद्धांत पर स्थापित की गई थीं। समितियाँ केवल एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिये स्थापित की जा सकती थीं। १९१२ के अधिनियम के अनुसार समितियों का भेद ग्राम तथा नगर न होकर परिमित दायित्व वाली तथा अपरिमित दायित्व वाली समितियाँ हो गया। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियाँ किसी भी कार्य के लिये स्थापित की जा सकती हैं। यही नहीं प्रारम्भिक सहकारी समितियों के अतिरिक्त उच्च स्तर की समितियाँ भी अब स्थापित की जा सकती हैं। इस प्रकार समितियों का कार्य चलता रहा। परन्तु कार्य करते-करते समय-समय पर समितियों के कार्य करने के ढङ्ग में कुछ दोष दिखाई पड़े जिनके कारण इनके कार्य करने के ढङ्ग में बहुत से परिवर्तन हो गये हैं। उदाहरण के लिये जहाँ पहले कृषि समितियाँ केवल साख देने के लिये चालू की जा सकती थी वहाँ अब वे किसी भी कृषि समस्या को सुलझाने के लिये स्थापित की जा सकती हैं। यद्यपि आज भी साख समितियों की संख्या इस देश में कुल की लगभग ७० प्रतिशत है तो भी हम कह सकते हैं कि इस देश में गैर-साख समितियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसके अतिरिक्त जहाँ पहले एक उद्देश्य समिति ही स्थापित की जा सकती थी वहाँ अब इस बात को विचारा जा रहा है कि सहकारी समिति को ग्राम के लोगों के सब कार्यों का केन्द्र बनाया जाये। दूसरे शब्दों में सहकारी समितियाँ

बहु-उद्देश्य होनी चाहिये । यद्यपि अभी तक बहु-उद्देश्य समितिया भी केवल एक-दो कार्य ही करती हैं तो भी ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि समितियों के कार्य का क्षेत्र बढ़ाया जाये । ऐसी समितियों की संख्या अब बढ़ती जा रही है । इसके अतिरिक्त पहले साख समितियों के सदस्यों का दायित्व अपरिमित होता था वहाँ अब परिमित दायित्व वाली समितिया बढ़ती जा रही हैं । १९५७-५६ में कृषि साख समितियों में से ४१४ प्रतिशत समितियों के सदस्यों का दायित्व परिमित था । इसके अतिरिक्त जहाँ कृषि, साख समितियों का कार्य-क्षेत्र केवल एक गांव होता था वहाँ अब ३-५ मील के क्षेत्र के बहुत से गांव मिलकर समितिया बनाते हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो नई समितिया बनाई जा रही है उनका कार्य-क्षेत्र अब कई मील होता है । श्री डालिंग ने अपनी हाल की रिपोर्ट में बताया है कि उत्तर प्रदेश में एक समिति का क्षेत्र ३ मील में बसे ३० गांव हैं, तथा राजस्थान में ५ मील है । इसके अतिरिक्त अब समितियों का प्रबन्ध करने वाले अवैतनिक न होकर वेतन लेने वाले होते जा रहे हैं ।

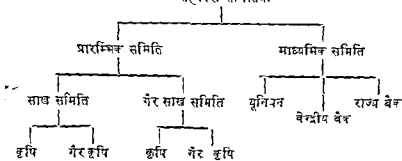
श्री डालिंग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार रेपीसन के सिद्धान्तों का छोड़ दिया गया है । अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ ८ पर उन्होंने कहा है, "इस प्रस्ताव के कारण मौलिक परिवर्तन हो गये हैं—अपरिमित दायित्व वाली समितियों के स्थान पर परिमित दायित्व वाली समितिया, अवैतनिक प्रबन्ध के स्थान पर गुप्त वेतनिक प्रबन्ध, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से एक गांव के स्थान पर बहुत से गांवों का समूह और अन्त में, परन्तु किसी प्रकार भी सबसे कम नहीं, सरकार का समिति में एक हिस्सेदार के रूप में भाग लेना, वास्तव में रेपीसन सिद्धान्त जिसके ऊपर कि भारत में कृषि सहकारी साख समितिया बनाई गई है उसको पूर्णरूप से छोड़ दिया गया है ।"

Q 42 Describe the structure of the co operative movement in India

प्रश्न ४२—भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन की रूप रेखा लिखिये ।

उत्तर—भारत में सहकारी आन्दोलन की रूप रेखा निम्नलिखित है—

सहकारी समितिया



कृषि सहकारी साख समितियाँ (Agricultural Co operative Credit Societies) — इन समितियों को कोई भी दत्त व्यक्ति मिनकर बना सकते हैं। इनका कार्य क्षेत्र एक गाँव होता है। इनके सदस्यों का दायित्व बहुधा अपरिमित होता है। परन्तु अब अग्रेज लोगों को समिति में लाय के दिये कड़ी की दायित्व परिमित भी है और अब इस प्रकार के दायित्व वाली समितियों की संख्या बढ़ती जा रही है। १९२८ ई० में अपरिमित दायित्व वाली समितियों की संख्या केवल ८ प्रतिशत थी। परन्तु १९५५-५६ ई० में यह बढ़कर ४१.४ प्रतिशत हो गई। इनका प्रबन्ध भी निम्न होता है। केवल मन्त्री कोषाध्यक्ष को ही वेतन मिलता है। परन्तु मद्रास सहकारी समिति ने १९४० में यह सुझाव दिया कि जहाँ तक हो प्रबन्धकर्त्ताओं को शुल्क देना चाहिये जिससे कि वे अपना पूरा समय लगाकर समिति के उत्थान के लिये प्रयत्न कर सकें। इन समितियों की कार्यशील पूँजी (Working Capital) सदस्यों के प्रवेश शुल्क, उनका डिपोजिट रेयर पूँजी, समिति के लाभ, दूसरी समितियों के डिपोजिट तथा ऋण, सरकार अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारी बैंकों के लिये हुये नष्ण आदि से एकत्र होती है। इसमें ऋण की मात्रा बहुत अधिक होती है। ३० जून १९५८ तक ११ बड़े बड़े राज्यों में कार्यशील पूँजी का केवल ६ प्रतिशत से भी कम डिपोजिट था इसका अभिप्राय यह हुआ कि ये समितियाँ लोगों में कृषि यत् की आदत नहीं डलवा रहीं हैं। सहकारी आन्दानन पर दी गई १९५५-५६ की रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि समितियों को इस ओर ध्यान देना चाहिये। ये समितियाँ बहुधा उत्पादन कार्यों के लिये ऋण देती हैं परन्तु कभी-कभी यह गैर उत्पादक कार्यों तथा पुराने ऋण को चुकाने के लिये भी ऋण देती हैं। ये समितियाँ अपने सदस्यों की सत्यता पर ही ऋण दे देती हैं। परन्तु अब ये उनसे कुछ धरोहर (Security) भी लेती हैं जिससे की समिति की आर्थिक स्थिति खराब न हो पाय। ये अपने लाभ को अपने सदस्यों में नहीं बाँटती बल्कि उनको एक स्थायी कोष में एकत्र करती रहती हैं। परन्तु १९१२ ई० के कानून के पास होने के बाद ये लाभ का कुछ भाग दान तथा विद्या के लिये भी खर्च कर सकती हैं। १९५६-५७ में इस प्रकार की समितियों की संख्या १६१,५१० थी। उनकी सदस्यता ८१,१६,८४६ तथा उनकी कार्यशील पूँजी ८८३० करोड़ थी। १९५६-५७ में इन समितियों ने ७३३ करोड़ के ऋण दिये। इस वर्ष के अन्त में इन समितियों की लेनदारी ७६८२ करोड़ रुपये थी। इस लेनदारी में से १६८२ करोड़ रुपये अर्थात् २०% की लेनदारी रुपया चुकाने के समय को पार कर चुकी थी। अपनी कार्यशील पूँजी के लिये ये केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर रहती हैं।

इन समितियों की व्याज की दर बहुत ऊँची होती है। बहुत से राज्यों में यह दर १२½ प्रतिशत थी तथा मनीपुर राज्य में तो यह २१ प्रतिशत थी। परन्तु

उन राज्यों में जहाँ सहकारी आन्दोलन की बहुत उन्नति हुई है ब्याज की दर ४ और १२ प्रतिशत के बीच में थी।

रिजर्व बैंक की १९५६-५७ की सहकारी आन्दोलन की रिपोर्ट से पता चलता है कि इन समितियों की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन समितियों की सदस्यता का औसत ५६ था। एक समिति की औसत हिस्सा पूँजी केवल १२२८ रु० थी। प्रति सदस्य पूँजी का औसत केवल २२ रु० था। प्रत्येक सदस्य के पीछे डिपोजिट का औसत केवल ६ रु० था। समितियों की कायशील पूँजी का औसत केवल ६०८६ रु० था। तथा समितियों ने प्रति सदस्य केवल ६४ रु० का ऋण दिया। इन आंकड़ों से पता चलता है कि न तो ये समितियाँ सदस्यों में कर्जायन करने की आदत ही डाल रही हैं और न उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को ही पूरी कर रही हैं। श्री डाल्टन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि १९५५-५६ में बिहार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों में केवल ८ प्रतिशत समितियाँ 'अ' वर्ग वर्गीकृत की थी।

कृषि सहकारी गैर साव समितियाँ (Agricultural Co operative non-credit Societies)—इस प्रकार की समितियों की आवश्यकता इस देश में बहुत अधिक है परन्तु अभी तक उनकी संख्या बहुत कम हुई है। १९५६-५७ में इस प्रकार की समितियाँ साठ समितियों की केवल ३१६०५ के लगभग ही थीं। इनके सदस्यों की संख्या २७ ५७,८११ थी तथा इनकी कायशील पूँजी २८ ४१ करोड़ थी। इस प्रकार की समितियाँ खेती के औजार खरीदने तथा बीज खरीदने के लिये बनाई गई हैं। कहीं-कहीं बिक्री समितियाँ भी बनाई गई हैं। कहीं-कहीं बैलों तथा खेती के बीभे के लिये सहकारी बीमा समितियाँ भी खोली गई हैं। पंजाब में पशु पालने के लिये समितियाँ खुली हुई हैं। मद्रास तथा बंगाल में सिंचाई समितियाँ हैं। पंजाब तथा बम्बई में सहकारी चकबन्दी समितियाँ पाई जाती हैं। अच्छी खेती को प्रोत्साहन देने के लिये बम्बई, मद्रास तथा पंजाब में कुछ समितियाँ हैं।

इस प्रकार की समितियों की आज दश के लिये बहुत आवश्यकता है। इनके उन्नत हुए बिना हम किसान की आर्थिक उन्नति की कभी भी आशा नहीं कर सकते। जहाँ कहीं इस प्रकार की समितियाँ बनाई गई हैं वहाँ पर किसानों को बहुत लाभ हुआ है। इसी कारण हम आशा करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की समितियाँ बहुत बढ़ती जाएंगी।

गैर कृषि सहकारिता (Non Agricultural Co operation)—

साव समितियाँ (Credit Societies)—इस प्रकार की समितियाँ भी दश के लिये बहुत उपयोगी हैं। मैकलेगन समिति के मतानुसार वर्तमान युग में जबकि वस्तुओं के भाव बढ़ रहे हों, मकानों की समस्या सामने हो, मजदूरी न दी जा रही हो, शिक्षा के प्रसार के कारण लोगों का जीवन-स्तर बढ़ रहा हो, इस प्रकार की समितियों की आवश्यकता है। दूसरे, खेती के लिये धन की आवश्यकता वर्ष के कुछ

ही महीनो में रहती है। शेष महीनो में केन्द्रीय तथा प्रांतीय बैंको का रुपया बेकार पड़ा रहता है। इस रुपये को उपभोग में लाने के लिये भी इस प्रकार की समितियों की देश में आवश्यकता है। आज हमारे देश में इस प्रकार की समितियों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है। ये समितियाँ गुल्ज डेलिस के सिद्धान्त पर आधारित हैं।

१९५६-५७ में इन समितियों तथा उनके सदस्यों की संख्या निम्न थी।

समिति का प्रकार	संख्या	सदस्यता
क्रय विक्रय	२७६७ (परिमित दायित्व) ३४६ (अपरिमित दायित्व)	६,६६,५७५
उत्पादन तथा विक्रय	६७३१ (परिमित दायित्व)	
(अ) विक्रय	४५८७ (")	६,६०,०१४
(ब) अन्य	६७४ (अपरिमित दायित्व)	
उत्पादन	६८६५ (परिमित दायित्व) ११२२ (अपरिमित दायित्व)	४,६४,२०२
सामाजिक कार्य	५२४३ (परिमित दायित्व)	
गृह	५४० (")	१७०४५

योजना आयोग Programme evaluation organisation ने हाल ही में इस बात की सिफारिश की है कि ग्राम समितियों को कुछ सहायता इस कारण की जानी चाहिये। जिससे कि वे किसानों को अपना माल इन समितियों को बे सकें। यह एक महत्व पूर्ण सिफारिश है क्योंकि आजकल किसानों को अपनी फसल के कुल मूल्य का केवल ६० प्रतिशत ही मिलता है तथा इस पर भी उसको व्याज देना पड़ता है। यह भी कहा गया है कि जैसे ही किसान अपनी फसल समिति को सौंपे तो उसको तुरन्त ही उसकी फसल के मूल्य का जितना भी अधिक अनुपात दिया सके वह देना चाहिये।

विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की गैर कृषि साख समितियाँ पाई जाती हैं। जैसे बम्बई तथा मद्रास में पीपिल्स बैंक हैं। ये बैंक इटली के खूजेटी बैंको के समान हैं। ये मध्य वर्ग के लोगों को आवश्यकता पड़ने पर धन की सहायता देते हैं। मद्रास, बम्बई तथा पंजाब में मध्य वर्ग के लोगों में कृषायत की आदत डालने के लिये मितव्ययिता समितियाँ पाई जाती हैं। बम्बई, मद्रास तथा बङ्गाल में जीवन बीमा समितियाँ पाई जाती हैं। दस्तकारों, जैसे जुलाहों, मोचियों, लुहारों, बढ़इयों, आदि को ऋण देने के लिये भी प्रायः सभी जगह समितियाँ बनी हुई हैं। इन समितियों द्वारा देश में कुटीर तथा छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों का बहुत प्रसार हो सकता है।

इस कारण यह आवश्यक है कि इनकी सख्या बढ़ाई जाय । बहुत से मिल क्षेत्रों में मजदूरों ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये भी सहकारी समितियाँ बनाई हैं । कहीं-कहीं अछूत लोगों ने भी सहकारी समितियाँ बनाई हैं किन्तु अर्थाभाव के कारण ये समितियाँ अधिक सफलता प्राप्त नहीं कर सकी ।

३० जून १९५७ ई० को इनकी सख्या १०१५० तथा इनके सदस्यों की सख्या ३२,३८७२७ थी । इनका हिस्सा पूँजी उस समय २० ८४ करोड़ रुपये थी तथा इनके डिपोजिट ६४ ५९ करोड़ रुपये थे जो कि कुल कार्यशील पूँजी के ६४ ३१ प्रतिशत थे । इससे पता चलता है कि इन समितियों में लोग कृषि समितियों की अपेक्षा अधिक धन जमा करते हैं । १९५६-५७ ई० में इन समितियों ने ८२ ०७ करोड़ रु० उधार दिये । ३० जून १९५७ ई० को इसमें से ७४ ९९ करोड़ पाना शेष था । इस धन में से ६ १४ करोड़ चुकाने की तिथि को पार कर चुका था । इन समितियों ने कुछ विक्री का कार्य भी किया । १९५६-५७ में इन्होंने ३ ५६ करोड़ का माल प्राप्त किया तथा ३ ५६ करोड़ का माल बेचा ।

नैर साख समितियाँ (Non-credit Societies)—हमारे देश में आज केवल कृषि समितियों अथवा नैर कृषि साख समितियों की ही आवश्यकता नहीं है बरन् जोर भी बहुत प्रकार की समितियों की आवश्यकता है । देश के बहु-सह्यक लोग आल धनी तथा मध्यजनों (Middle men) द्वारा लूटे तथा सताये जाते हैं । इन लोगों की सहायता यदि हो सकती है तो सहकारी समितियों द्वारा हो सकती है । नैर साख नैर कृषि समितियाँ बहुत प्रकार की हो सकती है । जैसे दस्तकार लोगों ने कच्चा माल खरीदने तथा पक्का माल बेचने के लिये अपनी समितियाँ बना रखी है । कहीं उपभोक्ता समितियाँ पाई जाती है । द्वितीय महायुद्ध से पूर्व उपभोक्ता समितियाँ बहुत कम सख्या में थी । परन्तु महायुद्ध में चीर बाजारी करने वालों से

समिति का प्रकार	सख्या	सदस्यता
अथ विक्रय	५७७८ (अ) १ (ब)	११,१०,६६०
उत्पादन तथा विक्रय	१२,१६९ (अ) १८४ (ब)	१२,४१,९२२
उत्पादन	४४०६ (अ) ६६ (ब)	४,४४,२२२
सामाजिक कार्य	२,५६९ (अ) ३२२ (ब)	१,५२,४२७
गृह	३०७९ (अ) २ (ब)	२,०६,९२२
बीमा	६ (अ)	७८६७

(अ) परिमित दायित्व वाली

(ब) अपरिमित दायित्व वाली

अपने आपको बचाने के लिये उपभोक्ताओं ने बहुत से स्थानों पर इस प्रकार की समितियाँ बनाई हैं। १९३८-३९ तथा १९४५-४६ के बीच उपभोक्ता समितियाँ की सख्या आसाम में १३ से बढ़कर १०१३, बम्बई में २५ से ६१२, मद्रास में ८५ से १७४० तथा उड़ीसा में ८ से ३७१ हो गई। उत्तर प्रदेश में भी इन समितियों की सख्या बहुत तेजी से बढ़ी। बहुत से स्थानों में गृह समितियाँ (Housing Societies) भी बनाई गई हैं। ये समितियाँ बम्बई, मैसूर तथा मद्रास में पाई जाती हैं। दूसरे स्थानों पर भी यह समितियाँ बटती जा रही हैं। इन समितियों से उन लोगों को बहुत लाभ है जो अपना मकान बनाना चाहते हैं पर उनके पास ऐसा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में धन नहीं होता है। इसी प्रकार और बहुत सी समस्याओं का निदान करने के लिये सहकारी समितियाँ बनाई जा सकती हैं।

केन्द्रीय समितियाँ (Central Societies)

केन्द्रीय समितियाँ तीन प्रकार की होती हैं—यूनियन, केन्द्रीय बैंक तथा राज्य बैंक। यूनियनों की सदस्यता केवल प्रारम्भिक समितियों के लिये खुली है। किन्तु केन्द्रीय बैंक तथा राज्य बैंकों के सदस्य प्रारम्भिक समितियाँ तथा कुछ और व्यक्ति भी होते हैं।

यूनियन—ये तीन प्रकार की होती हैं—(१) जिम्मेदारी लेने वाली (Guaranteeing) जैसे बम्बई में, (२) देख-भाल करने वाली (Supervising) जैसे मद्रास तथा बम्बई में, (३) बैंकिंग, जैसे पंजाब में।

यूनियन पाँच या पाँच से अधिक समितियों का एक सय होता है जो पाँच से आठ मील के क्षेत्रफल में काम करता है। इसका प्रबन्ध सदस्य समितियों के प्रतिनिधियों की एक समिति द्वारा होता है। यूनियन प्रारम्भिक सदस्यों तथा केन्द्रीय बैंकों के बीच एक शृंखला का कार्य करती है। १९५५-५६ में भारत में देखभाल करने वाली ५८२ यूनियन थी जिनके ३९२५९ सदस्य थे।

केन्द्रीय बैंक (Central Bank)—हमारे देश में केन्द्रीय बैंकों की बहुत आवश्यकता है क्योंकि प्रारम्भिक समितियाँ इतना धन एकत्र नहीं कर सकती जितना कि उनको चाहिये। इस कारण उनको अपना काम चलाने के लिये ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है इन समितियों को व्यापारिक बैंक ऋण नहीं देते। इसी कारण इन समितियों को ऋण देने के लिये विशेष प्रकार के सहकारी बैंकों की आवश्यकता है जो कि स्वयं एकत्र करके समितियों को ऋण के रूप में दे सकें। १९०४ ई० के सहकारी साख समिति ऐक्ट में इस प्रकार के बैंक बनाने के लिये कोई प्रवन्ध नहीं किया गया था। परन्तु शीघ्र ही सरकार को यह अनुभव हुआ कि सहकारी केन्द्रीय बैंकों का स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। इसी कारण १९१२ ई० के ऐक्ट में इन बैंकों को स्थापित करने का आयोजन किया गया।

केन्द्रीय बैंक का मुख्य कार्य प्रारम्भिक समितियों को ऋण देना है। यह ऋण या तो ये बैंक सीधे समितियों को दे देते हैं या जहाँ कहीं जिम्मेदारी लेने

वाली ग्रुनियन हैं उनके द्वारा देते हैं । कहीं-कहीं ये बैंक समितियों की देख-भाल का कार्य भी करते हैं । यह कार्य बहुधा उसी अवस्था में किया जाता है जबकि ये बैंक किसी प्रारम्भिक समिति के हिस्सेदार हों । ये बैंक बहुधा एक जिले या एक बड़े ताल्लुके में कार्य करते हैं ।

केन्द्रीय बैंक तीन प्रकार के होते हैं—पूजी वाले, मिश्रित तथा शुद्ध । पूजी वाले बैंक में केवल व्यक्ति ही होते हैं । मिश्रित में व्यक्ति तथा समितियाँ और शुद्ध में केवल समितियाँ ही होती हैं । भारतवर्ष की वर्तमान स्थिति में मिश्रित बैंक ही सबसे उपयुक्त हैं क्योंकि इस प्रकार के बैंक मध्यम श्रेणी के लोगों का धन एकत्र कर सकते हैं और इन लोगों के अनुभव से लाभ उठा सकते हैं और अवसर आने पर ये अपने आप को शुद्ध बैंको में बदल सकते हैं ।

केन्द्रीय बैंक बहुत से वह कार्य भी करते हैं जो व्यापारिक बैंक करने हैं, जैसे बम्बई तथा मद्रास में ये बैंक लोगों का रुपया जमा के रूप में रखते हैं, उनके बिलों, बैंकों तथा हुण्डियों का रुपया एकत्र करते हैं, डाक्टर तथा हुण्डियाँ जारी करते हैं, मूल्यवान् वस्तु को सुरक्षा के लिये रखते हैं, लोगों को धरोहर के बदले ऋण देते हैं, आदि-आदि ।

१९४०-४१ में ब्रिटिश भारत में ६०१ बैंक तथा बैंकिंग ग्रुनियन थी । उनके सदस्य ७६८३४ व्यक्ति थे तथा १२१,२६२ समितियाँ थी । उनकी कार्यशील पूजी ३६७ करोड़ (६ प्रतिशत), स्थायी कोष ४२७ करोड़ (१४ प्रतिशत), व्यक्तियों तथा समितियों द्वारा जमा किया हुआ धन १७६० करोड़ (६० प्रतिशत), प्रान्तीय बैंकों से लिया हुआ ऋण ४५० करोड़ (१५ प्रतिशत) और सरकार से लिया हुआ ऋण ५३८ करोड़ (२ प्रतिशत) था । इस प्रकार उनकी कार्यशील पूजी में ७६ प्रतिशत ऋण था । इस ऋण में से ५७ करोड़ तो व्यक्तियों पर तथा १८३१ करोड़ समितियों पर था । दूसरे शब्दों में, सेंट्रल बैंको द्वारा लिए हुए ऋण का ८५ प्रतिशत उन्होंने ऋण के रूप में व्यक्तियों तथा समितियों को दिया हुआ था । इस दिये हुये ऋण का बहुत सा धन तो भर चुका था और बहुत से का बहुत दिनों से भुगतान नहीं हुआ था । इसी कारण इन बैंकों की दशा बहुत खराब थी । गत वर्षों में किसानों की स्थिति सुधर जाने के कारण इन बैंकों की स्थिति सुधर गई है । इन बैंकों में डिपोजिट तथा कार्यशील पूजी की भी वृद्धि हुई है । १९५४-५५ में इनकी सख्या ४८५, कार्यशील पूजी ७३६६ करोड़ तथा दिये गये ऋण ६८१७ करोड़ रुपये थे । इनके सदस्यों की सख्या २७२ लाख थी तथा इनका द्रव्य कोष ६१४ करोड़ रुपये था परन्तु १९५५-५६ में इनकी सख्या घटकर ४७८ रह गई । सख्या में कमी का कारण यह था कि कुछ राज्यों में बमजोर बैंकों को दूसरों से मिला दिया था । परन्तु ऐसा करने से न तो सदस्यों की सख्या में कमी हुई, न कार्यशील पूजी में और न दिये गये ऋण में । १९५५-५६ में इनकी सदस्यता २,९९५,५५ थी जिनमें १४४००६ व्यक्ति तथा १५५५४९ समितियाँ थी । इनकी

भारतीय अर्थशास्त्र

सहकारी आन्दोलन की प्रगति (१९५६-५७)

कुल समितियाँ	राज्य वंश	केन्द्रीय वंश व यूनियन	प्रारम्भित ग्राम समितियाँ	प्रारम्भित ग्राम नगर साक्षर समितियाँ	प्रारम्भिक नगर कृषि साक्षर समितियाँ	प्रारम्भिक नगर कृषि नगर साक्षर समितियाँ
संख्या	२४४,७९६	४५१	१६१,५१०	३१६०५	१०१५०	२८५१६
सदस्यों की संख्या	१,६३,७३,३४६	३,१०,५५१	६१,१६,८४६	२७,५७,६११	३२,३८,७२७	३१,५६,१५३
कार्यशील पूँजी	५६७,९७ लाख रु०	१,१०,२६ लाख रु०	६८३० लाख रु०	NA	NA	NA
प्रारम्भिक समितियों द्वारा दिये गये ऋण	१७३१६ करोड़ रु०	१००८० करोड़ रु०	६७३३ करोड़ रु०	NA	८२०७ करोड़ रु०	NA
साध	८५८३८ करोड़ रु०	१५५२६ लाख रु०	१८६,८० लाख रु०	७७६८ लाख रु०	१८८,२७ लाख रु०	६५८५ लाख रु०

NA = Not Available

कामशील पूँजी ₹२६७ करोड़ ₹० थी जिसमें से १५१५ करोड़ अर्थात् १६४ प्रतिशत अपना धन, ₹५७१ करोड़ ₹० अर्थात् ६०१ प्रतिशत डिपोजिट था। इन्होंने ७६८३ करोड़ के ऋण दिये जिनमें से ७०४० करोड़ समितियों तथा बैंकों को तथा ₹४४ करोड़ ₹० व्यक्तियों को दिये। १९५६-५७ में इनकी सख्या और भी घट गई। अब इन बैंकों की सख्या केवल ४५१ हो गई तथा उनके सदस्यों की संख्या ३,१०,५५५ हो गई। इनकी कार्य शील पूँजी बढ़कर ११०२६ करोड़ ₹० हो गई। एक वर्ष में इन्होंने १००८० करोड़ ₹० के ऋण दिये। इनमें से जून १९५७ ई० के अन्त तक व्यक्तियों को ३८६ करोड़ ₹० देने थे तथा बैंकों और समितियों को ६८०४ करोड़ ₹०। ऋण चुकाने की अवधि तो पार हो गये ऋणों का प्रतिशत व्यक्तियों के लिये २१३ तथा बैंकों तथा समितियों के लिये १२५ था। इन बैंकों ने १९५६-५७ के अन्त में २९०५ करोड़ रुपये सरकारी तथा दूसरी धरोहर में लगा रखे थे।

केन्द्रीय बैंक न केवल साख वाले ही होते हैं वरन् गैर साख वाले भी होते थे। उनकी सख्या तथा सदस्यता नीचे दी गई है।

केन्द्रीय गैर-साख समितियाँ

समितियों के प्रकार	सख्या	सदस्यता	
		व्यक्ति	समितियाँ
बिक्री यूनियन तथा सस्बाये	२३३६	१६,६६,६७२	४०,८३४
थोकस्टोर तथा पूर्ति यूनियन	१६६	२८,५८३	१८,८१२
औद्योगिक यूनियन	११२	११,६१४	४६५७
ग्रह समितियाँ	२	—	१४०
दुग्ध यूनियन	६९	६७२०	१३०८
अन्य	२३२	३१९८६	८२७३

केन्द्रीय बैंकों ने कुछ गैरसरकारी साख सम्बन्धी काम, जैसे अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन को सहायता, उपभोक्ताओं के लिये उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध आदि किया है। परन्तु सभी स्थानों पर इनकी प्रगति समान रूप से नहीं हुई है। मद्रास, बम्बई तथा पंजाब आदि में इन बैंकों ने खूब प्रगति की है। परन्तु ब्रह्मपुत्र में इन्होंने कोई विकास प्रगति नहीं की और बिहार में तो इनकी स्थिति बहुत शोचनीय है।

राज्य सहकारी बैंक (State co operative Banks)—राज्य सहकारी बैंक भारतीय सहकारी आन्दोलन का एक प्रमुख अङ्ग है। मैकलेगन समिति ने उनकी स्थापना पर बहुत जोर दिया था और तब से प्रायः सभी राज्यों में ये बैंक स्थापित हो चुके हैं। ये बैंक केन्द्रीय बैंकों तथा वही कही समितियों को भी ऋण देते हैं। यदि ये बैंक स्थापित न होते तो केन्द्रीय बैंकों को कठिनाई का सामना करना

पड़ता क्योंकि व्यापारिक बैंक उनको ऋण देना नहीं चाहते। परन्तु व्यापारिक बैंक राज्य सहकारी बैंको को बिना किसी हिष्क के ऋण दे देते हैं। इस प्रकार ये बैंक भारतीय मुद्रा बाजार तथा सहकारी समितियों के बीच में सम्बन्ध स्थापित करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये बैंक रिजर्व बैंक के कृपि साख विभाग से भी ऋण ले सकते हैं। इन बैंको के सदस्य या तो केन्द्रीय बैंक होते हैं या व्यक्ति होते हैं। १९४०-४१ में इन बैंको की सख्या ८ थी उनके सदस्य ४५३७ व्यक्ति थे। तथा १८,८३८ समितियाँ थी, उनकी कार्यशील पूँजी १३७९ करोड़ थी। परन्तु १९५६-५७ में उनकी सख्या २३ थी। इनके सदस्य ३३४४० थे तथा उन्होंने १२३७१ करोड़ रुपये का ऋण दिया था। उस वर्ष उनकी कार्यशील पूँजी ७९५४ करोड़ रुपये थी। इनमें केवल ८७९ करोड़ अपना धन था तथा डिपोजिट ३८३९ करोड़ रुपये थे।

Q 43 Discuss the steps taken in recent years to re-organise rural credit co-operation in Uttar Pradesh.

प्रश्न २३—उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण साख सहकारिता को पुनः संगठित करने के लिये क्या किया गया है ?

१९४६ ई० तक उत्तर प्रदेश में सहकारी आन्दोलन केवल साख आन्दोलन था। परन्तु १९४७ ई० से इसमें हर प्रकार से उन्नति करने की बात सोची गयी। इसके प्लस्वरूप यह प्रयत्न किया गया कि सहकारी आन्दोलन को प्रत्येक आर्थिक समस्या को मुलजाने के काम में लाया जाय। इसी कारण ग्राम समितियों ने बहु-उद्देश्य समितियों का रूप धारण कर लिया और राज्य में बहुत सी गैर-साख सहकारी समितियाँ स्थापित हो गईं। सहकारी समितियों के आजकल के ढाँचे का रूप इस प्रकार है—सबसे नीचे एक ग्राम समिति होती है। उसके ऊपर १५-२० गावों की एक ब्लॉक यूनिट होती है। जिला-स्तर पर एक जिला संगठन होता है तथा राज्य-स्तर पर एक राज्य संगठन होता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः इस बात पर ध्यान दिया गया कि सहकारी समितियों को उन्नत किया जाय। इसी कारण योजना में बहु उद्देश्य सहकारी समितियों, सहकारी बीज गोदामों, सहकारी खेती-समितियों तथा सहकारी दुग्ध यूनिटों की स्थापना की योजना बनाई गई।

द्वितीय योजनाकाल के लिये जो योजना बनाई गई है वह अखिल भारतीय साख सर्वे रिपोर्ट के सुझावों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अब राज्य में बड़ा-बड़ी समितियाँ बनाई जाती हैं। अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि साख समिति को फसल की बिक्री का कार्य भी सौंपा जाय। द्वितीय योजना काल में १५०० बड़ी-बड़ी समितियाँ बनाई जाने वाली हैं जिनमें से १९५६-५७ तक ३०० स्थापित की

जा चुकी हैं। इन समितियों का कार्य-क्षेत्र एक गाँव से बढ़ाकर कई गाँव बना दिया गया है जिससे कि आर्थिक दृष्टि से वे मजबूत रहे। भविष्य में २६ जिलों की ४० मण्डियों के आस पास जो समितियाँ ऋण देने का कार्य करेंगी उनकी एक शर्त यह होगी कि ऋण लेने वाले सदस्य अपनी फसल को बिनी समिति के द्वारा करावें।

राज्य में ४४००० कृषि साख समितियाँ हैं जिनकी सदस्यता १४ लाख है तथा जिनकी अपनी पूँजी ४ करोड़ तथा कार्यशील पूँजी ८४६ करोड़ रुपये है। २६५५-५६ में इन समितियों ने ५५८ करोड़ के ऋण वाटे। ऐसी आशा की जाती है कि योजना के अन्त तक ऋण की मात्रा छ गुनी हो जायगी। ये समितियाँ अन्तिम ऋण लेने वालों से $\frac{८}{९}$ प्रतिशत व्याज लेते हैं। राज्य के ११ केन्द्रीय सरकारी बैंक समितियों से $\frac{६}{९}$ प्रतिशत व्याज लेते हैं। इन केन्द्रीय बैंकों के वर्तमान डिपोजिट व्यक्तियों से २६३ करोड़ रुपये तथा समितियों से १ करोड़ २० हैं।

रिजर्व बैंक की (Committee of Direction) की सिफारिश के अनुसार उत्तर प्रदेश ने निश्चय किया है कि वह State Agricultural Credit (Relief and Guarantee) Fund तथा State Co-operative Development Fund स्थापित करेगी। इन दोनों के लिये धन वार्षिक बजट में प्रवृत्त करके तथा विभिन्न सहकारी साख समितियों में सरकार द्वारा लगाए गये धन पर प्राप्त लाभों से एकत्र किया जायगा। इस प्रकार इस राज्य में सहकारी साख आन्दोलन में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है।

Q 44 In what ways will a multi-purpose society, popularly known 'the village bank, prove more successful than the common type of rural credit society is improving Indian 'village economy' ?

प्रश्न ४४—किस प्रकार एक बहुउद्देश्य समिति जिसको साधारणतया 'गाँव के बैंक' के नाम से जाना जाता है भारतीय ग्राम अर्थ-व्यवस्था को सुधारने में एक साधारण ग्राम साख समिति से अधिक सफल सिद्ध होगी ?

अभी कुछ वर्षों से हमारे देश में एक चर्चा है कि सहकारी समितियाँ एक उद्देश्य होने चाहियें अथवा बहुउद्देश्य। ऐसा प्रसङ्ग इसलिए आया क्योंकि हमारे देश में अभी तक एक उद्देश्य समितियाँ हैं जिनसे किसान की आर्थिक उन्नति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इसी कारण लोग अब यह सोचने लगे हैं कि ऐसा क्यों है। इसका उत्तर उन्हें सहज ही मिल सकता है। किसान साख समितियों से ऋण लेकर उसको या तो खेती के काम में लाता ही नहीं और यदि लाना भी है

तो जो कुछ वह उत्पन्न करता है उसको गाव के बनिये के हाथ बेचने के कारण कोई लाभ नहीं उठा सकता । साख समितियों के होते हुये भी आज किसान का गाव के बनिये के यहा बहुत से कामों के लिये जाना पड़ता है, जैसे वह उससे बीज खरीदता है, उपभोग कार्यों के लिये ऋण लेता है, खेत पर कोई स्थायी उन्नति करनी हो तो उसके लिये उससे ऋण लेता है और उसको अपनी फसल बेचता है । इसी कारण यद्यपि साख समितियाँ इस देश में पिछले ५५ वर्षों से काम कर रही हैं पर वे किसान की आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन न कर सकी । यही कारण है कि इस देश में अब यह विचारधारा बड़े जोरो से घर कर रही है कि सहकारी समितियाँ एक उद्देश्य न होकर बहु-उद्देश्य होनी चाहियें । रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग का मत है कि यदि भारत में सहकारी आन्दोलन को नष्ट-भ्रष्ट होने से बचाता है तो गाव के सहकारी बैंक की सब आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बनाना चाहिये । १९३६ ई० की एक सभा में सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों ने एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें उन्होंने इस बात की सिफारिश की थी कि देश में बहु-उद्देश्य सहकारी समितियाँ खोली जानी चाहियें । मद्रास सहकारी समिति १९४० ने भी बहु-उद्देश्य समितियों के पक्ष अपनी अनुमति दी थी । इसी प्रकार की राय देश के बहुत से लोग रखते हैं । ससार के कुछ और देश भी जैसे जर्मनी, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन आदि भी बहु-उद्देश्य समितियों के ही पक्ष में हैं ।

बहु-उद्देश्य समितियों के लाभ

एक उद्देश्य समितियाँ डेनमार्क को छोड़कर कहीं और अधिक फलान नहीं हुई हैं । हमारे देश में भी इस प्रकार की समितियाँ असफल ही सिद्ध हुई हैं । इसका कारण यह है कि यहाँ पर अभी तक साख समितियाँ ही चालू की गई हैं । इन साख समितियों से किसान के जीवन की केवल ऋण की ही आवश्यकता पूरी होती है । शेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उसे महाजन के पास ही जाना पड़ता है । इस कारण यह महाजन के चंगुल से नहीं निकल सकता । इसलिये यदि हम किसान की आर्थिक स्थिति उन्नत करना चाहते हैं तो हमको उसकी सभी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना पड़ेगा । दूसरे शब्दों में, हमको उसके ऋण देने के अतिरिक्त बीज, खाद, बेल, हल आदि का भी प्रबन्ध करना पड़ेगा । जब उसकी फसल तैयार हो जाय तो उसके ठीक समय, ठीक स्थान तथा ठीक मूल्य पर बेचने का भी प्रबन्ध करना पड़ेगा । उसकी उपभोग की वस्तुओं को भी उसे उचित मूल्य पर देना पड़ेगा । यदि उसके पास खेती से कुछ समय बचता है तो उस समय का सदुपयोग कराने के लिये उसे कुटीर तथा छोटे धन्धों में भी लगाना पड़ेगा । इस प्रकार हमको उसके जीवन की हर आवश्यकता की ओर ध्यान देना होगा । ऐसा करने के लिये या तो एक गाव में बहुत सी बहु-उद्देश्य समितियाँ खोली जा सकती हैं या एक बहु-उद्देश्य समिति खोली जा सकती है । हमारे देश में अभी योग्य प्रबन्ध करने वालों की बहुत कमी है । इसी कारण यह हो सकता है कि गाव में यदि बहुत सी

एक उद्देश्य समितियाँ खोली जायें तो उनका प्रबन्ध करने के लिये अच्छे व्यक्ति न मिलें। दूसरे, अभी तक किसान अपनी सभी आवश्यकताओं को एक महाजन से पूरी कर लेता था। इसलिये यदि उसे बहुत सी समितियों का सदस्य होना पड़ा तो वह उसको पसन्द न करेगा। तीसरे, यदि हम यह चाहते हैं कि किसान समिति के लिये ऋण का सदुपयोग करे तो हमको चाहिये कि हम उसको बीज, खाद, हल, बैल आदि सभी चीजें उचित दामों पर दें और उसकी फसल को भी सहकारी समिति द्वारा ही बेचने का प्रबन्ध करें। १९४६ ई० की सहकारी योजना समिति की भी यही राय है।

यदि किसान के हित के लिये गाव में एक बहु-उद्देश्य समिति चालू हो जायगी तो किसान उसमें खूब दिलचस्पी लेगा। वह उसकी उन्नति के लिये भी प्रयत्न करेगा। इसके कारण किसानों के सम्बन्ध एक दूसरे से बहुत अच्छे होने की सम्भावना है। बहु-उद्देश्य समिति के चलाने के खर्च में भी बहुत बचती हो जायगी। इस समिति के द्वारा किसानों में शिक्षा का प्रचार करना भी सहज हो जायगा।

जहाँ बहु-उद्देश्य समितियों से इतना लाभ होने की आशा है वहाँ उनसे कुछ हानि भी हो सकती है, जैसे बहुत से कार्य एक साथ करने से यदि एक कार्य में भी हानि हो जाय तो उससे सभी कार्यों को धक्का लगेगा। दूसरे यह आशंका है कि इतने सब उद्देश्य रखने वाली समिति को चलाने के लिये योग्य व्यक्ति न मिल सकें। तीसरे अपरिमित दायित्व के कारण इन समितियों को ऋण लेने में कठिनाई होगी और उनके सदस्य भी समिति के उत्थान में कम रुचि रखेंगे।

परन्तु इन सब बातों के होते हुये भी आज देश में अधिकतर लोगों की यह राय है कि बहु-उद्देश्य समितियाँ ही चालू करनी चाहियें। ऐसा विचार इसलिये है कि दूसरे देशों में जहाँ कहीं इस प्रकार की समितियाँ चालू की गई हैं वहाँ उनमें बहुत लाभ पहुँचते हैं।

हमारे देश में मद्रास, बम्बई तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में इन समितियों को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। १९४७-४८ में भारतवर्ष में १८१६२ ऐसी समितियाँ थी। उनके सदस्यों की संख्या ५७७२८६ तथा उनकी कार्यशील पूँजी ₹७८८८८ लाख रुपये थी। इन समितियों की अपेक्षा अधिक प्रगति उत्तर प्रदेश में हुई है जहाँ पर १९४८ में २२७८६ ऐसी समितियाँ थी। उनके सदस्यों की संख्या ७३ लाख तथा उनकी कार्यशील पूँजी ₹८८ करोड़ रुपये थी सारे देश में १९४८-५० में २०,५२५ समितियाँ थीं तथा उनके सदस्यों की संख्या १५ करोड़ थी।

एक बात यहाँ पर बताने योग्य है और यह है कि अभी तक बहु-उद्देश्य समितियाँ केवल आवश्यक वस्तुओं के वितरण का ही कार्य करती हैं। इतने कार्य में कोई अधिक लाभ नहीं होगा। इस कारण यह आवश्यक है कि इन समितियों को

अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहिये। यदि वे ऐसा न करेगी तो किसान की आर्थिक स्थिति में कोई विशेष उन्नति न होगी।

Q. 45. What are the achievements and defects of the co-operative movement in India? How will you remove the defects?

प्रश्न ४५—भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन के लाभ व दोष क्या हैं? आप उन दोषों को कैसे दूर करेंगे?

सहकारी आन्दोलन के लाभ—

उत्तर—यद्यपि हमारे देश में सहकारी आन्दोलन ने अभी तक बहुत कम प्रगति की है तो भी इससे निम्नलिखित लाभ हुये हैं—

(१) ब्याज की दर होना—सहकारी समितियों के स्थापित होने के पूर्व गाँव के महाजन किसानों तथा दस्तकारी से मनमाना ब्याज लिया करते थे परन्तु इन समितियों के स्थापित होने से उनके ब्याज की दर बहुत गिर गई है।

(२) लोगों में मितव्ययिता की आदत का फैलना—इन समितियों के स्थापित होने से सहरो और गाँवों में लोगों में बचत करने की आदत बढ़ रही है। प्रम प्रकार जो धन पहले उपयोग में नहीं आता था वह अब बहुत से उत्पादक कामों में आता है।

(३) खेती को लाभ—सहकारी समितियों के द्वारा किसानों में अच्छे बीज, खाद पशु, औजार आदि का प्रचार बढ़ रहा है।

सहकारी समितियों द्वारा गाँवों में सफाई का प्रचार बढ़ता जा रहा है। जो खाद पहले खुले तौर पर गाँव में एकत्र की जाती थी वह अब गड्डों में भर कर रखी जाती है। इससे गाँव में सफाई का स्तर ही ऊँचा नहीं होता बरन् अच्छी खाद भी नैयार हो जाती है। इसके अतिरिक्त इन समितियों द्वारा पशुओं के रोगों का इलाज भी किया जाता है।

गैर-साख-कृषि समितियों से भी खेती को बहुत लाभ पहुँच रहा है। इस प्रकार की समितियों में बम्बई की रुई समितियाँ, बङ्गाल की सिचाई तथा दूध समितियाँ मध्य प्रदेश की दूध तथा बीज समितियाँ, पंजाब की चकबन्दी समितियाँ उत्तर प्रदेश तथा बिहार की गन्ना समितियाँ, बम्बई की गुड समितियाँ मुख्य हैं।

(४) शिक्षात्मक लाभ—अच्छी समितियों में सदस्य बड़ी दिलचस्पी से काम करते हैं। वे समिति के कार्य में खूब लगन से भाग लेते हैं। वे ध्यानपूर्वक यह देखते हैं कि सदस्य किस प्रकार ऋण का उपभोग करते हैं। इस प्रकार साधारण सदस्यों को अपने धन के प्रयोग तथा सदस्यों के ऊपर नियन्त्रण करने की शिक्षा मिलनी है और प्रबन्ध सदस्यों को हिसाब रखने की शिक्षा मिलती है। इस प्रकार इन समितियों को ग्रामीण वित्त व्यवस्था का प्राश्मरी स्कूल समझना चाहिये।

(५) नैतिक तथा सामाजिक लाभ—आर्थिक तथा शिक्षात्मक लाभ से भी अधिक इनका नैतिक तथा सामाजिक लाभ है। सहकारी समितियों के कारण गाँव के लोगों के झगड़े बहुत कुछ समाप्त हो गए हैं तथा उनमें प्रेम बढ़ना जा रहा है। वे अब ये जान गये हैं मिलजुल कर सामान्य लाभ के लिये कंभे कायं किया जाय। सदस्यों में प्रेम बढ़ जाने से उनकी मुकदमेबाजी समाप्त हो रही है। इससे उनकी फिजूल खर्ची, जुआ खेलने, शराब पीने आदि की आदतें समाप्त होती जा रही हैं। इनके स्थान पर उनमें आत्म विश्वास, पुरुषार्थ, उचित व्यवहार, मितव्ययिता, स्वयं सहायता तथा आपसी सहायता की आदत बढ़ती जा रही है।

इस प्रकार सहकारी समितियों ने सदस्यों की निर्धनता दूर करने, व्याज की दर कम करने, चकबन्दी करने, मितव्ययिता बढ़ाने, आवश्यक उपभोग की सामग्री का मूल्य कम करने तथा फिजूलखर्ची कम करने में बड़ी सहायता की है।

सहकारी आन्दोलन के दोष

(Defects in the Co-operative Movement)

जिस समय सहकारी साख आन्दोलन इस देश में चालू किया गया था उस समय इससे बड़ी आशाएँ बांधी गई थी। यह आशा की जाती थी कि इसके द्वारा किसानों में मितव्ययिता की आदत पड़ जायेगी और वे अपने पैरो पर खड़ा होना सीख जायेंगे। इसके अतिरिक्त यह भी आशा की जाती थी कि इसके द्वारा किसानों के ऋण की समस्या भी सुलझ जायेगी। पर खेद का विषय है कि पिछले ५५ वर्षों में इस आन्दोलन से उतना लाभ नहीं हुआ जितनी कि इससे आशा की जाती थी। १९१६-१७ में केवल २५ प्रतिशत लोग इस आन्दोलन से लाभ उठा रहे थे। इसका कारण यह है कि इस आन्दोलन में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं जिनके कारण उसकी अधिक उन्नति नहीं हो सकी।

(१) सरकारी हस्तक्षेप—इस आन्दोलन का पहला दोष यह है कि इसके ऊपर सरकारी नियन्त्रण अभी तक भी इतना अधिक है कि सहकारी समिति के सदस्य समितियों को सरकारी बैंक समझते हैं। यह भावना सहकारिता के लिये बहुत घातक है क्योंकि इसके कारण सदस्य समितियों की उन्नति के लिये उतना प्रयत्न नहीं करते जितना कि उन्हें करना चाहिए। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को इस देश में इतनी शक्ति है कि सहकारी समिति के सदस्य स्वयं इच्छा से कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। इस कारण उनकी स्वेच्छा से कार्य करने की भावना नष्ट हो जाती है और समितियों की उन्नति उन्नति नहीं होने पाती जितनी कि होनी चाहिये।

सरकारी हस्तक्षेप की निन्दा करते हुए श्री एम डार्लिङ्ग ने अपनी एक हाल ही रिपोर्ट में कहा है, उच्चतम स्तर पर इसके पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है परन्तु प्रारम्भिक स्तर पर, जहाँ तक मितव्ययिता तथा साख समिति का सम्बन्ध है, प्रत्येक ठजुर्बेकार सहकारी इसकी चिन्ता की दृष्टि से देखेगा, क्योंकि

इसके कारण केवल स्वतन्त्रता तथा आत्म-विश्वास को शक्ति पहुँचाने की सम्भावना है जो कि आधार पर आन्दोलन की शक्ति के लिये आवश्यक है ।”

यह नहीं, राष्ट्रीय विकास काउन्सिल की स्टैंडिंग कमेटी की छोटी बैठक में प० नेहरू ने भी इस सरकारी हस्तक्षेप की निन्दा करते हुए कहा था, “ मैं सरकारीकरण के सारे विचार से बहुत अधिक परेशान हूँ । अपन छोटे-छोटे कार्य करने वालों की सब ओर बढ़ाने का मारा विचार मूल रूप से खराब, शरारत से भरा हुआ तथा गलत है, और जो बीज मुझे डराती है वह डझ है जिससे कि यह सब जगह ग्राम पंचायतों तथा सहकारी समितियों में फैलता है ।” इसके पश्चात् प० नेहरू ने कहा, “मुझे सरकारी अक्सरो से कोई विरोध नहीं है । यदि हम समाजवाद की ओर अग्रसर होंगे तो हमको अधिक सरकारी कार्य करने वालों की आवश्यकता पड़ेगी । यह एक भिन्न बात है, परन्तु इसका भी जनसाधारण के सहयोग से सन्तुलन होगा चाहिये, लोगों में अपनी जिम्मेदारी स्वयं अपन बन्धों पर लेने की प्रवृत्ति होनी चाहिए ।”

(२) साख पर अत्यधिक जोर—इस आन्दोलन का दूसरा दोष यह है कि अभी तक इस आन्दोलन में केवल किसानों को ऋण देने की ओर ही ध्यान दिया गया है । इसी कारण १९५५-५६ में कुल सहकारी साख समितियों की ७० प्रतिशत साख समितियाँ थी । किसान ऋण लेकर कभी-कभी उसका दुरुपयोग करता है । वह उसको खेती के काम में नहीं लगाता वरन् अपने निजी कामों में खर्च कर देता है । दूसरे यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि ऋण दे देने से ही किसान के जीवन की सब समस्याएँ हल नहीं हो जाती । जब तक सहकारी समितियाँ अपने हाथ में किसान के जीवन की सब समस्याएँ नहीं लेंगी तब तक उनको इन समितियों से कोई विशेष लाभ नहीं होगा । इण्डियन कोऑपरेटिव रिव्यू के सम्पादक श्री रामदास पतवू ने इसी सम्बन्ध में कहा था, “हमारी आशाओं के पूर्ण न होने के कारण यह नहीं है कि सहकारी साख आन्दोलन इस कार्य के लिये उपयुक्त नहीं है वरन् यह है कि हमने सहकारी साख के कार्य को ऐसे कार्यों से नहीं मिलाया जिनसे कि किसान की आय तथा क्रय शक्ति बढ़े और इस प्रकार वह इस योग्य हो जाए कि ऋण लेने के बदले कुछ बचा सके ।”

(३) सदस्यों की निरक्षरता—इस आन्दोलन का तीसरा दोष यह है कि सहकारी समितियों के सदस्य अशिक्षित होते हैं । वे यह नहीं जानते कि सहकारिता किसे कहते हैं और उसका आधारभूत सिद्धान्त क्या है । जब तक कि सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तों को ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे तब तक वे इस कार्य की प्रगति में कोई विशेष भाग नहीं ले सकते ।

(४) हिसाब की उचित जांच न होना—इस आन्दोलन का चौथा दोष यह है कि सहकारिता साख समितियों के हिसाब की जांच पड़ताल ठीक प्रकार से नहीं होती । इसी प्रकार कार्यकर्त्ताओं द्वारा गबन करने की बहुत आशंका रहती है । इसी

कारण हिसाब अधूरा भी पड़ा रहता है। यही कारण है कि समिति की आर्थिक स्थिति का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हिसाब को जाँच पड़ताल ठीक प्रकार न हो सकने के कारण आडिटरों की कमी है।

श्री एम० डालिङ्ग ने इस विषय में लिखा है कि दो राज्यों में मैंने आडिट बहुत बुरी तरह से अपूर्ण पाया। राजस्थान में ७७६ समितियों की दो वर्ष से अधिक से जाँच नहीं हुई, बिहार में कुछ समितियों की पांच वर्ष से जाँच नहीं हुई। वार्षिक आडिट के महत्व पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है, उमका कभी भी किसी ने विरोध नहीं किया।

(५) अपर्याप्त साधन—इस आन्दोलन का पाचवाँ दोष यह है कि सदस्यों की आवश्यकता से कम धन मिलता है और वह भी समय पर नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त ऋण केवल खेती के कामों के लिये मिलता है। इन्हीं सब बातों की वजह से किसान को महाजन के पास जाकर ऋण लेना पड़ता है। १९५५-५६ की सहकारिता पर दी गई रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि कृषि साख समितियों की औसत हिस्सा पूँजी १०१५ रु० तथा औसत कार्यशील पूँजी ४९४६ रु० है तथा इन समितियों द्वारा सदस्यों को दिए गए ऋण का औसत केवल ६० रु० है। इन आंकड़ों से हम स्वयं अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि समितियाँ अपने इन अपर्याप्त साधनों से अपने सदस्यों की कितनी सहायता कर सकती हैं तथा एक सदस्य जिसको साल भर में केवल ६४ रु० का ऋण मिलता है वह इससे क्या कर सकता है। यह बात ध्यान रखनी चाहिये कि ६४ रु० का ऋण केवल एक औसत मात्र है। इसका अर्थ यह हुआ कि ऋण बहुत ही कम लोगों को मिलता है तथा जिनको भी वह मिलता है वह मात्रा से कम है। यद्यपि दूसरी योजना में साख की पूर्ति को ४३ करोड़ रु० से बढ़ा कर २२५ करोड़ रु० करने की योजना है तो भी यह धन किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अपर्याप्त है।

(६) शेषपूर्ण व्यवस्था—इस आन्दोलन का छठा दोष यह है कि सहकारी समितियों का नियन्त्रण अयोग्य व्यक्तियों के हाथ में है। इस कारण समिति के अपसर ठीक प्रकार से हिसाब तैयार नहीं कर सकते और न ही वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि कौन-सा ऋण अवधि को पार कर चुका है और कौन-सा कम समय के लिए दिया गया है। यही कारण है कि द्वितीय महायुद्ध से पहले बहुत से राज्यों में सहकारी समितियों का बहुत-सा ऋण बढ़ा खात हो गया था और बहुत-सा ऋण की अवधि को पार कर गया था। यही कारण था कि इन राज्यों में बहुत-सी सहकारी समितियाँ फेल हो गईं और जो कुछ बचो उनकी अवस्था बहुत खराब थी। यदि द्वितीय महायुद्ध न छिड़ता तो सहकारी आन्दोलन इन राज्यों में प्रायः समाप्त हो जाता। परन्तु एम० डालिङ्ग की रिपोर्ट से पता चलता है कि १९५५-५६ में बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तथा पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में सहकारी आन्दोलन की स्थिति बड़ी खराब थी। इन राज्यों में केवल ८ प्रतिशत

समितियाँ ही A तथा B श्रेणियों में रखी जा सकती थीं। १९५३-५४ में उड़ीसा तथा राजस्थान में भी यही स्थिति थी तथा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा आसाम में तो ३० प्रतिशत से अधिक समितियाँ D और E श्रेणियों में रखी जा सकती थीं। पश्चिमी बंगाल में तो ४३ प्रतिशत D और E श्रेणी की समितियाँ थीं। इस प्रकार ११६०० समितियों में से लगभग ५००० समितियाँ समाप्त होने के लगभग थीं।

(७) आर्थिक व्यय—इस आन्दोलन का सातवाँ दोष यह है कि समितियों का खर्च बहुत है। इसी कारण समितियों के पास बहुत कम लाभ बचता है और उनको ऊँचे ब्याज पर ऋण देना पड़ता है। १९५४-५५ में ६ बड़े राज्यों में से ५ में कृषि समितियाँ २५% हानि पर कार्य कर रही थीं।

(८) कम कार्यशील पूँजी—आन्दोलन का आठवाँ दोष यह है कि १९५५-५६ में समितियों के पास कुल कार्यशील पूँजी का लगभग ३७ प्रतिशत स्वयं की पूँजी है। १२ बड़े-बड़े राज्यों के सदस्यों में डिपोजिट कुल कार्यशील पूँजी के केवल ६ प्रतिशत थे। इसका कारण यह है कि समिति के सदस्यों में धन बचाकर रखने की आदत नहीं होती। इसी कारण उनको बाहर से ऋण लेना पड़ता है। ऋण पर लिए हुये धन को ऋण के रूप में देने के कारण समितियों से ऋण लेने से कोई विशेष लाभ नहीं देखते।

१९५५-५६ की रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये समितियाँ सदस्यों में मितव्ययिता की आदत डालने में बिल्कुल असफल रही हैं। श्री डालिंग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि “मैंने कहीं भी डिपोजिट को प्राप्त करने का ढंगभूत प्रयत्न नहीं देखा। फिर भी रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग के मुख्य अधिकारी ने कहा है कि मितव्ययिता तथा बचत को प्रोत्साहन देना “कृषि साख समितियों का आधारभूत ध्येय है।” यह साधारणतः कहा जाता है कि भारत के किसान इतने निर्धन हैं कि कुछ बचा नहीं सकते। यह बात बहु-सूया के लिये ठीक हो सकती है, परन्तु समृद्धिशाली सब क्षेत्रों में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं और कम से कम इस श्रेणी के लोगों तक पहुँच करनी चाहिए। यह भी वास्तव में ठीक है कि सदस्यों की बचत डिपोजिट तक ही सीमित नहीं होती। समितियों की स्वयं की पूँजी को ध्यान में रखना चाहिये। परन्तु यहाँ भी बाकी धन की ६१ प्रतिशत से घट कर ४९ प्रतिशत तक गिरावट हो गई है।”

(९) अवधि-पार ऋण की अधिकता (Overdues)—भारत में सहकारी समितियों के कार्य करने के दृग् में यह दोष भी है कि उनके चुकाये जाने वाले ऋणों में ऐसे ऋणों की मात्रा बहुत अधिक है जो ऋण चुकाने की अवधि को पार कर चुके हैं। श्री डालिंग की रिपोर्ट से पता चलता है कि १९५४-५५ में राज्य ने सहकारी साख समितियों को कुल ऋण का २९ प्रतिशत दिया था परन्तु उसमें से ५२० करोड़ अर्थात् ३८ प्रतिशत ऋण अवधि-पार ऋण था। डालिंग साहब ने आगे कहा है कि

४ वर्षों में इस प्रकार के ऋण का प्रतिशत दुगुना हो गया है तब तबारे भारतवर्ष में इस प्रकार के अवधि पार ऋण की मात्रा बढ़ती जा रही है। श्री डालिंग ने यह भी बताया है कि १९४६-५० से १९५४-५५ के ५ वर्षों में जहाँ सहकारी समितियों द्वारा दिये गए ऋण ६७ प्रतिशत बढ़ गये हैं। वही चुकाये न जाने वाले ऋण की मात्रा भी ६४ प्रतिशत बढ़ गई है और उसमें अवधि-पार ऋण की मात्रा भी बढ़ती जा रही है।

(१०) प्रति समिति सदस्यों की कम संख्या—भारत में सहकारी समितियों का आकार (Size) इतना छोटा है कि उनको आर्थिक दृष्टि से लाभ पर नहीं चलाया जा सकता। १९५५-५६ में कम से कम छ राज्यों में सदस्यता औसत ३४ में भी कम था तथा आसाम में यह औसत १६ था। इसके विपरीत आंध्र, बिहार तथा मद्रास को औसत ६० से अधिक था।

द्वितीय योजनाकाल में जो नई-नई समितियाँ बनाई जा रही हैं उनमें सदस्यों की संख्या ५०० के लगभग रखने का निश्चय किया गया है। परन्तु श्री डालिङ्ग का मत है कि ५०० सदस्य बहुत अधिक हैं। उन्होंने बताया है कि पश्चिमी जर्मनी, फ्रान्स, स्वीटजरलैंड आदि में सदस्यों की संख्या १००-२०० से अधिक नहीं है।

(११) देख-भाल में दोष (Defect in supervision)—श्री डालिङ्ग की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में रजिस्ट्रार डिप्टी रजिस्ट्रार आदि पदाधिकारी भी सहकारिता की प्रशिक्षा प्राप्त नहीं करते। ऐसे लोगों के द्वारा जो सहकारिता की भावना से अनभिज्ञ हैं कैसे सहकारिता आन्दोलन की प्रगति हो सकती है।

(१) पदाधिकारियों के जल्दी-जल्दी तबादले—भारत में सहकारी आन्दोलन की उन्नति में पदाधिकारियों के जल्दी-जल्दी तबादले भी बाधक हैं। श्री डालिङ्ग ने बताया है कि पंजाब में जौलाई १९५१ से ५ रजिस्ट्रार बदले जा चुके हैं। राजस्थान में २½ वर्षों में ३ रजिस्ट्रार तथा केरल में ५ वर्षों में ४ रजिस्ट्रार बदले जा चुके हैं। श्री डालिङ्ग ने कहा है कि निरन्तर तबादलों के कारण नीति तथा कार्य में निरन्तरता नहीं आ सकती।

दोषों को दूर करने के उपाय

सहकारी आन्दोलन पर हमारा देश तभी सफल हो सकता है जबकि इस आन्दोलन के दोषों को दूर किया जाए। इस उपाय की मुख्य आवश्यकता यह है कि समितियों के सदस्यों को ठीक प्रकार से सहकारिता की शिक्षा दी जाये और उनको वह सिद्धान्त ठीक प्रकार से बताया जाये जिस पर यह आन्दोलन खड़ा है। यह कार्य सरकार तथा सहकारी विभागों द्वारा हो सकता है। इसमें विश्वविद्यालयों से भी बहुत सहायता ली जा सकती है। यदि समितियों के सदस्य सहकारी आन्दोलन की असली विचारधारा को समझ गये तो फिर वे इन समितियों के उन्नत करने में अविकाशिक हाथ बँटाये और अपनी आम में से कुछ न कुछ बनाकर समितियों

की आर्थिक स्थिति का भी उन्नत करेंगे। सदस्यों के समिति की ओर अधिक ध्यान देने के कारण अफसरो को गबन आदि करने का कम साहस होगा।

इनके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ने भी इन समितियों को सुधारने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

(१) समितियों को अपने अधिक समय वाल (Long term) ऋणों को ऋण की अवधि-पार (Overdues) किये ऋणों से अलग रखना चाहिये। ऐसा करने से ऋण के चुकाने वालों के विरुद्ध कायबाही की जा सकती है।

(२) समितियों को एक मजबूत स्थायी द्रव्य कोष बनाना चाहिये इससे कारण समितियाँ अपने आपको आपत्ति बाल में बचा सकती हैं।

(३) समितियों को केवल खेती के लिए ही ऋण देना चाहिये। कृषकों को बताना चाहिये कि वे अपनी आय से अधिक खर्च न करें। यह तभी हो सकता है जबकि किसान महाजन से ऋण न लें।

(४) प्रारम्भिक सहकारी नाबाल समितियों को यह प्रयत्न करना चाहिये कि वे किसान की अभी आवश्यकताओं को पूरा करें। दूसरे शब्दों में समितियाँ बहुउद्देश्य हों। १९४५ ई० की सरकारी योजना समिति का भी यह मत था कि सहकारी साख को सहकारी बिजली से सम्बन्धित करना चाहिये। बिना इसके किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती।

इनके अतिरिक्त श्री टॉलिवुड ने अपनी रिपोर्ट में सहकारी आंदोलन की स्थिति को सुधारने के लिये कुछ सुझाव दिये हैं जो निम्नलिखित हैं—

(१) भविष्य में इस बात की आवश्यकता है कि साख की मात्रा को बढ़ाते समय सावधानी से काम लिया जाय।

(२) द्वितीय योजनाकाल में सहकारी आंदोलन को जिस गति से बढ़ाने की योजना है उसको धीमा किया जाय और उन राज्यों में जहाँ वह कमजोर है योजना बिन्दु को प्राप्त करने का समय ५ वर्ष से बढ़ाकर १० वर्ष कर देना चाहिये।

(३) छोटी छोटी समितियों को बड़ा बनाने का प्रयत्न करना चाहिये।

(४) जिन समितियों के पास अपना कोई प्रशिक्षित सचिव नहीं है उनके किसी सदस्य को प्रशिक्षा देकर कार्य करने योग्य बनाना चाहिये।

(५) सहकारी समितियों को सदस्यों में मितव्ययिता की आदत डलवानी चाहिये और उनसे अधिक डिपोजिट प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

(६) आडिट की जिम्मेदारी रजिस्ट्रार की होनी चाहिये।

(७) साख को फसलों से सम्बन्धित करना चाहिये।

अन्त में यह कहना ठीक ही होगा कि हमारे देश में सहकारिता ना भविष्य बहुत उज्ज्वल है। हमारे देश में आज जितनी समस्याएँ मुहूँ बाये खड़ी हैं उनका निदान केवल सहकारी समितियों द्वारा ही हो सकता है। इसी कारण यह आवश्यक

है कि हम सहकारी समितियों की अवस्था को शीघ्र ही सुधारें जिससे कि देश की आर्थिक स्थिति सुधरे ।

Q- 46. What is the present position of co-operative stores movement in India ? What measures would you suggest to make it more Popular ?

प्रश्न ४६—भारतवर्ष में सहकारिता स्टोर आन्दोलन की वर्तमान स्थिति क्या है ? आप इसको लोकप्रिय बनाने के लिये क्या सुझाव देंगे ?

उत्तर—सहकारी स्टोर वह होते हैं जिनको उपभोक्ता मिल-जुल कर इसलिये बनाते हैं जिससे कि इसके द्वारा अपने उपभोग में आने वाली वस्तुयें अधिक मात्रा में खरीद सक तथा इस प्रकार मध्यवर्ती व्यापारियों के शोषण से बच सकें । यह आन्दोलन सबसे पहले राशटेल् (इङ्ग्लैंड) के २८ जुलाई ने चलाया था । प्रारम्भ में केवल मन्खन चीनी, गेहू तथा मोमबत्ती ही बेचना था परन्तु धीरे-धीरे उसने वृद्धि सी उपभोग में आने वाली चीजें रखनी आरम्भ कर दी । इस स्टोर को इङ्ग्लैंड में इसकी सफलता मिली कि धीरे-धीरे वहाँ बहुत से ऐसे स्टोर खुल गये । इङ्ग्लैंड में इसकी लोकप्रियता को देखकर दूसरे देशों में भी यह आन्दोलन फैल गया ।

सरकारी स्टोर आन्दोलन के कुछ मुख्य सिद्धान्त हैं जिनका जान लेना यहाँ आवश्यक है । इस आन्दोलन का पहला सिद्धान्त यह है कि वस्तुयें थोक भावों पर मोल लेकर बाजार भावों पर बेची जाती हैं । इसका दूसरा सिद्धान्त यह है कि वस्तुयें नन्द बेची जाती हैं, उधार नहीं बेची जाती । इसका तीसरा सिद्धान्त यह है कि स्टोर को वर्ष भर जो लाभ होता है वह सदस्यों में उस अनुपात में बाँटा जाता है जिस अनुपात में कि उन्होंने स्टोर से माल खरीदा है । इस प्रकार माल बेचते समय उसका भाव कम न करके वर्ष के अन्त में एक अच्छी रकम सदस्यों को लाभ के रूप में बाँट दी जाती है ।

भारतवर्ष में स्टोर आन्दोलन का आरम्भ मद्रास में हुआ । आज भी यह राज्य इसकी प्रगति की दृष्टि में सबसे आगे है । मद्रास के पश्चात् यह आन्दोलन दूसरे राज्यों में भी फैला । परन्तु द्वितीय महायुद्ध से पूर्व इसकी कोई विशेष उन्नति नहीं हुई थी ।

द्वितीय महायुद्ध के छिड़ जाने पर परिस्थिति में कुछ बदल आई । वस्तुओं की कमी के कारण उनका मूल्य दिनों दिन बढ़ने लगा । व्यापारी लोग चोर बाजारी करने लगे । आवश्यक वस्तुयें बाजार से गायब हो गईं । इस कारण उपभोक्ताओं को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा । उनकी कठिनाई को कम करने के लिये सरकार ने मूल्य पर नियन्त्रण किया तथा कुछ समय पश्चात् राशनिंग चालू किया । सरकार ने राशनिंग की योजना में स्टोर्स को भी सम्मिलित किया अर्थात् जहाँ-जहाँ

स्टोर थे वहा-वहाँ सरकार उनको थोक मूल्यो पर सामान बेचती थी। इस अवसर का लाभ उठाने के लिये प्रायः सभी राज्यों में बहुत से स्टोर चालू किये गये। इस प्रकार युद्धकाल में इस आन्दोलन ने बड़ी प्रगति की। परन्तु यह उन्नति सब राज्यों में समान नहीं है। १९४७-४८ में हमारे देश में इस प्रकार के ५१०० स्टोर थे जिनमें से १७०० मद्रास में, १००० आसाम में, ६०० बम्बई में, ५०० मध्य प्रदेश में, ४०० ट्रावनकोर में, ३०० पश्चिमी बङ्गाल में तथा २००, २०० उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा मैसूर में थे।

आन्दोलन की प्रगति में बाधाएँ—यद्यपि युद्धकाल में हमारे देश में इतने स्टोर खुल गये हैं तो भी ऐसा अनुमान है कि इनमें से बहुत से युद्ध के पश्चात् समाप्त हो गये होंगे। यदि हम इसकी धीमी प्रगति के कारण तलाश करें तो निम्नलिखित बातों में से मिलेंगे—

(१) प्रबन्धों की योग्यता तथा उनमें ट्रेनिंग की कमी, (२) सदस्यों की आवश्यकताओं के विषय में जानकारी न होना, (३) उन वस्तुओं को खरीद लेना जिनकी सीमित माग है, (४) सदस्यों का स्टोर के साथ बफादारी न करना, अर्थात् स्टोर से माल न खरीदने पर दूसरे स्थानों में खरीदना, (५) साख पर व्यापार करने से हानि हो जाना, (६) थोक तथा बिछी मूल्य में कम अन्तर होना, (७) ठीक ढङ्ग से माल का हिसाब न रखना तथा बहीखाता ठीक प्रकार न रखना, (८) स्टोर को चलाने का अधिक खर्चा हो जाना, (९) निशुल्क सेवा पर बहुत अधिक निर्भरता, (१०) मूल्यों पर से नियन्त्रण हट जाना और खुले बाजार में बीजों का आसानी से मिलना।

हमारे देश में भी इन्हीं में से अधिकतर कारण हमारे स्टोर आन्दोलन की धीमी प्रगति के लिये जिम्मेदार हैं।

स्टोर आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के सुझाव—

स्टोर आन्दोलन हमारे देश में तभी लोकप्रिय हो सकता है जबकि यह सदस्यों की अधिकतम आवश्यकता पूरी करेगा। जो वस्तुएँ स्टोर रखें वे अच्छी हों तथा उससे अधिक मूल्य पर न बेची जायें जिस पर कि वे बाजार में बेची जाती हैं। यह बात तभी सम्भव हो सकती है जबकि स्टोरों का प्रबन्ध योग्य लोगों के हाथ में होगा तथा वे समय-समय पर सदस्यों की आवश्यकताओं का अध्ययन करते रहेंगे। यदि हो सके तो स्टोर अपने सदस्यों के अतिरिक्त गैर सदस्यों को भी माल बेचे जिससे कि वह स्टोर की उपयोगिता को समझकर भविष्य में उसके सदस्य बन जायें। स्टोर में जो प्रबन्ध रखे जाय उनका व्यवहार सदस्यों तथा गैर सदस्यों के प्रति बहुत अच्छा होना चाहिये। स्टोर को अपनी थोक समितियाँ भी बनानी चाहियें। इङ्ग्लैंड में इस प्रकार की समितियाँ बनाने से इस आन्दोलन ने बड़ी प्रगति की है। सहकारी योजना समिति का विचार है कि यह आन्दोलन ग्रामों में भी फैलना चाहिये। औद्योगिक केन्द्रों में इस आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के लिये

यह आवश्यक है कि सदस्यों का सदस्यता शुल्क कम रखा जाय तथा मजदूरी का माल उधार वचा जाय तथा जब उनकी अपनी मजदूरी मिल तब धन वसूल किया जाय । अपने सदस्यों को स्टोर की उपयोगिता समझाने के लिये स्टारा का चाहिये कि वे समय-समय पर उनमें लिखित साहित्य वटवायें । उनकी यह भी चाहिये कि वे ऐसे नौकर रख जो योग्य हों । नौकर रखने में पक्षपात से काम नहीं लेना चाहिये । इन सब बातों के करने से यह आशा की जा सकती है कि यह आन्दोलन बहुत लाभ-प्रिय हो जायगा ।

Q 47 Discuss the necessity of land mortgage banks for meeting the long term credit needs of Indian agriculture, and account for the limited progress made by them in India

प्रश्न ४७—भारतीय कृषि की दीर्घकालीन साख की आवश्यकता को पूरी करने के लिये भूमि बन्धक बैंकों की आवश्यकता बतलाइये तथा इन बैंकों की कम उन्नति के कारण लिखिये ।

कृषि साख आवश्यकता तीन प्रकार की होती है—(१) अल्पकालीन, (२) मध्यकालीन तथा (३) दीर्घकालीन । अल्पकालीन आवश्यकताओं में बीज, खाद, सिंचाई, लगान आदि की आवश्यकता सम्मिलित है । मध्यकालीन आवश्यकताओं में बैल, कुआ आदि की आवश्यकता है । दीर्घकालीन आवश्यकताओं में पुराने ऋण को चुकाने, भूमि खरीदने, नए ढाँचा की मँहगी मशीन खरीदने, खेत के चारों ओर बाड़े बनाने, खेत के ऊपर खेतों पर बनाने, बड़ा कुआँ आदि बनाने की आवश्यकतायें सम्मिलित हैं । खेतों की अल्प तथा मध्यकालीन आवश्यकताओं का सहकारी साख समितियाँ अथवा गाँव का महाजन पूरा कर देता है । पर दीर्घकालीन आवश्यकता का पूरी करने के लिये सरकार से थोड़ा ऋण भूमि उन्नति ऋण कानून (Land Improvement Loans Act) के अन्तर्गत मिल जाता है । इसके अतिरिक्त और कोई सतोपजनक साधन इस देश में नहीं है । पर यह साधन भी बहुत ही अपर्याप्त है । इससे थोड़े किसानों को ऋण भले ही मिल जाता हो पर देश के बहुत अधिक किसानों को इस साधन से कोई ऋण नहीं मिलता । इन कारण हमारा दस में ऐसे बैंकों की आवश्यकता है जो कि कृषकों की दीर्घकालीन आवश्यकता को पूरी कर सकें । इस प्रकार के बैंक भूमि-बन्धक बैंक हो सकते हैं ।

भूमि बन्धक बैंक भूमि की धरोहर पर ऋण देते हैं । इनके ऋण देने का समय देश-देश में भिन्न है । हमारे देश में बैंक प्रायः २० वर्ष के लिये ऋण देते हैं पर आस्ट्रेलिया में ६० वर्ष तक के लिये ऋण दे दत्त हैं । इस प्रकार के बैंक या तो सहकारी या गैर सहकारी या आंशिक सहकारी होते हैं । भारत के अधिकांश बैंक

दूसरे राज्यों में ये बैंक अपनी कार्यशील पूँजी जनता से डिपोजिट के रूप में अथवा ऋण लेकर एकत्र करते हैं। १९५६-५७ में भारत में १६ ६५ करोड़ रु० के डिबेन्चरो प्रचलित थे। इसमें से लगभग ५४ प्रतिशत आंध्र तथा मद्रास के केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको ने इश्यू किये थे। ये बैंक २० वर्ष के लिये ऋण देते हैं क्योंकि इनके डिबेन्चरो की अवधि २० वर्ष ही होनी है। इस समय तक इन बैंको ने पुराने ऋण को चुकाने के लिये ऋण दिया है पर हर एक राज्य में इस बात की आवश्यकता प्रतीत की जा रही है कि खेती की उन्नति के लिये भी ऋण दिया जाना चाहिये। इनके कार्यों की देख-सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार करता है।

बैंको की कम उन्नति के कारण

भूमि बन्धक बैंको ने देश में कुछ अधिक उन्नति नहीं की, इसके निम्नलिखित कारण हैं—

(१) भारतवर्ष के ७० प्रतिशत भाग पर जमींदारी पाई जाती थी। रयत-वारी राज्यों में भी किसानों के पास अपनी भूमि नहीं थी। इसी कारण किसान भूमि को भूमि बन्धक बैंक के पास कंसे बन्धक बना सकता था। यही कारण है कि जमींदारी प्रान्तों में इन बैंको की बहुत कम प्रगति हुई है।

(२) भूमि बन्धक बैंको को अपनी कार्यशील पूँजी डिबेन्चरो द्वारा एकत्र करनी चाहिये। पर हमारे देश में लोग डिबेन्चरो में अपना रुपया लगाते हुये डगते हैं। डिबेन्चरो से केवल बम्बई, मद्रास, मसूर आदि में ही धन एकत्र हुआ है क्योंकि वहाँ राज्य सरकारों ने इनका मूलधन व व्याज गारन्टी किया हुआ है।

(३) बहुत से राज्यों में सरकार ने इन बैंको के डिबेन्चरो का मूलधन व व्याज अदा करने की जिम्मेदारी भी नहीं ली है। इसी कारण ऐसे राज्यों में ये बैंक अधिक कार्यशील पूँजी एकत्र नहीं कर सकते। जहाँ कहीं, जैसे मद्रास व बम्बई में, राज्य सरकारों ने इस प्रकार की जिम्मेदारी ली है वहाँ पर इन बैंको को बहुत सफलता मिली है।

(४) इन बैंको का कार्य अभी तक केवल पुराना ऋण चुकाना ही है। इस क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत अधिक कार्य नहीं किया। मद्रास राज्य में जहाँ इन बैंको को सबसे अधिक सफलता मिली है वहाँ भी इनका कार्य सिंचाई किये गये भाग तक ही सीमित है। दूसरे राज्यों में तो उन्होंने ऋण को अदा करने में नहीं बरबबर कार्य किया है।

उन्नति करने के सुझाव

भूमि बन्धक बैंको की इतनी आवश्यकता को देखते हुये यह आवश्यक है कि इन बैंको के कार्य करने के ढङ्ग में कुछ उन्नति की जाय। भविष्य में इन बैंको को खेती की उन्नति के लिये ऋण देना चाहिये। इस कार्य में इनकी तभी सफलता मिल सकती है जबकि इन बैंको का सम्बन्ध राज्य कृषि विभागों से हो। ये विभाग इन बैंको

को यह वना मक्ते है कि किसान के लिये कौन सी योजनाये उपयोगी है। यदि किसान को उपयोगी योजनाओ के लिय ऋण दिया जायेगा तो किसान को उससे लाभ होगा और बैंको का रुपया मारा जाने का भय न रहेगा। यदि ऋण समझौता बोर्डों के साथ भी इन बैंको का सम्बन्ध स्थापित हो जाये तो किसानों का पूरा ऋण अदा करने मे बहुत आसानी हो जायगी। यह भी आवश्यक है कि इन बैंको का सम्बन्ध सहकारी समितियों से हो। केवल ऐसे ही लोगो को ऋण दिया जाए जो सहकारी साथ समिति के सदस्य हों और जो इन समितियों का ऋण ठीक समय पर अदा करते हों। भूमि वन्धक बैंक से ऋण मिलने के पश्चात् भी ऋणों को बहु-उद्देश्य सहकारी समिति का सदस्य रहना चाहिये ताकि यह वहा से अपनी अल्पकालीन तथा मध्यकालीन आवश्यकताओ के लिये ऋण प्राप्त करता रहे और अपनी फसल को नमिति के द्वारा बेच सके। ऐसा करने से किसान किसी प्रकार भी साहूकार से नहीं लूटा जा सकेगा। जिन राज्यों मे सरकारों ने डिबेन्चरो के मूलप्रन व ब्याज अदा करने की जिम्मेदारी नहीं ली वहा पर सरकार को ऐसा अवश्य करना चाहिये। रिजर्व बैंक को भी इन बैंको के डिबेन्चरो को ट्रस्टी घोरोहर घोषित कर देना चाहिये। यदि ये दोनों बातें हो गईं तो हमारे देश मे लोग डिबेन्चरो मे रुपया लगाने मे मर्गेच न करेंगे। जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् इन बैंको को किसानों के भूमि मोल लेने मे सहायता करनी चाहिये। इस भूमि को बैंक अपने पास जमानत के रूप मे रख सकने है। यह हर्ष का विषय है कि सौराष्ट्र का बैंक किसानों को मीरूसी अधिकार प्राप्त करने के लिये धन दे रहा है। इससे किसानों तथा बैंको दोनों को लाभ होगा। इसी प्रकार भूमि वन्धक बैंकों को ठीक ढङ्ग पर चलाने की आवश्यकता है।



Q 48 How does the Reserve Bank of India help the co-operative movement ?

प्रश्न ४८—रिजर्व बैंक आफ इण्डिया सहकारी आन्दोलन की किस प्रकार सहायता करता है ?

उत्तर—रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने खेती सम्बन्धी कार्यों के लिये एक अलग विभाग चालू किया हुआ है जिसको कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department) कहते हैं। यह विभाग कृषि साख के सम्बन्ध मे खूब अध्ययन करता रहता है तथा सरकार और सहकारी बैंको को योग्य सलाह दता है। इसने दिसम्बर १९३७ मे एक वार्षिक रिपोर्ट छपी थी तथा उसके पश्चात् भी कई बुलिटीन छपे हैं। अब यह एक मासिक बुलिटीन भी छापता है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट मे रिजर्व बैंक ने यह बात स्पष्ट रूप से बताई थी कि यह खेती को केवल सकट के समय ही आधिक सहायता प्रदान कर सकता है क्योंकि इसके पास दूसरे बैंको का द्रव्य कोष

रहता है। इसलिये इसको वह उन कार्यों में नहीं लगा सकता जिसमें कि दूसरे शेड्यूल्ड बैंक लगाने को तैयार नहीं हैं। इस प्रकार यह दैनिक कार्यों के लिये धन देने को तैयार नहीं है।

(१) यह सरकारी प्रतिभूतियों (Securities) की धरोहर पर अधिक से अधिक ६० दिन के लिये राज्य सहकारी बैंको तथा केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंको को जो राज्य सहकारी बैंक घोषित कर दिये गये हो ऋण दे सकता है।

(२) यह भूमि बन्धक बैंको के ऋण-पत्रों (Debentures) के पीछे भी ऋण दे सकता है। परन्तु इस प्रकार के ऋण तभी दिये जा सकते हैं जबकि ऋण पत्र ट्रस्टी धरोहर घोषित कर दिये गए हों।

(३) यह राज्य सरकारी बैंको के खेती सम्बन्धी बिलों को जिनकी अवधि १५ मास से अधिक न हो पुनर्वट्टे (Re discount) पर खरीद सकता है।

अभी पिछले वर्ष रिजर्व बैंक एक्ट में संशोधन किया गया है जिसके फल-स्वरूप रिजर्व बैंक को ग्रामीण आर्थिक कार्यों के लिये अनेक प्रकार की वित्तीय सहायता देने का अधिकार प्रदान किया गया है। अब रिजर्व बैंक कृषि कार्यों के लिये निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर मध्यकालीन ऋण दे सकता है—

(१) ऋण का समय १५ मास से कम तथा ५ वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

(२) राज्य सरकारों द्वारा ऋण का मूलधन तथा व्याज चुकाने की गारन्टी दी जानी चाहिये।

(३) प्रत्येक राज्य सहकारी बैंक अपने साधनों से अधिक ऋण न दे सकेगा।

ऋण ५ करोड़ रुपये से अधिक नहीं दिया जायेगा। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों तथा सहकारी बैंकों को एक गंभीर चिट्ठी भेजी है जिसमें बताया गया है कि मध्यकालीन ऋण किस प्रकार देगा। इस चिट्ठी में कहा गया है कि यद्यपि रिजर्व बैंक ५ वर्ष तक के लिये ऋण दे सकता है परन्तु वह व्यवहार में ३ वर्ष तक के ही ऋण देगा जिससे कि रुपये की लौट फेर जल्दी से जल्दी हो सके। इससे अधिक समय का ऋण केवल बहुत आवश्यक हालतों में दिया जायेगा। यह ऋण भूमि को खेती के योग्य बनाने, खेतों के चारों ओर बाँध बाँधने, खेती की दूसरी प्रकार की उन्नति करने, भूमि को बाग लगाने के लिये तैयार करने, छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाएँ बनाने, पशु, मशीनें तथा अन्य सामान खरीदने, खेतों पर इमारतें बनाने के लिये दिया जायेगा।

लघुकालीन ऋण के समान ये ऋण भी केवल १½ प्रतिशत व्याज की दर से राज्य सरकारी बैंकों को दिये जायेंगे। कम व्याज की दर का लाभ किसानों को पहुँचाने के लिये रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों तथा राज्य सहकारी बैंकों तथा किसान

के बीच में कई मध्यवर्ती सहायकों के आ जाने के कारण किसानों से ली जाने वाली व्याज की दर $६\frac{१}{२}$ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये।

इस प्रकार हम देखत हैं कि रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों को सलाह के रूप में तथा रुपये पैसों के रूप में बड़ी सहायता कर रहा है। अब से कुछ वर्ष पूर्व तक दसवीं सहायता केवल सलाह के रूप में ही थी। परन्तु लगभग १९४७-४८ से इसने धन के रूप में भी सहायता देनी आरम्भ कर दी। यह सहायता वह निरन्तर बढ़ाता जा रहा है। १९४८-४९ में इसने केवल ६७.७० लाख रुपये का ऋण राज्य सहकारी बैंकों को दिया था। १९४९-५० में यह बढ़ाकर २.१४ करोड़, १९५०-५१ में ७.६१ करोड़, १९५२-५३ में १५ करोड़ तथा १९५७-५८ में इस बैंक ने राज्य सहकारी बैंकों को खेती के मौसमी कार्य करने तथा पसल की बिक्री करने सम्बन्धी ४८.२४ करोड़ यु० के ऋण प्रदान करने की अनुमति दी। १९५७-५८ में इन बैंकों से ४०.४७ करोड़ रु० पावना या जुलाहों की सहकारी समितियों को उत्पादन तथा बिक्री कार्य में सहायता पहुँचाने के लिये रिजर्व बैंक ने उनको बैंक दर से $१\frac{१}{२}$ प्रतिशत कम व्याज पर २०५.७८ लाख रु० उधार दिये। सहकारी चीनी समितियों को उनकी कार्यशील पूँजी में सहायता पहुँचाने के लिये ३ करोड़ रु० बैंक दर पर स्वीकार किये गये। १२ राज्य सहकारी बैंकों को ७.७२ करोड़ रु० के मध्य-कालीन ऋण देने मजूर किये गये। परन्तु इस-इस बढ़ते हुये ऋण से हम पूर्ण रूप से सन्तुष्ट नहीं हैं। क्योंकि भारतीय कृषि की कुल आवश्यकता ५०० करोड़ वार्षिक की है। ऐसी स्थिति में यह सहायता समुद्र में एक बूद के समान है इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि रिजर्व बैंक को अधिक ऋण देना चाहिये। परन्तु इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि रिजर्व बैंक भी कानून से बंधा हुआ है। वह केवल ऊँची धरोहरों के पीछे ऋण दे सकता है जो एनट के अनुसार उसको मान्य हैं। ऐसी धरोहरों के पैदा करने के लिये राज्य सरकारों को सरकारी गोदामों का निर्माण करना पड़ेगा। कहीं कहीं राज्य सरकारों को ऋण का व्याज तथा मूलधन गारंटी करना पड़ेगा। ऐसा सब कुछ करने के रिजर्व बैंक कृषि की अधिक सहायता कर सकेगा।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वे

१९५१ ई० में रिजर्व बैंक ने ग्रामीण साख सर्वे किया जिसमें देश के ७५ जिलों से से ६०० गाँव लिये गये। इस समिति के अध्यक्ष श्री गोरखाला थे। इस समिति की रिपोर्ट २० दिसम्बर १९५४ को छपी।

इस समिति ने देखा कि किसानों को दिए गए कुल ऋण का ३३ प्रतिशत सरकार द्वारा तथा ३१ प्रतिशत सहकारी समितियों द्वारा दिया जाता है। लगभग ७० प्रतिशत सहायता अब भी गाँव के महाजन द्वारा की जाती है। सहकारी समितियों को केन्द्रीय व राज्य सरकारों से बहुत सहायता मिलती है।

इस समिति का मत है कि सरकार को सहकारी समितियों को भिन्न भिन्न

अवसरो पर सहयोग देना चाहिये । सरकार को चाहिये कि वह राज्य सरकारी बैंको व भूमि बन्धक बैंको की पूँजी का ५१ प्रतिशत स्वयं लगाये । इस प्रकार राज्य सरकारों के द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंको व बड़ी बड़ी प्रारम्भिक समितियों को भी सहायता प्रदान की जानी चाहिये । इस कार्य के लिये रिजर्व बैंको को राज्य सरकारों की सहायता एवं राष्ट्रीय कृषि साख कोष में से जिसमें कि प्रारम्भ में रिजर्व बैंक ५ करोड़ रु० जमा करे तथा इसके पश्चात् इतना ही धन प्रति वर्ष जमा करे, करनी चाहिये । इस कोष में से राज्य सहकारी बैंको को मध्यकालीन तथा भूमि बन्धक बैंको को दीर्घकालीन ऋण देने चाहिये ।

समिति न यह यह भी सुझाव दिया है कि फसल की बिक्री तथा उसको एवज करने के लिये भी सरकारी सस्थाओं को सहयोग देना चाहिये ।

समिति का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव एक राज्य बैंक की स्थापना है जो कि इम्पीरियल तथा अन्य किसी बैंको को मिलाकर बनाया जाय । इस बैंक की शाखायें सब जिलों के केन्द्र स्थानों तथा छोट छोट केन्द्रों में होगी । यह बैंक सहकारी समितियों को साख की तथा उनके धन को हस्तान्तर करने की सुविधा प्रदान करेगा । इन बैंक की पूँजी इस प्रकार बढानी चाहिए जिससे कि भारत सरकार व रिजर्व बैंक का उसमें ५१ प्रतिशत भाग हो ।

सरकार ने इस समिति के सुझावों को मानकर द्वितीय योजनामाल में सहकारी साख को मजबूत बनाने के लिये उसमें एक बड़ा भाग लेने का निश्चय किया । न म लगान के लिये कुटीर उद्योग को बहुत आवश्यकता है । किसी देश के लिये बड़े उद्योगों का जो महत्व है उससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता । पर वर्तमान स्थिति में हमारा देश का उद्धार बड़े उद्योगों से नहीं हो सकता । क्योंकि व कम लोगों को रोजगार दे सकने हैं और बड़े उद्योगों को चलाने के लिये हमारे पास दस समय पर्याप्त मात्रा में साधन भी नहीं हैं । इस कारण कुछ समय तक हमको फटीर उद्योगों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा । बैबिंग बनेदी, कृषि कमीशन, बम्बई किया जायेगा । भविष्य में समितियाँ आने वाली फसल का बटवारा पर ऋण दे सकेंगी । इसके बदले ऋण लेने वाले को अपनी फसल सहकारी बिक्री समितियों को बेचनी पड़ेगी । इस योजना में १००० बिक्री समितियाँ बनाने की योजना है । इन बिक्री समितियों की सदस्य १२००० बड़ी बड़ी साख समितियाँ होगी जो कि सदस्यों में कृषि सम्बन्धी सामान का बटवारा करेंगी तथा उनकी फसल को एकत्र करेंगी । इस हेतु ६५७० गोदाम बनाने की योजना है जो कि साख तथा बिक्री समितियों के आधीत होंगे । इन गोदामों की, रसीदों के पीछे, जिसानों की, ऋण, प्राप्त, करते की, सुविधा भी दी जायेगी ।

लोक समा में Central Warehousing Corporation स्थापित करने के लिये एक बिल भी पेश किया गया है जिसके द्वारा एक Central Co-operation Development and Warehousing Board स्थापित किया जायेगा जो सहकारी समितियों द्वारा उत्पन्न बढाने, उसको बेचने, उसको गोदाम में रखने, उसके बाहर भेजने आदि का कार्य करेगा । इस बीच राज्यों को भी Warehousing Corporation स्थापित करने का अधिकार दिया गया ।

Q 39 Account for the decline of cottage industries in India during the second half of the nineteenth century ?

प्रश्न ४९—१९ वीं शताब्दी के दूसरे आधे भाग में भारतीय कुटीर उद्योग का पतन क्यों हुआ ?

१९ वीं शताब्दी के अर्धपूर्व में भारतवर्ष अपने उद्योगों के लिये सारे संसार में प्रसिद्ध था। हमारे देश में तैयार किया हुआ माल दूर-दूर के देशों को जाता था। वह माल बहुत ही सुन्दर होता था। कहते हैं कि रोम व यूनान की राजकुमारियाँ बड़े गर्व से भारतीय कपड़ा पहनती थी। भारत केवल सूती कपड़े के लिये ही प्रसिद्ध न था बरन् वह ऊनी तथा रेशमी कपड़े के लिये भी प्रसिद्ध था। काश्मीर के शाल दुशाले प्रसिद्ध थे। यही नहीं, भारतवर्ष में हाथी दान का काम, लकड़ी पर खुदाई का काम तथा लोहे का काम भी सूब होता था। यह सामान अरब के समुद्र तक सन्तुष्ट नहीं है। क्योंकि भारतीय कृषि की कुल आवश्यकता ५०० करोड़ बाण्डरों की है। ऐसी स्थिति में यह सहायता समुद्र में एक बुद के समान है इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि रिजर्व बैंक को अधिक ऋण देना चाहिये। परन्तु इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना पड़गा कि रिजर्व बैंक भी कानून से बंधा हुआ है। वह केवल उन्हीं धरोहरों के पीछे ऋण दे सकता है जो एक्ट के अनुसार उसको मान्य है। ऐसी धरोहरों के पैदा करन के लिये राज्य सरकारों को सरकारी गोदामों का निर्माण परन्तु बहुत सी बातों के कारण धीरे-धीरे हमारे उद्योग-धन्धे नष्ट हो गये। इनके नष्ट होने में नीचे लिखी बातों का प्रभाव भी पड़ा—

(१) देशी राजाओं के दरबारों का समाप्त होना—जब तक इस देश में मुगल बादशाह तथा नवाब आदि रहे तब तक वे बहुत सी फैशन की चीजें माँगते रहे। पर अंग्रेजों के आने के पश्चात् एक-एक करके सब बादशाह तथा नवाब समाप्त हो गये। इसी कारण फैशन की चीजों की माग जो बादशाह तथा उनके दरबारी किया करते थे वह समाप्त हो गई और इसी के साथ सब दस्तकारिया भी नष्ट हो गई।

(२) विदेशी प्रभाव—भारतवर्ष में अंग्रेजी राज्य स्थापित हो जाने के पश्चात् देश में शान्ति हो गई। इसके कारण हथियार बनाने के उद्योग प्रायः समाप्त हो गये। इसी कारण कुछ और उद्योगों का भी पतन हुआ। भारत में रहने वाले अंग्रेजी अफसर भारत की चीजों का प्रयोग न करके अपने देश की ही चीजों को

Q. 50. State the importance of cottage industries in Indian economy. What measures would you suggest to improve the organisation of cottage-industries in our country ? How is the Government helping them ?

प्रश्न ४६—भारतीय अर्थ-व्यवस्था में कुटीर उद्योगों का महत्व बताइये । हमारे देश में उद्योगों के संगठन को उन्नत करने के लिये आप क्या सुझाव देंगे ? सरकार उनकी किस प्रकार सहायता कर रही है ?

कुटीर उद्योग क्या होते हैं ? कुटीर उद्योग वे होते हैं जो कि दस्तकार लोग अपने घरों में अपने आप तथा अपने बाल बच्चों की सहायता से चलाते हैं । इन उद्योगों में दस्तकार लोग अपनी ही पूँजी लगाते हैं । परन्तु कभी कभी वे कारखाने-दारों की पूँजी से भी कार्य करते हैं । जहाँ कहीं सम्भव होता है वे बिजली की शक्ति से भी काम करते हैं ।

इन उद्योगों का महत्व—कुटीर उद्योग देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं । हमारे देश के लोग गरीब हैं और उनका जीवन स्तर बहुत नीचा है । सिंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर और शेष स्थानों के लोग वर्ष में कई महीने बेकार भी रहते हैं । बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वर्ष भर कोई काम करने को नहीं होता । घरों की स्त्रियाँ भी बहुधा बेकार ही रहती हैं । इन सब लोगों को काम में लगाने के लिये कुटीर उद्योग की बहुत आवश्यकता है । किसी देश के लिये बड़े उद्योगों का जो महत्व है उससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता । पर वर्तमान स्थिति में हमारा देश का उद्धार बड़े उद्योगों से नहीं हो सकता । क्योंकि वे कम लोगों को रोजगार दे सकते हैं और बड़े उद्योगों को चलाने के लिये हमारे पास इस समय पर्याप्त मात्रा में साधन भी नहीं हैं । इस कारण कुछ समय तक हमको कुटीर-उद्योगों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा । वैकिंग कमेटी, कृषि कमीशन, बम्बई योजना, सभी ने इस बात पर जोर दिया है कि भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये कुटीर उद्योगों का बहुत महत्व है । दूसरे देशों में जैसे जापान, जर्मनी, रूस, चीन, स्विटजरलैंड आदि ने कुटीर उद्योगों द्वारा ही बहुत उन्नति की है । इसलिये यह आशा है कि भविष्य में हमारे देश को इन उद्योगों से बहुत लाभ होगा ।

यदि हमारे देश में कुटीर उद्योग उत्तम हो गये तो इससे किसानों को बहुत लाभ होगा । पहला लाभ तो उनको यह होगा कि उनका बेकार समय काम में आ जायेगा । दूसरा लाभ यह होगा कि उनकी आय में वृद्धि हो जाने से उनका जीवन स्तर ऊँचा हो जायेगा । तीसरा लाभ यह होगा कि खेती पर से जनसंख्या का दबाव कम हो जाने के कारण खेती का क्षेत्र बड़ा हो जायेगा । खेती में उन्नत औजार काम में लाये जा सकेंगे । इस प्रकार खेती की भी उन्नति होगी । खेती की उन्नति में प्लैक्तरकार, व्यापारियों, रेलों आदि सभी को लाभ होगा ।

कुटीर उद्योगों द्वारा हमारे देश की बेकारी की समस्या भी हल हो सकती है। आजकल हमारे देश में लाखों मनुष्य बेकार पड़े हैं। उनको काम देने में कुटीर उद्योगों से ही सबसे अधिक सहायता मिल सकती है।

बड़े उद्योगों की अपेक्षा कुटीर उद्योगों में हमारे देश को यह भी लाभ होगा कि इनके द्वारा देश में धन का वितरण समान रूप से हो जायेगा। परन्तु बड़े उद्योगों में धन का केन्द्रीयकरण होता है। आजकल हमारे देश में धन के समान वितरण की बहुत आवश्यकता है क्योंकि इस देश में या तो वे लोग रहते हैं जिन्हें दिन में भोजन भी नहीं मिलता या वे हैं जो धन में पड़े रहते हैं।

चीन और रूस देशों द्वारा यह बात पूर्ण रूप से विदित हो गई है कि बाहरी आक्रमण के समय कुटीर उद्योग बहुत लाभदायक सिद्ध होते हैं। युद्ध के समय शत्रु बड़े-बड़े उद्योगों में बम डालकर उनको नष्ट-भ्रष्ट कर सकता है। पर वह कुटीर उद्योगों का कुछ भी नहीं धिगाड़ सकता। आक्रमण के समय बड़ी आसानी से उनको इधर-उधर ले जाया जा सकता है।

कुटीर उद्योगों के उन्नत होने से हमारे देश के सब भागों की आर्थिक उन्नति समान रूप से हो सकेगी। यह सत्य है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग चलाने से हम को निकट भविष्य में कुछ घाटा होगा परन्तु जब तक देश के समस्त क्षेत्रों की उन्नति समान रूप से नहीं होती तब तक हम पिछड़े क्षेत्रों के लोगों की योग्यता तथा शक्ति का ठीक उपयोग नहीं कर सकते। पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति केवल कुटीर उद्योगों द्वारा ही संभव है।

आजकल हमारे देश के लिये कुटीर उद्योगों का महत्व इसलिये भी है क्योंकि इन उद्योगों को कोई ऐसा ऊँचा माल नहीं चाहिये जिसमें कि विदेशी विनियम खर्च-करती पड़े। इस प्रकार इन उद्योगों के द्वारा हम लोगों को रोजगार प्रदान करते हुए भी अपने विदेशी विनियम के साधनों को बचा सकेंगे।

भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने इन उद्योगों के महत्व के विषय में कहा है कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिये घरेलू उद्योगों का विशेष महत्व है और इस देश की आर्थिक व्यवस्था में इनका ऊँचा स्थान होना चाहिये। आगे आपने कहा कि यदि इन उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन न दिया गया और वे सुप्त हो गये, तो इससे न केवल बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैलेगी बल्कि काला कांता होगा और देशतो में रहने वाले लोग, जो इस देश की आबादी के ८० प्रतिशत हैं और भी निर्धन हो जायेंगे।

कुटीर उद्योगों की कठिनाइयाँ तथा दोष—आजकल हमारे कुटीर उद्योगों के सामने बहुत सी कठिनाइयाँ हैं तथा उनके कार्य करने के ढङ्ग में बहुत दोष हैं जिनके कारण यह उन्नत नहीं होने पाते। बिना इन दोषों को दूर किये ये उद्योग कभी उन्नति न कर सकेंगे। ये दोष तथा कमियाँ निम्नलिखित हैं—

(१) इन उद्योगों की पहली कठिनाई यह है कि दस्तकारों को उद्योग के लिये सस्ते दामों पर कच्चा माल नहीं मिलता। इसलिये उनको कारखानेदारों पर निर्भर रहना पड़ता है और उन्हीं के हाथ अपना पक्का माल बेचना पड़ता है। जब वे उधार माल लेते हैं तो उनको महंगा मिलता है।

(२) दूसरी कठिनाई यह है कि दस्तकारों के पास पूँजी की बहुत ही कमी है इस कारण उनको महाजनों तथा दूसरे लोगों से ऋण लेना पड़ता है। यह ऋण उनको बहुत ऊँचे व्याज पर मिलता है। इस कारण वे सदा ऋणी रहते हैं और सब प्रकार के कष्ट सहन करते हैं।

(३) तीसरी कठिनाई यह है कि दस्तकार प्रशिक्षा प्राप्त किये हुये नहीं हैं। इस देश में दस्तकारी शिक्षा देने के साधन बहुत ही कम हैं और जो हैं भी वे बहुत महंगे हैं। दस्तकारी केन्द्रों में केवल धनी लोग ही अपने बच्चों को भेज सकते हैं।

(४) चौथी कठिनाई यह है कि इस देश के लोग अपने देश की बनी हुई वस्तुयें नहीं अपनाते। वे विदेशों की बनी हुई वस्तुयें काम में साने में ही अपना गौरव मानते हैं। इसी कारण उनकी माग कम है।

(५) अभी हाल ही तक सरकार भी इनको कुछ प्रोत्साहन न देती थी। सरकार अपनी आवश्यकतायें जो करोड़ों रुपये की थी। इङ्ग्लैंड से पूरी करती थी। अभी तक कुछ अंशों में यह नीति चली आ रही है। द्वितीय महायुद्ध में यह बात सिद्ध हो गई है कि यदि सरकार चाहे तो कुटीर उद्योग बहुत उन्नति कर सकते हैं।

इन कठिनाइयों के अतिरिक्त दस्तकारों के कार्य करने में बहुत में दोष हैं—

(१) दस्तकार लोग असंगठित हैं। इस कारण वे अपने आपकी दूसरों के शोषण से नहीं बचा सकते। यदि वे संगठित होते तो वे अपने हित को बहुत सी बातें सोच सकते थे तथा अपनी उन्नति भी कर सकते थे।

(२) दस्तकार लोग थोड़ा सामान खरीदते हैं तथा थोड़ा ही बेचते हैं। इसी कारण उनको बेचते समय तथा खरीदते समय घाटा होता है।

(३) दस्तकार लोग बहुधा रुढ़िवादी हैं। वे अभी तक पुराने औजारों से ही काम करते चले आ रहे हैं और नये औजार काम में लाना पसन्द नहीं करते।

(४) कुटीर उद्योगों का सामान बेचने के लिये भी इस देश में कोई अच्छा साधन नहीं है। दस्तकार गाँव के महाजन के हाथ या किसी कारखाने वाले को ही सस्ते दामों पर माल बेचते हैं।

कठिनाइयों तथा दोषों को दूर करने के उपरान्त—जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कुटीर उद्योग देश की उन्नति के लिये आवश्यक है। इसलिये उनको उन्नत करना हमारा कर्तव्य है। ये लोग निम्नलिखित ढङ्गों से उन्नत हो सकते हैं—

(१) दस्तकारों को चाहिये कि वे अपनी सहकारी समितियाँ बनायें। समितियाँ अपने सदस्यों के लिये आवश्यक मात्रा में कच्चा माल खरीदें तथा पक्का माल बेचें। इन समितियों को यह भी चाहिये कि वे अपने सदस्यों के लिये शिक्षा का

प्रवन्ध करें। भारतीय केन्द्रीय बैंकिंग जाच कमेटी ने इस बात पर जोर दिया था कि दस्तकारों की सहायता के लिये सहकारी समितियां बनाई जायें।

यहां यह बात बताने योग्य है कि हमारे देश में इस प्रकार की सहकारी समितियां पाई जाती हैं। इनमें से जुलाहों की सहकारी समितियां सबसे महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार की समितियां मद्रास और बम्बई में अधिक पाई जाती हैं। १९४७-४८ में मद्रास में ६५६ ऐसी समितियां थीं। उन समितियों की कार्यशील पूंजी १०७ लाख रुपये थी। इसी वर्ष बम्बई में २११ ऐसी समितियां थीं जिनकी कार्यशील पूंजी ३२५६ लाख थी। उत्तर प्रदेश में भी ५५० प्रारम्भिक तथा ३८ केन्द्रीय समितियां इसी वर्ष में थीं। उनके ७८७७२ सदस्य थे तथा उनमें से प्रारम्भिक समितियों की कार्यशील पूंजी १६ लाख रुपये थी तथा उन्होंने उस वर्ष ८० लाख रुपये का माल बेचा। भारत के २८,८०,००० करघों में से १६५७ ई० तक ११,२२,५३५ सहकारी आन्दोलन से लाभ उठा रहे थे। ३१ दिसम्बर १९५७ ई० तक भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को ६३,०६,०६५ रु० इसलिये दिये जिससे कि वे जुलाहों की सहकारी समितियां बनाने का प्रयत्न करें।

(२) दस्तकारों को चाहिये कि वे अच्छे औजारों को काम में लायें। बिहार में उन्नत औजारों का प्रयोग दिखाने के लिये निर्देशक नियुक्त किये गये हैं। कुटीर उद्योग गृह द्वारा बहुत प्रकार के प्रयोग किये जाते हैं। यह गृह जुलाहों को औजार, रंग आदि भी देता है और जुलाहों को नये-नये नमूने भी बताता है। मध्य प्रदेश में भी जुलाहों को नये-नये प्रकार के औजार दिये जा रहे हैं। यह अनिवार्य आवश्यक है कि इन प्रकार का कार्य और राज्यों में भी किया जाय तथा कपड़ा बनाने के अतिरिक्त और प्रकार के उद्योगों के लिये भी उन्नत औजार प्रदान किये जायें।

(३) दस्तकारों के लिये कम व्याज पर ऋण का प्रवन्ध भी होना चाहिये। हमारे देश में अभी तक ऋण लेने का साधन केवल गांव का महाजन है। कहीं-कहीं सहकारी समितियां भी ऋण देती हैं। पर उनकी संख्या बहुत कम है।

व्यापारिक बैंक दस्तकारों को रुपया उधार नहीं देते। थोड़ी आर्थिक सहायता सरकार के औद्योगिक विभाग (Department of Industries) से भी दी जाती है। इस प्रकार ऋण लेने का साधन केवल गांव का महाजन है। पर यह बहुत ऊंची दर पर ऋण देता है। भारतीय केन्द्रीय बैंकिंग जाच समिति ने बताया था कि इस देश में वर्तमान से अधिक सहकारी ऋण समितियां बनाई जानी चाहियें। औद्योगिक आयोग ने सुझाव दिया था कि उद्योगों के निर्देशक (Director of Industries) को छोटे ऋण देने चाहिये। उसने यद्वाभी सुझाव दिया कि दस्तकारों को उधार-क्रय रीति (Hire Purchase System) पर औजार दिये जायें। परन्तु ऋण देने का सबसे अच्छा ढङ्ग सहकारी समितियां हैं। अभी कुछ दिनों से सरकार तथा रिजर्व बैंक इन उद्योगों को बड़ी सहायता प्रदान कर रहे हैं जिससे कि दस्तकार को महाजन आदि से ऋण न लेना पड़े।

(७) यह भी आवश्यक है कि दस्तकारी द्वारा तैयार किया हुआ माल उचित रीति से बेचा जाय। अभी तक इस देश में सिवाय थोड़े स्थानों को छोड़कर सामान बेचने का कोई उचित साधन नहीं है। यदि लखनऊ के उत्तर प्रदेश आर्ट तथा क्रैफ्ट इम्पीरियल जैसी संस्थाएँ इस देश में स्थापित हो जायें तो बहुत लाभ हो। सरकार को चाहिये कि वह विदेशों में भारतीय कुटीर उद्योग के सामान का प्रचार करे। हर्ष का विषय है कि वर्तमान सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। सरकार ने देश में चारों ओर चलने फिरने वाली नुमायश भेजी है तथा बहुत से राज्यों में दस्तकारी सप्ताह भी मनाये जा चुके हैं। दिल्ली में कुटीर उद्योगों का अजायबघर बनाने की योजना है। १२ अप्रैल १९५५ ई० की एक सूचना के अनुसार भारत सरकार Indian Handicrafts Development Corporation (Private) Limited स्थापित किया है। इसकी अधिकृत पूंजी १ करोड़ रुपये है। यह कारपोरेशन कुटीर उद्योगों की उत्पत्ति को इस प्रकार चलायेगी जिससे कि विदेशी माग को शीघ्र ही पूरा किया जा सके। इस कारपोरेशन का मुख्य कार्य हम-उद्योगों के माल को विदेशों में निर्यात के लिये प्रोत्साहन देना होगा।

इस सब प्रयत्न के फलस्वरूप हमारा बहुत सा कपड़ा तथा अन्य सामान अमेरिका आदि देशों में विक रहा है। पश्चिमी जर्मनी, अफ्रीका आदि देशों में निर्यात करने का प्रयत्न जारी है। भारतीय कुटीर उद्योगों का माल प्रेस, लन्दन, पेरिस, मेराबी आदि स्थानों में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में दिखाया गया है। १९५६-५७ में सोवियत रूस तथा जेकोस्लोवेकिया से भारतीय हाथ के उद्योगों के बहुत से आर्डर प्राप्त हैं।

(५) दस्तकारी की शिक्षा का प्रबन्ध करना भी बहुत आवश्यक है। यह शिक्षा सस्ते दायों पर होनी चाहिये। बम्बई राज्य में इस ओर ध्यान दिया जा रहा है, पर अभी तक जो कार्य हुआ है वह महासागर में एक बिन्दु के समान है। इस ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे देश में अब सरकार का ध्यान इस ओर जाने लगा है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मन्त्री ने घोषणा की थी कि भविष्य में उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को हाथ से चीजे बनाना सिखाई जायेंगी। बर्मा शिक्षा प्रणाली में भी इसी प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया जाता है आजकल इस देश में शिक्षा लेने वालों की कमी नहीं है। वही है शिक्षा के केन्द्रों की। 'कुटीर उद्योगों' को 'टैक्नीकल' सहायता प्रदान करने का कार्य 'केन्द्रीय सरकार' ने अपने ऊपर लिया है। बम्बई, कलकत्ता देहली तथा मद्रास में चार क्षेत्रीय संस्थाएँ तथा त्रिवेन्द्रम में एक-एक शाखा पहले से ही कार्य करने लगी है। टैक्नीकल सामग्री में सहयोग देने के लिये विदेशों से विशेषज्ञ बुलाये गये हैं कांग्रेस द्वारा प्रकाशित 'स्वतन्त्रता का दसवाँ वर्ष' नामक पुस्तक के ६६ पृष्ठ पर लिखा है कि ट्रेनिङ्ग के प्रोग्राम पर काफी जोर डाला जा रहा है। दस्तकारी को तालीम देने के लिये विभिन्न ग्राम उद्योगों के लिये बहुत से ट्रेनिंग केन्द्र खोले गये हैं।

(६) सरकार को भी यह चाहिये कि वह इस देश के दस्तकारों से अपनी आवश्यकता पूरी करने का प्रयत्न करे। यदि सरकार ऐसा करने लगे तो कुटीर उद्योगों को बहुत लाभ हो।

(१) कुटीर उद्योगों के लिये कुछ क्षेत्र निश्चित किये जा रहे हैं जिसमें कि उन क्षेत्रों में उनके साथ बड़े पैमाने के उद्योगों की कोई प्रतियोगिता न हो।

(२) कुटीर उद्योग से लाभ के लिये उसी प्रकार के बड़े पैमाने के उद्योग पर उपकर (Cess) लगाया जा रहा है।

(३) जहाँ तक हो सके बड़े पैमाने के उद्योग को उत्तम न किया जाय।

सरकारी सहायता

कुटीर उद्योगों की व्यवस्था करने का कार्य मुख्यतः राज्य सरकारी पर है। इस कार्य में सहायता करने के लिये सरकार ने ये संस्थायें स्थापित की हैं। अखिल भारतीय खादी बोर्ड, कुटीर उद्योग बोर्ड, कोयल बोर्ड तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड।

कुटीर उद्योगों को सरकार तथा बैंक दोनों ही सहायता देते हैं। हाल ही में सहायता को प्रभावी बनाने के लिये कुछ कदम उठाये गये हैं। १९५७-५८ में ३३ करोड़ के ऋण तथा ११ करोड़ रु० की सहायता राज्य सरकारी को कुटीर उद्योगों की सहायता करने के लिये दिये गये हैं। सरकार ने ७२ औद्योगिक स्टेट स्थापित करने के लिये मजूरी दी है। इन स्टेटों का उद्देश्य यह है कि छोटे उद्योगों को नगरों से हटा कर नये-नये स्थानों पर स्थापित किया जाये। इनको केंद्री के बराबर स्थान दिया जायगा। इन स्टेटों में विभिन्न उद्योगों को कुशल कार्य करने के लिये कुछ सामान्य सुविधायें प्रदान की जायेंगी। जैसे ये भूमि का विकास करेंगी, छोटे औद्योगिक केन्द्रों के लिये आवश्यक कर्म केन्द्रों की इमारतों को बनायेंगी, विजली, पानी, गैस, भाप, दवावयुक्त वायु और अन्य सुविधाओं का प्रबन्ध करेंगी और सामुदायिक सेवाओं की व्यवस्था करेंगी। सितम्बर १९५८ तक १७ ऐसी स्टेटें तैयार हो चुकी थी। इन स्टेटों के बनाने की कुल लागत राज्यों सरकारों को केन्द्रीय सरकार ऋण के रूप में देगी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक उन्नति प्लाकी में जिन १६ स्टेटों के बनाने की सिफारिश की गई है उनमें से २ बनाई जा रही है। योजना में इन स्टेटों को बनाने की लागत १० करोड़ से उठा कर १५ करोड़ कर दी गई है।

कुटीर उद्योगों को टेक्निकल सहायता प्रदान करने के लिये केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक विस्तार सेवा (Industrial Extension Service) का प्रोग्राम चालू किया है। चार क्षेत्रीय संस्थायें बम्बई, नई दिल्ली तथा मद्रास में, १२ बड़ी-बड़ी संस्थायें, पाँच शाखा संस्थायें तथा ६२ विस्तार केन्द्र भी कार्य कर रहे हैं। दिसम्बर १९५८ में इस सेवा कार्य का पुनर्संगठन किया गया था जिससे कि प्रत्येक राज्य में एक-एक संस्था स्थापित की जा सके। Ford Foundation के अन्तर्गत विदेशों से

इन उद्योगों को सहायता करने के लिये विशेषज्ञ कुलाये जाते हैं तथा यहाँ के आदमी विदेशों में प्रशिक्षा लेने के लिये विदेशों में भेजे जाते हैं ।

फरवरी १९५५ ई० में एक राष्ट्रीय लघु उद्योग कारपोरेशन की स्थापना की गई है जो कि सरकार से माल स्पलाई करने के लिये आर्डर लिया करेगा । इस आर्डर की स्पलाई वह छोटी-छोटी इकाइयों को ठेका देकर पूरी करेगा । अभी तक ३१६० छोटी इकाइयों के ऐसे समझौते हो चुके हैं । १९५५-५६ में केन्द्रीय सरकार ने कुटीर उद्योगों के ३४ करोड़ ६० का माल खरीदा । कारपोरेशन ने छोटी-छोटी इकाइयों के लिये मशीनें खरीदने के लिये उधार-क्रम (Hire Purchase) की एक योजना चालू की गई है । इस योजना के अन्तर्गत १४३ लाख ६० की मशीनें खरीदी जा चुकी है । इस कारपोरेशन का कार्य चलाने के लिये केन्द्रीय सरकार ने अभी तक १२० करोड़ ६० के ऋण व सहायता प्रदान की है ।

सामूहिक विकास क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों में भी कुटीर उद्योगों को उन्नत करने का प्रयत्न किया जा रहा है । इस प्रकार का प्रोग्राम २६ क्षेत्रों में चल रहा है ।

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड जो कि १९५२ में स्थापित हुआ था इस बात का प्रयत्न कर रहा है कि देश तथा विदेशों में कुटीर उद्योगों के उत्पादन तथा वित्री की उन्नति हो । भारतीय दस्तकारी विकास कारपोरेशन निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये स्थापित किया गया है । इस कारपोरेशन ने चलती-फिरती नुमायशों को देश में इधर-उधर भेजा है तथा विभिन्न राज्यों में 'दस्तकारी सप्ताह' बटुचा मनाये जाते हैं । आजकल हाथ से बने हुये सामान का मूल्य लगभग १०० ६० वार्षिक होगा । इस से लगभग ७ करोड़ ६० का माल विदेशों को निर्यात किया गया ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न बोर्डों के द्वारा निम्न-लिखित सहायता प्रदान की—

प्रथम पंच वर्षीय योजना में कुटीर उद्योगों पर किया गया खर्च ।

	करोड़ ६० में
	१९५१-५६
हथकरघा	१२२
खादी	१२३
ग्राम उद्योग	२६
छोटे पैमाने के उद्योग	४४
दस्तकारी	० ८
रेशम उद्योग	० ७
नारियल उद्योग	० ३
योग	३३६

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में २०० करोड़ रु० रखे गये हैं जो इस प्रकार खर्च किये जायेंगे—

उद्योग का नाम	करोड़ रु० में
हथ कर्षी	
रुई कातना	५६०
रेशम कातना	१५
ऊन कातना	२०
योग	<u>५९५</u>
खादी	
ऊन कातना व बुनना	१६
विकेंद्रित मूल कातना तथा खादी	१४८
योग	<u>१६४</u>
ग्राम उद्योग	
ढेकी से चावल निकालना	५०
वेजीटेबिल तेल (धानी)	६७
चमड़ा रगना व बुता बनाना (ग्राम)	५०
गुड़ तथा खडसारी	७०
कुटीर दियारालाई	११
अन्य ग्राम उद्योग	१४०
योग	<u>३८८</u>
वस्तुकारी	६०
छोटे-पमाने के उद्योग	५५०
अन्य उद्योग	
रेशम	५०
नारियल कातना व बुनना	१०
सामान्य योजनाय (कार्य संचालन, रिसर्च)	१५०
योग	<u>२०००</u>

ग्राम उद्योगों पर योजना के पहले दो वर्षों में ५६ करोड़ रु० खर्च हुआ।

इसके अतिरिक्त तन्त्र उद्योगों को सरलता से और समुचित अर्थ प्राप्त हो सके, इसके लिये इस दिशा में वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली सभी संस्थाओं के परस्पर सहयोग से एक कार्य-क्रम बनाया गया। अप्रैल १९५६ में स्टेट बैंक आफ इंडिया ने रिजर्व बैंक, राज्यों के उद्योग विभागों राज्यवित्त नियमों तथा सहकारी बैंकों के सहयोग से एक प्रायोगिक योजना आरम्भ की। उस समय यह केवल ६ स्थानों में स्थापित की गई थी परन्तु अब यह ५० से अधिक नगरों पर काम कर रही है। इस योजना के अनुसार उद्योगों को एक संस्था से ही ऋण लेना चाहिये।

अम्बर चर्खा—द्वितीय योजना काल में कातने के लिये अम्बर चर्खे पर जोर दिया गया है। इसमें चार तक होते हैं। इस कारण १९५६-५७ के लिये ७५००० अम्बर चर्खे चालू करने की स्वीकृति दी गई। दिसम्बर १९५६ तक ३७१७५ ऐसे चर्खे बनाये गये तथा उन से २,१४,७११ पौंड सूत काता गया तथा ५,८३,८८४ वर्ग गज कपड़ा बनाया गया। १९५७-५८ में इस चर्खों से १११ ५ लाख वर्ग गज कपड़ा बनाया गया। १९५६-५७ में अम्बर चर्खों से ५७२७० सोगो को तथा १९५७-५८ में १,१०,१५३ लोगो को रोजगार मिला।

तीसरी योजना—१९५८ के अन्तिम भाग में श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि “तीसरी योजना में लघु उद्योगों पर बल देना ही होगा।” हाल ही में शास्त्री ने कहा है कि “सरकार तीसरी योजना की अवधि में लघु उद्योगों की स्थापना के लिये ५ अरब से लेकर ६ अरब रुपये तक की रकम निर्धारित करना चाहती है।”

खार्च समिति रिपोर्ट—यह समिति जून १९५५ में नियुक्त की गई थी। इस समिति को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर एक योजना तैयार करनी थी—

(१) वे चीजें, जिनकी सर्वसाधारण में मांग हो, द्वितीय योजना काल में अधिकतर कुटीर उद्योगों द्वारा बनाई जायें।

(२) इन उद्योगों द्वारा रोजगार निरन्तर बढ़ता रहे।

(३) इन उद्योगों का उत्पादन व बिक्री सहकारी ढङ्ग पर हो।

इस रिपोर्ट की मोटी-मोटी बातों को मानकर द्वितीय योजना में उनको सम्मिलित कर लिया गया है।

इस समिति द्वारा दिये गये सुझावों का पहला उद्देश्य यह है कि उत्पादन के नये साधनों को ग्रहण करने के कारण पूँजी व श्रम में जो बेरोजगारी फैलनी है उसको ठीक तथा योजनाबद्ध ढङ्ग से दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। इसका दूसरा उद्देश्य यह है कि जो मजदूर बेरोजगार है या जिनको पूरे समय काम नहीं मिलता उनको अधिक से अधिक रोजगार उन उद्योगों में मिल जाये जिनको उन्होंने अपने घर में रह कर सीखा है या जिनके चलाने के लिये उनके पास पर्याप्त मात्रा में समान है।

कुटीर व छोटे पैमाने के उद्योगों की उन्नति सहकारी ढङ्ग को अपनाने से ही हो सकती है। इन उद्योगों को कुछ समय तक अचल व चल पूँजी राज्यों की देनी पड़ेगी, राज्य वित्त कारपोरेशनों को इन उद्योगों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं के लिये ऋण देना पड़ेगा। चालू आवश्यकताओं के लिये सहकारी केन्द्रीय वित्त सस्थाओं द्वारा ऋण दिये जायेंगे और यह प्रयत्न किया जायगा कि इन ऋणों को उसी प्रकार दिया जाये जिस प्रकार कि फसलों को ऋण दिया जाता है। वे ग्राम उद्योग जो सहकारी ढङ्ग पर चल रहे हैं उनको ऋण देने की रिजर्व बैंक पर ही जिम्मेदारी होगी जो कि उस पर कृषि साख देने की है।

खार्वे समिति ने सुझाव दिया है कि अखिल भारतीय ६ बोर्डों के कार्य का एकीकरण करने तथा केन्द्र द्वारा बनाई हुई योजनाओं को जिला, ताल्लुका व ग्रामो तक पहुँचाने के लिये एक अलग मन्त्रालय स्थापित किया जाये। कुछ लोगों का सुझाव है कि बड़े व छोटे उद्योगों में एकीकरण स्थापित करने के लिये केवल एक ही मन्त्रालय होना चाहिये। आजकल खार्वे समिति के सुझावों के साथ-साथ एक अलग मन्त्रालय स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार हो रहा है।

बड़े पैमाने के उद्योग

Q. 51. What are the causes of Industrial backwardness of India ? How would India benefit by the industrial development ?

प्रश्न ५१—भारत के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये होने के क्या कारण हैं ? भारत को औद्योगिक उन्नति से क्या लाभ हैं ?

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने का अर्थ—भारतवर्ष में बड़े पैमाने के उद्योग १९ वीं शताब्दी के मध्य के पश्चात् से चलने आरम्भ हुये हैं। उस दिन से हमारे देश में निरन्तर उद्योगों की उन्नति हुई है जिसके फलस्वरूप आज भारतवर्ष ससार के सब देशों में औद्योगिक विकास की दृष्टि से आठवाँ नम्बर लिये हुए है। फिर भी हमें यह बात कहनी पड़ेगी कि हमारा देश औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। ऐसा हम निम्नलिखित बातों के कारण कहते हैं—

(१) हमारे देश में १९५१ की जनगणना के अनुसार लगभग ७० प्रतिशत लोग खेती पर लगे हुये हैं और केवल ११ प्रतिशत खानों व उद्योग-धन्धों में लगे हुए हैं। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय आय की लगभग ५० प्रतिशत आय खेती तथा सहायक उद्योगों से प्राप्त होती है और केवल १६ प्रतिशत आय खानों, कुटीर उद्योगों से प्राप्त होती है। इस बात से देश का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ होना प्रत्यक्ष है।

(२) हमारे देश में सब प्रकार के उद्योग-धन्धे नहीं हैं। यहाँ पर केवल वही उद्योग हैं जिनमें लाभ अधिक होने की सम्भावना है जैसे सूती वपड़े, चीनी आदि के उद्योग, शेष उद्योग, जिनमें आधारभूत उद्योग सम्मिलित हैं, इस देश में प्रायः नहीं हैं। आज भी हमको मशीनों के पुर्जों, भारी रासायनिक पदार्थों आदि के लिये विदेशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है।

(३) देश के विस्तार व प्राकृतिक साधनों को देखते हुये अभी तक इस देश में उद्योग-धन्धों की बहुत कम उन्नति हुई है।

(४) आज भी हमारे देश में टेक्नीकल और रासायनिक विशेषज्ञों, इंजीनियरों आदि की बड़ी कमी है। ये हमको बड़े-बड़े वेतन देकर विदेशों से बुलाने पड़ते हैं। इसका कारण यह है कि इस प्रकार के लोगों को तैयार करने के लिये हमारे देश में उचित प्रशिक्षण (Training) का प्रबन्ध नहीं है।

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण—

हमारे देश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए होने के निम्नलिखित कारण हैं—

(१) सरकार का उद्योगों की ओर सौतेली-मा वाला व्यवहार—जिस समय से हमारे देश में उद्योग-धन्धों की उन्नति हुई है उस समय से पहले से ही यहाँ पर विदेशी शासन था। इस शासन को देश की औद्योगिक उन्नति में कोई दिल-चस्पी न थी। इसका सदा यह प्रयत्न रहा कि यह देश पक्के माल का आयात कर्त्ता तथा कच्चे माल का निर्यातकर्त्ता बन जाए। इस कारण सरकार ने कभी भी उद्योगों की उन्नति की ओर ध्यान न दिया। प्रथम महायुद्ध तक के देश अवाप्त व्यापार (Free Trade) की नीति पर था जिसके फलस्वरूप सब प्रकार का पक्का माल सस्ते दामों पर इस देश में आता था और उसी के कारण यहाँ के उद्योग-धन्धे पनपने नहीं पाते थे। यही नहीं सरकार अपनी आवश्यकता के लिए जो करोड़ों रुपए का माल खरीदती थी वह सब इंग्लैंड से आता था। यदि वह माल भारत वर्ष से खरीदा जाता तो इस देश के बहुत से उद्योग-धन्धे पनप जाते। इसके अतिरिक्त सरकार ने इस देश में तकनीक-प्रशिक्षण का कोई प्रयत्न नहीं किया जिसके कारण हमारे देश में कारखानों आदि को चलाने के लिये योग्य इन्जीनियर आदि उत्पन्न न हो सके। इस देश में सबसे पहले प्रथम महायुद्ध में सरकार ने यह बात अनुभव की कि इस देश में उद्योग धन्धों की उन्नति होने से सरकार को बहुत लाभ हो सकता है। इस कारण युद्ध समाप्त होने पर सरकार ने अवाप्त व्यापार की नीति को छोड़कर सञ्चरण की नीति को अपनाया। पर क्योंकि सुरक्षण की नीति भी उदार न थी इस कारण वहाँ पर उद्योग-धन्धों की बहुत अधिक प्रगति न हो सकी परन्तु फिर भी वहन से अधिक थी।

(१) पूँजी की कमी—अब से कुछ वर्ष पूर्व तक भारतीय पूँजी को शर्मिली कहा जाता था। इसका कारण यह था कि पूँजीपति लाभ की अनिश्चितता के कारण उद्योग धन्धों में अपनी पूँजी लगाने को तैयार न थे। देश के पूँजीपतियों के आगे न बढ़ने के कारण विदेशियों ने इस देश में कई प्रकार के कारखाने चलाए। आज भी अधिकतर जूट मिलों में विदेशी पूँजी लगी हुई है। सूती कपड़े का उद्योग भी, भिसमें आज पूर्ण रूप से भारतीय पूँजी लगी हुई है, विदेशियों द्वारा ही इस देश में चालू किया गया। इस प्रकार हमारे देश में विदेशी पूँजी का अनुमान ८०० से १२०० करोड़ रु० तक किया गया है। आजकल भारतीय पूँजी के औद्योगिक क्षेत्र में जा जाने पर भी हमारे देश की पूँजी की कमी पूरी नहीं हुई है। विदेशी सहायता न मिलने के कारण हमारी पञ्चवर्षीय योजना के पूरा होने में कठिनाई पड़ी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूँजी की कमी हमारे देश की औद्योगिक प्रगति में बड़ी बाधा है।

५ (३) सस्ती शक्ति की कमी—भारत में शक्ति के साधनों में कोयला ही अभी तक मुख्य है क्योंकि पेट्रोल इस देश में निक्कलता नहीं और बिजली शक्ति

अभी हाल ही में प्राप्त की गई है और वह देश की आवश्यकता को देखते हुए बहुत ही कम है। रही कोयले की बात, वह भी इस देश में अधिक नहीं निकाला जाता। यहाँ पर घाटिया प्रकार का कोयला पाया जाता है और इसका भी देश के सब भागों में वितरण नहीं है। सब कोयला छोटा नागपुर के प्लेटों में में केन्द्रित है। इस स्थान से दूर-दूर के स्थानों तक इसको सस्ते दामों पर भी नहीं पहुँचाया जा सकता क्योंकि हमारे देश में रेल का भाड़ा बहुत अधिक है। यही कारण है कि कारखानों का पक्कि के अभाव में चमना कठिन है।

5(४) कुशल धन की कमी—उद्योग धन्धों को चलाने में जहाँ एक ओर साधारण मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ दूसरी ओर कुशल मजदूरों की भी आवश्यकता पड़ती है। पर यद्यपि इस देश में रोजगार की तालाश में फिरने वाले लोगों की कमी नहीं है परन्तु उनमें से बहुत कम ऐसे हैं जो कुशल हैं। इस कमी के कारण उद्योग धन्धों को चलाने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है।

6(५) योग्य व्यवस्थापकों की कमी—हमारे देश में योग्य व्यवस्थापकों की भी बड़ी कमी है। इस देश में इस प्रकार के लोगों को तैयार करने के लिये प्रशिक्षण का कोई प्रयत्न नहीं है। अभी हाल ही में हमारे देश के लोग विदेशों में जाकर इस प्रकार की प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं। पर इस प्रकार कितने लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और वे किस प्रकार सारे देश की आवश्यकता पूर्ति कर सकते हैं। यही कारण है कि हमको अपने कारखानों में बड़-बड़े पदों पर विदेशी व्यवस्थापकों को रखना पड़ता है और उनको बड़-बड़े वेतन देने पड़ते हैं। योग्य व्यवस्थापकों की कमी के कारण भी हमारे देश के औद्योगिक विकास में बड़ी बाधा पड़ी है।

3(६) कच्चे माल की कमी—हमारे देश में कच्चे माल की भी कमी पाई जाती है। आज भी हमको अपना सूनी मिलों के लिए लम्बे रेंचें वाली खई, छूट मिल के लिए छूट आदि विदेशों से मगाना पड़ता है और उसके कारण हमारे सामान का प्रति इन्फाई उत्पादन व्यय बढ़ जाता है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारी प्रतियोगी शक्ति कम हो जाती है। यही नहीं, यदि हम छूट के सामान के लिए विदेशों से कच्चा माल मगाने से अवाफल हो जाते हैं तो हमको अपनी मिलों को बन्द करनी पड़ती है।

7(७) रेल भाड़े की नीति—हमारे देश में रेल भाड़े की नीति भी हमारी औद्योगिक उन्नति में बाधक रही है। यहाँ पर रेलों का भाड़ा बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त यदि कच्चा माल बन्दरगाहों को भेजा जाता है तो उस पर भाड़ा वम है परन्तु यदि यही माल देश के एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र तक भेजा जाता है तो उस पर अधिक भाड़ा लिया जाता है। इस नीति के कारण हमारे देश में बन्दरगाहों पर ही बहुत से उद्योग केन्द्रित हो गये हैं और देश के भीतर के केन्द्रों में उद्योग-धन्धे उत्पन्न न हो सके।

औद्योगिक उन्नति के लाभ—यदि हमारे देश की औद्योगिक उन्नति होती है तो उससे निम्नलिखित लाभ होने की आशा है—

(१) संतुलित-अर्थ-व्यवस्था—यह बात हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे देश के लगभग ७० प्रतिशत लोग खेती पर लगे हुए हैं। यह हमारे देश के लिये दुर्भाग्य की बात है। यदि किसी वर्ष मानसून फेल हो जाता है तो देश के ऊपर बड़ा सकट आ जाता है। ऐसी स्थिति में यदि देश में बड़े-बड़े उद्योग धन्धों की उन्नति हो जाये तो देश के बहुत से लोग खेती से हटकर उद्योग-धन्धों में लग जायेंगे। इस प्रकार भूमि पर से जनसंख्या का दबाव कम हो जायेगा। इससे खेती की अवस्था ठीक हो जायेगी। देश को इससे यह लाभ होगा कि खेती की अनिश्चितता के कारण जो कष्ट उठाना पड़ता है वह कष्ट कम हो जायेगा।

(२) राष्ट्रीय आय में वृद्धि—उद्योग धन्धों के उन्नत होने पर देश की राष्ट्रीय आय बहुत बढ़ जायेगी। राष्ट्रीय आय बढ़ जाने का कारण जनसाधारण का जीवन-स्तर ऊँचा हो जायेगा। जीवन-स्तर ऊँचा होने पर लोगों की कार्यक्षमता बढ़ जायेगी। कार्य क्षमता बढ़ जाने पर देश में अधिक उत्पत्ति होगी। इस प्रकार देश को बड़ा लाभ होगा।

(३) कर देने की योग्यता में वृद्धि—राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर देश के लोगों की कर देने की योग्यता बढ़ जायेगी। इसके कारण सरकार की आय भी बढ़ जायेगी। आय बढ़ जाने पर सरकार की बहुत सी योजनाएँ जो अब धन की कमी के कारण पूरी नहीं हो पाती वे भी पूरी हो जायेंगी।

(४) बेरोजगारी की समस्या का मुलझना—उद्योग धन्धों के उन्नत होने के कारण हमारे देश के हजारों लोग जो आज बेरोजगार फिर रहे हैं उनको रोजगार मिल जायेगा। इस प्रकार सरकारी नौकरी पर निर्भरता बहुत कुछ कम हो जायेगी।

(५) खेती की उन्नति होना—उद्योग धन्धों की उन्नति के होने से खेती को लाभ होगा। यह लाभ इसलिये ही नहीं होगा कि खेती पर से जनसंख्या का दबाव कम हो जायेगा बल्कि इसलिये भी होगा कि खेती सम्बन्धी औजार भी उन्नत हो जायेंगे और इससे खेती की उन्नति होगी।

(६) देश की रक्षा की दृष्टि से लाभ—उद्योग धन्धों की उन्नति के कारण देश शक्तिशाली हो जायेगा क्योंकि देश में ही युद्ध सम्बन्धी सामग्री तैयार होने लगेगी। आजकल के युग में जबकि सारे ससार में हथियार बनाने की दौड़ लगी हुई है यह देश बहुत अत्यन्त कमजोर है। अतएव कामजोरी, एक पाप है तथा यह शक्तिशाली को आक्रमण करने का प्रेरणादायक देती है। इसलिये यदि हम चाहते हैं कि हम तत्काल में सुख से रहे तो हमको युद्ध सामग्री तैयार करनी पड़ेगी। इसके लिये कारखानों की आवश्यकता है।

(७) लोगों में मितव्ययता की आदत का पड़ना—देश में उद्योग धन्धों की उन्नति होने से पूँजी की माग बढ़ जायेगी। इसके फलस्वरूप बैंकों आदि की उन्नति

बड़े पैमाने के उद्योग

होगी। बैंक के अधिकाधिक खुल जाने के कारण लोगो में खया वचाने की आदत पड़ जायेगी।

(८) सम्यता का विकास—उद्योग धन्धो की उन्नति के कारण देश में सम्यता का विकास होगा क्योंकि उद्योग धन्धो के कारण नगरो का विकास होता है और नगर सम्यता के केन्द्र होने है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमको औद्योगीकरण से लाभ अवश्य होगा। यहाँ यह बात बतानी आवश्यक है कि गांधी जी औद्योगीकरण के पक्ष में नहीं थे। वे इस देश में कुटीर उद्योगो की उन्नति चाहते थे। हम देश की वर्तमान स्थिति में कुटीर उद्योगो के महत्व को मानते हुए यह कह सकते हैं कि बड़े-बड़े उद्योग भी चलाने बहुत आवश्यक हैं क्योंकि इस औद्योगिक युग में केवल कुटीर उद्योगो पर निर्भर रहना हमारे लिये हितकर न होगा। हमारे प्रधान मंत्री श्री नेहरू भी देश के औद्योगीकरण के पक्ष में हैं।

Q 52 Describe the existing system of industrial finance in India and make suggestion for its development in the future
प्रश्न ५२—भारत की वर्तमान औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था का वर्णन कीजिये और भविष्य में इसकी उन्नति के लिये सुझाव दीजिये।

बड़े-बड़े उद्योगो की द्रव्य सम्बन्धी आवश्यकता दो प्रकार की होती है। पहली, भारी पदार्थों को प्राप्त करने सम्बन्धी आवश्यकता—इसमें भूमि, मशीन, इमारत, फर्नीचर आदि खरीदने के लिये धन की आवश्यकता होती है। दूसरी, दैनिक कार्यों को चलाने सम्बन्धी आवश्यकता—इसमें कच्चा माल, कोयला आदि खरीदने व मजदूरो को मजदूरी देने की आवश्यकता आती है। इनमें से दूसरी प्रकार की आवश्यकता साधारणतया व्यापारिक बैंको द्वारा पूरी हो जाती है परन्तु पहली प्रकार की आवश्यकता की पूर्ति के लिये विशेष प्रकार की संस्थाओं, जिनको औद्योगिक बैंक कहते हैं, की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार की आवश्यकता पूर्ति के लिये प्राय सभी देशो में ऐसी संस्थाएँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की संस्थाओं के कुछ उदाहरण फ्रांस में बैंक डी पैरिस, अमरीका में इश्यू हाउसेज, जर्मनी में प्रोस बैंक, इङ्गलैण्ड में ब्रिटिश ट्रेड कॉर्पोरेशन आदि हैं। भारतवर्ष में १९४८ ई० से औद्योगिक अर्थ प्रमदल (Industrial Finance Corporation) की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी।

भारतवर्ष में वर्तमान औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था—

भारतवर्ष में उद्योगो की अग्रलिखित ढग से आर्थिक सहायता प्राप्त होती है—

(१) हिस्सो तथा ऋण पत्रों से—बड़े-बड़े उद्योग अपनी पूँजी को हिस्से तथा ऋण पत्र बेचकर प्राप्त करते हैं। इनमें से हिस्सो द्वारा अधिकतर पूँजी प्राप्त की

जाती है और ऋण पत्रों द्वारा बहुत कम। इसका कारण यह है कि हमारे देश में लोगों को अधिक समय तक के लिये अपना रुपया लगाने में डर लगता है। इसके अनिश्चित यहाँ पर बैंक इनमें अपना धन लगाने को तैयार नहीं हैं। यहाँ पर ऋण पत्रों के हस्तान्तरित करने पर बहुत भारी स्टाम्प कर लगता है। अन्त में यह बात भी है कि इस देश में ऐसी कोई संगठित संस्था या संघ नहीं है जो कि ऋण पत्रों को उठाने का कार्य करे। यदि हमारे देश में पूँजी ऋण पत्रों द्वारा प्राप्त हो जाता करता तो उद्योगों को अपनी अचल सम्पत्ति सम्बन्धी आवश्यकता का पूरा करने में कोई कठिनाई उपस्थित न होती। परन्तु ऋण पत्रों से पर्याप्त मात्रा में धन न मिल सकने के कारण हमारे देश में एक विशेष प्रकार की पद्धति का जन्म हुआ जिसको मैनेजिंग एजेंसी कहते हैं।

मैनेजिंग एजेंट—ये एक व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी हो सकते हैं। इनके साधन बहुत अधिक होते हैं। इन साधनों के फलस्वरूप ही उन्होंने भारत की बहुत सी कम्पनियों को चलान में सहायता दी और समय समय पर उनकी ओर भी सहायता करते रहते हैं। इस प्रकार उनके निम्नलिखित कार्य हैं—

(अ) वे उद्योगों को चलाते हैं।

(आ) वे औद्योगिक कम्पनियों के हिस्से देवने में सहायता करते हैं और यदि वे आवश्यकता से कम बिकते हैं तो उनको स्वयं खरीद लेते हैं।

(इ) वे उद्योगों की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति या तो स्वयं कर देते हैं या उसको प्राप्त कराते हैं।

यद्यपि मैनेजिंग एजेंट भारत के उद्योगों की इतनी सहायता करते हैं तो भी हम यह कहे बिना नहीं रह सकते हैं कि उन दोषों के कारण जो उनमें आ गये हैं वे लाभप्रद के स्थान पर हानिकारक हो जा रहे हैं। इन दोषों के कारण ही १९२६ के संशोधित भारतीय कम्पनीज ऐक्ट में तथा अभी हाल ही में उनके कार्य के ऊपर बहुत ही पाबन्धियाँ लगा दी गई हैं।

मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली का उन्मूलन

कम्पनी विधेयक के सम्बन्ध में नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति के सुझाव के अनुसार, जिसकी रिपोर्ट संसद में उपस्थित की गई थी, भारतीय संसद ने मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली के वर्तमान स्वरूप को समाप्त कर देने का निश्चय किया है। इस निश्चय के अनुसार विशिष्ट उद्योगों को छोड़कर शेष सभी में मैनेजिंग एजेंटों को १५ अगस्त १९६० से पदच्युत कर दिया जायेगा। इसके बाद केवल उन्हीं व्यक्तियों को मैनेजिंग पद पर नियुक्त किया जायेगा जो सरकार की दृष्टि में इसके लिये उपयुक्त और योग्य समझे जायेंगे। स्पष्ट है कि समिति के सुझावों को मान कर संसद ने एक बात साफ कह दी है कि वह मैनेजिंग एजेंसी प्रणाली को समाप्त नहीं करना चाहती। उसकी उपयोगिता में उसका विश्वास अब भी है। यह भी

निश्चय हुआ है कि किसी एक मैनजिंग एजेंट के जिम्मे १० से अधिक कम्पनियां नहीं होंगी। यह सत्या किम आधार पर निश्चिन की गई है, यह स्पष्ट नहीं है। उचित तो यही था कि उद्योगों के वयक्तिक क्षेत्र में उनकी आवश्यकता को देखकर उनके वर्तमान रूप में कोई सुधार कर दिया जाता।

(३) डिपोजिट—वम्बई तथा अहमदावाद की मृती कपडे की मिलें बहुत सा धन जान पहचान के लोगों से जमा के रूप में प्राप्त करती हैं। इनके बदले मिल मालिक जमा करने वालों को उसी के हिसाब से लाभांश देने हैं। परन्तु धन प्राप्त करने का यह ढङ्ग सन्तोषजनक नहीं है क्योंकि जमा करने वाला उसको किसी भी समय मांग सकता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी आर्थिक सकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

(४) व्यापारिक बैंक—व्यापारिक बैंक उद्योग-धन्यों की सहायता खुले दिल से नहीं करते। इस मामले में वे इम्पीरियल बैंक जिसका नाम अब बदल कर स्टेट बैंक हो गया है के पद चिन्हों पर चलते हैं जो कि उद्योगों को बहुत कम सहायता प्रदान करता है। जब य बैंक उद्योगों की सहायता करने हैं तो वे धरोहर के मूल्य का केवल ५० प्रतिशत ही ऋण के रूप में देते हैं। यह ऋण भी केवल ३-४ महीने के लिये दिया जाता है। अबल सम्पत्ति आदि के खरीदन के लिय बैंक कोई धन उधार नहीं देते। इस प्रकार हमारे देश में अबल सम्पत्ति को खरीदन के लिय उद्योगों को दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है।

(५) औद्योगिक बैंक—भारतवर्ष में औद्योगिक बैंकों का प्रायः अभाव सा है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसे बैंकों के स्थापित करने का कभी प्रयत्न नहीं हुआ। इस प्रकार के कई प्रयत्न प्रथम महायुद्ध में हुए। इसमें टाटा औद्योगिक बैंक १९१७ में, कलकत्ता औद्योगिक बैंक १९१९ में, भारतीय औद्योगिक बैंक १९२० में लक्ष्मी औद्योगिक बैंक १९२३ में स्थापित किये गये। परन्तु य बैंक सट्टेबाजी तथा औद्योगिक वक्त्रिय के सिद्धान्तों को ठीक प्रकार न अपनाने के कारण अपने कार्य में सफल न हो सके। आजकल हमारे देश में कोई बड़ा औद्योगिक बैंक नहीं है। इस कमी के कारण उद्योगों को अबल सम्पत्ति प्राप्त करने के लिय किसी स्थान से धन नहीं मिलता।

(६) औद्योगिक वित्त निगम—उद्योगों के लिये हमारे देश में दीर्घकालीन अर्थ व्यवस्था न होने की बात सबसे अस्पष्ट थी। इस कमी को पूरा करने के लिय भारत सरकार ने १९४८ में एक औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की। इसका कार्य १ जुलाई १९४९ से चालू हो गया है। इसकी पूंजी १० करोड़ है। इसके अतिरिक्त इसको ऋण पत्रों को जारी करने का भी अधिकार है। इस प्रमण्डल^१ के निम्नलिखित कार्य हैं—

(अ) औद्योगिक संस्थाओं के द्वारा उधार दिये हुये उन दीर्घकालीन ऋणों की गारन्टी करना जो अधिक से २५ वर्ष की अवधि के लिय पूंजी बाजार में प्राप्त किये गये हैं।

(आ) औद्योगिक सस्थाओं द्वारा निर्मित किये हुये स्टावो, हिस्सो, ऋण पत्रों आदि का अभिगोपन (Underwrite) करना ।

(इ) अभिगोपन किये हुये हिस्सो, ऋण-पत्रों आदि को यदि जनता ने तुरन्त न खरीदा हो तो इन्हे इनकी प्राप्ति से अधिक से अधिक ७ वर्ष के अन्दर रख कर बेच देना ।

(ई) औद्योगिक सस्थाओं को इस प्रकार के ऋण देना अथवा उनके ऋण-पत्रों को खरीदना जिनका भुगतान २५ वर्ष के अन्दर होने वाला है ।

(उ) अन्य उन सारे कार्यों को करना जो कि उद्योगों के नामों से सम्बन्धित हैं तथा प्रमण्डल को अपने अधिकारों तथा उत्तरदायित्वों को भली भाँति पूरा करने के लिये आवश्यक है ।

जैसा ऊपर बताया गया है कि इस वित्त निगम को कार्य करते हुए लगभग ११ वर्ष हो गये हैं । इस बीच में इसने मात्र १९५८ ई० तक ५७४२ करोड़ के ऋण मञ्जूर किये जिसमें से ३२०३ करोड़ के ऋण वास्तव में बाट दिये गये । इन पर ६ प्रतिशत व्याज लिया जाता है । इस निगम ने टेक्सटाइल, रासायनिक विद्युत, शीशे, चीनी, सीमेंट आदि के उद्योगों को आर्थिक सहायता दी है । इस निगम के कार्यालय कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा कानपुर में हैं । इसके अतिरिक्त भारत में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम तथा औद्योगिक साख तथा वित्त निगम भी स्थापित किये गये हैं । इनमें से पहला सरकारी पूँजी तथा दूसरा निजी पूँजी द्वारा स्थापित किया जायगा । पहला निगम १ करोड़ पूँजी से चालू किया गया है । यह सरकारी योजनाओं को सहायता प्रदान करेगा । दूसरे निगम की पूँजी ५ करोड़ है । इसमें से ३३ करोड़ भारतीय द्वारा तथा १२ करोड़ विदेशियों द्वारा लगाई जायगी । इस दूसरे निगम की द्वितीय वार्षिक बैठक में इसके सभापति डाक्टर रामास्वामी मुदालियर ने कहा था कि हम केवल ऋण देने का कार्य नहीं करते बल्कि हमने बहुत से हिस्सों का अभिगोपन (Underwriting) ही नहीं किया बल्कि बहुत सी कम्पनियों की हिस्सा पूँजी भी खरीदी है । १९५७ ई० के अन्त तक निगम ने ११६५ करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की । इनमें से ५४४ करोड़ रु० ऋणों के रूप में तथा ६२१ करोड़ रुपय हिस्सों तथा ऋण-पत्रों के अभिगोपन के रूप में प्रदान किया गया । इस ऋण से कागज उद्योग, रासायनिक उद्योग, बिजली का सामान बनाने वाले उद्योगों, टेक्सटाइल उद्योगों, चीनी उद्योग, बच्ची धातु उद्योग, चूना तथा सीमेंट के कार्य, शीशा बनाने वाले उद्योगों आदि को लाभ पहुँचा है । १९५७ ई० में जिन ३५ प्राजेक्ट्स को इस निगम से लाभ पहुँचा उनमें १६ नये थे । परन्तु १९५७ ई० में मञ्जूर किये हुये ऋणों में से केवल १९ करोड़ रुपये बाटे गये । अभिगोपन किये गये ऋण में से केवल २१ करोड़ रु० में निगम ने अपना धन लगाया । जहाँ १९५६ में निगम का लाभ ४३ लाख रु० था वहाँ १९५७ में वह बढ़ कर ५४ लाख रु० हो गया ।

केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार के प्रमण्डल स्थापित करने की आज्ञा राज्यों को दे दी है। पश्चिमी बंगाल, बिहार, बम्बई, उत्तर प्रदेश, आसाम, हैदराबाद, सौराष्ट्र, त्रिखुर, कोचीन आदि १३ राज्यों में भी ऐसे प्रमण्डल स्थापित करने की घोषणा कर दी गई है।

भारत सरकार ने अभी १९५७ ई० में निश्चय किया है कि वह मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयों को सहायता के लिये एक पुनर्वित्तीय कारपोरेशन (Re-Finance Corporation) की स्थापना करेगी। इस कारपोरेशन में भाग लेने के लिये देश के १५ बड़े-बड़े बैंकों को नियन्त्रण दिया गया था। यह कारपोरेशन एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में स्थापित किया जायेगा। यह १२५ करोड़ की साधारण पूँजी (Ordinary Capital) से स्थापित किया जायेगा। यह पूँजी आगे चलकर बढ़ाई जा सकती है। इस पूँजी में से ५ करोड़ रिजर्व बैंक, २५ करोड़ स्टेट बैंक, २५ करोड़ भारतीय बैंक, २५ करोड़ अन्य बैंक लेंगे।

यह ६० प्राप्त होने की आशा है। परन्तु भारत के वित्त मंत्री टी० टी० सनमार्ग ने अभी हाल ही में अमेरिका में कहा है कि हमारे विदेशी विनिमय के करोड़ २००० मिलियन की डालर की खाई है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत वर्ष १ देश ने जो भारत की आर्थिक उन्नति की छः वर्षीय योजना दी है उसमें भी विदेशी पूँजी की आवश्यकता ६० करोड़ ७० लाख पौण्ड बताई गई है। श्री जी० डी० बिडला की अध्यक्षता में भारत का जो औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस तथा पश्चिमी जर्मनी में गया था उसका मत है कि उन्नति करने के लिये भारत को कम से कम अगले २५ वर्षों में बहुत अधिक मात्रा में विदेशी पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे देश की आर्थिक उन्नति की जो भी योजना बनाई जाती है उसमें विदेशी पूँजी की आवश्यकता अनुभव की जाती है।

सन्मार्ग के जन-योजना विरोधियों ने दिये एक लेख में श्री बी० एम० बिडला विदेशी पूँजी की आवश्यकता इस प्रकार बताते हैं, “अभी हमारी राष्ट्रीय आय १२०० करोड़ रुपये है। इनमें से लगभग २५०० करोड़ ६० मूल्य के समान कारखानों में उत्पादित होते हैं। शेष आय में समानता लाने के लिये भी हमें कारखानों के उत्पादन में प्रतिवर्ष वृद्धि करनी होगी। प्रतिवर्ष १०,००० करोड़ रुपये मूल्य के समान उत्पादन के लिये उत्पादक प्रतिष्ठानों में लगभग २५००० करोड़ रुपये नियोजित करने पड़ेंगे। जब हम २५००० करोड़ रुपये पूँजी नियोजन की बात सोचते हैं जिसका ४० प्रतिशत विदेशी विनिमय पर आधारित है तो इसे प्राप्त करने का उपाय क्या है। विश्व में अमेरिका एक ऐसा देश है जो हमारी सहायता कर सकता है। परन्तु आसानी से यह धन राशि प्राप्त करना संभव नहीं। इसके लिये अमेरिकी उद्योगपतियों को आकृष्ट करना होगा जिससे वे हमारे देश में पूँजी लगायें। यहाँ लगाना उनके लिये सुरक्षित है। यह उन्हें समझाना है। इसके लिये आवश्यक

सकते। कुछ लोगों का विश्वास है कि हमारे देश में इतनी पूँजी मौजूद है कि हमको विदेशी पूँजी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ सकती। उनका यह कहना ठीक प्रतीत नहीं होता। इसके २ कारण हैं—पहला कारण यह है कि हमारे देश में आज इतनी समस्याएँ सुलझाने के लिये पड़ी हैं कि हम केवल अपने देश की पूँजी से काम नहीं चला सकते। देश में अभी तक जो भी योजनाएँ बनी हैं उन सबमें विदेशी पूँजी की आवश्यकता बताई गई। जैसे वम्बई योजना में विदेशी पूँजी की आवश्यकता ७०० करोड़ रुपये बताई गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि इस बात के कहने से कोई लाभ न होगा कि यदि, भारतवर्ष इतनी गति से आगे बढ़ना चाहता है जिससे प्रजातन्त्रिक सत्ताओं को बिना कोई क्षति पहुँचाये यह देश का अधिकतर जनसंख्या के जीवन-स्तर को बहुत जल्दी ही ऊँचा उठा दे ता उसको कुछ वर्षों तक दुनिया के उन्नत देशों से सहायता लेनी पड़ेगी। अग्री तक विदेशी पूँजी की सहायता से हमको ५८ करोड़ ६० प्राप्त हुई तथा दूसरी योजना में ८०० करोड़ ६० प्राप्त होने की आशा है। परन्तु भारत के वित्त मंत्री टी० टी० कृष्णामाचारी ने अभी हाल ही में अमेरिका में कहा है कि हमारे विदेशी विनिमय के माध्यमों में २००० मिलियन की डालर की खाई है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गतारे देश ने जो भारत की आर्थिक उन्नति की छः वर्षीय योजना दी है उसमें भी विदेशी पूँजी की आवश्यकता ६० करोड़ ७० लाख पाउण्ड बताई गई है। श्री जी० डी० बिडला की अध्यक्षता में भारत का जो औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल संयुक्त एश्ट्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस तथा पश्चिमी जर्मनी में गया था उसका मत है कि उन्नति करने के लिये भारत को कम से कम अगले २५ वर्षों में बहुत अधिक मात्रा में विदेशी पूँजी की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे देश की आर्थिक उन्नति की जो भी योजना बनाई जाती है उसमें विदेशी पूँजी की आवश्यकता अनुभव की जाती है।

सन्मार्ग के जन-योजना विशेषांक में दिये एक लेख में श्री बी० एम० विरला विदेशी पूँजी की आवश्यकता इस प्रकार बताते हैं, “अभी हमारी राष्ट्रीय आय १२०० करोड़ रुपये है। इनमें से लगभग २५०० करोड़ ६० मूल्य के समान कारखानों में उत्पादित होते हैं। शेष आय में समानता लाने के लिये भी हमें कारखानों के उत्पादन में प्रतिवर्त वृद्धि करनी होगी। प्रतिवर्ष १०,००० करोड़ रुपये मूल्य के उमान उत्पादन के लिये उत्पादक प्रतिष्ठानों में लगभग २५००० करोड़ रुपये नियोजित करने पड़ेंगे। जब हम २५००० करोड़ रुपये पूँजी नियोजन की बात सोचते हैं जिसका ४० प्रतिशत विदेशी विनिमय पर आधारित है तो इसे प्राप्त करने का उपाय क्या है। विश्व में अमेरिका एक ऐसा देश है जो हमारी सहायता कर सकता है। परन्तु आसानी से यह धन राशि प्राप्त करना संभव नहीं। इसके लिये अमेरिकी उद्योगपतियों को आकृष्ट करना होगा जिससे वे हमारे देश में पूँजी लगायें। यहाँ पूँजी लगाना उनके लिये सुरक्षित है। यह उन्हें समझाना है। इसके लिये आवश्यक

वातावरण तैयार करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे जीवन स्तर में सुधार सम्भव नहीं।”

दूसरे, यदि हम अपने देश के भीतरी साधनों पर दृष्टि डालें तो हमको पता चलेगा कि हमारे देश में पूँजी की बहुत कमी है। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध काल में किसानों ने बहुत धन कमाया था परन्तु यह धन देश की औद्योगिक उन्नति के काम में नहीं आ सकता क्योंकि पहले तो बहुत सा धन किसान के जीवन स्तर को उठाने के लिये व्यय हो गया और जो कुछ बचा, उसमें उन्होंने पैतृक ऋण चुका दिया है। इस प्रकार उनके पास अधिक धन नहीं रह गया है। मजदूरों के पास भी इतना धन नहीं है कि वे देश के उद्योगों की उन्नति के लिये कुछ धन बचा सकें। मध्य श्रेणी के लोगों के पास भी सदा धन की कमी रहती है। पूँजीपति अपना बहुत सा धन उद्योगों में लगा रहे हैं। परन्तु यह धन भारत की वर्तमान आवश्यकता के लिये बहुत कम है। यदि इस देश में विदेशी पूँजी आ जाये तो उससे रोजगार, उत्पत्ति तथा आय सब बढ़ेंगे। भारत में उपभोग के पश्चात् बहुत कम ऐसा धन बचता है जिसको कि उद्योग धन्धों में लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त भारत में टेक्नीकल योग्यता तथा पूँजी वस्तुओं का अभाव है। इस कारण हमारे देश में विदेशी पूँजी की आवश्यकता भारत के लिये कोई नई चीज नहीं है। यदि हम बहुत से देशों की आर्थिक उन्नति के विषय में जानकारी प्राप्त करें तो हमको पता चलेगा कि उन सबकी उन्नति में विदेशी पूँजी सहायक सिद्ध हुई है।

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हमारे देश की आर्थिक उन्नति की योजनाएँ अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण लेकर पूरी की जा सकती हैं। परन्तु यह बात दो बातों की वजह से ठीक मालूम नहीं पड़ती। पहली बात तो यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के पास इतना धन नहीं है कि वह हमारी अधिक सहायता कर सके और दूसरी बात यह है कि यह बैंक मुख्यता यूरोपीय देशों की कम सहायता कर सकेगा। तीसरे इस बैंक की ब्याज की दर बहुत ऊँची है। इन सब बातों के होते हुए भी इस बैंक ने भारत को ४२५ मिलियन डालर की सहायता ऋण के रूप में प्रदान की है।

इन सब बातों से यह सिद्ध होता है कि हमारे देश की आर्थिक उन्नति के लिये विदेशी पूँजी की बहुत ही आवश्यकता है। इस आवश्यकता को प्रतीत करते हुए भी देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो विदेशी पूँजी का विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि विदेशी पूँजी के कारण हमारा देश, आर्थिक दृष्टि से विदेशों का दास हो जायेगा। इसी के कारण विदेशी लोग हमारे देश का धन लाभ के रूप में लूट कर ले जायेंगे। इसी के कारण विदेशी लोग हमारे देश के प्राकृतिक साधनों को अपने लाभ के लिये काम में लायेंगे। यही नहीं यह भी हो सकता है कि किसी समय विदेशी पूँजीपति इतने शक्तिशाली हो जायें कि वे देश की उन्नति की योजनाओं में बाधा म्प से खड़े हो जायें। यहाँ यह बात बताने योग्य है कि यह सब डर लोगों को इस लिये लग रहा है क्योंकि भूतकाल में अंग्रेजी पूँजी द्वारा सब बातें हो चुकी हैं।

परन्तु यदि हम विचार करें तो यह बात भली भाँति समझ में आ सकती है कि पहले वी और जय की स्थिति में बहुत अन्तर है। पहले हमारा देश अङ्गरेज का दास था। आज हम स्वतन्त्र हैं, इस कारण विदेशी लोग हमारे देश में मनमानी न कर सकेंगे। दूसरी पिछनी बातों को देखकर अब हमारी आँखें खुल गई हैं। इस कारण विदेशी लोग आसानी से हमारा शोषण न कर सकेंगे। इसलिये हम समझते हैं कि हमारे देश को आज विदेशी पूजा के शोषण से नहीं डरना चाहिये। इसके साथ-साथ विदेशी पूजा के शोषण से बचने के साधन भी हैं। इस पूजा को देश में आने की आज्ञा देने से पहले हम उनका ऊपर कुछ शर्तें लगा सकते हैं जिससे हम विदेशी पूजा के शोषण से भी बच सकें और साथ ही साथ वह पूजा हमारी आर्थिक उन्नति में सहायक भी सिद्ध हो। इन प्रकार की शर्तें निम्नलिखित हो सकती हैं—

(१) विदेशी कम्पनियाँ हमारे देश में ही चालू की जायें तथा वे इसी देश के कम्पनी ऐक्ट के अधीन कार्य करें। इससे यह लाभ हो सकता है कुछ समय परचात भारतवासी इनके सब हिस्से खरीद कर कम्पनी के मालिक बन सकते हैं।

(२) कम्पनी में भारतीय तथा विदेशी लोगों के हिस्से का अनुपात इस प्रकार हो कि भारतवासियों के हाथ में कम्पनी का प्रबन्ध हो। यह हो सकता है कि प्रारम्भ में बड़े-बड़े पदों पर विदेशी लोग रहें जायें परन्तु अन्त में भारतवासियों को ही वे पद मिलने चाहियें।

(३) जो विदेशी कम्पनी भारत में कार्य करें उन पर यह भार हो कि भारत-वासियों की शिक्षा दें।

(४) सरकार एक निश्चित समय के पश्चात् जब चाहे उस कम्पनी को क्षति पूर्ति देकर मोल ले ले।

हम समझते हैं कि यदि इस प्रकार की कुछ शर्तें लगा दी जाय तो विदेशी पूजा हानि करने के बदले लाभ करेगी।

देश के स्वतन्त्र हो जाने के पश्चात् भारत सरकार ने १९४८ ई० में पूजा सम्बन्धी नवीन नीति निर्धारण की। इसके अनुसार जिस उद्योग में विदेशी पूजा लगाई जायगी उसमें प्रधान रूप से भारतीयों का ही स्वामित्व होगा तथा उस उद्योग के नियन्त्रण तथा प्रबन्ध आदि में भी भारतवासी ही प्रधान होंगे, हा यह हो सकता है कि उस समय तक के लिये जब तक कि भारतवासी बड़े पद ग्रहण करने योग्य हो सरकार यह आज्ञा दे दे कि कम्पनी का नियन्त्रण कुछ समय के लिये विदेशियों के हाथ में रहेगा। इसके अतिरिक्त सरकार इन उद्योगों को क्षति-पूर्ति देकर ले सकती है। इन उद्योगों पर यह भी भार है कि भारतवासियों को कुछ टैक्नीकल शिक्षा दे।

इन सब शर्तों के होते हुए हम यह आशा नहीं करते कि विदेशी हमको लूट कर ले जायेंगे। हमें तो यही समझते हैं कि विदेशी पूजा हमारे देश के लिये बहुत

ही आवश्यक है और इस कारण उसको देश की आर्थिक उन्नति व हित में आने देना चाहिये। भारत सरकार विदेशी पूँजी की आवश्यकता को अनुभव करती है। इसकी सम्भावना के लिये भारत के भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी यूरोप व अमेरिका गये थे और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि बहुत से विदेशी लोग भारत में अपना धन लगाना चाहते हैं परन्तु कुछ बातों के कारण व अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं।

यहाँ यह बात बताने योग्य है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में विदेशी पूँजी की आमद बहुत कम हुई है। इसका कारण यह था कि स्वतन्त्रता के पश्चात् विदेशियों को इस बात का पता न था कि भविष्य में भारत की आर्थिक तथा राजनैतिक उन्नति किस दिशा में होगी। इसके अतिरिक्त विदेशियों में यह भी तय था कि भारत के उद्योगों का शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण हो जायगा तथा भारत सरकार विदेशियों के साथ भेद-भाव की नीति को अपनायगी। इस कारण प्रथम योजना काल में ६०० करोड़ रुपये की विदेशी पूँजी के स्थान पर केवल १६७ करोड़ रुपये की पूँजी प्राप्त की जा सकी और यह पूँजी भी तब प्राप्त हुई जबकि भारत सरकार ने विदेशियों को यह आश्वासन दिया कि वह भारतीय तथा विदेशी पूँजी में कोई भेद-भाव न करेगी तथा विदेशियों को अपना लाभ अपने देशों में भेजने की पूरी सुविधाय दी जायगी तथा यदि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा तो उनको मुआवजा देकर प्राप्त किया जायगा। श्री बङ्कर जो भारत में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राजदूत हैं यह बताते हुए कि भारत में संयुक्त राष्ट्र की पूँजी के लिये अच्छा क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि इस पूँजी के लिये अच्छा वायुमण्डल निर्माण करने के लिये तीन बातों की आवश्यकता है—(१) अपरिवर्तनशीलता अथवा विदेशी उद्योगों को उखाड़ कर फेंकने से बचत, (२) दोहरे कर से रक्षा तथा (३) कर से छुटकारा। यह आवश्यक है कि भारत सरकार विदेशी पूँजी को देश में आकर्षित करने के लिये आवश्यक वायुमण्डल निर्माण करे।



Q 55 What is the present industrial policy of the Government of India ?

प्रश्न ५५—भारतीय सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति क्या है ?

जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी इस देश में आई तो उसने यहाँ के उद्योग धन्धों को बहुत प्रोत्साहन दिया। परन्तु अङ्गरेजी लोक सभा में इस बात की कड़ी आलोचना हुई। इस कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अपनी नीति बदलनी पड़ी। इसके पश्चात् इसका कार्य भारत के कच्चे माल का निर्यात करना तथा विदेश में बन हुए पक्के माल का आयात करना रह गया। इस प्रकार इसने उद्योग धन्धों के विकास की ओर कुछ भी ध्यान न दिया।

भारत के सम्राट के हाथ में चले जाने के पश्चात् भी भारतीय सरकार ने इस ओर कुछ काम न किया। उसने हस्तक्षेप न करने की नीति को (Laissez Faire policy) ही अपनाये रखा। इस नीति के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों को विदेशों के साथ कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ी और भारतीय उद्योग पनप न सके।

प्रथम महायुद्ध में सरकार की आँखें खुली। युद्ध काल में विदेशों से सामान जाना बन्द हो गया। इसी कारण युद्ध के लिये भारतीय उद्योग-धन्धों के विकास की आवश्यकता पड़ी। १९१६ में औद्योगिक कमीशन की नियुक्ति हुई। इस कमीशन ने यह सुझाव दिया कि भारतीय उद्योग-धन्धों के विकास में सरकार को सहयोग प्रदान करना चाहिये। १९१७ में इण्डियन म्युनिशियन बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड के कार्यों से भारतीय उद्योग-धन्धों के विकास को अच्छी सहायता प्राप्त हुई। भारत में बहुत से नए उद्योगों की स्थापना की गई। युद्ध के समाप्त होने तक प्रायः सभी प्रान्तों में औद्योगिक विभाग (Department of Industries) खुल गये।

सन् १९१८ के मुधारों से यह बात मान ली गई कि भारतवर्ष को आर्थिक स्वतन्त्रता (Fiscal Autonomy) मिलनी चाहिये। इसीलिये १९२१ में पहला अर्थ कमीशन (Fiscal Commission) नियुक्त किया गया। इस कमीशन ने भारत के लिये एक विवेकात्मक संरक्षण नीति (Discriminating Protection Policy) का सुझाव, रखा। इसके अनुसार प्रत्येक उद्योग को संरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती थी वरन् ऐसे उद्योगों को हो सकती थी जो संरक्षण चाहता था। यह संरक्षण पूरी जाच के पश्चात् दिया जाता था। संरक्षण केवल उन्हीं उद्योगों को दिया जा सकता था जिनका एक घरेलू बाजार हो जिनके लिये देश में पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल तथा श्रम हो, जो संरक्षण बिना न चल सकते हों तथा जो कुछ समय पश्चात् इतने दृढ़ हो जायें कि वे बिना संरक्षण के अपने आप चल सकें। य सब बात बड़ी कड़ाई के साथ मानी गई। इस नीति के अन्तर्गत कुछ उद्योगों, जैसे लोहा तथा फौलाद, सूती वपड़ा, चीनी आदि को संरक्षण प्रदान किया गया। इस संरक्षण से इन उद्योगों की उन्नति तो हुई पर इतनी नहीं जितनी कि उदार अर्थ-नीति से हो सकती थी।

द्वितीय महायुद्ध में भारतवर्ष मित्रराष्ट्रों के प्रभावित महासागर के मोर्चे के लिये एक केन्द्र बना। इसके अतिरिक्त भारतीय सरकार को भी बहुत सी युद्ध-सामग्री की आवश्यकता हुई। इसी कारण सरकार ने उद्योगों को उन्नत करने में बहुत सहायता प्रदान की। सरकार ने यहाँ के युवकों को टैक्निकल शिक्षा ग्रहण करने के लिये इंग्लैण्ड भेजा। १९४० में सरकार ने यह घोषणा भी की कि यदि आवश्यक हुआ तो युद्ध काल के पश्चात् उन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जायगा जो युद्ध काल में उन्नत होंगे। सरकार ने १९४१ में एक ऐसी कमेटी नियुक्त की जो युद्ध समाप्त होने पर देश की आर्थिक स्थिति सुधारन में सहायक हो। इनक अनिश्चित भी सरकार ने ऐसे बहुत से कार्य किये जिनसे इस देश के उद्योग उन्नत हो।

ही आवश्यक है और इस कारण उसको देश की आर्थिक उन्नति के हित में देने देना चाहिये। भारत सरकार विदेशी पूँजी की आवश्यकता को अनुभव करती है। इसकी सम्भावना के लिये भारत के भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री टी० टी० कृष्णामाचारी यूरोप व अमेरिका गये थे और वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि बहुत से विदेशी लोग भारत में अपना धन लगाना चाहते हैं परन्तु कुछ बातों के कारण वे अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं।

यह बात बताने योग्य है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में विदेशी पूँजी की आमद बहुत कम हुई है। इसका कारण यह था कि स्वतन्त्रता के पश्चात् विदेशियों को इस बात का पता न था कि शक्ति में भारत की आर्थिक तथा राजनैतिक उन्नति किस दिशा में होगी। इसके अतिरिक्त विदेशियों में यह भी तय था कि भारत के उद्योगों का शीघ्र ही राष्ट्रीयकरण हो जायगा तथा भारत सरकार विदेशियों के साथ भेद-भाव की नीति को अपनायेगी। इस कारण प्रथम योजना काल में ६०० करोड़ रुपये की विदेशी पूँजी के स्थान पर केवल १६७ करोड़ रुपये की पूँजी प्राप्त की जा सकी और यह पूँजी भी तब प्राप्त हुई जबकि भारत सरकार ने विदेशियों को यह आश्वासन दिया कि वह भारतीय तथा विदेशी पूँजी में कोई भेद-भाव न करेगी तथा विदेशियों को अपना लाभ अपने देशों में भेजने की पूरी सुविधायें दी जायेंगी तथा यदि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जायगा तो उनको मुआवजा देकर प्राप्त किया जायगा। श्री बङ्कर जो भारत में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राजदूत हैं यह बताते हुए कि भारत में संयुक्त राष्ट्र की पूँजी के लिये अच्छा क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि इस पूँजी के लिये अच्छा वायुमण्डल निर्माण करने के लिये तीन बातों की आवश्यकता है—(१) अपरिवर्तनशीलता अथवा विदेशी उद्योगों को उखाड़ कर फेंकने से बचत, (२) दोहरे कर से रक्षा तथा (३) कर से छुटकारा। यह आवश्यक है कि भारत सरकार विदेशी पूँजी को देश में आकर्षित करने के लिये आवश्यक वायुमण्डल निर्माण करे।



Q 55 What is the present industrial policy of the Government of India ?

प्रश्न ५५—भारतीय सरकार की वर्तमान औद्योगिक नीति क्या है ?

जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी इस देश में आई तो उसने यहाँ के उद्योग-धन्यों को बहुत प्रोत्साहन दिया। परन्तु अङ्गरेजी लोक सभा में इस बात की बड़ी आलोचना हुई। इस कारण ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अपनी नीति बदलनी पड़ी। इसके पश्चात् इसका कार्य भारत के कच्चे माल का निर्यात करना तथा विदेश में बने हुये पक्के माल का आयात करना रह गया। इस प्रकार इसने उद्योग-धन्यों के विकास की ओर कुछ भी ध्यान न दिया।

भारत के सम्राट के हाथ में चले जाने के पश्चात् भी भारतीय सरकार ने इस ओर कुछ ध्यान न दिया। उसने हस्तक्षेप न करने की नीति को (Laissez Faire policy) ही अपनाये रखा। इस नीति के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों को विदेशों के साथ कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ी और भारतीय उद्योग पनप न सके।

प्रथम महायुद्ध में सरकार की आँखें खुली। युद्ध काल में विदेशों से सामान आना बन्द हो गया। इसी कारण युद्ध के लिये भारतीय उद्योग-धन्धों के विकास की आवश्यकता पड़ी। १९१६ में औद्योगिक कमिशन की नियुक्ति हुई। इस कमिशन ने यह सुझाव दिया कि भारतीय उद्योग-धन्धों के विकास में सरकार को सहयोग प्रदान करना चाहिये। १९१७ में इण्डियन म्यूनिरान बोर्ड की स्थापना की गई। इस बोर्ड के कार्यों से भारतीय उद्योग-धन्धों के विकास को अच्छी सहायता प्राप्त हुई। भारत में बहुत से नये उद्योगों की स्थापना की गई। युद्ध व समाप्त होने तक प्रायः सभी प्रान्तों में औद्योगिक विभाग (Department of Industries) खुल गये।

सन् १९१९ के सुधारों से यह बात मान ली गई कि भारतवर्ष को आर्थिक स्वतन्त्रता (Fiscal Autonomy) मिलनी चाहिये। इसीलिये १९२१ में पहला अर्थ कमिशन (Fiscal Commission) नियुक्त किया गया। इस कमिशन ने भारत के लिये एक विवेकात्मक संरक्षण नीति (Discriminating Protection Policy) का सुझाव रखा। इसके अनुसार प्रत्येक उद्योग को संरक्षण की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती थी वरन् ऐसे उद्योगों को हो सकती थी जो संरक्षण चाहता था। यह संरक्षण पूरी जाच के पश्चात् दिया जाता था। संरक्षण केवल उन्हीं उद्योगों को दिया जा सकता था जिनका एक परेडू बाजार हो जिनके लिये देश में पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल तथा श्रम हो, जो संरक्षण बिना न चल सकते हों तथा जो कुछ समय पश्चात् इतने दृढ़ हो जायें कि वे बिना संरक्षण के अपने आप चल सकें। ये सब बातें बड़ी कड़ाई के साथ मानी गई। इस नीति के अन्तर्गत कुछ उद्योगों, जैसे लोहा तथा फौलाद, सूती वपड़ा, चीनी आदि को संरक्षण प्रदान किया गया। इस संरक्षण से इन उद्योगों की उन्नति तो हुई पर इतनी नहीं जितनी कि उदार अर्थ-नीति से हो सकती थी।

द्वितीय महायुद्ध में भारतवर्ष मित्रराष्ट्रों के प्रशान्त महासागर के मोर्चों के लिये एक केन्द्र बना। इसके अतिरिक्त भारतीय सरकार को भी बहुत सी युद्ध-सामग्रियों की आवश्यकता हुई। इसी कारण सरकार ने उद्योगों को उन्नत करने में बहुत सहायता प्रदान की। सरकार ने यहाँ के युवकों को टैक्निकल शिक्षा ग्रहण करने के लिये इन्कलैड भेजा। १९४० में सरकार ने यह घोषणा भी की कि यदि आवश्यक हुआ तो युद्ध काल के पश्चात् उन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जायगा जो युद्ध काल में उन्नत होंगे। सरकार ने १९४१ में एक ऐसी कमेटी नियुक्त की जो युद्ध समाप्त होने पर देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक हो। इनके अतिरिक्त भी सरकार ने ऐसे बहुत से कार्य किये जिनसे इन देश के उद्योग उन्नत हो।

१५ अगस्त १९४७ को देश स्वतन्त्र हुआ। ७ अप्रैल, सन् १९४८ को सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं—

(१) भारतीय उद्योग धन्धों में काम करने वाले मजदूरों की दशा सुधारने का प्रयत्न करना।

(२) सरकार ने सारे उद्योगों को चार भागों में विभक्त किया है—

(अ) वे उद्योग जिन पर पूर्णरूप से सरकार का एकाधिकार है जैसे शस्त्रों का निर्माण, रेलवे यातायात तथा अणु-शक्ति की उत्पत्ति तथा नियन्त्रण आदि। इनके अतिरिक्त सरकार किसी भी उस उद्योग को ले सकती है जो राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक है।

(ब) निम्नलिखित उद्योगों को केन्द्रीय अथवा स्थानीय सरकार स्वयं चलायेगी। परन्तु यदि आवश्यक होगा तो सरकार पूँजीपतियों से भी सहायता ले सकती है—

(१) कोयला, (२) लोहा और फोलाद, (३) वायुयान, (४) जलयान, टेलीफोन, तार तथा बेतार का तार आदि बनाना, (५) मिट्टी का तेल।

सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इसमें से कोई भी ले ले। परन्तु इन उद्योगों में लगी हुई निजी सम्पत्ति को दस वर्ष तक स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार होगा। दस वर्ष के पश्चात् सरकार इन उद्योगों की क्षति-पूर्ति देकर ले करेगी।

(स) इनके अतिरिक्त जो उद्योग होंगे उनमें गैर सरकारी पूँजी व्यक्तिगत रूप से अथवा सहकारी रूप से लगाई जा सकती है। परन्तु इन उद्योगों को भी सरकार धीरे-धीरे लेगी। सरकार इन उद्योगों में उस समय भी हस्तक्षेप कर सकती है जबकि उनका कार्य सुचारु रूप से न चल रहा हो।

(द) इनके अतिरिक्त सरकार यह समझती है कि नीचे लिखे उद्योगों की योजना तथा नियन्त्रण का कार्य भी राष्ट्रीय हित में सरकार के पाम ही रहना चाहिए। ये नीचे लिखे हैं—

(१) नमक, (२) मोटर तथा ट्रक्टर, (३) मशीन के पुर्जें, (४) खाद आदि, (५) विजली-रासायनिक उद्योग, (६) लोहे के अतिरिक्त दूसरी धातु, (७) रबड़ का उद्योग, (८) शक्ति तथा औद्योगिक मद्यसार (Power and Industrial alcohol) (९) सूती तथा ऊनी कपड़े का उद्योग, (१०) सीमेन्ट, (११) चीनी, (१२) कागज तथा अखबारी कागज, (१३) वायु तथा समुद्री याता-यात, (१४) धातुएं, (१५) रक्षा सम्बन्धी उद्योग।

बड़े उद्योगों के अतिरिक्त सरकार ने कुटीर तथा छोटे उद्योगों पर भी बहुत अधिक जोर दिया है। सरकार इन उद्योगों की उन्नति के लिए अधिक से अधिक

बड़े पैमाने के उद्योग

प्रयत्न करेगी। इन उद्योगों की उन्नति के लिये सरकार ने कुटीर उद्योग बोर्ड भी स्थापित किया है।

सरकार समझती है कि अधिक से अधिक उत्पत्ति तभी हो सकती है जबकि पूँजी तथा श्रम में मेल जोल हो। इसी कारण सरकार ने यह प्रवन्ध किया है कि मुनाफे का ठीक प्रकार से वितरण हो, मजदूरों को उचित वेतन मिले, पूँजीपतियों को पूँजी पर उचित लाभ मिले।

सरकार श्रम तथा पूँजी के बीच होने वाले झगड़े का निपटारा करने के लिये उचित प्रकार के साधन जुटायेगी। श्रमिकों के घरों को उन्नत करने तथा नये घर बनवाने के लिये सरकार एक हाउसिंग बोर्ड भी स्थापित करेगी। यह बोर्ड दस वर्ष में दस लाख मजदूरों के घर बनायेगा। यह सरकार तथा पूँजीपतियों द्वारा बनाये जायेंगे। मजदूरों का हिस्सा उनसे उचित किराये के रूप में लिया जायगा।

सरकार का विचार है कि उद्योग धन्धों की उन्नति के लिये विदेशी पूँजी राष्ट्रीय हित के काम में लाई जा रही है।

सरकार की अर्थ नीति इस प्रकार की होगी जिससे कि उपभोक्ताओं के ऊपर बिना किसी प्रकार का दबाव डाले विदेशी प्रतियोगिता से बचा सके।

उद्योग (उन्नति तथा नियन्त्रण) विधेयक १९५१ जो १९५३ ई० में सशोधित किया गया—यह विधेयक ८ मई १९५२ ई० से लागू हुआ। इस विधेयक के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को उन ४५ से अधिक आवश्यक उद्योगों के ऊपर अत्यधिक शक्ति प्रदान की गई है जिनका इस विधेयक की पहली तालिका में उल्लेख है। इस विधेयक की मुख्य धाराय निम्नलिखित हैं—

(१) वे वर्तमान उद्योग जिनका उल्लेख इस ऐक्ट की पहली तालिका में किया गया है सरकार से रजिस्टर्ड होने चाहियें। नई मिलें उस समय तक नहीं चलाई जा सकती जब तक कि उनको चलाने से पहले अनुज्ञा-पत्र (Licence) प्राप्त न हो जाय।

(२) सब मिलों का सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्तियों द्वारा किसी समय भी निरीक्षण किया जा सकता है।

(३) केन्द्रीय सरकार किसी भी अनुचित उद्योग का निरीक्षण कर सकती है यदि उसका उत्पादन गिर रहा हो, यदि उसका माल घटिया हो जाय, यदि उसके मूल्य में वृद्धि हो जाय या उसकी व्यवस्था खराब हो जाय। राष्ट्रीय महत्व के साधनों को बचाने के लिये भी सरकार किसी भी उद्योग का निरीक्षण कर सकती है।

(४) निरीक्षण के पश्चात् सरकार उद्योग की उत्पत्ति, वितरण तथा मूल्य सम्बन्धी कोई भी आदेश जारी कर सकती है।

(५) यदि सरकार की आज्ञा का पालन न किया जाय तो सरकार उद्योग का प्रवन्ध लेकर एक विकास सभा (Development Council) अथवा और किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को अधिक से अधिक ५ वर्षों के लिये दे सकती है।

(६) अपने कार्य को चलाने के लिये सरकार निम्नलिखित सस्थाओं से सलाह लेगी ।

(अ) केन्द्रीय सलाहकार सभा—इसमें मालिकों, मजदूरों, उपभोक्ताओं, प्रारम्भिक उत्पादकों के प्रतिनिधि होंगे । इसकी सदस्य ३० होंगी ।

(आ) विकास सभा—प्रत्येक अनुसूचित उद्योग के लिये एक विकास सभा होगी । इसमें सरकार मालिकों, यन्त्र विशेषज्ञों, मजदूरों तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि नियुक्त करेगी । यह विकास सभा निश्चिन करेगी कि कितनी उत्पत्ति की जाय किस प्रकार ठीक ढङ्ग से वस्तुओं की विक्री तथा वितरण किया जाय आदि ।

(७) सरकार अपना खर्च चलाने के लिये उत्पन्न की हुई वस्तुओं के मूल्य पर (दो आने प्रतिशत के हिसाब से उपकर लगा सकती है ।

३० अप्रैल सन् १९५६ ई० को भारत सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में फिर से परिवर्तन किया है । परिवर्तन कई बातों के कारण करना आवश्यक था । पहला यह है भारत ने इस बीच में अपना विधान देश के ऊपर लागू किया है जिसमें देश के हर नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा का वचन दिया गया है । देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है तथा देश ने समाज के समाजवादी ढांचे को अपनाने का निश्चय किया है ।

नई औद्योगिक नीति के अनुसार सरकार अधिक से अधिक उद्योगों को अपने हाथ में लेगी तथा यातायात के साधनों की उन्नति करेगी । सरकार एक बड़े पैमाने पर व्यापार को भी अपने हाथ में लेगी । इसके साथ-साथ निजी पूँजी को भी उन्नति करने का अवसर दिया जायगा ।

नई नीति के अनुसार उद्योगों को तीन श्रेणियों में बाँटा गया है । पहली श्रेणी में वे उद्योग आते हैं जिनकी उन्नति का पूरा भार सरकार पर होगा । दूसरी श्रेणी में वे उद्योग आते हैं जिनमें सरकार अधिकाधिक हिस्सा लेगी । परन्तु इस श्रेणी के उद्योगों में पूँजीपति भी सरकार का हाथ बटावेंगे । तीसरी श्रेणी में शेष उद्योग होंगे और उनकी उन्नति का भार निजी पूँजी पर होगा ।

पहली श्रेणी के उद्योगों में निम्नलिखित आते हैं—हथियार तथा गोला बारूद, अणु शक्ति, लोहे तथा फौलाद के उद्योग, बिजली, कोयला, मिट्टी का तेल, लोहा, मैंगनीज, क्रोम, जिप्सम, गन्धक, सोना, हीरा, ताँबा, शीशा, जस्ता, टीन, खोदने के उद्योग, वायु तथा रेल यातायात, जहाज बनाना, टेलीफोन तथा टेलीफोन के तार बनाना तथा वेतार का सामान, बिजली का उत्पन्न करना तथा उसकी वितरण करना ।

दूसरी श्रेणी के उद्योगों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—शेष धातुएँ, मशीनों के औजार, दवाई, रज्ज, प्लास्टिक, खाद, रबड़, कोयले से कार्बन बनाना, रासायनिक पल्प, सड़क तथा समुद्री यातायात ।

बड़े पैमाने के उद्योग

तीसरी श्रेणी में दोष सब उद्योग आते हैं। परन्तु इन उद्योगों की ये श्रेणियाँ अविभाजित नहीं हैं। पहली श्रेणी के कुछ उद्योग भी पूँजीपतियों के हाथ में हो सकते हैं। अथवा सरकार इन उद्योगों के लिये बहुत सा सामान पूँजीपतियों से खरीद सकती है।

सरकार अपनी इस नीति में कुटीर उद्योगों की महत्ता को भी स्वीकार करती है। उसका विश्वास है कि इन उद्योगों से बेरोजगारी की समस्या बहुत कुछ सुलझ जायेगी तथा उनके द्वारा धन का सगान वितरण हो सकेगा। सरकार इन उद्योगों को बड़े उद्योगों की उत्पत्ति की सीमा निश्चित करके उन पर कर लगा कर इन उद्योगों को व्यय-साह्य (Subsidy) देकर उन्नत करेगी। इन उद्योगों की बड़े उद्योगों से मुकाबला करने की शक्ति को बढ़ाने के लिये सरकार उनको आधुनिक ढङ्ग से उन्नत करेगी। सरकार इनको टेक्नीकल तथा आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। इनकी बहुत सी कमिटीयों सहकारी समितियों के द्वारा दूर किया जायगा।

सरकार का यह प्रयत्न होगा कि देश के सब भागों में उद्योगों की उन्नति हो न कि वे देश के कुछ भागों में केन्द्रीय हो जाये। आशा है कि तृतीय पञ्चवर्षीय योजना में इस ध्येय की पूर्ति की जायगी। सरकार टेक्नीकल तथा मैनेजरी की शिक्षा प्रदान करने का भी प्रयत्न करेगी।

इस नीति का भी उद्देश्य होगा कि मजदूरों की काम करने की हालत सुधरे, मजदूरों तथा मालिकों में आपस में मेल जोल हो।

केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों की उद्योगों को उन्नत करने की जिम्मेदारी (Industries Development and Regulation Act) में निश्चित कर दी गई है तथा विदेशी पूँजी के विषय में ६ अप्रैल १९४६ ई० की घोषणा कर दी गई।

आलोचनाएँ—सरकार की औद्योगिक नीति के विरुद्ध निम्नलिखित आलोचनाएँ की गई हैं।

(१) जिन उद्योगों को सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है उनमें पूँजीपति अपनी पूँजी नहीं लगा रहे।

(२) सरकार को अपने ऊपर इस बात का अल्पाधिक विश्वास है कि वह उद्योगों का निजी पूँजीपतियों की अपेक्षा अधिक अच्छा प्रबन्ध कर सकती है। परन्तु यह बात नहीं है। देखने में यह आया है कि सरकारी कर्मचारी बहुत बार लापरवाही से काम करते हैं जब तक कि उनमें प्रखर राष्ट्र भक्ति की भावना न हो।

(३) उद्योगों की उन्नति राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आती है। परन्तु प्रत्येक राज्य की उद्योगों के सम्बन्ध में अपनी अलग नीति है। इसके कारण औद्योगिक विकास में बड़ी बाधा उत्पन्न होती है।

Q. 56. Explain the principles on which the present fiscal policy of government of India is based. How far in your opinion, has this policy promoted the development of Indian Industries ?

प्रश्न ५६—भारत सरकार की वर्तमान अर्थ-नीति किन सिद्धान्तों पर आधारित है। आपकी राय में इस नीति से कहाँ तक भारतीय उद्योगों की उन्नति हुई है ?

उत्तर—सन् १९१९ के सुधारों के पूर्व यह देश अबाध व्यापार की नीति पर था। पर १९१९ के सुधारों में यह बात स्वीकार कर ली गई कि इस देश को आर्थिक मामलों में पूर्ण स्वतन्त्रता मिलनी चाहिए। इस नीति के अन्तर्गत १९२१ में पहला वित्तीय आयोग (Fiscal Commission) नियुक्त किया गया। इस रिपोर्ट में कमिशन ने भारत के लिये विवेकात्मक अर्थ-नीति (Discriminating Protection Policy) का सुझाव दिया। इस नीति के अनुसार किसी उद्योग को उस समय संरक्षण मिल सकता है जबकि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करे—

(१) उद्योग के लिये देश में प्राकृतिक साधन पाये जाते हों। इन प्राकृतिक साधनों में पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल, सस्ती शक्ति, पर्याप्त श्रम तथा विस्तृत घरेलू बाजार सम्मिलित थे।

(२) उद्योग बिना संरक्षण के न चल सके और यदि चल भी सके तो इतनी गति से नहीं जितनी गति से उसको राष्ट्रीय हित में चलना चाहिये।

(३) उद्योग इस प्रकार का होना चाहिये जो अन्त में बिना संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना कर सके।

दोनों विश्व महायुद्ध के बीच में सरकार ने उसी अर्थ नीति से काम लिया। जहाँ तक इस नीति के सिद्धान्तों की बात है वहाँ तो उसमें कुछ अधिक दोष न थे। परन्तु ये सिद्धान्त इतनी कड़ाई में माने गये कि उसके कारण इस नीति की बड़ी आलोचना हुई। दूसरे इस नीति के अन्तर्गत केवल पुराने उद्योगों को संरक्षण मिलने की बात आती ही न थी। इस नीति के अन्तर्गत सरकार ने शीशे के उद्योग को इस लिये संरक्षण नहीं दिया क्योंकि भारत में सोडा एष नही पाया जाता था। इसी प्रकार सरकार ने भारी रासायनिक उद्योगों को भी संरक्षण नहीं दिया यद्यपि यह उद्योग भारत के लिये बहुत आवश्यक था। इस प्रकार इस नीति के अन्तर्गत इस बात का कोई ध्यान न रखा जाता था कि कोई उद्योग राष्ट्रीय हित के लिये आवश्यक है अथवा नहीं। इंग्लैण्ड में कई बड़े-बड़े उद्योगों के लिये न तो कच्चा माल ही पाया जाता है और न ही उसका विस्तृत घरेलू बाजार है परन्तु फिर भी वे उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पीछे नहीं हैं। इसलिये हम कह सकते हैं कि यह नीति भारत के लिये अपनानी अनुचित थी।

सरकार को भी अन्त में इस नीति के अवशुण मानने पड़े और इस नीति में सुधार करने के लिये उसने १९५४ में एक अन्तरवालीन टैरिफ बोर्ड की नियुक्ति

बड़े पैमाने के उद्योग

की। इस बोर्ड ने यह बताया कि सरक्षण उन उद्योगों को मिलना चाहिए जो अच्छी प्रकार से चल रहे हैं अथवा जिनको ऐसी प्राकृतिक एवं आर्थिक सुविधायें प्राप्त हो कि वे अन्त में बिना सरक्षण अथवा सरकारी सहायता के मफलतापूर्वक चल सकें अथवा जिनको राष्ट्रीय हित में सरक्षण देना आवश्यक हो और जिसका भार समाज के ऊपर अधिक न हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि सरकार की अर्थ नीति पहले से कुछ उदार हो गई।

१९४७ में टैरिफ बोर्ड का पुनर्स्थापन हुआ और उसको वस्तु मूल्य बोर्ड (Commodities Price Board) के कुछ कार्य भी सौंप दिये गए। १९४८ में इस बोर्ड के कार्यों में कुछ और भी वृद्धि कर दी गई।

सन् १९४६ में द्वितीय वित्तीय आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उद्योगों को सरक्षण देने का कार्य अकेले तय नहीं हो सकता क्योंकि इसका सम्बन्ध देश की पूर्ण आर्थिक नीति से है। जब तक देश के लिये एक बड़ी आर्थिक योजना बने उस समय के लिये आयोग ने निम्नलिखित सिद्धान्तों पर सरक्षण देने का सुझाव दिया है—

कमिशन ने सब उद्योगों को तीन भागों में बाटा है—(१) सुरक्षा तथा सेना सम्बन्धी उद्योग, (२) आधारभूत उद्योग, (३) अन्य उद्योग। आयोग का सुझाव है कि चाहे कितना भी व्यय हो सुरक्षा तथा सैनिक दृष्टि के महत्व में उद्योगों का सरक्षण प्रदान किया जाय। जहां तक आधारभूत उद्योगों के विकास का प्रश्न है इस सम्बन्ध में 'टैरिफ आर्थरिटी' सरक्षण के रूप का तथा सरक्षण की शर्तों आदि का निश्चय करेगी। वह समय-समय पर इस बात की जांच करती रहेगी इन शर्तों की कहां तक पूर्ति हो रही है। इन उद्योगों को भी सरक्षण मिलना चाहिये।

अन्य उद्योगों को सरक्षण प्रदान करने के लिये आयोग ने कहा कि 'टैरिफ आर्थरिटी' यह देखे कि जिस उद्योग को सरक्षण दिया जाने वाला है उस उद्योग को कौन-कौन सी आर्थिक सुविधायें प्राप्त हैं। उसके उत्पादन की वास्तविक लागत क्या होती है या होने की सम्भावना है। 'आर्थरिटी' यह देखे कि क्या उद्योग ऐसी स्थिति में है जो थोड़े समय में बिना सरक्षण के या सरक्षण सहित अपना उचित विनास कर लेगा तथा आत्म निभर हो जायगा, या वह ऐसा उद्योग है जिसे राष्ट्र के हित की दृष्टि से सरक्षण या अन्य सरकारी सहायता प्रदान करना आवश्यक है। उपरोक्त बातों के अतिरिक्त आयोग ने निम्नलिखित सुझाव और पेश किये हैं—

(१) आयोग ने कहा कि सरक्षण प्रदान करने के लिये इस बात का हाना कि अमुक उद्योग को अपने निकटवर्ती प्रदेश में बच्चा माल मिलेगा या नहीं, आवश्यक नहीं होना चाहिये। यदि उद्योग को अन्य सुविधायें जैसे भूमि, घरेलू बाजार आदि प्राप्त हैं परन्तु उसे बच्चा माल प्राप्त करने की सुविधा नहीं है तो उद्योग को सरक्षण प्रदान करने में कोई आपत्ति न होनी चाहिये।

(२) किसी उद्योग को संरक्षण प्रदान करने समय अच्छे विदेशी बाजारों या विप्री के क्षेत्रों का भी ध्यान रखना चाहिए ।

(३) संरक्षण प्रदान करने की यह शर्त नहीं होनी चाहिये कि कोई उद्योग देश की सारी माँग पूरी कर ।

(४) देश के वे उद्योग जो संरक्षण वाले उद्योगों के उत्पादन में महुायना कर रहे हैं, उन्हें भी एक प्रकार के क्षति पूरक संरक्षण (Compensatory Protection) की आवश्यकता होगी ।

(५) नवीन उद्योगों के लिये जिनमें काफी मात्रा में पूँजी लगती है और जिनके लिये कुशल श्रम की आवश्यकता होती है, उनको संरक्षण प्रदान करना काफी आवश्यक है ।

(६) राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिये वृषि उत्पादन की कुछ वस्तुओं को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है किन्तु ऐसा संरक्षण प्रदान करने समय यह ध्यान रखा जाना चाहिये कि जितनी कम वस्तुओं को संरक्षण प्रदान किया जाय उतना ही अच्छा है । इस संरक्षण का समय भी बहुत ही कम होना चाहिए और पाँच वर्षों से अधिक नहीं होना चाहिये । संरक्षण के साथ-साथ वृषि की उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिये ।

(७) जहाँ तक हो संरक्षण वाले उद्योगों पर उत्पादन-कर नहीं लगाना चाहिये । ऐसा तभी किया जाये जबकि सरकार को बहुत ही अधिक धन की आवश्यकता हो ।

जिन उद्योगों को संरक्षण दिया जायेगा उनके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी जो निम्नलिखित होंगी—

(१) मूल्य पर नियन्त्रण करना, (२) उत्पत्ति को बढ़ाने रहना, (३) वस्तु के गुण को ठीक रखना (४) उत्पत्ति के नय-नये साधनों का उपयोग करना आदि ।

टैरिफ आथैरिटी का कर्तव्य होगा कि वह संरक्षित उद्योग के साथ सम्बन्ध रखे और समय पर उनकी वास्तविक रिपोर्ट सरकार को देती रहे ।

कमीशन ने यह सुझाव भी दिया कि एक स्थायी टैरिफ कमीशन की स्थापना की जाय । यह लोक सभा द्वारा स्थापित किया जाये । इसमें प्रधान सहित पाँच सदस्य होना चाहिये । इस कमीशन का यह वाय होगा कि वह इन बातों की जाँच करे कि संरक्षण किस उद्योग को दिया जाये ।

स्थायी टैरिफ कमीशन को स्थापित करने के लिये एक बिल लोकसभा में पेश किया गया था जो कि पास हो चुका है । इस कमीशन का वही कार्य होगा जो उसके लिये वित्तीय कमीशन ने बताया था ।

इस प्रकार द्वितीय कमीशन के सुझावों का मान लेने से भारतीय अर्थ-नीति में एक बहुत बड़ी बदल हो गई है । अर्थ कमीशन के सुझाव के अनुसार संरक्षण केवल विदेशी प्रतियोगिता से बचने के लिये ही नहीं लगाना चाहिये । परन्तु देश के

बड़े पैमाने के उद्योग

प्राकृतिक साधनों का पूरा-पूरा उपयोग करने के लिये भी लगाना चाहिये। इस प्रकार भविष्य में संरक्षण हमारे देश के लिये राष्ट्रीय हित का एक साधन बन जायेगा।

संरक्षण और भारतीय उद्योग—यद्यपि हमारे देश के उद्योगों को अभी तक विवेकात्मक संरक्षण ही प्रदान किया गया था तो भी इस देश के उद्योगों ने बहुत उन्नति की। जिन उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया गया उन्होंने (जूट तथा लोहे के अतिरिक्त) मदी के समय भी खूब उन्नति की। १९२२ तथा १९२६ के बीच फौलाद के सामान की उत्पत्ति आठ गुनी, सूती कपड़े की ढाई गुनी, दियासलाई की ३८%, कागज की १८% और चीनी की उत्पत्ति २४,००० से ६९१,००० टन बढ़ गई। इन सब उद्योगों की इतनी अधिक उन्नति उस समय हुई जबकि उनको विवेकात्मक संरक्षण दिया गया। यदि उनको ठीक प्रकार का संरक्षण दिया जाता तो वह और भी अधिक उन्नति कर जाते। इस बात से यह साफ जाहिर है कि इस देश के उद्योगों को संरक्षण की आवश्यकता है। वर्तमान संरक्षण नीति से हम यह आशा कर सकते हैं कि देश के उद्योगों की बहुत उन्नति होगी।

Q 57 Discuss the desirability or otherwise of nationalising Indian industries at the present moment

प्रश्न ५७—वर्तमान में भारतीय उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की अच्छाई अथवा बुराई के विषय में लिखिये।

उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का जब उस स्थिति से होता है जबकि उद्योगों का स्वामित्व तथा उनको व्यवस्था सरकार के हाथ में होती है। भारतीय उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की समस्या द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने पर सामने आई। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विषय में योजना आयोग ने विचार किया। भारत सरकार ने भी उद्योगों के विषय में अपनी पहली नीति ७ अप्रैल १९४८ ई० को घोषित की तथा दूसरी नीति ३० अप्रैल १९५६ को। इन दोनों में बताया गया कि भारत के लिये मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (Mixed Economy) सबसे उपयुक्त है। श्री गुलजारीलाल नन्दा ने इस विषय में कहा है, 'यदि किसी विशेष उद्योग के राष्ट्रीयकरण से अच्छा फल प्राप्त होता है तथा वह सबको अच्छा सतोष प्रदान करता है, तो उसको ठीक ढङ्ग से चलाने में कोई बाधा नहीं। यदि एक निजी उद्योग कुछ कारणों से ठीक प्रकार से कार्य करता है और अधिक सतोष प्रदान करता है, तो अवश्य ही उसको रहने दिया जायगा।' १६ जून १९५२ ई० को श्री के० सी रेड्डी ने जो उस समय उत्पादन मन्त्री थे, कहा था, 'यदि मुझे वर्तमान निजी उत्पाद उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने तथा उसके बदले एक सरकारी उत्पाद उद्योग चालू करने के बीच छाना करने के लिये कहा जाय तो मैं निःसंकोच वर्तमान उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में साधनों को

नष्ट करने की अपेक्षा नये उद्योग को चालू करने के पक्ष में राय दूंगा।' ७ जनवरी १९५६ ई० में श्री नेहरू ने Standing Committee of the National Development Council के सामने कहा, 'मैं राष्ट्रीयकरण में विश्वास नहीं करता क्योंकि जब राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो मावजा देना पड़ता है। मैं कोई लाभ दत्त बात में नहीं देखता कि हम मावजा देने में अपने साधनों को नष्ट करें जब तक कि कोई चीज हमारे रास्ते में न आये और हमको इसे बदलना पड़े' - जहाँ तक मिलो का सम्बन्ध है मैं एक नई मिल खड़ी करूँगा और निजी मिल के साथ प्रतियोगिता करूँगा। ८ जून १९५६ ई० को श्री नेहरू ने फेडरेशन आफ इंडिया चेम्बर आफ कामर्स की समिति के सम्मुख कहा कि सरकार की यह भी नीति है कि यद्यपि साधारणतः आधारभूत उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में पड़ेंगे परन्तु वे वर्तमान उद्योगों का राष्ट्रीयकरण केवल राष्ट्रीयकरण के लिये नहीं करेंगे। निजी उद्योगों में भी तब तक बड़े पैमाने की इकाइयों को चालू करने की आज्ञा देने का प्रश्न नहीं उठता जब तक कि वे हमारी आर्थिक व्यवस्था के हित में कार्य करते हैं। इन उदाहरणों से सरकार की उद्योग के प्रति नीति का पता चलता है।

इससे पूर्व कि हम यह कहें कि भारतीय सरकार की मिश्रित अर्थ-व्यवस्था कहाँ तक भारत के लिये उपयुक्त है हमें यह देखना चाहिये कि यदि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाय तो उससे क्या लाभ अथवा हानि हो सकती है।

राष्ट्रीयकरण के लाभ—

(१) राष्ट्रीयकरण करने से प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और उसके कारण विज्ञापन आदि करने का खर्च समाप्त हो जाता है।

(२) राष्ट्रीयकरण से उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ होता है। उसका कारण यह है कि सरकार के सामने लाभ का उद्देश्य न होने के कारण वस्तु का मूल्य कम होता है। उपभोक्ताओं को निजी पूँजी के शोषण से बचाने के लिये प्रायः सभी देशों में उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है जो राष्ट्र के लोगों के लिये बहुत आवश्यक हैं जैसे, गेस, बिजली, कोयले आदि के उद्योग।

(३) राष्ट्रीयकरण से मजदूरी को बड़ा लाभ होता है। सरकार सारे देश के लोगों के हित की बात सोचती है। इसलिये जो मजदूर सरकारी कारखानों में काम करते हैं उनको अच्छी मजदूरी मिलती है, उनसे कम घण्टे काम लिया जाता है, उनके लिये मिलों में बहुत प्रकार की सुविधायें प्रदान की जाती हैं आदि-आदि।

(४) राष्ट्रीयकरण करने से उद्योगों को जो लाभ प्राप्त होता है वह समाज के सब लोगों के हित के लिये खर्च किया जाता है। इससे लोगों का जीवन स्तर ऊँचा होता है।

(५) कुछ ऐसे उद्योग भी होते हैं जिनके ऊपर सारे राष्ट्र का जीवन निर्भर होता है। ऐसे उद्योगों को निजी पूँजी को सौंप कर देश को एक अनिश्चित स्थिति में डालना है क्योंकि यदि किसी समय इन उद्योगों में लाभ कम हो जाये तो निजी

बड़े पैमाने के उद्योग

पूँजीपति उत्पत्ति करना छोड़ देंगे अथवा उत्पादन कम कर देंगे। इसके विपरीत यदि ऐसे उद्योग सरकार के हाथ में होते हैं तो वे चलते ही रहते हैं, चाहे उनमें लाभ हो अथवा हानि। ऐसे उद्योगों में लोहे व इस्पात का उद्योग, शास्त्र आदि बनाने के उद्योग, रेलवे उद्योग, कोयले का उद्योग, वायुयात, जलयान उद्योग, टेलीफोन व टेलीग्राम उद्योग आदि सम्मिलित होते हैं।

(६) राष्ट्रीयकरण कुछ ऐसे उद्योगों के लिये भी आवश्यक हो जाता है जो बिल्कुल नये होते हैं और इस कारण उनमें निजी पूँजी नहीं लगाई जाती क्योंकि उनका लाभ अनिश्चित होता है।

(७) कभी कभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण उस समय भी किया जाता है जबकि देश के किसी पिछड़े हुए भाग में निजी पूँजी न लगाई जा रही हो। ऐसे भाग में सरकार अपनी पूँजी से उद्योग चलाकर उस भाग को उन्नत बना देती है।

(८) १२ अक्टूबर १९५१ ई० को राष्ट्रीयकरण के विषय में लोग सभा में भाषण करते हुए श्री गुलजारीलाल नन्दा, याजवा मन्त्री न कहा था कि यह सम्भव है कि राष्ट्रीयकरण किये गये उद्योग में मजदूरों, जिनके लाभ के लिये राष्ट्रीयकरण किया गया है, की स्थिति मजदूरों के दृष्टिकोण से खराब हो जाय। इसी प्रकार यह सम्भव है कि किसी दूसरे उद्योग में उपभोक्ताओं को जिनके लाभ के लिये उस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया है, अधिक मूल्य देना पड़ा। इसके अतिरिक्त सरकार को किसी दूसरे राष्ट्रीयकरण किये हुए उद्योग से लाभ न हो। राष्ट्रीयकरण कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किया जाता है और यदि उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाय तो सरकार को उनको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। इंग्लैंड तक में राष्ट्रीयकरण किये गये उद्योगों में मजदूरों को सतोष नहीं मिल रहा है। इसलिये भारत के लोगों को चाहिये कि वे कार्य करें और स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न करें।

राष्ट्रीयकरण की हानियाँ—

(१) जहाँ राष्ट्रीयकरण से ये सब लाभ हैं वहाँ उससे निम्नलिखित हानियाँ भी हैं—

(१) जब किसी देश में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तब लोगो की स्वयं इच्छा से कार्य करने की भावना (Initiative) नष्ट हो जाती है।

(२) उद्योगों के राष्ट्रीयकरण करने से उत्पादन करने में बहुत कम मित-

व्ययिता होती है। पूँजीपति को अधिकाधिक लाभ कमाने की धुन लगी रहती है। इसलिये वह हर समय उन सब ढङ्गों को सोचता रहता है जिनसे कि वह कम से कम खर्च करके अधिकाधिक लाभ कमा सके। परन्तु राष्ट्रीयकरण किये गये उद्योगों का नियंत्रण तथा संचालन वैयक्तिक मनेजरो द्वारा किया जाता है। ये लोग उद्योगों में मितव्ययिता करने में कोई दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि ऐसा करने से उनको कोई

व्यक्तिगत लाभ नहीं होता। वे केवल इतना कार्य करते हैं जिससे कि उनको उपयोगिता का आरोप लगाकर पदच्युत न कर दिया जाय। इस प्रकार उद्योगों में काम मितव्ययिता होती है।

(३) यद्यपि यह बात सत्य है कि राष्ट्रीयकरण करने से मजदूरों की स्थिति कुछ अच्छी हो जाती है परन्तु ऐसा भी होता है कि मजदूरों की हड़ताल आदि करने की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है। सरकार के हाथ में कानून बनाने की शक्ति होने के कारण, वह मजदूरों के इस अधिकार को छीन लेती है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के कारण मजदूर सचो की शक्ति बहुत कम हो जाती है।

(४) सरकारी उद्योगों में भी वही दोष पाये जाते हैं, जो कि सरकारी दफ्तर में पाये जाते हैं। उद्योगों में भी पक्षपात, बेईमानी, काम का देर में होना आदि दोष पाये जाते हैं।

(५) राष्ट्रीयकरण करने से तभी लाभ हो सकता है जबकि देश में सच्चे और ईमानदार लोग होते हैं। यदि देश में इस प्रकार के लोगों की कमी होती है तो राष्ट्रीयकरण से लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होती है।

(६) राष्ट्रीयकरण करने से पूँजी के एकाग्र करने में बड़ी बाधा पड़ती है।

यदि हम राष्ट्रीयकरण के गुण व दोषों को ध्यान में रखकर यह विचार करें कि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भारत के लिये लाभप्रद है या नहीं तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भारत के लिये मिश्रित अर्थ-व्यवस्था (Mixed Economy) की नीति सबसे अच्छी है। इसके कई कारण हैं—

(१) भारत सरकार के पास इस समय इतनी पूँजी नहीं है कि वह सब अथवा अधिकतर उद्योगों को अपने हाथ में ले सके। इसका सबूत यह है कि सरकार को पंचवर्षीय योजना के चलाने में पूँजी की कमी के कारण बड़ी कठिनाई पड़ी थी। इसलिये सरकार के लिये सबसे अच्छा रास्ता यह है कि वह उन उद्योगों में जिनमें कि निजी पूँजी पर्याप्त मात्रा में लग रही है निजी पूँजी को लगने दे। जिन उद्योगों में निजी पूँजी नहीं लग रही है उनको सरकार चलाये। इनके अतिरिक्त सरकार उन उद्योगों को जो राष्ट्रीय हित के लिये आवश्यक है स्वयं चलाये। ऐसे उद्योगों में आधारभूत उद्योग जैसे लोहे और इस्पात का उद्योग, भारी रासायनिक उद्योग आदि हैं, रक्षा की दृष्टि से आवश्यक उद्योग जैसे अणु-शक्ति, गोला बारूद, हथियार आदि बनाने के उद्योग तथा लोक-हित उद्योग जैसे बिजली, गैस, रेलवे, कोयला आदि उद्योग सम्मिलित हैं। उनमें निजी पूँजी को पूर्ण स्वतन्त्रता होगी चाहिये।

यह एक अच्छी बात है कि भारत सरकार ने उद्योगों के सम्बन्ध में यही नीति अपनाई है।

(२) सरकार के पास इस समय ऐसे योग्य व्यक्तियों की कमी है जो उद्योगों का कार्य संचालन कर सकें।

(३) भारतवर्ष में जो भी योग्य व्यक्ति है वे कार्य संचालन करते समय बहुत प्रकार की बुराइयों में फँस जाते हैं। इसके उदाहरण हमको महालेखा निरीक्षक (Auditor General) की रिपोर्टों से मिल सकते हैं। सरकार द्वारा आजकल पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो बड़े-बड़े कार्य किये जा रहे हैं उनमें करोड़ों रुपये के खर्च की बातें पढ़ने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त उनमें कार्य की प्रगति बहुत धीमी है। इसलिये हम कह सकते हैं कि जब तक देश में सच्चे और ईमानदार लोगों की कमी है उस समय तक राष्ट्रीयकरण लाभप्रद न होगा।

(४) हमारे देश के संकड़ों वर्ष तक गुलाम बने रहने के कारण लोगों की अपनी योग्यता दिखाने का कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ। देश के स्वतन्त्र होने पर उनको यह अवसर मिला है। यदि उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो लोगों को फिर गुलामों के समान सरकार की आज्ञानुसार कार्य करना पड़ेगा। इससे देश को बड़ी हानि होगी।

इन्हीं सब बातों के कारण हम भारत की वर्तमान स्थिति में सब उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हैं। हम देश के लिये एक मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के पक्ष में हैं।

Q 58 Discuss the desirability of nationalizing insurance in India in the next five years

प्रश्न ५८—भारत में अगले पाँच वर्षों में बीमे के राष्ट्रीयकरण की उपयुक्तता की विवेचना कीजिये।

१६ जनवरी १९५६ ई० को राष्ट्रपति के एक विशेष आदेश द्वारा जीवन बीमे के कार्य का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसका प्रभाव १४६ भारतीय तथा १६ अन्तराष्ट्रीय कम्पनियों पर पड़ा। इन कम्पनियों को सरकार उचित मुआवजा देगी।

भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के चालू होने पर यह आवश्यक हो गया कि भारत का सारा आर्थिक ढांचा इस प्रकार स्थापित किया जाय जिससे कि वह देश की उन्नति की योजनाओं में सहायक हो सके। इस दृष्टि से इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। जीवन बीमे के कार्य का राष्ट्रीयकरण उस ओर दूसरा पग है। इसके द्वारा देश के लोगों की वृद्ध राष्ट्रीय उन्नति की योजनाओं में सहायक हो सकेगी।

भारतवर्ष में आजकल ५० लाख बीमे की पालिसी है जिससे ५५ करोड़ वार्षिक प्रीमियम मिलता है। जीवन बीमा कम्पनियों की सम्पत्ति ३८० करोड़ रुपये है जिससे उनको १२ करोड़ ८० वार्षिक की आय प्राप्त होती है। परन्तु अभी

भारत में जीवन बीमा कार्य बढ़ाने के लिये इतनी गुन्जायश है कि उनकी सम्पत्ति ८००० करोड़ रुपये तक बढ़ सकती है। इस प्रकार जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण करके सरकार देश के लोगों की बहुत सी बचत राष्ट्र हित के कार्यों में लगा सकेगी।

जब भारत में जीवन बीमे का राष्ट्रीयकरण किया गया तब साधारण जनता इसका बड़ा स्वागत किया। प० नेहरू ने अपने एक भाषण में इसको एक बड़ा पग तथा एक अच्छा निर्णय बताया क्योंकि यह न केवल पंचवर्षीय योजना के लिये अच्छा है बरन् समाज के समाजवादी ढांचे के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये भी महत्वपूर्ण है। साधारण जनता ने इसका स्वागत इसलिये किया क्योंकि इसके कारण उनका रुपया सुरक्षित रहेगा। यदि सरकार ऐसा न करती तो भोली भाली जनता को लोगों की बदनियतों का शिकार होना पड़ता। इसका विपरीत बहुत सी बीमा कम्पनियों के ज़ेयरमैनो ने इसका विरोध किया और कहा कि बीमे का कार्य नवल निजी हाथों में रहकर बढ़ सकता है। क्योंकि वहाँ प्रतियोगिता के कारण हर एक कम्पनी अपने कार्य को बढ़ाने का प्रयत्न करती है।

बीमे में राष्ट्रीयकरण के पक्ष व विपक्ष में तर्क—

राष्ट्रीयकरण के विपक्ष में लोगों का कहना है कि इस देश तथा विदेशों में लोगों का अनुभव है कि राष्ट्रीयकरण के द्वारा उसमें काय कुशलता तथा लचकीलापन प्राप्त नहीं होता जो निजी हाथों में हो जाता है। गद्दी कारण है कि उन देशों में जहाँ इस प्रकार के प्रश्न उठे लोगों ने इसका विपक्ष में अपने मत दिये। उनका यह भी कहना है कि राष्ट्रीयकरण के द्वारा बीमे के उच्चतम आदर्शों को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

इस तर्क का खण्डन करते हुए भारत के भूतपूर्व वित्तीय मन्त्री श्री देशमुख ने कहा था कि दूसरे देशों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि जहाँ कहीं भी पूरे दिल से प्रयत्न किया गया है सफलता केवल उन्हीं हालतों में मिली है जबकि पूरे तौर पर प्रयत्न किया गया। मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता कि राष्ट्रीयकरण किया गया व्यापार क्यों ठीक प्रकार नहीं चल सकता। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगों को यह विश्वास सा हो गया है कि सरकार द्वारा चलाये गए सब कार्य खराबी के साथ चलाये जाते हैं तथा ऐसे लोग निजी कार्य कुशलता की बड़ी डींग मारते हैं। भारत में ही बीमे के कार्य के विषय में, यह अनुभव है कि बीमे के व्यापार में जहाँ कोई भी इकाई फेल नहीं होनी चाहिए पिछले १० वर्षों में लगभग २५ बीमा कम्पनियाँ फेल हो गईं तथा दूसरी २५ ने अपने साधनों का ऐसा दुरुपयोग किया कि उनका कार्य दूसरी कम्पनियों को हस्तांतरित करना पड़ा। कुछ हालतों में बीमा कम्पनियों ने अपने साधनों को गलत स्थानों पर लगाया। भारत बीमा कम्पनियाँ इसके उदाहरण हैं।

राष्ट्रीयकरण के द्वारा यह बात सम्भव हो सकती कि देश में वे कम्पनियाँ जो आजकल अच्छी प्रकार काय नहीं कर रही हैं उनको आपस में मिलाकर अथवा

और किसी ढंग से सुचारु रूप से चलाया जा सकेगा। इसके द्वारा यह भी सम्भव सकेगा कि जीवन बीमे का कार्य जो आजकल केवल शहरो तथा नगरों तक ही सीमित है उसको बढ़ा कर गावों तक ले जाया जा सकेगा और इस प्रकार गावों के लोगों की वचत को भी देश के हित के कार्यों में लगाया जा सकेगा।

राष्ट्रीयकरण के कारण द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अर्थ-प्रबन्धन (Financing) में भी सहायता मिलेगी। यह बात ऊपर भी बताई जा चुकी है।

इसके द्वारा जैसा ५० नेहरू व श्री देशमुख ने कहा है, "समाजवादी ढांचे को जिसको प्राप्त करने का देश ने १९५४ में निश्चय किया है, प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

इस प्रकार बीमे के राष्ट्रीयकरण को देश के लिये हितकर ही करना उचित होगा।

यहाँ यह बात बतानी अनुचित न होगी कि जीवन बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात् भारत सरकार ने १ जूलाई १९५६ ई० को एक जीवन बीमा कारपोरेशन स्थापित की जिसने सब जीवन बीमा कंपनियों की लेनदारी व देनदारी अपने ऊपर ले ली है। केवल डाकखाना जीवन बीमा फण्ड का कार्य इसने नहीं लिया है। भविष्य में कोई भी बीमा कंपनी जीवन बीमे का कार्य भारत में न कर सकेगी।

कारपोरेशन की प्रारम्भिक पूँजी ५ करोड़ रु० होगी जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी। इसके कार्य की देख-रेख १५ सदस्यों का एक बोर्ड करेगा। सभापति इन्हीं में से एक होगा। साधारण निरीक्षण का कार्य एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा जायेगा जिसके ५ सदस्य होंगे। धन का विनियोग करने के लिये एक विनियोग समिति स्थापित की जा सकती है जिसमें ७ सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। इन ७ में से ३ कारपोरेशन में से लिये जायेंगे तथा शेष वे होंगे जो कि आर्थिक मामलों में तजुर्बा रखने वाले होंगे।

इस प्रकार जीवन बीमा कारपोरेशन स्थापित करके भारत सरकार ने १९ जनवरी १९५६ से पूर्व की सब पालिसियों की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है।

Q 59 Trace the growth and development of iron and steel industry in India and discuss the present problems of the industry

प्रश्न ५९-भारतवर्ष के लोहे और फौलाद के उद्योगों का विकास तथा उन्नति के बारे में लिखिए तथा इस उद्योग की वर्तमान समस्याओं का वर्णन कीजिये।

उत्तर-लोहे और फौलाद का उद्योग सभी उद्योगों का आधार स्तम्भ है। आधुनिक युग में यह उद्योग न केवल सेती व यातायात के लिये ही आवश्यक है वरन् सब

प्रकार के उद्योगों जिनमें इजीनियरिंग व रसा सम्बन्धी उद्योग भी हैं के लिये आवश्यक है। भारतवर्ष का यह एक बहुत पुराना उद्योग है। देहली के पास का लोहे का स्तम्भ १५०० वर्ष पुराना बताया जाता है। यह स्तम्भ इस बात का प्रमाण है कि अतीत में भारतवासियों ने लोहे और फौलाद के उद्योगों में निपुणता प्राप्त कर ली थी। भारतवर्ष के कारखाने में बनी हुई लोहे और फौलाद की चीजों की माग दूर-दूर के देश करते थे। पर धीरे-धीरे इस उद्योग का पतन हो गया। समय-समय पर उसकी उन्नति का प्रयत्न किया गया पर निष्फल हुआ।

भारत में आधुनिक ढङ्ग के अनुसार लोहे और फौलाद का उद्योग अभी ५० वर्षों से चालू हुआ है। इससे पूर्व कुछ यूरोप के लोगों ने इस उद्योग को चालू करने का प्रयत्न किया पर उनको कोई सफलता न मिली। प्रारम्भ में किये गए इस प्रकार के प्रयत्नों में से एक प्रयत्न शारकर का लोहे का कारखाना था। १८८६ में इस कारखाने को कलकत्ते की मारटिन कम्पनी ने ले लिया। इसके पश्चात् इसको फिर ठीक-ठीक ढङ्ग पर चालू किया गया है। कुछ समय पश्चात् इसको इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में मिला दिया गया है।

परन्तु इस उद्योग को आधुनिक प्रणाली पर चलाने का श्रेय टाटा को है। उसने १९०७ में सच्ची स्थान पर टाटा कम्पनी की नींव डाली। प्रारम्भ की सब कठिनाइयों का सामना करते हुये कारखाना दिनो-दिन उन्नति करता गया। सन् १९१४-१८ के महायुद्ध में इस कम्पनी की बहुत उन्नति हुई। १९१७ में इसको बढ़ाने की एक योजना तैयार की गई जो १९२४ में बनकर तैयार हुई। टाटा के कारखाने की उन्नति को देखकर दूसरे लोगों को भी दूसरे कारखाने खोलने का साहस हुआ। १९०८ ई० में होरापुर में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बनाई गई। इसके पश्चात् १९२३ में भद्रावती में मैमूर स्टेट आयरन वर्क्स चालू किया गया। सन् १९३७ में बङ्गाल स्टील कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई। इनके अतिरिक्त बङ्गाल के आस पास कुछ और छोटे-छोटे लोहे के कारखाने हैं। १९५४ ई० की एक गणना के अनुसार भारत में १२६ लोहे व इस्पात के कारखाने हैं। इनमें ३५६ करोड़ रु० की अचल पूंजी तथा ३४३ करोड़ रु० की चल पूंजी लगी हुई है तथा इसमें ८५६३४ आदमी लगे हुए हैं।

सरक्षण (Protection)

जैसा ऊपर बताया गया है कि लोहे और फौलाद के उद्योग ने प्रथम महायुद्ध में खूब उन्नति की। युद्ध समाप्त होने पर इस उद्योग को विदेशों से काफी कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ी। इसलिये उद्योग ने सरकार से सरक्षण के लिये प्रार्थना की। टैरिफ बोर्ड जाय-पडताले के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यदि इस उद्योग को सरक्षण प्रदान कर दिया गया तो थोड़े ही समय में कम लागत पर भारत अपनी आवश्यकता के लिये फौलाद उत्पन्न कर सकेगा। इस कारण १९२४ में इस उद्योग को केवल तीन वर्ष के लिये अधिक आयात कर (Import Duties) तथा

निर्यात वृत्ति (Bounties) के रूप में सरक्षण मिला। इसके पश्चात् इस सरक्षण की मात्रा वर्ष के लिये और बढ़ा दिया गया। सन् १९३३ में सरक्षण की अवधि फिर ७ वर्ष के लिये बढ़ा दी गई। सरक्षण के लिये सबसे अन्तिम जाँच १९४७ ई० में हुई जिसमें इस उद्योग ने सरक्षण जारी रखने के लिये कोई जोर नहीं दिया। इसी कारण टैरिफ बोर्ड ने सरक्षण हटाने का सुझाव रखा। इस प्रकार २१ वर्ष के सरक्षण के पश्चात् अब यह उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सरक्षण से इस उद्योग की बहुत प्रगति हुई। इस जतावृत्ती के प्रारम्भ में इस देश में ३५००० टन गला हुआ लोहा (Pig iron) तैयार होता था पर अगस्त १९५७ में इसकी उत्पत्ति बढ़कर १७ ८९ लाख टन हो गई। इसके अतिरिक्त हमारे देश में आजकल बहुत सा इस्पात भी उत्पन्न होता है। १९५७ में तैयार फौलाद की उत्पत्ति १३४६ ४ हजार टन थी। १९५८ में टाटा के कारखाने में हड़ताल होने के कारण फौलाद की उत्पत्ति घटकर १२ ९५ लाख टन रह गई।

द्वितीय महायुद्ध से प्रगति

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने से विदेशों से फौलाद का आयात बन्द हो गया। इसी बीच सरकार तथा रेलों द्वारा फौलाद की मांग बढ़ गई। इस मांग को पूरा करने के लिये देश में ही फौलाद की उत्पत्ति बढ़ने लगी। टाटा कम्पनी ने १९३१ ई० में जमशेदपुर में एक स्टील टायर तथा ऐक्सेल मशीन लगाई। इसके पश्चात् फौलाद की उत्पत्ति दिनों-दिन बढ़ती चली गई।

युद्ध के पश्चात् की स्थिति

युद्ध के पश्चात् इस उद्योग को बड़े सकट का सामना करना पड़ा। इस सकट के आन्तरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार के कारण थे। आन्तरिक कारणों में श्रम की उत्पादन-शक्ति का कम होना, वेतन में वृद्धि, मशीनों का पुराना तथा घिसा हुआ होना, मशीनों के पुनर्गठन की कठिनाई, पूँजी की कमी, कच्चे माल की कठिनाई ये। बाह्य कारणों में मुद्रा-स्फीति, देश की राजनीतिक अव्यवस्था तथा देश का विभाजन, युद्ध सम्बन्धी मांग का समाप्त हो जाना तथा सरकार की असंतोषजनक औद्योगिक नीति ये। इनके अतिरिक्त सरकार की मूल्य नियन्त्रण सम्बन्धी नीति भी असंतोषजनक थी।

पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत उद्योगों की स्थिति—

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार ने लोहे व फौलाद के उद्योगों को बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इसलिये सरकार का विचार था कि वह ३१ मार्च १९५६ तक ३० करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र (Public Sector) में खर्च करेगी तथा ४३ करोड़ रुपये निजी उद्योगपतियों को उद्योग को बढ़ाने के लिये देगी। निजी उद्योगों में सरकार ने १०-१० करोड़ रु० के बिना व्याज के ऋण टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दिये हैं।

इसके अतिरिक्त १९५६ ई० में सरकार ने विश्व बैंक से मिलने वाले ऋण की भी गारन्टी की है। इसके कारण उस बैंक से टाटा कम्पनी को ७५ मिलियन डॉलर का ऋण तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को २० मिलियन डॉलर का ऋण मिला है। टाटा का विस्तार कार्य १९५६ ई० तक तथा इण्डिया आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार कार्य फरवरी १९५८ में पूरा हो चुका है। विस्तार के कार्य के फलस्वरूप टाटा कम्पनी की उत्पत्ति ८ लाख टन तैयार फोलाद से बढ़कर १५ लाख टन तथा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी की ३,००,००० टन से बढ़कर ८,००,००० टन वार्षिक हो जायेगी। इसके अतिरिक्त दक्षिणी भारत में कोयमबदूर में १५,००० टन वार्षिक उत्पत्ति का एक छोटा कारखाना बनाने की भी आज्ञा दी गई है। इसके अतिरिक्त मैंगूर आयरन तथा स्टील वर्क्स में १९६०-६१ तक १००,००० टन फोलाद उत्पत्ति बढ़ाने की योजना है।

सार्वजनिक क्षेत्र में तीन स्टील प्लान्ट्स लगाये जा रहे हैं जिनमें से प्रत्येक की वार्षिक उत्पादन-शक्ति १० लाख टन होगी। ये कारखाने रुर्केला, भिलाई तथा दुर्गापुर में स्थित होंगे। रुर्केला तथा भिलाई के कारखानों में क्रमशः ३,४ जनवरी १९५८ में उत्पादन का कार्य शुरू होगया तथा दुर्गापुर के कारखाने में १९५८ ई० में ऐसी आशा है कि रुर्केला तथा दुर्गापुर के कारखाने पूर्ण रूप से १९६१ तक तैयार हो जायेंगे तथा भिलाई का १९६० तक रुर्केला प्लान्ट ७२०,००० टन स्टील, भिलाई प्लान्ट ७,७०,००० टन स्टील तथा ३,००,००० टन गला हुआ लोहा तथा दुर्गापुर प्लान्ट ७६०,००० टन स्टील तथा ३,५०,००० गला हुआ लोहा उत्पन्न करेगा। इनमें रुर्केला के कारखाने की लागत १७० करोड़ रु०, भिलाई की १३१ करोड़ रु० तथा दुर्गापुर की १३८ करोड़ रु० होगी।

इस प्रकार योजना के अन्तिम वर्ष में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग २ मिलियन टन तैयार फोलाद तथा निजी क्षेत्र में ४३ मिलियन टन फोलाद तैयार हो सकेगा। इस सब कार्य के फलस्वरूप न केवल फोलाद का आयात बन्द हो जायगा वरन् भारत लगभग ५० करोड़ रु० वार्षिक का फोलाद विदेशों को भेज सकेगा।

वर्तमान स्थिति—१९५५ ई० में भारत में १२६ रजिस्टर्ड फैक्टरी थी। उनमें से ११५ के आकड़े प्राप्त हो पाये। इनमें ४०८८ लाख रु० अचल पूजी (Fixed capital) तथा ३७०३ लाख रु० कार्यशील पूजी लगी हुई थी इनमें ७३ हजार मजदूर काम करते थे। मजदूरों के अतिरिक्त और भी १६ हजार आदमी काम करते थे। मजदूरों का १२८६ लाख रु० मजदूरी दी गई तथा दूसरे लोगों को ४७६ लाख रु० वेतन के रूप में दिये गये।

उद्योग की समस्याएँ—

(१) **बित्त**—इस उद्योग को नई मशीनें लगाने तथा पुरानी मशीनों को ठीक करने के लिये बहुत से धन की आवश्यकता है जो कि अभी हमारी शक्ति के बाहर की बात है।

बड़े पैमाने के उद्योग

(२) श्रम—उद्योग के सामने दूसरी समस्या श्रम की है। श्रमिक कार्य कम करना चाहते हैं परन्तु वे ऊँची मजदूरी प्राप्त करना चाहते हैं। इसके कारण बाटा के कारखाने में प्रति टन मजदूरी का खर्च जो १९३९-४० में केवल २७ रुपये प्रति टन था वह बढ़कर आजकल १०१ रुपये प्रति टन हो गया है। इसके विपरीत इस्पात की प्रति मजदूरी उत्पत्ति ३९९ टन से घटकर केवल २३८ टन ही रह गई।

(३) सरकारी नीति—सरकार की इस उद्योग के प्रति कोई मतोपजनक नीति नहीं है। सरकार निजी पूँजी को अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहती। यह उसकी ओर शका की दृष्टि से देखती है। इस कारण उद्योगपति अपना धन लगाते हुये डरते हैं।

उन्नति के मुद्दाय—

उद्योग को उन्नत करने के लिये प्रथम पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित मुद्दाय दिये गये हैं—

(१) उद्योग को बढ़ाया जाय तथा उसका नवीनीकरण किया जाय।

(२) वैज्ञानिक तथा अच्छे ढङ्गों द्वारा इस बात का प्रयत्न किया जाय कि मकान आदि बनाने में फौलाद का प्रयोग कम से कम हो।

(३) उद्योग के लिय अधिक से अधिक धन का प्रवन्ध किया जाय जिसमें उनकी उन्नति में बाधा न पड़े।

Q 60 Trace the growth and development of cotton industry in India mentioning its special problems

प्रश्न ३०—भारतवर्ष में सूती कपड़े के उद्योग का विकास तथा उन्नति उसकी मुख्य समस्याओं को बताते हुये लिखिये।

भारतवर्ष सूती कपड़ा बनाने के लिय सदा ही प्रसिद्ध रहा है। पुराने समय में कपड़ा हाथ से बनाया जाता था। परन्तु १९वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही इस देश में कपड़े का उद्योग चलाने का प्रयत्न आरम्भ हो गया। १८१८ में कलकत्ते में एक सूती कपड़े की मिल चालू की गई। पर कलकत्ता सूती कपड़े के उद्योग के लिय उपयुक्त स्थान न था। इस कारण सूती कपड़े की मिल १८५४ में चालू हुई। प्रारम्भ में बम्बई में सूती कपड़े का उद्योग इसलिये केन्द्रित नहीं हुआ कि वहाँ पर उसके लिये प्राकृतिक साधन थे, वरन् इसलिये हुआ कि वहाँ पर पूँजी की मात्रा अधिक थी, यातायात के साधन उपलब्ध थे और चीन बम्बई से घागा मगाता था। १८७७ ई० से यह उद्योग देश के भीतरी भागों में फैलना शुरू हुआ। प्रथम महायुद्ध में इस उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिला क्योंकि लड़ाई में बाहर से सामान आना बन्द हो गया और सरकार ने भी बहुत सा माल खरीदा। परन्तु यह उद्योग

बिना कठिनाई के युद्ध के पश्चात् ६ वर्ष तक चलता रहा । इसी बीच में जापान तथा अमेरिका से बहुत प्रतियोगिता हुई जिससे भारतवर्ष के उद्योग को बहुत बुरा हानि हुई ।

सरक्षण

इस उद्योग को मरक्षण देने के प्रश्न पर टैरिफ बोर्ड ने १९२७ में विचार किया । बोर्ड ने वह सब कारण बताये जिनके द्वारा यह उद्योग पतन की ओर जाने लगा था और उन सब बातों को दूर करने के उपाय भी बताये । सरक्षण के विषय में बोर्ड ने नीचे लिखे सुझाव दिये—

(१) आयात कर (Import duty) ११ प्रतिशत से बढ़ाकर १५ प्रतिशत कर दिया जाये । (२) ब्रिडिया सूत कातने पर निर्यात वृत्ति (Bounties) दी जाये । (३) उद्योग सम्बन्धी मशीन तथा पुर्जों पर आयात कर न लिया जाय । पर इन सब बातों से भारत की जनता को सन्तुष्टि न हुई । इसलिये इसका कडा विरोध किया गया । इस कारण सरकार ने सूती धागे पर मूल्य के अनुसार (Advelorem) ५ प्रतिशत अथवा $1\frac{1}{2}$ आना प्रति पीड—इन दोनों में से जो भी अधिक हो—सरक्षण कर (Protective Duties) लगाया । पर इससे भी भारतवासियों की सन्तुष्टि न हुई । इसलिये १९२६ में श्री० जे० एस० हार्डी को इस बात की जांच करने के लिये नियुक्त किया कि भारतीय कपड़े के उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से कहां तक हानि पहुंच रही है । श्री हार्डी की रिपोर्ट के छपने पश्चात् सूती कपड़ा उद्योग सरक्षण कर ऐक्ट (Cotton Textile Industry Protection Act) अप्रैल १९३० में पास किया गया । इस ऐक्ट के द्वारा जापान से आने वाले माल पर बहुत अधिक सरक्षण कर लगाया गया । यह ऐक्ट मार्च १९३३ तक के लिये पास किया गया था । १९३१ के दो और ऐक्टों द्वारा इस उद्योग को और भी सरक्षण मिला । इसके फलस्वरूप अङ्गरेजी सादे सफेद कपड़े पर आयात कर मूल्यानुसार २५ प्रतिशत अथवा $8\frac{1}{2}$ आने प्रति पीड, इन दोनों में जो अधिक हो, लगाया गया और इङ्गलैंड के अतिरिक्त और देशों से आने वाले कपड़े पर मूल्यानुसार $31\frac{1}{2}$ प्रतिशत अथवा $8\frac{1}{2}$ आने प्रति पीड इन दोनों में जो अधिक हो, कर लगाया गया । इस कपड़े के अतिरिक्त और सब कपड़े पर २५ प्रतिशत (इङ्गलैंड से आने वाले पर) तथा $31\frac{1}{2}$ प्रतिशत (गैर अङ्ग्रेजी कपड़े पर) कर लगाया गया ।

इसी बीच १९३२ में जापानी मुद्रा का मूल्य बहुत ही अधिक गिर गया । इस कारण जापानी माल के साथ और भी अधिक प्रतियोगिता हो गई । इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार ने पहले आयात कर $31\frac{1}{2}$ प्रतिशत के स्थान पर ५० प्रतिशत तथा इसके पश्चात् ७५ प्रतिशत (मूल्यानुसार) अथवा $6\frac{1}{2}$ आने प्रति पीड कर दिया । इस पर जापान ने कडा विरोध किया । उसने निश्चय किया कि वह भारतवर्ष से कपास न खरीदेगा । भारतवर्ष को इससे बहुत हानि हुई । इस कारण १९३४ में भारतीय-जापान समझौता हुआ । तभी एक समझौता इङ्गलैंड से

भी हुआ। इन दोनों समझौते को ध्यान में रखते हुए १९३४ में भारतीय चुन्नी (कपड़ा संरक्षण) संशोधन ऐक्ट (Indian Tariff Textile Protection Amendment Act) पास किया गया। इस ऐक्ट के अनुसार इङ्ग्लैंड को छोड़कर और देशों से आने वाले माल पर मूलानुसार ५० प्रतिशत (परन्तु कम के कम ५३ प्रतिशत) चुन्नी लगाई गई। कुछ समय पश्चात् इस ऐक्ट की अवधि ३१ मार्च १९३६ तक बढ़ा दी गई। १९३६ में इङ्ग्लैंड के साथ एक नया समझौता हुआ जिसके अनुसार अङ्गरेजी माल पर चुन्नी और भी घटा दी गई है। चुन्नी छप हुआ माल पर १७ प्रतिशत (मूलानुसार) तथा और सब माल पर १५ प्रतिशत (मूलानुसार) हो गई। इस समझौते के अनुसार यदि किसी वर्ष में भारत इङ्ग्लैंड में ३५ करोड़ गज कपड़े से कम खरीदता तो चुन्नी २१% कम हो जाती और यदि ५० करोड़ गज अधिक खरीदता तो चुन्नी बढ़ जाती। इसके बदले में इङ्ग्लैंड ने भारतवर्ष से १९३६ में ५ लाख गट्टे, १९४० में ५३ लाख गट्टे तथा और आगे के वर्षों में ६ लाख गट्टे कपास खरीदने का वचन दिया। ७३ लाख गट्टों से अधिक खरीदने पर इङ्ग्लैंड को कुछ और लाभ हो जाना था। इस देश में इस समझौते की कड़ी आलोचना हुई क्योंकि इससे इङ्ग्लैंड को ही अधिक लाभ था, भारत को अधिक लाभ न था।

द्वितीय महायुद्ध में उद्योग की स्थिति

द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने से पहले इस उद्योग की अवस्था बहुत शोचनीय थी। पर युद्ध के बीच में इसकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई है क्योंकि विदेशी प्रतिযোগिता प्रायः समाप्त हो गई। सरकार की कपड़े की माँग भी बहुत बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अफ्रीका, पारस, लङ्का, मलाया, आस्ट्रेलिया आदि से भी कपड़े की माँग घूँस हुई। इस कारण कपड़े के दाम बहुत बढ़ गये और सरकार को कपड़े पर नियन्त्रण करना पड़ा। सरकार ने सस्ते कपड़ की अपनी दूकानें भी खोली पर इससे कोई विशेष लाभ न हुआ। इस कारण सरकार को उस योजना को छोड़ना पड़ा।

युद्ध के पश्चात् उद्योग की स्थिति

युद्ध के समाप्त होने पर १९४६ में सरकार ने एक अन्तर्कालीन योजना घोषित की जिसके अनुसार भारतीय मिलों को हर वर्ष ६५० करोड़ गज कपड़ा तैयार करना था। १९४७ में इस उद्योग पर से संरक्षण भी हटा दिया गया। १९४७ में देश का विभाजन हुआ जिसके कारण इस उद्योग को बहुत हानि हुई क्योंकि भारतीय मिलें लम्बे घागे वाली अधिकतर कपास सिंध से लिया करती थी। विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान ने राजनीतिक कारणों से वह कपास देनी बन्द कर दी। इसलिये भारतीय सरकार ने मिस्र तथा अमेरिका से कपास खरीदनी शुरू कर दी। अब यह देश इन्हीं देशों में लम्बे घागे वाली कपास खरीदता है।

वर्तमान स्थिति

आजकल खेती के पश्चात् यही उद्योग देश के सबसे अधिक लोगो को रोज-गार देता है। १९५८ ई० के प्रारम्भ में इस देश में ४७० रजिस्टर्ड फैक्टरी थीं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि इस उद्योग में १२० करोड़ रुपये की चल व अवल पूँजी लगी हुई थी। इसमें लगभग ६ मजदूर लगे हुए थे।

१९५३ ई० में इस उद्योग ने उत्पादन का सबसे बड़ा रिकार्ड कायम किया। इस वर्ष कुल ४६० ५ करोड़ गज कपड़ा तैयार हुआ जबकि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केवल ४७० करोड़ गज कपड़े का लक्ष्य रखा गया था। १९५४ में उत्पादन बढ़ कर ५०० करोड़ गज, १९५५ में ५०६ करोड़ गज तथा १९५६ में ५३० ६ करोड़ गज, १९५७ में ५३१ ७४ करोड़ गज तथा १९५८ में ४६२ ७० करोड़ गज कपड़ा तैयार हुआ।

उद्योग की वर्तमान समस्याएँ

आजकल इस उद्योग के सामने बहुत सी समस्याएँ हैं जिनके कारण उत्पत्ति के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। प्रथम तो यह कि महायुद्ध में अधिक समय तक काम करने के कारण मशीनें बहुत घिस गई हैं। जब तक घिसी हुई मशीनों को बदला न जायगा तब तक उत्पत्ति अधिक न बढ़ सकेगी। दूसरे विदेशों में मशीनों के भाव ऊँचे हो रहे हैं। इस कारण बाहर से मंगाई हुई मशीन बहुत महंगी पड़ती हैं। रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् से दाम और भी अधिक हो गये हैं। तीसरे श्रमिकों की मजदूरी कम नहीं हुई। पर वे पहले से कम उत्पत्ति करते हैं। इस समय सूती माल के दाम बढ़ गये। चौथे कपास के दाम भी बहुत ऊँचे हैं। इस कारण कपड़े के दाम भी ऊँचे रहते हैं। पाँचवें मिलों को कभी-कभी कपास न मिलने के कारण भारी सकट का सामना करना पड़ता है। छठे मर्याद की निर्यात की नीति अनिश्चित रही है। इस अनिश्चितता के कारण मिलों को भारी सकट का सामना करना पड़ता है। सातवें माल को इधर-उधर ले जाने के लिये रेल की सुविधा भी कम मिलती है। इस कारण मिलों के पास कभी-कभी बहुत सा माल जमा हो जाता है। आठवें फरवरी १९५२ की मन्दी में तो इस उद्योग की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। प्रायः सभी राज्य सरकारों ने अपना निश्चित कोटा लेने से इन्कार कर दिया। इस कारण बहुत सी मिलें बन्द हो गईं। यद्यपि हाल ही में उत्पत्ति बढ़ रही है परन्तु मन्दी के कारण इस उद्योग की स्थिति बहुत खराब है। नवें युद्धकाल में प्राप्त हुये बाजारों में अब जापान आदि देशों से प्रतियोगिता बढ़ रही है। दसवें नवीनीकरण के प्रश्न पर मिलों व मजदूरों के झगड़े खड़े हो रहे हैं।

उन्नति के सुझाव—

उद्योग को उन्नत करने के लिये राष्ट्रीय योजना कमिशन ने अथ लिखित सुझाव दिये हैं—

एण्ड इन्डस्ट्री द्वारा मचालित एक समा के सामने श्री मुरारजी देसाई भूतपूर्व कामर्च तथा इन्डस्ट्री मन्त्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में जबकि वे अत्यधिक उत्पत्ति तथा स्टॉक के जमा होने की शिकायत कर रहे हैं तब मिल द्वारा बने हुए कपड़े के ध्येय बिन्दु को १४०० मिलियन गज से बढ़ा देना बेमूल है।

अभिनवीकरण व नवीनीकरण के विषय में अपने विचार प्रकट करते हुये उन्होंने कहा कि इस कार्य में अभी देर लगेगी क्योंकि जो मजदूर इस कार्य के द्वारा हटाये जायेंगे उनको किसी दूसरे उद्योग में लगाना आवश्यक है।

उपर्युक्त बात से सरकार का इस उद्योग के प्रति जो रुख है उसका पता चलता है।

Textile Inquiry Committee की रिपोर्ट —

इस समिति की रिपोर्ट जोलाई १९१८ में पेश की गई है। इस समिति का कहना है कि सरकार जिन मिलों को अपने अधिकार में ले उसके लिये उसको एक स्वतन्त्र कारपोरेशन स्थापित करना चाहिये जिसके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी हो।

समिति ने दो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। पहला यह कि अभिनवीकरण (Rationalization) के प्रश्नों पर विचार करने के लिये एक अभिनवीकरण उप समिति का निर्माण किया जाय। दूसरा सुझाव है कि टेक्सटाइल कमिशनर को सलाह देने के लिये एक सलाहकार समिति का निर्माण किया जाय जिसके सदस्य सभी हितों के आदमी हों।

समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी स्थानों पर समान अथवा स्टैण्डर्ड कोस्टिंग पद्धति चालू की जाय।

समिति का सुझाव है कि Cotton Textile Export Promotion Council को अधिक धन प्रदान करना चाहिये जिससे कि वह विदेशों में अपने स्थान खोल सके तथा विदेशी मांग का ठीक अनुमान लगा सके।

माँग से अधिक उत्पत्ति को कम करने के लिये समिति ने सुझाव दिया है कि मिलों को तीन पावों में काम करने दिया जाय तथा अधिक उत्पत्ति पर रिबेट न दिया जाय।

समिति ने यह सुझाव भी दिया है कि बैंकों को सूती उद्योग को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिये।

समिति का मत है कि उत्पादन कर में वर्ष के बीच में कोई परिवर्तन न किया जाय।

विक्री कर के स्थान पर उत्पादन कर लगाने के कारण राज्यों को चाहिये कि वे कोई अनिश्चित कर न लगायें।

१९१५ ई० से सरकार इस उद्योग का सर्वे कर रही है जिससे कि इस उद्योग के आधुनिक सामान व मशीनों की आवश्यकता का पता लग सके। राष्ट्रीय औद्योगिक

विकास कारपोरेशन (National Industrial Development Corporation) इस उद्योग की सहायता इसी सूचना के आधार पर कर रही है। इस कारपोरेशन ने १९५५ तक ३७१ करोड़ ६० के ऋणों की मजूरी दी।

—

Q 61 Review briefly the growth of present position of Indian coal industry

प्रश्न ६१—भारतवर्ष के कोयले के उद्योग की उन्नति और वर्तमान स्थिति के विषय में लिखिये।

कोयला भारतवर्ष की शक्ति के साधनों में सबसे मुख्य है। भारतवर्ष में कोयले का उद्योग देश के दूसरे उद्योग धन्धों की कोयले की मांग के कारण नहीं हुआ बल्कि रेलों की कोयले की मांग के कारण हुआ। जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अंग्रेजी कोयले से सस्ते कोयले की आवश्यकता प्रतीत हुई तो उसने बहुत सी अंग्रेजी कम्पनियों द्वारा कोयले की खानों को खोदना आरम्भ किया। इसके पूर्व कोयला खोदने के लिये ब्रिटेन में प्रयत्न निष्फल रहे। इस प्रकार का पहला प्रयत्न १७७४ ई० में, दूसरा १८१४ में हुआ। १८६५ के लगभग भारतवर्ष में कोयले की उत्पत्ति केवल ५०,००० टन थी। धीरे-धीरे उत्पत्ति बढ़ती रही। १९०० में कोयले की वार्षिक उत्पत्ति ६१,००,००० टन हो गई। इस समय तक कोयले की मांग देश के भीतरी भागों तक सीमित न रह गई थी। भारत का कोयला कुछ दूसरे देशों जैसे जका, मलाया तथा पूर्वी द्वीप समूह आदि को भी जाने लगा। इसी कारण कोयले की उत्पत्ति बढ़ती रही और प्रथम महायुद्ध के पूर्व कोयले की वार्षिक उत्पत्ति १ करोड़ ७४ लाख टन तक पहुँच गई। महायुद्ध में कोयला बाहर से आना बन्द हो गया। इस कारण इस उद्योग की खूब उन्नति हुई। इसके फलस्वरूप १९२० में कोयले की वार्षिक उत्पत्ति १ करोड़ ८० लाख टन के लगभग हो गई। परन्तु रेतगाड़ी तथा मजदूरों की कमी के कारण यह उद्योग बहुत अधिक उन्नति न कर सका। युद्ध समाप्त होने पर बहुत सी नई खानें खोदी गई। पर इस समय भारतीय कोयले की खानों को अफ्रीका से आये हुये कोयले के साथ प्रतिযোগिता करनी पड़ी। देश के भीतर की कोयले की मांग देशों कोयले से ही पूर्ण हो जाये। इस कारण सरकार ने कोयले के निर्यात पर पाबन्दी लगा दी। इससे कोयले की उत्पत्ति पर बहुत प्रभाव पड़ा। पर धीरे-धीरे यह कठिनाई भी दूर हो गई और अब अफ्रीका के कोयले की मांग बहुत ही कम हो गई है।

१९२७ में १९३० के बीच में इस उद्योग की बहुत उन्नति हुई और भारतवर्ष ने खोप हुये बहुत से बाजारों को फिर प्राप्त कर लिया। इसी बीच कोयले की उत्पत्ति बढ़ती रही और १९३० में २,३८०४८ टन हो गई। इसके पश्चात् मन्दी

के कारण कोयले का मूल्य गिर गया और बहुत सी मिलें बन्द होने के कारण देश की कोयले की मांग भी घट गई। इसी कारण इस समय बहुत सी खानें बन्द हो गईं। परन्तु १९३४ ई० से इस उद्योग ने फिर उन्नति करनी प्रारम्भ की और इसकी उत्पत्ति २,३०,१६,६९५ टन हो गई। १९३६ के पश्चात् देश में उद्योग धन्यों की प्रगति शुरू हुई। इसलिये देश के भीतर कोयले की मांग बहुत बढ़ गई। इसके पश्चात् विदेशों में भी भारतवर्ष से कोयला भेजा जाने लगा।

द्वितीय महायुद्ध में उद्योग की प्रगति

युद्ध के प्रारम्भ होने पर कुछ समय तक इस उद्योग ने बहुत उन्नति की। परन्तु आगे चलकर उत्पत्ति घटने लगी। क्योंकि कोयले को इधर-उधर ले जाने के लिये न तो रेलें ही मिलती थी और न जहाज ही। उस समय मजदूरों की भी बहुत कमी हो गई। कोयले की उत्पत्ति बढ़ाने के लिये सरकार को बहुत से काम करने पड़े जैसे मजदूरों को बुलाना, उत्पत्ति बोनस का देना, अधिक लाभ कर में छूट करना तथा अधिक घिसाई (Depreciation) मंजूर करना आदि। इस कारण उत्पत्ति फिर बढ़ी और १९४६ में २ करोड़ ६० लाख टन पहुँच गई।

दिसम्बर १९४५ में सरकार ने एक समिति नियुक्त की जो इस बात की जाँच करे कि पिछले २० वर्षों में इस सम्बन्ध में जो तीन समितियाँ नियुक्त हो चुकी हैं उनके सुझाव क्या हैं तथा उन पर कहाँ तक कार्य किया गया है तथा इस सम्बन्ध में और क्या करना आवश्यक है। इस समिति ने यह सुझाव दिया कि केन्द्रीय सरकार को एक राष्ट्रीय कोयला आयोग नियुक्त करना चाहिये जो कोयले के उद्योग सम्बन्धी सभी बातों की ओर ध्यान दे।

योजना आयोग के सुझावों के अनुसार भारत सरकार ने १९५२ ई० में कोयले की खानों का सुरक्षण तथा सुरक्षा एक्ट पास किया। इसके अनुसार सरकार को कोयले की खानों की रक्षा तथा कोयले के उचित उपभोग के विषय में शक्ति दी गई है। इसके अतिरिक्त सरकार को यह भी शक्ति दी गई है कि वह कोयले पर उपकर लगाये तथा ग्यंगार कोयले (Cooking coal) पर अधिक उपकर लगाये तथा उसको एकत्र करे। एक कोयला बोर्ड की स्थापना भी की गई है। १ जुलाई सन् १९५३ ई० से कोयले के क्षेत्रीय बंटवारे (Regional Distribution) की योजना भी बनाई गई है। अभी हाल ही में एक उच्च शक्ति समिति 'भारत की कोयला काउन्सिल' की स्थापना की गई। इस समिति का कार्य यह होगा कि वह कोयले सम्बन्धी उन्नति की योजना तथा कोयले को बचाकर रखने तथा उसके उपयोग सम्बन्धी बातों पर विचार करे। साधनों का व्यौरा, आवश्यकताओं व उपयोग उत्पादन तथा तैयारी तथा यातायात सम्बन्धी बातों के अध्ययन के लिये ४ समितियाँ बनाई गई हैं।

छोटी-छोटी कोयले की खानों को मिलाने की समस्या का अध्ययन करने के लिये श्री बलवन्तराय महता की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। इसकी

रिपोर्ट नवम्बर १९५६ में प्राप्त हुई। इस समिति ने सुझाव दिया है कि बे खान जिनकी मासिक उत्पत्ति १०,००० टन तथा जिनका क्षेत्र १०० एकड़ से कम है उनको मिलाकर बड़ी समितियाँ बनाई जायें। इसमें यह भी सुझाव दिया है कि कोयले की खानों का एकीकरण आयोग (Collieries Amalgamation Commission) स्थापित किया जाय तथा खानों को मिलाने सम्बन्धी एक कानून पास किया जाए। सरकार इन सुझावों पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार कर रही है। भारत में १९५७ ई० में लगभग ४३५ करोड़ टन कोयले की उत्पत्ति हुई तथा १९५८ में ४५२ करोड़ टन उत्पन्न होने की आशा है। अक्टूबर १९५६ में भारत सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले कोयले को उत्पन्न करने तथा उसका बटवारा करने के लिये वम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत राष्ट्रीय कोयला विकास कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड (National Coal Development Corporation (Private) Ltd) स्थापित की है। सार्वजनिक क्षेत्र में कोयले का उत्पादन शुरू हो गया है और इस साधन से ७ लाख टन कोयला उत्पन्न हुआ। आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी नाम की कोयले की खान का उत्पादन १९५८ में २१ लाख टन हो गया।

इसके अतिरिक्त बहुत सी नई खानों में उत्पादन कार्य आरम्भ हो गया है। रुदकेला तथा भिलाई के इस्पात के कारखानों को कोकिंग कोल देने के लिये एक कोयला घाँसे का कारखाना १९५८ में एक जापानी फर्म की सहायता से स्थापित किया गया है। इसकी लागत २३८ करोड़ रु० है तथा इसकी शक्ति २२ लाख टन कच्चे कोयले की है। दुर्गापुर के लोहे के कारखाने को कोकिंग कोल प्रदान करने के लिये पश्चिमी बङ्गाल सरकार ने पश्चिमी जर्मन फर्म की सहायता से दुर्गापुर कोक ओवन प्लान्ट लगाया है। इसकी लागत ७५ करोड़ रु० है तथा इसकी शक्ति प्रति दिन १००० टन बढ़िया प्रकार के सख्त कोयले की है। यह माच १९५६ में चालू किया गया है।

क्योंकि दक्षिणी भारत में कोयले की कमी है इस कारण वहु उद्देश्य दक्षिणी अर्काट लिगनाइट प्रोजेक्ट को सबसे ऊँची प्राथमिकता दी जा रही है। इसकी लागत ६८८ करोड़ रु० होगी तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस पर ५२ करोड़ रु० खर्च होगा।

सरक्षण का प्रश्न

कोयले के उद्योग ने सरकार से यह प्रार्थना की कि उसको सरक्षण प्रदान किया जाए। इस कारण सरकार ने १९२४ में भारतीय कोयला कमेटी को नियुक्ति की। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय कोयला अच्छी प्रकार का नहीं है इस कारण विदेशियों को उससे बहुत असंतोष रहता है। यदि इस कोयले को ठीक प्रकार से खोदा जाये तथा उसको छाँटकर बाहर भेजा जाय तो उससे बहुत लाभ हो सक्ता है और भारत के खोये हुये बाजार फिर उसको प्राप्त हो सकते हैं। इस कमेटी ने यह सुझाव दिया कि एक भारतीय कोयला ग्रेडिंग बाड को नियुक्ति की

जाए जो कोयले को खानों की अलग अलग तहों को छाटकर कोयले को बाहर भेजने की अनुमति दे। इस बोर्ड की नियुक्ति १९२५ में की गई और जिस कोयले को विदेशों में भेजने की अनुमति कोयला बोर्ड दे देता है उसको रेल का किराया तथा जहाज का किराया कम देना पड़ता है। कोयला बोर्ड की देख-रेख में जो कोयला भेजा जाता है वह बहुत अच्छा होता है और इस कारण भारतीय कोयले की विदेशों में माँग बढ़ गई।

विशेष समस्याएँ

(१) कोयला उद्योग के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या उसको धोने की है। इस कारण न तो यह उद्योग अपने वास्तविक बाजारों को ही प्राप्त कर सकता है और न ही उपभोक्ताओं को सस्त मूल्य पर कोयला दे सकता है।

(२) भारतवर्ष में कोयले के मूल्य में साठ या सत्तर प्रतिशत मजदूरी के दाम हैं। पहले मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता था परन्तु महायुद्ध में मजदूरों का वेतन बहुत बढ़ गया। उनको कम मूल्य पर अनाज मिलता है, कुछ बीनस भी मिल जाता है तथा और बहुत से आराम के साधन उनके लिये एनत्र कर दिये गये हैं। अखिल भारतीय आधार पर नियुक्त किय गये ट्रिब्युनल की सिफारिश के अनुसार कोयले का मूल्य १५ ६० प्रति टन बढ़ गया है। पर खेद का विषय है कि उन्होंने अपनी कोयला खोदने की शक्ति का नहीं बढ़ाया। १९३८ और १९४७ के बीच मजदूरों की सट्टा पहले से ६० या ७० प्रतिशत बढ़ गई पर उत्पात्ति केवल ७ ही प्रतिशत बढ़ी। इसके अतिरिक्त कोयले का मूल्य १९४७ में निर्धारित किया गया था। तब से मजदूरों २०० प्रतिशत तथा कल पुर्जों का दाम ५० प्रतिशत बढ़ गया है। इसके अलावा खानों पर अन्य भी जिम्मेदारियाँ लाद दी गई हैं। अनुमान किया जाता है कि कोयले का उत्पादन व्यय ५० प्रतिशत बढ़ गया किन्तु कोयले के मूल्यों में ३१ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी कारण यह आवश्यकता है कि मजदूरों की अपनी काय-कुशलता बढ़ानी चाहिये।

(३) उत्पादन व्यय के अनुसार मूल्य में वृद्धि न होने के कारण कोयला उद्योग का मुनाफा इतना कम हो गया कि अधिकांश कम्पनियों के लिये लाभार्थ कायम रखना कठिन हो गया है। अतः अपने साधनों के विकास के लिये पूँजी प्राप्त करता उसके लिये अशभव सा हो गया है। ऐसा अनुमान है कि कोयले के शेयरों में रुपया लगाने से वास्तविक आय २ प्रतिशत से अधिक नहीं बैठता तो फिर इस उद्योग में धन कौन लगायगा।

(४) भारतवर्ष में कोयले के उद्योग पर बड़ा भारी सरकारी नियन्त्रण है। यह न केवल उसके मूल्य तथा बटवारे पर ही है वरन् दूसरे ढङ्ग से भी है। उदाहरण के लिये सरकार ने Coal Mines Conservation and Safety Rules को लागू किया है जिनके कारण सरकार के खान खोदने के ढङ्ग, धोने के स्थानों की स्थापना करने आदि पर कड़ा नियन्त्रण है।

(५) भारतवर्ष में वैज्ञानिक ढङ्ग से कोयला नहीं खोदा जाता। बहुत सा कोयला खोदने में नष्ट हो जाता है। इसी कारण इस बात की आवश्यकता है कि कोयले को ठीक प्रकार में खोदा जाये ताकि खोदने में कोयला कम से कम नष्ट हो।

आजकल कोयला खोदने में बहुत नये साधनों का उपयोग किया जा रहा है। उनमें से उत्पत्ति के बहुत कुछ बच जाने की आशा है। यदि कोयले के इधर-उधर ले जाने का कोई सस्ता ढङ्ग निकल आये तो विदेशों में हमारा कोयला बहुत मात्रा में जा सकता है क्योंकि ऐसा कहते हैं कि खान के मुह पर भारतीय कोयला सबसे सस्ता होता है।

योजना आयोग के सुझाव

योजना आयोग ने इस उद्योग को उन्नत करने के लिय निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

(१) कोयले के भण्डार का अनुमान लगाया जाए तथा उसका एक नक्शा तयार किया जाए।

(२) बिहार और बंगाल की कोयले की खानों के आस-पास जो रेल आदि के साधन हैं उनके विषय में आँकड़े एकत्र किय जायें।

(३) कोयले के भण्डार की भौतिक तथा रासायनिक जाँच की जाये तथा उसका फिर से वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण किया जाये।

(४) कोयले की यातायात का अभिनवीकरण (Rationalisation) किया जाए जिससे कि उसकी उत्पत्ति तथा वितरण का अभिनवीकरण किया जा सके।

(५) ईंधन अन्वेषणशाला को कोयले के विषय में अन्वेषण (Research) करना चाहिये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा कोयले के उद्योग—जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष १९५५-५६ के लिये कोयले के उत्पादन का बिन्दु ३० मिलियन टन रखा गया था, द्वितीय योजना के अन्तिम वर्ष १९६०-६१ के लिये यह ६० मिलियन रखा गया है। इसमें से १० मिलियन टन अतिरिक्त कोयला सार्वजनिक क्षेत्र तथा २० मिलियन टन निजी क्षेत्र के लिये रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की उत्पत्ति के लिये योजना में ४० करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है परन्तु आवश्यकता ६० करोड़ रुपये की है। शेष रुपये को इधर-उधर से बटवारा करके प्राप्त किया जायँगा।

ये रंगो व प्लास्टिक में काम में लाओगे, अपने पौधों पर छिड़कोगे, अपने पशुओं को इलाओगे ।

(५) करों की अधिकता—भारतवर्ष में चीनी पर उत्पादन कर केन्द्रीय सरकार लगाती है तथा गन्ने पर उपकर (cess) राज्य सरकारें लगाती हैं । १९५८-५९ के बजट के अनुमान के अनुसार भारत सरकार को ४४.१८ करोड़ रुपये प्राप्त की आशा है । चीनी पर उत्पादन-कर बढ़ने से १२.१८ करोड़ रुपये आय प्राप्त होने का अनुमान है । राज्य सरकारें गन्ने पर जो उपकर लेती हैं वे केवल उत्तर प्रदेश व बिहार में १९५५-५६ में ३५० लाख व १५६.०६ करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई । यद्यपि यह उपकर गन्ने को उन्नत करने के लिए दिया जाता है तो भी इसमें से बहुत सा धन दूसरे कामों में लगा दिया जाता है । १९५५-५६ में उत्तर प्रदेश में केवल ४७.६० लाख रुपये इस कार्य के लिये खर्च किये गये ।

(६) सरकारी नियन्त्रण—केन्द्रीय सरकार न केवल चीनी का ही मूल्य नियंत्रित करती है बल्कि यह गन्ने का मूल्य भी नियंत्रित करती है । इस कारण किसानों के उत्पादकों को बहुत कम लाभ होता है ।

उन्नति के सुझाव

चीनी उद्योग को सुधारने के लिये योजना आयोग ने निम्नलिखित सुझाव हैं—

(१) नई मिलों के स्थापित करने की अपेक्षा पुरानी मिलों को उनकी अधिक-क्षमता तक चलाना चाहिये ।

(२) जो मिलें गन्ने की पूर्ति के स्थानों से दूर बसी हैं उनको अपनी स्थिति अपनी चाहिये जिससे कि भाड़े का खर्च कम हो जाये ।

(३) वर्तमान उत्पत्ति के ढङ्ग का सावधानी से संरक्षण किया जाय ।

(४) राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किये गन्ने के उपकर को गन्ने के अनुसंधान खर्च किया जाय ।

(५) उद्योग को मशीनों को प्राप्त करने की सुविधा दी जाय जिसमें कि वे नई हुई व पुरानी मशीनों के बदले उनको लगा सकें ।

(६) सरकार को समय-समय पर चीनी की उत्पत्ति पर नियन्त्रण, गुण व मूल्यों के मुन्यों का उतार-चढ़ाव आदि पर विचार करना चाहिये जिससे कि चीनी व गन्ने के उद्योग की उचित प्रकार की उन्नति हो सके ।

(७) यह आवश्यक है कि किसान के गन्ने का मूल्य केवल गन्ने के बहन के हार न दिया जाय बल्कि गन्ने में चीनी की मात्रा के अनुसार दिया जाय । ऐसा करने पर किसान गन्ने के गुण को सुधारने का प्रयत्न करेगा ।

अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश से चीनी के ६४ उत्पादकों में से ३० उत्पादकों

को उद्योग के नवीनीकरण (Modernization) की योजनाये तैयार करनी है। इसका उद्देश्य उद्योग की व्यवस्था सुधारना है।

द्वितीय योजना के लिये चीनी के उत्पादन का ध्येय २२५ लाख रुपये रखा गया है। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिये ३७ नई मिलों को लाइसेंस दिया गया है तथा ४० मिलों को अपनी उत्पादन शक्ति बढ़ाने की आज्ञा दी गई है। इस उद्योग की कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिये मिल क्षेत्रों में यातायात की सुविधा बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है तथा गन्ने की सिंचाई करने के लिये नल, कुएँ खोदे जा रहे हैं।

चीनी उद्योग की उन्नति सभा के सुझाव के अनुसार भारत सरकार ने पाँच आदमियों का एक प्रतिनिधि मण्डल आस्ट्रेलिया तथा इन्डोनेशिया भेजा था जिसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को मार्च १९५६ में पेश की। इस रिपोर्ट में चीनी के उद्योग को उन्नत करने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

(१) चीनी के मूल्य पर कंट्रोल न लगाया जाय क्योंकि भारत तथा आस्ट्रेलिया का अनुभव है कि इसके कारण उद्योग के विकास में बाधा पड़ती है।

(२) चीनी व गुड़ की बिक्री के लिये कोई केन्द्रीय बिक्री सभा नियुक्त न की जाय।

(३) चीनी के मूल्य तथा बटवारे पर जो नियन्त्रण है तथा सरकार ज २५% चीनी को नियन्त्रण मूल्य पर बेचने का अधिकार रखती है तथा सरकार जो चीनी को विदेशों से मगाकर उसको निश्चित मूल्य पर बेचती है उस नीति को वर्तमान में कायम रखा जाय।

(४) सरकार को हर वर्ष गुड़ की न्यूनतम कीमत निश्चित करनी चाहिये जिससे कि गुड़ व चीनी के मूल्य तथा सम्पत्ति में समतोल (Balance) स्थापित हो सके। सरकार को हर मौसम के शुरू में यह घोषित करना चाहिये कि यदि गुड़ का मूल्य बाजार में निश्चित मूल्य से कम होगा तो वह उसको स्वयं खरीदेगी। सरकार को गुड़ खरीदने के लिये गुड़ के मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में सहकारी समितियाँ स्थापित करनी चाहियें।

(५) गन्ने का मूल्य निश्चित करने के लिये सरकार को स्थायी सलाहकार समिति नियुक्त करनी चाहिये जिसमें गन्ना उगात वाले तथा मिलों के बराबर बराबर प्रतिनिधि हों तथा जिसका सभापति एक जज हो।

(६) गन्ना उगाने वालों को गन्ने का मूल्य उसके गुण के अनुसार देना चाहिये।

(७) गन्ने की प्रति एकड़ उपज को बढ़ाने के लिये मण्डल ने निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

गन्ने का उन्नत बीज बोना तथा गन्ने की बीमारियों से बचना, आस्ट्रेलिया, जावा आदि से बढ़िया प्रकार के गन्ने का आयात करना तथा उसको भारत में उत्पन्न

१९१४ ई० के महायुद्ध से पहले विदेशी कागज की प्रतियोगिता के कारण कागज के उद्योग की अवस्था बड़ी खराब हो गई। उस समय तक देश में केवल २ मिलें थी। १९०५ ई० में इस उद्योग की संरक्षण देने के विषय में टैरिफ बोर्ड ने विचार किया। जांच के पश्चात् उसने केवल बांग्ला में तैयार होने वाले कागज को ही संरक्षण देने की सिफारिश की। सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया और तत्पश्चात् वर्षों के लिये संरक्षण दिया। १९३१ ई० में संरक्षण की अवधि १९३६ ई० तक बढ़ा दी गई।

द्वितीय महायुद्ध में विदेशों से कागज आना बन्द हो गया परन्तु कागज की मांग बढ़ गई। अतः भारतीय मिलों ने पूरी शक्ति लगाकर उत्पादन कार्य किया। १९३८ ई० के फलस्वरूप कागज की उत्पत्ति जो १९३८-३९ ई० में ५६,१६२ टन थी बढ़ गई। १९४४ में १,०३,८८४ टन हो गई। इस बीच कागज की मिलों की संख्या ६ में बढ़कर १५ हो गई।

विभाजन के फलस्वरूप बङ्गाल में मिलों के सामने एक बड़ी कठिनाई आ गयी। क्योंकि इन मिलों में कच्चा माल अर्थात् घास और बांस पूर्वी बङ्गाल के जंगलों में से आता था परन्तु पाकिस्तान बन जाने के कारण इन चीजों का मिलना मुश्किल हो गया। परन्तु कुछ समय पश्चात् जब में सब चीजें देश के दूसरे भागों से आने लगीं तो यह समस्या समाप्त हो गई। तब कागज का उत्पादन बढ़ने लगा।

युद्ध काल में दूसरे उद्योगों के समान इस उद्योग को भी संरक्षण दिया गया। १९४६ ई० तक चलता रहा। १९४६ ई० में संरक्षण की अवधि को एक वर्ष के लिये बढ़ाया दिया गया। १९४७ ई० में टैरिफ बोर्ड ने इस उद्योग की जांच करके बताया कि इसको आयात-कर लगाकर संरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ने टैरिफ बोर्ड की इस सिफारिश को मानकर १ अप्रैल १९४७ ई० से कागज और लुग्दी के आयात पर से संरक्षण हटा लिया।

वर्तमान स्थिति

प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में इस देश में १७ कागज की मिलें थी। छह चार सालों में भारत में कागज का उत्पादन लगभग ५० हजार टन बढ़ गया। १९५० में कागज का उत्पादन १,०८,८१२ टन था पर १९५५ में बढ़कर १,४८ हजार टन, १९५६ में १,६३ हजार टन तथा १९५७ में २,१०,१ हजार टन हो गया।

वर्तमान कारखानों की विस्तार योजनाओं और नये कारखानों की स्थापना के फलस्वरूप, इस उद्योग की उत्पादन-क्षमता ३५२० हजार टन में अधिक होगी। देश को प्रति वर्ष लगभग २ लाख टन कागज की जरूरत होती है। केवल ही उद्योगों और उपभोक्ताओं के लिये विशेष प्रकार का कागज बाहर न मगाना पड़ेगा।

इस समय कागज उद्योग में २८००० व्यक्ति काम कर रहे हैं जिनमें से

२१०० शिल्पिक कर्मचारी है १९६०-६१ तक कर्मचारियों की सख्या ४४,००० तक पहुच जायेगी, जिनमे ४ हजार शिल्पिक होंगे। इस उद्योग मे इस समय २१.६२ करोड रुपया लगा हुआ है। नई योजनाओ के अन्तर्गत १४.३ करोड रुपया और लगने की आशा है। इसका अर्थ यह हुआ कि २२ करोड रुपये की लागत और लगा देने पर यह उद्योग १९६०-६१ तक ३,७०,००० टन कागज के उत्पादन की क्षमता प्राप्त कर लेगा और इस प्रकार अभिष्ट लक्ष्य प्राप्त हो जायगा।

पिछले पाच सालो मे कागज की प्रति व्यक्ति खपत ५० प्रतिशत बढ गई। देश मे साक्षरता के प्रचार और रहन-सहन के स्तर मे सुधार के कारण खपत तेजा से बढती जा रही है। खाद्य और कृषि संगठन के एक कागज विशेषज्ञ का कहना है कि १९६१-६२ तक खपत ४,८१,००० टन तक पहुच सकेगी।

इस समय २१ कारखाने कागज बना रहे हैं। इनमे से ७ दक्षिण भारत मे, ६ बम्बई और मध्य प्रदेश मे, २ पंजाब और मध्य प्रदेश मे तथा ६ पश्चिम बङ्गाल, बिहार और उड़ीसा मे हैं। बास, सर्वाई घास, खोई, शिथडे, रद्दी कागज, तरु तरह के रेशे आदि चीजे, जो इस उद्योग मे कच्ची सामग्री के रूप मे इस्तेमाल की जाती हैं देश मे मौजूद है।

विशेष समस्याये

कागज के उद्योग के सामने निम्नलिखित समस्यायें है—

(१) कागज की मिलें आदर्श आकार (Optimum size) की नहीं हैं। इसलिये इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है। कम से कम ८ हजार टन प्रतिवर्ष कागज की उत्पादन करने वाली मिल आर्थिक इवाई समझी जाती है। इसलिये छोटी मिलो को स्तर पर लाना चाहिये।

(२) देश मे अखबार व छपाई का कागज उत्पन्न नहीं होता। परन्तु इसको बास से बनाया जा सकता है। भविष्य मे इसको बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। अखबार का कागज बनाने का पहला कारखाना जनवरी १९५५ मे चालू किया गया इसकी निर्मित क्षमति ३०,००० टन है जबकि मांग ७०,००० टन वार्षिक है।

(३) देश मे इस समय लगभग २ लाख टन कागज की आवश्यकता है यदि कागज बनाने मे बास का उपयोग करे तो हमको विदेशो से कागज मगाने की आवश्यकता न रहेगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कागज का उद्योग—

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १८० हजार टन कागज, २० हजार टन अखबारी कागज तथा ७५ हजार टन कार्ड बोर्ड के उत्पादन का निश्चय किया गया था। इस योजना मे कागज तथा दफती के उद्योग की उन्नति के लिये ५३५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई थी। यह हर्ष की बात है कि प्रथम योजना मे निश्चित बिन्दु को लगभग प्राप्त कर लिया गया।

कागज की उत्पत्ति में वृद्धि बहुत कम अतिरिक्त पूँजी लगाकर प्राप्त की गई है क्योंकि इस उद्योग ने अपने लाभ की हिस्सेदारी में न बाँटकर उद्योग में ही लगा दिया ।

योजना कमीशन ने इस उद्योग को बढ़ाने के लिये तो सुझाव दिये थे । पहला, विकास सभा की स्थापना तथा दूसरा कच्चे माल की जाँच करना जिससे कि नई व पुरानी मिलों की उन्नति हो सके । सरकार ने विकास सभा स्थापित न करके १९५५ में एक पेपर पैन्ल की स्थापना की घोषणा की है । कच्चे माल की जाँच के लिये भी सरकार ने एक (Adhoc Committee) नियुक्त की है ।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत—

इस योजना में उद्योग की उत्पादन लक्ष्यता ५,५०,००० टन तथा उत्पत्ति ३,५०,००० टन रखने का ध्येय रखा गया है ।

विशेष समस्याओं में पहली समस्या यातायात की है जिसके मुलङ्गने की आशा द्वितीय योजनाकाल में भी नहीं है क्योंकि रेलवे मन्त्री ने कहा है कि लोहे इस्पात तथा कुछ सीमा तक कोयले व सीमेंट के उद्योग को छोड़कर रेल दूसरे उद्योगों की आवश्यकता पूरी न कर सकेंगी ।

दूसरी समस्या उत्पत्ति कर का संग्रान है । इसके कारण कागज का मूल्य बढ़ जाता है तथा कागज के उपभोग तथा उसकी उत्पत्ति दोनों पर ही उसका प्रभाव पड़ता है ।

Q 65 Trace the growth and development of the Indian cement industry mentioning its special problems

प्रश्न ६५—भारतीय सीमेंट के उद्योग के विकास तथा उन्नति के विषय में उसकी मुख्य समस्याओं को बताते हुए लिखिए ।

हमारे देश के लिए सीमेंट की बड़ी आवश्यकता है क्योंकि यह मकानों, पुलों बाँधों, शहरीयों आदि के बनाने के काम में आता है । हमारे देश में मकानों का अभाव है । नई-नई सिंचाई व बिजली की योजनाएँ चल रही हैं । ट्यूब वेल बनाए जा रहे हैं । इन सबको सीमेंट बिना नहीं बनाया जा सकता ।

प्रथम महायुद्ध से पूर्व हमारे देश में सीमेंट उद्योग का कोई महत्वपूर्ण स्थान न था । १९१४ से पहले भारतवर्ष प्रतिवर्ष एक लाख टन सीमेंट विदेशों से मगाया करता था । परन्तु १९१८ ई० के पश्चात् सीमेंट की माँग बढ़ती चली गई और अब वह माँग बहुत अधिक बढ़ गई है ।

भारतवर्ष में सबसे पहली सीमेंट फैक्टरी मद्रास में चालू की गई परन्तु पर्याप्त मात्रा में सीमेंट की उत्पत्ति १९१२ ई० से हुई जबकि पोरबन्दर (वाठियावाट) मध्य प्रदेश, राजपूताना आदि में सीमेंट की फैक्टरियाँ स्थापित की गईं । प्रथम

महायुद्ध में सीमेण्ट की मांग बढ़ जाने के कारण इस उद्योग ने बड़ी प्रगति की। युद्ध समाप्त होने पर सीमेण्ट की मांग बनी रही जिसके फलस्वरूप देश में बहुत सी सीमेण्ट की फैक्टरियाँ चालू हुईं। १९२३ ई० तक पुरानी तीन फैक्टरियों की उत्पत्ति दुगुनी हो गई तथा छ नई फैक्टरियाँ खोली गईं। इसके फलस्वरूप सीमेण्ट की उत्पत्ति जो १९१४ ई० में केवल ६४५ टन थी बढ़कर २,३६,७४६ टन हो गई। सीमेण्ट की उत्पत्ति बढ़ जाने के कारण इसका आयात बहुत घट गया।

१९२४ ई० में इस उद्योग ने सुरक्षण की मांग की परन्तु टैरिफ बोर्ड ने इसको सुरक्षण न देने की सिफारिश की। बोर्ड का मत था कि उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से हानि नहीं हो रही है, वरन् वापसी प्रतियोगिता तथा अत्यधिक उत्पत्ति के कारण ऐसा हो रहा है। बोर्ड ने वन्दरगाह वाले नगरों में बिकने वाले सीमेण्ट के लिये उनके कारखानों को नकद द्रव्य के रूप में सहायता देने की सिफारिश की परन्तु सरकार ने उसे नहीं माना। बोर्ड ने यह भी गुआव दिया कि सीमेण्ट के उत्पादकों में आपस में मेल व सहयोग होना चाहिए।

१९२७ में भारतीय सीमेण्ट उत्पादकों की एक सभा बनाई गई जिसका कार्य सीमेण्ट के विषय मूल्य पर नियन्त्रण करना था। इस सभा ने सीमेण्ट फैक्टरियों से ५ आने प्रति टन की दर से एक कर गणन किया जिससे जनता में देशी सीमेण्ट के उपभोग के लिए प्रचार किया जाय। १९३० ई० में सीमेण्ट मार्केटिंग कम्पनी की स्थापना की गई। इसका कार्य प्रत्येक फैक्टरी का उत्पादन निश्चित करना था। परन्तु इस कम्पनी की स्थापना से कोई विशेष लाभ न हुआ। १९३२ में एसोशियेटेड सीमेण्ट कम्पनी का निर्माण किया गया जिसका उद्देश्य आन्तरिक तथा बाह्य प्रतियोगिता से सीमेण्ट फैक्टरियों को बचाना था। परन्तु १९३६ में डालमिया सीमेण्ट कम्पनी के स्थापित होने पर प्रतियोगिता बहुत बढ़ गई और इस उद्योग को बड़ी हानि हुई। परन्तु १९४० ई० में डालमिया तथा एसोशियेटेड कम्पनियों में समझौता हो गया।

द्वितीय महायुद्ध में सीमेण्ट की मांग न केवल देश में ही बढ़ गई वरन् विदेशों से भी इसकी मांग होने लगी। इस कारण सरकार ने इसके ऊपर नियन्त्रण किया और कुल उत्पत्ति का लगभग ८०% अपने हाथ में ले लिया। इस कारण जनता को बड़ा कष्ट हुआ। सीमेण्ट की कमी के कारण उसका मूल्य भी बेहद बढ़ गया।

यहूकाल में सीमेण्ट की मजदूरी, अधिक उत्पत्ति, १९३३-३४ ई० में हुई जबकि २२ लाख टन सीमेण्ट उत्पन्न किया गया। उसके पश्चात् मजदूरी के झगड़ों, कोयला न मिलने, यातायात की कठिनाइयों आदि बातों के कारण इसकी उत्पत्ति कम होनी चली गई। १९४६-४७ में इसकी उत्पत्ति घटकर बस १० लाख टन रह गई।

विभाजन के पूर्व भारत में सीमेण्ट के २५ कारखाने थे जिनमें २८ लाख टन सीमेण्ट तैयार करने की शक्ति थी। विभाजन के कारण ६ कारखाने पाकिस्तान में

चले गये और हमारी उत्पादन शक्ति घटकर २१ लाख टन रह गई। इसका अनिश्चित विभाजन के कारण हमारे देश में जिप्सम (जो सीमेण्ट बनाने का काम आता है) की कमी हो गई। इससे सीमेण्ट बनाने में कठिनाई होने लगी। परन्तु अब हमारे देश के सौराष्ट्र तथा राजपूताने के प्रदेशों में जिप्सम की उत्पत्ति बढ़ने की आशा है जिसके फलस्वरूप हमारी कठिनाई दूर हो जायगी।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमारे देश में १९५५-५६ तक २७ फीक्टरिया होने की आशा थी। इनकी उत्पादन शक्ति ५३.०६ लाख टन तथा वास्तविक उत्पत्ति ४८.० लाख टन होनी थी। उस समय ३ लाख टन सीमेण्ट का निर्यात भी किया जाने वाला था।

आजकल हमारे देश में सीमेण्ट का उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है। जहाँ देश के विभाजन के बाद सीमेण्ट उद्योग की सामर्थ्य २१.१५ लाख टन थी वहाँ १९५७ तक यह ६५.३४ लाख टन तक पहुँच गई है। १९५४ में सीमेण्ट का उत्पादन ४३.९८ लाख टन के लगभग था। परन्तु १९५८ में सीमेण्ट की उत्पत्ति ६०.६ लाख टन पहुँच गई है।

१९५५ में हमारे देश में २५ रजिस्टर्ड फीक्टरिया थी, परन्तु १९५८ में उनकी संख्या ३१ हो गई उनमें से २४ में ३३ लाख ६० की चल व अचल पूँजी लगी हुई थी। उस समय इस उद्योग में ७० हजार लोगों से भी अधिक काम करते थे।

द्वितीय योजना के लिये सीमेण्ट की उत्पत्ति का ध्येय बिन्दु १ करोड़ टन रह रखा गया है।

विशेष समस्याय

(१) माँग की कमी—द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ से ही देश में सीमेण्ट का उत्पादन माँग से कम चल रहा था। परन्तु गतवर्ष सीमेण्ट उद्योग के सामने एक नयी समस्या खड़ी हो गई क्योंकि सीमेण्ट की माँग उत्पादन से कम पड़ गई तथा कारखानों के पास ज्यादा मात्रा में माल जमा हो गया है। इसके कई कारण थे। एक तो इस्पात की कमी से विकास योजनाओं की प्रगति धीमी पड़ गई। पहले सरकार सम्पूर्ण उत्पादन का ८० प्रतिशत लिया करती थी परन्तु गतवर्ष उसकी माँग ४० से ४५ प्रतिशत रह गई।

(२) पूँजी की कमी—अनुमान किया गया है कि सीमेण्ट की उत्पादन क्षमता प्राय १०० लाख टन वृद्धि के लिये १०० करोड़ रुपये की पूँजी की आवश्यकता होगी क्योंकि लागत व्यय बढ़ता जा रहा है। योजना आयोग ने इसके लिये ८१ करोड़ रुपये पूँजी की ही व्यवस्था की है। वर्तमान स्थिति में उद्योग के लिये इतनी पूँजी प्राप्त करना कठिन होगा क्योंकि न तो वह आन्तरिक साधनों से इतनी ज्यादा बचत कर सकता है और न शेष पूँजी जारी करके।

(३) विदेशी विनिमय की कमी—विदेशिक विनिमय की समस्या भी कम जटिल नहीं है। भारत में योजना आयोग ने योजना की प्रगति की समीक्षा करते

हुए यह विचार व्यक्त किया था कि, उद्योग की उत्पादन क्षमता ८६ लाख टन बढ़ाने के लिये विदेशिक विनिमय उपलब्ध हो सकेगा।

(४) यातायात की कठिनाई—सीमेन्ट उद्योग के विकास के लिये यातायात की भी विशेष आवश्यकता है। रेलवे मंत्रालय ने १९६०-६१ तक ६० लाख टन सीमेन्ट के यातायात की योजना बनायी है। अतः इससे ज्यादा उत्पादन में वृद्धि होने पर यातायात की कठिनाई भी उत्पन्न हो सकती है।

Q. 66 Heavy, small and other industries all need to be developed at the same time in the present economic conditions of India. Do you agree? Give reasons for your answer. How can the small-scale industries hold their own against large-scale industries?

प्रश्न ६६—भारी, छोटे तथा दूसरे उद्योग—सबको भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति में एक साथ उन्नत होने की आवश्यकता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण दीजिये। छोटे पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों का किस प्रकार सामना कर सकते हैं?

इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व हमको भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति से परिचय कर लेना आवश्यक है। भारतवर्ष औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है। इस देश में आधारभूत उद्योगों का तो पता ही नहीं है दूसरे प्रकार के उद्योग भी बहुत कम पाये जाते हैं। कुटीर उद्योग, जिनके लिये भारतवर्ष भूतकाल में सस्तर में प्रसिद्ध था, वे भी आजकल पिछड़ी हुई दशा में कहे जा सकते हैं और तो और कृषि उद्योग भी जिसके ऊपर भारत की ७० प्रतिशत जनता निर्भर है बहुत बुरी हालत में है। ऐसी स्थिति में यह बात आवश्यक ही जान पड़ती है कि हमारे देश में भारी, छोटे तथा कुटीर उद्योग सब एक साथ उन्नत किये जायें।

कई बार हमारे देश में इस बात पर तर्क-वितर्क होता है कि देश में कुटीर उद्योग उन्नत किये जायें अथवा बड़े पैमाने के उद्योग। महात्मा गांधी तथा उनके विचार से सहमत लोगों का मत है कि देश में केवल कुटीर उद्योगों की ही उन्नति हो क्योंकि इससे देश के अधिकतर लोगों को रोजगार मिलेगा तथा देश में धन का समान वितरण हो जायेगा। इसके विपरीत कुछ लोगों का मत है कि जब सस्तर के दूसरे देश औद्योगिक दृष्टि से दोनों दिन उन्नति करते जा रहे हैं तब हमको कुटीर उद्योगों के ऊपर ध्यान न देकर केवल बड़े पैमाने के उद्योगों पर ही ध्यान देना चाहिए। परन्तु ये दोनों ही विचारधाराएँ गलत हैं। सत्य बात यह है कि हमको सब प्रकार के उद्योग-धन्धों पर ध्यान देना चाहिये और यदि ध्यान पूर्वक देखा जाय तो पड़े के उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों में इस प्रकार के वाद-विवाद

होने की कोई मु'आयस नहीं है क्योंकि दोनों के क्षेत्र अलग-अलग निश्चित विषे जा सकते हैं। इस विषय पर अपने एक भाषण में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने अप्रैल १९५४ ई० में कहा था कि ग्रामोद्योगों तथा विपुल पूंजी और भारी मशीनों से बड़े पैमाने पर चलाए जाने वाले उद्योगों में परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए। इन दोनों प्रकार के उद्योगों की प्रणाली अलग-अलग है। दोनों अपनी-अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं और यदि उनके कार्य क्षेत्र अलग कर दिये जायें तो दोनों देश के लिये हितकर हो सकते हैं। इसलिये यह सोचना भूल है कि इस औद्योगीकरण के युग में ग्राम उद्योगों का कोई स्थान नहीं अथवा इनके बारे में सोचना आधुनिक विचारधारा के प्रतिवृत्त है। आज के युग में यह कोई नहीं चाहेगा कि रेल की पटरियाँ अथवा समुद्री या हवाई जहाज किसी लुहार के घर में बनाये जायें। यह न तो सम्भव है और न विचारणीय। यह मानना ही होगा कि इनसे यदि हम बचना भी चाहें तो बच नहीं सकते। इस प्रकार की चीजें होने बड़े कारखानों में ही बनानी पड़ेंगी पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं और उनके भी कुछ ऐसे अंग और पुर्जें हो सकते हैं जो घरों में बनाये जा सकते हैं। पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिना कठिनार्द के घरेलू तौर पर बन सकती हैं और वे जीवन की अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं में से हैं। इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन यदि घरेलू उद्योगों से कराया जाय तो सबका लाभ होगा। एक ओर बेरोजगारी का भय बहुत दूर तक हल हो सकेगा और दूसरी ओर जो कल पुर्जों के लिए विदेशों का मुँह देखना पड़ता है वह भी बच सकेगा इसलिए हमारी पंचवर्षीय योजना में इन दोनों प्रकार के उद्योगों को स्थान दिया गया है। जहाँ कोयला, कागज, सीमेंट आदि बड़े उद्योगों में उत्पादन की वृद्धि पर जोर दिया गया है, वहाँ देहात के घरेलू उद्योगों को हट करने और जहाँ वे सुख हो गये हैं इन्हें फिर से चलाने की सलाह दी गई है।

उन्होंने आगे कहा कि मेरी राय में हमारे देश की सम्पन्नता के दो अंग हैं और ये एक दूसरे के पूरक हैं। भारत में ही नहीं विदेशों में भी लोगों का ऐसा ही मत है। ऐसे देशों में भी जो औद्योगीकरण की दृष्टि से काफी उन्नत हैं, ग्राम उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है। इंग्लैंड, संयुक्त राष्ट्र अमरीका, जापान आदि के उदाहरण हमारे सामने हैं।

ऊपर के कथन से यह बात स्पष्ट रूप से समझ में आ सकती है कि आज देश को न केवल बृहत्तर उद्योगों की ही आवश्यकता है बल्कि बड़े पैमाने के उद्योग की भी। संसार में जीवित रहने तथा उन्नति करने के लिये हमारे देश में कई प्रकार के उद्योगों की आवश्यकता है और उन सबका उन्नत करना आवश्यक है। उदाहरण के लिये देश की रक्षा के लिये हवाई व समुद्री जहाजों के उद्योग, वन, अणु वन व परमाणु बमों के उद्योग, देश की यातायात की समस्या को हल करने के लिये रेल के इंजिन व गाड़ियाँ, मोटरकार आदि के उद्योग, देश में मशीनें बनाने के लिये जिससे कि हमको मशीनों के लिये विदेशों का मुँह न ताकना

पड़े, बड़े-बड़े आधारभूत उद्योग, देश में लोगों के जीवन-स्तर को उठाने के लिये कुटीर व उपभोग से सम्बन्धित उद्योग, बड़े व छोटे उद्योगों को कच्चा माल व शक्ति प्रदान करने के लिये खेती, खनिज पदार्थ व बिजली उत्पन्न करने वाले उद्योगों का उन्नत करना परम आवश्यक है। हम इनमें से किसी प्रकार के उद्योग को नहीं छोड़ सकते। यही कारण है कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में इन सब बातों को ध्यान में रखकर सब प्रकार के उद्योगों की उन्नति पर जोर दिया गया है। जहाँ प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्य समस्या को सुलझाने के लिये कृषि उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था वहीं द्वितीय योजना में देश को औद्योगिक दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाने के लिए बड़े पैमाने तथा दूसरे प्रकार के उद्योगों की उन्नति पर जोर दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश में कुटीर भारी, तथा दूसरे प्रकार के उद्योगों को एक साथ उन्नत करने की आवश्यकता है।

छोटे पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने के उद्योगों का किस प्रकार सामना कर सकते हैं—छोटे-बड़े पैमाने के उद्योगों का महत्व बताते समय हम सिखा आये हैं कि वास्तव में देखा जाय तो छोटे पैमाने तथा बड़े पैमाने के उद्योगों में कोई प्रतियोगिता नहीं है। यह प्रतियोगिता इसलिये होती है कि एक ही चीज को जब बड़े व छोटे दोनों पैमानों पर उत्पन्न की जाती है तो सामना करने का प्रश्न आकर खड़ा हो जाता है। परन्तु यदि दोनों प्रकार के उद्योगों के कार्य-क्षेत्र निश्चित कर दिये जायें तो मुकाबला करने का प्रश्न ही नहीं रहता। योजना कमिशन ने इस प्रतियोगिता को समाप्त करने के तीन ढंग बताये हैं—

(१) उत्पादन के क्षेत्रों को बाँट देना अथवा निश्चित कर देना,

(२) जहाँ तक हो सके बड़े पैमाने के उद्योगों को न चलाया जाय,

(३) बड़े पैमाने के उद्योग पर उप-कर लगाना जिससे कि उसी प्रकार के छोटे पैमाने के उद्योग को लाभ पहुँचे। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि बड़े पैमाने के उद्योगों की वृद्धि पर रोक लगाते समय उस वस्तु की कुल माँग को जान लेना चाहिये और यह देखना चाहिये कि छोटे पैमाने के उद्योग इस माँग को कहाँ तक पूरा कर सकते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग के साथ के लिये उप-कर लगाते समय भी इसी बात का ध्यान रखना चाहिये।

इन सब बातों के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि छोटे पैमाने के उद्योग अपनी स्थिति को सुधारें। वे अपने उत्पादन के ढंग को उन्नत करें। अपनी वस्तुओं को ठीक ढंग से बेचें, अपने लिये नये-नये यन्त्र प्राप्त करने का प्रयत्न करें आदि। वे सब काम तब ही सकते हैं जबकि छोटे-छोटे दस्तकार अपने आपको सहकारी समितियों में संगठित करें।

औद्योगिक श्रम

Q. 67. Survey briefly the development of Trade Union Movement in India. What are the main obstacles to their growth? Discuss their effects on Indian labour Problem

प्रश्न ६७—भारतवर्ष के मजदूर संघ आन्दोलन के विकास का संक्षेप में विवरण दीजिये। उसके उन्नति के मार्ग में क्या मुख्य बाधाएँ हैं? उनके भारतीय श्रम समस्या पर प्रभाव के विषय में बताइये।

मजदूर संघों का जन्म उन सब कठिनाइयों के कारण हुआ जो कि मजदूरों की बड़े कारखानों में अपना श्रम बेचने पर सहन करनी पड़ी। भारतवर्ष में भी जब बड़े बड़े कारखाने चालू होने लगे तब मजदूरों को उसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा जिनका उनको औद्योगिक क्रांति के पश्चात् इंग्लैंड में करना पड़ा था। इस कारण इस देश में मजदूर संघों का स्थापित होना भी स्वाभाविक था।

भारतवर्ष में सबसे पहला मजदूर संघ १८७५ ई० में सोराब जी रुस्तम बगाली के प्रयत्न के फलस्वरूप चालू हुआ। परन्तु प्रथम महायुद्ध तक मजदूर संघ आन्दोलन को कोई विशेष सफलता न मिली। उस समय तक मजदूर संघों का कार्य केवल हड़ताल कराना ही था। पश्चात्प देशों के मजदूर संघों के समान इस देश के मजदूर संघों की कार्य-क्षमता बढ़ाने तथा उनको किसी प्रकार की सहायता देने का कोई प्रयत्न न किया था। परन्तु प्रथम महायुद्ध के कारण मजदूरों में बड़ी जागृति पैदा हो गई। उनका जीवन-स्तर बहुत बढ़ गया परन्तु जब मजदूरी उसके अनुसार न बढ़ी तब उन्होंने मजदूर संघों की स्थापना करके बहुत सी हड़तालों की। इसके अतिरिक्त युद्ध के पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ (International Labour Organization) की स्थापना हुई जिसमें प्रत्येक देश के मजदूरों को अपने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। इस कारण यह आवश्यक हो गया कि मजदूर अपने आपको मजदूर संघों में संगठित करें तथा सब मजदूर संघ अपना एक अखिल भारतीय संघ बनायें। इन सब बातों के कारण इस देश में प्रथम महायुद्ध के उपरान्त मजदूर संघों का निर्माण स्थायी रूप से हो गया।

भारतवर्ष में इस प्रकार के स्थायी मजदूर संघों का सूत्रपात २७ अप्रैल, १९१८ ई० को श्री वी० पी० वादिया द्वारा बङ्कधम और कर्नाटक टैक्सटाइल मिल, मद्रास के मजदूरों के मजदूर संघ से हुआ। १९१९ ई० में मद्रास में ४ मजदूर संघ

हो गये। उनके सदस्य २०,००० मजदूर थे। मद्रास से यह आन्दोलन भारत के दूसरे प्रान्तों में फैला। १९२० ई० में अखिल भारतीय मजदूर सघ (All India Trade Union Congress) की स्थापना हुई। यह विभिन्न स्थानों पर अपनी सभाये करती रही। इस कारण मजदूरों को नये-नये सघ बनाने के लिये प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार बम्बई केन्द्रीय बोर्ड, बङ्गाल मजदूर सघ तथा अखिल भारतीय रेलवे सघ १९२२ ई० में स्थापित हुए। इसके कुछ समय पश्चात् तार व डाकखाने का एक सघ बना।

मजदूर सघों का स्थापित होना भारतवर्ष के पूँजीपतियों के लिये एक असह्य बात थी। इसी कारण उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। १९२० ई० में बकिङ्गम की मिलों के मुकदमे के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने मद्रास श्रम सघ के विरुद्ध एक आज्ञा निकाली जिसमें श्रम सघ के नेताओं से यह कहा गया कि वे हड़ताल करने के लिये मजदूरों को न भड़कावें। इसके अतिरिक्त मजदूर सघ के नेताओं को पकड़ लिया गया तथा उन पर ७००० पौंड का जुर्माना लगाया गया। इससे मजदूर संघों को बहुत हानि पहुँची। इस बात को देखकर मजदूर सघ के नेता श्री एम० एन० जोशी ने पाँच वर्ष के निरन्तर प्रयत्न के पश्चात् १९२६ में भारतीय मजदूर सघ कानून पास कराया। इस कानून के अनुसार कोई भी सात या सात से अधिक मजदूर मिलकर अपना सघ बना सकते थे या रजिस्ट्री करा सकते थे। पर रजिस्ट्री के लिए यह आवश्यक था कि सघ में कम से कम ५० प्रतिशत लोग मजदूर हों। इन सघों के दो कोष होते थे, एक साधारण दूसरा राजनीतिक। कानून में यह दिया हुआ था कि कोषों का धन कैसे खर्च किया जायगा। मजदूर सघ कानून का १९४८ में संशोधन किया गया। इस संशोधित कानून में श्रम न्यायालय की आज्ञानुसार उद्योगपतियों द्वारा मजदूर सघों की मान्यता की व्यवस्था की गई है। परन्तु इस पर अभी कार्य करना आरम्भ नहीं हुआ है।

१९२८-२९ तक मजदूर सघों में साम्यवादियों का बोलबाला रहा परन्तु १९२९ में अखिल भारतीय मजदूर सघ कांग्रेस के दसवें अधिवेशन में जो नागपुर में हुआ, श्री एम० एन० जोशी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मजदूर सघ फ़ेडरेशन का निर्माण हुआ। १९३१ में इन दलों में और भी फूट हो गई। परन्तु इसी बीच में इन भिन्न भिन्न दलों के आपस में मिलाने का प्रयत्न बराबर जारी रहा। इस प्रयत्न का कोई विशेष परिणाम १९३८ तक न निकला। १९३८ के अधिवेशन में भारतीय मजदूर सघ कांग्रेस तथा भारतीय मजदूर सघ फ़ेडरेशन ने मिलने का निश्चय किया। द्वितीय महायुद्ध में इनमें गतभेद हो गया। इस समय मजदूर सघ कांग्रेस ने सरकार को युद्ध में सहायता न देने का निश्चय किया। परन्तु एम० एन० राय के नेतृत्व में स्थापित हुये मजदूर सघ फ़ेडरेशन ने सरकार की सहायता करने का निश्चय किया। उसने अपनी एक अलग सभा (Indian Federation Labour) बना ली। सरकार ने इस सभा की आर्थिक सहायता भी की। राष्ट्रीय नेता पकड़े गये और अखिल भारतीय श्रम सघ कांग्रेस फिर साम्यवादियों के हाथ में पहुँच

रजिस्टर्ड मजदूर संघ व उनकी सदस्यता

रजिस्टर्ड मजदूर संघ व उनकी सदस्यता					
	केंद्रीय मजदूर संघ		राज्य मजदूर संघ		
	१९५४-५५	१९५५-५६	१९५६-५७	१९५७-५८	१९५९-६०
रजिस्टर पर मजदूर सघों की संख्या	१४४	१७४	१७३	२००	४२६७
सूचना देने वाले सघों की संख्या	१०५	१०५	१०२	१६,६४,६४२	२१,६६,४६७
सूचना देने वाले सघों की संख्या	१,७५,५०८	२,१२,८४८	१,८७,२६५	२०,६१,८८४	२१,६६,४६७

औद्योगिक श्रम

द्विज भारतीय सन्थाओ की सदस्यता

आखिल भारतीय मजदूर संघों की संख्या	सामान्यतः मजदूर संघों की संख्या				१९५५	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०
	१९५४	१९५५	१९५६	१९५७						
भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ संभा	६०६	६०४	६१७	६७२	६,२०,९६८	७,७१,७४०	८,३५,३८५	८,३५,३८५	८,३५,३८५	८,३५,३८५
हिन्द मजदूर संभा	३३१	१५७	११६	१३८	२,११,३१५	२,०३,७६८	४,२२,८५१	४,२२,८५१	४,२२,८५१	४,२२,८५१
अखिल भारतीय मजदूर संघ संभा	६२५	४८१	४५८	४३८	३,०६,९६३	३,०६,९६३	३,०६,९६३	३,०६,९६३	३,०६,९६३	३,०६,९६३
संयुक्त मजदूर संघ संभा	१६६	२२८	२३७	२३७	१,६५,१०६	१,६५,१०६	१,६५,१०६	१,६५,१०६	१,६५,१०६	१,६५,१०६

कल योग

✖आँकड़े उपलब्ध नहीं।

गई। सुदृढ समाप्त होने पर जब भारत के हाथ में राज्य सत्ता आई तब कांग्रेस ने मजदूरी पर से साम्यवादियों का प्रभाव समाप्त करने के लिये १९४६ ई० में भारतीय राष्ट्रीय श्रम संघ सभा (Indian National Trade Union Congress) बनाई। समाजवादियों ने भी अपनी एक अलग सभा १९४८ ई० में बनाई जिसको हिन्दू मजदूर सभा कहते हैं। प्रो० के० टी० शाह ने संयुक्त श्रम संघ सभा (United Trade Union Congress) बना ली। इस प्रकार भारत के सब मजदूर संघों को उनकी राजनीतिक विचारधारा के अनुसार निम्नलिखित चार भागों में बाँट सकते हैं। १९५४ ई० में इनकी स्थिति इस प्रकार थी—

उपयुक्त अखिल भारतीय संस्थाओं में से भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ सभा काँग्रेस की, हिन्दू मजदूर सभा समाजवादियों की, अखिल भारतीय मजदूर संघ सभा साम्यवाद की विचारधारा से प्रभावित है।

बाधाएँ—यद्यपि भारतवर्ष में मजदूर संघ आन्दोलन निरन्तर प्रगति कर रहा है तो भी हम यह कह सकते हैं कि उसके मार्ग में अभी तक बहुत सी कठिनाइयाँ हैं। जिनके कारण इसकी उन्नति मजदूरों की संख्या को देखते हुये बहुत ही कम हुई। ये बाधाएँ निम्नलिखित हैं—

(१) भारतीय मजदूर अभी तक अशिक्षित हैं। इस कारण वह अपने अधिकार सभा सत्तों को नहीं समझते।

(२) मजदूर औद्योगिक क्षेत्रों में स्थायी रूप से नहीं रहते। वे फसल कटने तथा बोनस के समय गाँवों में चले जाते हैं। जब वे लौटते हैं तब वे कारखानों में नौकरी करने पते जाते हैं। उनके अस्थायी रूप से रहने का दूसरा कारण लीयर भी है और वह यह कि औद्योगिक क्षेत्र में मकानों की बहुत कमी है। इसी कारण मजदूर लीयरों की मकान नहीं मिलते और उनकी इच्छा रहते हुये भी वे स्थायी रूप से औद्योगिक क्षेत्रों में नहीं रह सकते। अस्थायी रूप से रहने के कारण मजदूर लोग मजदूर संघों की उन्नति में कोई दिलचस्पी नहीं लेते।

(३) भाषा, धर्म, जाति अथवा सामाजिक रीति-रिवाज में भिन्नता होने के कारण मजदूरों में आपस में एक आत्मीयता नहीं होने पाती।

(४) मजदूर निधन हैं। इसी कारण वे मजदूर संघ का चन्दा नहीं दे सकते और उससे अलग रहने का प्रयत्न करते हैं।

(५) मजदूर लोग मजदूर संघों के अनुशासन का पालन न कर सकने के कारण उनसे अलग रहते हैं।

(६) मजदूर अतिशय हैं इसी कारण उनको अपने से बाहर के नेताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। ये नेता मजदूरों का अपने स्वार्थ के लिए शोषण करते हैं।

(७) मजदूर प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों में अधिक विश्वास नहीं रखते। इस प्रकार के विश्वास न होने के कारण मजदूर संघों की अधिक उन्नति होनी कठिन है।

(८) कारखाने वाले भी मजदूर संघों के विरुद्ध रहते हैं। वे मजदूर संघों को नहीं मानते और उनसे बातें करने के लिये तैयार नहीं होते।

(६) हमारे देश में मजदूरों को कारखानों में बहुत अधिक समय तक काम करना पड़ता है। इतना काम करने के पश्चात् न तो उनके पास इतना समय ही रहता और न ही उनमें इतनी शक्ति ही रहती कि वे मजदूर सघों में जा सकें।

(१०) अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सस्था की चौथी एशिया की क्षेत्रीय बैठक की समिति ने यह बात स्वीकार की है कि एशिया के मजदूर सघों की एक कमजोरी यह है कि यहाँ पर राजनीतिक तथा अन्य विचारधाराओं के कारण बहुत से मजदूर सघ पाये जाते हैं।

उपचार—उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण हमारे देश में मजदूर सघ आन्दोलन अधिक उन्नति न कर सका। इसलिये यह आवश्यक है कि बाधाओं को दूर किया जाय। ऐसा करने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं—

(१) मजदूर सघों के नेता स्वयं मजदूर बनें क्योंकि ऐसे नेता ही मजदूरों के हितों को समझकर उनकी भलाई के लिये कार्य कर सकते हैं।

(२) सरकार को चाहिये कि वह मजदूरों के लिये पर्याप्त सहायता में मकान बनाये जिससे कि मजदूर स्थायी रूप से औद्योगिक केंद्रों में रह सकें।

(३) मिल मालिकों को चाहिये कि वे मजदूर सघों को मान्यता दें। ऐसा करने में उनको लाभ होगा क्योंकि फिर वे मजदूरों के साथ अपने झगड़ों को आपस में सुलझा सकेंगे। इससे उनके और मजदूरों के सम्बन्ध आपस में अच्छे हो जायेंगे।

(४) मजदूर सघों को चाहिये कि वे मजदूरों में शिक्षा का प्रचार करें ताकि मजदूर अपने कर्तव्यों का पालन ठीक प्रकार से कर सकें तथा उनको शायद हो जाय कि मजदूर सघ का सदस्य होने से उनको क्या लाभ होगा।

(५) मजदूर सघों की अधिकता को दूर करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सस्था की एशिया की चौथी क्षेत्रीय बैठक ने सुझाव दिया है कि सरकारी देख रेख में एक गोपनीय मतदान होना चाहिए कि कौन मजदूर सघ मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है तथा उसी मजदूर सघ को बातचीत करने का अधिकार दिया जाय। मजदूर सघों के धन को खर्च करने में (Check off) पद्धति को पारण करना जिससे कि मजदूर सघों को वित्तीय स्वतंत्रता बनी रह मजदूर सघों का सरकारी रजिस्ट्रेशन करना तथा मजदूर सघों तथा मिल मालिकों के कोषों की देखभाल तथा आडिट करना। सामूहिक सौदे के समझौतों को कानून द्वारा लागू करना आदि दूसरे सुझाव थे।

प्रो जोसेफ डी० कीनन (Joseph D Keenan) ने जो कि एक प्रसिद्ध अमेरिकन मजदूर सघ नेता है भारत में प्रजातान्त्रिक मजदूर सघ आन्दोलन को शक्तिशाली बनाने के लिये निम्नलिखित तीन सुझाव दिये हैं—(१) मजदूर सघ उद्योग तथा दस्तकारी के आधार पर निर्माण किये जाने चाहियें। (२) उनका राजनीतिक दलों से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। (३) अनिवार्य न्याय को जिसके कारण कि मजदूर सघ आन्दोलन को बहुत शक्ति पहुँचती है समाप्त कर देना चाहिये।

मजदूर संघों और भारतीय श्रम समस्या—यद्यपि हमारे देश के मजदूर सघ आन्दोलन के सामने बहुत सी बाधाएँ हैं तब भी हम यह कह सकते हैं कि खानो तथा चाप के बागों को छोड़कर इस आन्दोलन ने अच्छी सफलता प्राप्त की है। इस आन्दोलन के द्वारा हमारे देश के मजदूरों का जीवन-स्तर ऊँचा उठा है। इन संघों के द्वारा मजदूर मिल मालिकों से बहुत सी सुविधाएँ प्राप्त करने में सफल हुए हैं। यद्यपि कहीं-कहीं मजदूरों को भारी हानि भी उठानी पड़ी है। पर यह बात ठीक है कि इस समय तक मजदूर संघों का कार्य केवल मिल मालिकों के सामने मजदूरों के कष्टों को रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर मजदूरों के लिये लड़ना रहा है। उन्होंने इस समय तक मजदूरों की कार्य-क्षमता बढ़ाने तथा उनके जीवन को सुखी बनाने के लिये बहुत ही कम काम किया है। घन की कमी के कारण वे पाश्चात्य देशों के मजदूर संघों के समान न तो बीमारों के समय, न बेरोजगारी के समय और न बुढ़ापे में मजदूरों की कोई सहायता कर सकते हैं। कुछ मजदूर सघ अपनी कठिनाइयों को जनता के सामने रखने के लिए अखबार भी निकालते हैं। पर वे शायद ही मजदूरों की अवस्था सुधारने के लिये कभी कोई नई योजना बनाते हों। अहमदाबाद टैक्सटाइल मजदूर सघ मजदूरों के हित की दृष्टि से अच्छा कार्य कर रहा है।

इन सब बातों के होते हुए भी हम यह कह सकते हैं कि हमारे देश में मजदूर सघ आन्दोलन का भविष्य उज्ज्वल है। अभी तक हमारे देश में मजदूर सघ आन्दोलन बहुत ही थोड़े मजदूरों तक पहुँचा है इसी कारण हम यह आशा करते हैं कि कुछ प्रयत्न करके बहुत से मजदूरों को मजदूर संघों का सदस्य बनाया जा सकता है। आजकल सरकार की श्रम के प्रति जो नीति है उससे हम यह आशा करते हैं कि मजदूर सघ आन्दोलन शीघ्र प्रगति करेगा।

Q. 68 Give a historical retrospect of the Indian Factory Legislation

प्रश्न ६८—भारतीय फैक्टरी एक्ट का संक्षिप्त ऐतिहासिक सिंहावलोकन कीजिये।

बड़े-बड़े उद्योग धन्धों के इस देश में स्थापित हो जाने के पश्चात् भी इस देश में बहुत समय तक कोई फैक्टरी एक्ट नहीं बना। इसके फलस्वरूप मिल मालिक मजदूरों से मनमाना काम लेते थे। उन्हें बहुत समय तक परिश्रम करना पड़ता था। स्त्रियों तथा बालकों की दशा बहुत बुरी थी। इन्हीं सब बातों को देखकर सरकार ने समय समय पर फैक्टरी एक्ट पास किए। पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि प्रारम्भ से सरकार ने इसलिये फैक्टरी एक्ट पास नहीं किया क्योंकि वह मजदूरों की दशा सुधारना चाहती थी वरन् इसलिए किया कि लकाशायर के मिल मालिक यह चाहते थे कि उनके समान भारतीय मिलों पर भी फैक्टरी कानून लागू होने चाहिये।

र रही हैं। इनमें Y. M. C. A. ' बम्बई सामाजिक सेवा लीग, भारत की-सेवा समिति, सेवा सदन समिति आदि मुख्य हैं।

धर्म हितकारी कोष—१९४६ ई० में, बहुत से धर्म हितकारी कोषों का ' र्गण किया गया जिनका उद्देश्य मजदूरों के लाभ के लिये कार्य करना है। आज देश में २०० से ऊपर ऐसे कोष हैं जिनमें १९५४-५५ में १,५६,००० मजदूरों का लाभ पहुँच रहा था।

धर्म हितकारी केन्द्र—बहुत ही राज्य सरकारें धर्म हितकारी केन्द्र चला रही हैं। १ नवम्बर १९५६ को उनकी संख्या इस प्रकार थी—बम्बई में ५४, उत्तर-प्रदेश में २, पश्चिमी बंगाल में २६, सीराष्ट्र में २१, राजस्थान में १२, पंजाब में ७, आंध्र में ६, मध्यभारत में १, बिहार में ४, मध्यप्रदेश में ३, ट्रावनकोर कोचीन में मैसूर में २, त्रिपुरा में २, हैदराबाद में १, दिल्ली में १।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में मजदूरों के लाभ के लिये बहुत से धर्म हितकारी कार्य किए जा रहा है। इस कार्य के द्वारा मजदूरों का जीवन सुखी हुआ है। पर अभी तक जो कार्य किया गया है वह आवश्यकता से बहुत कम है। यदि हम यह चाहते हैं कि हमारी मिलें अधिक सामान उत्पन्न करें तो हमको धर्म हितकारी कार्य मजदूरों के जीवन को सुखी बनाने के लिये करना पड़ेगा। इस कार्य में रुकना जरूर सच होता है। परन्तु जितना धन संचय किया जाता है उससे अधिक लाभ उत्पन्न हो जाता है। प्रारम्भ में जब राबर्ट ओविन ने अपनी मिल में इस प्रकार का कार्य चालू किया तो दूतरे मिल मालिकों ने उसका मजाक उड़ाया क्योंकि उनका विश्वास था कि उससे बड़ी हानि होगी परन्तु ओविन का विश्वास था कि जितने ही मजदूर खुश व कार्य-क्रांत होंगे उतना ही मिल को लाभ होगा और हुआ भी ऐसा ही। इसलिये हमारे देश के मिल मालिकों को भी अपने लाभ के हित में अधिकधिक धर्म हितकारी कार्य करना चाहिये।

Q. 70. Explain the necessity and importance of Social insurance from the point of view of Indian Industrial labour. Review briefly the policy of the government of India in this connection, indicating the steps taken by it.

प्रश्न ७०—भारतीय बौद्योगिक धर्म की दृष्टि से सामाजिक बीमे की आवश्यकता तथा महत्व बताइये। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति, इसके द्वारा किये गये कार्य को बताते हुए लिखिये।

सामाजिक बीमे का विचार सबसे पहले १८८१ ई० में जर्मनी के विलियम प्रोप के मन्त्रिण में उत्पन्न हुआ। परन्तु हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय धर्म सन्स्था के

मातृत्व लाभ, मजदूर क्षतिपूर्ति, रोग, दुटापे, बेरोजगारी आदि का बीमा प्रस्तावों के कारण इसका बड़ा प्रचार हुआ। इस प्रकार के प्रस्तावों को संसार के बहुत से देशों ने माना है।

सामाजिक बीमे का अर्थ—सामाजिक बीमा वह सहकारी प्रयत्न है जिसके द्वारा बीमा कराने वाले व्यक्ति को आवश्यक रूप (Compulsory basis) से बेरोजगारी, बीमारी तथा इस प्रकार के दूसरे अवसरों पर पर्याप्त मात्रा में सहायता प्रदान की जाती है जिससे कि वह एक यूननतम प्रकार का जीवन-स्तर कायम रख सके। यह सहायता एक ऐसे कोष से प्रदान की जाती है जो मजदूरों, मालिकों तथा राज्यों द्वारा दिये गये धन से निर्माण किया जाता है। सहायता बीमा कराने वाले को इसलिये प्रदान की जाती है कि इसको पाने का उसका अधिकार होता है।

भारतीय अर्थ के लिये सामाजिक बीमे की आवश्यकता तथा महत्व—

भारतवर्ष में मजदूरों को बहुत कम मजदूरी मिलती है। परन्तु उनकी वास्तविक मजदूरी और भी कम है क्योंकि वे कम मात्रा में खरीदते हैं जिसके कारण मूल्यों के कम होने पर भी उनको उसका लाभ प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार उनको अपनी आय का ८० प्रतिशत खाने तथा इंधन पर खर्च करना पड़ता है, ४ से १० प्रतिशत तक वे साराय पर खर्च करते हैं और शेष को सिनेमा, रथोहारों, विवाहों पर खर्च करते हैं। इस प्रकार उनके पास बीमारी, बेरोजगारी मृत्यु आदि अवसरों के लिये कुछ नहीं बचता। इस कारण ऐसे अवसरों पर उनको श्रृण लेना पड़ता है। परन्तु श्रृण लेने की एक सीमा होनी है। इसके अतिरिक्त श्रृण का भार स्थायी होता है। श्रृण लेने से मजदूर और भी निर्धन होता है। इस कारण इस बात की आवश्यकता है कि मजदूरों के लिये एक ऐसा ढग निकाला जाय जिससे कि वे बिना श्रृण लिये एक यूननतम जीवन-स्तर बिता सकें। यह ढग सामाजिक बीमा है।

भारतवर्ष में सामाजिक बीमे की आजकल बड़ी आवश्यकता है और यह आवश्यकता बहुत समय तक कायम रहगी। इसका कारण यह है कि आज हमारा देश इस स्थिति में नहीं है कि वह देश के सारे लोगों के लिये सहायता प्रदान कर सके।

सामाजिक बीमे की आवश्यकता केवल इसलिये नहीं है कि इसके द्वारा मजदूर की आय कायम रहती है बरन् इसलिये भी है कि इसके कारण मजदूर की कार्य-क्षमता कम नहीं होती। इसके अतिरिक्त यह कार्य-क्षमता का ह्रास नहीं होने देता। अन्त में इसके कारण मजदूर अपने आपको उस समय कायम रखता है जबकि उसके पास कोई कार्य करने के लिये नहीं होता।

भारत में सामाजिक बीमे की वर्तमान दशा—

एक पूर्ण सामाजिक बीमे की योजना के निम्नलिखित अंग होते हैं—

(अ) बीमारी, (२) मातृत्व, (३) औद्योगिक दुर्घटनाएँ, (४) गैर औद्योगिक घटनाएँ, (५) रोग ग्रस्त अवस्था (Invalidity), (६) बेरोजगारी, (७) बुढ़ापे की पेंशन, (८) मृत्यु के वच्चे तथा विधवा स्त्री की सहायता।

यदि हम इस कसौटी पर भारत को कसैं तो हम कहेंगे कि यह देश सामाजिक बीमों की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि इस देश ने अभी इस ओर ध्यान बढ़ाना आरम्भ किया है। भूतकाल में समय-समय पर इस बात पर विचार किया गया है परन्तु उसका अभी कोई फल नहीं निकला। १९२८-२९ की बम्बई हडताल जाँच समिति, १९३१ के साही श्रम आयोग, १९३८ ई० की कानपुर श्रम जाँच समिति, १९४० की बिहार जाँच समिति तथा बम्बई टैक्सटाइल श्रम जाँच समिति ने सामाजिक बीमों के विषय में कुछ बातें कहीं परन्तु उनका व्यावहारिक दृष्टि से कोई लाभ न हुआ। इन समितियों ने केवल बीमारी के बीमों का ही जिक्र किया है और किसी-किसी ने बुढ़ापे की पेंशन तथा बेरोजगारी के बीमों की ओर भी संकेत किया है। इनके अतिरिक्त उन्होंने दूसरी प्रकार की कठिनाइयों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। परन्तु सरकार ने उनकी इस एक रोग वाले बीमों की सिफारिश को भी नहीं माना क्योंकि वह इसको चलाकर अपना धन नहीं बढ़ाना चाहती थी।

भारतवर्ष में मजदूरों के लिये इस दृष्टि से किए गए काम को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—(१) वैधानिक, (२) लोक-हितकारी।

(१) वैधानिक (Statutory)—इसमें दो प्रकार के लाभ सम्मिलित किए जा सकते हैं—(१) श्रमिक क्षतिपूर्ति विधेयक १९२३ के अन्तर्गत दिया गया धन जो कि औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण दिया जाता है। (२) मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) जो कि कुछ ही राज्यों में दिया जाता है। इनके अतिरिक्त युद्धकाल में पास किये गये १९४१ ई० तथा १९४३ ई० के दो विधेयकों के अन्तर्गत उन मजदूरों को जो लड़ाई में जखमी हो जाते थे औषधि आदि लाभ प्रदान किया जाता था तथा श्रमिक क्षतिपूर्ति विधेयक के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ भी दिया जाता था।

(२) लोकहितकारी (Welfare)—कहीं कहीं राज्य सरकारों तथा नगर-पालिकाओं ने अस्पताल आदि खुलवा रखे हैं परन्तु उनसे बहुत कम मजदूरों को लाभ पहुँच पाता है। इसलिये अब प्रायः सभी मिलों ने चिकित्सालय खोले हुये हैं, जिनमें कि मजदूरों को बीमारी के समय औषधि मिल सकती है।

इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं मजदूर सघ भी औषधि लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। उनमें से टैक्सटाइल लेबर एसोसियेशन ऑफ अहमदाबाद एक अस्पताल चला रही है। परन्तु ऐसे बहुत कम उदाहरण दिये जा सकते हैं। वैसे कि मजदूर सघों के पास धन की कमी है।

कहीं-कहीं कुछ कारखानों में बुढ़ापे की पेंशन, प्राविडेण्ड फण्ड तथा उपहार (Gratuity) भी दिये जाते हैं। सरकार ने पेंशन के ढंग को अपनाया है। कुछ मिलों तथा रेलों में प्राविडेण्ड फण्ड दिया जाता है। उपहार (Gratuity) का रिवाज बहुत कम है। यह उन लोगों को दिया जाता है जो दीर्घकाल तक नौकरी कर चुके हों। उपहार रेलों तथा बम्बई व बिहार राज्यों की कुछ मिलों द्वारा ही

दिया जाता है। परन्तु उपहार पाने वाले व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं। इनके अतिरिक्त हमारे देश में सामाजिक बीमे की ओर ओर कोई कार्य नहीं किया जाता है।

सरकार की सामाजिक बीमे की ओर नीति—१९४३ ई० से पूर्व भारत सरकार ने सामाजिक बीमे की योजना को चलााने के लिये कोई कार्य नहीं किया परन्तु तब से परिस्थिति में कुछ बदल आई है। १९४३ ई० में सरकार ने श्री बी० पी० आदारकर को विशेष अफसर (Special officer) के रूप में नियुक्त किया और उनसे भारतवर्ष के लिये बीमारी के बीम की एक योजना तैयार करने के लिये कहा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट १५ मास के पश्चात् दी। उनकी योजना के अन्तर्गत १२ लाख मजदूर आते थे और योजना का खर्च २६ करोड़ रुपये था। इस योजना में मिल मालिक की प्रत्येक मजदूर के लिये १ रु० ४ आ० तथा प्रत्येक मजदूर को १२ आ० देने की योजना थी। यदि सरकार इस योजना में भाग लेना चाहे तो चन्दा देने की योजना इस प्रकार थी—सरकार ८ आ०, मालिक १४ आ० तथा मजदूर १० आ०।

इसके पश्चात् भारत सरकार के श्रम विभाग ने १९४४ ई० में एक श्रम जाँच समिति नियुक्त की जिससे निम्नलिखित बातों पर खोज करने को कहा गया—

(अ) दूसरी बातों के अतिरिक्त भारत में औद्योगिक श्रमिकों की मजदूरी, रोजगार, मकान, सामाजिक अवस्था आदि के विषय में आँकड़े एकत्र करना।

(आ) निम्नलिखित बातों की जाँच करके उस पर रिपोर्ट देना—

(१) वे खतरे जिनसे जोखिम (Insecurity) होती है, (२) मजदूरों को उन खतरों का सामना करने की आवश्यकता, (३) इन खतरों का मुकाबला करने के सबसे उत्तम ढंग, (४) घरो तथा कारखानों की अवस्था।

इस समिति की रिपोर्ट भी पेश की जा चुकी है।

सरकार द्वारा किया गया कार्य—१९४८ ई० में सरकार ने मजदूरों का राजकीय बीमा विधेयक (Employee's State Insurance Act) पास किया। इसमें सितम्बर १९५१ ई० में संशोधन किया गया। इसका उद्घाटन २१ फरवरी १९५२ ई० को किया गया। यह विधेयक भारत की बारह महीनों काम करने वाली मिलों के २५ लाख मजदूरों पर लागू होगा। परन्तु प्रारम्भ में इसको दिल्ली व कानपुर, बम्बई और १६ राज्यों के ५१ क्षेत्रों के ११½ लाख मजदूरों पर ही लागू किया गया। दोष मजदूरों पर इसको योजना काल के अन्त तक लागू किया जायेगा।

यह विधेयक उन सर्वकारखानों पर लागू होता है जो शक्ति का प्रयोग करते हैं तथा जिनमें २० अथवा अधिक मजदूर काम करते हैं। इस योजना से केवल उन्हीं लोगों को लाभ होगा जिनको ४०० रु० से कम वेतन मिलना है।

इस कार्य का संचालन करने के लिये सरकार ने मजदूरों की एक राजकीय बीमा कारपोरेशन बालू की है जिसमें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, मिल मालिक,

मजदूर, डाक्टर तथा लोक सभा के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। इस कार्य का संचालन एक स्थायी समिति द्वारा होता है।

कारपोरेशन की धन व्यवस्था मजदूरों व मिल मालिकों के चन्दे द्वारा की जायेगी। जिन मजदूरों को १ रुपया प्रतिदिन से कम मजदूरी मिलती है उनसे कोई चन्दा नहीं लिया जायेगा। जिन क्षेत्रों में यह योजना लागू की गई है उन क्षेत्रों के मजदूरों में से उनको जिनको कि १ और १३ ६० के बीच में मजदूरी मिलती है, १ आने प्रति सप्ताह देना पड़ेगा। इससे अधिक मजदूरी पाने वाले लोगों को ४ आने से १३ ६० तक देना पड़ेगा। यह चन्दा मजदूरी के २ प्रतिशत के लगभग होगा। कानपुर, दिल्ली आदि के मालिकों को—जहाँ यह योजना चालू हो गई है—कुल मजदूरी के बिल का १३ प्रतिशत देना होगा। हमारे स्थानों के मालिकों को कारपोरेशन का खर्च चलाने के लिये अपने मजदूरी बिल का ३ प्रतिशत तक देना पड़ेगा। इस प्रकार मजदूरों तथा मालिकों से २ करोड़ रुपये एकत्र होने की आशा है।

स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जायगा जिनको डाक्टरों खर्च का ३ सहन करना पड़ेगा। रोप ३ कारपोरेशन देगी। केन्द्रीय सरकार पाँच वर्ष तक योजना को चलाने का ३ खर्च (लाभ के अनिरिक्त) सहन करेगी।

योजना में प्रदान किये गये लाभ—इस योजना के अन्तर्गत अप्रतिष्ठित लाभ प्रदान किये जायेंगे।

(१) बीमारी से लाभ (Sickness Benefit)—यदि मजदूर को ऐसा रोग लग जाय कि वह काम पर न जा सके तो उसको एक बीमारी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके पश्चात् उसको ३६५ दिनों में अधिक से अधिक ८ सप्ताह तक बीमारी का लाभ प्रदान किया जायगा। बीमारी आरम्भ होने पर दो दिन तक कोई लाभ न दिया जायगा। परन्तु मजदूर एक बार बीमार पड़ने के १५ दिन के अन्दर ही दूसरी बार बीमार पड़ जाय तो यह दो दिन की शर्त लागू न होगी। लाभ की दर (यदि छुट्टियों को भी लगाया जाय तो) मजदूरी की ३२ पड़ेगी।

(२) मातृत्व लाभ (Maternity Benefit)—इस प्रकार का लाभ उन स्त्रियों को प्रदान किया जायगा जिनके बच्चा पैदा होने वाला है। लाभ की अधिक से अधिक अवधि १२ सप्ताह होगी जो बच्चा पैदा होने से पहले ६ सप्ताह से अधिक न होगी। शेष ६ सप्ताह बच्चा होने के पश्चात् होगी। इस दशा में लाभ की दर १२ आने प्रतिदिन अथवा बीमारी लाभ की दर (इन दोनों में जो भी अधिक हो) होगी। इस प्रकार यह लाभ की मजदूरी के ३२ के लगभग होगी। १३ रुपए प्रति दिन पाने वाली स्त्रियों का लाभ तो इससे भी अधिक होगा क्योंकि उनको १२ आने प्रति दिन मिलेगा।

(३) अयोग्यता लाभ (Disablement Benefit)—यदि किसी मजदूर को कारखाने में काम करने के कारण कोई स्थायी अथवा अस्थायी अयोग्यता हो जाय

तो ऐसे मजदूर को अयोग्यता लाभ प्रदान किया जावेगा। यदि अयोग्यता अस्थायी है तो लाभ की दर मजदूरों की ५२ होगी। यह लाभ उस समय तक पहुँचाया जायगा जब तक अयोग्यता चलती है। इस प्रकार बीमारी के समान इस दशा में लाभ पहुँचाने की कोई सीमा नहीं है। परन्तु अयोग्यता अस्थायी रूप से है तो मजदूर को श्रमिक क्षतिपूर्ति विधेयक १९२३ की तालिका १ में दिए गए ढग से लाभ प्रदान किया जाएगा।

(४) आश्रितों के लाभ (Dependents Benefit)—यदि कारखाने में काम करते-करते किसी मजदूर की मृत्यु हो जाय तो उसके मरने के पश्चात् उसकी विधवा स्त्री तथा उसके बच्चों को सहायता दी जायगी। यह सहायता मजदूर की पूरी मजदूरी के हिसाब से दी जायगी। इसमें से ६६ तो मजदूर की स्त्री अथवा स्त्रियों को मिलेगी और ३३ उसके लड़के लड़कियों को। स्त्री को जीवन भर सहायता मिलती रहेगी परन्तु बच्चों को १५ वर्ष की आयु तक। परन्तु यदि बच्चे विद्या प्राप्त कर रहे हों तो उनको १८ वर्ष तक सहायता मिल सकती है।

चन्दे की अवधि—उस मजदूर को जिसको बीमारी अथवा मातृत्व लाभ प्रदान किया जायगा कम से कम २६ सप्ताह तक चन्दा देना चाहिये। इसके १३ सप्ताह बाब तक उसको कोई लाभ प्रदान न किया जायगा। उसके पश्चात् ही मजदूर लाभ प्राप्त कर सकता है। परन्तु अयोग्यता तथा आश्रितों के लाभ के लिये चन्दा देने की इस प्रकार की कोई शर्त नहीं है। यदि मजदूर पहले दिन आकर ही अयोग्य हो जाय अथवा मर जाय तो उसको भी अयोग्यता लाभ अथवा उसके बच्चों और विधवा स्त्री को आश्रितों का लाभ मिलेगा। कुछ समय से इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इस विधेयक के अन्तर्गत मजदूरों के परिवारों को भी चिकित्सा लाभ पहुँचाया जाय। यह बात तय हो चुकी है और अब इस बात को अमल में लाने की तैयारी हो रही है। अप्रैल १९५७ ई० दिल्ली में हुई कारपोरेशन की बैठक में यह प्रस्ताव किया गया है कि मजदूरों के परिवारों को इस प्रकार का लाभ पहुँचाया जाय।

१९५७—५८ में १७३ करोड़ रु० बीमारी में, ५१७ लाख रु० मातृत्व लाभ, मे २६७५ लाख रु० अयोग्यता लाभ में तथा ५४४ लाख रु० आश्रित लाभ आदि के रूप में बाँटे गये तथा आसाम, बिहार, मैसूर, पंजाब तथा राजस्थान में सदस्यों के परिवारों को भी चिकित्सा लाभ प्रदान किया गया।

यह योजना देहली, कलकत्ता शहर तथा हावड़ा जिला, तथा आंध्र प्रदेश के ६, बम्बई के ४, केरल के १, मध्य प्रदेश के ५, मद्रास के ५, पंजाब के ७, राजस्थान के ६ तथा उत्तर प्रदेश के ४ औद्योगिक केन्द्रों पर लागू है।

मजदूरों का प्राविडेन्ट फण्ड विधेयक (Employees Provident Fund Act)—१९५२ ई० सरकार ने मजदूरों का एक प्राविडेन्ट फण्ड विधेयक भी पास किया है। इस विधेयक के अनुसार मिल मालिकों को ५०० रु० महीना से कम पाने

वाले मजदूर की मूल (Basic) मजदूरी तथा महीनाई भत्ते का ६३ प्रतिशत चन्दा देना होगा। मजदूर को भी इतना ही चन्दा देना पड़ेगा परन्तु यदि वह चाहे तो अपने चन्दे को ८३ प्रतिशत कर सकता है।

यह विधेयक अभी सोमेट, सिगरेट, विद्युत यांत्रिक तथा इजीनियरी, लोहे व फोलाद, कागज और टैक्सटाइल मिलों पर लागू होगा। ३१ जुलाई १९५६ ई० से इसका क्षेत्र बढ़ाकर चीनी, रबड़, चाय, छपाई आदि उद्योगों तक फैला दिया गया है। ३१ जुलाई १९५६ ई० से इस योजना को खाने के तेल व चर्बी, चीनी, रबड़, विजली, चाय (आसाम को छोड़कर), छपाई आदि १८ नये उद्योगों पर लागू किया गया। इसके पश्चात् एक और विधेयक से इसको बागों, खानों, व्यापारिक तथा अन्य पेशों पर भी लागू करने का निर्णय किया गया है। इस प्रकार सितम्बर १९५८ तक इस योजना के अन्तर्गत ७१८६ फैक्टरी तथा २४०४ लाख के लगभग मजदूर थे। अब यह सरकार अथवा स्थानीय सस्थाओं के कारखानों पर भी लागू होता है।

श्री वी० के० मेतन की अध्यक्षता में नियुक्त हुई एक समिति ने इस बात का सुझाव दिया है कि नौकरी का राजकीय बीमा एक्ट, नौकरी का प्राविडेण्ट फण्ड एक्ट, कोयले की खानों का प्राविडेण्ट फण्ड एक्ट, आसाम चाय बागान एक्ट आदि का प्रबन्ध एक ही कानूनी सस्था के हाथ में रहना चाहिये।

इस समिति का दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि मालिकों के ऊपर यह कानूनी जिम्मेदारी हो कि वे नौकरी को ग्रेचविटी दें और मालिकों को चाहिये कि वे पेन्शन तथा ग्रेचविटी योजना में चन्दा देकर इसको अदा करें।

इस समिति का यह भी सुझाव है कि बीमारों का लाभ अधिक से अधिक १३ सप्ताह तक दिया जाय। इसी प्रकार मातृत्व लाभ भी बढ़ाना चाहिये कि वह स्त्री की पूर्ण औसत मजदूरी के बराबर हो जाय तथा इसकी कम से कम दर १ रु० प्रतिदिन हो।

समिति ने यह भी कहा है कि प्राविडेण्ट फण्ड योजना को एक कानूनी पेन्शन योजना में बदल देना चाहिये। उचित मात्रा में पेन्शन देने के लिये साधनों का बढ़ाना आवश्यक है। इस दृष्टि से समिति ने सुझाव दिया है कि मजदूरों तथा मालिकों की प्राविडेण्ट फण्ड के चन्दे की दर वर्तमान ६३ प्रतिशत से बढ़ाकर ८३ प्रतिशत कर दी जाय। समिति ने कहा है कि प्राविडेण्ट फण्ड की योजना को पेन्शन योजना में बदलने में अभी कुछ समय लगेगा परन्तु प्राविडेण्ट फण्ड के चन्दे की दर को एक दम बढ़ा देना चाहिये।

समिति ने यह माना है कि मजदूरों को काम पर से हटा देने अथवा काम छोड़ने का स्थायी इलाज यह है कि मजदूरों को बेरोजगारी लाभ दिया जाय, क्योंकि इस प्रकार की योजना को इस समय कार्यान्वित नहीं किया जा सकता इस कारण समिति ने एक कम महीना सुझाव दिया है। इसके अनुसार मालिकों पर यह जिम्मेदारी

होगी कि वे काम पर से हटाने की क्षतिपूर्ति दें। प्रस्तावित नेन्द्रीय कानूनी सस्था पर भी कुछ बेरोजगारी लाभ देने की जिम्मेदारी होगी।

समिति ने कहा है कि दूसरे देशों में सामाजिक बीमे की योजना का, मालिकों का खर्च भारतवर्ष से कहीं अधिक है। समिति ने यह भी कहा है कि उसके मुद्दावों के कारण मिल मालिकों पर बहुत अधिक बोझा नहीं पड़ेगा।

समिति के इन मुद्दावों पर विचार करने के लिये १६ मई १९१८ ई० को श्रम मन्त्रियों की एक सभा नैनीताल में हुई।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत सरकार मजदूरों के प्रति अपना कर्तव्य समझने लगी है। उसने अभी काम आरम्भ ही किया है। हम आशा करते हैं कि धीरे धीरे यह सामाजिक बीमे की योजना को लागू कर देगी।

Q 71. What are the factors that affect the efficiency of labour? How far do you find them operating in India?

प्रश्न ७१—श्रम की कार्य कुशलता पर किन बातों का प्रभाव पड़ता है? आप उनकी भारत में कहीं तक पाते हैं?

श्रम की कार्य कुशलता का अभिप्राय—श्रम की कार्य-कुशलता का अभिप्राय है श्रमिक की सम्पत्ति उत्पन्न करने की शक्ति। वह श्रम कुशल कहा जाता है जो एक दिने हुए समय में या तो अधिक कार्य करे और अधिक कार्य भी करे और अच्छा भी करे। जब हम कहते हैं कि एक अमेरिका या इंग्लैंड का श्रमिक भारतीय श्रमिक की अपेक्षा अधिक कुशल है तो उसका यह अभिप्राय है कि वह भारतीय श्रमिक से अधिक तथा अच्छा कार्य करता है। उदाहरण के लिये १९२७ ई० में एक भारतीय श्रमिक १२८ टन कोयला प्रति वर्ष खोद सकता था। परन्तु अमेरिका का श्रमिक उसी समय ६७७ टन कोयला खोद सकता था। १९२७ ई० के भारतीय टैरिफ बोर्ड ने भारतीय श्रमिक की कार्य-कुशलता का अनुमान इस प्रकार लगाया था—

देश	एक श्रमिक द्वारा देखे गये तकिये	एक जुलाहे द्वारा देखे गये करवे
संयुक्त राष्ट्र	११२०	६
इंग्लैंड	५४० से ६००	४ से ६
जापान	२४०	२½
भारत	१८०	२

इस उदाहरण से राफ पता चलता है कि भारतीय श्रमिक की कार्य-कुशलता दूसरे देशों के श्रमिकों की कार्य-कुशलता से कम है।

श्रमिक की कार्य-कुशलता पर प्रभाव डालने वाली शक्तियाँ—

(१) शारीरिक शक्ति—कार्य करने के लिए शारीरिक शक्ति का बड़ा महत्व है। जो श्रमिक जितनी ही शारीरिक शक्ति लिये हुये होगा उतना ही वह अधिक कार्य कर सकेगा। दुर्बल श्रमिक शीघ्र ही थक जाता है और कार्य करने के योग्य नहीं

रहता। औद्योगिक दृष्टि से शारीरिक शक्ति का अनुमान करने के लिये हमको यह देखना चाहिये कि एक श्रमिक एक दिन में कितने घण्टे, एक वर्ष में कितने दिन तथा सारे जीवनकाल में कितने वर्ष कार्य कर सकता है। सम्य देश की अपेक्षा पिछड़े हुए देशों में शारीरिक शक्ति अधिक होती है।

शारीरिक शक्ति निम्नलिखित बातों पर निर्भर होती है—

(अ) जलवायु—जलवायु का मनुष्य की शारीरिक शक्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। गर्म देशों में मनुष्य की शारीरिक शक्ति कम होती है और वह थोड़े समय काम करके थक जाता है परन्तु ठण्डे देशों में वह बहुत अधिक समय तक कार्य कर सकता है।

(आ) जातीय गुण—मनुष्य की शारीरिक शक्ति बहुत कुछ जातीय गुणों पर भी निर्भर होती है। भारतवर्ष में जाट तथा राजपूत बड़े शक्तिशाली होते हैं। अंग्रेज अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अंग्रेजी मजदूर भारतीय मजदूर की अपेक्षा इसलिए कार्यकुशल है क्योंकि उसमें शारीरिक तथा नैतिक कुछ ऐसे गुण होते हैं जो भारतीय श्रमिक में नहीं पाये जाते।

(इ. रहन-सहन का दर्जा—श्रमिक किस प्रकार का भोजन करता है, किस प्रकार के वस्त्र पहनता है तथा किस प्रकार के मकान में रहता है इस बात पर श्रमिक की शारीरिक शक्ति बहुत कुछ निर्भर होती है। जिन श्रमिकों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है, जो पर्याप्त वस्त्र पहनते हैं तथा जो स्वच्छ हवादार मकान में रहते हैं वह शक्तिशाली होते हैं तथा अधिक समय तक कार्य कर सकते हैं। इसके विपरीत जो श्रमिक इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित होते हैं वे दुबल होते हैं तथा अधिक कार्य नहीं कर सकते।

भारतीय श्रमिकों की शारीरिक शक्ति कम है क्योंकि भारतवर्ष की जलवायु गर्म है जिसमें श्रमिक अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त भारतीय श्रमिक का जीवन स्तर बहुत नीचा है। भारत में अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको न तो पर्याप्त मात्रा में भोजन ही मिलता है और न ही भोजन अच्छे प्रकार का होता है। उसको दूध, सागभाजी आदि नहीं मिलती। भारतवर्ष के एक व्यक्ति को प्रति दिन इतना खाना मिलता है जिससे केवल १८०० कलोरीज गर्मी मिलती है परन्तु उसको कम से कम इतना मिलना चाहिये जिससे २६०० कलोरीज गर्मी मिल सके। इसके विपरीत अमेरिका का एक व्यक्ति इतना भोजन करता है जिससे ३२०० कलोरीज गर्मी उत्पन्न होती है। भोजन की कमी के अतिरिक्त भारत का एक व्यक्ति कुल १६१ गज कपड़ा पहनता है जबकि अमेरिका का एक व्यक्ति ६४ गज कपड़ा प्रति वर्ष पहनता है। यही नहीं, भारत में श्रमिकों के पास रहने के लिये अच्छे मकान भी नहीं हैं। उनके मकान नीचे होने हैं, उनमें हवा तथा रोशनी भी नहीं जा सकती है। इनके अतिरिक्त एक मकान में बहुत से व्यक्ति रहते हैं। इन सब बातों के कारण भारतीय श्रमिक की शारीरिक शक्ति बहुत कम है।

(२) नैतिक गुण—श्रमिक की कार्य कुशलता उनके नैतिक गुणों पर भी बहुत कुछ निर्भर होती है। एक श्रमिक भले ही शक्ति रखता हो परन्तु यदि वह कार्य न करना चाहे तो वह बहुत कम काल करेगा। इसके विपरीत जो मजदूर सच्चा तथा ईमानदार होता है और अपने वस्तु को समझता है वह कमजोर होते हुए भी अधिक काम कर लेता है।

आजकल भारतवर्ष में श्रमिकों की कार्यकुशलता बहुत कुछ इसी कारण से कम है कि वह अपना कर्तव्य समझकर कार्य नहीं करते। वह अपना बहुत सा समय मूढ कर देते हैं और उसी समय काम करते हैं जब कि उनको कोई देख रहा हो।

(३) मानसिक योग्यता (Intelligence Judgement and Imagination)—कार्यकुशलता शारीरिक शक्ति पर ही निर्भर नहीं होती वरन् वह श्रमिक की बुद्धि के विकास तथा उसकी योग्यता पर भी निर्भर होती है। वाकर (Walker) साहब ने कहा है कि योग्य श्रमिक अयोग्य की अपेक्षा अधिक लाभदायक होता है क्योंकि (अ) उसको काम सीखने में आधा, तिहाई अथवा चौथाई समय लगता है, (आ) उसको किसी काम के देखने वाले की आवश्यकता नहीं पड़ती, (इ) वह सामान को कम बर्बाद करता है, यह मशीन का प्रयोग, चाहे वह कितनी भी पेचीदा हो, शीघ्र ही सीख जाता है।

मानसिक योग्यता प्रकृति की देन होती है। परन्तु उसको शिक्षा द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। यह शिक्षा साधारण तथा शिल्प (Technical) की होनी चाहिये। साधारण शिक्षा (General Education) से मनुष्य की मानसिक शक्ति का विकास होता है तथा प्रत्येक वस्तु को समझने, देखने, छोटने व सीखने की योग्यता बढ़ती है। इसके विपरीत शिल्प शिक्षा (Technical Education) से मनुष्य की आँखें तथा उँगलियाँ निपुण हो जाती हैं और वह अधिक तेजी से कार्य करने लगता है।

भारतवर्ष में दोनों प्रकार की शिक्षा का प्रायः अभाव सा है। भारत में १६६ प्रतिशत शिक्षित हैं और इनमें से भी बहुत से केवल बहुत कम पढ़ना लिखना जानते हैं। शिल्प शिक्षा तो कहीं-कहीं दी जाती है और जहाँ कहीं भी यह दी जाती है वह इतनी महँगी है कि साधारण साधनों के मनुष्य का तो यह साहस भी नहीं हो सकता कि वह उसको ग्रहण कर सकें। इसके अतिरिक्त शिल्प शिक्षा केन्द्रों में विद्यार्थियों का दाखिला भी बड़ा कठिनाई से होता है। इसलिये भारतिय श्रमिक अयोग्य है तो इसमें कोई अचरज नहीं। १९५६-५७ में सारे भारत में केवल ३२८३ ऐसी संस्थायें थी।

(४) उत्पत्ति और लाभ की आशा (Hopefulness, freedom and change)—इनके कारण मजदूर अपने कार्य में दिल लगाकर काम करता है। इसके विपरीत यदि मजदूर को दास के रूप में रक्खा जाय तथा उस पर अत्याचार

किया जाये तो वह अधिक कार्य न करेगा। इसके अतिरिक्त यदि मजदूर को इस बात की आशा होती है कि उसके काम के अनुसार उन्नति होती जायेगी तो वह खूब कार्य करता है जिससे कि उसकी शीघ्रातिशीघ्र उन्नति हो सके। इसके अतिरिक्त कार्य तथा दोस्तों के बदलने से मनुष्यों को नई बातें सीखने को मिलती हैं और उसमें कार्य करने की नवीन शक्ति आ जाती है। यदि कोई मजदूर एक ही स्थान पर बहुत समय तक रहे तो वह उकता जायेगा और कम कार्य करेगा।

(५) कार्य करने की साधारण परिस्थिति (General working conditions)—जिस प्रकार की परिस्थिति में मजदूर कार्य करता है उसका भी उसकी कार्य कुशलता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिन मिलों में सफेदी, रोसनी, सफाई, हवा आदि का ठीक प्रबन्ध है वहाँ पर मजदूर अधिक कार्य कर सकता है। वह स्वस्थ भी रहता है। परन्तु जिन मिलों में रोसनी आदि का प्रबन्ध नहीं होता तथा जहाँ मशीनों की अधिक गड़गड़ाहट रहती है वहाँ पर मजदूर बहुत कम काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि मजदूरों के लिये ठण्डे पानी का प्रबन्ध हो, उसको आराम करने के लिये स्थान तथा समय दिया जाये। उसके लिये डाक्टर, नर्स खेल कूद, मनोरंजन आदि का प्रबन्ध हो। इन बातों से उसकी कार्य कुशलता बहुत अधिक बढ़ती है।

भारतवर्ष में इस दृष्टि से हालत बहुत खराब है। यहाँ पर कुछ समय पूर्व तक रोसनी, सफाई आदि का कोई विशेष स्थान नहीं रखता जाता था। ऊई तथा जूट धुनने वाली फैक्ट्रियों में तो कूड़ा करकट हर समय उड़ता रहता था इसलिये भारतीय मजदूर कुशल नहीं थे।

(६) मशीन, औजार आदि—श्रमिक की कार्य क्षमता पर मशीन व औजार आदि का भी प्रभाव पड़ता है। मशीन जितनी ही अच्छी होगी उसपर उतना ही अधिक कार्य हो सकेगा। यदि मशीन पुरानी व घिसी हुई होती है तो उस पर कार्य कम होता है।

भारतवर्ष के मजदूरों की कार्य-क्षमता इसलिये भी कम है कि यहाँ पर मशीन व औजार अच्छे नहीं हैं। जो मशीन यूरोप व अमेरिका में पुरानी समझकर छोड़ दी जाती है उन्हीं से भारतवर्ष में काम लिया जाता है। ऐसी स्थिति में भारतवर्ष के मजदूरों की कार्य क्षमता कैसे अधिक हो सकती है।

(७) काम के घण्टे व उनका वितरण—काम के घण्टे तथा उनके वितरण का भी कार्य कुशलता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि काम के घण्टे अधिक होते हैं तथा उनका वितरण ठीक नहीं होता तो मजदूर की कार्य क्षमता घट जाती है। परन्तु कम कार्य होने तथा उनका ठीक वितरण होने से उसकी कार्य-कुशलता बढ़ जाती है।

यूरोप तथा अमेरिका में कार्य करने के घण्टे ६ या ७ हैं इसके विपरीत भारतवर्ष में ८ या ९ हैं। अब से कुछ वर्ष पूर्व भारतवर्ष में काम करने के घण्टे

१० या ११ थे। पाश्चात्य देशों में कार्य करने के घण्टे इसलिये घटाये जा रहे हैं क्योंकि अब यह अनुभव किया जा रहा है कि यदि मजदूर से अधिक देर तक काम लिया जायगा तो उसको थकान हो जायेगी और वह कुछ घण्टे काम करने के पश्चात् अधिक काम न कर सकेगा।

(८) मजदूरी—मजदूरी मजदूर के जीवन-स्तर को निर्दिष्ट करती है। जिन मजदूरों को इतनी मजदूरी मिलती है कि उससे उनका तथा उनके कुटुम्ब का जीवन निर्वाह ठीक प्रकार से हो सकता है तो उन मजदूरों की कार्य-कुशलता अधिक होती है। परन्तु जिन मजदूरों को इतनी कम मजदूरी मिलती है कि उगते उनका गुजारा ठीक प्रकार नहीं होता तो उनकी कार्य-कुशलता कम होती है। मजदूरों में केवल रुपये पैसे के रूप में मिलने वाली मजदूरी ही सम्मिलित नहीं की जाती वरन् वह सब सुविधायें जो मजदूर को किसी पेशे में रहकर मिलती हैं, उनको भी मजदूरी में सम्मिलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में मजदूर की वास्तविक मजदूरी उसके जीवन निर्वाह के लिये पर्याप्त होनी चाहिये।

भारतवर्ष में मजदूरों को बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। युद्ध से पहले तो बहुत से मजदूरों को १० या १५ रुपये मासिक ही मजदूरी मिलती थी। ऐसा विचार किया जाता है कि भारतीय मजदूर को प्रायः दूसरे देशों के मजदूरों से कम मजदूरी मिलती है। ऐसी स्थिति में वह कार्य-कुशल कैसे हो सकता है ?

(९) धन व्यवस्था (Organisation of Labour)—धन व्यवस्था पर भी कार्य-कुशलता निर्भर होती है। यदि मजदूर को उसकी योग्यतानुसार कार्य दिया जाना है तो वह अधिक कार्य कर सकता है। परन्तु यदि उसको एक गलत स्थान पर लगा दिया जाता है तो वह अधिक कार्य नहीं कर सकता।

(१०) मजदूर संघ (Trade Unions)—मजदूर संघ मजदूर की सोदा करने की शक्ति को बढ़ाते हैं। वह मजदूरों को शिक्षा आदि भी देते हैं तथा उनकी श्रमिकी तथा बेरोजगारी में सहायता करते हैं। इस प्रकार वह उनकी कार्य-कुशलता को बढ़ाते हैं।

भारतवर्ष में अभी तक मजदूर संघों ने बहुत कम उन्नति की है तथा अभी तक उनका काम हड़तालें कराकर मजदूरों की सहायता करना ही रहा है। इसलिये मजदूर संघों से भारत के मजदूरों को कोई अधिक लाभ नहीं पहुँचा है।

इस प्रकार हम यह कहते हैं कि भारतीय मजदूर विशेष परिस्थितियों के कारण कार्य-कुशल नहीं हैं। यदि भारतीय मजदूर को उसी प्रकार की हालत में रखा जाये जिसमें कि यूरोप और अमेरिका के मजदूर रहता है तो उसकी भी कार्य-कुशलता बढ़ सकती है।

Q. 72. Discuss the causes of Industrial disputes in India. What measures have been taken to promote industrial peace in this country ?

प्रश्न ७२—भारत में औद्योगिक संघर्ष के कारण बताइये । इस देश में औद्योगिक शांति को प्राप्त करने के लिये क्या कार्य किये गये हैं ?

औद्योगिक क्रांति के पश्चात् श्रम और पूंजी में पहले जैसा निरन्तर सम्बन्ध नहीं रहा । इस कारण एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझाने में असमर्थ रहा तो फिर उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक हो था । इसके फलस्वरूप मजदूर हड़ताल तथा उद्योगपति तालाबन्दी करते हैं । वह संघर्ष दो कारणों से होता है—(१) वार्षिक, (२) अवार्षिक ।

(१) वार्षिक कारण—इन कारणों में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं—

(अ) कम मजदूरी—युद्ध काल में मजदूरों का जीवन स्तर मँहगा हो जाता है जिसके कारण उनका काम पहली मजदूरी से नहीं चलता । मिल मालिक मजदूरों के बढ़ते हुए खर्च के अनुसार स्वयं इच्छा से मजदूरी नहीं बढ़ाता । इसलिये मजदूरों को मजदूरी बढ़वाने के लिये संघर्ष करना पड़ता है ।

(आ) कार्य करने के लिये असन्तोषजनक परिस्थिति—कभी-कभी मिल मालिक मजदूरों के लिये सफाई, पीने का पानी, आरामगाह, हवा, रोशनी आदि का प्रबन्ध नहीं करता । कभी-कभी मजदूर इन सब सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये संघर्ष करते हैं ।

(इ) नौकरी की अनिश्चितता—कभी कभी मिल मालिक मजदूरों को किसी समय नौकरी से अलग करने का अधिकार अपने अन्दर सुरक्षित रखता है जिसके फलस्वरूप वह मजदूर को किसी समय भी अलग कर देता है । अभिन्नवीकरण के समय तो ऐसा हो ही जाता है । इस प्रकार से अलग किये जाने के विरुद्ध मजदूर संघर्ष करते हैं ।

(ई) अधिक काम के घण्टे—पहले मजदूरों से बहुत अधिक घण्टों तक काम लिया जाता था परन्तु अब उनको घटाकर ४८ घण्टे प्रति सप्ताह कर दिया गया है । इसके अतिरिक्त मिल मालिक समय के पश्चात् भी काम लेते रहते हैं जब कभी मजदूरों के काम करने के घण्टे अधिक होते हैं तब मजदूरों व मालिकों में संघर्ष होता स्वाभाविक है ।

(उ) शोषण आदि के कारण—कभी-कभी मिल मालिक अत्यधिक लाभ कमाकर उस सबको स्वयं हजम करने का प्रयत्न करता है । मजदूर जानते हैं कि यह लाभ उनके परिश्रम के कारण ही कमाया गया है । इसलिये वे इस लाभ को प्राप्त करने के लिये संघर्ष करते हैं ।

(२) अवार्षिक कारण—इसमें निम्नलिखित कारण सम्मिलित हैं—

(अ) राजनैतिक—बहुत सी हड़ताले राजनैतिक होती हैं । जब देश में कोई

राजनैतिक क्रान्ति होती है अथवा इसी प्रकार का कोई संघर्ष होता है तो मजदूर उसकी सहानुभूति में काम बन्द कर देते हैं।

(आ) मजदूरों में जागृति उत्पन्न होना—मिल मालिक मजदूरों को बहुत समय तक अनुचित ढंग से दबाकर नहीं रख सकता। कुछ समय पश्चात् उनमें जागृति उत्पन्न होती है। जागृति का उत्पन्न होना देश में सभ्यता के विकास पर भी निर्भर होता है। चाहे जिस ढंग से भी हो जब मजदूरों में जागृति पैदा हो जाती है तो वे अपने अधिकारों की समझने लगते हैं और उनके लिए संघर्ष करते हैं।

(इ) मजदूर संघ की उन्नति—मजदूर संघों की उन्नति से मजदूरों की सोदा करने की शक्ति बढ़ जाती है और फिर वे अपने अधिकारों के लिये अधिकाधिक संघर्ष करते हैं।

भारतवर्ष में औद्योगिक संघर्ष—

प्रथम महायुद्ध से पूर्व हमारे देश में हड़तालें बहुत कम होती थीं। परन्तु युद्ध काल में मजदूरों में बड़ी जागृति पैदा हो गई तथा उनका जीवन-स्तर बढ़ गया जिसके कारण युद्ध समाप्त होते-होते इस देश में बहुत सी हड़तालें हुईं। १९२१ में १७६ हड़तालें हुईं। उसके पश्चात् उनकी संख्या कुछ कम हो गई और १९२४ और १९३६ ई० के बीच उनकी प्रतिवर्ष की औसत संख्या १४७ रही। परन्तु द्वितीय महायुद्ध के कारण स्थिति में फिर बदल आई और १९३६ ई० में ४०६ हड़तालें हुईं। उसके पश्चात् भी हड़तालों की संख्या बढ़ती रही। यह संख्या १९४० में ३२२, १९४१ में ३५६, १९४२ में ६६४, १९४३ में ७१६, १९४४ में ६५८, १९४५ में ८२०, १९४६ में १६२६, १९४७ में १८११ तथा १९४८ में १२५६ थी। उसके पश्चात् इनकी संख्या कुछ घटने लगी और १९४९ में यह संख्या ६२४, १९५० में ८१६, १९५१ से १०६८, १९५२ में ६६० थी। सितम्बर १९५८ तक इनकी संख्या ६७० हो गई।

भारतवर्ष में औद्योगिक संघर्ष के कारणों को देखने से पता चलता है कि १९-१ और १९२८ ई० के बीच ६७६ हड़तालें मजदूरों व बोनस के कारण हुईं तथा ४४५ हड़तालें हटाये गये मजदूरों को फिर से रखवाने के लिये हुईं। केवल ७४ हड़तालें छुट्टी व काम करने के घण्टों से सम्बन्धित थीं। १९४८ में जो हड़तालें हुईं उनमें से ३८३ मजदूरों से, ११२ बोनस से, ३६३ मजदूरों के फिर से रखवाने से, ११० छुट्टी व काम करने के घण्टों से तथा शेष अन्य कारणों से सम्बन्धित थीं। १९५० में होने वाली हड़तालों में से २८६ प्रतिशत बोनस से, ८६ प्रतिशत छुट्टी व काम करने के घण्टों से तथा शेष अन्य कारणों से सम्बन्धित थीं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष में हड़तालों के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—

(१) मजदूरों, भत्ते व बोनस, (२) हटाये गये मजदूर, (३) काम करने के घण्टे व छुट्टी।

भारत में संघर्ष को सुलझाने के ढंग—

औद्योगिक संघर्ष को तीन प्रकार से सुलझाया जा सकता है—(१) मध्यस्थों द्वारा (Through arbitration)—अहमदाबाद में महात्मा गांधी की मध्यस्थता के कारण बहुत से झगड़े सुलझ गये। (२) समझौते द्वारा (Through voluntary conciliation)—इस प्रकार के समझौते श्रमिकों और मालिकों के प्रतिनिधियों के बीच होते हैं। इंग्लैंड में ह्यूटले समितियाँ इसी प्रकार से झगड़े तय करती हैं। भारत में भी इस प्रकार प्रयत्न किया जा रहा है। (३) अनिवार्य समझौते द्वारा (Through compulsory settlement)—इस प्रकार के झगड़े सरकार द्वारा नियुक्त किये गये न्यायालयों द्वारा तय होते हैं।

भारतवर्ष में इस प्रकार के झगड़ों को सुलझाने के लिये १९२६ ई० में एक एक्ट पास किया। इसके अनुसार जब झगड़ा करने वाला कोई पक्ष सरकार को झगड़ा सुलझाने के लिये प्रार्थना-पत्र देता या तो एक जाँच अदालत (Court of Enquiry) तथा समझौता समिति (Board of Conciliation) की नियुक्ति कर दी जाती थी। परन्तु इनकी खोज व निर्णय को मानना किसी भी पक्ष के लिये अनिवार्य न था। इसलिये इस एक्ट से कोई विशेष लाभ न हुआ। इसी कारण १९३८ ई० में बम्बई में एक कानून पास किया गया जिसके अनुसार हड़ताल बंधवा तालाबन्दी घोषित करने से पूर्व झगड़े की जाँच हो जानी अनिवार्य थी। कुछ राज्यों में मजदूर व पूँजीपतियों के सम्बन्धों की अच्छा बनाने के लिए समझौता अधिकारी (Conciliation Officer) नियुक्त किये गये। युद्ध काल में आवश्यक सेवाओं वाले उद्योगों के झगड़ों को अनिवार्य रूप से सुलझाने का प्रयत्न किया गया।

युद्ध समाप्त होने पर औद्योगिक झगड़ों की संख्या बहुत बढ़ गई। ऐसी दशा में भारत सरकार ने १९४७ ई० में औद्योगिक संघर्ष एक्ट पास किया जिसमें पहले १९४६ में फिर १९५० में तथा उसके पश्चात् १९५६ में संशोधन किया गया। १९४७ के एक्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं—

(१) प्रत्येक उद्योग जिसमें १०० अथवा अधिक आदमी काम करते हैं एक श्रम समिति (Works Committee) का निर्माण करेगा जिसमें श्रमिकों तथा अधिकारियों के प्रतिनिधि होंगे। समिति दोनों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करेगी।

(२) बहुत से समझौता अधिकारी (Conciliation Officers) नियुक्त किये जायेंगे और ये झगड़े की जाँच करके उसको निबटाने का प्रयत्न करेंगे।

(३) झगड़ा प्रारम्भ होने पर सरकार एक समझौता बोर्ड नियुक्त कर सकती है जिसमें कि एक स्वतन्त्र अध्यक्ष तथा प्रत्येक पक्ष के एक या दो प्रतिनिधि होंगे।

(४) सरकार झगड़े की जाँच कराने के लिये एक जाँच अदालत (Court of Enquiry) भी नियुक्त कर सकती है जिसमें स्वतन्त्र व्यक्ति होंगे।

(१) अनिवार्य रूप से झगड़े का निबटारा कराने के लिये सरकार एक औद्योगिक न्यायालय भी स्थापित कर सकती है जिसमें एक या दो हाईकोर्ट अथवा जिला अदालत के जज होंगे ।

(६) यदि समझौता बोर्ड अथवा अफसर द्वारा कोई झगड़ा तय हो जाता है तो वह दोनों पक्षों पर लागू होगा । जाँच अदालत की रिपोर्ट मानना किसी भी पक्ष के लिये आवश्यक नहीं है परन्तु इस रिपोर्ट को सरकार जनता की सूचना के लिये छापेगी । परन्तु औद्योगिक न्यायालय का निर्णय दोनों पक्षों को मानना पड़ेगा ।

(७) निम्नलिखित हड़ताले अथवा तालेबन्दी अवैध घोषित की गई हैं—

(अ) लोकहित सेवाओं वाले उद्योगों में यदि छ' सप्ताह का नोटिस न दिया गया हो ।

(आ) उस समय जबकि कोई झगड़ा समझौता बोर्ड अथवा औद्योगिक न्यायालय के सामने पेश हो ।

(इ) यदि सरकार ने किसी झगड़े को बोर्ड, अदालत अथवा न्यायालय को सौंप रखा हो और सरकार ने उस समय तक के लिए हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया हो जब तक कि मामले की जाँच हो ।

(ए) वे लोग जो अवैध हड़तालों में सम्मिलित होंगे अथवा ऐसी हड़तालों को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे उनको दण्ड दिया जायगा । किसी भी मजदूर को उस समय तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि मामला समझौता बोर्ड के पास है ।

१९५० ई० में एक एक्ट पास किया गया जिसके अनुसार एक श्रम अपील न्यायालय नियुक्त करने का प्रबन्ध किया गया है । इसमें हाईकोर्ट के जज होंगे । इस न्यायालय के सामने औद्योगिक न्यायालयों, जाँच दरबारी, मजदूरी बोर्ड के फैसले की अपील होगी । इस न्यायालय का फैसला अन्तिम होगा और दोनों पक्षों पर लागू होगा ।

१९५१ ई० में सरकार ने एक श्रम सम्बन्ध विधेयक, (Labour Relations Act) पास किया जिसमें इस बात पर जोर डाला गया कि झगड़े को सुलझाने के लिये आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार की मशीनरी होनी चाहिये । इसके अनुसार सरकार कई प्रकार के अफसर न न्यायालय स्थापित कर सकती है । इस विधेयक के अनुसार रजिस्ट्री करने वाले कर्मचारी नियुक्त किये जायेंगे जिसके पास मिल मालिक अपनी आज्ञाओं की प्रतिलिपियाँ भेजेंगे । श्रमिकों की बातें सुनने के पश्चात् उन आज्ञाओं में बदल की जा सकती है ।

जब कोई झगड़ा हो या होने की सम्भावना हो तो कोई भी पक्ष दूसरे को झगड़ा निबटाने के लिए एक नोटिस दे सकता है । साधारण उद्योगों में यह झगड़ा ७ दिन में तथा लोकहित उद्योगों में १४ दिन में निबट जाना चाहिये । यदि झगड़ा न निबटे तो सरकार इसे बोर्ड को अथवा न्यायालय को सौंप सकती है यदि फिर भी

कोई समझौता न हो तो इसकी रिपोर्ट सरकार को दी जायेगी। अपील करने के लिये सबसे ऊँचा न्यायालय अपील न्यायालय (Appellate Tribunal) है। परन्तु सरकार इस न्यायालय के नियम को भी बदल सकती है।

नियम विरुद्ध हड़ताल करने या ताला बन्द करने के लिये भड़काना एक अपराध बना दिया गया है। जो मजदूर नियम विरुद्ध हड़तालों में भाग लेंगे उनको हड़ताल के समय अपनी मजदूरी, छुट्टी, बोनस आदि नहीं मिलेंगे। नियम विरुद्ध मिल बन्द करने वाले मालिक की सामान्य मजदूरी के दुगुने तक देने के लिये कहा जा सकता है।

यदि कोई श्रम-संघ समझौते की शर्तों को न मानेगा तो उसकी मान्यता (Recognition) रोक दी जा सकती है। स्थायी मजदूर को काम पर से हटाने से पूर्व उसको अपने व्यवहार का स्पष्टीकरण करने का अवसर दिया जायेगा। फालतू मजदूरों को हटाने के लिये भी एक महीने के नोटिस की आवश्यकता है।

इस विधेयक में मजदूरों का सगडा करने का अधिकार स्वीकार किया गया है परन्तु वे उस समय हड़ताल न कर सकेंगे जबकि कोई मामला विचाराधीन हो। धीरे-धीरे काम करने की नीति, सहायुभूति की हड़ताल, तथा लोकहित व्यवसायों में हड़ताल नियम के विरुद्ध घोषित कर दी गई है। यदि हड़ताल नियम के विरुद्ध न हो तो मजदूरों को औसत मजदूरी का ३ मिलेगा।

आपसी समझौता करने के प्रोत्साहन देने के लिये अधिकृत सोदा करने वाले एजेंट (Certified bargaining agents) की व्यवस्था की गई। आपसी समझौता न होने होने पर मध्यस्थ निर्माण (Arbitration) स्वीकार करना पड़ेगा। नियम को भंग करने वाले को दण्ड दिया जायेगा।

उचित कारणों से छटनी (Retrenchment) करने पर मजदूरों को प्रति एक वर्ष नौकरी के पीछे आगे महीने की मजदूरी उपहार के रूप में देनी पड़ेगी। मजदूरों में भत्ता भी सम्मिलित होगा।

औद्योगिक संघों संशोधित एक्ट १९१६ के अनुसार अब तीन प्रकार के ट्रेड्यूनल नियुक्त किये जायेंगे। श्रम अदालत, औद्योगिक ट्रेड्यूनल तथा राष्ट्रीय ट्रेड्यूनल। श्रम दरबार का कार्य छोटे-छोटे मामलों को सुलझाना होगा। औद्योगिक ट्रेड्यूनल का कार्य मजदूरों तथा भत्ते, कार्य करने के घण्टे, छुट्टी तथा बन्दी तथा बोनस आदि महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाना होगा। राष्ट्रीय ट्रेड्यूनल को केन्द्रीय सरकार उन सगडों को सुलझाने के लिये नियुक्त करेगी, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं तथा जो एक से अधिक राज्यों पर प्रभाव डालते हैं।

त्रिपक्ष सम्मेलन (Tripartite Conference)—

देश में एक अच्छा वातावरण पैदा करने के लिये सरकार ने यह सोचा कि यदि श्रमिक अधिकारी तथा सरकार के प्रतिनिधि समय-समय पर एकत्र होकर उद्योगों से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करते रहें और उन्हें हल करने का

प्रयत्न करें तो उससे उद्योगों की समुचित उन्नति होगी। इस भावना को लेकर सरकार ने दिसम्बर १९४७ ई० में एक ऐसे सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें सर्व सम्मति से एक प्रस्ताव पास किया गया जिसको औद्योगिक विराम सन्धि (Industrial Truce) कहते हैं। इस सन्धि में कहा गया है कि देश की वर्तमान परिस्थिति के लिये औद्योगिक उत्पादन अत्यन्त आवश्यक है। परन्तु यह श्रमिकों तथा मिल मालिकों के सहयोग बिना नहीं हो सकता। यह सहयोग सभी प्राप्त हो सकता है जबकि मजदूर व मालिक एक दूसरे के महत्व को समझेंगे तथा मिल-जुलकर अपनी समस्याओं को हल करेंगे। भारत सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार करके अप्रैल १९४८ में इसे अपनी नीति का एक प्रमुख अंग बना लिया है।

भारत में आजकल त्रिगुट सम्मेलन भारतीय श्रम काँग्रेस, स्टैंडिंग श्रम समिति तथा बहुत सी औद्योगिक तथा सलाह देने वाली समितियाँ हैं।

इसके फलस्वरूप बहुत से झगड़े आपस में तय हो गये हैं। १९५५ ई० में ग्रहमदादा टैक्सटाइल उद्योग में बोनस के मामले पर हुये एक झगड़े को इसी प्रकार तय किया गया। यह भी निर्णय किया गया कि भविष्य में भी सब झगड़े आपसी बातचीत से तम किये जायेंगे। यदि ऐसे झगड़ा तय न हो तभी उसको मध्यस्थ द्वारा तय किया जायगा। बम्बई टैक्सटाइल उद्योग में भी बोनस के मामले को इसी प्रकार सुलझाया गया है। इसके अतिरिक्त इस बात का भी प्रयत्न किया जा रहा है कि उन कारणों का पता लगाया जाय जिनके कारण झगड़े होते हैं तथा उन सब मामलों पर झगड़ों को दूर करने का प्रयत्न किया जाय।

बागान, सूती टैक्सटाइल, कोयला, सीमेंट, चमड़ा, निर्माण आदि उद्योगों में त्रिगुट समितियाँ हैं जिनका कार्य सलाह देने का है। परन्तु इनके द्वारा औद्योगिक हानि प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिली है। हाल ही में पास किये गये बहुत से श्रम सम्बन्धी कानून इन समितियों के द्वारा विचार जा चुके हैं। औद्योगिक समितियों के अच्छे कार्य से प्रभावित होकर ही सरकार दूसरे उद्योगों में भी इसी प्रकार की समितियाँ स्थापित करने की बात सोच रही है। राज्य सरकारों ने भी इसी प्रकार की बहुत सी समितियाँ स्थापित की हैं।

आपसी सलाह मसाले को प्रोत्साहन देने के लिये उन सब कारखानों में जिनमें १०० अथवा अधिक मजदूर काम करते हैं नर्स समितियाँ बनानी पड़ती हैं। १९५० में इनकी संख्या लगभग ११०० थी। परन्तु १९५६ में उनकी संख्या लगभग दृगुनी थी। इनके अतिरिक्त उत्पादक समितियाँ, दुर्घटना रोकने वाली समितियाँ भी बहुत से उद्योगों में पाई जाती हैं।

इनके अतिरिक्त द्वि-गुट आधार पर भी कुछ समितियाँ स्थापित की गई हैं। १९५६-५७ में ६४ ऐसी समितियाँ थी जो कार्य-कुशलता को बढ़ाने, बर्बादों के दूर करने, मशीनों तथा औजारों का उचित उपयोग करने आदि महत्वपूर्ण प्रदनों पर विचार करती हैं। इनसे बहुत से अच्छे परामर्श आये हैं।

पञ्चवर्षीय योजना तथा औद्योगिक शान्ति—

पञ्चवर्षीय योजना में यह बात मानी गई है कि श्रम व पूँजी के अच्छे सम्बन्धों के बिना आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती। अतः यह आवश्यक है कि उत्पादन कार्य में मजदूर के महत्व को माना जाय। ऐसा करने के लिये मालिक व मजदूर में हर स्तर (Level) पर घनिष्ट सम्बन्ध हो।

मजदूर के संगठन करने के अधिकार को भी मान्यता दी गई है। इस कारण मजदूर सघों का स्वागत किया गया है। जहाँ तक हो सके आपस में ही सुलझाने का प्रयत्न किया जाय परन्तु झगडा सुलझाने पर सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है।

सघर्ष से बचने के लिये यह आवश्यक है कि मजदूर व मालिकों के अधिकारों व कर्तव्यों के नियम बना दिये जायें। इस हेतु यह आवश्यक है कि मजदूरों को ऐसे आदेश दिये जायें कि वे किस प्रकार अपने झगडे सुलझा सकते हैं। यह भी आवश्यक है कि उनको उद्योग की स्थिति के विषय में पूर्णरूप से सूचित रखा जाय। यदि नियमों में कोई बदल की जाय तो उसकी सूचना भी उनको दे दी जाय। यदि मजदूरों को किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उनको मानिक को सूचित कर देना चाहिये। यदि कोई भी पक्ष सीधी कार्यवाही करे तो उसको दण्ड दिया जाय।

झगडों को सुलझाने के लिये कार्य समितियाँ (Works committees) के निर्माण के लिये भी कहा गया है। ये हर मिल में होगी। उद्योग की सारी मिलों के झगडों को सुलझाने के लिये सामूहिक समितियाँ (Joint Committees) होगी।

यदि कोई झगडा समझौते से तय न होगा तो वह मध्यस्थ के द्वारा तय कराया जायगा। यदि कोई झगडा सारे भारतवर्ष से सम्बन्धित हो तो उसको सुलझाने के लिये एक केन्द्रीय न्यायालय (Central Tribunal) की स्थापना करनी चाहिये।

इस प्रकार इस बात की आवश्यकता है कि श्रम व उद्योगपतियों के झगडों को पूर्ण रूप से समाप्त न किया जा सके तो उनको कम जखर कर दिया जाय। औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों में मजदूरों के संगठन इतने शक्तिशाली हैं कि वे मिल मालिकों से बराबरी के आधार पर बात-चीत करते हैं। इस कारण उनमें मुकदमे-बाजी व अनिवार्य समझौते बहुत कम होते हैं। परन्तु भारतवर्ष में इस प्रकार की बात नहीं है। इसी कारण इस बात की आवश्यकता है कि जहाँ तक हो सके अनिवार्य समझौते की नीव न आये वरन् मजदूर व मिल मालिक अपने झगडे स्वयं तय करें। ऐसा करने से मजदूर सघों की शक्ति बढ़ेगी तथा मिल मालिक उत्पत्ति की दृष्टि से हानि न उठा सकेंगे।

भारत में यातायात के साधन

यातायात के साधनों का महत्व—यातायात के साधनों में रेलों, सड़कों, जल तथा हवा वाले साधनों को सम्मिलित किया जाता है। इन साधनों की उन्नति ने ससार की कायापलट ही कर दी है। जब से ये उन्नत हुये हैं तब से ससार का एक देश दूसरे देश के निकट आ गया है। इसका प्रभाव यह हुआ कि ससार में सभ्यता का विकास हुआ, उद्योग घन्धों, कृषि तथा व्यापार की उन्नति हुई। वास्तव में यदि इन साधनों की उन्नति न होती तो ससार में व्यापार तथा उद्योग घन्धों की इतनी उन्नति न हो पाती। यह बात इन साधनों का महत्व बताने में पर्याप्त मालूम पड़ती है। अब हम भारत के यातायात के साधनों के सम्बन्ध में विचार करेंगे।

रेल यातायात

Q. 73 Give a connected account of the railway development in India.

प्रश्न ७३—भारतवर्ष में रेलों के विकास का क्रमबद्ध इतिहास दीजिए।

भारतवर्ष में रेल बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले १८४४ में किया गया। इसी कारण कलकत्ता तथा बम्बई के पास दो छोटी रेलें बनाने का ठेका दिया गया। परन्तु इस देश में रेलों की स्थापना ठीक प्रकार से १८५३ के पश्चात् हुई जबकि लाइंडे डलहोजी ने कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स को लिखा कि 'भारत में अंग्रेजी राज्य के प्रसार के लिये यह आवश्यक है कि यहाँ रेलों की स्थापना की जाय'। डाइरेक्टर्स ने डलहोजी के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। इसी कारण १८५४ तथा १८६० के बीच आठ कम्पनियों को पुरानी गारन्टी के अनुसार रेलें बनाने का काम दिया गया। सरकार और कम्पनियों के बीच जो शर्तें तय हुई वे इस प्रकार थी—(१) बिना पैसा लिये भूमि दी जाय, (२) ५ प्रतिशत व्याज की गारन्टी, (३) इसके साथ यह तय किया कि कम्पनियों के बीच अपने अत्याधिक लाभ (जो पिछले न दिये हुये गारन्टी व्याज को काटकर बचे) का आधा भाग सरकार को दे, शेष आधा भाग हिस्सेदारों में बाँटे, (४) सरकार ने रेलवे कर्मचारियों की नियुक्ति के अतिरिक्त कुछ विशेष मामलों में देख-भाल करने की शक्ति अपने हाथ में रखी (५) सरकार ने अपने हाथ में यह अधिकार ले लिया कि वह २५ अथवा ५० वर्ष पश्चात् रेलों को व्याज सहित मोल ले ले।

रेल बनाने का यह ढंग अच्छा सिद्ध नहीं हुआ। इस ढंग में कम्पनियों को सावधानी से काम करने की कोई आवश्यकता न थी क्योंकि उनकी तो गारन्टी

किया हुआ सूद मिलता था। इसका परिणाम यह हुआ कि सरकार की इन कम्पनियों को बहुत भारी धन की मात्रा व्याज के रूप में देनी पड़ी। सन् १८६६ में सरकार ने रेल बनाने के इस ढंग का विरोध किया।

१८६६ तथा १८७६ के बीच में सरकार ने रेलें बनाने का कार्य स्वयं अपने हाथ में ले लिया। जहाँ तक व्यय का सम्बन्ध था वहाँ तक तो सरकार को रेलें बनाने में लाभ था पर सरकार के सामने सबसे बड़ी कठिनाई पूँजी की थी। इस समय सरकार अफगानों के साथ लड़ाई लड़ रही थी तथा देश में भीषण अकाल पड़ रहे थे, तथा रुपये का मूल्य, चाँदी का मूल्य गिरने के कारण लगातार गिर रहा था। इसके अतिरिक्त १८५० के अकाल कमीशन ने यह सुझाव दिया कि सरकार को चाहिये कि वह ५००० मील लम्बी रेलें बनायें तथा उसने यह भी बताया कि देश अकाल से उस समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक कि २०,००० मील लम्बी रेल न बनें। यह कार्य सरकार की शक्ति के बाहर था। इसी कारण सरकार ने फिर कम्पनियों को रेलें बनाने का ठेका दिया। इस बार कम्पनियों से जो रेलें बनाने का समझौता किया गया उसकी शर्तें पहले से कुछ ढीली थीं। यह शर्तें निम्न-लिखित थी—

(१) इस बार रेलें प्रारम्भ से भारत मन्त्री की सम्मति घोषित कर दी गई। भारत मन्त्री को यह अधिकार था कि वह २५ वर्ष पश्चात् अथवा उसके पश्चात् हर इस वर्ष के पीछे रेलों को उनमें प्रारम्भ में लगी हुई पूँजी देकर मोल ले लें।

(२) रेलों पर लगी हुई पूँजी पर ३½ प्रतिशत व्याज गारन्टी किया गया।

(३) इस बार सरकार ने अतिरिक्त लाभ (Surplus Profit) में से ⅓ भाग लेने की घोषणा की।

इस प्रकार सरकार ने कम्पनियों को पहले से कम सुविधायें दीं। जब पुरानी कम्पनियों के ठेके की अवधि समाप्त हो गई तब सरकार ने उनको अपने हाथ में ले लिया। इसी प्रकार अब नई कम्पनियों के ठेकों की अवधि समाप्त हुई तब सरकार ने उनको दी जाने वाली बहुत सी सुविधायें वापिस ले लीं।

इस बीच बीच लाइन कम्पनियाँ बनाई गईं और रियासतों को भी इस बात का नियन्त्रण दिया गया कि वे अपनी रियासतों में बीच लाइनें बनायें।

यद्यपि १९०० ई० तक मुख्य रेलवे लाइनें पूरी हो चुकी थीं परन्तु अभी अन्य छोटी ब्रांच लाइनों की बड़ी आवश्यकता थी। १९०५ में एक रेलवे बोर्ड बनाया गया जिसमें एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य थे। १९०५ में मंके समिति ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को रेलों के लिए प्रतिवर्ष १,३५,००,००० रुपये खर्च करने चाहियें। यद्यपि सरकार ने इस सुझाव को पूरे तौर पर नहीं माना तो भी सरकार रेलों के ऊपर पहले से अधिक खर्च करने लगी, इस प्रकार रेलें बढ़ने लगीं। वे १९०६ में १४७५२ मील से बढ़कर १९१४ में ३४,६५६ मील हो गईं। सन् १९०० तथा १९१४ के बीच में रेलों ने सबसे पहले लाभ कमाया।

युद्धकाल में हमारे देश की रेलों के ऊपर बहुत जोर पड़ा। इस बीच विदेशों से इन्जन आदि न मँगाये जा सके। इस कारण रेलों के निर्माण की नई योजनाओं को स्थापित करना पड़ा। नई लाइनों की स्थापना की बात तो दूर रही, बहुत सी पुरानी लाइनों को भी चालू न रखना जा सका। यहाँ के रेलवे कर्मचारियों को विदेशों को भेज दिया गया। बहुत से पुल इतने खराब हो गये कि उन पर गाड़ियों का चलना खतरे से खाली न था। इस प्रकार रेलों की व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी हुई। सन् १९२१ में एक्वर्थ समिति (Acworth Committee) नियुक्त की गई। इस समिति ने यह सुझाव पेश किया कि सरकार को रेलों को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए तथा रेलवे बजट को साधारण बजट से अलग दे देना चाहिए। सरकार ने इन दोनों बातों को मान लिया। उसने एक के पश्चात् दूसरी लाइनों को अपने हाथ में लेना शुरू किया। इस प्रकार उसने प्रायः सभी रेलों को अपने अधिकार में ले लिया। सन् १९२४ से रेलवे बजट अलग पेश किया जाने लगा।

सन् १९२६-३० तक रेलें लाभ वमाती रही। परन्तु उसके पश्चात् जो मंदी (Depression) आई उसमें रेलों को बहुत हानि हुई। इसी बीच सरकार ने रेलों की स्थिति को सुधारने के लिये दो समितियाँ नियुक्त की—(१) पोप समिति तथा (२) वेजबुड समिति। इन समितियों ने रेलों की आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा उनको ठीक प्रकार से चालू रखने के लिए बहुत सुझाव दिये।

सन् १९३६-४५ के युद्ध के आरम्भ में रेलों की स्थिति बहुत अच्छी थी। पर जैसे-जैसे युद्ध का दबाव पड़ा वैसे वैसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि रेलें युद्ध की माँग को पूरा न कर सकेंगी। जापान के युद्ध में आने के पश्चात् समुद्री तटों का व्यापार असम्भव हो गया और तब यातायात का सारा भार जिसमें मुख्यतः कोयले को ढोना था, रेलों पर पड़ गया। इस प्रकार जनता के लिये रेल के डिब्बों का अभाव बढ़ गया।

युद्धकाल में रेलवे के अधिक कुशल शिल्पियों को अस्त्र शस्त्र बनाने के काम में लगा दिया गया। १९४२ में युद्ध यातायात समिति (War Transport Board) का निर्माण किया गया। इसमें रेलवे विभाग भी सम्मिलित था। इस वर्ष भयानक आठ, सूकान तथा क्रांति के कारण कई रेलवे लाइनें टूट गईं। इसी समय केन्द्र में केन्द्रीय यातायात संघ (Central Transport Organisation) तथा प्रान्तों में प्रादेशिक यातायात बोर्ड (Provincial & Regional Transport Boards) की स्थापना की गई। इन समितियों का कार्य यातायात के अन्य साधनों का संगठन कर रेलों के यातायात सम्बन्धी भार को कम करना था। इसी समय प्राथमिकता की पद्धति (Priority System) का भी श्रीगणेश किया गया। अनावश्यक यातायात को बन्द कर दिया गया। सस्ते विराये आदि की जो भी सुविधायें थी उनको हटा लिया गया। मुसाफिर गाड़ियों में कमी कर दी गई। इससे मुसाफिरों की कठिनाई

धीरे भी बढ़ गई। परन्तु जहाँ रेलों पर इतना भार पड़ा वहाँ रेलों की आर्थिक स्थिति बहुत सुधर गई। रेलों ने इस समय न केवल युद्ध के पूर्व के घाट को ही पूरा कर लिया बल्कि उन्होंने बहुत सा लाभ भी कमा लिया।

१९४७ में देश का विभाजन हुआ। इसके कारण बहुत से कर्मचारी जो मुसलमान थे पाकिस्तान चले गए। इसी वजह से रेलवे कर्मचारियों की बहुत कमी हो गई और रेलों की बहुत हानि उठानी पड़ी। परन्तु धीरे धीरे ये कठिनाइयाँ भी दूर हो गईं। सन् १९४६ तक रेलों की स्थिति कुछ सुधर गई। गाड़ियों के डिब्बों की बनावट में परिवर्तन किया गया। मुसाफिरों के आराम के लिये प्रयत्न किया गया। गाड़ियों की प्राथमिकता पद्धति को समाप्त कर दिया गया।

१९५० में जब सरकार के हाथ में सब रेलें आ गईं तब सरकार ने कुछ छोटी, हल्की गाड़ियों को छोड़कर समस्त रेलों को सात बड़े वृत्तों (Zones) में बाँटा जिससे कि रेलवे प्रबन्ध में कुशलता की वृद्धि के साथ ही साथ अधिक लाभ भी हो।

ये वृत्त निम्नलिखित हैं —

प्रथम वृत्त (First Zone) उत्तरी रेलवे—इसका १४ अप्रैल १९५२ को निर्माण किया गया। इस वृत्त में उत्तरी भाग की रेल हैं जिनमें ई० पी० रेलवे, ई० आई० रेलवे का पश्चिमी विभाग (लखनऊ, कानपुर, देहली व लखनऊ), बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे का आगरा से कानपुर वाला भाग तथा छपरा के पश्चिमी भाग में अवधि निरहृत रेलवे सम्मिलित हैं। इसकी लम्बाई ६३६८४० मील है।

द्वितीय वृत्त (Second Zone) पश्चिमी रेलवे—इसका ५ नवम्बर १९५१ को निर्माण किया गया। इस वृत्त में बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे के कानपुर से आगरे वाले भाग को छोड़कर श्याम भाग तथा सोराष्ट्र, बीकानेर, जयपुर, राजस्थान व कच्छ राज्यों की रेलें सम्मिलित हैं। इसकी लम्बाई ६०१७६१ मील है।

तृतीय वृत्त (Third Zone) केन्द्रीय रेलवे—इसका ५ नवम्बर १९५१ को निर्माण किया गया। इस रेलवे में बी० बी० एण्ड सी० आई० रेलवे का बड़ा गेज वाला भाग, जी० आई० पी० रेलवे का अधिकांश भाग सिविलिया, तथा धौलपुर राज्यों की रेलें सम्मिलित हैं। इसकी लम्बाई ५३३०५२ मील है।

चतुर्थ वृत्त (Fourth Zone) दक्षिण रेलवे—यह १४ अप्रैल १९५१ को निर्माण किया गया। इसमें दक्षिणी भारत की बड़ी/छोटी लाइनें, एम० एण्ड ए० एम० रेलवे का अधिकांश भाग तथा मैसूर राज्य रेलवे का सम्पूर्ण भाग सम्मिलित हैं। इसकी लम्बाई ६१५६३६ मील है।

पंचम वृत्त (Fifth Zone) उत्तरी पूर्वी रेलवे—यह १४ अप्रैल १९५२ ई० को निर्माण किया गया। इस रेलवे में लखनऊ, कानपुर के पूर्व का भाग, बंगाल व बिहार का कोयले का क्षेत्र जिसमें बी० एन० रेलवे है। हावड़ा से सहगपुर का भाग, छपरा से पूर्व की अवधि निरहृत रेलवे तथा आसाम रेलवे सम्मिलित हैं। इसकी रेलवे लाइन की लम्बाई ३०६३५२ मील है।

षष्ठम वृत्त (Sixth Zone) पूर्वी रेलवे—इसमें तीन उत्तर डिब्बीजन को छोड़कर सारी ईस्ट इण्डिया रेलवे है। इसका १ अगस्त १९५५ को निर्माण किया गया तथा इसकी कुल लम्बाई २३२४.६८ मील है।

सप्तम वृत्त (Seventh Zone) दक्षिणी-पूर्वी—यह भी १ अगस्त १९५५ को निर्माण किया गया। इसमें बंगाल, नागपुर रेलवे आती है इसकी कुल लम्बाई ३४१६.४८ मील है।

अष्टम वृत्त (Eighth Zone) उत्तरी पूर्वी सीमा रेलवे—इसका निर्माण १५ जनवरी १९५८ से हुआ। इसकी लम्बाई केवल १७३८ मील है। इसका निर्माण रक्षा, व्यवस्था तथा कार्य में बचत आदि कई बातों के कारण किया गया है।

रेलों के पुनर्वर्गीकरण के लाभ—

रेलो के पुनर्वर्गीकरण से निम्नलिखित लाभ होने की आशा है—

(१) हर एक वृत्त में किराया भाड़ा समान हो जायेगा।

(२) रेलों की व्यवस्था करने का खर्च कम हो जायेगा क्योंकि एक स्थान पर एक से अधिक कर्मचारी रखने की आवश्यकता न रहेगी।

(३) जकड़ानों आदि पर एक ही अधिकारी का नियन्त्रण रहेगा।

(४) कार्य श्रमता में वृद्धि होगी क्योंकि साधनों तथा शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग हो सकेगा। रेलों का समय ठीक हो जायेगा। सुरक्षा सम्बन्धी बातों को शीघ्रातिशीघ्र काम में लाया जा सकेगा और क्षतिपूर्ति की माँगों का निबटारा जल्दी हो सकेगा।

रेलों के पुनर्वर्गीकरण का कार्य अभी हाल ही में संयुक्त राज्य (U. K.) में भी किया गया है और वहाँ इससे बहुत लाभ हुआ है। भारत में भी इसका कोई विशेष विरोध नहीं है।

पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलें—

देश की प्रथम पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलों के लिये ४०० करोड़ रुपये खर्चे गये हैं जिनमें २२० करोड़ रुपये की रकम स्वयं रेलों से प्राप्त होनी थी। इस काल में रेलों का वास्तविक खर्च ४०० करोड़ से बढ़कर ४२३.७३ करोड़ हुआ। इस योजनाकाल में ४२० मील लम्बी खराब रेल की लाइन को दुबारा ठीक किया गया। ३८० मील लम्बी नई रेल की लाइन बनाई गई तथा ४६ मील लम्बी छोटे गेज की रेल मीटर गेज में बदली गई। योजनाकाल के अन्त में ४५३ मील नई रेल की लाइन बन रही थी, ५२ मील को चौड़े गेज में बदलने की योजना थी तथा २००० मील लम्बी रेल की लाइन का सर्वे चल रहा था।

इस काल में हमारे देश में रेल के डिब्बे व इंजन भी बनाये गये। भारत में अब यह निश्चय किया है कि वह रेल के डिब्बे विदेशों से नहीं मंगायेगा। जब चितरजन व टाटा के कारखाने में पूरे वेग से काम होने लगेगा तब भारत विदेशों से रेल के इंजन भी नहीं मंगायेगा। चितरजन में दिसम्बर १९५८ तक ७६० बड़ी

लाइन के इजन तथा टाटा के कारखाने में दिसम्बर १९५८ तक मीटर गेज के ३७१ इजन बनाये गये। इसके अतिरिक्त देश में रेल के डिब्बे बनाने का काम भी बड़ी जोर से चल रहा है। अब सिवय विजली के डिब्बों के कोई आयात रेल के डिब्बों की नहीं की जाती।

दूसरी योजना काल की उन्नति—

यह आशा की जाती है कि दूसरी योजनाकाल में १८० मिलियन टन अधिक माल तथा १९५० लाख अधिक यात्रियों द्वारा रेल की माँग की जायगी। इस माँग को पूरा करने के लिये ११२५ करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। इसमें से ४२५ करोड़ रुपये विदेशी वित्तमय के रूप में चाहियें। यह हर्ष का विषय है कि विश्व बैंक ने भारत को ६० मिलियन डॉलर का रेलवे श्रृण देना स्वीकार कर लिया है। इस काल में निम्नलिखित कार्य किया जायगा—

१६०७ मील के रास्ते में दुहरी रेलवे लाइन बिछाना, २६५ मील मीटर गेज की लाइन को बड़े गेज की बनाना, ८२६ मील लम्बी लाइन को बिजली से चलने वाली बनाना ८४२ मील लम्बी नई लाइन बनाना, ८००० मील लम्बे पुराने रास्ते को नया बनाना, २२५८ इजिन, १,०७,२४७ गाड़ियाँ तथा ११,३६४ रेल के डिब्बे बनाना।

वर्तमान स्थिति—आजकल भारत में १०,००० इजिन, २५०,००० रेल के डिब्बे तथा २०,००० रेलगाड़ियाँ १३८२ मिलियन यात्रियों तथा १२४ मिलियन टन सामान प्रति वर्ष होठी हैं। चौड़े गेज तथा मध्यम गेज पर प्रति दिन ४४२१ यात्री गाड़ियाँ तथा २५४६ मील गाड़ियाँ चलती हैं। देश में इस समय लगभग ३५००० मील रेल का रास्ता है। इसके होते हुए भी भविष्य में यह आशा की जाती है कि यात्री गाड़ियों व माल गाड़ियों की माँग बहुत बढ़ जायगी। ऐसा अनुमान है कि १९६०-६१ ई० में रेलों को १८० मिलियन टन माल डोना पड़ेगा। आजकल भी रेलों की कमी बुरी तरह से है जिसके कारण रेलों में बहुत मोड़ रहती है तथा माल का बुकिंग करने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। रेलों की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिये निम्नलिखित पग उठाये गये हैं—

(१) रेलों की लाइनों को बढ़ाना तथा रेलवे यात्रों की शक्ति में वृद्धि करना।

(२) वर्कशापों को सज्जत करना तथा उनकी शक्ति को बढ़ाना जिससे कि खराब स्टॉक को जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके।

(३) रेल के डिब्बों को जल्दी से प्रदान करने का प्रयत्न करना। इसको प्राप्त करने के लिये रेल के डिब्बों को प्रारम्भ, बीच तथा अन्तिम स्थानों पर कम से कम समय रोक़ा जाता है।

(४) जहाँ वहाँ भी सम्भव है वहाँ भारी भारी इजिनों को चलाना जिससे कि अधिक लम्बी व भारी गाड़ियाँ चलाई जा सकें।

(५) ऐसी सस्याओं का निर्माण करना जो यह देखती हैं कि रेल के डिब्बों को कहीं देर लगती है तथा उन स्थानों पर उस देरी में कमी करना।

(६) अधिक इन्जिन, रेल गाड़ियों तथा रेल के डिब्बों को चलाना।

इसके अतिरिक्त सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि यात्रियों को यात्रा करने में अधिक सुविधा प्राप्त हो। इस दृष्टि से सरकार ने तीसरे दर्जे के यात्रियों को सुविधायें देने के लिये १९५०-५१ में २ ७३ करोड़ रु०, १९५१-५२ में २ ४४ करोड़ रु०, १९५२-५३ में २ ३३ करोड़ रु०, १९५३-५४ में २ ४७ करोड़ रु०, १९५४-५५ में ३ ०३ करोड़ रु०, १९५५-५६ में ३ ०५ करोड़ रु० खर्च किये। सरकार ने यात्रियों के लिये रिटार्डिंग रुम, वेटिंग रुम आदि बनवाये हैं। प्लेटफार्मों को चौड़ा किया है। प्लेटफार्मों पर बैठने की बेंच तथा बिजली के पखे लगवाये हैं। पाखाने व पुसलखाने बनवाये हैं। बहुत सी तीसरे दर्जे की जनता गाड़ियाँ चालू की हैं। कुछ एयरकन्डीशन्ड गाड़ियाँ भी चालू की हैं। तीसरे दर्जे के यात्रियों को यह सुविधा दी गई है कि वे पहले ही अपनी सीट रिजर्व करा लें। तीसरे दर्जे के यात्रियों को भी सोने की सुविधा प्रदान की जाती है।

परन्तु इतना सब होते हुये भी अभी तक बड़ी भीड़ रहती है। रेलवे मन्त्री ने अपना १९५८-५९ का रेल बजट पेश करते समय कहा था कि भीड़ की समस्या अभी तक नहीं सुधरी है। इसका कारण घन की कमी, रेल के बनाने की सीमित शक्ति तथा रेल की लाइनों की सीमित शक्ति है। रेल मन्त्री का अनुमान है कि कठिनाइयाँ भविष्य में भी ऐसी ही रहेंगी जैसी कि वे वर्तमान में हैं।

Q 74 Give the advantages and disadvantages of Railway Transport in India

प्रश्न ७४—भारत में रेल यातायात के लाभ व हानियाँ बताइए।

रेल यातायात के लाभ—भारत में रेलों से निम्नलिखित लाभ हुये हैं—

(१) रेलों के द्वारा गाँवों की प्रयुक्तता समाप्त हो गई है। इस प्रकार सारे देश में राष्ट्रीय एकता का निर्माण हो गया।

(२) रेलों उन स्थानों का माल जहाँ वह सस्ता होता है उन स्थानों पर ले जाती हैं जहाँ वह महँगा होता है। इस प्रकार सारे देश में मूल्य स्तर समान हो जाता है।

(३) रेलों के द्वारा श्रम में शक्ति शीलता आ गई जिसके कारण औद्योगिक केन्द्रों में श्रम की कमी दूर हो गई है।

(४) रेलों के द्वारा बड़े बड़े उद्योगों का माल दूर दूर के गाँवों में पहुँच जाता है और कृषि की फसलें दूर दूर के सहरो तक पहुँच जाती हैं। इस प्रकार उद्योगों तथा कृषि दोनों को ही रेलों से लाभ पहुँचा है।

(५) हमारे देश में जब से रेलों का निर्माण हुआ है तब से अकाल का भय

बहुत अधिक ज्यादा है। दोपहरकाल में यह इतनी रास्ती व इतनी तेज न हो जितनी कि रेल यातायात परन्तु इसको अधिक तेजी से व बहुत कम खर्च करके चालू किया जा सकता है। यह उन स्थानों पर भी पहुँच सकती है जहाँ कि रेल यातायात के पहुँचने की कभी कोई आशा नहीं। यह हो सकता है कि इतनी तेज व इतनी दूर तक जाने वाली न हो जितनी कि हवाई यातायात परन्तु यह बहुत से सामान के लिये एक निरन्तर चलने वाला सस्ता साधन है। आगे चलकर उन्होंने कहा कि सड़क का महत्व न केवल आसाम के लिये ही है बल्कि वह सारे उत्तरी भारत के लिये है। देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह बात आवश्यक है कि इस सारे भाग में सड़कों का जाल बिछा हुआ हो जिससे कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जा सके। श्री एस० के० पाटिल, केन्द्रीय यातायात तथा सवाववाहन मन्त्री ने वगाल नेशनल चेम्बर ऑफ कामर्स तथा इंडस्ट्री के सामने अपना भाषण देते हुए कहा था कि सड़क यातायात का महत्व बढ़ना जा रहा है। प्रत्येक चीज को रेल द्वारा नहीं ले जाया जा सकता। सड़क गाँव के लिये तो जाने जाने का सबसे उत्तम साधन बना रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि किसी को भी सड़क को गौण श्रेणी के महत्व की नहीं समझनी चाहिये। यदि रेलें १००० करोड़ की पूँजी से केन्द्रीय राजकोष को ४० करोड़ रुपये देती है तो सड़कें लगभग १५०० करोड़ की पूँजी से उससे दुगुना लगभग ६५ करोड़ रुपये करो के रूप में प्रदान करती हैं। रोजगार प्रदान करने में भी सड़कें रेलों से आगे हैं।

वर्तमान स्थिति—भारतवर्ष में जितने भी यातायात के साधन हैं उनमें सड़क यातायात की दशा सबसे खराब है। भारत में पक्की सड़कें तो कम हैं ही, कच्ची सड़कों का भी प्रायः अभाव है। यदि हम भारत की सड़क यातायात की तुलना दूसरे अ देशों से कर तो हमको पता लगेगा कि हमारी स्थिति खराब है (नीचे दी हुई तालिका ग्राहक प्रमाण है)*

देश	सड़क की लम्बाई	प्रति १ हजार वर्गमील पर सड़क की लम्बाई (मीलों में)	प्रति १ लाख मनुष्यों पर सड़क की लम्बाई (मीलों में)
ऑस्ट्रेलिया	५०० ५	१६८	६६२
जर्मनी	१०५	४०	६२
जोनाडा	५५३ ४	१६०	४३६८
भारत	२४६०	२०१	३७६
इटली	१७० ५	१४६७	७२८
जपान	५६७ ५	३६८८	३८१
नार्वे	१८३ ६	२०७०	२११४
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका	३०४५ ३	१००६	

इन आँकड़ों के देखने से पता चलता है कि सड़कों की दृष्टि से हमारी स्थिति ब्रह्मा को छोड़कर सबसे खराब है। हमारे देश में सड़कों की कमी ही नहीं है वरन् जो सड़कें हैं उनकी हालत भी बड़ी खराब है क्योंकि उनकी मरम्मत का कोई उचित प्रबन्ध नहीं है। भारतवर्ष की सड़कें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों के आधीन हैं। इनमें से कोई भी उनकी उन्नति की परवाह नहीं करता। हमारे देश में सड़कों पर अभी खर्च किया जाता है जबकि सरकार के बजट में बचत होती है। हमारे देश में नागपुर योजना को सड़कों की भविष्य की उन्नति के लिये माना गया था। इस योजना में सड़कों पर खर्च करने के लिये ३७२ करोड़ रुपये रखे गये थे। इनमें से ६६ ५ करोड़ रुपये राष्ट्रीय सड़कों के लिये और शेष ३०५ ५ करोड़ रुपये दूसरी सड़कों के लिये रखे गये थे। ये आँकड़े युद्ध पूर्व से ५० प्रतिशत अधिक मूल्य स्तर के आधार पर रखे गये थे। उस समय से यदि मूल-स्तर दुगुना भी माना जाय तो कुल खर्च ७४४ करोड़ रुपया हो जाना चाहिये था। इनमें से १३३ करोड़ राष्ट्रीय सड़कों पर तथा शेष ६११ करोड़ रुपया शेष सड़कों पर खर्च होना चाहिये था। पर खेद का विषय है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कों की उन्नति के लिये केवल ६३ करोड़ रुपये रखे गये थे तथा द्वितीय योजना के लिये २२१ करोड़ रुपये रखे गये हैं।

नागपुर योजना में सारे भारत के लिये ३,३१००० मील लम्बी सड़कों का ध्येय रखा गया था जो इस प्रकार था—

राष्ट्रीय सड़क	१६६,००
राष्ट्रीय ट्रेलस	४,१५०
प्रान्तीय सड़क	५३,६५०
जिला व गाँव की सड़कें	२,५६३००
	<hr/>
	३,३१०००

इसमें १,२३,००० मील लम्बी सड़कें पक्की तथा २,०८,००० मील लम्बी सड़कें कच्ची बनाने की योजना थी।

परन्तु प्रथम योजना के अन्त में (३१ मार्च १९५६ ई० को) भारत में कुल सड़कों की लम्बाई ३,२०,००० मील थी जिनमें १,२२,००० मील पक्की तथा १,९८,००० मील कच्ची थीं। यद्यपि प्रथम योजना के अन्त में सड़कों की कुल लम्बाई नागपुर योजना से कम है तो भी इसको सतोपजनक कहा जा सकता है।

द्वितीय योजना के ध्येय बिन्दु—इस योजना में ये राष्ट्रीय सड़क पूरी की जायेंगी जिन पर प्रथम योजना में कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त ६०० नई सड़कें, ७२ बड़े पुल बनाये जायेंगे तथा १००० मील लम्बी सड़क की मरम्मत की जायेगी तथा ३७५० मील लम्बी सड़क को चौड़ा किया जायेगा। दूसरी सड़कों में से ११५० मील लम्बी सड़कें बनाई जायेंगी तथा ५०० मील की सड़कों को दत्त किया जायेगा। राज्य १८००० मील लम्बी सड़कें बनायेंगे जिनपर १६२

करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है। राष्ट्रीय विकास तथा सामूहिक विकास योजना के द्वारा गाँवों में बहुत सी सड़कें बन सकेंगी। इस प्रकार दूसरी योजना के अन्त तक नागपुर योजना में निश्चित सिन्दु को प्राप्त कर लिया जायेगा। इस योजना में सामान ढोने का कार्य निजी पूंजी वाले लोग करेंगे। यह भी प्रयत्न किया जायगा कि एक से अधिक राक्यों में कार्य करने वाले मोटरों को दो बार कर न देना पड़े। यात्री तथा सामान यातायात को उन्नत करने का प्रयत्न किया जायेगा।

यदि हम मोटर गाड़ियों की दृष्टि से अपनी सड़क यातायात का अनुमान लगायें तो भी हम देखते हैं कि हमारी स्थिति बड़ी खराब है। हमारे देश में प्रति १००० मील सम्बन्धी सड़क के पीछे केवल ८२९ मोटर गाड़ियाँ हैं जबकि इंग्लैंड में १८७४, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में १२१४६ तथा फ्रांस में ३७१७ गाड़ियाँ हैं। हमारे देश में प्रति १२७० व्यक्तियों के पीछे एक मोटरगाड़ी है जब कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ३ के पीछे आस्ट्रेलिया में ५ के पीछे, इंग्लैंड में १५ के पीछे और फ्रांस में ११ के पीछे है।*

उपसुक्त सड़क की सम्बाई व मोटर गाड़ियों की संख्या को देखकर हम कह सकते हैं कि हमारे देश में सड़क यातायात की स्थिति बड़ी खराब है।

सड़कों की खराब अवस्था के कारण—हमारे देश में सड़कें इसलिये खराब हैं कि उनकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया है क्योंकि सड़कों के सम्बन्ध में नागपुर की इंजीनियरों की सभा, योजना आयोग तथा दूसरी इसी प्रकार की संस्थाओं ने ध्यान दिया है परन्तु इसके दूसरे कारण हैं। इसका प्रथम कारण तो धन की कमी है। हम पहले भी सकेत कर चुके हैं कि हमारे देश में सड़कों के बनाने का भार केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों के ऊपर है। इनमें से केन्द्रीय सरकार तो केवल राष्ट्रीय महत्व की सड़कों को ही बनाती है परन्तु इस प्रकार की सड़कें बहुत कम हैं। दोप सड़कें राज्य सरकारें तथा स्थानीय संस्थाएँ बनाती हैं। परन्तु राज्य सरकारों की आय के स्रोत तो ऐसे हैं जिनसे उन्नति के साथ-साथ आय नहीं बढ़ती परन्तु उनके व्यय के मद ऐसे हैं जिन पर खर्च बढ़ता रहता है। ऐसी स्थिति में उनके पास सड़क बनाने के लिये बहुत कम धन बचता है जिनको वे सड़कों पर लगाती हैं। स्थानीय संस्थाओं की आय तो पहली ही इतनी कम है कि वे सड़कों पर खर्चा लगाने की बात सोच ही नहीं सकती। हमारे देश में रेलों के समान सड़कों को सार्वजनिक नृण द्वारा भी नहीं बनाया गया है। यही कारण है कि हमारे देश में सड़कें न बनाई जा सकीं।

सड़क यातायात की उन्नति में दूसरी बाधा मोटर गाड़ियों का बहुत अधिक भार है। यह अनुमान लगाया गया है जबकि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक मोटर गाड़ी का कर भार केवल ५०० रु० है भारतवर्ष में यह कर भार २०७० रु०

*The above figures have been taken from Commerce of 6th Feb. 1954-P, 189

है। फ्रांस में यह भार ५०० रु०, भावें में १००० रु०, इंग्लैंड में १३०० रु०, पश्चिमी जर्मनी में १२०० रु० है। इतने कर भार के कारण मोटर यातायात की उन्नति नहीं होती। भारत का ही ऐसा अनुभव है कि जिन राज्यों में मोटर कर कम है वहाँ सबसे अधिक मोटरों की संख्या बढ़ी है परन्तु जहाँ उनपर कर भार अधिक है वहाँ उनकी संख्या बहुत कम बढ़ी है।

सड़क यातायात की उन्नति में तीसरी बाधा सरकार की अनुज्ञा-पत्र देने की बाधा है। भारत में १९३६ में मोटर गाड़ो एक्ट पास होने पर मोटरों के ऊपर बहुत सी पाबन्धियाँ लगा दी गई हैं जिनके फलस्वरूप मोटर यातायात की उन्नति में बाधा पड़ती है।

सड़क यातायात की उन्नति में चौथी बाधा उसके राष्ट्रीयकरण का डर है। इस समय आसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मनीपुर, बिलासपुर, राजस्थान, बम्बई, कच्छ, सौराष्ट्र, हैदराबाद, मैसूर, ट्रावनकोर और कोचीन में सीमित मात्रा में सरकार द्वारा वाणिज्यो व माल ढोने के लिये मोटरें चलाई जाती हैं।

उन्नति के सुझाव—भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल (Federation of Indian Chamber of commerce and Industry) ने सड़को की उन्नत करने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये हैं—

(१) केन्द्र और राज्यों में एक सड़क उन्नति संस्था (Road development Corporation) की स्थापना की जाय।

(२) सड़क के लिये अधिक धन का प्रवन्ध किया जाय।

(३) रेलों तथा बड़ी सड़कों को मिलाते वाली सड़कों को प्राथमिकता दी जाय।

(४) मोटरों पर कर कम लगाये जायें।

(५) निजी मोटर यातायात को प्रोत्साहन दिया जाय।

श्री पी० एल० वर्मा, अध्यक्ष भारतीय सड़क कांग्रेस ने २१वीं बैठक के सामने अपने भाषण में सड़क की भविष्य की उन्नति के विषय में बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि रेलों ने यातायात की समस्या को सुलझाने की ओर अपना ध्यान दिया है परन्तु जब हम यह देखते हैं कि सत्तर के उन्नत देशों में आंतरिक यातायात की तीन चौथाई आवश्यकता सड़कों से पूरी होती है तब हम को चाहिये कि हम अपनी जन संख्या के भविष्य के क्षेत्रीय बंटवारे को देखें तथा उसी के अनुसार सड़कों की उन्नत कर। यदि हम सड़कों को ऐसे स्थानों पर उन्नत करेंगे जहाँ से कि अन्त में उनकी सहायता पड़ेगी तो यह एक अनुचित बात होगी। औद्योगिक केन्द्रों की आवश्यकता कृषि क्षेत्रों से भिन्न होगी। इस कारण इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

/ , हमारे देश में सड़कों के बनाने व उनके लिये भूमि प्राप्त करने के लिये धन की बहुत कमी है। पंजाब में चक्रवर्दी का कार्य करते समय जो भूमि प्राप्त की गई

है उसमें से कुछ भूमि सड़को के लिये रखकर शेष को किसानों में बाँटा गया है। यदि यही कार्य दूसरे राज्यों में भी किया जाय तो उससे भूमि को प्राप्त करने की समस्या बहुत कुछ सुलभ सकती है।

श्री वर्मा ने आगे कहा कि श्रमदान योजना से गाँव की सड़कें उन्नत हो सकती हैं परन्तु यह सब कार्य योजना के साथ किया जाना चाहिये अन्यथा सब श्रम बेकार हो जायेगा।

सड़क की समस्या न केवल गाँवों के लिये है वरन् वह शहरों के लिये भी है। शहरों के पास से जाने वाली राष्ट्रीय सड़को को भी स्थानीय समस्याओं की बिम्बेदारी समझा जाता है। इसी कारण उनकी हालत भी खराब है। शहरों के अन्दर की सड़को की हालत भी बहुत खराब है क्योंकि स्थानीय समस्याओं के पास धन की कमी है। इस कारण कर के ढाँचे को बदलने की आवश्यकता है।

श्री वर्मा ने न केवल कर ढाँचे को बदलने का सुझाव दिया है वरन् सड़क के अर्ध-प्रबन्धक को बदलने की सलाह भी दी है। उन्होंने कहा है कि नागपुर योजना के ध्येय के अनुसार उन्नत क्षेत्रों में कोई भी गाँव पक्की सड़क से ५ मील दूर तथा अवनत क्षेत्र में २० मील से दूर नहीं रहना चाहिये। इसके लिये पक्की सड़को की लम्बाई १,२३,००० मील निश्चित की गई थी। अब यदि हम उन्नत क्षेत्र में प्रत्येक गाँव को पक्की सड़क के ३ मील के व्यास में तथा अर्द्ध-उन्नत व जगली क्षेत्र में ६ मील के व्यास में तथा अवनत क्षेत्र में २० मील के व्यास में खाना चाहते हैं तो हम को पक्की सड़को की लम्बाई ३२,००,००० मील चाहिये। इसकी तथा कच्ची सड़को की कीमत ४००० करोड़ रु० के लगभग होगी। परन्तु दूसरी योजना में सड़को की उन्नति के लिये केवल २२१ करोड़ रु० रखे गये हैं। इस गति से इस ध्येय बिन्दु को प्राप्त करने में ७५ वर्ष लगेंगे। इतना प्राप्त होने पर भी उस समय हमारे देश में सड़क की लम्बाई केवल ०.५ मील प्रति वर्ग मील होगी जबकि यह लम्बाई ब्रिटेन में १.१६ मील तथा फ्रांस में २.४ मील है। इसी कारण सड़को पर अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता है। इस धन को प्राप्त करने के लिये नए सड़क बनाने के बाँट चालू कर सकते हैं। इनकी गारन्टी राज्य सरकार ले सकती है तथा ये कुछ निश्चित समय पश्चात् चुकाये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सड़क के प्रयोग के कदम को सड़क के बनाने पर खर्च करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त भविष्य की उन्नति के लिये सही आँकड़ों का एकत्र करना भी आवश्यक है। इस कार्य के लिये केन्द्र व राज्यों में अपनी-अपनी संगठनता होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त देश में इंजीनियरों की भी कमी है। इसके लिये इस बात की आवश्यकता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ लड़के लेकर उनको इस कार्य की शिक्षा दी जाय।

श्री वर्मा ने यह भी बताया कि सड़को को बनाने का कार्य भी उचित ढंग

से नहीं किया जाता। इस कारण उनके बनाने में देर लगती है। इसी कारण इस बात की आवश्यकता है कि सड़क बनाने के लिये पूरे वर्ष की घन की मजदूरी पहले ही प्राप्त करली जाय तथा अगले वर्ष का टेक्नीकल तथा आर्थिक प्रोग्राम अपने हाथ में हो और तीसरे वर्ष के लिये योजना बनाई जा रही हो। ऐसा करने से सड़क बनाने का कार्य निरन्तर बिना रुकावट के चलता रहेगा।

इसके अतिरिक्त श्री वर्मा ने सड़क इंजीनियरों को सलाह दी कि उनको सड़क पर ऐसा घातावरण तैयार करना चाहिये कि यात्रा करने वाले को अपनी यात्रा जीवन भर याद रहे।

उन्होंने यह भी बताया कि सड़क की उन्नति के लिये यह भी आवश्यक है कि सड़क सम्बन्धी अनुसन्धान किया जाय तथा दूसरे देशों की खोज का लाभ उठाया जाय।

अभी ३ जून १९५८ ई० की एक सूचना के अनुसार रेलवे बोर्ड ने निश्चय किया है कि वह चालू वर्ष २५ करोड़ रुपया सड़क यातायात पर खर्च करेगा। यह रुपया आंध्र में ५० लाख, बम्बई में ५४ लाख, बिहार व मध्य प्रदेश में से प्रत्येक में ४० लाख, मैसूर में ३५ लाख, पंजाब में ५ लाख, हिमांचल प्रदेश में ४ लाख तथा उड़ीसा में १ लाख रुपया खर्च होगा। इस घन के खर्च करने में देश का अधिकतम हित सामने रखना जायेगा।

मिनो मसानो समिति (Minoo Masani Road Transport Re-organization Committee)—इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल १९५६ में पेश की। इस समिति ने रेलों की इस माँग को ठुकराया है कि उनके लाभ को बचाने के लिये सड़कों पर पाबन्दी लगाई जाय। इसके विपरीत समिति ने सुझाव दिया है कि सड़क पर चलने वाली गाड़ियों को उदार दिल से लाइसेंस दिया जाय तथा उनके रास्ते में से लम्बे रास्ते तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर जो पाबन्दी है उसको दूर कर दिया जाय। इस समिति का सुझाव है कि उपभोक्ता के हित को सर्वोपरि रखा जाय। इस कारण रेलों तथा सड़कों के बीच स्वतन्त्र तथा खुली प्रतियोगिता होनी चाहिये जिससे कि लोगों को प्राथमिक तथा तेज सेवा प्राप्त हो सके। समिति ने यह भी कहा है, कि रेल सड़क सहयोग के नाम पर रेलों को लाभ पहुँचाने के लिये सड़कों को हानि पहुँचाई गई है। ऐसा भविष्य में नहीं किया जाना चाहिये। समिति का यह भी सुझाव है कि लाइसेंस देने वाला अधिकारी या तो कमिश्नर हो या जिलाधीश। समिति का यह भी सुझाव है कि लाइसेंस पूरे राज्य के लिये होना चाहिये न कि किसी विशेष रास्ते के लिये।

Q. 78: Discuss the merits of Government roadways as against private motor companies in the carrying of passengers and goods. Give reasons for your preference.

प्रश्न ७८—यात्रियों तथा सामान के ले जाने में सरकारी रोडवेज के प्राइवेट मोटर कम्पनियों की अपेक्षा क्या लाभ हैं ? अपनी मान्यता का कारण दीजिये ।

भारतवर्ष में अभी हाल ही तक सड़क के ऊपर प्राइवेट मोटर कम्पनियों का पूर्ण अधिकार था । पर अभी कुछ वर्षों से राज्य सरकारें इस कार्य को अपने हाथ में ले रही हैं । उत्तर प्रदेश में बहुत से स्थानों पर सरकारी रोडवेज चलनी आरम्भ हो गई हैं । बम्बई में भी यह कार्य प्रारम्भ हो गया है । पंजाब में भी यह काम आरम्भ हो गया है । इसके फलस्वरूप लगभग २५ प्रतिशत यात्री-सम्बन्धी यातायात सरकार के हाथ में आ गई है, शेष ७५ प्रतिशत यात्री सम्बन्धी तथा पूरी की पूरी माल यातायात अब भी निजी लोगों के हाथों में है । सरकारी रोडवेज कम्पनियों से निम्नलिखित लाभ हैं :—

(१) सरकारी रोडवेज समय का बड़ा ध्यान रखती हैं । वे ठीक समय पर चलती हैं तथा निश्चित समय के लिये स्टेशनों पर ठहरती हैं पर प्राइवेट मोटर समय का अधिक ध्यान नहीं रखती । वे उस समय तक नहीं चलती जब तक कि उनमें पूरी सवारी नहीं हो जाती । मार्ग के स्टेशनों पर भी वे बहुत समय तक ठहरती हैं । इस प्रकार यात्री को बहुत सा समय नष्ट करना पड़ता है ।

(२) सरकारी रोडवेज यात्रियों की निश्चित सहायता ले जाती हैं । इस कारण उनमें यात्रियों को कुछ कष्ट नहीं होता । पर प्राइवेट मोटर अधिक से अधिक यात्रियों को ले जाने का प्रयत्न करती हैं । वे यात्रियों को सुविधा का तनिक भी ध्यान नहीं रखतीं । इस कारण यात्रियों को बड़ा कष्ट होता है ।

(३) सरकारी रोडवेज का किराया निश्चित होता है, वे उससे अधिक नहीं लेती । यद्यपि सरकार द्वारा प्राइवेट मोटरों का किराया भी निश्चित होता है तो भी बहुत बार वे उससे अधिक लेती हैं और बीच के एक स्थान से दूसरे स्थान तक का किराया वे अपनी इच्छानुसार ही लेती हैं ।

(४) सरकारी रोडवेज की सीट बहुत अच्छी बनी होती हैं । उन पर बैठने पर यात्री को बहुत आराम मिलता है पर प्राइवेट मोटरों की सीट अच्छी बनी हुई नहीं होती । इस कारण उन पर यात्री को अधिक आराम नहीं मिलता ।

(५) सरकारी रोडवेज की मशीन बहुत अच्छी होती है । यह समय-समय पर ठीक भी होती रहती है । इसी कारण यह प्राइवेट मोटरों की अपेक्षा अधिक वेग से चलती है ।

(६) सरकारी रोडवेज किसी मनुष्य के साथ भी रियायत नहीं करती । पर प्राइवेट मोटर पुलिस के आदमियों से बहुत डरती है । वह उनसे बिना किराया लिये ही उनको सबसे अच्छा स्थान देती है । ऐसा करने में कभी-कभी यात्रियों को भारी कष्ट सहन करना पड़ता है ।

(७) सरकारी रोडवेज एडवांस बुकिंग की सुविधा भी प्रदान करती है जो कि प्राइवेट मोटर नहीं करती ।

(८) मोटरों के स्टेशनों पर रोडवेज यात्रियों के लिये पानी, चाय, आदि की सुविधा प्रदान करती है जो कि प्राइवेट मोटर नहीं करती ।

इसी प्रकार सामान के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सरकारी मोटर निश्चित दर से किराया चार्ज करती है तथा सामान को ठीक समय पर पहुँचा देती है तथा बिना किसी को रियायत किये सामान को उसके नम्बर पर ले जाती है । परन्तु यह बात ध्यान रहे कि सरकारी मोटरों अभी तथा निकट भविष्य में इस कार्य को नहीं करेंगी ।

पर जहाँ सरकारी रोडवेज के यह गुण हैं वहाँ उनके निम्न दोष भी हैं—

(१) प्राइवेट मोटर वाले रोडवेज की अपेक्षा यात्रियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं ।

(२) प्रतियोगिता के कारण उनका किराया घट जाता है । इसका लाभ यात्रियों को मिलता है । परन्तु रोडवेज का किराया इस प्रकार नहीं घट सकता । यह किराया साधारणतया प्राइवेट बसों से अधिक होता है ।

(३) प्राइवेट मोटरों पर बहुत सा सामान बिना किसी किराये के यात्री ले जा सकता है । परन्तु रोडवेज में थोड़े सामान का किराया भी लिया जाता है ।

(४) सामान ले जाने में तो प्राइवेट मोटरों से बहुत सी सुविधायें मिलती हैं, वैसे उनके द्वारा किसी समय भी सामान ले जाया जा सकता है, उनको सामान के गोदाम के पास लाया जा सकता है तथा प्राइवेट मोटर वाला सामान को बहुत सावधानी से ले जा सकता है । कभी-कभी वे सरकारी मोटरों से भी कम किराया लेती हैं ।

(५) प्राइवेट मोटरों के कर्मचारियों का व्यवहार यात्रियों के प्रति उससे अच्छा होता है जितना कि रोडवेज के कर्मचारियों का होता है ।

(६) रोडवेज के बस स्टैंड पर यात्रियों को बहुत देर तक इन्तजार देखनी पड़ती है ।

(७) रोडवेज का किराया प्राइवेट बसों से बहुधा अधिक होता है ।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोडवेज यात्रियों को ले जाने के लिये उपयुक्त है और प्राइवेट बस सामान के लिये । योजना आयोग ने एक विशेष स्टुडी ग्रुप के द्वारा सड़क यातायात की उन्नति की जाँच कराई थी । आयोग ने सुझाव दिया है कि दूसरी योजनाकाल में माल यातायात का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए वरन् निजी गाड़ी चलाने वालों को प्रतियोगी इकाई बनाने में सहायता करनी चाहिये । यात्री यातायात के विषय में आयोग सुझाव दिया है कि राष्ट्रीयकरण का कार्य ठीक योजना के साथ चलाना चाहिये और जहाँ सरकार इस भार को अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है वहाँ निजी चलाने वालों को उदारतापूर्वक साइंस देने चाहियें ।

रेल-सड़क प्रति-स्पर्धा (Rail-Road Competition)

Q. 79. Give the essentials of road rail controversy. Offer suggestions for the solution of this rivalry.

प्रश्न ७९—सड़क-रेल संघर्ष की विशेषतायें दीजिये । इस प्रतिद्वन्द्विता को सुलझाने के लिये सुझाव दीजिये ।

सड़क तथा रेल की प्रतियोगिता भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह संसार के प्रायः सभी देशों में पाई जाती है । अमेरिका के समान भारतवर्ष में सड़क तथा रेल प्रतियोगिता १०, ६० मील तक ही होती है । परन्तु इङ्ग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस तथा इटली जहाँ अधिक फासले नहीं पाये जाते वहाँ पर इस प्रतियोगिता ने बड़ा उग्र रूप धारण किया हुआ है । इस देश में सड़कों तथा रेलों की प्रतियोगिता इसलिये हो गई है क्योंकि सड़कें रेलों के समानान्तर चलती हैं । यदि यह बात न होती तो हमारे देश में यह समस्या शायद न खड़ी होती ।

बहुत समय तक इस देश में रेलों के साथ किसी दूसरे प्रकार के यातायात के साधन की प्रतियोगिता न थी । पर हाल ही में मोटरों का जोर बढ़ रहा है । इसी कारण रेलों के साथ उनकी प्रतियोगिता हो गई है । इसके कारण रेलों तथा मोटरों ने अपने किराये बहुत कम कर दिये और दोनों को अधिक हानि हुई ।

रेलों का कहना है कि उनको मोटरों के कारण बहुत हानि हो रही है क्योंकि मोटरों को रेलों की अपेक्षा बहुत सी सुविधायें प्राप्त हैं । रेलों को अपने खर्च पर रास्ते का प्रबन्ध करना पड़ता है परन्तु मोटरों को सड़क बनाने पर बहुत ही कम व्यय करना पड़ता है । रेलों को बहुत सा धन स्टेशन बनाने, रेलवे साइडिंग बनाने तथा एक बड़ा कर्मचारी वर्ग रखने के लिए खर्च करना पड़ता है परन्तु मोटरों को इन सब बातों पर कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता । इन बातों के कारण रेलें यह चाहती हैं कि उनको मोटरों की अपेक्षा कुछ अधिक सुविधायें मिलें जिससे वे मोटरों के साथ ठीक प्रकार से प्रतियोगिता कर सकें । परन्तु रेलों की दलील गलत है । यह अनुमान लगाया गया है कि रेलों द्वारा एक टन सामान ले जाने का खर्च ११'१ पाई प्रति मील है जबकि एक पब्लिक मोटर पर एक टन सामान का कर का खर्च २३ से २४ पाई प्रति मील पड़ता है ।

परन्तु हमें यह सोचना है कि इन बातों में क्या सार है । यदि हम ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमको पता चलेगा कि रेल तथा मोटर की प्रतियोगिता निम्न है । किसी देश के लिये दोनों ही प्रकार के यातायात के साधनों का महत्व है । रेल सम्भी यात्रा के लिये उपयोगी है । और मोटर छोटी यात्रा के लिये । हमारे देश में जहाँ बाढ़ आदि आती रहती है सड़कों के, बनाने में बहुत अधिक व्यय करना पड़ता है । इसके होते हुए भी सड़कों पर कम व्यय करना पड़ता है । क्योंकि मोटरों के लिये स्टेशनों तथा साइडिंग आदि की आवश्यकता नहीं है । बहुत से स्थानों, जैसे खेतों तथा किसानों के मकानों तक रेल नहीं पहुँच सकती । ऐसे स्थानों पर मोटरों से ही

काम लेना पड़ेगा। कृपि कमोशन के मतानुसार हमारे देश में मोटरों रेलों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। रेलें भारतवर्ष के गाँव तक नहीं पहुँची हुई हैं। गाँव में से यात्री तथा सामान एकत्रित करके मोटर गाड़ियाँ रेलों तक पहुँच सकती हैं। यदि मोटर गाड़ियाँ वह काम न करें तो या तो रेलों को स्वयं यह काम करना पड़ेगा या इनको उस सामान तथा यात्रियों से हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार इस देश में रेलों तथा मोटरों में प्रतियोगिता होने के बदले ये दोनों एक दूसरे के सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त इस समय रेलें देश की यातायात की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने में असमर्थ हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेलों की उन्नति के लिए १६८० करोड़ रु० की योजना बनाई गई थी परन्तु योजना में उसके लिये केवल ११२५ करोड़ रुपए का प्रबन्ध किया गया है। इस कमी के कारण जैसा कि रेलवे मन्त्री ने स्वीकार किया है, रेलें पेंसिजर ट्रैफिक की ३० प्रतिशत माँग के स्थान पर १५ प्रतिशत माँग व गुड्स ट्रैफिक की ६०-८० मिलियन टन की माँग के स्थान पर केवल ४२ मिलियन टन पूरा कर सकेंगे। दोप माँग को पूरा करने के लिए यातायात के दूसरे साधनों को उन्नत करने की आवश्यकता है। देश के जल यातायात को उन्नत करने में बहुत समय लगेगा। यद्यपि देश में १६ लाख वैलगाड़ियाँ हैं तो भी उनसे देश के यातायात की समस्या नहीं सुलझ सकती क्योंकि वे एक घंटे में एक मील से अधिक नहीं चलती। इस कारण उनके द्वारा दूर तक सस्ते मूल्य पर सामान नहीं ले जाया जा सकता। हवाई जहाज से सामान ढोने का खर्च बहुत पड़ता है। इसी कारण देश में मोटर यातायात को उन्नत करने की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त यह बात भी बताने योग्य है कि हमारे देश में आज मोटरों तथा रेलों पर इतनी पूँजी लगी हुई है कि यदि हम उनमें से एक को भी समाप्त करें तो भी देश को बड़ी हानि होगी। इसके साथ ही साथ यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे देश में इसके क्षेत्रफल को देखते हुए रेलों तथा मोटरों की बहुत कम उन्नति हुई है। अभी हमारे देश में दोनों ही प्रकार के यातायात के साधनों को उन्नत करने के लिए बहुत अवसर हैं। हमें चाहिए कि भविष्य में हम रेलों तथा सड़कों को इस प्रकार बनायें कि इन दोनों में प्रतियोगिता होने के बदले ये एक दूसरे के सहायक बन सकें। श्री एस० के० पाटिल केन्द्रीय यातायात मन्त्री ने अभी हाल ही में कहा है कि अगले २५ वर्षों में रेल तथा सड़क यातायात में प्रतियोगिता का कोई खतरा नहीं है।

हमारे देश में रेलों तथा मोटरों में मन्दो के समय बड़ी प्रतियोगिता हुई। इस प्रतियोगिता का सामना करने के लिये वेजबुड कमेटी ने बहुत से सुझाव दिये।^१ उसने बताया कि रेलों को अपना किराया नहीं घटाना चाहिये। इसके बदले उनको यह प्रयत्न करना चाहिये कि वे यात्रियों तथा सामान को अधिक तेजी से ले जायें तथा उनको अधिक सुविधा दें। रेलों ने इस प्रकार कार्य किया परन्तु उनको इससे कोई अधिक लाभ न हुआ। इस कारण रेल तथा मोटरों में सहयोग की नीति पर

जोर दिया गया। १९३२-३३ की मिचल-किर्कनेस रिपोर्ट ने इस बात का सुझाव दिया कि रेलों तथा मोटरों में ठीक प्रकार की प्रतियोगिता प्राप्त करने के लिये मोटरों पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट ने यह भी बताया गया कि इस दृष्टि से प्रान्तों में एक केन्द्रीय यातायात परामर्श बोर्ड बनाया जाय तथा कमिशनरियों में कमिशनरी बनाई जाय। मिचल किर्कनेस कमेटी के आदेशानुसार १९३३ में एक रेल सडक कांफ्रेंस हुई। इस कांफ्रेंस ने बताया कि यातायात की प्रतियोगिता को दूर करने के लिये यातायात के सब साधनों में सहयोग हो। ऐसा करने के लिये उसने यह बताया कि रेलों को मोटर चलाने की आज्ञा मिलनी चाहिए। १९३५ में एक यातायात परामर्श कौंसिल भी बनाई गई। इसका कार्य यह था कि सडकों की इस प्रकार की नीति बनाये जिससे कि भिन्न भिन्न प्रकार के यातायात के साधनों में सहयोग हो सके। १९३० में एक असम यातायात विभाग खुलने के पश्चात् इस प्रकार कार्य बहुत ही सरल हो गया। १९३७ में वेजवुड कमेटी ने बताया कि रेलों तथा सडकों पर ठीक प्रकार का नियन्त्रण न होने के कारण दोनों ही प्रकार के यातायात के साधनों को बड़ी हानि हो रही है। इसी के कारण उसने दोनों प्रकार के साधनों पर कड़ा नियन्त्रण करने का सुझाव दिया। वेजवुड कमेटी ने इस बात पर जोर दिया कि रेलों को अपनी मोटर गाड़ियाँ चलानी चाहियें।

१९३६ में मोटरगाड़ी एक्ट पास किया गया जिसके अनुसार मोटरों के ऊपर बहुत सी पाबन्दियाँ हो गईं। १९४५ में सरकार ने रेलों, मोटरों तथा प्रांतीय सरकारों की लिमिटेड कम्पनी बनाने का सुझाव पेश किया। परन्तु इसमें रेलें पूंजी का अधिक भाग लेना चाहती थीं। मोटर वाहनों ने इसका विरोध किया। इस कारण वह स्कीम तब न चल सकी। परन्तु १९५० ई० में रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट पास किया गया जिसके फलस्वरूप रेल, मोटर वाले तथा राज्य सरकारें तीनों मिलकर सडक यातायात का कार्य करेंगी।

दूसरी योजना के लिए योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि वर्तमान सडक यातायात को राज्य सरकारों द्वारा लिये जाने का कार्य ठीक टङ्क से होना चाहिए और राज्य स्वयं सडक यातायात को चलाने का इरादा नहीं रखता वहाँ निजी चलाने वालों को उदार दिल से अनुज्ञापत्र देने चाहियें। सरकारी सडक यातायात का नियन्त्रण ऐसे कार्पोरेशन के द्वारा किया जाना चाहिए जिनमें रेलों, निजी चलाने वालों के तथा सरकार के प्रतिनिधि हों। इस योजना में सानान ले जाने का कार्य निजी चलाने वालों के द्वारा किया जायगा तथा इसका राष्ट्रीयकरण इस योजना में नहीं विचारा गया है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलों व सडकों के सहयोग से ही देश की वास्तविक उन्नति हो सकती है। भारत सरकार द्वारा नियुक्त (Study Group on Transport) ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि देश में न केवल रेलों की ही

भारतवर्ष में बहुत सी बड़ी नदियाँ हैं। उत्तर में गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियाँ हैं जो हिमालय पहाड़ से निकलने के कारण सदा बहती रहती हैं। दक्षिण में गहानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि हैं। परन्तु इनका पानी गर्मी के दिनों में सूख जाता है, ये नदियाँ भारत के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये यहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। सिंचाई के लिये पानी देती हैं तथा यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन रही हैं। इतना होते हुए भी नदियों की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

रेलों के बनने से पूर्व नदियाँ यातायात का महत्वपूर्ण साधन थीं। यमुना नदी में मुगलकाल में आगरा तक नावें चलती थीं। उधर सतलज में लुधियाना तक नावें चलती थीं। परन्तु मिट्टी के अधिक जमा हो जाने के कारण उनमें आजकल नावें नहीं चलाई जाती। १८५६ तक गोदावरी आदि नदियों में समुद्र से देश के भीतर ४०० मील तक नावें चलती थीं।

परन्तु रेलों के आ जाने पर भारत की जल यातायात पीछे पड़ गई। सरकार ने इसकी उन्नति की ओर जरा भी ध्यान न दिया और अपनी सारी शक्ति रेलों के बनाने में खर्च कर दी। फल जो होना चाहिए था वही हुआ। भीतरी जल यातायात का देश की अर्थ-व्यवस्था में कोई भी स्थान न रहा।

परन्तु देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात् हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने इस अवनत जल यातायात को फिर उन्नत करें। इससे देश को बहुत लाभ होगा। इसका कारण यह है कि यह सबसे सस्ता यातायात का साधन है। इस कारण भारी-भारी सामान को दूर तक ले जाने के लिये यह सबसे उपयुक्त साधन है। इसके उन्नत होने पर खेती तथा उद्योग दोनों को ही लाभ होगा। खेती को यह लाभ होगा कि खेती के औजार कम कीमत पर दूर-दूर तक ले जाये जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त खेती की उपज को भी मंडियों तक ले जाने का खर्च बहुत घट जायगा। पशुओं को खिलाने के लिये बनों की घास को दूर-दूर के स्थानों तक केवल इसी साधन से भेजा जा सकता है। इसके साथ-साथ भारत में कृषि के लिए यह एक बड़ी समस्या है कि गोबर की खाद को ईंधन के रूप में जलाया जाता है जिसके कारण उपज कम मिलती है। यदि जल यातायात उन्नत हो जाए तो बनों की सस्ती लकड़ी किसान के पास तक पहुँचाई जा सकेगी जिसके फलस्वरूप वह खाद को न जलायेगा।

खेती के अतिरिक्त उद्योग वर्गों के लिये भी इस यातायात के साधन का बड़ा महत्व है। इसके द्वारा भारी कच्चा माल औद्योगिक केन्द्रों तक कम मूल्य पर पहुँच सकेगा तथा पक्का माल औद्योगिक केन्द्रों से उपभोग केन्द्रों तक बहुत सस्ता पहुँचाया जा सकेगा। इस प्रकार इन साधनों के उन्नत होने से खेती व उद्योगों दोनों को ही लाभ होगा।

बहुधा ब्यान्तरिक जल यातायात की उन्नति का विरोध इसलिए किया जाता है कि इसके कारण रेलों तथा सड़कों से अनावश्यक प्रतियोगिता बढेगी। परन्तु

ऐसा सोचना गलत है क्योंकि संसार के अन्य बड़े-बड़े देशों जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हालैंड आदि में जल मार्गों की उन्नति यातायात के दूसरे साधनों के साथ हुई है। इन देशों में बड़ी-बड़ी नदियों को नहरों से मिला दिया गया है जिसके कारण जल मार्ग से एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक जाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र में सेन्टलारेन्स नदी व बड़ी झीलो व मिसिसिपी मिसौरी को नहरों से मिलाकर उत्तर में सेन्टलारेन्स की खाड़ी से दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी तक जल मार्ग से सामान ले जाया जा सकता है। इसी प्रकार रूस में कृष्ण सागर, श्वेत सागर, बाल्टिक सागर तथा कैस्पियन सागर को नहरों द्वारा मिलाकर इसी प्रकार के अन्तर्देशीय जलमार्ग प्रदान किये गये हैं। भारत में भी इस प्रकार के अन्तर्देशीय जल मार्गों की सम्भावना है। जेम्स रेनल ने १७६२ ई० में कहा था कि नर्मदा व सोन को आपस में मिलाने से इस प्रकार का अन्तर्देशीय मार्ग प्रदान किया जा सकता है। यह हर्ष का विषय है कि भारत सरकार इस प्रकार की सम्भावना पर विचार कर रही है।

भारत में इस समय २०,००० मील लम्बे जल मार्ग हैं जिनमें ५००० मील नदियों के तथा शेष १२००० मील लम्बे नहरों के हैं। इनमें नदियों में ३००० मील तक नावें चलती हैं। इस ३००० मील में से २००० मील केवल पश्चिमी बंगाल व आसाम में है। नहरों में से उनके उन्नत करने पर ३००० मील में स्टीमर तथा ६००० मील में नावें चल सकती हैं। आजकल सरकार द्वारा संचालित चैनलों में २५० मिलियन टन मील प्रति वर्ष सामान ले जाया जाता है जो कि रेलों द्वारा ले जाये जाने वाले सामान का केवल १ प्रतिशत है।

भारत में आजकल यह अनुभव किया जा रहा है कि देश के जल यातायात को उन्नत किया जाय। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों पर जल यातायात को उन्नत करने तथा उनमें सामञ्जस्य स्थापित करने के लिये १९५० ई० में गंगा, ब्रह्मपुत्र जल यातायात बोर्ड स्थापित किया गया। यह केन्द्र तथा राज्य सरकारों के गामूहिक प्रयत्न द्वारा स्थापित किया गया है। केन्द्रीय सरकार इस प्रकार के बोर्ड आंध्र, मद्रास, केरल आदि में स्थापित करने का प्रस्ताव रखेगा।

भारत में आजकल १५५७ मील लम्बी नदियों में मशीन से चलने वाले स्टीमर चलते हैं तथा ३५८७ मील में बड़ी-बड़ी नावें चलती हैं। देश में जल यातायात अभी उन्नत हो सकती है जबकि या तो नदियों को गहरा किया जाय, या उनमें पानी के बहाव पर नियन्त्रण किया जाय, या ऐसी नावें बनाई जायें जो कि कम गहरे पानी में चल सकें। नदियों को गहरा करने में बहुत पूंजी की आवश्यकता है। इसी कारण इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि ऐसी नावें बनाई जायें जो कि कम गहरे पानी में चल सकें। गंगा-ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहा है मुख्य-मुख्य जल मार्गों की मिट्टी साफ करना, नावें चलाने के लिये सहायता करना

तथा मुख्य प्रमुख स्थानों पर बन्दरगाह बनाना है। योजना में बर्किशम नहर को उन्नत करना तथा उसको मद्रास के बन्दरगाह से मिलाना तथा पश्चिमी समुद्रतट की नहरों को उन्नत करना रखा गया है। योजना में आन्तरिक जल यातायात को उन्नत करने के लिये केवल ३ करोड़ रुपया रखा गया है। इसमें से ११५ लाख तो बर्किशम नहर को उन्नत करने के लिये तथा ४३ लाख पश्चिमी समुद्रतट की नहरों को उन्नत करने के लिये रखा है। शेष धन तथा राज्य सरकारों का चन्दा शेष दूसरे भागों की उन्नति के लिये काम में लाया जायगा।

इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी योजनाएँ हैं। इनमें कलकत्ता-कोचीन योजना में बहुत सी नहरें हैं, जैसे मिदनापुर तथा उड़ीसा की तटीय नहरें, गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टे की नहरें, बर्किशम नहर तथा वेदारनपुर नहर। इनमें से मिदनापुर तटीय नहर बहुत से स्थानों पर खराब हो गई है। यदि इन नहरों को मिला दिया जाय तो कलकत्ता से कावेरी तक एक जल मार्ग हो जायेगा। ऊपर कावेरी के ऊपरी भाग से एक नहर निकालकर कोचीन के बन्दरगाह को मिलाया जा सकता है, परन्तु योजना में कावेरी के दक्षिण में एक नहर बनाये जाने का प्रबन्ध किया गया है।

गंगा को ब्रह्मपुत्र से भारतीय राज्य सीमा में होकर एक नहर से मिलाने की योजना भी है। इस नहर के बन जाने से आसाम का सामान भारत में आ सकेगा। इनके अतिरिक्त और भी योजनाएँ हैं जैसे नर्मदा को जोहिला से जो कि सोन की सहायक नदी से मिलाना, नर्मदा की सहायक नदी, बीरु की सोन की सहायक नदी कटनी से मिलाना, वीरमा केन की सहायक को नर्मदा से मिलाना, नर्मदा की सहायक नदी, करम को चम्बुल से मिलाना, नर्मदा को गोदावरी की सहायक नदी वेनगंगा से मिलाना, महानदी की सहायक नदी हसू को रिहाड से जो कि सोन की सहायक नदी है, मिलाना, वर्धा, गोदावरी की सहायक नदी को ताप्ती से मिलाना आदि। यदि ऊपरी तथा निचली गंगा की नहरों को जोड़ कर दिया जाय तो नावें हरिद्वार तक चल सकती हैं। इन सब योजनाओं के पूरा होने पर बंगाल की खाड़ी के बन्दरगाह अरब सागर के बन्दरगाहों से आन्तरिक जल मार्गों से मिल जायेंगे। ऐसा होने पर हमारी यातायात की समस्या बहुत कुछ सुलझ जायगी।



जहाजी यातायात (Shipping Transport)

Q 81 How do you account for the backward condition of Indian shipping ? What attempts have been made to improve it ? Give your own suggestions

प्रश्न ८१—भारत में जहाजी यातायात के पिछड़े होने के क्या कारण हैं ? इसको उन्नत करने के लिये क्या प्रयत्न किये हैं ? अपने सुझाव दीजिये ।

१९वीं शताब्दी के आरम्भ तक भारतवर्ष जहाजरानी के लिये प्रसिद्ध था । भारतवर्ष में उस समय ऐसे जहाज बनते थे जो इंग्लैंड तक जाते थे । परन्तु जब से लोहे के भाप की शक्ति से चलने वाले जहाज बनने लगे तब से इस देश के लकड़ी के जहाजों को बड़ा आघात पहुँचा । इससे साथ ही साथ अंग्रेजी जहाजी कानूनों से भी इस देश की जहाजरानी को बड़ी क्षति पहुँची । इन कानूनों द्वारा भारतीय जहाजों का इंग्लिश चैनल में जाना वर्जित कर दिया गया था । जैसे जैसे अंग्रेजों का भारतवर्ष पर प्रभुत्व स्थापित होता गया वैसे ही वैसे उन्होंने इस देश के जहाजी यातायात को नष्ट कर दिया । इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने के समय भारतवर्ष के समुद्री किनारे के व्यापार में से २५ प्रतिशत तथा दूसरे देशों के व्यापार में से ४ प्रतिशत भाग था ।

भारत के समुद्री यातायात पर एक अंग्रेजी जहाजी मण्डल का नियन्त्रण है । यह मण्डल दो प्रकार से भारतीय जहाजों को हानि पहुँचाता है—(१) किराये की लड़ाई (Freight War) तथा (२) विलम्बित छूट पद्धति (Deferred Rebate System) ।

(१) किराये की लड़ाई—जब कभी कोई नई भारतीय जहाज कम्पनी चालू की जाती है तभी यह मण्डल अपने जहाजों का किराया इतना कम कर देता है कि नई कम्पनी को मुकाबले में टिकना असम्भव हो जाता है और अन्त में वह कम्पनी फल हा जाती है । भारतीय जहाजी कम्पनी के नष्ट हो जाने के पश्चात् मण्डल फिर किराया बढ़ा देता है । इस प्रकार पिछले सौ वर्षों में सैकड़ों जहाजी कम्पनियाँ फेल हो गईं और भारतवर्ष को करोड़ों रुपये की हानि हुई । इसके एक दो उदाहरण देने आवश्यक हैं । एक बार टाटा कम्पनी ने भारतवर्ष से चीन को घागा से जाने के लिये एक जहाज चलाया तब मण्डल ने किराये की दर १६ रुपये टन से घटाकर १२ रुपये कर दी । १९२१ में मण्डल ने सिन्धिया कम्पनी के विरुद्ध चावल से जाने की दर को १८ रुपये से घटाकर ६ रुपये कर दी । १९३४ में चावल से जाने का किराया १४ रुपये से घटाकर आठ रुपये प्रति टन कर दिया ।

(२) विलम्बित छूट पद्धति—इसके अनुसार अंग्रेजी जहाजी कम्पनियाँ यह घोषित करती हैं कि यदि सोदागर अपना माल ४ या ६ महीने तक मण्डल के जहाजों

पर ले जाता रहेगा तो उसको कुल किराये का जो उसने दिया है एक भाग (लगभग १० प्रतिशत) छूट के रूप में मिलेगा। परन्तु यह छूट उसको उस समय मिलेगी जब वह अपना माल अगले ४ या ६ महीने तक मण्डल के जहाजों पर ले जाता रहेगा। इस प्रकार की पद्धति को विलम्बित बड़ा पद्धति कहते हैं। इसके द्वारा सीदागर लोग अपना माल मण्डल के जहाजों पर लादते हैं। इस कारण देशी जहाजों को जो छूट नहीं दे सकते बड़ी हानि पहुँचती है।

इसके अतिरिक्त बन्दरगाह चाले भी जहाजी कम्पनियों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते आये हैं। कई बार वे विदेशी जहाजों को उस स्थान पर खड़े होने की आज्ञा दे देते थे जहाँ पर भारतीय जहाजों को खड़ा होना था। इस प्रकार वह सामान जो, भारतीय जहाजों पर लादा जाता वह विदेशी जहाजों पर लद जाता था और इस प्रकार भारतीय जहाजों को बड़ी हानि होती थी।

यही नहीं, भारतीय सरकार की नीति भी हमारी, जहाजी यातायात की उन्नति के मार्ग में बाधा के रूप में खड़ी हुई थी। सरकार कभी भी भारतीय जहाजों पर कोई सामान न तो विदेशों को ले जाती थी और न लाती थी। उसने समुद्र तटीय व्यापार के लिये भी जो कि सभी देशों में उस देश का एकाधिकार होता है, विदेशी जहाजों को खुली छोड़ी दे रखी थी। इस प्रकार १९४४-४५ में भारतीय जहाजों का समुद्रतटीय जहाजों में केवल २५ प्रतिशत भाग था।

इन सब बातों के कारण हमारे देश में जहाजी यातायात की उन्नति न हो सकी।

जहाजी यातायात को उन्नत करने के प्रयत्न-१९२३ की फरवरी में "इण्डियन मरचेन्टाइल तथा मीरिन कमेटी" नियुक्त की गई। इस समिति का उद्देश्य यह जाँच करना था कि भारतीय जहाज चलाने तथा जहाज बनाने के काम में किन-किन उपायों से उन्नति हो सकती है। इस समिति ने समुद्रतटीय व्यापार को भारतीय जहाजों के लिये सुरक्षित रखने का सुझाव रखा। परन्तु सरकार ने इस सुझाव की ओर कोई ध्यान न दिया। इसके पश्चात् १९२५ में अलेक्जेंड्री के मिस्त्रियर के अधिवेशन में श्री हाजी ने तटीय यातायात को भारतीय जहाजों के लिये सुरक्षित रखने के हेतु एक बिल उपस्थित किया। परन्तु उसको स्वीकार नहीं किया गया। १९२६ में श्री हाजी ने विलम्बित छूट के अन्त के लिये प्रस्ताव रखवा। परन्तु वह भी स्वीकार न हुआ। १९३७ में सर अब्दुल हातिम गजनवी ने समुद्री यातायात को सुधारने के लिये एक बिल पेश किया परन्तु उसको भी सरकार ने न माना। १९३६ में श्री पी० एन० सपरू ने एक बिल पेश किया जिसमें सरकार से प्रार्थना की गई थी कि वह तटीय व्यापार को भारतीय जहाजों के लिये सुरक्षित करदे। परन्तु सरकार ने सदा की तरह इस बात को भी न माना।

सुदूरकाल में सरकार को भारत की जहाज सम्बन्धी नीति की कभी प्रतीत हुई। इस कारण उसने १९४५ में पुनर्निर्माण नीति उपसमिति (Reconstruction

Policy Sub-committee) नियुक्त की जिसने १९४७ में अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में समिति ने यह सुझाव दिया कि भारतीय जहाजी समस्या के लिये सरकार को एक हठ राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। इस समिति ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अपने तटीय व्यापार को शत प्रतिशत, बर्मा तथा लङ्का के साथ होने वाले व्यापार का ७५ प्रतिशत तथा अन्य देशों के साथ होने वाले व्यापार का ५० प्रतिशत अपनाना चाहिये। सरकार ने इस सुझाव को मान लिया।

सरकार की जहाज सम्बन्धी नीति की घोषणा होने के पश्चात् भारतीय जहाजी व्यापार की खूब उन्नति हुई। इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध के समाप्त होने पर इस देश में ११ कम्पनियाँ थी जिनके पास ६३ जहाज थे। ये जहाज १३१,७४८ टन के थे। १९४६ के अन्त में इस देश में १६ कम्पनियाँ थी जिनके पास ३४३,००० टन के जहाज थे। इनमें से १६२,५०० टन के २२ जहाज विदेशी व्यापार में लगे हुये थे। इसके अतिरिक्त १,८०,५०० टन के ७५ जहाज तटीय व्यापार में लगे हुये थे। १९५१ के अन्त में भारतवर्ष के जहाज ३६१,००० टन के थे। आजकल भारतीय जहाजों के हाथ में सारा तटीय व्यापार तथा भारत, बर्मा, लका, व्यापार का ४० प्रतिशत व्यापार है। युद्ध से पहले भारतवर्ष का कोई भी जहाज विदेशी व्यापार में नहीं लगा हुआ था पर आजकल भारतीय जहाजी कम्पनियाँ सामान तथा यात्रियों को ले जाने के लिये मलाया, जापान, इंग्लैंड तथा योरोप महाद्वीप तक जाती हैं तथा केवल सामान को ले जाने, लाने के लिये इंग्लैंड, संयुक्तराष्ट्र अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया तक जाती हैं। १९४७-५० के बीच भारतवर्ष में जहाजों की वृद्धि हुई। इनमें से ३६,१९५ टन के आठ जहाज भारतवर्ष के ही बने हुये हैं। १९५१ से ५६ तक के लिये सरकार ने अपनी योजना बनाई। इस योजना के अनुसार भारत के जहाजों में ६ लाख टन के जहाजों की वृद्धि होनी थी। इनमें से ३६५,००० टन के जहाज तटीय व्यापार में तथा २९३,००० टन के जहाज विदेशी व्यापार में लगेंगे। प्रथम योजना के अन्त तक भारत में ५,६५,७०७ टन के जहाज थे। प्रथम योजना-का-व्यय बिन्दु एक वर्ष पीछे प्राप्त कर लिया गया। मार्च १९५६ तक भारत के पास ६४७,८१२ टन के जहाज थे। इस प्रकार दूसरी योजना बिन्दु को प्राप्त करने में अभी १३०,१८८ टन की कमी है।

१९४७ में सरकार ने इस बात की घोषणा की थी कि वह दस करोड़ की पूंजी से तीन जहाजी कार्पोरेशन स्थापित करेगी जिसमें सरकार की पूंजी ५१ प्रतिशत से लेकर ७४ प्रतिशत तक हो सकती है। शेष पूंजी पूंजीपतियों की होगी। इन तीनों में से एक कार्पोरेशन १९५० में स्थापित हो चुकी है। इसकी अधिकृत पूंजी १० करोड़ रुपये है। इसकी व्यवस्था सरकार ने अगस्त १९५६ से अपने हाथ में ले ली है। इसके पास ८ जहाजों का वेडा है जो सामान तथा यात्रियों को जापान, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर पूर्वी अफ्रीका ले जाता है। दूसरे की रजिस्ट्री जून १९५६ में की गई। इसकी पूंजी १० करोड़ रु० है। यह लाल सागर, फारस की खाड़ी पोलैंड तथा रूस में कार्य करेगी।

दिसम्बर १९५५ के भारत और रूस के बीच हुये व्यापारिक समझौते के फलस्वरूप अब भारत और रूस के बीच का व्यापार बढ़ने के कारण इस कार्पोरेशन ने अपना कार्य-क्षेत्र काले सागर के बन्दरगाहों तक बढ़ा दिया है। भारत और पोलैंड के बीच भी जहाजी सविस शुरू हो गई है।

पंचवर्षीय योजना में जहाजी यातायात का स्थान—

पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ६००,००० टन के जहाजों का ध्येय रखा गया है। २३.७२ करोड़ रु० ऋण के रूप में जहाजी कम्पनियों को जहाज खरीदने के लिए दिये गये हैं। ऐसी आशा की जाती है कि अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से भी कुछ सहायता प्राप्त हो जायगी।

भारत में अभी तक अच्छे बन्दरगाहों की कमी है। इसलिये वर्तमान पाँच बन्दरगाहों—बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कोचीन तथा विशाखापट्टन—को उन्नत करने के लिये सरकार १२ करोड़ रुपये का ऋण देगी। योजना में कांठला (Kandla) बन्दरगाहों को उन्नत करने के लिये १२.०५ करोड़ रु० रखे गये हैं। यह बन्दरगाह उस माल की प्राप्त करेगा जो पहले कराँची जाता था। तेल साफ करने वाली कम्पनियों को बन्दरगाह की सुविधा प्रदान करने के लिये ८ करोड़ रुपये रखे गये हैं।

जहाजी यातायात सम्बन्धी सभी बातों की देखभाल करने तथा सरकार को इन पर परामशें देने के लिये एक जहाजी बोर्ड (Shipping Board) की स्थापना भी की गई है।

दूसरी योजना में ६ लाख टन का ध्येय रखा गया है। इस योजना के अन्त तक भारतवर्ष का सुदूर सामूहिक व्यापार में १५ प्रतिशत भाग हो जायगा।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड को बढ़ाया जायगा जिससे वह ४ जहाज प्रतिवर्ष बना सकेगा। एक दूसरे जहाज बनाने के कारखाने का प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिया जायेगा। इसकी उत्पादन शक्ति ६०,००० टन होगी जो कि ८०,००० टन तक बढ़ाई जा सकेगी।

जहाँ प्रथम योजना काल में हमारी जहाजी शक्ति बहुत कम रही वहाँ द्वितीय योजना काल के पहले ही वर्ष में (१९५६-५७) से उसने बहुत उन्नति की। इस वर्ष में द्वितीय योजना काल के लिये निश्चित ३७ करोड़ रु०, सब के सब भारत तथा यूरोप से जहाज खरीदने में खर्च कर दिये गये। इसके कारण हमारी जहाजी शक्ति में १८०,००० टन की वृद्धि हो गई। १९५७-५८ में स्वयं वित्तीय आधार (Self financing basis) पर जहाज खरीदे गये। इस योजना के अन्तर्गत अगस्त १९५७ से अगस्त १९५८ तक ४४००० टन के जहाज खरीदे गये। इस योजना के अनुसार जहाजों का मूल्य विस्तार में छुकाया जायगा। जहाजों से जो लाभ प्राप्त होगा उसी की किस्ती में दिया जायगा। इसके अतिरिक्त इस वर्ष में बहुत से नए जहाज प्राप्त हुए जिनके लिए कि पिछले वर्षों में आर्डर दिये हुये थे।

जहाजी यातायात तथा जहाज बनाने के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने १९५७-५८ में एक जहाजी विकास कोष (Shipping Development Fund) भी स्थापित किया। इस कोष की १ करोड़ की पूंजी से स्थापित किया गया है तथा यह वन भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) में से दिया गया है। भविष्य में भी इस निधि में से आवश्यकतानुसार धन हस्तान्तरित किया जायगा। ऐसी आशा है कि १९६०-६१ तक इस कोष में ६५ करोड़ रु० एकत्र हो जायेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसी आशा है कि निजी पूंजी जहाजी यातायात की उन्नति के लिये २० करोड़ रु० खर्च करेगी। इसके अतिरिक्त सरकार को जापान से जो १० बिलियन मन का ऋण मिला था उसमें से उसने ५ बिलियन मन जापान से जहाज खरीदने के लिये रख छोड़े हैं। इस के अतिरिक्त सरकार जहाजी यातायात की ओर भी कई प्रकार से लाभ पहुँचा रही है। उसके हाल ही में एक शिपिंग कांफिडेंशन कमेटी बनाई है जो कि विभिन्न मन्त्रालयों से सूचना लेकर भारत सरकार की आवश्यकता का सब माल भारतीय जहाजों पर विदेशों से मंगायेगी। १९५८ में एक नया मर्चेंट शिपिंग बिल पास किया गया जिसके फलस्वरूप एक नेशनल शिपिंग बोर्ड स्थापित किया जायगा जो कि सरकार को उचित परामर्श देगा। परन्तु सरकार ने अपनी १९४७ वाली नीति को नहीं बदला अर्थात् तटीय व्यापार केवल उन्हीं जहाजों के लिये सुरक्षित रहेगा जिनकी ७५ प्रतिशत पूंजी भारतीयों के हाथ में होगी।

इस प्रकार तटीय व्यापार को भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित करके सरकार ने इस देश के लोगों की बहुत पुरानी माँग को पूरा कर दिया है। अब सरकार को चाहिए कि रेलों तथा जहाजों के सहयोग की नीति बनाये जिसमें कि बिना किसी हानि के तटीय व्यापार रेलों अथवा जहाजों पर सस्ते दामों पर किया जा सके। सरकार को अब यह भी चाहिये कि वह देश के लिए अधिक जहाज खरीदे। जहाँ तक हो उसे प्रयत्न करना चाहिए कि जहाज देश में ही बने। जहाज बनाने का एक कारखाना देश के लिए अपर्याप्त है। इस देश में नये बन्दरगाह भी बनाने चाहिये। प्रथम योजना में काँधला नामक नया बन्दरगाह बनाया गया है तथा वर्तमान बन्दरगाहों का आधुनीकरण किया जायगा। दूसरी योजना में बड़े बन्दरगाहों की शक्ति को ३० प्रतिशत बढ़ाया जायगा तथा बहुत से छोटे बन्दरगाहों की उन्नति किया जायगा। सरकार लाइट हाऊस को भी उन्नत करेगी तथा घीरे-घीरे उनका प्रबन्ध स्वयं ले लेगी। जहाजों को विदेशी प्रतियोगिता से किसी न किसी तरह बचाना चाहिये। इस प्रकार भारतीय जल यातायात को अधिकाधिक मजबूत बनाना चाहिये।

वायु यातायात (Air Transport)

Q. 82. Give a brief history of Indian Airways. What is their present position ?

प्रश्न ८२—भारतीय वायु यातायात का संक्षिप्त इतिहास दीजिये । उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

भारतवर्ष में वायु यातायात, दिनो-दिन उन्नति करता जा रहा है । सर्व प्रथम १९११ में भारत के विभिन्न स्थानों में वायुयानों का प्रदर्शन किया गया । प्रथम महायुद्ध के पश्चात् यह पता चल गया कि यूरोप, सुदूरपूर्व (Far East) एवं वास्ट्रेलिया को मिलाने के लिये भारत में वातायात की उन्नति करनी आवश्यक है । हाँ इस देश में प्राप्त ऋच सर्विस प्रारम्भ हुई तथा इंग्लैंड और फ्राँस के बीच साप्ताहिक सर्विस चालू की गई । इम्पायर मेल स्कीम चालू होने के पश्चात् इस देश में वायु यातायात ने खूब उन्नति की । १९३२ में टाटा वायुमार्ग लिमिटेड (Tata Airways Ltd.) द्वारा इलाहाबाद, कलकत्ता तथा कोलम्बो में अन्तर्देशीय वायु सेवाओं की स्थापना की गई ।

द्वितीय महायुद्ध में इस देश में वायु यातायात ने खूब उन्नति की । उस समय देश में जितनी वायुयान कम्पनियाँ थी वे सब देश की सुरक्षा के कार्य में लग गई । उस समय बहुत से वायुयान खरीदे गये । नवीन सेवाओं का श्रीगणेश हुआ । मगलौर में एक वायुयान बनाने का कारखाना खोला गया । देश में बहुत से हवाई अड्डे बनाये गये । इस प्रकार धीरे-धीरे करके इस देश में वायु यातायात ने खूब उन्नति कर ली है । इस प्रकार देश के प्रायः सभी बड़े बड़े शहर एक दूसरे से वायु सेवा द्वारा जुड़े हुये हैं । आजकल वायुयानों से यात्री ही नहीं वरन् बहुत सा तानान भी ले जाया जा सकता है । आजकल बड़े बड़े शहरों की डाक ले जाने का कार्य भी वायुयान के द्वारा ही किया जाता है । इस देश के लोग केवल देश के भीतर ही वायुयान सेवा नहीं करते वरन् वह विदेशों में भी यह सेवा करते हैं । १९४८ में सब से पहले वायु-भारत अन्तर्राष्ट्रीय लिमिटेड (Air-India International) ने दम्बई तथा लन्दन के बीच वायु सेवा चालू की । पूर्व की ओर भारत एयरवेज ने बिना सरकार की सहायता के हाँगकाँग तथा बैंकाक तक सेवा आरम्भ की ।

भारत सरकार भी वायु सेवा की उन्नति के लिये बहुत प्रयत्नशील है । वह हर वर्ष कई करोड़ रुपये इस कार्य के लिये व्यय करती है । सरकार ने वायुयानों को चलाने की शिक्षा के लिये इस देश में स्कूल खोल दिए हैं जिनमें बहुत से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं । ग्राउण्ड इंजीनियर्स को शिक्षा देने के लिये प्रबन्ध किया गया है । बहुत सा खर्चा उड़ाकू कप्तानों की सहायता के रूप में दिया जाता है । १९४८ में ३१२ लोगों को विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी गई तथा नवम्बर के अन्त में १७७ लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे ।

१९५३ ई० में हमारे देश में ८ भारतीय वायु-यातायात कम्पनियाँ थी जो २०,००० मील पर सेवा कर रही थी। भारत के प्रायः सभी बड़े शहर अब वायु-यातायात से जुड़े हुये हैं।

यद्यपि भारत में वायु-यातायात की इतनी उन्नति हो रही थी तो भी बहुत सी वायु कम्पनियाँ नुकसान उठा रही थी। उनकी सहायता के लिये सरकार ने उनको वायु-यातायात के लिये खरीदे हुये पेट्रोल से प्राप्त चुंगी का $\frac{1}{2}$ भाग सहायता के रूप में दिया। उनको ढाक ले जाने का काम भी दिया। इसके अतिरिक्त सरकार ने १९५१ ई० में एक हवाई यातायात जाँच समिति (Air Transport Enquiry Committee) बैठाई। इस समिति ने बताया कि वायु कम्पनियों के घाटे पर चलने का मुख्य कारण यह है कि इनकी सख्या आवश्यकता से अधिक है। इसलिये इस समिति ने वायु यातायात कम्पनियों का पुनर्संगठन करने, इनकी सख्या में कमी करने और अनुसूचित संचालकों की प्रमाणित लागत व वास्तविक आय के अन्तर के बराबर अर्थ सहायता देने की योजना का सुझाव दिया।

वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण—

१९५३ ई० में एयर कार्पोरेशन एक्ट पास किया गया जिसके अनुसार सरकार ने दो एयर कार्पोरेशन स्थापित किये—(१) इण्डियन एयर लाइन कार्पोरेशन और (२) एयर इण्डिया इन्टरनेशनल। इनमें से पहले ने सब देशी लाइनों को अपने अधिकार में लिया है और दूसरे ने विदेशी लाइनों को। सरकार इन दोनों कार्पोरेशनों के अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त करेगी। ये कार्पोरेशन सरकार को अपने कार्य करने का वार्षिक प्रोग्राम देगी तथा यह भी बतायेंगी कि वय भर में कितना धन खर्च होने का अनुमान है। सरकार राष्ट्रीय हित में इन कार्पोरेशनों को कोई भी आज्ञा दे सकती है। इन दोनों कार्पोरेशनों के कार्य में सम्बन्ध स्थापित करने के लिये सरकार ने एक वायु-यातायात सभा (Air Transport Council) भी स्थापित की है।

सरकार निजी कम्पनियों को ४८ करोड़ रु० क्षतिपूर्ति के रूप में देगी। इनमें से ४८ लाख रु० नकद मिलेंगे तथा शेष के लिये $\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज के प्रतिज्ञापत्र (Bonds) लिये जायेंगे जिनका धन पाँच वर्ष पश्चात् चुकाया जायगा। ३० जून १९५२ को कम्पनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को सरकार रख लेगी।

वायु-यातायात के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न में तर्क—

वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण निम्नलिखित बातों के कारण उचित कहा जा सकता है—

(१) निजी कम्पनियाँ घाटे पर चल रही थी और शीघ्र ही वे बन्द हो जाती।

(२) देश की रक्षा के हित के लिये सरकार को वायु यातायात को अपने हाथ में लेना चाहिये था।

(३) वायु-यातायात के नवीनीकरण (Modernisation) के लिये जितने व्यय की आवश्यकता है वह निजी पूंजीपतियों की शक्ति के बाहर की बात थी ।

(४) राष्ट्रीयकरण के कारण आन्तरिक प्रतियोगिता समाप्त हो गई और इसके फलस्वरूप खर्च भी कम हो गया ।

राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध केवल गृही बात कही जा सकती है कि सरकारी काम बहुत धीमा चला करता है और उसमें निजी लाभ की आशा न होने के कारण उतना अच्छा काम नहीं होता जितना कि निजी उद्योग में होता है । परन्तु हम देखते हैं कि सरकार रेलों को वही अच्छी प्रकार चला रही है और उसको खूब लाभ भी होता है ।

प्रथम पंचतर्षीय योजना में निजी उद्योगों की क्षति-पूर्ति देने तथा नये हवाई जहाज खरीदने के लिये १५ करोड़ २० लाख रुपये थे तथा १००७ करोड़ रुपये नये हवाई अड्डे बनाने तथा पुरानों की मरम्मत करने के लिये रखे गये थे । परन्तु योजना काल में लगभग ८ करोड़ २० लाख किये गये । दूसरी योजना में जो कार्य किये जायेंगे उन पर १८ करोड़ २० लाख होने की आशा है परन्तु योजना में केवल १२.५ करोड़ २० लाख रुपये हैं । प्रथम योजना में ६ हवाई अड्डे बनवाये गये । दो और शीघ्र ही पूरे होने वाले हैं । दूसरी योजना में ८ नये अड्डे बनाये जायेंगे । हवाई जहाज की ट्रेनिंग का केन्द्रीकरण करने का भी निश्चय किया गया है । यह इलाहाबाद में होगी । दूसरी योजना में १० नये ग्लाइडिंग केन्द्र तथा ५ नये उड़ाकू क्लब स्थापित किये जायेंगे ।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् की गई उन्नति—

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् भारत में वायु यातायात में बहुत उन्नति की जिस के फलस्वरूप आज हमारे देश के प्रायः सभी मुख्य-मुख्य नगर हवाई सविन से जुड़े हुये हैं । देश के भीतर हवाई रास्ते की लम्बाई १६६८५ मील है । विदेशों में हमारे हवाई जहाज १५ देशों में काम करते हैं और इस रास्ते की लम्बाई २३,४८३ मील है । भारत ने बहुत से देशों से हवाई यातायात के समझौते भी किये हैं । इन देशों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इराक, जापान, अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, लवा, मिस्र, फास, पाकिस्तान, फिलिपाइन, स्वीडन, स्वीट्जरलैंड, संयुक्त राज्य आदि हैं । इनके अतिरिक्त ईरान, नावे, डेनमार्क, स्वीडन, थाइलैंड, ब्रह्मा, नेपाल, इटली, पश्चिमी जर्मनी आदि देशों से भी कार्य करने के अस्थायी प्रबन्ध हैं ।

भारतीय हवाई यातायात की उन्नति इस बात से समझी जा सकती है कि जहाँ १६४० ई० में हवाई यातायात न ६३६२ हजार मील की यात्रा की, २५५ हजार यात्रियों को उड़ाया, ५६४८ हजार पौंड सागान तथा १४०५ हजार पौंड डाक को ले गई वहाँ १६५८ में इसने २४०८६ हजार मील तथा किये, ६८३ हजार यात्री उड़ाये तथा

६८,४६४ हजार पौंड सामान व १३,१८० हजार पौंड डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का प्रयत्न किया ।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् वायु सर्विस ने कई प्रकार से उन्नति की है । सर्विस अब पहले से अच्छी हो गई है । बहुत से जहाज जो खराब हो गये थे उनकी मरम्मत हो गई है । बुकिंग के दफ्तरो को फिर से ठीक किया गया है । यात्रियों को काश्मीर जाने की सुविधा दी जाती है । डाक को रात में ले जाने का प्रबन्ध किया गया है ।



१६

भारतवर्ष का विदेशी व्यापार

Q 83—Give the development of India's foreign trade after the middle of the 19th century. What, in your opinion, is going to be nature and direction of India's foreign trade in the immediate future ?

प्रश्न ८३—१९वीं शताब्दी के मध्य के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार की उन्नति बताइये। आपकी राय में निश्चय भविष्य में भारत के विदेशी व्यापार की रूप-रेखा क्या होने वाली है ?

प्राचीन काल में भारतवर्ष के व्यापारिक सम्बन्ध मध्य, रोम, अरब, फारस, चीन तथा प्रशान्त महासागर के अन्य द्वीपों के साथ थे। भारत से बड़िया सूती कपड़े तथा अन्य बहुमूल्य सामग्रियाँ, सुन्दर बर्तन, इत्र आदि निर्यात किया जाता था। इसके बदले भारत में विदेशों से घोड़े, शराब, मोती आदि आते थे। मुसलमानों के समय बहुत सी फसल की चीजें विदेशों को भेजी जाती थी तथा सोना, चाँदी, रत्न, बहुमूल्य पत्थर आदि बाहर से आते थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में भी इस देश से बड़िया सामान विदेशों को भेजा जाता था। परन्तु एंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के पश्चात् भारतवर्ष के विदेशी व्यापार की रूप-रेखा बदल गई। इसके पश्चात् भारतवर्ष से कच्चा माल विदेशों को भेजा जाने लगा तथा विदेशों का पक्का माल इस देश में आने लगा।

१८६६ में स्वेज नहर खुली। इसके पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार में बहुत उन्नति की। १८६४-६५ में भारत का वार्षिक निर्यात ५६ करोड़ रुपये था। १८२८-२९ में यह बढ़कर ३५३.३१ करोड़ रुपये हो गया। इसी बीच में भारत का आयात ३१ करोड़ रुपये से बढ़कर २५१ करोड़ हो गया। इस बीच में भारत के निर्यात में चाय, साबुनी, चाय, कपास, जूट, तेल निर्यात के बीच, खालें आदि सम्मिलित थे। इसके विपरीत आयात में सूती कपड़ा, मशीन, रेल का सामान, रंग आदि सम्मिलित थे। इस बीच में भारतवर्ष अन्तर्गत व्यापार (Free Trade) की नीति पर चल रहा था।

१९वीं शताब्दी के अन्त में इस देश के व्यापारिक सम्बन्ध जापान तथा जर्मनी से भी बढ़ने लगे। इन देशों ने अपने व्यापार को अधिक सहायता पहुँचाने के लिये इस देश में वेतों की माँग की थी।

२०वीं शताब्दी के आरम्भ में इस देश का विदेशी व्यापार बड़ी तेजी से बढ़ा क्योंकि उस समय इस देश में रुपये की दर स्थायी रही तथा देश में अकाल

जैसी कोई आपत्ति नहीं आई। युद्ध काल में इस देश का आयात तथा निर्यात दोनों कम हो गये।

आयात तथा निर्यात में कमी होने के बहुत से कारण थे। उनमें जहाजों के मिलने की कठिनाई, विदेशी विनिमय मिलने की कठिनाई, शत्रु देशों से व्यापार का बन्द हो जाना, व्यापार पर बहुत सी पाबन्दियाँ आदि का होना मुख्य कारण थे।

युद्ध के पश्चात् व्यापार पर से युद्ध काल की बहुत सी पाबन्दियों को हटा लिया गया। यूरोप के देश अपने उद्योगों का पुनर्निर्माण कर रहे थे। इस कारण उनको भारत से बहुत सा सामान खरीदने की आवश्यकता हुई। पर उनके पास क्रय शक्ति की कमी होने के कारण वे अधिक माल न खरीद सके। इससे भारत सरकार ने रुपये की दर २ शिलिंग (स्वर्ण) कर दी। इस कारण भारत के लोगों को यूरोप से माल खरीदने में बहुत प्रोत्साहन मिला। उन्होंने बहुत सा माल खरीदने के लिए आर्डर दिये। इस कारण १९२०-२१ में भारत का व्यापारिक सन्तुलन (Balance of Trade) ८० करोड़ रु० से उसके विरुद्ध हो गया। १९२१-२३ तक यूरोप की मुद्रा स्थायी हो गई। इस कारण यूरोप के देशों ने बहुत सा माल भारत-वर्ष से खरीदा और इस प्रकार व्यापारिक सन्तुलन फिर ७० करोड़ रुपये से भारत-वर्ष के पक्ष में हो गया।

१९२६ के पश्चात् सत्तार में मंदी का युग आ गया। इस कारण भारतवर्ष के कच्चे माल के दाम बहुत तेजी से गिरने लगे। इसके फलस्वरूप भारतवर्ष को १९३०-३५ के बीच ३८२ करोड़ रुपये का सोना बाहर भेजना पड़ा। १९३४ के पश्चात् मूल्य धीरे-धीरे बढ़ने लगे। इसी बीच बहुत से देशों ने अपनी मुद्राओं का मूल्य कम कर दिया। इस प्रकार उन्होंने विदेशी व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न किया। मन्दी काल तथा उसके पश्चात् प्रायः सभी देशों ने व्यापारिक समझौतों (Trade Agreements) द्वारा अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न किया। भारत ने इस प्रकार के व्यापारिक समझौते ब्रिगलैंड तथा जापान से किये। इस प्रकार भारत का व्यापारिक सन्तुलन जो १९३२-३३ में ३ करोड़ रह गया था, बढ़कर १९३६-३७ में ७८ करोड़ रुपये हो गया।

द्वितीय महायुद्ध का प्रभाव— १९३६ ई० में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया जिसके फलस्वरूप व्यापार पर सरकार की नियन्त्रण करना पड़ा। युद्धकाल में भारत ने युद्ध क्षेत्रों में खाद्य आदि अनेक प्रकार की चीजें भेजी। इसके अतिरिक्त एशिया के उन देशों को तैयार माल भी भेजना पड़ा जो युद्ध से पहले जापान तथा जर्मनी से माल खरीदा करते थे। इसी कारण भारत से ईरान, ईराक, मिश्र आदि देशों को चीनी बहुत अधिक भेजी गई। भारत का व्यापार संयुक्त राष्ट्र अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, मिस्र आदि देशों से बढ़ने लगा। इस प्रकार भारत से अत्यधिक निर्यात किये गये तथा आयात बहुत घट गये। इस प्रकार भारत का निर्यात जो १९३८ में १६८.५ करोड़ रुपया था वह बढ़कर १९४१ में २४.० करोड़ रुपया

हो गया। उसके पश्चात् निर्यात में कुछ कमी आ गई और वह १९४३ में १९६६.३१ करोड़ रुपये रह गया परन्तु इसके पश्चात् १९४५ ई० में वह फिर बढ़कर २३६.२ करोड़ रुपये हो गया। इसके फलस्वरूप हमारा व्यापारिक आधिव्य (Balance of Trade) जो १९३८ ई० में केवल १५.१ करोड़ रुपये था वह बढ़कर १९४४ में ५३.१ करोड़ रुपये हो गया।

युद्ध के फलस्वरूप हमारी आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में भी परिवर्तन हो गया। युद्ध के पूर्व तक हमारे देश से अधिकतर कच्चा माल व खाद्य सामग्री बाहर को भेजे जाते थे तथा पक्का माल बाहर से मंगाया जाता था। परन्तु युद्ध के फलस्वरूप निर्यात में कच्चे माल का अनुपात घटने लगा। इसके विपरीत हमारे देश में अधिक मात्रा में पक्का माल बाहर को भेजा जाने लगा तथा कम मात्रा में पक्का माल बाहर से आने लगा।

युद्ध का एक प्रभाव और भी व्यापार पर पड़ा। युद्ध से पूर्व तक हमारे देश का बहुत सा व्यापार जर्मनी व जापान से होता था। परन्तु युद्ध में इन देशों को शत्रु घोषित करने के कारण इनसे हमारे व्यापारिक सम्बन्ध साम्राज्य के देशों तथा संयुक्त राष्ट्र अमरीका से बढ़ने लगे।

विभाजन का प्रभाव—युद्ध के पश्चात् १९४७ ई० में देश का विभाजन हो गया। विभाजन के फलस्वरूप हमारे विदेशी व्यापार की रूप-रेखा ही बदल गई। पाकिस्तान बनने से पूर्व भारतवर्ष जूट, रुई, तैल निकालने के बीज आदि पर्याप्त मात्रा में विदेशों में भेजा करता था परन्तु पाकिस्तान बनने पर इन वस्तुओं का उगाने वाला अधिकतर क्षेत्र पाकिस्तान के अधिकार में चला गया और भारत को इन चीजों का आयात पाकिस्तान तथा अन्य देशों से करना पड़ा। इस कारण भारत का विपरीत व्यापारिक आधिव्य जो १९४६-४७ में १४८ करोड़ व १९४७-४८ में ३७.१ करोड़ था वह बढ़कर १९४८-४९ में २१६.२ करोड़ रुपये हो गया।

भारत ने इस स्थिति पर काबू पाने के लिए एकदम कदम उठाया। पहले जहाँ निर्यात पर कन्ट्रोल था वहाँ सरकार ने निर्यात की प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई। आयात को कम किया गया। इसके साथ-साथ आवश्यक कच्चे माल की उत्पात्ति बढ़ाने का प्रयत्न किया गया।

बहुत से देशों से व्यापारिक समझौते किये गये। इन देशों में स्वीट्जरलैंड, हंगरी, पोलैंड, फिनलैंड, मिश्र, ईराक, अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, ब्रह्मा, पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रिया, इण्डोनेसिया तथा जापान सम्मिलित थे। इन समझौतों के कारण भारत को अख्त्यारी कागज, रूई वस्तुएँ तथा दूसरा और आवश्यक सामान प्राप्त हो गया। इन सब बातों के कारण भारत का विपरीत आधिव्य घटकर १९४८-४९ में १३२.७ करोड़ हो गया।

रुपये के अवमूल्यन का प्रभाव—१७ दिसम्बर १९४९ ई० में इंग्लैंड में पौंड स्टर्लिंग का अवमूल्यन कर दिया। भारत ने भी इंग्लैंड का अनुकरण किया और

१६ सितम्बर १९४६ को रुपये का अवमूल्यन कर दिया। हमारा रुपया जो पहले ३०.५ सेन्ट के बराबर था वह २१ सेन्ट के बराबर कर दिया गया। रुपये का अवमूल्यन करते समय भारत को यह आशा थी कि पाकिस्तान भी अपने रुपये का अवमूल्यन करेगा परन्तु पाकिस्तान ने ऐसा न किया। इसके फलस्वरूप पाकिस्तान के साथ व्यापार करने में कठिनाई बढ़ने लगी। लगभग एक वर्ष तक भारत का-पाकिस्तान से व्यापार बन्द रहा। परन्तु इसके पश्चात् जब कोरिया युद्ध छिड़ गया और हमको अमरीका आदि से सामान भेजाने में कठिनाई पड़ने लगी तब फिर पाकिस्तान से हमारा व्यापार चालू हुआ।

रुपये के अवमूल्यन से हमको यह आशा थी कि हमारे व्यापारिक आधिक्य की स्थिति में बहुत कुछ सुधार हो जायगा और विशेषतः हमारा व्यापार अमरीका से बढ़ जायगा और हुआ भी ऐसे ही क्योंकि अक्टूबर १९४६ व नवम्बर १९५० में भारत की निर्यात ६११.३ करोड़ रुपये थी जो कि १९४८-४९ से २७.४५ प्रतिशत अधिक थी।

इसी प्रकार आलर क्षेत्र को हमारी निर्यात ११४.७ करोड़ रुपये से बढ़कर १५०.८ करोड़ रुपये हो गई। दूसरे दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों को भी हमारी निर्यात २३ प्रतिशत बढ़ गई। अवमूल्यन के पश्चात् के १४ महीनों भारत की निर्यात मुलभूत गुद्रा क्षेत्रों को ४६०.४७ करोड़ रुपये हो गई जो कि इसके पहले वर्ष के उन्ही महीनों की निर्यात से २६ प्रतिशत अधिक थी। इसके फलस्वरूप हमारा विपरीत व्यापारिक आधिक्य जो अवमूल्यन से पूर्व २३२ करोड़ था वह अवमूल्यन के पश्चात् घटकर केवल ५.४ करोड़ रुपये रह गया।

विभाजन के पश्चात् सबसे पहले १९५०-५१ ई० में हमारा व्यापारिक आधिक्य ४०.२७ करोड़ रुपये से हमारे पक्ष में था। इसके पश्चात् के ३ वर्षों में हमारा व्यापार कुछ घट गया परन्तु १९५४ के पश्चात् यह फिर बढ़ा। जबकि १९५७-५८ में हमारे व्यापार का कुल मूल्य १५६४.६२ करोड़ रुपये था। १९५४-५५ ई० में वह १२४६.८० करोड़ तथा १९५३-५४ में वह ११०२.५५ करोड़ रुपया था।

१९५१-५२ से हमारे व्यापारिक आधिक्य की स्थिति इस प्रकार थी:—

करोड़ रुपये में

१९५१-५२	२१०.१४
१९५२-५३	६२.५१
१९५३-५४	४१.३१
१९५४-५५	६२.७२
१९५५-५६	६५.४०
१९५६-५७	२१६.६३
१९५७-५८	२८६.७६

इस काल में हमारे देश में गन्ने का आयात गिरा तथा औद्योगिक कच्चे माल का बढ़ा। इससे आन्तरिक उत्पत्ति बढ़ने लगी। देश में उत्पन्न होने वाली चीजों के आयात पर कड़ाई कर दी गई तथा आवश्यक वस्तुओं के आयात पर से कड़ाई कम कर दी गई।

इस बीच में हमारे देश के निर्यात बड़े। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सुतली, जूट का सामान, चाय तथा रुई का सामान आदि थे। हाल ही में वनस्पति तेल, कपास तथा चीलास के निर्यात बढ़ रहे हैं।

व्यापारिक नीति—१९५५-५६ ई० में भारत की आयात नीति सन्तुलित परन्तु नियंत्रित उदारता की रही है। इस नीति का उद्देश्य देश की आर्थिक उन्नति के लिये आवश्यक चीजों का आयात करना था। डालर क्षेत्र से आने वाली वस्तुओं के आयात को कुछ बढ़ा दिया गया। विदेशी विनिमय को बचाने के लिये कुछ चीजें जिनका उत्पादन देश में बढ़ रहा था, का आयात कम कर दिया गया। निर्यात को बढ़ावा देने के लिये (Export Promotion Councils) स्थापित की गईं। कुछ चीजों जैसे कपास, जूट का सामान, मूंगफली का तेल व खली, क्रोम धातु आदि पर या तो निर्यात कर को कम कर दिया गया या उसको समाप्त कर दिया गया। ऊन, छोटे रेशे की कपास, मूंगफली व उसका तेल और चाय के लिये कुछ अतिरिक्त कोटे प्रदान किये गये।

१९५६ ई० में बहुत अधिक आयात होने व निर्यात में कमी होने के कारण देश के विदेशी विनिमय के साधन बहुत कम हो गये जिसके कारण १९५७ ई० के पहले ६ महीनों में साधारणतः कम आवश्यक चीजों के आयात को बहुत कम कर दिया गया है तथा उदारता से लाइसेंस देने व नये आदमियों को लाइसेंस देने भी बन्द कर दिये गये हैं। इस प्रकार ५०६ चीजों के आयात कोटे को कम कर दिया गया। इन चीजों में फल, मसाले, शराब, सुपारी, सिग्रेट, तेल, साबुन, ऊनी सामान, सूती व रेशमी सामान, साइकिल आदि सम्मिलित हैं। वे चीजें जो देश में उत्पन्न होती हैं उनकी आयात में कटौती की गई है। सुलभ मुद्रा तथा दुर्लभ मुद्रा दोनों का भेदभाव कम कर दिया गया और आयात कर्तव्यों को यह छूट दी गई कि वे अपने कोटे का कम से कम १० प्रतिशत दुर्लभ मुद्रा क्षेत्रों से खरीद लें। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये Export Promotion Scheme में कुछ नई चीजें सम्मिलित की गईं।

१९५७ के अगले ६ माह की नीति में भी उदारता से लाइसेंस न देने की नीति को कायम रखा गया है तथा १५० चीजों को आयात को बिल्कुल बन्द कर दिया गया है। इनमें हजामत बनाने के ब्लेड, तम्बाकू का सामान, ऊनी कपड़ा, पड़ियाँ, साइकिल, फाउन्टेनपेन, क्रोकररी, काँच का सामान, कटलरी इन, नाबुन, तेल, बाजे, शराब आदि सम्मिलित हैं। दूध का भोजन, मसाले, सुपारी आदि बहुत कम मात्रा में आ सकेंगे। इसके विपरीत उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये आवश्यक कच्चे माल का आयात बढ़ाया जायगा तथा मशीनों के हिस्से भी उदारता से आयात

किये जायेंगे। परन्तु कोटे यहाँ भी बहुत कम कर दिये गये हैं। यह सब विदेशी विनिमय को बचाने के लिये किया गया है।

मार्च १९५८ ई० में अगले ६ महीनों के लिये जो नीति घोषित की गई है उसमें से उस कच्चे माल के आयात को प्रोत्साहन दिया जायगा जो कि हमारे उद्योगों के लिये आवश्यक है। इसके अतिरिक्त शेष चीजों के आयात को और भी कम कर दिया गया है क्योंकि ये चीजें भारत में ही बनने लगी हैं। कच्चे माल के अतिरिक्त खेती के ट्रैक्टर तथा छापने की मशीनें भी आयात की जायेंगी। पाकिस्तान से आने वाले फल, दूध, मछली आदि के आयात को बहुत बड़ी सीमा तक कम कर दिया है। ब्लेड, घड़ियाँ आदि बिल्कुल भी नहीं मँगवाई जाएंगी।

अक्टूबर १९५८ से मार्च १९५९ तक के ६ महीनों के लिये यह निश्चित किया गया कि निर्यात करने वाली टेक्सटाइल मिलों को उन की विदेशी विनिमय की आय के एक निश्चित प्रतिशत तक रंग तथा कैमीकल आयात करने की आज्ञा दी जाय। उन को कुछ शर्तों के अन्तर्गत आधुनिक मशीनें आयात करने की भी आज्ञा दी जायगी।

कुछ चीजें जैसे बाल बियरिंग, बिजली के मोटर, स्टार्टर जो देश में ही पैदा होते हैं उन के कोटे घटा दिया गये। टेक्सटाइल रंग तथा कैमीकल के कोटों को भी घटा दिया गया। काफूर का कोटा समाप्त कर दिया गया तथा सुपारी और लॉग का कोटा कम कर दिया गया। परन्तु कुछ औजारों, कैमीकल आदि के कोटे बड़ा दिये गये। कुछ चीजों जैसे लपेटने का कागज, बनावटी रेशम का घागा आदि के छोटे छोटे कोटे दिये गये तथा बच्चों के दूध, घड़ियाँ, फोटोग्राफ के सामान, एक्स-रे, फिल्म आदि के कोटे में उदारता की गई।

निर्यात को प्रोत्साहन—निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने सूती कपड़े, रेशम तथा रेयन कपड़े, प्लास्टिक, इजीनियरिंग का सामान काजू तथा मिर्च, तम्बाकू तथा चमड़े आदि के लिये (Export promotion Council) स्थापित की। ये सब कौंसिल निर्यात को प्रोत्साहन देने में प्रयत्नशील हैं। उन्होंने विदेशों में भारतीय सामान के लिये बाजार ढूँढने का प्रयत्न किया है तथा यह बात जानने का प्रयत्न किया है कि भारतीय सामान का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या काम करना चाहिये।

निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा उसको विभिन्न दिशाओं में फैलाने के लिये विदेशी व्यापार बोर्ड का फिर से गठन किया गया है। इस बोर्ड के सर्वोच्च अधिकारी विदेशी व्यापार के डाइरेक्टर जनरल होंगे। डाइरेक्टर जनरल को उसके काम में सहायता देने के लिये एक (Directorate of Export promotion) स्थापित किया गया है। इसका कार्य यह होगा कि यह उद्योग तथा निर्यात करने वालों के साथ सम्बन्ध स्थापित करे तथा उनकी कठिनाई को जानकर उनको हल करने का प्रयत्न करे। बम्बई में एक (Liasion Unit) स्थापित की गई है जो एक विशेष अधिकारी

के नीचे होगी। इसका कार्य जहाजी कम्पनियों से सम्बन्ध स्थापित करके निर्यात करने वाली की कठिनाइयों को दूर करना होगा। इसके अतिरिक्त बम्बई, कलकत्ता तथा बम्बई के बन्दरगाहों पर निर्यात प्रोत्साहन सलाहकार समितियाँ भी स्थापित की हैं। इन समितियों में तजुर्बेकार व्यापारी होते हैं। इन समितियों का कार्य यह होगा कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में यह खोज करें कि वे और कौन सी चीजें हैं जिनके निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

निर्यात साख गारण्टी समिति की रिपोर्ट में दिये गये सुझाव के अनुसार सरकार ने सितम्बर १९५७ ई० में एक Export Risks Insurance Corporation स्थापित की है जो कि उन खतरो का बीमा करेगी जिनका बीमा साधारणतः बीमा कम्पनियाँ नहीं करती। २८ फरवरी १९५८ ई० तक इस कार्पोरेशन ने १३२९४ लाख की ६८ पालिसी जारी की हैं।

इन सब के अतिरिक्त सरकार निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये बहुत सी चीजों के निर्यात पर स बन्दोल ढीला करती जा रही है। १९५७ ई० में बहुत सी चीजों के निर्यात पर स बन्दोल हटा लिया गया है। इसके अतिरिक्त चीनी, चावल की भूसी, तौड़े की चादरें, सूखी मिर्चें आदि जो पहले बाहर नहीं भेजी जा सकती थी उन को अब कोटे के अनुसार निर्यात किया जा सकता है। परन्तु कुछ आवश्यक वस्तुओं का जिनमें चावल, ज्वार, दालें, गेहूँ का सामान आदि सम्मिलित हैं, निर्यात नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त घरेलू माँग को पूरा करने के लिये मूँगफली तिल आदि तेलों का भी निर्यात बर्जित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त निर्यात पर लगाये जाने वाले करों में भी परिवर्तन कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप अब यह कहा जा सकता है कि आयात कर अथवा उत्पादन-कर के कारण निर्यात करने में कोई बाधा खड़ी नहीं होती। अब यह प्रयत्न किया जा रहा है कि व्यापारियों को वह सब कच्चा माल मिले जो कि निर्यात करने-वाले उद्योग को चलाने में सहायता देता है।

इसके अतिरिक्त निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये भारत अब विदेशों में होने वाली प्रदर्शनियों में अधिकाधिक भाग लेता जा रहा है। इस प्रकार भारत ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पोलैंड, जापान, सीरिया आदि देशों में होने वाली प्रदर्शनियों में भाग लिया तथा पेरिस (चीन) और खारतूम (सूडान) में तो केवल भारतीय प्रदर्शनियाँ ही की गईं। इनसे भारतीय सामान विदेशों में प्रसिद्ध होता जा रहा है।

इसके अतिरिक्त बहुत से व्यापारिक समझौते भी किये गये तथा जिन देशों के समझौते समाप्त हो गये थे उनको फिर से चालू किया गया। इस प्रकार भारत ने २४ देशों से व्यापारिक समझौते किये। इन देशों में अफगानिस्तान, आस्ट्रेलिया, बसगारिया, ब्रह्मा, लका, चीनी, चीन, मिस्र, पाकिस्तान, पश्चिमी जर्मनी, इटली, इराक, नाबो, पोलैंड, रूस आदि देश सम्मिलित हैं।

इसके अतिरिक्त हमारे देश के बहुत से व्यापारिक डेलिगेशन विदेशों में गये।

इसमें पश्चिमी जर्मनी, पाकिस्तान मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, बर्मा, लका आदि के ट्रेड डेलिगेशन हमारे देश में आये और व्यापार की सम्भावना के विषय में बातचीत की।

इस प्रकार हमारे देश में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये बड़ा प्रयत्न किया जा रहा है। १ जुलाई १९५८ ई० की एक सूचना के अनुसार वाणिज्य तथा व्यापार मन्त्रालय नई-नई चीजों के निर्यात को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न कर रहा है। इनमें से कृषि पदार्थों का निर्यात मुख्य है। इन पदार्थों में चीनी, तेल निकालने के बीज तथा तेल आदि मुख्य हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका निर्यात अभी कम है परन्तु उसको बढ़ाया जा सकता है। इन चीजों में चमड़ा व खालें, सिरा, जूते, मछली, मांस, फल व तरकारी तथा अल्कोहल आदि का निर्यात अभी तक कम है परन्तु उसको बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बिजली के पम्पे, बिजली की मोटर, सीने की मशीन, आदि अधिक संख्या में भेजी जा रही हैं और उनका निर्यात और भी बढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त टेक्सटाइल, चाय तथा जूट के लिये भी नये-नये बाजार खोजे जा रहे हैं।

व्यापारिक आधिव्यय—

१९५१-५२ तथा १९५५-५६ के बीच हमारी व्यापारिक आधिव्यय की स्थिति निम्नलिखित थी—

करोड़ रुपये में

	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	१९५४-५५	१९५५-५६
आयात	६४३.१३	६६६.८८	५७१.६३	६५६.२६	७०४.८१
निर्यात	७३२.६६	५७७.३७	५३०.६२	५६३.५४	६०६.४१
आधिव्यय	-२१०.१४	-६२.५१	-४१.३१	-६२.७२	-६५.४०

१९५७ ई० में हमारा विदेशी व्यापार १९५६ ई० की अपेक्षा २० प्रतिशत बढ़ गया क्योंकि हमारे देश में पूँजी-वस्तुओं तथा कच्चे माल का आयात बहुत बढ़ गया। १९५६-५७ में हमारी आयात ८३२.४५ करोड़ रु० तथा निर्यात ६१२.५२ करोड़ रु० तक पहुँच गये। इस प्रकार विपक्षी व्यापारिक आधिव्यय २१६.६३ करोड़ रु० हो गया। १९५७-५८ में हमारे आयात ६२७.१६ करोड़ रु० तथा निर्यात ६३७.४३ करोड़ रु० थे तथा विपक्षी व्यापारिक आधिव्यय २८६.७७ करोड़ रु० था।

व्यापारिक ढाँचा—१९५७ ई० में हमारा व्यापारिक ढाँचा निम्नलिखित ढग पर था—

आयात—लोहे व फीलाद का सामान, मशीनें, यातायात का सामान, पेट्रोल तथा अन्य बिकनाई, कपास कुछ Non-ferrous धातु, रासायनिक पदार्थ, फल तथा तरकारी, खाने का सामान, रंगने का सामान व रंग, कागज तथा कागज बनाने का सामान, ऊन, जूट तथा अन्य सामान।

इस प्रकार हम देखते हैं कि १९५७ में हमारी आयात में मशीनों, यातायात का सामान तथा कच्चा माल अधिक था। यह सामान द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बिन्दुओं को पूरा करने के लिए आवश्यक था।

निर्यात—जूट का सामान, चाय, सूती कपड़ा, मैंगनीज धातु, कच्चा लोहा, चमड़ा व चमड़े का सामान, कपास व रद्दी रुई, वनस्पति तेल, तम्बाकू, मसाले, काजू, अन्नक, लाख व गोद, छालें, कहुवा, नारियल की रस्सियाँ व अन्य सामान।

यद्यपि भारत में आयात की अपेक्षा निर्यात बहुत कम बड़े परन्तु फिर भी पिछले वर्षों की अपेक्षा निर्यात कुछ अवश्य बड़े हैं। इससे भविष्य में आशा बड़ी है। कोरिया के युद्ध के पश्चात् हमारे निर्यात लगभग सामान्य से रहे हैं परन्तु १९५७ ई० में वे काफी बड़े हैं। १९५७ के पहले १० महीनों में चीनी का निर्यात १२ करोड़, मैंगनीज का १० करोड़, सूती कपड़े का ६ करोड़ जूट की रस्सियों का ७ करोड़ बड़े गया है परन्तु इसके विपरीत, चाय, कपास तथा वनस्पति तेल आदि की निर्यात पहले की अपेक्षा घट गई है।

व्यापार की दशा—

यद्यपि हमारा अधिकतर व्यापार अब भी संयुक्त राज्य (U K) से होता है तो भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी आदि से व्यापार बढ़ता जा रहा है। जहाँ संयुक्त राज्य से १९५६ में हमने २०८ करोड़ रु० का सामान आयात किया वहीं १९५७ में २३८१० करोड़ रुपये का सामान मंगाया। इसके विपरीत उसी काल में हमारे निर्यात १८७ करोड़ रु० से घटकर १६० करोड़ रुपये रह गये। इसके विपरीत इसी काल में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को हमारे निर्यात ८६८० करोड़ रुपये से बढ़कर १३१३६ करोड़ रु० हो गये। तथा आयात ६४२१ करोड़ रु० से बढ़कर १७०३२ करोड़ रु० हो गये। इसी बीच पश्चिमी जर्मनी से हमारे आयात ८१८२ करोड़ रु० से बढ़कर १२२८२ करोड़ रु० हो गये तथा निर्यात १५ करोड़ से बढ़कर १६ करोड़ रु० हो गये। रूस को जहाँ १९५१ ई० में हमने केवल २४७ करोड़ रु० का माल भेजा वहीं १९५७ ई० में १७४८ करोड़ रुपये का सामान भेजा गया। इसी बीच रूस से हमारी आयात १४६१ करोड़ रु० से बढ़कर २२६८ करोड़ रु० हो गये। इसके अतिरिक्त चीन, जेकोसलेवेकिया, पोलैंड, रूमानिया, यूगोस्लेविया आदि की साथ हमारा व्यापार बढ़ता जा रहा है।

दूसरी योजना में विदेशी व्यापार—

यह सब अनुमान १९५५ के पहले ६ महीनों के मूल्या पर आधारित है। इस तालिका के देखने से पता चलता है कि योजनाकाल में हमारे निर्यात बहुत कम बढ़ने वाले हैं। इसका कारण यह है कि १९५५ में हमारे देश से तेल व कपास का निर्यात अधिक था जो कि योजनाकाल में कम बढेगा।

दूसरी योजना में हमारे देश के व्यापार की स्थिति निम्नलिखित ढंग से होने की आशा है—

निर्यात

	१९५५	१९६०-६१	योजना का वार्षिक औसत	पञ्च वर्षीय योग
चाय	११२	१३३	१२७	६३५
जूट का सामान	१२६	११८	१२२	६१०
सूती सामान	६३	८४	७५	३७५
तेल	३६	२४	२२	११०
तम्बाकू	११	१७	१५	७५
खालें व चमड़ा	२७	२८	२८	१४०
कपास	३५	२२	२२	११०
कच्ची धातु व बेकार लोहा व स्पात	२०	२७	२३	११५
कोयला	४	३	५	२५
रासायनिक द्रवाइयाँ	४	५	५	२५
बिजली, लोहे के भाग व मशीनें	४	४	४	२०
अन्य	१५१	१५१	१४५	७२५
	५६६	६१५	५६३	२६६५

उपयुक्त तालिका के देखने से पता चलता है कि भारत के निर्यात में चाय, जूट का सामान व रुई का सामान मुख्य हैं जिनका मूल्य कुल का आधा है। हमारे देश की मुख्य निर्यात वस्तुओं को भविष्य में बड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। इसके कारण हमारे निर्यात कम होंगे। भारत के निर्यात तभी बढ़ने की आशा है जबकि उद्योगों की उन्नति के कारण हमारे देश से बहुत सा सामान विदेशों को भेजा जायेगा।

आयात

इस प्रकार हम देखते हैं कि निकट भविष्य में हमारे देश में विदेशों से मशीनें, गाडियाँ, लोहे व इस्पात का सामान आदि मँगाये जायेंगे। योजनाकास की कुल आयात में से १५०० करोड़ रुपये की मशीनें व गाडियाँ मँगवाई जायेंगी। ४२५ करोड़ रुपये का यातायात का सामान आयेगा जिसमें से २६० करोड़ का सामान रेलों के लिये होगा। २६० करोड़ रुपये का सामान उद्योगों के लिये मँगाया जायेगा। इसमें से १८० करोड़ रुपये का इस्पात प्लान्ट होगा। १७० करोड़ का सामान सिंचाई व शक्ति की योजनाओं के लिये होगा तथा १६५ करोड़ रुपये का सामान सरकारी कारों

योजनाकाल के आयात का ढाँचा निम्नलिखित होने की आशा है—

आयात

	१९५५	१९६०-६१	योजना का वार्षिक औसत	५ वर्ष का योग
मशीनें व गाड़ियाँ	१५६	२५०	३००	१५००
लोहा व इस्पात	५०	६०	८६	४३०
अन्य धातुएँ	२५	४०	४४	२२०
गन्ना, दालें व आटा	३५	४०	४८	२४०
चीनी	२०	७	७	३५
तेल	६३	६०	८२	४१०
रासायनिक, दवाइयाँ	३४	३३	३२	१६०
रंग	१८	१५	१७	८५
कागज आदि	१४	१०	११	५५
कटलरी, बिजली का सामान	३६	२६	२६	१४५
कपास	५४	१४	५४	२७०
जूट	१७	१८	१८	६०
अन्य	१३०	१४०	१४०	७००
	६५५	७८६	८६८	४३४०

के लिये मँगाया जायेगा। निजी क्षेत्र की मशीनों व गाड़ियों की आवश्यकता का अनुमान ४५० करोड़ रुपये है।

स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन

मई १९५६ में सरकार ने स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना की। इसकी स्वीकृत पूंजी १ करोड़ रुपये है। इसका उद्देश्य व्यापार को प्रोत्साहन देना है। जब से यह कॉर्पोरेशन बनी है तब से यह इस बात का प्रयत्न कर रही है कि इस्पात, सीमेंट, औद्योगिक सामान आदि विदेशों से मँगाया जाये। इसका प्रयत्न है कि स्टर्लिंग रिजर्व पर कम से कम प्रभाव पड़े। कॉर्पोरेशन ने कम कीमत पर सीमेंट, सोडा, कास्टिक सोडा, रेसम, खाद, जिप्सम खरीदा है। इस कॉर्पोरेशन ने विदेशों को धातुएँ, जूते, हाथ का बना सामान भेजने का प्रयत्न किया है। यह सामान रूस, पोलैंड तथा जेकोसलेवेकिया को भेजा गया। जूट का सामान व सन वाटनाम की रेशम तथा जसा-तस्कर इन्होंने विदेशों को भेजे। इसके अतिरिक्त अरबों डॉलर की रस्सी, रुई तथा सीप हथरी को तथा चीनी वाटनाम को भेजी गई। इसी प्रकार चीन से कास्टिक सोडा व सोडा ऐश व रूस से मशीनें मँगाई गई। १ जुलाई १९५७ ई० से कच्चा लोहा भी इसी कॉर्पोरेशन द्वारा निर्यात करने का निश्चय किया गया है। इसके फलस्वरूप इस कॉर्पोरेशन ने जापान को ७२ मिलियन टन कच्चा लोहा बेचने का एक दीर्घकालीन समझौता किया है। इसी प्रकार के समझौते पोलैंड व जेकोसलेवेकिया से किये गये हैं।

कार्पोरेशन ने यह प्रयत्न किया है कि आवश्यक पदार्थों की आयात को भारतीय निर्यात से सम्बन्धित किया जाये। इस प्रकार के प्रबन्ध संयुक्त राज्य (U. K.), वाटनम, रूस, हंगरी, रूमानिया, जेकोसलेवेकिया तथा मिस्र से किये गये हैं। इसके कारण हमारे निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अतिरिक्त कार्पोरेशन विदेशी प्रदर्शनियों में भी भाग ले रही है। पहले वर्ष में कार्पोरेशन को ३२६३००० रुपये का लाभ हुआ।

भारतीय मुद्रा तथा विनिमय

Q. 84. Briefly describe the Indian Currency System between 1925-38.

प्रश्न ८४—१९२५ से ३८ तक भारतीय मुद्रा प्रणाली का वर्णन कीजिये।

२५ अगस्त १९२५ ई० को भारत सरकार ने हिल्टन दम कमीशन को नियुक्त किया। इस कमीशन को स्वर्ण विनिमय मान की अच्छी प्रकार जाँच करके भारत के लिये एक उपयुक्त मुद्रा प्रणाली के लिये सुझाव देना था। इसके अतिरिक्त इस कमीशन को यह भी बताना था कि भारतीय मुद्रा पद्धति तथा भारतीय बैंकिंग में किस प्रकार सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता था। इस कमीशन ने स्वान-स्वात पर ध्यानकर तथा बहुत से लोगों से बातचीत करके निम्नलिखित तीन प्रकार के सुझाव दिए—

(१) भारत के लिये एक उपयुक्त मुद्रा प्रणाली।

(२) विनिमय-दर।

(३) एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना।

भारत के लिये उपयुक्त मुद्रा प्रणाली—

इस कमीशन ने स्वर्ण विनिमय मान की अच्छी प्रकार जाँच करके बताया कि भारतवर्ष में इस मान के कार्य करने के ढंग में निम्नलिखित दोष पाये जाते थे—

(१) यह मुद्रा पद्धति सरल न थी। (२) इसके कार्य करने की विधि इतनी पेचीदा थी कि पड़े-लिखे लोगों की समझ में भी न आती थी। (३) इसको संचालन करने में बहुत अधिक सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। (४) इस पद्धति में कहने के लिये रुपये तथा सोने में सम्बन्ध था पर व्यवहार में ऐसा न था। (५) इसमें दो स्थानों पर स्वर्णकोष रखना पड़ता था—इंग्लैंड में स्वर्णकोष रखना तथा भारतवर्ष में कागजी द्रव्य कोष रखना। (६) यह लोचदार न थी क्योंकि भारतवर्ष में मुद्रा का कम या अधिक होना भारत मन्त्री की इच्छा पर निर्भर था। (७) इस मान का ठीक प्रकार से चलना चाँदी के मूल्य पर निर्भर था। जब तक चाँदी के दाम ४३ पैस प्रति औंस से कम रहे, यह कार्य करता रहा पर जब चाँदी के दाम उससे ऊपर चले गये तो वह न चल सका। (८) जिस उद्देश्य के लिये स्वर्णकोष रखा गया था वह उसके लिए खर्च न किया गया वरन् उसको दूसरे कामों के लिये भी खर्च कर दिया गया, जैसे रेलों के बनाने के लिये। (९) इस मान के द्वारा लन्दन

के मुद्रा बाजार को ही लाभ पहुँचता था। भारत के मुद्रा बाजार को इससे कोई लाभ न था। (१०) इस मुद्रा पद्धति में जनता का विश्वास न था।

इन सब बातों के कारण इस कमीशन ने स्वर्ण विनिमय मान को ग्रहण न करने की सलाह दी।

इसके पश्चात् कमीशन ने स्वर्ण मुद्रा मान की जाँच की परन्तु इसको ग्रहण करने के लिए भी कमीशन ने राय न दी क्योंकि इसको चलाने में बहुत सोने की आवश्यकता थी और इसको ग्रहण करने से देश में अधिक साख्ता बढ़ना सम्भव न था।

कमीशन ने बताया कि भारतवर्ष के लिए स्वर्ण धातु मान सबसे श्रेष्ठ होगा क्योंकि यह मान बहुत ही सरल था, स्वयं संचालित था और इसके अन्तर्गत विनिमय दरों का स्थायी रखना सम्भव था। कमीशन ने सलाह दी कि साबरेन आदि सोने के सिक्के वैधानिक ग्राह्य न रहें परन्तु चाँदी के रुपये और कागज के नोट ही कानूनी ग्राह्य रहे और उनके बदले एक निश्चित मात्रा में अर्थात् ४०० औंस (१०६५ तोले) शुद्ध सोना खरीदने तथा बेचने का उत्तरदायित्व सरकार पर रखा जाय।

विनिमय दर—कमीशन ने यह सलाह दी कि रुपये की विनिमय दर १ शि० ६ पैसे होनी चाहिये क्योंकि इसी के अनुसार वस्तुओं के मूल्य, मजदूरों की मजदूरियाँ, व्यापारियों के लेन-देन, किसानों का लगान और सरकारी ठेके निश्चित हुए हैं और इसमें परिवर्तन करने से किसानों को अधिक सकट होगा। इसके विपरीत १ शि० ४ पैसे दर भारत के लिए बिल्कुल उपयुक्त न होगी क्योंकि यह अस्वाभाविक दर है, इसका नियन्त्रण करना विशेषकर ऐसे समय में कठिन होगा जबकि व्यापारिक सन्तुलन भारतवर्ष के प्रतिकूल हो। इस दर के अनुसार, मूल्य-स्तर तथा मजदूरियों का सामंजस्य न होगा। इसके कारण भारत सरकार को भी अधिक सकट का सामना करना पड़ेगा। बजट में सन्तुलन न होने से भारतवर्ष की विदेशों में साख गिर जायेगी और इसलिए भारतवर्ष की विदेशों से ऋण लेने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

परन्तु सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने जो इस कमीशन के सदस्य थे इस दर की बड़ी कड़ी आलोचना की। उन्होंने बताया कि १ शि० ६ पैसे दर भारत के लिये बिल्कुल अनुपयुक्त है क्योंकि वह दर अस्वाभाविक है और सरकार के बहुत अधिक हस्तक्षेप के पश्चात् यह स्थापित हुई है। उन्होंने यह भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि इस दर पर न तो वस्तुओं के मूल्य का, न मजदूरों की मजदूरी का, और न व्यापारियों के लेन देन का सामंजस्य हुआ है। इसके कारण मजदूरों और पूँजीपतियों के संघर्ष और भी अधिक बढ़ने की सम्भावना है। इसके कारण विदेशों से आयात को प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिये भारतीय उद्योगों को बड़ा फाटा उठाना पड़ेगा। इस दर के कारण ऋणियों का ऋण भार और भी बढ़ जायेगा। इसके विपरीत सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास ने बताया कि १ शि० ४ पैसे एक स्वाभाविक

दर है क्योंकि यह पिछले २० वर्षों से भारतवर्ष में चालू है। इसके कारण सरकार को भी कोई विशेष आर्थिक संकट का सामना न करना पड़ेगा क्योंकि जितनी हानि उसको स्टैलिङ्ग भेजने में होगी उससे अधिक लाभ उसको दूसरे साधनों से हो जायेगा। १ शि० ६ पैं० के कारण भारतीय उत्पादकों को बड़ी हानि होगी क्योंकि उनको अपने सामान को बेचकर कम रुपये मिलेंगे। १ शि० ४ पैं० के कारण उन लोगों को कोई कठिनाई न होगी जिन्होंने १९१७ से पहले सोदे किये थे और इस प्रकार के सोदे भारतीय किसानों ने किये थे जिनके हित का ध्यान भारतीय सरकार को अवश्य रखना चाहिए। किसी भी देश ने युद्ध से पहले की विनिमय दर से ऊँची दर रखना ठीक नहीं समझा है इसलिये भारत को भी अपनी विनिमय दर न बढ़ाना चाहिए। यह सब कहने के पश्चात् सर मुल्पोलमदास ने कहा कि यदि १ शि० ६ पैं० की दर को ग्रहण किया गया तो अगले कुछ वर्षों में भारतीय आर्थिक ढाँचे में इतनी उथल-पुथल हो जायेगी जिसका अनुमान लगाना बहुत कठिन है परन्तु जिसका फल भारत के लिये बहुत ही भयानक होगा।

केन्द्रीय बैंक—

कमीशन की तीसरी सिफारिश यह थी कि भारतीय मुद्रा बाजार का नियन्त्रण करने के लिये केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाये। इस बैंक को रुपये की विनिमय दर को ठीक रखने का भार सौंप देना चाहिए तथा इसको नोट छापने का भी अधिकार देना चाहिए। यह बैंक हिस्सेदारों का बैंक होना चाहिये।

कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार का कार्य

भारत सरकार ने विरोध के होते हुये भी बहुमत की इन तीनों सिफारिशों को मान लिया। इनको कार्य रूप में खाने के लिये सरकार ने जनवरी १९२७ में स्वर्णमान तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बिल पेश किया। इस बिल को एक प्रवर समिति (Select Committee) को जाँच करने के लिए सौंप दिया गया। इस बिल पर कमेटी ने बड़ा मतभेद था। यह मतभेद बैंक के हिस्सेदारों का बैंक होने पर था। इस कमेटी का बहुमत यह भी चाहता था कि बैंक के गवर्नर तथा उप-गवर्नर भारतीय हों। इस कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि सोने की मोहरें बनानी चाहियें। सरकार तथा विरोधी दल में मतभेद होने के कारण यह बिल सन् १९२५ में पेश किया गया था, इस प्रयत्न ना तो रिजर्व बैंक ही स्थापित हो सका और न स्वर्ण धातुमान ही ग्रहण किया गया।

सरकार ने रुपये के विनिमय की दर १ शि० ६ पैं० मान ली और उसको कार्यान्वित करने के लिये १९२७ में मुद्रा एक्ट बनाया गया। जिसके अनुसार रुपये की विनिमय दर १ शि० ६ पैं० हो गई और सरकार के लिये कम से कम ४० तोले वाली सोने की छड़ें २१ रुपये ३ आ० १० पा० प्रति तोला पर मोल लेना तथा कम से कम १०६५ तोले (४०० औंस) सोना या स्टैलिङ्ग १ शि० ५४ पैं० प्रति

रुपये की दर पर बेचना अनिवार्य हो गया। परन्तु इस एक्ट द्वारा भारत में स्वर्ण धातुमान स्थापित न हो सका क्योंकि सरकार ने नोटों के बदले कभी भी सोना न दिया वरन् स्टलिंग ही दिया। इस प्रकार इस समय भारतवर्ष में स्वर्ण धातुमान के स्थान पर स्टलिंग विनिमय मान स्थापित हो गया।

१९२७ के पश्चात् जब यह एक्ट पास किया गया तब भारतवर्ष के आयात-तथा निर्यात में खूब वृद्धि हुई। परन्तु यह वृद्धि नई विनिमय दर के ग्रहण करने के कारण न थी वरन् इसलिये थी कि सारे सप्ताह में व्यापार की स्थिति कुछ सुधर गई थी। परन्तु यह स्थिति बहुत थोड़े समय तक रही क्योंकि १९२९ में बहुत अधिक मन्दी (Depression) आ गई। इसके कारण सभी प्रकार के सामान के दाम गिर गये और किसानों, मजदूरों तथा उद्योगपतियों को बहुत घाटा उठाना पड़ा। १९३० के असहयोग आन्दोलन के कारण भी व्यापार तथा उद्योगों को बड़ी हानि हुई और भारतवर्ष की बहुत सी पूँजी विदेशों को जाने लगी।

सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिये द्रव्य को घटाया। बहुत अधिक मात्रा में ट्रेजरी बिल बेचे गये। १ करोड़ ४० लाख पौंड के रिर्वर्स काउन्सिल भी बेचे गये तथा १३८३ करोड़ रुपये चलन में से कम कर दिये गये। इसके कारण रुपये की बहुत कमी हो गई और वस्तुओं के भाव और भी अधिक गिर गये। व्यापारियों ने इस नीति का कड़ा विरोध किया।

२१ सितम्बर १९३१ को इंग्लैंड ने स्वर्ण मान का त्याग कर दिया। इसलिये भारतवर्ष को यह सोचना पड़ा कि रुपये को स्टलिंग से सम्बन्धित करे अथवा न करे। भारतीयों ने इस सम्बन्ध का विरोध किया परन्तु उनकी एक न सुनी गई और रुपये को स्टलिंग से १ शि० ६ पै० पर सम्बन्धित कर दिया गया। सरकार ने कहा कि स्टलिंग से सम्बन्ध स्थापित होने से रुपये की विनिमय दर में बहुत कुछ स्थिरता आ जायेगी। ऐसे सम्बन्ध से भारतवर्ष का अपना स्टलिंग ऋण तथा घरेलू व्यय चुकाने में बहुत सुविधा हो जायेगी। इसके अतिरिक्त जब तक भारत ऋणी है तब तक रुपये को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। भारतवर्ष का अधिकतर व्यापार इंग्लैंड तथा ब्रिटिश साम्राज्य के देशों से है। इस सम्बन्ध द्वारा कम से कम इस व्यापार में स्थायित्व आ जायेगा।

परन्तु भारतवासियों ने इस नवीन मुद्रा पद्धति की बहुत कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सम्बन्ध के कारण इंग्लैंड के मूल्य स्तर के परिवर्तन भारतवर्ष के मूल्य-स्तर पर भी प्रभाव डालेंगे। इस विनिमय दर के कारण इंग्लैंड के निर्यात वस्तुओं को दूसरे स्वर्ण मान देशों के निर्यात वस्तुओं की अपेक्षा लाभ होगा। इसके कारण देश का स्वर्ण कोष अत्यधिक निर्यात के कारण बहुत कम हो जायेगा। वास्तव में ये आलोचनाएँ बहुत सीमा तक उचित भी थीं।

इसके पश्चात् हमारे देश के व्यापार को बहुत बड़ा आघात पहुँचा और १९३१ से १९३७ तक भारतवर्ष से ३८२ करोड़ रुपये का सोना विदेशों को चला गया।

१९३५ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई। बैंक को नोट छापने का एकाधिकार दिया गया। यह सहकारी बैंक तथा दूसरे बैंकों का बैंक भी बन गया। इन कार्यों के अतिरिक्त इसके ऊपर यह भार था कि वह भारतीय विनिमय दर को १ शि० ६ $\frac{1}{4}$ पैसे प्रति रुपया पर स्टलिंग खरीद कर तथा १ शि० ५ $\frac{3}{4}$ पैसे पर उसको बेचकर १ शि० ६ पैसे पर स्थिर रखे। इस बैंक के स्थापित होने पर स्वर्णमान कोष तथा कागजी मुद्रा कोष को मिला दिया गया। इस बैंक के स्थापित होने से यह लाभ हुआ कि मुद्रा साख का नियन्त्रण एक ही संस्था के हाथ में आ गया। इससे पूर्व देश की साख इम्पीरियल बैंक के हाथ में थी तथा नोट छापने का अधिकार भारत सरकार के हाथ में था, इसलिये भारत की मुद्रा पद्धति में सजीलापन नहीं था।

भारत से इतना अधिक सोने का निर्यात होने के कारण भारतवर्ष के लोगों ने यह माँग की कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन (Devaluation) होना चाहिये। हमारे देश के लोगो ने कहा कि जबकि डालर तथा फ्रैंक मूल्य में गिरा दिये हैं, तब रुपये का मूल्य भी गिरा देना चाहिए नहीं तो भारतवर्ष को इन देशों की अपेक्षा व्यापार करने में हानि होगी।

परन्तु इसके विरोध में कुछ लोगो ने कहा कि रुपये का अवमूल्यन करने से संयुक्त राज्य (United Kingdom), संयुक्त राष्ट्र (United States) तथा फ्रांस के बीच हुआ मुद्रा समझौता भग्न हो जायेगा और ससार की मुद्राओं में स्थिरता आने की आशा बहुत कम रह जायेगी। इसके अतिरिक्त रुपये को स्टलिंग से सम्बन्धित करने के कारण रुपये का मूल्य सोने के रूप में पहले ही ४० प्रतिशत गिरा हुआ है। रुपये के अवमूल्यन के कारण सर ओटो निम्यर अवार्ड को कार्यान्वित करने में बड़ी कठिनाई आयेगी। इन सब बानों के अतिरिक्त रुपये के अवमूल्यन की कोई आवश्यकता दिखाई नहीं पड़ती क्योंकि ऐसा कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात् न घाटे का बजट है, न ऊँची व्याज की दर है, न स्वर्ण कोष में सोना ही कम हुआ है, न व्यापारिक सन्तुलन ही प्रतिकूल है और न मुद्रा संकुचन ही है, जिससे यह कहा जा सके कि रुपये का मूल्य आवश्यकता से अधिक है।

परन्तु अप्रैल से अगस्त १९३८ तक भारत में इस बात की माँग बड़े जोरो से की गई कि रुपये का अवमूल्यन किया जाय क्योंकि उस समय रिजर्व बैंक स्टलिंग को नीची दर पर खरीद रहा था तथा देश के व्यापारिक सन्तुलन में भी बहुत कमी आ गई थी। इण्डियन नेशनल कांग्रेस की कार्यकारिणी ने इस प्रश्न को अपने हाथ में ले लिया और बहुत सी प्रान्तीय सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को लिखा कि रुपये की विनिमय दर में बदल कर दी जाये परन्तु केन्द्रीय सरकार ने ६ जून १९३८ को एक विज्ञापन द्वारा यह बताया कि रुपये स्टलिंग की वर्तमान विनिमय दर को कायम

रखने के लिये भारतवर्ष के हित में है और रिजर्व बैंक के पास इस दर को कायम रखने के लिये पर्याप्त मात्रा में सोना तथा स्टर्लिंग है।

Q 58 Review the course of events in India's Currency and Exchange between 1939-45.

प्रश्न ८१—१९३९-४५ के बीच भारतीय मुद्रा और विनिमय में जो घटनाएँ हुई उनका उल्लेख कीजिये।

३ सितम्बर १९३९ को यूरोप में द्वितीय महायुद्ध छिड़ा। यद्यपि भारतवर्ष युद्धस्थल से बहुत दूर था तो भी भारतवर्ष में युद्ध की तैयारियाँ शुरू हो गई क्योंकि इंग्लैंड युद्ध में सम्मिलित था। युद्ध की घोषणा होने के पश्चात् भारत की मुद्रा विनिमय पर बहुत प्रभाव पड़ा।

युद्ध के कारण भारत में बहुत अधिक मात्रा में नोट छापे गये। इसके कारण इस देश में मुद्रा स्फीति हो गई। १९३८-३९ में हमारे देश में ८२.३६ करोड़ रुपये के नोट थे। ये नोट बढ़कर २६ अप्रैल १९४६ को १२३१.७३ करोड़ रुपये के हो गये। इतने अधिक नोट छपने के कारण देश में सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये क्योंकि नोट तो बड़े वेग से छपते रहे परन्तु उत्पादन पहले की अपेक्षा बहुत ही कम बढ़ा। कलकत्ता सूचक अंक के अनुसार मार्च १९४५ ई० में थोक मूल्य ३१० के बराबर थे। केन्द्रीय सरकार के आर्थिक सलाहकार के सूचक अंक के अनुसार भी १९४४-४५ में औसत थोक मूल्य २४४ के लगभग रहे। यदि इस बीच में चोर बाजार के मूल्यों के अनुसार सूचक अंक बनाये जाते तो मूल्य इनसे भी अधिक ऊँचे निकलते।

इतने अधिक नोटों का छापना इसलिये सम्भव हुआ कि रिजर्व बैंक के सुरक्षित कोष (Assets) में भारी परिवर्तन किये गये। युद्धकाल में अधिकतर नोट स्टर्लिंग सिक्वोरिटीज के पीछे छापे गये। युद्ध से पहले ये सिक्वोरिटीज ६६.९ करोड़ रुपये की थी परन्तु २६ अप्रैल १९४६ को ये ११२५.३२ करोड़ रुपये की हो गई। यही नहीं, रुपये सिक्वोरिटीज की मात्रा भी सुरक्षित कोष में बहुत बढ़ गई। युद्ध से पहले इस प्रकार की सिक्वोरिटीज कुल छपे हुए नोटों की $\frac{1}{4}$ अथवा ५० करोड़ रुपये इन दोनों में जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं हो सकती थी। परन्तु ११ फरवरी १९४१ की एक आज्ञा से इसमें बदल कर दी गई और रिजर्व बैंक को यह स्वतन्त्रता दी गई कि वह किसी भी सीमा तक इन सिक्वोरिटीज के पीछे नोट छाप सकता था। इसके कारण इनकी मात्रा ३७ करोड़ रुपये से बढ़कर ४ जनवरी १९४६ को ५८ करोड़ रुपये हो गई। परन्तु इसी बीच सोना ४४४ करोड़ रुपये का ही रहा।

सरकार ने पुराने चाँदी के सिक्के भी चलन में निकाल लिये और उनके धान पर नये प्रामाणिक तथा सार्केतिक सिक्के और नोट जारी किये और यह आज्ञा दी कि कोई भी सिक्को को आवश्यकता से अधिक न रखे। जनता की सिक्को की माँग को पूरा करने के लिये सरकार ने १९४० में एक रुपये के नोट जारी किये। १९४० में फ्रांस के हार जाने के पश्चात् लोगों का विश्वास सरकार में बहुत कम हो गया, इसलिये उन्होंने नोटों को रुपये में बदलना शुरू किया और डाकघाने तथा बैंकों से भी अपने रुपये निकालने शुरू किये। इसके कारण रिजर्व बैंक के पास रुपये की बड़ी कमी हो गई। इसलिये २५ जून १९४० को सरकार ने यह घोषित किया कि रिजर्व बैंक के ऊपर नोटों के बदले रुपये के सिक्के देने का कोई भार नहीं है। यह भी घोषित किया गया कि कोई भी मनुष्य अपनी आवश्यकता से अधिक हरद के सिक्के न रखे। उसी समय एक रुपये के नोट जारी किये गये। १९४० के आखिरी में रोजगारी की बड़ी कमी हो गई और इस कमी को सरकार ने नये सार्केतिक सिक्के जारी करके पूरा किया। १९४३ में दो रुपये का नोट भी चालू किया गया। सरकार ने युद्ध काल में जो सिक्के जारी किये उनमें चाँदी की मात्रा को घटा दिया। कुछ सिक्को के वजन में भी कमी कर दी गई, जैसे पैसे का वजन ७५ ग्रेन से घटा कर ३० ग्रेन कर दिया गया। १९४३ में एक नये आधे आने का सिक्का भी जारी किया गया।

युद्ध का प्रभाव भारतीय राजस्व पर भी पड़ा। इसके कारण नये-नये कर लगाये गए तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के युद्ध ऋण लिए गये। परन्तु जब इन साधनों से सरकार की आवश्यकता पूरी न हुई तो उसने रिजर्व बैंक द्वारा स्टर्लिंग सिक्को-रिट्रीज के आधार पर कागजी नोट छपवाये। युद्ध व्यय के बढ़ने के कारण वजट का घाटा भी बढ़ता चला गया। इस घाटे को पूरा करने के लिए ही नोट छापे गये। युद्धकाल में भारतवर्ष ने इंग्लैंड तथा दूसरे देशों को इतना भाल देखा कि उससे भारत ने प्रायः सब स्टर्लिंग ऋण चुका दिया और अन्त में इंग्लैंड भारतवर्ष का ऋणी हो गया।

युद्ध काल में रिजर्व बैंक की देख-रेख में एक विनिमय नियन्त्रण विभाग (Exchange Control Department) भी खोला गया। इस विभाग के द्वारा विदेशी विनिमय, स्वर्ण तथा स्वर्ण सिक्कोरिट्रीज के खरीदने-बेचने पर पाबन्दी लगा दी गई। भारतवर्ष में केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही विदेशी विनिमय, स्वर्ण तथा स्वर्ण सिक्कोरिट्रीज में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। विदेशी विनिमय को लोक युद्ध से पहले के ऋणों को चुकाने के लिए बख्खा माना करने के लिए बख्खा अपने निजी कामों के लिए रिजर्व बैंक की अनुमति से ले सकते थे। यदि किसी मनुष्य को स्टर्लिंग क्षेत्र के बाहर कुछ धन भेजना होता था तो भेजने वाले व्यक्ति को एक फार्म भरना पड़ता था जिसमें इस धन की भेजने के कारण दिए जाते थे। हर एक उस व्यक्ति को जिसको विदेशी विनिमय में व्यापार करने का

बन गया। इस कारण यह आवश्यक हो गया कि भारतवर्ष स्टलिंग से अपना सम्बन्ध विच्छेद करे। इस कारण २ अप्रैल १९४७ को श्री लियाकतअली ने (जो उस समय वित्त मन्त्री थे) एक बिल पेश किया जिसके द्वारा रिजर्व बैंक को यह आज्ञा दी गई कि वह स्टलिंग के अतिरिक्त और दूसरी मुद्राओं को भी खरीद सकता है। इस प्रकार हमारा एक स्वतन्त्र मुद्रा के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ४ १४५१४ ग्रेन शुद्ध सोने की दर से सम्बन्धित कर दिया गया। इस प्रकार भारत में अन्तर्राष्ट्रीय मान स्थापित हो गया। परन्तु इस सम्बन्ध के स्थापित होते हुये भी हमारा हमारा सब देशों की मुद्राओं में स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं बदला जा सकता क्योंकि अन्तर्वर्ती समय (Transitional period) के लिए कोष ने भारतवर्ष को विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करने की आज्ञा दी हुई है। भारतवर्ष अब भी विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करता है। इसलिये हमारा हमारा स्वतन्त्रतापूर्वक किसी भी मुद्रा में नहीं बदला जा सकता।

१५ अगस्त १९४७ को देश का विभाजन हुआ। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय मुद्रा पद्धति में कुछ परिवर्तन करने आवश्यक थे। ३० सितम्बर १९४८ तक रिजर्व बैंक को भारत और पाकिस्तान की मुद्रा पद्धति का नियन्त्रण करने के लिये नियुक्त किया गया। इस समय रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान सरकार के नोट व सिक्के जारी किये जो पाकिस्तान में ही चल सकते थे। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्थापना हुई तो उसने पाकिस्तान के नोटों का भार अपने ऊपर लिया। इसलिये रिजर्व बैंक को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को १५२ करोड़ रुपये की सम्पत्ति देनी पड़ी। पाकिस्तान के सिक्कों के निकलने के एक वर्ष पश्चात् भी भारतीय रुपया तथा अन्य छोटे सिक्के पाकिस्तान में वानूनी ग्राह्य कर दिये गये। इन सिक्कों को रिजर्व बैंक को लौटा दिया गया। मार्च १९४९ तक रिजर्व बैंक को इनके बदले ८२ करोड़ रुपये का सोना, सोने के बने सिक्के, स्टलिंग सिक्कोरिटोज आदि देने पड़े। इस प्रकार भारत में नोट चलन से कम हो गये।

भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जिसमें भारतीय तथा पाकिस्तानी रुपये की विनिमय दर भी तय हुई। इस समझौते के अनुसार रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान के १०० रुपये, भारत के ८९ ३/४ रुपये के बदले मोल लेने तथा १०० ३/४ रुपये के बदले बेचने की घोषणा की। परन्तु जब भारत ने अपने रुपये का अवमूल्यन किया और पाकिस्तान ने न किया तब इस विनिमय दर में बदल होनी स्वाभाविक ही थी। पहले तो बहुत समय तक भारत को यह आशा रही कि पाकिस्तान भी भारत के समान अपने रुपये का अवमूल्यन करेगा। परन्तु जब पाकिस्तान ने ऐसा न किया और भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता हुई तब भारत ने पाकिस्तान की दर को स्वीकार कर लिया। उसके कुछ ही समय पश्चात् अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पाकिस्तान की दर को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अब भारत के १४४ रुपये पाकिस्तान के १०० रुपये के

बराबर हो गये। परन्तु २१ जूलाई १९५५ को पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन भारत के समान ही कर दिया है। अब पाकिस्तान का एक रुपया १ दि० ६ पैसे स्टलिंग तथा १ डालर ४ ७६१६० पाकिस्तानी रुपये के बराबर है।

१७ सितम्बर १९४६ को इंग्लैंड ने स्टलिंग का अवमूल्यन किया। उसके साथ-साथ और बहुत से देशों ने भी अपनी-अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया। भारत ने भी १६ सितम्बर को रुपये का बाह्य मूल्य सोने तथा डालर के रूप में ३०.५ प्रतिशत घटा दिया। इस प्रकार रुपया जो पहले ३०.२ सेन्ट्स के बराबर था अवमूल्यन के पश्चात् २१ सेन्ट्स के बराबर रह गया।

रुपये के अवमूल्यन से भारत को यह आशा थी कि भारतवर्ष को विदेशी व्यापार में और विशेषतया अमेरिका के साथ व्यापार करने में बहुत लाभ होगा। इससे भारतवर्ष को लाभ तो अवश्य हुआ परन्तु इतना नहीं जितनी कि आशा थी। अवमूल्यन से भारत को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि जो खाद्य सामग्री अथवा मशीनें संयुक्तराष्ट्र से भारत आईं उनके दाम ४४ प्रतिशत बढ़ गये। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से जो ऋण भारत ने लिया उसका भार भारत के ऊपर और अधिक बढ़ गया। पाकिस्तान के साथ व्यापार लगभग एक वर्ष तक बन्द रहा। भारतवर्ष जो पाकिस्तान से जूट तथा रुई मोल लेता था, उसको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अवमूल्यन से भारत में वस्तुओं के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये और उपभोक्ताओं को बड़े सकट का सामना करना पड़ा। इन्हीं सब बातों के कारण भारतवर्ष में इस बात की माँग है कि रुपये का पुनर्मूल्यन होना चाहिये। परन्तु भारत सरकार अभी तक यह बात मानने को तैयार नहीं है कि अवमूल्यन से भारतवर्ष को हानि हुई है। इसलिये वह रुपये का पुनर्मूल्यन करने को तैयार नहीं है।

पञ्चवर्षीय योजना का मुद्रा तथा करेन्सी पर प्रभाव—

मुद्रा तथा करेन्सी पर योजना का प्रभाव जानने के लिये हमको योजनावाले को दो भागों में बाँटना पड़ेगा। पहला काल १९५१-५३ का है जिसमें द्रव्य की पूर्ति २१४ करोड़ रुपये घट गई जिसमें से कि अधिकतर १९५१-५२ में घटी। इसके पश्चात् अगले तीन वर्षों में द्रव्य की पूर्ति ४२० करोड़ रुपये बढ़ गई। इस प्रकार कुल योजनाकाल में २०६ करोड़ रुपये की द्रव्य पूर्ति बढ़ी। इसके अतिरिक्त इस बीच बैंक द्रव्य में भी १३७ करोड़ रुपये की वृद्धि हुई।

पहले दो वर्षों में द्रव्य की कमी का कारण हमारे विदेशी विनिमय के साधनों में कमी होना था। इस काल में रिजर्व बैंक के विदेशी विनिमय के साधन १६० करोड़ रु० तक घट गये। पिछले तीन वर्षों में मुद्रा बढ़ने के दो कारण थे—
(१) बजट में घाटा तथा (२) बैंको द्वारा निजी उद्योगों तथा व्यापार के लिये साख निर्माण करना। इस बीच में विदेशी विनिमय के साधनों में भी २२ करोड़ रुपये

की वृद्धि हुई। इसके कारण भी नोटों में कुछ वृद्धि हुई। परन्तु आजकल तो विदेशी विनिमय के साधन निरन्तर कम होते जा रहे हैं परन्तु नोटों की पूर्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है। ये नोट अधिकतर रुपया प्रति-भूतियों को रिजर्व में रखकर छापे जाते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आजकल भारतवर्ष का रुपया प्रामाणिक सिक्का है। यह १८० ग्रेन का है। द्वितीय महायुद्ध के पहले यह ३६ शुद्ध चांदी का था परन्तु महायुद्ध में यह ६६ शुद्ध रह गया। १९४७ की अप्रैल से रुपया गिल्ट का बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार एक रुपये का नोट भी छापती है जो हर दृष्टि से एक रुपये के सिक्के के बराबर है। छोटे-छोटे सौदों को तप करने के लिये सार्कितिक सिक्के हैं जिनमें चवथी, दुबली, इकथी, अधप्रा, पेंसा तथा पाई हैं। इनके अतिरिक्त अठथी का सिक्का भी है। इन सबको भारत सरकार बनाती है। भारतवर्ष में रुपया यद्यपि प्रामाणिक सिक्का है तो भी न तो इसकी स्वतन्त्र मुद्रा ढलाई है और न इसका टंकशाली मूल्य इसके वास्तविक मूल्य के बराबर है। इसी लिये इसको सार्कितिक प्रमाण कहते हैं। अगस्त १९५५ ई० में भारत सरकार ने दशमलव प्रणाली को स्वीकार करके रुपए को १०० भागों में बाँटकर दशमलव प्रणाली का सूत्रपात किया। ये सिक्के एक अप्रैल सन् १९५७ ई० से चालू किये गये हैं।

परन्तु प्रारम्भ में ३ वर्ग तक नये और पुराने दोनों प्रकार के सिक्के चलेंगे। धीरे-धीरे पुराने सिक्के निकास लिये जायेंगे और अन्त में नये सिक्के चलन में रह जायेंगे।

नई दशमलव प्रणाली के अनुसार एक रुपये में १०० नये पैसे हैं। नई प्रणाली में १ पैसा, २ पैसे, ५ पैसे, १० पैसे, २५ पैसे, ५० पैसे, तथा १०० पैसे के सिक्के होंगे। नया सिक्का कांसे या कसकुट का बना होगा। २, ५ और १० नये पैसे के सिक्के तीन चौथाई तांबे तथा एक चौथाई निकल से मिली धातु से बनाये जायेंगे। २५, ५०, १०० नये पैसे के सिक्के वर्तमान चवथी, अठथी, रुपये की भाँति निकास के बने होंगे।

रुपये के विदेशी मूल्य को भारतवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दी हुई विनिमय दर के अनुसार नियन्त्रित करता है। रिजर्व बैंक केवल कुछ अधिकृत लोगों को विदेशी विनिमय देव सकता है और वह भी दो लाख से कम नहीं। १९४७ ई० से हमारा रुपया स्टर्लिंग के अतिरिक्त और दूसरी मुद्राओं से सम्बन्धित हो गया है। इस प्रकार भारत के वर्तमान मान को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नियन्त्रित मान कह सकते हैं।

Q 87. What are sterling balance ? How have they been accumulated and utilized ?

प्रश्न ८७—पौंड पावने से क्या अभिप्राय है ? यह कैसे एकत्र हुआ तथा उसका किस प्रकार उपयोग किया गया ?

पौंड पावने वह धन है जो भारतवर्ष ने स्टर्लिंग सिक्कोरिटीज में लगाया हुआ है। आजकल यह रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के आधोन है और रिजर्व बैंक ने उसके पीछे नोट छाप रखे हैं। भारतवर्ष ने सदा ही स्टर्लिंग को अपने रिजर्व में रखा है। भारत के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होने से पूर्व रिजर्व बैंक जितने रुपये के नोट छापता था उसका ३ भाग सोने के सिक्के अथवा स्टर्लिंग सिक्कोरिटीज के रूप में रखता था। रिजर्व बैंक एक्ट की एक धारा के अनुसार स्टर्लिंग इतनी ही अच्छी मानी गई थी जितना कि सोना। इसीलिये जब द्वितीय महायुद्ध छिड़ा और सरकार को रुपये की आवश्यकता हुई तो उसने स्टर्लिंग सिक्कोरिटीज के पीछे नोट छापने के लिये सरकार को बाध्य किया। इस प्रकार स्टर्लिंग सिक्कोरिटीज रिजर्व बैंक के पास एकत्र हो गई।

उसके एकत्रित होने के कारण—पौंड पावने की युद्ध काल में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। इसके कई कारण थे—(१) ब्रिटेन ने युद्ध काल में भारतवर्ष से बहुत सा माल खरीदा। इस माल के बदले उसने भारत को रुपये नहीं दिये, न ही सोना दिया वरन् इंग्लैंड की सरकार ने अपने प्रमाण-पत्र दिये जो भिन्न अवधियों के थे। (२) भारत ने मित्र-राष्ट्रों की जनता तथा सेनाओं के लिये भी बहुत अधिक माल भेजा जिसके फलस्वरूप भारत का व्यापारिक सतुलन इन देशों के साथ भी पक्ष में रहा। (३) युद्ध काल में ब्रिटिश भारत में रहने वाले समस्त व्यक्तियों को डालर तथा अन्य दुर्लभ मुद्राओं के रूप में जो धन मिलता था वह भी ब्रिटिश साम्राज्य के 'डालर पूल' के लिये अनिवार्य रूप से ले लिया गया। (४) अमरीका को निर्यात तथा अमरीका की सेना पर भारत में होने वाले व्यय के बदले में भारत को जो डालर प्राप्त हुये वे भी 'डालर पूल' में जमा कर दिये गये। इस प्रकार भारतवर्ष को जो इंग्लैंड अथवा विदेशों से पाना था उन सब के बदले स्टर्लिंग सिक्कोरिटीज दी गई। भारत सरकार इनको रिजर्व बैंक को देती रही और रिजर्व बैंक उनको रिजर्व में रखकर नोट छापता रहा।

पौंड पावने का उपयोग—युद्ध समाप्त होने पर इस देश में इस बात की बड़ी चर्चा हुई कि पौंड पावने का उपयोग किस प्रकार किया जाय। भारत के भिन्न-भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न सुझाव रखे। किसी ने कहा कि इनके बदले इंग्लैंड से मशीनें भेगाई जायें। किसी ने कहा कि इनको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास धरोहर के रूप में रखकर कोष से ऋण लिया जाय। इसके विपरीत इंग्लैंड में कुछ ऐसे लोग थे जो इनको युद्ध ऋण बताकर बहुत कम कर देना चाहते थे।

इस प्रकार की खीचातानी में अगस्त १९४७ में भारत इंग्लैंड के बीच एक अन्तर्कालीन समझौता (Interim agreement) हुआ। यह समझौता केवल छ मास के लिये था। जनवरी १९४८ में इस समझौते की अवधि फिर छ मास के लिये बढ़ा दी गई। इन दो समझौतों से ८३० लाख पौंड पावने भारत को फिर मिले, इनमें से केवल ३० लाख पौंड काम में लाये जा सकते थे। इनके पश्चात् जून १९४८ में होने वाले समझौते के अनुसार ३० जून १९५१ तक के समय में भारत को उसके गत वर्षों के बचे हुये १०७ करोड़ रुपये के अतिरिक्त १०६ करोड़ रुपये अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करने की स्वतन्त्रता दी गई। उसी समय भारत सरकार ने पौंड पावने में से ब्रिटिश सरकार को करीब ३५७ करोड़ रुपया मुद्रा सामग्री के खरीदने तथा ब्रिटिश अफसरो की पेंशमें चुकाने के लिये दे दिये। जुलाई १९४९ में एक नया समझौता हुआ जिसमें भारत को यह अधिकार दिया गया कि जून १९५१ तक १०६ करोड़ रुपये के बदले १३३ करोड़ रुपये तक खर्च कर सकेगा। इसी समझौते में यह भी निश्चय किया गया कि भारत १९४८-४९ के लिये लगभग १०८ करोड़ रुपय खर्च कर सकेगा। फरवरी १९५२ में इस सम्बन्ध में सबसे आखिरी समझौता हुआ। यह समझौता ३० जून १९५७ तक के लिये किया गया है। इस समझौते के अनुसार ब्रिटेन १ जोलाई १९५१ ई० से लेकर छ वर्ष तक प्रतिवर्ष ३३ करोड़ पौंड स्टर्लिंग सम्पत्ति भारत को देगा। अक्टूबर १९५१ ई० के एक दूसरे समझौते के अनुसार भारत को यह अधिकार दिया गया है कि वह ३१ करोड़ पौंड सकट के समय इंग्लैंड की आज्ञा से खर्च कर सकता है।

इस सम्बन्ध में यह बात बताने योग्य है कि पौंड पावने को भारत ने बड़ी कठिनाई से एकजिन किया था। मुद्रा के समाप्त होने पर यह आशा की गई कि इनको विदेशों से मशीनें आदि मँगाने के लिये काम में लाया जायेगा अथवा इनके द्वारा अंग्रेजी व्यापारी कम्पनियों को खरीदा जायेगा। पर सेद है कि वे प्रायः सबके सब विदेशों से अन्न मँगाने में समाप्त हो गये और हम जैसे के तैसे ही रह गये।

—:०.—

Q 88. What do you understand by the Devaluation of Rupee? How has it affected the economy of India? Are you in favour of the revaluation of Indian rupee?

प्रश्न ८८—रुपए के अवमूल्यन से क्या अभिप्राय है? इससे भारतीय रुपये पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या आप भारतीय रुपये के पुनर्मूल्यन के पक्ष में हैं?

रुपये के अवमूल्यन का अभिप्राय है रुपये की विनिमय दर को कम कर देना। अवमूल्यन से पूर्व हमारा रुपा ३०.२२५ सेंट के बराबर था पर अब रुपया २१ सेंट के बराबर रह गया। इस प्रकार हमारे रुपये का मूल्य ३०.५ प्रतिशत कम कर दिया गया।

भारत से पहले ब्रिटेन ने पौंड स्टर्लिंग का अवमूल्यन किया। ब्रिटेन के साथ ही साथ ब्रिटिश साम्राज्य के बहुत से देशों ने भी अपनी-अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया। ऐसा होने पर भारतवर्ष ने भी रुपए का अवमूल्यन किया। यदि भारत ऐसा न करता तो उसको अवमूल्यन करने वाले देशों की अपेक्षा दुर्लभ मुद्रा वाले देशों से व्यापार करने में हानि होती। यही बात सोचकर भारत ने रुपए का अवमूल्यन किया। परन्तु जैसा कि भारत सोचता था उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया।

अवमूल्यन पर भारतीय रुपये का प्रभाव—रुपये के अवमूल्यन का भारतीय द्रव्य पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा—

(१) डालर क्षेत्रों में भेजे जाने वाले माल के निर्यात को प्रोत्साहन मिला क्योंकि अवमूल्यन के पश्चात् हमारा माल पहले से सस्ता हो गया।

(२) इसके विपरीत डालर देशों से आने वाला माल हमको महँगा पड़ने लगा और क्योंकि आज हमारा देश बहुत सा अन्न तथा मशीनें डालर देशों से मँगाता है। इस कारण हमें बहुत घाटा हो रहा है।

(३) पाकिस्तान जिसने कि अपने रुपये का अवमूल्यन नहीं किया, उसके साथ व्यापार करने में हमको बहुत घाटा रहा। पाकिस्तान से आने वाला जूट, रुई तथा अन्य चीजें हमारे लिये पहले से ४४ प्रतिशत महँगी हो गई। इससे हमारे जूट तथा रुई के उद्योग को बहुत भारी धक्का लगा। पहले भारत यह चाहता था कि पाकिस्तान को भी परिस्थिति से विवश होकर अपने रुपए का अवमूल्यन करना पड़ेगा। इसी कारण भारत ने पाकिस्तान से बहुत समय तक व्यापारिक सम्बन्ध न रखे। इतना सब होते हुए भी पाकिस्तान ने ऐसा न किया। अन्त में भारत को पाकिस्तान की पुरानी ही विनिमय दर माननी पड़ी और पुनः पाकिस्तान से व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने पड़े। इस व्यापार में भारत को हानि हुई। भारत को पाकिस्तान से कुछ रुपया लेना था। अवमूल्यन के कारण भारत को पहले से ४४ प्रतिशत रुपये कम मिलते। परन्तु हाल ही में पाकिस्तान ने भी अपने रुपये का अवमूल्यन कर दिया है।

(४) अवमूल्यन के कारण भारतवर्ष को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिये हुये ऋण पर ४४ प्रतिशत रुपये अधिक देने पड़ेंगे, तथा उस ऋण पर लगे हुये व्याज को भी पहले से अधिक देना पड़ेगा।

(५) भारतवर्ष को पौंड पावने के उस भाग का जो उसको डालर के रूप में मिलेगा ४४ प्रतिशत कम मिलेगा।

(६) अमरीका तथा डालर देशों में भारतीय राजदूतों का खर्च ४४ प्रतिशत बढ़ गया।

(७) अवमूल्यन से हमारी शोधनाधिक्य (Balance of payments) में सन्तुलन होने में भी कोई विशेष लाभ न हुआ। हमारी शोधनाधिक्य की समस्या

कुछ समय तक तो सुधरी परन्तु इसके पश्चात् जब हमारी साध समस्या गम्भीर होती गई तब यह समस्या पहले से भी गम्भीर हो गई ।

अवमूल्यन का प्रभाव देश पर यह हुआ कि उसके कारण बहुत सी चीजों का मूल्य बहुत बढ़ गया और देश के उपभोक्ताओं को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा ।

रुपये का पुनर्मूल्यन—इस प्रकार हम देखते हैं कि रुपये के अवमूल्यन से हमको विशेष लाभ नहीं हुआ । यह बात तो ठीक है कि इस कारण हमारे निर्यात में कुछ वृद्धि हुई पर इस दर के द्वारा देश को जो हानि हुई वह लाभ से कहीं अधिक है । इस कारण देश के अन्दर प्रायः सभी चीजों का मूल्य बढ़ गया जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी हानि हुई । पाकिस्तान तथा दूसरे दुर्लभ मुद्रा वाले देशों से व्यापार करने में हानि हुई । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया हुआ ऋण रुपये के रूप में बढ़ गया और इसी प्रकार से कई तरफ हानि हुई । इसी कारण देश के कुछ लोग जिनमें डा० जोन मेथार्ड, भूतपूर्व वित्त मन्त्री भी सम्मिलित हैं, यह कहते हैं कि रुपये का पुनर्मूल्यन होना चाहिये जिससे कि यह सब हानि दूर सके । डा० मेथार्ड ने पुनर्मूल्यन के निम्नलिखित लाभ बताये हैं—

(१) इससे हमें विदेशों से मँगाये हुये गन्ने के कम दाम देने पड़ेंगे ।

(२) इससे हमें व्यापार में थोड़ा सा लाभ होगा ।

(३) इसके कारण हमारी शोधनाविवय की स्थिति किसी-प्रकार भी खराब न होगी ।

(४) यद्यपि चुँगी आदि से कम आय होगी तो भी यह कमी खर्च में भी कमी होने से पूरी हो जायेगी ।

डा० मेथार्ड का कहना है कि जो लोग यह कहते हैं कि आजकल की ससार में होने वाली गड़बड़ के कारण कोई ऐसा कार्य न करना चाहिये, उनको यह समझना चाहिये कि गड़बड़ के कारण हमें पुनर्मूल्यन के प्रश्न को खटाई में नहीं डालना चाहिये वरन् इसी कारण हमें शीघ्र कदम उठाना चाहिये । इसके साथ ही साथ डा० मेथार्ड का कहना है कि अभी हाल ही में शान्ति की कोई आशा दिखाई नहीं पड़ती । इस कारण हमें चाहिये कि हम इस बात की बाट न देखें कि दूसरे देश क्या करते हैं क्योंकि जो वे करेंगे वह हमारे लिये किसी प्रकार भी उपयोगी न होगा वरन् हम अपनी परिस्थिति को देखते हुये जो कदम उठावेंगे वही हमारे लिये उपयोगी सिद्ध होगा ।

अभी हाल ही में इस देश में इस बात की बड़ी चर्चा थी कि रुपये का फिर से अवमूल्यन किया जाय । परन्तु सरकार इस बात के पक्ष में नहीं है । उसका कहना है कि रुपये की स्थिति बहुत मजबूत है और यह हो सकता है कि कुछ दिनों में यह दुर्लभ मुद्रा हो जाय । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री जेकबसन ने १५ फरवरी १९५८ ई० को बम्बई में कहा कि वर्तमान मुद्रातान

आधिव्यय की समस्या को सुलझाने का ठीक ढंग यह नहीं है कि रुपये का अवमूल्यन किया जाय। उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में कहा, “आपको मामले की जड़ में जाना चाहिये। आप को साख समस्या तथा अन्तर्राष्ट्रीय खर्च के प्रश्न को सुलझाना चाहिये बजाय इसके कि आप विनिमय दर के आर्जी पहलू को छुएँ।” उन्होंने आगे कहा “कि मैं अवमूल्यन को दूर करना चाहूँगा। यदि कोय एक बार अवमूल्यन का सहारा लेगे तो जब दूसरी बार इसी प्रकार की कठिनाइयाँ आयेंगी तो सोय दूसरे अवमूल्यन की आशा करेंगे और आप एक अवमूल्यन से दूसरे पर जायेंगे और लोगों का मुद्रा पर से विश्वास उठ जायगा।”

O. 89. What are the causes of the Foreign Exchange crisis in India ? How can it be solved ?

— प्रश्न ८९—भारत में विदेशी विनिमय संकट के क्या कारण हैं ? यह कैसे दूर किया जा सकता है ?

संकट का अनुमान—संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अपना तीन सप्ताह का दौरा समाप्त करने के पश्चात् श्री बी० के० नेहरू भारतीय वित्त सचिव ने प्रेस रिपोर्टों से कहा कि भारतीय भुगतानाधिक्य वमी १० मिलियन डालर प्रति सप्ताह की गति से चल रही है और यदि देश ने वर्तमान अर्थ-व्यवस्था तथा पञ्च-वर्षीय योजना को कायम रखे तो इसके रिजर्व इस वर्ष के अन्त तक समाप्त हो जायेंगे। इस कारण १९५८ के समाप्त होने के पूर्व कुछ भुगतानाधिक्य सहायता की चर्ची आवश्यकता है। श्री नेहरू ने बताया कि वर्तमान में भारत के रिजर्व ४३० मिलियन डालर (लगभग २ ५० मिलियन रुपये) हैं। भारत के सामने अब या तो यह छांट है कि वह कहीं से ऋण ले या वह आयात को काटकर अपनी अर्थ-व्यवस्था को भुखो मार दे।

भारतवर्ष की विदेशी विनिमय की स्थिति १९५८-५९ में कुछ अच्छी रही क्योंकि इस वर्ष हमने अपने विदेशी विनिमय के साधनों में से केवल ४७ करोड़ रु० ही खर्च किये जबकि १९५७-५८ में २६० करोड़ रु० तथा १९५६-५७ में २२१ करोड़ रु० खर्च किये गये। परन्तु १९५९-६० में एक बड़ी खाई होने की आशा है तथा भविष्य में और भी अधिक होने की आशा है।

संकट का कारण—वर्तमान संकट का कारण जानने के लिये हमको लघुकालीन व दीर्घकालीन दोनों प्रकार के कारणों को देखना पड़ेगा। लघुकालीन कारणों में हमारे हाल ही में किये गये बहुत अधिक आयात हैं। हमारे देश में हाल में इतने अधिक आयात व इतने कम निर्यात किये कि उसके कारण हमारा संकट बढ़ता चला गया। अगले दो वर्षों में हमको बहुत सी आयात का घन चुकाना है। यहाँ तक कि अप्रैल १९५९ से पहले हमको लगभग ३०० करोड़ रु०

का भुगतान करना पड़ेगा । इस कमी को विदेशी श्रमों द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे कुछ विशिष्ट कार्यों के लिये दिये गये हैं । आजकल हमारे विदेशी विनिमय के साधन इतने कम हो गये हैं कि हम उनको और कम करने का साहस नहीं कर सकते ।

भारत ने पिछले दो वर्षों में १२५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष गल्ला विदेशों से खरीदा । परन्तु योजना में धारणा की गई थी कि हम केवल ४८ करोड़ प्रति वर्ष गल्ला खरीदेंगे । इसके अतिरिक्त पिछले दो वर्षों में उत्पादन को बढ़ाने के लिये भारत ने बहुत सा कच्चा माल विदेशों से खरीदा । इसके अतिरिक्त हमारे देश में मशीनों का आयात भी बहुत बढ़ गया है । इन तीनों प्रकार की आयात का भुगतान करने के लिये भारत ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये बहुत से प्रयत्न किये । उदाहरण के लिये भारत ने बहुत सी Export Promotion Councils स्थापित की, विदेशी बाजारों को ढूँढ़ने का प्रयत्न किया गया, आयात कर में परिवर्तन किया गया आदि । परन्तु इसके होते हुए भी हमारे निर्यात बहुत अधिक न हो सके । इसका कारण यह है कि भारत को कच्चा माल निर्यात करने में कुछ साधारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ना है तथा कुछ घरेलू कठिनाइयाँ भी हैं । घरेलू कठिनाइयों में घरेलू बाजारों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य का अधिक होना, उनकी देश में अधिक माँग होना आदि हैं । उदाहरण के लिये भारत विदेशों को चीनी व खाने का तेल भेज सकता है परन्तु चीनी का मूल्य देश में ही इतना है कि व्यापारी उसको निर्यात करना नहीं चाहते । इसके अतिरिक्त खाने के तेल की देश में इतनी कमी थी कि पिछले वर्षों में उसके निर्यात पर पूरी पाबन्दी थी । निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये देश के लोगों से यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे अपने जीवन स्तर को घटा दें क्योंकि भारतवासियों का जीवन स्तर पहले ही बहुत नीचा है । इस प्रकार भारत से निर्यात का अवसर कम है । इसी कारण निकट भविष्य में हमारे देश में विदेशी विनिमय का संकट रहने वाला है । हाँ, यदि हमको कुछ विदेशी सहायता मिल गई तो भले ही यह संकट कुछ समय के लिये टल जाय, सदा के लिये नहीं टल सकता ।

परन्तु यह बात ध्यान रखनी आवश्यक है कि विदेशी विनिमय का संकट केवल लघुकालीन ही नहीं है बल्कि दीर्घकालीन भी है । भविष्य में जब तक भारत अपनी उन्नति की योजनायें बनाता रहेगा तब तक उसको विदेशों से मशीनों आदि का आयात करना पड़ेगा । इस सब आयात का भुगतान करना देश की नीति से सम्भव नहीं है । इसी कारण दीर्घकाल में भी संकट होने की आशा है । श्री पी० एम्० लोकराज्यन ने अपने एक लेख में कहा है कि भारतीय विदेशी विनिमय संकट के विषय में आवश्यकतानुसार बात यह नहीं है कि इसने इतनी घोर इतना भयानक रूप धारण कर लिया बल्कि यह है कि यह इतनी देर में आया ।

१९५१ ई० में जब प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी^१ तब यह अनुमान

लगाया था कि भारत के विदेशी विनिमय के साधनों में से २६० करोड़ रुपये निकालने पड़ेंगे। परन्तु प्रथम योजनाकाल में चालू विपरीत व्यापारी आधिक्य इतना कम था कि केवल १२१ करोड़ रुपये ही निकालने पड़े। इस प्रकार हमारे विदेशी विनिमय का रिजर्व ७५६ करोड़ रुपये रह गया था। प्रथम योजनाकाल में कम विपरीत व्यापारिक आधिक्य होने का कारण यह था कि मानसून के अच्छा होने के कारण फसल अच्छी हो गई। इस कारण हमको विदेशों से गल्ला व कच्चा सामान मँगाने की कम आवश्यकता पड़ी। इसके अतिरिक्त प्रथम योजनाकाल में न तो सोहे व फोलाद तथा अन्य भारी उद्योगों की स्थापना की गई और न गैर-जल्दारी चीजों का आयात किया गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रथम योजना काल में उतना खर्च नहीं किया गया जितना कि सोचा गया था। इसके अतिरिक्त हमने अमेरिका से गेहूँ का ऋण मिला व कालम्बी योजना देशों से भी बहुत सी सहायता मिली। इन सशर्त बातों के कारण उस काल में हमारे चालू व्यापारिक आधिक्य की खाई कम हो गई थी। इस कारण हमको भविष्य भी उज्ज्वल दिखाई पड़ने लगा।

दूसरी योजना में अनुमान लगाया गया था कि योजना के प्रथम वर्ष में २०० करोड़ रुपये के, दूसरे वर्ष में ६०० करोड़ रुपये तथा तीसरे वर्ष में १००० करोड़ रुपये के आयात किये जायेंगे तथा उस काल के गश्चात् के दो वर्षों में ८०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष के आयात किये जायेंगे। इस प्रकार योजनाकाल का योग ४३४० करोड़ रुपये खर्चा गया था। इसके विपरीत निर्यात से ६०० करोड़ रु० प्रति वर्ष प्राप्त करने का अनुमान था। इस प्रकार ५ वर्षों का योग ३००० करोड़ रु० था। यह भी अनुमान लगाया था कि इस बीच २२५ करोड़ रु० के अतिरिक्त विनियोजन (Investments) किये जायेंगे। इस प्रकार विदेशी विनिमय में ११०० करोड़ रु० की कमी का अनुमान था।

परन्तु योजनाकाल में किये गये अनुमान ठीक सिद्ध न हुये क्योंकि १९५६-५७ में ७०० करोड़ की अपेक्षा १०७७ करोड़ रुपये के आयात किये गये १९५७-५८ में ६०० करोड़ की अपेक्षा ११७५ करोड़ रुपये के आयात किये गये। इसके विपरीत इन दो वर्षों के निर्यात क्रमशः ६३७ करोड़ रुपये और ५७५ करोड़ रुपये थे। इस प्रकार देश में विदेशी विनिमय के साधनों में एक बड़ी खाई खड़ी हो गई। इस प्रकार योजना के पहले दो वर्षों में रिजर्व बैंक में से ७७६ करोड़ रु० की विदेशी विनिमय खर्च हो गई। अप्रैल १९५८ के प्रारम्भ में रिजर्व बैंक के विदेशी विनिमय के साधन ४७६ करोड़ रु० थे। परन्तु जून १९५८ ई० के अन्त तक लगभग २१८ करोड़ रु० के तथा जलाई १९५८ के तीसरे सप्ताह तक लगभग २०० करोड़ रु० के साधन थे। आजकल हम बड़ी भयानक परिस्थिति में हैं और यदि इसी गति से हमारे विदेशी विनिमय के साधन कम होते रहे तो १९५८ ई० के अन्त तक वे प्रायः समाप्त हो जायेंगे।

परन्तु जहाँ हमारे सामने यह निराशाजनक स्थिति है वहाँ कुछ आशाजनक बातें भी दिखाई पड़ती हैं। अभी विदेशों में विशेषतः अमेरिका, इंग्लैंड आदि में यह बात अनुभव की जा रही है कि भारत को अधिकाधिक सहायता दी जाय। इसके फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों में हमको ४३८ करोड़ रुपये की विदेशी सहायता प्राप्त हो गई है और आशा है कि अगले दो वर्षों में हमको ६०० करोड़ रु० की सहायता प्राप्त हो जाय। परन्तु फिर भी लगभग ४०० करोड़ रु० की आवश्यकता पड़ेगी।

परन्तु योजना के भार के अतिरिक्त अगले कुछ वर्षों में हमारे ऊपर विदेशी ऋण को चुकाने का भार पड़ने वाला है। यह ऋण इस प्रकार चुकाया जायगा। १९५८-५९ में २३ करोड़ रु०, १९५९-६० में ३५ करोड़ रु०, १९६०-६१ में ६२ करोड़ रु०, १९६१-६२ में १२२ करोड़ रु०, १९६२-६३ में १०७ करोड़ रु०, १९६३-६४ में ४८ करोड़ रु० तथा १९६४-६५ में ३५ करोड़ रु०। इसके अतिरिक्त तीसरी योजना काल में भी विदेशी विनिमय की बहुत आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि इस योजना में भी भारी उद्योगों के ऊपर ही अधिक जोर दिया जायगा। इस कारण ऐसी आशा है कि अगले कुछ वर्षों में हमारी विदेशी विनिमय के साधनों की आवश्यकता ६०० करोड़ रु० प्रति वर्ष होगी परन्तु इन साधनों को न तो हम अपने आयात कम करके और न अपने निर्यात बढ़ाकर पूरे कर सकते हैं। इस कारण हमको विदेशी सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा।

कुछ सुझाव—वैसे तो भविष्य में हमको विदेशी विनिमय के सकट रहने की आशा है तो भी हम स्थिति का मुकाबला करने के लिये कुछ सुझाव दे सकते हैं—

(१) चीनी, तेल, सूती कपड़े आदि के निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाय।

(२) आयात को कम किया जाय। इसके लिये हमको जहाँ तक सम्भव हो अपने उपभोग को कम करना चाहिये। परन्तु उद्योगों में काम आने वाले बच्चे माल के आयात को कम नहीं करना चाहिये।

(३) कृषि की उन्नति की जाय और इस प्रकार कृषि पदार्थों का आयात कम कर दिया जाय।

(४) विदेशी पूँजी के विषय में एक ऐसी नीति रखी जाय जिससे कि वह अधिकाधिक मात्रा में देश में लगाई जा सके। श्री पी० सी० जैन का सुझाव है कि जहाँ तक हो विदेशी निजी पूँजी को देश में आने का प्रोत्साहन दिया जाय। यह तब आ सकती है जबकि वह अपने आप की सुरक्षित समझे।

(५) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय। यह तभी हो सकता है जब कि हमारी लागत विदेशों से कम हो। लागत को कम करने के लिये सरकार को चाहिए कि वह निर्यात करने वाले उद्योगों पर कोई कर न लगावे। मजदूरी की मजदूरी अगले कुछ वर्षों में न बढ़े परन्तु मजदूर अपनी पूरी शक्ति लगा कर कार्य करें।

(६) कम अवधि वाले ऋणों को दीर्घ अवधि वाले ऋणों में बदला जाय ।

(७) तीसरी योजना को दो भागों में बाँटा जाय । एक भाग को प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता से सम्बन्धित रक्खा जाय तथा दूसरे भाग को उससे सम्बन्धित न किया जाय । दूसरे भाग में केवल वही कार्यक्रम रखे जायें जो विदेशी सहायता प्राप्त न होने पर किये जा सकें । परन्तु यदि वह प्राप्त न हो तो उससे पहले भाग की योजनाओं को कोई हानि न हो ।

(८) देश में इस प्रकार का प्रचार किया जाय कि लोग अपना छुग हुआ सोना जिसका अनुमान ३००० करोड़ रु० सोना व २००० करोड़ रु० चाँदी है, देश के हित के लिये दे सकें ।

इन सब बातों के करने से शायद विदेशी विनिमय का संकट कुछ कम हो सकता है ।

भारतीय बैंकिंग

इसमें निम्नलिखित प्रकार के बैंक सम्मिलित हैं—

(१) देशी बैंक व महाजन, (२) सहकारी साख समितियाँ, (३) भूमि बैंक बैंक, (४) औद्योगिक बैंक, (५) व्यापारिक बैंक, (६) विनिमय बैंक, (७) स्टेट बैंक, (८) रिजर्व बैंक ।

इनमें से पहले चार बैंकों के विषय में उनके यथास्थान पर लिखा जा चुका है । इस कारण हम दोष चार बैंकों का ही इस अध्याय में वर्णन करेंगे ।

Q. 90 What business do Ind an Joint Stock Banks transact ? What are their difficulties and defects ? Give suggestions for their improvement. Why have they not been nationalized ?

प्रश्न ९०—भारतीय व्यापारिक बैंक क्या कार्य करते हैं ? उनकी क्या कठिनाइयाँ तथा दोष हैं ? उनको उन्नत करने के सुझाव दीजिए । उनका राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया ?

भारतीय व्यापारिक बैंक भारत के व्यापार तथा उद्योग वर्गों के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं । वे अपने हिस्से देवकर जनता से धन एकत्र करते हैं । इसके अतिरिक्त इन बैंकों का मुख्य कार्य जनता से स्याही, चालू, दफ्त तथा मोलक खातों के लिए जमाय आकर्षित करना है । इन जमाओं पर ये बैंक ब्याज भी देते हैं परन्तु चालू खातों पर ब्याज की दर स्थायी खातों की अपेक्षा बहुत ही कम होती है ।

जनता से लिये हुए धन को यह बैंक नही पड़ा रहने देते । उसको यह भिन्न-भिन्न प्रकार से लगा देते हैं । परन्तु धन लगाते समय वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी अधिक से अधिक आय हो परन्तु यह बात भी ध्यान रखते हैं कि उनका रुपया मारे जाने का भय न हो । इस प्रकार अपने कुल धन का २० प्रतिशत नकद कोष, सोने तथा अन्य प्रथम श्रेणी के सिक्योरिटीज में रखते हैं । इसके अतिरिक्त अपनी मौज्जा जमाओं का ५ प्रतिशत तथा अपनी समाविधि जमाओं का २ प्रतिशत ये रिजर्व बैंक के पास रखते हैं । ऋण को ये ऋण-पत्रों, भिन्न-भिन्न प्रकार के ऋणों आदि में लगा देते हैं । ऋण के बदले जो धरोहर वे लेते हैं वह ऐसी होती है जो बाजार में बिना कठिनाई के शीघ्रतातिसीघ्र बिक जाये । ये बैंक थोड़े समय के लिए ही ऋण देते हैं । अधिकतर व्यापारी लोगों को ही ऋण देते हैं । उद्योग-पतियों को जो ऋण दिया जाता है वह भी उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए थोड़े समय के लिए ही दिया जाता है ।

इन कार्यों के अतिरिक्त वे और भी बहुत से कार्य करते हैं, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजना, अपने ग्राहकों को अर्थ सम्बन्धी सलाह देना, उनके लिये हिस्से तथा सरकारी ऋण-पत्र बेचना तथा खरीदना आदि ।

भारतीय व्यापारिक बैंकों की कठिनाइयाँ

व्यापारिक बैंकों से भारतवर्ष को काफी लाभ हुआ परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण ये अधिक उन्नति न कर सके । ये कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं—

(१) इन बैंकों को न तो केन्द्रीय सरकार की ओर से ही कोई सहयोग तथा प्रोत्साहन मिलता है और न प्रांतीय, रियासती तथा स्थानीय सरकारों ने ही अपना लेन-देन इनसे रक्खा है ।

(२) विदेशी विनिमय बैंकों का कार्य बन्दरगाहों तक ही सीमित न रहा वरन् उनकी शाखाएँ देश के भीतर भी खुल गईं जिससे इन बैंकों के साथ भारतीय बैंकों की प्रतियोगिता बढ़ गई ।

(३) भारत का अधिकतर व्यापार विदेशियों के हाथ में रहने के कारण भारतीय व्यापारिक बैंकों को अधिक कार्य नहीं मिलता क्योंकि विदेशी लोग विदेशी बैंकों से अपना सम्बन्ध रखते हैं ।

(४) विदेशियों के अतिरिक्त वे भारतवासी भी जिनपर विदेशियों का प्रभाव है भारतीय व्यापारिक बैंकों से अपना सम्बन्ध नहीं रखते ।

(५) भारतीय बैंकों को राज्य बैंकों से भी बड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ी जिसके कारण इनको बड़ी हानि होती है ।

(६) भारतवर्ष में अवलम्बित सम्पत्ति के कुछ ऐसे नियम बने हुए हैं जिनके कारण व्यापारिक बैंक उनमें अपना रुपया नहीं लगा सकते । इसके कारण साख बढ़ाने में बड़ी कठिनाई आती है ।

(७) उनके पास कार्यशील पूँजी की भी कमी रहती है । इसलिए उनको जनता की जमाओं को आकर्षित करने के लिये अधिक व्याज देना पड़ता है और इसलिए उनको हानि होती है ।

व्यापारिक बैंकों के कार्य के दोष

(१) इस देश में अभी तक व्यापारिक बिलों का विकास न होने के कारण साख सृजन में बड़ी बाधा पड़ती है । बिलों का विकास नकद साख (Cash credit) तथा अधिकार-पत्रों (Documents of title) के अभाव के कारण न हो सका ।

(२) हमारे देश में व्यक्तिगत साख (Personal credit) के रिवाज बहुत कम हैं । इसके कई कारण हैं, जैसे भारत में इंग्लैंड की साइड्स (Seyd's) तथा समुक्त राष्ट्र की डन्स (Dun's) और ब्रेडस्ट्रीट (Bradstreet) जैसे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना देने वाली संस्थाओं का अभाव, इम्पीरियल बैंक और भारत

कम्पनीज एक्टस में सुरक्षित तथा अमुरक्षित ऋणों को अलग-अलग दिखाने की पद्धति और व्यक्तिगत धरोहर पर दिये हुये ऋण को अमुरक्षित ऋण मानता ।

(३) व्यापारिक बैंक अपना अधिकतर कार्य अंग्रेजी भाषा में करते हैं जिसको जन साधारण नहीं समझता ।

(४) इनका संचालन व्यय बहुत अधिक होता है क्योंकि यह राज्य बैंक जैसा बटिया फर्नीचर तथा दूसरा सामान रखते हैं ।

(५) बहुत से बैंकों के डाइरेक्टर अयोग्य होते हैं जिसके कारण जनता का उनपर विश्वास नहीं होता ।

(६) ये बैंक कई बार दूसरे बैंकों से प्रतियोगिता की भावना से अपने लाभ का एक बड़ा भाग लाभार्थ के रूप में बांट देते हैं ।

(७) इन बैंकों में आपस में विलुप्त सहयोग नहीं है और वे एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं ।

(८) इस देश में अभी तक निवासी गृहों की उन्नति नहीं हुई है ।

दोषों को दूर करने के सुझाव

(१) सरकार को चाहिये कि वह व्यापारिक बैंकों के साथ भी उसी प्रकार की नम्र नीति का व्यवहार करे जिस प्रकार कि वह सहकारी बैंकों के साथ करती है ।

(२) बैंकों की प्रतियोगिता को कम करने के लिये केन्द्रीय बैंडिंग जांच कमेटी तथा विदेशी विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया था कि इस देश में एक अखिल भारतीय बैंक संघ होना चाहिये जो कि प्रतियोगिता को कम करने का प्रयत्न करे ।

(३) केन्द्रीय जांच कमेटी ने यह सुझाव भी दिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को चाहिये कि वह व्यापारिक बैंकों द्वारा उच्च स्थानों पर खोली हुई, जहाँ पर बैंक नहीं हैं, शाखाओं को पाँच रुप तक अधिक सहायता दे तथा उनका अपना एक स्थान से दूसरे स्थान को सस्ती दर पर हस्तान्तरित करे तथा उनके रिजर्वों की सुविधा दे तथा नकद साख के स्थान पर विलो को उन्नत करे ।

(४) भारत के अखिल सम्पत्ति के नियमों में परिवर्तन हो जिससे बैंक अपना धन उनमें भी लगा सकें ।

(५) बैंकों को चाहिये कि वे व्यक्तिगत साख पर ध्यान दें और ग्राहकों की आर्थिक स्थिति की जांच करने के लिये अखिल भारतीय बैंक संघ की स्थापना की जाये ।

(६) बैंकों को चाहिये कि वे अपने ग्राहकों को स्थानीय भाषा के प्रयोग करने की स्वतन्त्रता दें ।

(७) बैंकों को यह भी चाहिये कि वे विभिन्न बैंकों के समान कार्य-कुशल हों तथा देशी बैंकों के समान सारे हों ।

(८) यह भी आवश्यक है कि बैंकों के कार्य करने का समय भारतीय परिस्थिति के अनुसार हो ।

(९) जनता में इस बात का प्रचार किया जाये कि वह भारतीय बैंकों को अपनाये ।

इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं किया गया

१९५६ ई० के सालाना अधिवेशन में लोक सभा में एक कांग्रेसी सदस्य ने एक बिल पेश किया था जिसमें कि व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की गई थी । परन्तु यह बिल पास न हो सका ।

जो लोग राष्ट्रीयकरण के पक्ष में हैं उनका कहना है कि इन बैंकों की अपार धन-राशि निजी हाथों में होने के कारण देश की विकास योजनाओं में लाभदायक ढंग से नहीं लगाई जाती । दूसरी बात वे यह कहते हैं कि इन बैंकों को होने वाला ३० करोड़ रु० वार्षिक का लाभ फिर से उन्नति के काम में लगाया जा सकता है यदि ये बैंक सरकार के हाथ में हों ।

परन्तु इसके विरुद्ध सरकार का कहना है कि रिजर्व बैंक का इन बैंकों पर इतना नियन्त्रण है कि वे अपने साधनों को अनुचित ढंग से खर्च नहीं कर सकते । बैंकिंग कम्पनीज (सशोधित) एक्ट के अन्तर्गत इस नियन्त्रण को और भी कड़ा कर दिया गया है । पहले रिजर्व बैंक प्रत्येक बैंक की जाँच तीन वर्ष में एक बार कर सकता था परन्तु आजकल वह दो वर्ष में कर सकता है तथा भविष्य में वह प्रतिवर्ष कर सकेगा ।

सरकार का यह भी कहना है कि जीवन बीमा कम्पनियों के समान वर्तमान बैंक अपने साधनों का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे ।

इस समय राष्ट्रीयकरण का विचार स्थगित करने का कारण यह भी है कि ऐसा करने से सरकार के सामने जीवन बीमा के समान वमचारियों तथा अवस्था की समस्या आकर खड़ी हो जायगी । आजकल इन बैंकों के ३७५० आफिस हैं तथा भविष्य में और अधिक खुलने की आशा है । सरकार का मत है कि इन सबको अपने हाथ में लेने से राष्ट्र की शक्ति की बर्बादी होगी ।

इस के अतिरिक्त आजकल व्यापारिक बैंकों के कुल साधनों का ३ राज्य बैंक के हाथ में है तथा भविष्य में जब इस के साथ पहली रियासतों के कुछ बैंक मिला दिये जायेंगे तब इसके साधन और भी बढ़ जायेंगे ।

इन सबके अतिरिक्त एक राजनीतिक कारण भी है कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से विनिमय बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण करना होगा परन्तु ऐसा करना आजकल की परिस्थिति में उचित नहीं है । इन सब बातों के कारण सरकार इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना नहीं चाहती ।

Q. 91. Describe the business transacted by the Exchange Banks in India. What criticisms have been levelled against them ?

प्रश्न ९१—भारत में विनिमय बैंक क्या करते हैं ? उनके विरुद्ध क्या आलोचनाएँ की गई हैं ?

भारत के विदेशी व्यापार पर विनिमय बैंकों का एकाधिकार है, ये बैंक सबके सब विदेशी हैं और उनके प्रधान कार्यालय विदेशों में हैं। भारत के विदेशी बैंक व्यापार को ही आर्थिक सहायता नहीं पहुँचाते वरन् भारत के आन्तरिक व्यापार को भी आर्थिक सहायता पहुँचाते हैं। १९५१ के अन्त तक भारत में विदेशी बैंकों की संख्या २० थी जिनमें से एक ने कार्य करना छोड़ दिया, एक को बैंकिंग का कार्य न करने के लिये कह दिया गया। शेष में से ५ पाकिस्तानी, ७ अंग्रेजी (जिनकी भारत में ४९ शाखाएँ हैं), २ संयुक्त राष्ट्र के (जिनकी भारत में ३ शाखाएँ हैं), २ हावर्ड के (जिनकी भारत में ४ शाखाएँ हैं), १ चीन का तथा १ फ्रांस का (जिसकी भारत में दो शाखाएँ हैं)—इस प्रकार कुल १८ बैंक हैं। ये बैंक अधिकतर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा कोचीन के बन्दरगाहों पर स्थित हैं। भारत की बैंकिंग प्रणाली में विदेशी बैंकों का क्या स्थान है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि १९५१ ई० में इनमें जनता की जमा १७५ करोड़ रुपये थी, जो कि कुल बैंकों में जमा किये हुये धन की १८ प्रतिशत थी तथा इनका लाभ ३ १६ करोड़ रुपये था जो कि कुल भारतीय बैंकों द्वारा कमाये हुये लाभ का लगभग ५० प्रतिशत था।

भारत के बैंकों ने अभी कुछ ही समय से विदेशी व्यापार की ओर ध्यान दिया है। इन बैंकों का कार्य अभी तक दक्षिणी-पूर्वी, एशिया, सुदूर पूर्व, पाकिस्तान, लका, ब्रह्मा घाईलैण्ड तथा जापान तक ही सीमित है।

विनिमय बैंकों के कार्य—

विदेशी बैंकों के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं—

(१) आयात-निर्यात की आर्थिक सहायता देना।

(२) सोने-चाँदी का विक्रय करना।

(३) विदेशी विनिमय बिलों का क्रय विक्रय करना।

(४) विदेशों को रुपया भेजने की सुविधा प्रदान करना।

(५) आन्तरिक व्यापार की आर्थिक सहायता पहुँचाना।

(६) अन्य साधारण बैंकिंग कार्य करना।

(१) आयात निर्यात की आर्थिक सहायता प्रदान करना, विनिमय बैंकों का मुख्य कार्य है। जब कोई भारतवासी विदेशों से माल का आयात करता है तो दो प्रकार के बिल भिजे जाते हैं—(१) भारतीय आयातकर्ता पर ९० दिन का देयन हार बिल (60 day's sight D. P. Bill), (२) लन्दन के साख कार्यालय पर लिखा हुआ बिल। पहली दशा में विनिमय बैंक आयातकर्ता से बिलों का धन एका

करता है। दूसरी दशा में लन्दन का निर्यात-वर्त्ता लन्दन के साख कार्यालय पर जिसके साथ कि भारतीय आयात वर्त्ता पहले ही साख का प्रबन्ध कर लेता है, एक बिल लिखता है। जिसकी कि यह स्वीकार कर लेता है। इस बिल को लन्दन का निर्यात-कर्त्ता यदि चाहे तो लन्दन के मुद्रा बाजार में बट्टे पर बेचकर धन प्राप्त कर सकता है। लन्दन स्थित बैंक उस बिल तथा उसके साथ लगे हुये बहुत से अधिकार पत्र जैसे जहाजी रसीद, समुद्री बीमे की रसीद, बीजक आदि भारत में स्थित अपनी शाखा के पास भेज देता है। भारत स्थित शाखा भारतीय आयात-कर्त्ताओं से अवधि समाप्त होने से पहिले ही रुपये वसूल करके लन्दन भेज देती है। इनमें से पहली दशा में बिल के लिखने की तिथि से रुपये के लन्दन पहुँचने तक व्यापारी को ६% व्याज देना पड़ता है। परन्तु दूसरी दशा में बिल कम व्याज पर लन्दन के मुद्रा बाजार में बट्टे पर बेच दिया जाता है। इस प्रकार दूसरी दशा में व्यापारी को लाभ होता है।

जब भारत के व्यापारी माल का निर्यात करते हैं तब वे ६० दिन के देखन-हार स्वीकार किये जाने वाले अथवा भुगतान किये जाने वाले बिल लिखते हैं। इस प्रकार बिलों को विनिमय बैंक सदा ही मोल ले लेता है। विनिमय बैंक इन बिलों को लन्दन भेज देता है जहाँ पर उनको लन्दन का बैंक अथवा साख गृह स्वीकार कर लेता है और वह लन्दन के मुद्रा बाजार में बट्टे पर विक्रि जते है। इस प्रकार लन्दन के बैंको को भारतवर्ष में दिये गये धन के बदले लन्दन के मुद्रा बाजार में स्टैलिम मिल जाती है। यदि निर्यातकर्त्ता अथवा बिल के बट्टे पर मोल लेने वाला बैंक चाहे तो बिल की अवधि समाप्त होने तक बाट देख सकता है और उसके बाद लन्दन के आयातकर्त्ता से उसका धन प्राप्त कर सकता है।

(१) इस प्रकार हम देखते हैं भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार स्टैलिम बिलों द्वारा किया जाता है और जब भारतवासी माल को आयात करते हैं तो उनके ऊपर ६० दिन के देखनहार भुगतान किये जाने वाले बिल लिखे जाते हैं परन्तु जब वे माल का निर्यात करते हैं तब उनकी विदेशी आयात-वर्त्ता पर ६० दिन के स्वीकार किये जाने वाले बिल लिखने पड़ते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि चाहे माल का आयात हो अथवा निर्यात दोनों दशाओं में लन्दन के मुद्रा बाजार में बिल विक्रि होते हैं और भारत के मुद्रा बाजार को किसी दशा में कोई लाभ नहीं पहुँचता।

(२) आयात-निर्यात को आर्थिक सहायता पहुँचाने के अतिरिक्त वे सीना-चाँदी भी खरीदते बेचते हैं। परन्तु द्वितीय महायुद्ध में जब से सोने के क्रय-विक्रय करने का कार्य रिजर्व बैंक को दिया गया है तब से इनका यह कार्य सीमित हो गया है।

(३) विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में लिखे गये बिलों का क्रय-विक्रय करना भी इन बैंकों का एक कार्य है। जब इन बैंकों के पास इस प्रकार के बिलों की सख्या बहुत अधिक हो जाती है तब ये उनकी रिजर्व बैंक को बेच देते हैं।

(४) विदेशी विनिमय बैंक बैंक ड्राफ्ट, विदेशी विनिमय बिलों तथा तार द्वारा विदेशी में धन भेजने का भी प्रबन्ध करता है।

(५) विदेशी विनिमय बैंक भारत के अन्तरिक व्यापारिक केन्द्रों से बन्दरगाहों तक तथा बन्दरगाहों से अन्तरिक व्यापारी केन्द्रों तक भी व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं।

(६) इन सब कामों के अतिरिक्त विदेशी विनिमय बैंक जनता से जमा के रूप में श्रृण लेते हैं, व्यापारियों को श्रृण देते हैं, बाउल का कार्य करते हैं तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक रकबा भेजते हैं।

विनिमय बैंकों के विरुद्ध की गई आलोचनाएँ—

भारत में विदेशी विनिमय बैंकों की बड़ी बड़ी आलोचना की गई है क्योंकि ये भारतीय तथा विदेशी व्यापारियों में भेदभाव करते हैं। इनके भेदभाव के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं—

• (१) भारतीय आयात कर्ताओं की भुगतान करने वाले बिलों (D. P. Bills) पर तथा विदेशी आयात कर्ताओं की स्वीकार करने वाले बिलों (D. A. Bills) पर व्यापार करना पड़ता है।

(२) परिमाणिक साख पत्र (Confirmed letter of credit) प्राप्त करने के लिये उत्तम श्रेणी के भारतीय व्यापारी गृहों को भी आयात किये हुये माल के कुल मूल्य का १०-१५ प्रतिशत विनिमय बैंकों के पास जमा करना पड़ता है जबकि इस प्रकार की जमा विदेशी लोगों को नहीं करनी पड़ती है।

(३) विनिमय बैंक भारत के बड़े व्यापारियों के विषय में भी विदेशी व्यापारियों को अच्छी सूचना नहीं देते जबकि निम्न श्रेणी के विदेशी व्यापारियों के विषय में अच्छी सूचना देते हैं।

(४) भारतीय व्यापारियों को यह नहीं बताया जाता कि विनिमय बैंक सब (Exchange Banks Association) किन नियमों के अनुसार कार्य करता है। उनको सघों के नियमों में जो समय-समय पर परिवर्तन होते रहते हैं उनकी सूचना भी नहीं दी जाती।

(५) जबकि किसी भारतीय आयात कर्ता का ड्राफ्ट विनिमय बैंक के द्वारा आता है तो उसकी सूचना भेज दी जाती है कि वह बाकर उस ड्राफ्ट का निरीक्षण से। परन्तु विदेशी व्यापारी को उसके कार्यालय पर ही वह ड्राफ्ट भेज दिया जाता है।

(६) ये बैंक यद्यपि भारतवर्ष से प्रतिवर्ष इतना लाभ कमाते हैं तो भी वे भारत के लोगों को ऊँचे पदों पर नियुक्त नहीं करते।

इन भेदभावों के अतिरिक्त विनिमय बैंकों के विरुद्ध कुछ और आलोचनाएँ भी की जाती हैं जो निम्नलिखित हैं—

(१) १९४६ के बैंकिंग एक्ट से पूर्व इन बैंकों पर भारत का कोई बैंकिंग कानून लागू न था।

(२) इन बैंको ने भारतवासियों की जमा राशि के आधार पर भारतीय विदेशी व्यापार की आर्थिक व्यवस्था करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। 'इस घन राशि का लाभ अधिकतर विदेशी मुद्रा बाजारों को हुआ, भारतीय मुद्रा बाजार को न हुआ।

(३) इन बैंको ने भारतीय मुद्रा-बाजार को दो भागों में विभाजित कर दिया है। एक देशी द्रव्य बाजार जिसमें भारतीय बैंक, भारतीय दलाल तथा भारतीय बीमा कम्पनियाँ कार्य करती हैं तथा दूसरा विदेशी द्रव्य बाजार जिसमें विदेशी विनिमय बैंक, विदेशी दलाल तथा विदेशी बीमा कम्पनियाँ कार्य करती हैं। इन दोनों में गला काटने वाली प्रतियोगिता रहती है और इसमें भारतीय मुद्रा बाजार को हानि होती है क्योंकि उनके साधन सीमित हैं।

(४) इन बैंको ने भारत की राजनीतिक तथा आर्थिक उन्नति में अनेकों बार रोड़े अटकाये।

(५) अभी तक ये बैंक भारत में आय कर भी नहीं देते थे।

(६) ये बैंक अपने भारतीय तथा विदेशी व्यापार की सूचना अलग-अलग नहीं छापते जिससे उनके व्यापार के विषय में कोई पता नहीं चल सकता।

इन सब दोषों को दूर करने के लिये भारतीय बैंकिंग जाँच कमेटी ने निम्न-लिखित सुझाव दिये—

विदेशी बैंको को भारत में कार्य करने के लिये एक अनुज्ञापत्र (Licence) लेना चाहिये ताकि उनके कार्य के ऊपर नियन्त्रण किया जा सके। इस आज्ञा पत्र की शर्तों में निम्नलिखित बात हो सकती है—

(१) केवल उन बैंकों को ही भारत में जमा आकर्षित करने की आज्ञा दी जाए जिनकी शेयर पूंजी रुपये में हो।

(२) विदेशी बैंको को देश के अतिरिक्त भागों में शाखाएँ खोलने की आज्ञा न दी जाए।

(३) विदेशी बैंको को किसी भी भारतीय बैंक से नियन्त्रण करने वाले हाथ को प्राप्त करने का अवसर न दिया जाये।

(४) उनको ट्रस्टी कार्य करने की आज्ञा न हो।

(५) उनको बाध्य किया जाय कि वे कुछ ऊपर के लोगों को छोड़कर शेष कर्मचारी भारत के ही रखें।

(६) वे भारत में आय कर दें।

(७) उनको अपने कार्य की रिपोर्ट देनी चाहिये।

(८) उनको एकाधिकार प्राप्त करने के लिये रिंग, पूल आदि न बनाने दिये जायें।

(९) इन बैंको के कर्मचारी भारतीय हित के विरुद्ध कोई कार्य न करें।

इस कमेटी ने यह सुझाव दिया कि एक भारतीय विनिमय बैंक की स्थापना की जाय। रिजर्व बैंक के स्थापित होने पर यह कार्य इम्पीरियल बैंक को करने की

आज्ञा दी जाय । इसके अतिरिक्त एक नया विनियम बैंक स्थापित किया जाय, जिस की सेयर पूंजी ३ करोड़ रुपये हो । इसके अतिरिक्त एक नया विनियम बैंक स्थापित किया जा सकता है जिसका नियन्त्रण भारतवासियों तथा विदेशियों के हाथ में हो । धीरे-धीरे इस पर से विदेशियों को हटा दिया जाए और भारतवासियों को उनके स्थान पर रख दिया जाए ।

यद्यपि विनियम बैंको के विरुद्ध भारतवासी इतनी आलोचनाएँ करते हैं तो भी हम उनको एकदम नहीं हटा सकते क्योंकि अभी तक भारतवर्ष में कोई इतना बड़ा बैंक नहीं है जो इस कार्य को कर सके । इस कारण हमको इन बैंको को उस समय तक रखना पड़ेगा जब तक कि हमारा अपना बैंक न हो । इसी बीच में हम उनके कार्य पर नियन्त्रण कर सकते हैं जिससे कि वे भारतवर्ष के विरुद्ध कोई कार्य न कर सकें ।



Q 92 What changes were brought about by the Imperial Bank Amendment Act in the Constitution and function of the Imperial Bank Why was it not converted into a central Bank then and why has it been changed into a State Bank now ?

प्रश्न ९२ - इम्पीरियल बैंक संशोधित एक्ट द्वारा इम्पीरियल बैंक के विधान तथा कार्य में क्या परिवर्तन किये गये ? इसकी तब एक केन्द्रीय बैंक के रूप में क्यों नहीं बदला गया तथा उसको अब एक स्टेट बैंक क्यों बनाया गया है ?

इम्पीरियल बैंक की स्थापना इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट १९२१ के अन्तर्गत की गई । यह बैंक बम्बई, बंगाल तथा मद्रास के प्रेसीडेन्सी बैंको का एकीकरण करके स्थापित किया गया है । इसकी अधिकृत पूंजी ११½ करोड़ रुपये थी । यह ५०० रुपये के २,२५००० हिस्सों में विभाजित थी । इस पूंजी का आधा भाग तो प्राप्त किया जा चुका था और शेष को रक्षित दायित्व (Reserve liability) के रूप में रखा हुआ था ।

बैंक का प्रश्न—सन् १९३४ के इम्पीरियल बैंक संशोधित एक्ट से पूर्व इम्पीरियल बैंक का प्रबन्ध एक केन्द्रीय बोर्ड द्वारा होता था । इस बोर्ड के १६ गवर्नर थे जिनमें से १० की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती थी । इसके अतिरिक्त सरकार को बैंक का हिसाब जाँचने के लिये आडिटर नियुक्त करने तथा आदेश देने का भी अधिकार था ।

परन्तु १९३४ के संशोधित एक्ट के पास होने पर बैंक के ऊपर सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम हो गया । अब केन्द्रीय सरकार १६ में से केवल २ सदस्य ही नियुक्त कर सकती थी । इसके अतिरिक्त एक सरकारी अफसर भी जिसको मत देने का अधिकार न था, बोर्ड की बैठकों में भाग ले सकता था परन्तु ग्राम जीव कमेटी

१९५१ ने सरकार से सिफारिश की कि इस बैंक के ऊपर फिर कड़ा सरकारी नियन्त्रण किया जावे ।

बैंक के कार्य—१९२१ के एक्ट के अनुसार इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक के कुछ कार्य करता था जो निम्नलिखित हैं—

(१) सरकारी बैंक के कार्य—रिजर्व बैंक की स्थापना से पहले इम्पीरियल बैंक सरकारी बैंक का कार्य करता था । सरकार अपना धन बैंक में बिना व्याज के रखती थी । इसके बदले बैंक सरकार के ऋण, आय व्यय आदि का हिसाब रखता था और सरकार से कोई कमीशन न लेता था । सरकारी बैंक होने के कारण इस बैंक पर बड़ा कड़ा सरकारी नियन्त्रण था ।

(२) बैंकों के बैंक का कार्य—देश में कोई केन्द्रीय बैंक न होने के कारण व्यापारिक बैंक इम्पीरियल बैंक की ओर देखते थे । वे इस बैंक के पास अपना धन सुरक्षा के लिये रखते थे और आवश्यकता पड़ने पर उससे रुपया उधार भी लेते थे । इस बैंक के हाथ में किसानों गृहों का प्रबन्ध भी था ।

१९२१ ई० के एक्ट के अनुसार इस बैंक पर यह भार था कि वह प्रथम पाँच वर्षों में १०० शाखाएँ स्थापित करे ।

केन्द्रीय बैंक के इन कार्यों के अतिरिक्त इम्पीरियल बैंक एक साधारण बैंक का कार्य भी करता था । वह जनता से जमायें लेता था और ट्रस्टी, सरकारी तथा अन्य प्रकार की उत्तम श्रेणी की धरोहरों, ऋण-पत्रों, माल तथा माल के अधिकार पत्रों की जमानत पर छ मास के लिये ऋण दे सकता था । यह जनता के बिलों तथा अन्य प्रकार के पत्रों को लिख सकता था तथा उन्हें बट्टे पर मोल ले सकता था । इसके अतिरिक्त वह सोने चाँदी का क्रय-विक्रय भी कर सकता था । परन्तु इस बैंक के कार्य के ऊपर कुछ रुकावट भी थी जैसे यह बैंक देश के बाहर न तो जमायें ही ले सकता था और न ऋण ही ले सकता था । इसको विदेशी विनिमय का कार्य करने का भी अधिकार न था ।

१९३४ के संशोधन एक्ट के अनुसार इम्पीरियल बैंक न तो सरकारी बैंक ही रहा और न वह दूसरे बैंकों के लिये ही बैंक का कार्य करता था । परन्तु क्योंकि यह बैंक रिजर्व बैंक का एजेंट था और जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं थी वहाँ सरकारी कोष भी रखता था, इस कारण इस बैंक के कार्य पर कुछ सरकारी हस्तक्षेप था और उसको कुछ कार्य करने की आज्ञा नहीं थी, जैसे यह न तो अचल सम्पत्ति पर ऋण दे सकता था और न ही अपने हिस्सों की जमानत पर ऋण दे सकता था । यह बैंक किसी एक ऋण लेने वाले को एक निश्चित मात्रा से अधिक ऋण नहीं दे सकता था ।

इन पाबन्दीयों को छोड़कर बैंक और सब मामलों में स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य कर सकता था । इसको अब विदेशी विनिमय के प्राप्त करने का अधिकार मिल गया । यह अब विदेशों से ऋण ले सकता था तथा विदेशों में अपनी शाखाएँ खोल

सकता था। इसके ऋण देने की अवधि को भी ६ मास से बढ़ाकर ६ मास कर दिया गया। यह बैंक अब रिजर्व बैंक के हिस्से तथा नगरपालिकाओं के ऋण पत्रों पर भी ऋण दे सकता था। इसके अतिरिक्त यह व्यापारिक माल की जमानत पर ऋण दे सकता था।

बैंक को केन्द्रीय बैंक न बनाने के कारण—

जिस समय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई उस समय कुछ लोगों ने कहा कि इम्पीरियल बैंक को ही केन्द्रीय बैंक बनी न बना दिया जाय। परन्तु ऐसा न करने के बहुत से कारण थे जो नीचे दिये हैं—

(१) केन्द्रीय बैंक को एक विनाश राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखना चाहिये जिसकी आशा इम्पीरियल बैंक से न थी क्योंकि हिल्टन मग फमीशन को बहुत से बैंकों ने बताया कि इम्पीरियल बैंक उनकी सहायता नहीं करता।

(२) भारतीय बैंकों ने इम्पीरियल बैंक को सदा ही अपना प्रतिपक्षी समझा है। केन्द्रीय बैंक बनाने के पश्चात् भी ये बैंक इम्पीरियल बैंक को दूसरी दृष्टि से नहीं देख सकते।

(३) इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक बनाने पर इसकी बहुत सी छायाओं को बन्द करना पड़ता है। ऐसा करने से देश के व्यापार तथा उद्योग-धन्धों को बड़ा घबका लगता।

(४) इस बैंक के अधितर हिस्सेदार विदेशी थे जो भारतीय हितों के लिये कार्य नहीं कर सकते थे।

(५) इस बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना है परन्तु केन्द्रीय बैंक इस दृष्टिकोण से कार्य नहीं कर सकता।

(६) बहुत से विद्वानों का कहना था कि जब फ्रांस का बैंक केन्द्रीय तथा व्यापारिक बैंक का कार्य कर सकता है तब इम्पीरियल बैंक नहीं कर सकता। परन्तु सब देशों में परिस्थिति एक सी नहीं होती। यदि इस बैंक को केन्द्रीय बैंक के कार्य भी सौंप दिये जाते तो यह इतना शक्तिशाली हो जाता कि दूसरे बैंक इसके सामने न ठहर सकते थे।

(७) अन्त में यदि इस बैंक को केन्द्रीय बैंक में बदल दिया जाता और इसके लाभांश को कानून द्वारा सीमित कर दिया जाता तो इसके हिस्सेदार बभी पसन्द नहीं करते।

इन सब बातों के कारण इम्पीरियल बैंक को एक केन्द्रीय बैंक में नहीं बदला गया।

स्टेट बैंक—१९४८ ई० में जिस समय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसी समय केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य श्री बी० दास ने माँग की थी कि इम्पीरियल बैंक को सरकार अपने हाथ में ले ले परन्तु उस सरकार ने उस बात को टाल दिया। १९५१ ई० में रिजर्व बैंक ने एक निर्देशन समिति जिसको

गोरवाला समिति भी कहते हैं, नियुक्त की। इस समिति पर देश भर में ग्रामीण साख सम्बन्धी जाँच का कार्य भार सौंपा गया। जाँच के बाद इस समिति ने जो रिपोर्ट पेश की, उसमें बताया गया है कि इस समय ग्रामीण ऋण की आवश्यकता पूरी करने के जो साधन उपलब्ध हैं उनकी मात्रा अपर्याप्त है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में ग्रामीणों की कुल आवश्यकता का लगभग १३ प्रतिशत ऋण तो महाजनो व जमींदारों द्वारा दिया जाता है और शेष ७ प्रतिशत सरकार सहकारी समितियों तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा। यही कारण है कि ग्रामीण ऋण महंगा तथा अनुरपादक है। इस कारण इस समिति ने एक स्टेट बैंक बनाने का सुझाव दिया जो भारत के भिन्न भिन्न ग्रामों, कस्बों व जिलों में अपनी शाखाएँ खोलेगा। यह बैंक निम्नलिखित १० बैंकों को विलीन करके बनाया गया है—

(१) इम्पीरियल बैंक, (२) सोराष्ट्र राज्य बैंक, (३) पटियाला बैंक, (४) धौकानेर बैंक, (५) जयपुर बैंक, (६) राजस्थान बैंक, (७) बड़ौदा बैंक, (८) इन्दौर बैंक, (९) भेंसूर बैंक, (१०) त्रावनकोर बैंक।

इस बैंक की पूंजी को बढ़ाकर २० करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसमें से भारत सरकार व रिजर्व बैंक का भाग ५२ प्रतिशत होगा।

इस बैंक की स्थापना की घोषणा २० दिसम्बर १९५४ ई० को की गई तथा इसने १ जुलाई १९५५ से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

इस बैंक का मुख्य उद्देश्य समस्त देश में फ़ैली शाखाओं की एक सक्रिय मशीनरी बनाना है जिससे पूंजी जमा करने तथा ग्रामीण बैंकिंग की सुविधायें बढ़ाई जायें।

यदि यह बैंक अपने इस उद्देश्य में सफल हो गया तो भारतवर्ष की कृषि को बहुत लाभ होगा क्योंकि किसानों को कम ब्याज पर ऋण मिल सकेगा और वे महाजनो आदि के शोषण से बच जायेंगे।

इस बैंक का मुख्य उद्देश्य समस्त गाँवों में अधिकाधिक साख की सुविधायें प्रदान करना है। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिये इस बैंक पर यह जिम्मेवारी है कि वह ५ वर्ष में अथवा थोड़े-अधिक में सारे देश में ४०० शाखाएँ खोलेगा। प्रारम्भ में १०० शाखाएँ खोलने की योजना बनाई गई है। १ जुलाई १९५५ से ३१ दिसम्बर १९५६ तक इस बैंक ने ६६ शाखाएँ खोली। इनमें से ४६ शाखाएँ १९५६ में खोली गईं। इनके अतिरिक्त ५० तथा ३२ शाखाओं की लिस्ट सरकार ने और स्वीकार करली है। शाखाओं के खोलने में सबसे बड़ी बाधा यह है कि उनके लिये उचित स्थान नहीं मिलता।

इसके अतिरिक्त यह बैंक व्यापार तथा उद्योग धन्धों की भी बड़ी सहायता कर रहा है। दिसम्बर १९५६ तक इसने निजी क्षेत्र को १०० करोड़ ६० के ऋण दिए। इस प्रकार इस बैंक के राष्ट्रीयकरण से निजी क्षेत्र को कोई हानि नहीं पहुँची है।

यह बैंक विदेशी विनिमय कार्य को भी बढ़ा रहा है। इस क्षेत्र में भी इस बैंक ने बड़ी सफलता प्राप्त की है परन्तु इस कार्य को करने के लिये प्रशिक्षित लोगों की कमी एक बड़ी बाधा है।

इसके अतिरिक्त यह बैंक कृषि को भी साख प्रदान करने का प्रयत्न कर रहा है। परन्तु अभी तक इस कार्य में बहुत कम सफलता प्राप्त हुई है। यह बैंक सहकारी बैंकों को साधारण दर से २ प्रतिशत कम दर पर ऋण देता है। केन्द्रीय तथा राज्य बैंकों का धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कोई खर्च उससे नहीं लिया जाता। यह बैंक इस बात का भी प्रयत्न कर रहा है कि खेती को दीर्घ-कालीन ऋण दिये जाये। इस हेतु यह बैंक भूमि वन्धक बैंकों के ऋण-पत्र मोल लेता है तथा उनको बाजार में बेचने में सहायता करता है।

कुटीर उद्योगों की सहायता के लिये बैंक ने एक पायलेट योजना रखी है जिस पर बम्बई, बंगाल तथा मद्रास में कार्य होगा। इस योजना के अनुसार एक साधारण प्रार्थना-पत्र ईशू किया जाता है जिस पर ऋण लेने वाला अपनी कुल साख की आवश्यकता को बयान करता है। इसके पश्चात् प्रार्थना पत्र की जाँच करके यह निश्चित किया जाता है कि किसको ऋण दिया जाय तथा इस ऋण को राज्य सरकार दे अथवा राज्य अर्थ-प्रमण्डल दे अथवा यह स्वयं दे। यद्यपि बैंक ऋण देने में रुढ़िवादी है परन्तु कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में यह थोड़ी उदारता से काम लेगा। कुछ दशाओं में इन उद्योगों में लगे हुए लोगों को बिना धरोहर के ऋण दिये जा सकते हैं।

Q. 93. Describe carefully the working of the Reserve Bank of India.

प्रश्न ९३—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की कार्य पद्धति को ध्यानपूर्वक बताइये।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना को सिफारिश सबसे पहले हिल्टन यंग कमिशन ने १९२५ में की थी। इस सिफारिश को सरकार ने मान लिया परन्तु कुछ मतभेदों के कारण रिजर्व बैंक बिल पास न हो सका। अन्त में यह बिल १९३४ में पास हुआ और रिजर्व बैंक ने १ अप्रैल १९३५ से कार्य करना आरम्भ कर दिया। इस बैंक की निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं—

(१) नोट छापना—रिजर्व बैंक एक्ट की धारा २२ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को नोट छापने का एकाधिकार दिया गया है। नोट छापने का कार्य रिजर्व बैंक का ईशू विभाग करता है। पहले रिजर्व बैंक को छापे हुये नोटों के पीछे ४० प्रतिशत सोना, सोने के सिक्कों अथवा विदेशी धरोहरों के रूप में रखना पड़ता था। इसमें से कम से कम ४० करोड़ रुपये का सोना अवश्य होना चाहिये था और इस ४० करोड़ रुपये के सोने का काम कम से कम २५ भाग भारत में होना चाहिये था। १९४६ से पूर्व जब भारतवर्ष के रुपये का सम्बन्ध स्टर्लिंग से विच्छेद नहीं हुआ

या तब तक विदेशी धरोहरो के स्थान पर रिजर्व बैंक को नोटों के पीछे स्टॉलिंग धरोहरे रखनी पड़ती थी। शेष ६० प्रतिशत को रुपये के सिक्को, फुटकर रेजगारी, रुपये की धरोहरो तथा देशी बिरा आदि के रूप में रखा जाता था। २० जून १९५६ ई० को पास किये गये रिजर्व बैंक एक्ट सशोधित बिल के द्वारा रिजर्व बैंक की कुछ धाराओं में संशोधन किया गया है। यह संशोधन इसलिये आवश्यक हुआ क्योंकि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १००० करोड़ रुपये के हीनाथ अर्थ-प्रबन्धन का अनुमान है तथा योजना के कारण यह भी आवश्यक हो गया कि रिजर्व बैंक का दूसरे बैंको पर कड़ा नियन्त्रण हो। इन्हीं दो बातों को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक एक्ट में संशोधन किए गये हैं। इनमें से नोट छापने के पीछे रिजर्व बैंक जो धरोहर रखता है उससे सम्बन्धित निम्नलिखित संशोधन किये गए हैं—

(१) धारा ३३ (२) के एक संशोधन के अनुसार पहले रिजर्व बैंक को कम से कम ४०० रुपये की विदेशी धरोहरें तथा ११५ करोड़ रुपये का सोना ईश्यू विभाग में रखना पड़ता था। परन्तु अब बैंक इस सीमा को २०० करोड़ रुपये तक कर सकता है। इसमें ११५ करोड़ रुपये का सोना होना चाहिये।

यह भी ज्ञात हुआ है कि रिजर्व बैंक को एक विदेशी विनिमय गारन्टी कोष निर्माण करने का अधिकार दिया जायेगा जिसके फनस्वरूप यह बैंक अनुसूचित बैंकों की उस गारन्टी का अभिगोपन (Under Writing) कर सकेगा जो कि उन्होंने विदेशी बैंको अथवा व्यापारियों को भावी भुगतान के आधार पर मशीनों का आयात करने के लिये दी है।

(२) धारा ३३ (४) को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा माने गये सोने के मूल्य के अनुसार सोने का मूल्य बदलने के लिए संशोधित किया गया है। अभी तक रिजर्व बैंक में रखे गए सोने का मूल्य २१ रुपए ३ आने १० पाई प्रति तोला था परन्तु अब उसका मूल्य ६२ रुपए ८ आने प्रति तोला अथवा ३५ डालर प्रति औंस कर दिया गया। ऐसा करने से सोना जो पहले रिजर्व में केवल ४०.०१ करोड़ रुपए का था वह बढ़कर ११८.०२ करोड़ रुपए का हो जायेगा।

(३) धारा ३७ में किए गए संशोधन से अब यदि रिजर्व बैंक के पास किसी समय आवश्यकता से कम विदेशी विनिमय होगी तो उसको उस कमी पर अब सरकार को कोई कर नहीं देना पड़ेगा।

इस प्रकार अब भारत में अनुपातिक नोट पद्धति के स्थान पर न्यूनतम कोष पद्धति (Minimum Reserve Method) हो गई है। इस पद्धति के आने से अब आवश्यकतानुसार नोटों को बढ़ाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अब विदेशी विनिमय को रिजर्व के रूप में देकार बन्द करके नहीं रखना पड़ेगा वरन् उसको अब देश की विदेशी विनिमय की माँग को पूरा करने के काम में लाया जा सकेगा। देश में ६ अगस्त १९५६ तक लगभग १७०० करोड़ रुपये के नोट थे जिनके पीछे १६३.०१ करोड़ रुपये की विदेशी विनिमय थी।

(२) बैंकों का बैंक होना—रिजर्व बैंक देश के हमारे बैंको का नियन्त्रण, पथ प्रदर्शन तथा संगठन भी करता है। हमारे देश में दो प्रकार के बैंक हैं—(१) अनुसूचित बैंक (Scheduled), जिनका नाम रिजर्व बैंक एक्ट के दूसरे परिशिष्ट में दिया हुआ है तथा (२) गैर-अनुसूचित बैंक (Non-Scheduled), जिनका नाम इस परिशिष्ट में नहीं दिया हुआ है। इनमें से अनुसूचित बैंक की पूंजी तथा संचित कोष कम से कम ५ लाख रुपये का होना चाहिए। जिन बैंकों की पूंजी तथा संचित कोष ५ लाख रुपये से कम है वे रिजर्व बैंक के सदस्य नहीं बन सकते। सदस्य बैंकों के लिये यह अनिवार्य है कि वह अपनी चालू जमा (Demand liabilities) का कम से कम ५ प्रतिशत तथा स्थाई जमा (Time liabilities) का कम से कम २ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखें। रिजर्व बैंक एक्ट के एक संशोधन के अनुसार (जो जीलाई १९५६ ई० में किया गया) रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वह अनुसूचित बैंकों द्वारा रखे गये रिजर्व को चालू जमाओं के केस में ५ प्रतिशत से २० प्रतिशत के बीच में बढ़ा घटा सके तथा स्थायी जमाओं के केस में २ प्रतिशत से ८ प्रतिशत के बीच में बढ़ा घटा सके। इस प्रकार की पद्धति मनुक्त राष्ट्र अमरीका में पाई जाती है। इसके अनिश्चित आस्ट्रेलिया के समान रिजर्व बैंक को अधिकार दिया गया है कि वह एक निश्चित तिथि के पश्चात् इन बैंकों को अपनी अतिरिक्त जमाओं का १०० प्रतिशत रिजर्व के रूप में रखने के लिये मजबूर करे। रिजर्व बैंक को यह शक्ति इसलिए दी गई है जिससे कि उसका देश के साथ ढाँचे पर अधिकाधिक नियन्त्रण हो सके क्योंकि दूसरी योजना काल के लिए और बातों के अतिरिक्त मुद्रा स्थिति को रोकना बहुत आवश्यक है जो कि इस प्रकार के नियन्त्रण से बहुत कुछ रोकी जा सकती है क्योंकि बैंको द्वारा दिए गये ऋण मुद्रा स्थिति को बढ़ाने में बहुत कुछ सहायक होते हैं।

परन्तु राज्य सहकारी बैंको को अपनी माँग जमा का २५ प्रतिशत तथा अपनी स्थाई जमा का १ प्रतिशत ही रखना पड़ता है। बैंको को यह धन-राशि इसलिये रखनी पड़ती है जिससे कि रिजर्व बैंक का उन पर नियन्त्रण रहे। यदि कोई बैंक इस धन-राशि को रिजर्व बैंक के पास ही नहीं रखता तो उसकी जुमाने का ब्याज देना पड़ता है। सदस्य बैंकों के लिये यह भी अनिवार्य है कि वे हर सप्ताह अपने दो जिम्मेदार कर्मचारियों के हस्ताक्षर करा कर एक साप्ताहिक विवरण (Weekly return) रिजर्व बैंक तथा केन्द्रीय सरकार को भेजें जिसमें निम्नलिखित बातें हैं—

(१) भारत में चालू तथा स्थायी जमायें, (२) भारत में रखे हुए नोट, (३) रुपए के सिक्के तथा रेजगारी के रूप में रखता हुआ धन, (४) भारत में दिये गये ऋण तथा बढ़ा किये गये बिलों का व्योरा, (५) रिजर्व बैंक के पास रखा हुआ धन।

इसके बदले रिजर्व बैंक इन बैंको को पुनर्वंटों की सुविधा देता है तथा उसके

घन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सस्ती दर पर भेज देता है। रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि वह वास्तविक व्यापारिक दिलों को जो १० दिन से अधिक न हो तथा जिनपर दो या दो से अधिक अच्छे हस्ताक्षर हो, जिनमें से एक सदस्य बैंक के होने चाहियें, पुनर्वट्टे पर मोल ले सकता है। वह खेती सम्बन्धी दिलों को भी जिनकी अवधि १५ मास हो पुनर्वट्टे पर मोल ले सकता है। इसके अतिरिक्त अभी हाल में ही उसको १५ से अधिक तथा ५ वर्ष से कम के मध्यकालीन ऋण देने का भी अधिकार दिया गया है। जोलाई १९५६ में रिजर्व बैंक एक्ट में किये गये संशोधन से रिजर्व बैंक को नव निमित्त राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन कार्य) कोष में से राज्य सहकारी बैंकों को खेती तथा उससे सम्बन्धित कार्यों के लिये ऋण देने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त वह सरकारी ट्रस्ट, घरोंहरो तथा सोने के पीछे भी ऋण दे सकता है।

(३) सरकारी बैंक होना—रिजर्व बैंक एक्ट की २०वीं धारा के अनुसार रिजर्व बैंक पर यह भार है कि वह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का धन ले तथा उस धन का भुगतान सरकार के ऋण दाताओं को कर दे यह बैंक उनके धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाता है। जब सरकार को जनता से ऋण लेना होता है अथवा ऋण चुकाना होता है अथवा उस ऋण पर व्याज देना पड़ता है तब यह सब कार्य रिजर्व बैंक ही करता है। सरकार अपने सब धन को रिजर्व बैंक में बिना व्याज के रखती है। यदि सरकार को थोड़े समय के लिये रुपए की आवश्यकता होती है तो वह रिजर्व बैंक से काम चलाऊ ऋण (Ways and means Advances) प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक राज्य सरकारों तथा विशेष कर केन्द्रीय सरकार को समय समय पर देश की आर्थिक समस्याओं, मुद्रा नीति, बैंकिंग प्रगति तथा विनियोग नीति पर अपनी सम्मति भी देता रहता है।

(४) विदेशी विनिमय का नियन्त्रण करना—१९४६ ई० से पूर्व रिजर्व बैंक के ऊपर यह भार था कि वह १ शिलिंग ५ $\frac{१}{४}$ पैसे पर स्टलिंग बेच कर तथा १ शिलिंग ६ $\frac{३}{४}$ पैसे पर उसको मोल लेकर रुपये की विनिमय दर १ शिलिंग ६ पैसे पर स्थिर रखे।

परन्तु विदेशी विनिमय नियन्त्रण कानून १९४७ के अनुसार रिजर्व बैंक यह क्रय विक्रय केवल कुछ ही अधिकृत व्यक्तियों के साथ कर सकता है और वह भी केवल बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, देहली के कार्यालयों द्वारा। यह क्रय-विक्रय उन दरों पर किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोई की शर्तों की ध्यान में रखकर निश्चित कर देती है। अब रिजर्व बैंक प्रायः सभी देशों की विनिमय के क्रय विक्रय का कार्य करता है।

(५) अन्य कार्य—इन कार्यों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक कुछ और भी कार्य करता है, जैसे धारा ५८ के अन्तर्गत यह देश के निकासी गृहों का नियन्त्रण करता है। यद्यपि रिजर्व बैंक ने अभी तक निकासी गृहों पर नियन्त्रण करने के लिये कोई

नियम नहीं बनाये हैं तो भी वह बम्बई, कलकत्ता, देहली तथा मद्रास, बंगलौर तथा नागपुर के निकासी गृहों का प्रबन्ध करता है ।

इस बैंक को अपने ईश्यू तथा बैंकिंग विभागों का एक साप्ताहिक विवरण देना पड़ता है जो सरकारी गजट में छापता है । यह बैंक हर सप्ताह अपने सदस्य बैंकों के कार्यों का एक सामूहिक विवरण भी छापता है ।

रिजर्व बैंक के निम्नलिखित कार्य—रिजर्व बैंक एक्ट की धारा १५ के अनुसार बैंक के लिए निम्नलिखित कार्य निषेध कर दिये गये—

(१) यह बैंक किसी व्यापारिक तथा व्यवसायिक कार्य को स्वयं नहीं कर सकता और न यह निजी व्यापार या उद्योग ही खोल सकता है और न किसी व्यापार या उद्योग में भाग ले सकता है और न उसे आर्थिक सहायता ही प्रदान कर सकता है ।

(२) यह अचल सम्पत्ति को रहन रखकर उस पर ऋण नहीं दे सकता और न अचल सम्पत्ति को अपने निजी काम के अतिरिक्त खरीद ही सकता है ।

(३) यह बैंक अपने या और किसी बैंक अथवा कम्पनी के हिस्से नहीं खरीद सकता और न इस प्रकार के हिस्से की जमानत पर ऋण ही दे सकता है ।

(४) यह बैंक ऐसे विलों को न तो लिख ही सकता है और न स्वीकार ही कर सकता है जिनका भुगतान मारने पर न हो अर्थात् जो मुहूर्ती हो ।

(५) यह अपनी जमाओं का ब्याज नहीं दे सकता ।

(६) यह बैंक अरक्षित ऋण (Unsecured loans and Advances) नहीं दे सकता ।

रिजर्व बैंक और कृषि साख व्यवस्था—भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है । इस देश में खेती की अवस्था बहुत ही शोचनीय है । इस कारण यह आवश्यक था कि रिजर्व बैंक खेती के लिये सस्ते ऋण दे तथा समय-समय पर खेती सम्बन्धी आर्थिक समस्याओं पर सलाह दे । इस दृष्टि से रिजर्व बैंक के अन्तर्गत एक कृषि साख विभाग खोला गया । इस विभाग का कार्य कृषि साख की सचित्त व्यवस्था करना, कृषि साख सम्बन्धी समस्याओं को हल करना, समय-समय पर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, राज्य सहकारी बैंकों तथा अन्य कृषि समस्याओं को मन्त्रणा देना, उनका मार्ग दर्शन करना तथा सहकारी आन्दोलन को समर्थित करना है ।

रिजर्व बैंक को कृषि सम्बन्धी निम्नलिखित सुविधाएँ देने का अधिकार है—

(१) यह सहकारी धरोहर की जमानत पर अधिक से अधिक ६० दिन के लिए राज्य सहकारी बैंकों तथा केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों को जो राज्य सहकारी बैंक घोषित कर दिये गये हैं, ऋण दे सकता है ।

(२) यह बैंक भूमि बन्धक बैंकों के ऋण-पत्रों के आधार पर भी ऋण दे सकता है । परन्तु ऐसे ऋण तभी दिये जा सकते हैं जब कि ऋण-पत्र द्रष्टी धरोहर घोषित कर दिये गये हैं ।

(३) यह राज्य सहकारी बैंको के खेती सम्बन्धी दिलों को भी जिनकी अवधि १५ मास से अधिक न हो, पुनर्वंदे पर मोन ले सकता है।

(४) अभी हाल ही में इसको १५ मास से ५ वर्ष तक के मध्यकालीन ऋण देने का भी अधिकार दिया गया है।

(५) रिजर्व बैंक सशोधन अधिनियम के अनुसार दो कोष स्थापित किये जायेंगे, (१) राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष और (२) राष्ट्रीय कृषि साख (स्थापित्व) कोष। राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष की सहायता से रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण देगा, जो इन ऋणों को उद्योग सहकारी साख संस्थाओं की पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने में करेंगी। इसके लिये आवश्यक होगा कि जिस सहकारी संस्था को सहायता दी जाय वह केवल ग्रामीण साख से सम्बन्धित हो। जहाँ तक राष्ट्रीय कृषि साख (स्थापित्व) कोष का सम्बन्ध है, इसका उपयोग रिजर्व बैंक राज्य सहकारी बैंकों की सहायता के लिये करेगा। राज्य सहकारी बैंकों को यह सहायता प्राकृतिक सवटो जैसे, अकाल, बाढ़ आदि के समय और अल्पकालीन ऋण सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिये दी जायेगी। यह उपाय बहुत ही मत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कुछ या अधिकांश ऋण की बापसी स्थगित हो सकेगी। इस सम्बन्ध में सटकने वाली बात यह अवश्य है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर किसान इतना मन्वूर हो सकता है कि बिस्तुल अदायगी न कर सके।

उन्मुक्त दोनों कोषों में पहला कोष अर्थात् राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष ३ फरवरी १९५६ ई० से चालू हो गया है। प्रारम्भ में इस कोष में १० करोड़ रुपये रखे गये हैं। २० जून १९५६ ई० से पाँच वर्ष तक इस कोष में ५ करोड़ २० प्रत्येक वर्ष हस्तान्तरित किये जायेंगे। इसीलिये जीलाई १९५८ ई० में इस कोष में २० करोड़ २० थे। इस कोष में से पहला ८ लाख २० का ऋण मद्रास सरकार को बटो-बटो सहकारी साख समितियों की पूंजी में चन्द्रे के रूप में देने के लिए दिया गया है। दूसरा कोष भी स्थापित हो गया है। इसमें जीलाई १९५८ ई० में २ करोड़ २० थे।

परन्तु यह बात बताने योग्य है कि आरम्भ से अब तक रिजर्व बैंक ने खेती की आर्थिक सहायता बहुत ही कम की है। १९४७-४८ से पूर्व इतने प्रांतीय सहकारी बैंकों को बहुत कम ऋण दिये थे और अब भी ऋण की मात्रा ५० करोड़ रुपये से अधिक नहीं है। इस प्रकार रिजर्व बैंक के स्थापित होने पर कृषि साख समस्या उतनी ही जटिल है जितनी कि वह पहले थी।

रिजर्व बैंक और स्वदेशी बैंक—धारा ५५ (२) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक के ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वह स्थापित होने के तीन वर्ष के अन्दर एक रिपोर्ट सरकार को दे जिसमें वह यह सुझाव दे कि ब्रिटिश भारत में बैंकिंग के कार्य में लगे हुए व्यक्ति तथा संस्थाओं को आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिये किस प्रकार का कानून बचित होना।

इस दृष्टि से रिजर्व बैंक ने १९३७ में दो बार इस बात का प्रयत्न किया कि वह देशी बैंको को अपना सदस्य बनाये। परन्तु क्योंकि सदस्यता की शर्तें स्वदेशी बैंको को मान्य नहीं थी इस कारण वह बैंक रिजर्व बैंक के सदस्य न बन सके।

रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण—१ जनवरी १९४६ से रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसलिए सरकार ने बैंक के सब हिस्सों को खरीद लिया है। सरकार हिस्सेदारों के प्रति १०० रुपये के हिस्से पर ११८.१० रुपये के हिसाब से देगी। यह धन कुछ तो धन के रूप में दिया जायेगा और कुछ रकमों के रूप में दिया जायेगा। भविष्य में बैंक का प्रबंध एक केन्द्रीय बोर्ड को सौंप दिया गया है। इस बोर्ड में एक गवर्नर, दो उप-गवर्नर, १० डायरेक्टर और एक सरकारी अफसर होंगे जिनकी नियुक्ति सरकार करेगी। गवर्नर केवल चार साल कार्य करेंगे। स्थानीय बोर्ड में अब ८ के बदले केवल ५ ही सदस्य होंगे और इनकी नियुक्ति भी सरकार ही करेगी।

बैंकिंग कम्पनीज एक्ट १९४६ और रिजर्व बैंक—

१९४६ के बैंकिंग कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को सारे भारतवर्ष के बैंको के ऊपर नियन्त्रण करने की शक्ति दी गई है। रिजर्व बैंक अब बैंको की ऋण देने की नीति को निर्धारित कर सकता है तथा यह भी तय कर सकता है कि किस कार्य के लिये ऋण दिया जाये तथा ऋण पर क्या व्याज लिया जाये। रिजर्व बैंक स्वयं या सरकार के आदेशानुसार बैंको के हिसाब की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है। यदि बैंक अपनी सारियाँ खोलना चाहें तो उनको ऐसा करने के लिये रिजर्व बैंक की आज्ञा लेनी पड़ेगी। बैंको को समय-समय पर अपने कार्य का तथा अपनी सम्पत्ति का ब्योरा रिजर्व बैंक को देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक को बैंको के एकीकरण तथा उनके स्वयं इच्छा से कार्य बन्द करने के सम्बन्ध में भी कुछ शक्ति दी गई।

रिजर्व बैंक के कार्य पर दृष्टि—

रिजर्व बैंक ने इस देश में १ अप्रैल १९१५ ई० से कार्य करना आरम्भ किया। इस बैंक की स्थापना से भारतीय बैंकिंग पद्धति कुछ सीमा तक सुदृढ़, सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित हो सकी है। इस बैंक की स्थापना के पश्चात् भारतीय मुद्रा बाजार में व्याज की दर कुछ सीमा तक गिरी है और भारतीय मुद्रा बाजार में द्रव्य की जो कमी रहती थी वह भी दूर हो गई है। इस बैंक ने प्रारम्भ से ही सस्ती मुद्रा नीति (Cheap Money policy) को अपनाकर भारतीय व्यापार, उद्योग धन्धों तथा कृषि की बढ़ती हुई रुपये की माँग की पूर्ति करने में बहुत सफलता प्राप्त की है। इसने भारत सरकार की सब काल में बहुत सहायता की है। इसने रुपये की विनिमय दर को भी स्थिर रखा है। परन्तु इतना होते हुए भी रिजर्व बैंक की स्थापना से भारत के मुद्रा बाजार को अधिक लाभ न हुआ।

इस बैंक की स्थापना से भारतवर्ष के विभिन्न मुद्रा बाजारों में जो व्याज की

दरों में विचलन पाई जाती थी वह आज भी पाई जाती है। अप्रैल १९५८ में भी जब कि रिजर्व बैंक की बैंक दर केवल ४ प्रतिशत थी, कलकत्ते और बम्बई से द्रव्य बाजारों की हुण्डी व्याज दर, बिल व्याज दर तथा अन्य साधारण व्याज दरें ४ प्रतिशत से १२ प्रतिशत तक घटती बढ़ती हैं। यह बैंक अभी तक भारतवर्ष में एक-विस्तृत बिल बाजार कायम न कर सका क्योंकि इस प्रकार के बिलों का भारतवर्ष में अभाव है। परन्तु जनवरी १९५२ ई० से इस बैंक ने भारत में बिल बाजार निर्माण करना आरम्भ कर दिया है। इस कारण ६ अगस्त १९५६ को सरकार के अतिरिक्त अन्य दिये गये ७० करोड़ के ऋण में से ५० लाख रु० के ऋण बिलों के पीछे दिये गये थे। यह बैंक भारतवर्ष की विभिन्न साख संस्थाओं (जैसे स्वदेशी बैंक, सहकारी साख समिति तथा और दूसरे बैंक) में सहयोग स्थापित करने में भी सफल न हो सका। खेती की आर्थिक सहायता न करने के कारण यह बैंक खेती की उन्नति में भी सहायक न हो सका। मुद्रा काल में यह बैंक देश में होने वाले मुद्रा प्रसार को भी न रोक सका। इसके कारण देश में मूल्य स्तर बहुत ऊँचा हो गया और लोगों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस बैंक की सबसे बड़ी कमी यह रही है कि इसका देश की साख के ऊपर पूर्ण रूप से नियन्त्रण नहीं है। इसका कारण यह है कि देशी बैंक तथा महाजन जो देश के लगभग तीन चौथाई से अधिक व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं उनके ऊपर इस बैंक का कोई प्रभाव नहीं है। इस कारण बैंक दर के कम या अधिक करने का भारतीय मुद्रा बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

परन्तु अभी हाल में रिजर्व बैंक ने यह प्रयत्न किया कि मुद्रा प्रसार को कुछ कम किया जाये तथा इस देश के मुद्रा बाजार में लचीलापन आये। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये नवम्बर १९५१ में बैंक दर ३ प्रतिशत से ३½ प्रतिशत कर दी गई। इसके साथ-साथ रिजर्व बैंक ने सरकारी धरोहरों पर खपा देना बन्द कर दिया। साथ-साथ रिजर्व बैंक ने मुद्रा बिलों पर भी जिनके साथ माँग वाले रुपये लगे हुये हो ऋण देना आरम्भ कर दिया। यह इस देश में बिल बाजार को उन्नत करने के लिये किया गया है। इस प्रकार के बिलों के पीछे अब यह बैंक बहुत खपा उधार दे रहा है। इसके साथ-साथ बैंकिंग कम्पनीज एक्ट १९४६ ने जो शक्ति बैंकों के ऊपर नियन्त्रण करने की रिजर्व बैंक को दी है उसके कारण अब धीरे धीरे रिजर्व बैंक का प्रभाव देश के मुद्रा बाजार पर पड़ने लगा है। जौलाई १९५६ के सशोधन के कारण इस बैंक का देश के मुद्रा बाजार पर और भी बड़ा नियन्त्रण हो जायेगा। आशा है निकट भविष्य में यह बैंक देश की साख पर नियन्त्रण करने में बहुत हद तक सफल हो जायेगा। श्री सी० एच० भामा ने जो कि भारतीय बैंक संभा के अध्यक्ष हैं इस बात की सिफारिश की है कि रिजर्व बैंक को सरकार प्रभाव से मुक्त किया जाय।

Q. 94 Point out the main defects of the present banking organisation of India. Indicate further lines of improvement.

प्रश्न ९४—भारत की वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था के मुख्य दोष बताइये। उनमें सुधार के साधन भी बताइये।

भारतवर्ष में अभी तक बैंकिंग की बहुत कम उन्नति हुई है। इस कारण इस देश के उद्योग-धन्धे तथा व्यापार भी कम उन्नत हो सके हैं। भारत की वर्तमान बैंकिंग व्यवस्था में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं—

(१) भारतवर्ष में देश के क्षेत्रफल तथा प्राकृतिक साधनों को देखते हुये बैंकिंग की बहुत कम उन्नति हुई है। जबकि ब्रिटेन में हर ७ वर्गमील और ३४२४ मनुष्यों के पीछे एक व्यापारिक बैंक है, भारत में यह १७७५ वर्गमील तथा ७५,००० मनुष्यों के पीछे है। इस देश में बैंक कुछ नगरी तथा बड़े-बड़े शहरों तक ही सीमित हैं। गाँव में बैंकों का नाम भी नहीं है। इस कारण हमारे गाँव के लिये का कोई उपयोग नहीं हो सकता। उसको लोग गाहकर रख देते हैं।

(२) इस देश का मुद्रा बाजार कई भागों में बँटा हुआ है जिनमें आपस में कोई सम्बन्ध नहीं है। भिन्न-भिन्न प्रकार के बैंक भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं और एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं रखते। व्यापारिक बैंक इम्पोरियल बैंक (राज्य बैंक) से ईर्ष्या रखते हैं। विदेशी विनिमय बैंकों का इस देश में एक विशेष स्थान है। यह बैंक परिस्थिति का लाभ उठाकर भारतीय बैंकों को बहुत हानि पहुँचाते रहे हैं। सहकारी बैंकों तथा व्यापारिक बैंकों का आपस में कोई सम्बन्ध नहीं। इन सब बातों से भी अधिक विशेष बात यह है कि हमारे देश के देशी बैंकों तथा महाजनो का सम्बन्ध देश के दूसरे बैंकों से नहीं है और देशी बैंकों में भी आपस में बड़ा मतभेद पाया जाता है जैसे बम्बई में इनके गुजराती, मुलतानी तथा मारवाड़ी बाजार हैं जिनका एक दूसरे से बहुत कम सम्बन्ध है।

(३) इस देश के बैंकों में आपस में कोई सम्बन्ध न होने का परिणाम यह है कि इस देश में सभी स्थानों पर व्याज की एक ही दर नहीं है। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच कमेटी ने बताया कि यदि माँग वाले ऋण की व्याज की दर १/४% हो, हुण्डी की दर तीन प्रतिशत हो, बैंक की दर ४ प्रतिशत हो, बम्बई बाजार में छोटे-छोटे व्यापारियों के बिलों की दर १० प्रतिशत हो तो यह इस बात का द्योतक है कि देश के एक मुद्रा बाजार से दूसरे मुद्रा बाजार में रुपया नहीं आता-जाता। मुद्रा बाजार की ओर स्थिति १९३० में थी उसमें अभी तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि अगस्त १९५८ में कलकत्ते और बम्बई में माँग ऋण की दर ३ प्रतिशत से ३ १/२ प्रतिशत तक तथा ३ १/२ प्रतिशत से ४ १/२ प्रतिशत तक, बैंक की दर ४ से ४ १/२ प्रतिशत, इम्पोरियल बैंक की हुण्डी की दर ४ १/२ प्रतिशत, बम्बई बाजार में छोटे-छोटे व्यापार-

रियो के व्याज की दर ६ $\frac{3}{4}$ से १० $\frac{1}{2}$ प्रतिशत तथा कलकत्ते बाजार में बिलों की यह दर १२ प्रतिशत तथा मद्रास में १२ $\frac{3}{4}$ प्रतिशत थी ।

(४) हमारे देश के द्रव्य बाजार की एक बड़ी कमी यह है कि इसमें उद्योग घरों तथा व्यापार की माँग की पूर्ति करने के लिये द्रव्य और साख नहीं है । इस घन की कमी के मुख्य कारण जनता में रुपये को दबाकर रखने की आदत का होना भारतीय जनता की अत्यन्त गरीबी, उसकी अज्ञानता तथा अतिशय है । घन की कमी फसल के समय तो बहुत ही अधिक हो जाती है । इसके विपरीत, बरसात में जब कम व्यापार होता है रुपए की इतनी कमी नहीं रहती । यही कारण है कि मन्दे तथा अधिक व्यापार के समय की ब्याज की दरों में बहुत अन्तर रहता है । जैसे १९२४ में ऊँची दर ६ प्रतिशत तथा नीची दर ४ प्रतिशत थी । १९२८ में ऊँची दर ७ प्रतिशत तथा नीची दर ५ प्रतिशत थी तथा १९२९ में ऊँची दर ८ प्रतिशत तथा नीची दर ५ प्रतिशत थी ।

(५) हमारे देश के द्रव्य बाजार का एक दोष यह भी है कि इसमें बिल बाजार का अभाव है । इस अभाव के बहुत से कारण हैं जैसे—(१) भारत में बैंक सरकारी धरोहरो तथा अन्य श्रेष्ठ प्रकार की धरोहरो में अपना रुपया लगाना अधिक पसन्द करते हैं । (२) भारतवर्ष में इंग्लैंड के स वित्तीय गृहों (Finance houses) के समान संस्थाएँ नहीं हैं जो अपने ग्राहकों के लिये बिलों को स्वीकार कर सकें । (३) बहुत से बिल व हुण्डियाँ ऐसी होती हैं जिनका यह पता लगाना बहुत ही कठिन है कि वे व्यवसाय के लिये लिखी गई हैं या केवल उधार लेने के उद्देश्य से क्योंकि वहाँ पर प्रमाणित भण्डारों तथा गोदामों के अभाव के कारण माल के अधिकार पत्र नहीं लगाये जाते । (४) यहाँ पर समावधि बिली तथा मुद्दती हुण्डियों पर स्टाम्प-कर बहुत अधिक है । (५) हमारे देश में नकद साख का बहुत रिवाज है । (६) भारतवर्ष में जिस प्रकार के बिल पाये जाते हैं उनकी रिजर्व बैंक पुनर्बंट पर नहीं खरीदता । इसलिये दूसरे बैंक भी उन बिलों का बट्टा नहीं करते । (७) भारत के विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में जो बिल लिखे जाते हैं वे सब स्टर्लिङ्ग में होते हैं इसलिये उनसे भारत के मुद्रा बाजार को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता ।

(६) हमारे देश में साख बैंकिंग की बहुत कम उन्नति हुई है । यदि यहाँ पर साख बैंकिंग उन्नत हो जाय तो गाँवों को भी बैंकिंग से लाभ पहुँच सकता है ।

(७) हमारे देश में निकासी गृहों की भी बहुत कम उन्नति हुई । इस कारण बैंकों को अपने द्रव्य कोष में अधिक रुपया रखना पड़ता है और वे कम साख सृजन कर सकते हैं ।

दोषों को दूर करने के उपाय—

भारतीय बैंकिंग के इन दोषों को दूर करने के लिय रिजर्व बैंक को बहुत कार्य करना पड़ेगा । रिजर्व बैंक एक्ट के अतिरिक्त बैंकिंग कम्पनीज एक्ट में रिजर्व बैंक

को बहुत शक्ति प्रदान की है जिसके आधार पर वह बैंको को ठीक प्रकार से उन्नत कर सकता है। इसके साथ साथ इसको ऐसे कार्य भी करने पड़ेंगे जो बैंको की शक्ति के बाहर हैं परन्तु इसकी शक्ति के अन्दर हैं, जैसे इसको इस बात का प्रयत्न करना पड़ेगा कि इस देश में बिल बाजार उन्नत हो। यह तभी हो सकता है जब कि सरकार बिलो का स्टाम्प कर कम करे तथा रिजर्व बैंक बिलो को पुनर्वट्टे पर खरीदना आरम्भ कर दे। अभी पिछले एक वर्ष से रिजर्व बैंक ने बिल बाजार बनाने के लिये कुछ प्रयत्न आरम्भ किया है। आशा है कि शीघ्र ही हमारे देश में एक अच्छा बिल बाजार निर्माण हो जायगा।

रिजर्व बैंक को यह भी प्रयत्न करना पड़ेगा कि गांवों में बैंकिंग की उन्नति हो। इसके लिये केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमेटी का यह सुझाव है कि रिजर्व बैंक की व्यापारिक बैंको द्वारा उन स्थानों पर खुली हुई (जहाँ पर बैंक नहीं हैं) शाखाओं को पांच वर्ष तक आर्थिक सहायता देनी चाहिये, उपयुक्त ही मालूम पड़ती है।

रिजर्व बैंक को यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि वह देशी बैंकों तथा महाजनो से अपना सम्बन्ध स्थापित करे। बिना इस प्रकार के सम्बन्ध के रिजर्व बैंक का साख पर पूर्णरूप से नियन्त्रण नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक को यह भी प्रयत्न करना चाहिये कि एक प्रकार के बैंको का दूसरे प्रकार के बैंक से सम्बन्ध स्थापित हो जिससे कि उनका फालतू रुपया एक दूसरे के काम आ सके। ऐसा होने से भिन्न-भिन्न स्थानों पर व्याज की दर समान हो जायगी।

हमारे देश में सरकारी गोदाम भी बनने चाहियें ताकि उनमें सामान रख कर अधिकार पत्र प्राप्त किये जा सकें। इस प्रकार के अधिकार-पत्रों के होने पर रिजर्व बैंक को बिलो का पुनर्वट्टा करने में कोई आपत्ति न होगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार के बहुत से गोदाम बनाने की योजना है।

रिजर्व बैंक को चाहिये कि वह इस देश में निकासी-गृह उन्नत करने का प्रयत्न करे।

अभी हाल ही में नियुक्त साख समिति ने सुझाव दिया है कि बैंकों की आपसी प्रतियोगिता को काम करने के लिये एक अखिल भारतीय बैंक संघ स्थापित होना चाहिये जिसका काम बैंको के हितों की रक्षा करना तथा सामान्य हित की बातों पर विचार विनिमय करना हो।

Q. 95. Describe briefly the principal provisions of the Banking Companies Act 1949.

प्रश्न ९५—बैंकिंग कम्पनीज एक्ट १९४९ की मुख्य मुख्य बातें संक्षेप में बताइये ।

यद्यपि रिजर्व बैंक ने सन् १९३९ में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत सरकार के सामने एक बैंकिंग बिल रखा था परन्तु भारत सरकार के छड़ाई के कार्य में व्यस्त होने के कारण वह बिल पास न किया गया । हाँ सरकार ने समय-समय पर भारतीय कम्पनीज एक्ट में संशोधन करके बैंकों के ऊपर नियन्त्रण करने का प्रयत्न किया । इन सब संशोधनों तथा कानूनों का एकीकरण करके बैंकिंग कम्पनीज एक्ट १९४९ में बनाया गया । यह एक्ट १६ मार्च १९४९ से लागू हुआ ।

इस एक्ट की धारा ३ के अनुसार यह एक्ट सहकारी बैंकों को छोड़कर सब बैंकिंग कम्पनियों पर लागू होता है । अब कोई भी संस्था उस समय तक बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकती जब तक कि वह अपने नाम के आगे बैंक, बैंकिंग अथवा बैंकर शब्द प्रयोग न करे । इस एक्ट के अनुसार बैंकिंग का अर्थ है जनता से उधार देने या विनियोग के लिए ऐसी धन-राशि जमा के रूप में लेना जो माँग पर या अन्य भाँति देय है तथा बैंक ड्राफ्ट, आदेश के द्वारा या अन्य प्रकार से निकाली जा सकती है ।

इस एक्ट की धारा २२ के अनुसार कोई भी बैंक उस समय तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि वह रिजर्व बैंक से अनुज्ञा-पत्र (Licence) प्राप्त न कर ले । यह एक्ट पुराने तथा नये दोनों प्रकार के बैंकों पर लागू होता है । पुराने बैंकों के लिये एक्ट लागू होने के ६ मास के अन्दर अन्दर इस प्रकार का अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए । नये बैंकों को आरम्भ से ही इस अनुज्ञा-पत्र को प्राप्त करना आवश्यक है ।

इस एक्ट की धारा ५१ के अनुसार जो बैंक केवल एक ही स्थान पर अपना कार्यालय रखे उसको कम से कम ५० हजार रुपये की पूंजी तथा संचित कोष रखना पड़ेगा । यदि किसी बैंक का कार्य एक से अधिक राज्यों में हो तो उसे ५ लाख रुपये की पूंजी तथा संचित कोष रखना आवश्यक है । जो बैंक कलकत्ते तथा बम्बई में कार्य करते हैं उनकी पूंजी तथा संचित कोष में कम से कम १० लाख रुपये होने चाहियें । विदेशी कम्पनियों की पूंजी तथा संचित कोष में कम से कम १५ लाख रुपये होने चाहियें और यदि ये बैंक कलकत्ता तथा बम्बई में भी कार्य करते हों तो इनकी पूंजी तथा संचित कोष २० लाख रुपये होना चाहिए ।

इस एक्ट की धारा १२ के अनुसार किसी भी बैंक की प्रायिक पूंजी (Subscribed capital) उसकी अधिकृत पूंजी (Authorised capital) की आधी से कम नहीं होगी तथा उसकी प्राप्त पूंजी उसकी प्रयोजित पूंजी की आधी से कम न

होगी। प्रत्येक बैंक अपनी पूँजी को साधारण हिस्सों के रूप में प्राप्त कर सकता है। १ जोलाई १९४४ से पूर्व बेचे गये पूर्वाधिकारी हिस्सों के रूप में भी पूँजी प्राप्त की जा सकती है।

इस एक्ट की धारा १० में बैंक के प्रबन्ध के बारे में दिया गया है। अब किसी बैंक का प्रबन्ध, प्रबन्धकर्ता (Managing Agents) द्वारा नहीं किया जा सकता। बैंकों के प्रबन्ध के लिए ऐसे व्यक्ति भी नियुक्त नहीं किये जा सकते जो दिवालिया हो चुके हों। किसी भी प्रबन्धकर्ता को कम्पनी के लाभ में से वेतन के रूप में नहीं दिया जा सकता। ऐसे व्यक्ति भी कम्पनी के संचालक नियुक्त नहीं किये जा सकते जो अन्य कम्पनी के संचालक हो अथवा जो अन्य प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हो अथवा जिसने कम्पनी का प्रबन्ध करने के लिये कम्पनी से पाँच वर्ष से अधिक के लिये समझौता कर लिया हो।

इस एक्ट की धारा २४ के अनुसार इस एक्ट के लागू होने के दो वर्ष पश्चात् प्रत्येक बैंक को अपनी कुल मुद्दती तथा माँग जमाओं का प्रतिदिन २० प्रतिशत नकद रखा, सोना तथा अन्य प्रकार की अनुमोदित धरोहरें भारत में रखनी पड़ेंगी। इसका विवरण प्रति मास रिजर्व बैंक को भेजना पड़ेगा। धारा २५ के अनुसार प्रत्येक बैंक को हर तीसरे महीने के अन्तिम दिन अपनी मुद्दती तथा माँग देनदारियों की कम से कम ७५ प्रतिशत मूल्य की सम्पत्ति भारत के विभिन्न राज्यों में रखनी पड़ेगी और इसका विवरण रिजर्व बैंक को भेजना पड़ेगा।

सदस्य बैंकों के समान गैर सदस्य बैंकों के लिये भी यह आवश्यक हो गया है कि वे अपनी माँग जमा का ५ प्रतिशत और मुद्दती जमा का २ प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास अथवा अपने पास प्रतिक्षण रखें तथा प्रत्येक मास के अन्तिम नुक़्तवार को इस आसय का एक विवरण रिजर्व बैंक को भी भेजें। परन्तु रिजर्व बैंक अब उसकी माँग जमा के केस में ५ से २० प्रतिशत के बीच में तथा समाधि जमाओं के केस में २ से ८ प्रतिशत के बीच घटा-बड़ा सकता है। इसके अतिरिक्त एक निश्चित तिथि के पश्चात् वह इन बैंकों को अपनी जमाओं का १०० प्रतिशत रखने के लिये मजबूर कर सकता है।

धारा १७ के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिये यह आवश्यक है कि वह साभास विवरण करने से पूर्व साभ का कम से कम २० प्रतिशत भाग प्रतिवर्ष संचित कोष में तब तक हस्तान्तर करता रहे जब तक कि वह कोष प्राप्त पूँजी के बराबर न हो जाये।

इस एक्ट की धारा १२ के अनुसार कोई भी बैंक कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये और वह भी रिजर्व बैंक की अनुमति से, सहायक प्रमण्डल (Subsidiary Company) की स्थापना कर सकेगा अन्यथा नहीं। अब बैंक अपने ही हिस्सों की जमानत पर ऋण न दे सकेगा तथा अपने किसी संचालक को अरक्षित ऋण न

दे सकेगा। बैंक अब किसी ऐसी दूसरी कम्पनी या बैंक को ऋण न दे सकेगा जिसमें बैंक का कोई भी संचालक साझेदार हो।

इस एक्ट ने रिजर्व बैंक को देश की बैंकिंग व्यवस्था का नियन्त्रण तथा सगठन करने के उद्देश्य से निम्नलिखित अधिकार दिये हैं—

हर एक नये अथवा पुराने बैंक को अपना कार्य करने के लिये रिजर्व बैंक से एक अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना पड़ेगा। कोई भी बैंक बिना रिजर्व बैंक की आज्ञा के किसी स्थान पर अपनी शाखाएँ नहीं खोल सकेगा। रिजर्व बैंक अपनी इच्छा से अथवा केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार किसी भी बैंक का हिसाब तथा अन्य विवरण का किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है। यदि निरीक्षण करने पर किसी बैंक का कार्य ठीक न पाया जाय तो रिजर्व बैंक केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार उस बैंक को भविष्य में जमायें लेने से रोक सकता है तथा उसे अपना कार्य बन्द करने की भी लिखित आज्ञा दे सकता है। प्रत्येक बैंक के लिये यह आवश्यक है कि वह रिजर्व बैंक के पास अपनी मांग देनदारी का ५ प्रतिशत (अब ५ से २० प्रतिशत के बीच) तथा अपनी मुद्दती देनदारी का २ प्रतिशत (अब २ से ५ प्रतिशत के बीच) रखे तथा महीने के अन्त में इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट रिजर्व बैंक को भेजे। रिजर्व बैंक को अधिकार है कि जनहित के लिये देश के समस्त बैंकों को अथवा किसी एक बैंक को यह आदेश दे कि वह प्रमुख उद्देश्यों के लिये ही ऋण दे और वह भी रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित की हुई दर पर। इन सबके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक बैंक रिजर्व बैंक के पास निम्नलिखित सूचनायें भेजे—

(१) प्रति मास एक ऐसा विवरण जिसमें उन समस्त अरक्षित ऋणों का वर्णन हो जो उस बैंक ने ऐसी कम्पनियों को दिये जिसमें वह बैंक अथवा उसका संचालक अथवा प्रबन्ध-कर्त्ता प्रत्यभविता (Guarantor) के रूप में कार्य करते हो।

(२) प्रत्येक मास एक ऐसा विवरण जिसमें उस सम्पत्ति का विवरण हो जो प्रत्येक बैंक को अपनी मुद्दती तथा मांग जमाओं के मूल्य का २० प्रतिशत नकद रुपये तथा सोना आदि के रूप में रखना आवश्यक है।

(३) हर तीसरे महीने एक ऐसा विवरण जिसमें यह दिखाया गया हो कि बैंक ने अपनी कुल देनदारी का ७५ प्रतिशत भारत सम्पत्ति के रूप में रखा है।

(४) प्रतिवर्ष के अन्त में प्रत्येक बैंक को उन जमाओं का एक विवरण भेजना पड़ेगा जिनमें से पिछले दस वर्षों में कोई रुपया निकाला नहीं गया है।

(५) प्रत्येक बैंक को अपना वार्षिक चिट्ठा तथा अन्य खाते आडीटर की रिपोर्ट सहित भेजने पड़ेंगे।

(६) इनके अतिरिक्त यदि रिजर्व बैंक किसी बैंक की कोई सूचना भेजने के लिये आज्ञा देता है तो वह सूचना उसको भेजनी पड़ेगी।

रिजर्व बैंक की स्वीकृति बिना कोई भी बैंक किसी प्रकार का एकीकरण, पुनर्गठन तथा अन्य प्रकार की योजनायें नहीं कर सकता।

यदि किसी बैंक का अदालत द्वारा निस्तारण (Liquidation) कर दिया गया हो और रिजर्व बैंक उस बैंक का राजकीय निस्तारक (Official Liquidator) नियुक्त किये जाने की प्रार्थना करे तो वह इस कार्य के लिये नियुक्त किया जायेगा। रिजर्व बैंक किसी भी बैंकिंग कम्पनी को किसी भी प्रकार की सलाह दे सकता है। वह बैंक का एकीकरण करवाने में मध्यस्थ बनकर सहायता कर सकता है। यह बैंक किसी भी बैंक को वृण देकर सहायता कर सकता है। यह किसी भी बैंक का निरीक्षण करके उस बैंक को अपने संचालकों की उस निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के लिये बैठक बुलाने तथा उस रिपोर्ट में दिये गये सुझावों का पालन करने का आदेश दे सकता है। यह बैंक किसी भी बैंक को बन्द करने के लिये अदालत से प्रार्थना कर सकता है। यह बैंक केन्द्रीय सरकार को प्रविवर्ण भारतीय बैंकिंग की प्रगति के सम्बन्ध में रिपोर्ट देगा और इस रिपोर्ट में भारतीय बैंकिंग को सुदृढ़ बनाने के सुझाव भी देगा। इस प्रकार यह एक्ट देश की बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में बहुत सहायक होगा।

भारतीय अर्थ-व्यवस्था

Q 96 —Classify the main sources of income and heads of expenditure of the Central and State Governments. How is the Five Year's Plan being financed ?

प्रश्न ६६—केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के आय तथा व्यय की मुख्य मदों का वर्णन कीजिये । पंचवर्षीय योजना के लिये धन कैसे खर्च किया जाता है ?

उत्तर—२६ जनवरी १९५० को भारत में गणराज्य स्थापित होने के पश्चात् राज्य के अधिकार, उत्तरदायित्व तथा कार्य आदि सघ (Union) तथा राज्यों (States) में विभाजित कर दिये गये । जिस सिद्धान्त पर सघ और राज्य में कार्यों का विभाजन हुआ है लगभग उसी प्रकार उसमें आय व्यय के मदों का विभाजन हुआ है । ऐसे कर जिनका सम्बन्ध सारे देश से है उनको सघ सरकार को दिया गया है तथा जिनका सम्बन्ध किसी विशेष स्थान से है वे स्थानीय सरकार को दिये गये हैं । इसी सिद्धान्त पर सघ राज्यो तथा स्थानीय सरकारो में व्यय के मदों का विभाजन किया गया है ।

सघ सरकार की आय व्यय के मुख्य मद—सघ सरकार की आय के मुख्य मद निम्नलिखित हैं—(१) सीमा शुल्क, (२) उत्पादन शुल्क, (३) कार्पोरेशन कर, (४) आय कर (कार्पोरेशन कर को छोड़ कर), (५) सम्पत्ति शुल्क, (Estate own) (६) पूंजी कर (Wealth Tax), (७) रेल के किराये पर कर, (८) व्यय कर, (९) उपहार कर (Gift Tax), (१०) अफीम, (११) व्याज, (१२) नागरिक प्रसासन, (१३) मुद्रा और टकसाल, (१४) नागरिक निर्माण कार्य, (१५) आय के अन्य साधन, (१६) डाक और तार की वास्तविक आय जो जनरल रिवेन्यूज को प्राप्त हुई, (१७) रेलवे से आय जो जनरल रिवेन्यूज को प्राप्त हुई, (१८) असाधारण मद, (१९) राज्यों को दिया जाने वाला आय कर भाग जो आय में से घटाया जाता है ।

सघ सरकार के मुख्य व्यय के मद निम्नलिखित हैं—(१) राजस्व से सीधी सांगें, (२) सिंचाई, (३) ऋण पर व्याज आदि, (४) नागरिक प्रसासन, (५) मुद्रा और टकसाल, (६) नागरिक निर्माण कार्य, (७) पेन्शन, (८) शरणार्थियों पर व्यय, (९) खाद्य पदार्थों पर व्यय, (१०) अन्य व्यय, (११) राज्य को सहायता, (१२) असाधारण मदें, (१३) रक्षा व्यय, (१४) विभाजन के पूर्व की अदायगी ।

(१) सीमा शुल्क (Customs)—यह वह कर है जो विदेशों से आने वाले तथा विदेशों को जाने वाले माल पर लगाया जाता है । यह कर या तो मूल्य

(Ad Velorem) या परिमाणानुसार (Specific) लगाया जाता है। यह कर या तो राज्य की आय बढ़ाने के लिये लगाया जाता है या देश के उद्योग-धन्धों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिये लगाया जाता है। पहले जब हमारा देश अबाध व्यापार की नीति पर था तब इस मद से बहुत कम आय प्राप्त होती थी पर जब से हमारे देश ने उद्योगों को संरक्षण देने की नीति अपनाई है तब से इस मद से काफी आय बढ़ गई है।

(२) उत्पादन शुल्क (Union Excise)—यह कर देश के अन्दर उत्पन्न होने वाली कुछ चीजों पर लगाया जाता है। इसीलिये इसको उत्पादन कर कहते हैं। हमारे देश में आजकल यह कर तम्बाकू, मिट्टी का तेल, वनस्पति तेल, दियासलाई, चाय, कपड़ा, चीनी, टायर, ट्यूब, कढ़वे आदि पर लगाया जाता है। ये कर आय प्राप्त करने तथा कभी-कभी कुछ चीजों का उपभोग बन्द करने के लिये लगाये जाते हैं।

(३) आय कर (Income Tax)—यह कर आय के ऊपर लगाया जाता है। इस कर की दर समय-समय पर बढ़ती रहती है। हमारे देश में यह कर स्लैब पद्धति (Slab system) के अनुसार लगाया जाता है। इसमें ३००० रुपये तक की आय के ऊपर कोई कर नहीं लगाया जाता। इसके ऊपर वाली आय के ऊपर कर लगना आरम्भ होता है। नीची आयदनी पर कर की दर नीची है। जैसे-जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे ही वैसे कर की दर बढ़ती जाती है। इस प्रकार यदि ३००० से ५००० रुपये की आय पर ३ प्रतिशत कर लगता है तो १५००० रुपये पर १४ प्रतिशत लगता है। १५००० रुपये से २०,००० रु० तक की आय पर कर की दर १८ प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त ७५०० की आय के ऊपर ५ प्रतिशत के हिसाब से एक अतिरिक्त कर (Surcharge) भी लगने लगता है। २०,००० रु० की आय से ऊपर सुपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। ऐसा करते-करते कर की दर अर्जित आय के केस ७७ प्रतिशत तथा अनाजित आय के केस में ८४ प्रतिशत तक पहुँच जाती है। इस प्रकार हमारी कर पद्धति वर्तमान कही जा सकती है। १९५७-५८ से जहाँ कर लगाने की न्यूनतम सीमा ४२०० रु० से घटाकर ३००० रु० की गई है वहाँ बच्चों की छूट भी दी जाती है जो कि प्रति बच्चा ३०० रु० है। परन्तु छूट ६०० से अधिक नहीं दी जा सकती।

आय कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया तथा वसूल किया जाता है। परन्तु इसका कुछ भाग राज्यों को भी दिया जाता है। प्रथम वित्तीय आयोग की सिफारिश के अनुसार कुल आय कर का ५५ प्रतिशत राज्यों को बाँटा जाता है। इसमें से ८० प्रतिशत तो जनसंख्या के हिसाब से तथा २० प्रतिशत कर के एकत्र करने के स्थान के हिसाब से बाँटा जाता था। परन्तु दूसरे वित्तीय आयोग ने सिफारिश की है कि कुल एकत्र किये गए धन का ६० प्रतिशत राज्यों में बाँटा जाय जिसमें से ६०% जनसंख्या की दृष्टि से तथा १० प्रतिशत उसके एकत्र करने के स्थान की दृष्टि से बाँटा जाय।

भारत सरकार का बजट
(लाल बपये में)

आय के मद्र	बजट १९५८-५९	संशोधित १९५८-५९	बजट १९५९-६०	व्यय के मद्र	बजट १९५९-६०	संशोधित १९५८-५९	बजट १९५९-६०
सीमा शुल्क	१७०००	१६६००	१३०,००० + २७७५	राजस्व पर सीधी माँगें	२४४५	६६६३	१०१६५
यूनियन उत्पादन कर	३०४७६	३०११५	३०७०० + १८०८५	सिंचाई	१३	१६	१६
कार्पोरेशन कर	५४५०	५६००	५८७५	कृषि पर व्याज	५०००	४२०६	५७८८
आय कर	१६१५०	१६२५०	१६६२५	नागरिक प्रशासन	२००४४	१६७७२	२२२७३
सम्पत्ति शुल्क (Estate Duty)	२५०	२५०	२८५	मुद्रा व टकसाल	८५०	६१४	६८३
पूँजी कर (Wealth Tax)	१२५०	१०००	१०५० + २५०५	नागरिक निर्माण			
रेल भाड़े पर कर	६२२	११००	११००	विविध सांख्यिक उन्नति	१८७१	१८३२	१६३५
व्यय पर कर (Expenditure Tax)	३००	१००	१००	पेयान	६४०	६५१	६१३
				विविध—			
उपहार कर	२००	१२०	१२०	सारणायियों पर व्यय	२०४८	२४७५	१६६६

वर्ग	१९३१	१९३२	१९३३	१९३४	१९३५	१९३६	१९३७	१९३८	१९३९	१९४०
अन्तर्गत	३६३	१०७५	३५८०	५५६३	३५६०	३००	४१६३	५२०	५५८	७१३०
राज्य	८३१	८३६	४५२४	३६६२	२८७	२८२१	२३४	७०४	—७६६७	५७८१
नागरिक प्रशासन -										
मुद्रा व टंकमाला	६६०	४५२४	३६६२	२८७	२८२१	२३४	७०४	—७६६७	—५६६५	५७८१
नागरिक निर्माण कार्य	३६३	१०७५	३५८०	५५६३	३५६०	३००	४१६३	५२०	५५८	७१३०
आय के अन्य साधन	८३१	८३६	४५२४	३६६२	२८७	२८२१	२३४	७०४	—७६६७	५७८१
डाक और तार	६६०	४५२४	३६६२	२८७	२८२१	२३४	७०४	—७६६७	—५६६५	५७८१
रेल	३६३	१०७५	३५८०	५५६३	३५६०	३००	४१६३	५२०	५५८	७१३०
घटाओ—राज्यो का आय	८३१	८३६	४५२४	३६६२	२८७	२८२१	२३४	७०४	—७६६७	५७८१
कर का भाग	६६०	४५२४	३६६२	२८७	२८२१	२३४	७०४	—७६६७	—५६६५	५७८१
सम्पत्ति शुल्क	३६३	१०७५	३५८०	५५६३	३५६०	३००	४१६३	५२०	५५८	७१३०
रेल भाडे	८३१	८३६	४५२४	३६६२	२८७	२८२१	२३४	७०४	—७६६७	५७८१
यवट प्रस्तावो का प्रभाव	६६०	४५२४	३६६२	२८७	२८२१	२३४	७०४	—७६६७	—५६६५	५७८१

(४) कारपोरेशन कर—यह कर कम्पनियों की आय पर सुपर टैक्स के रूप में लगाया जाता है और अधिक से अधिक दर पर लगाया जाता है। इसमें आय का कोई भी भाग कर मुक्त (Tax Free) नहीं होता।

(५) सम्पत्ति शुल्क (Estate Duty)—यह भारत के लिये एक नया कर है। यह अवतूबर १९५३ से लागू किया गया है। इस कर के अनुसार किसी व्यक्ति के मर जाने के पश्चात् उसकी सम्पत्ति का कुछ भाग सरकार ले लेगी। यह ५०,००० रु० की सम्पत्तियों से ऊपर लगेगा। इस कर को केन्द्रीय सरकार लगायेगी परन्तु इसका अधिकतर भाग राज्यों में बाँटा जाता है। यह कर ५०,००० रु० तक नहीं लगता (अगले ५०,००० रु० पर ६ प्रतिशत, उससे अगले ५०,००० रु० पर ८ प्रतिशत, उससे अगले ५०,००० रु० पर १० प्रतिशत, उससे अगले १,००,००० रु० पर १२ प्रतिशत, इस प्रकार कर की दर बढ़ती जाती है। अन्त में ५० लाख रु० से अधिक की सम्पत्ति पर कर की दर ४० प्रतिशत हो जाती है।

पूँजी कर (Wealth Tax)—यह एक नया कर है। यह कर व्यक्तियों सामूहिक परिवारों तथा कम्पनियों द्वारा दिया जायेगा। परन्तु जिन व्यक्तियों की सम्पत्ति दो या दो लाख से कम होगी उनको यह कर नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रकार सामूहिक परिवारों को ४ लाख रु० तक की छूट दी गई है। कम्पनियों को ५ लाख रु० तक की वास्तविक पूँजी पर कोई कर नहीं देना पड़ेगा। उसके पश्चात् यह कर निम्नलिखित ढंग से लिया जायेगा:—

व्यक्तियों से—

दो लाख से ऊपर अगली दस लाख की वास्तविक पूँजी पर	३%
उसके पश्चात् अगली १० लाख की वास्तविक पूँजी पर	१%
उसके पश्चात् शेष वास्तविक पूँजी पर	१३%

सामूहिक परिवारों से—

पहले ४ लाख की वास्तविक पूँजी पर	कुछ नहीं
उसके पश्चात् ६ लाख की वास्तविक पूँजी पर	३%
उसके पश्चात् की १० लाख की वास्तविक पूँजी पर	१%
उसके पश्चात् शेष वास्तविक पूँजी पर	१३%

कम्पनियों से—

पहले पाँच लाख की वास्तविक पूँजी पर	कुछ नहीं
उसके पश्चात् शेष वास्तविक पूँजी पर	३%

इस कर से निम्नलिखित सम्पत्ति मुक्त होंगी—कृषि सम्पत्ति, धार्मिक अथवा दान देने वाले ट्रस्टों की सम्पत्ति, नलात्मक कार्य, पुरानी चीजें जो बेचने के लिये न हों (Archaeological Collections), बीमा पालिसी तथा स्वीकृत प्रोविडेंट फंड में एकत्र धन, २५००० तक व्यक्ति वा पर्वीषर, कार, गहने आदि, वे वित्तार्थ जो बेचने के लिये न हों।

व्यय कर (Expenditure Tax)—यह एक ऐसा नया कर है जो अभी तक संसार के दूसरे देशों में लगा हुआ नहीं है। इस कर का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपने धन की दिखावे के लिये खर्च न करे और उसको धन बचाने में प्रोत्साहन मिले। प्रारम्भ में यह कर उन व्यक्तियों तथा सामूहिक परिवारों पर लगाया जायगा जिन की आय, आय-कर के लिये ६०,००० रु० से कम नहीं है। यह कर कुछ खर्च से अधिक जो कि परिवार के साइज पर निर्भर होगा, हर प्रकार के खर्च पर लगाया जायगा। यदि व्यक्ति तथा उसकी पत्नी का खर्च २४००० रु० तक होगा तो उनको कोई कर न देना पड़ेगा। उसके पश्चात् प्रत्येक बच्चे के लिये ५००० रु० की छूट दी जायेगी। इस कर की दर स्तैव पद्धति पर आधारित होगी। ऊँचे-ऊँचे खर्चों पर कर की दर बढ़ती जायगी। यह कर १९५८-५९ से लागू किया गया।

सम्बन्धित दोनों करों का उद्देश्य कर पद्धति में समानता लाना तथा कर से बचने वालों को हर प्रकार से पकड़ना है क्योंकि यदि वे आय-कर नहीं देते तो उस धन को या तो वे किसी व्यापार में लगायेंगे या उसको खर्च करेंगे। व्यापार में लगाने पर उनको पूंजी कर देना पड़ेगा तथा खर्च करने में उनको व्यय-कर देना पड़ेगा। इस प्रकार कर से बचने वाले कर से बचने का अधिक प्रयत्न न करेंगे।

(६) अफीम—अफीम की खेती करना, बढ़ाना तथा बेचना यह राज्य का एकमात्र अधिकार (Monopoly) बहुत पुराने समय से रहा है। पहले हमारे देश से बहुत सी अफीम चीन को जाती थी। उस समय इस मद से बहुत सी आय प्राप्त होती थी। पर अब चीन की अफीम जानी बन्द हो गई है। अब अफीम से १९५६-५७ में केवल २२४ लाख रुपये बसूल हुए और १९५७-५८ में २५० लाख रुपये बसूल होने की आशा है।

(७) व्याज—यह व्याज केन्द्रीय सरकार उच्च ऋण पर प्राप्त करती है जो वह राज्य सरकारों तथा दूसरे देशों को देती है।

(८) नागरिक प्रशासन—यह आय केन्द्रीय 'सरकार राज्य' के लोगों को न्याय आदि देने के सम्बन्ध में प्राप्त करती है।

(९) मुद्रा और टकसाल—रिजर्व बैंक को नोट छापने तथा सरकार को धातु के सिक्के बनाने से जो लाभ होता है वह इस मद के अन्तर्गत आता है।

(१०) नागरिक निर्माण—यह आय सड़कों, इमारतों तथा केन्द्र द्वारा नियन्त्रित नहरों द्वारा प्राप्त होती है।

(११) डाक और तार—डाक और तार पर केन्द्रीय सरकार का एकाधिकार है और उससे प्राप्त आय उसी को मिलती है।

(१२) रेलें—रेलो पर भी केन्द्रीय सरकार का एकाधिकार है। अपने सब खर्च काट कर आय का कुछ भाग रेलें जनरल रिवेन्यूज में हस्तान्तरित करती हैं।

(१३) नमक—भारत के स्वतन्त्र होने के पूर्व हमारे देश में नमक से लगभग ८ करोड़ रुपये की आय प्राप्त होती थी। अब नमक पर कोई कर नहीं है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता हाथ में आते ही सब से पहले इस कर को हटाया, क्योंकि १९३१ में गांधी जी ने अपना आन्दोलन नमक का कानून तोड़कर ही चलाया था। बात यह है कि नमक जीवन की प्रमुख आवश्यकता है और इसका भार सबसे अधिक गरीबों पर पड़ता है। इसी कारण इस कर को हटाया गया है। परन्तु अब बहुत से लोग आय प्राप्ति के हित में इसको फिर से लगाने की बात का समर्थन करते हैं।

केन्द्रीय व्यय के मद—

(१) राजस्व से सीधी मांगें—केन्द्रीय सरकार को भिन्न भिन्न करों के वसूल करने में जो खर्च करना पड़ता है वह इस मद में आता है।

(२) सिंचाई—केन्द्रीय सरकार को बड़ी-बड़ी सिंचाई की योजनाओं जैसे दामोदर घाटी की योजना, हीरा कुंड की योजना आदि, पर जो रुपया खर्च करना पड़ता है वह इस मद में आता है।

(३) ऋण पर व्याज—केन्द्रीय सरकार को बहुत से कामों के लिये देश तथा विदेशों से जो ऋण लेना पड़ता है वह उस ऋण पर जो व्याज देती है वह इस मद में आता है।

(४) नागरिक शासन—सरकार को बहुत से बड़े-बड़े अफसर शासन प्रबन्ध करने के लिये रखने पड़ते हैं, संसद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ता देना पड़ता है। राजदूतों का खर्च उठाना पड़ता है। यह आजकल बहुत अधिक है। युद्ध के पहले इस मद पर ८ करोड़ रुपया खर्च किया जाता था। १९५३-५४ में यह खर्च बढ़ कर ६८-५७ करोड़ हो गया है। १९५४-५५ में यह खर्च ६३-६३ करोड़ रुपया हो गया तथा १९५५-५६ में यह १०५-४१ करोड़, तथा १९५६-५७ में १३३-६४ करोड़, १९५७-५८ में १६८ करोड़ ४०, १९५८-५९ में १९८ करोड़ तथा १९५९-६० में २२३ करोड़ होने की आशा है।

इस खर्च की बाबत भारत में सदा ही असन्तोष रहा है। लोगों का कहना था कि आई० ए० एस० के लोगों को सरकार बड़े वेतन देती है जो अनुचित है। अपनी सरकार के स्थापित होने पर आशा थी कि इस मद पर कम खर्च होने लगेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। खर्च पहले से कई गुना हो गया है क्योंकि सरकार ने अफसरों का वेतन तो कम किया नहीं उल्टा बढ़ा दिया है। साथ साथ उसने नये नये विभाग खोलकर नये-नये दूतावास स्थापित करके खर्च को बढ़ा दिया है। यह अनुचित है। इस खर्च को कम करना आवश्यक है।

(५) मुद्रा और टकसाल—सरकार का सिक्का बनाने तथा रिजर्व बैंक का नोट बनाने में जो धन व्यय होता है वह इस मद में आता है।

(६) नागरिक निर्माण कार्य—इसमें वह खर्च सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार सड़को, इमारतों आदि के ऊपर करती है ।

(७) पेन्शन—इसमें नौकरी से रिटायर्ड होने वाले लोगों की पेन्शन सम्मिलित है ।

(८) शरणार्थियों पर व्यय—पाकिस्तान बन जाने पर जो लोग भारतवर्ष में आये उन पर केन्द्रीय सरकार को बहुत सा धन खर्च करना पड़ा । मद्यपि देश का विभाजन हुये लगभग १२ वर्ष हो गये हैं तो भी १९५६-५७ में इस मद पर २१.८६ करोड़ रुपये, १९५७-५८ में १२.५० करोड़ रुपये, १९५८-५९ में लगभग २५ करोड़ रु० तथा १९५९-६० में लगभग २० करोड़ रु० खर्च होने का अनुमान है ।

(९) खाद्य पदार्थों पर व्यय—इस देश में खाद्य पदार्थों की कमी हो जाने पर सरकार को बहुत सा अन्न विदेशों से ऊँचे मूल्य पर खरीदना पड़ा । पर इसलिये कि उससे जनता का जीवन-स्तर महँगा न हो जाये सरकार ने उसको नीचे भाव पर बेचा । इस प्रकार जो घाटा हुआ वह सरकार ने स्वयं ही उठाया । सरकार ने इस खर्च को कई वर्षों तक किया पर अब इसके लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता ।

(१०) राज्यों की सहायता—सरकार समय-समय पर राज्यों को बहुत से कामों के लिये जैसे कुएँ बनवाने के लिये अथवा अज्ञान पीड़ितों की सहायता करने के लिये बहुत सा धन सहायता के रूप में देती रही है, वही इस मद में आता है ।

(११) रक्षा व्यय—रक्षा के ऊपर भी हमारे देश में बहुत अधिक धन खर्च होता रहता है । इस खर्च के ऊपर भी भारतवासियों में सदा ही असन्तोष रहा है । युद्ध से पहले यह व्यय ४६ करोड़ रुपये के लगभग था पर युद्ध में यह कई सौ करोड़ रुपए हो गया । युद्ध समाप्त होने पर यह आशा की जाती थी कि इस मद पर कम व्यय होने लगेगा । पर अब भी सरकार इसके लिये एक बड़ी सेना रखती है क्योंकि उसे विदेशी हमले का बहुत भय रहता है । १९५६-५७ में इस मद पर २०.२९५ करोड़ रुपए खर्च हुए, १९५७-५८ में इस मद पर २५६.७२ करोड़ रुपये, १९५८-५९ में २६६.८७ करोड़ रु० तथा १९५९-६० में २४२.६८ करोड़ रुपये खर्च होने की आशा है ।

यद्यपि स्वतन्त्रता से पूर्व हम इस व्यय के विरुद्ध बहुत सी बातें कहते थे परन्तु आजकल की परिस्थिति में जबकि हमको अपने लिये भूमि, जल तथा वायु सेना का प्रबन्ध करना है, युद्ध का सामान बनाना है, नौजवानों को सैनिक शिक्षा देनी है, पाकिस्तान जैसे शत्रु का सामना करना है, यह खर्च बढ़ना स्वाभाविक ही है ।

राज्य सरकारों की आय और व्यय के भेद

राज्य सरकारों के जिम्मे वे मद हैं जिन पर सारे राष्ट्र का जीवन निर्भर रहता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई आदि । परन्तु इनके पास जो आय के मद हैं इन्से कम आमदनी होती है और जो होती भी है वह आवश्यकता के साथ नहीं बढती । इस कारण राज्य सरकारों को अपनी आय बढ़ाने के लिये नये कर

उत्तर प्रदेश सरकार का बजट
(साल १० में)

आय के मद	बजट अनुमान १९४८-४९	समाधित बजट १९४८-४९	बजट अनुमान १९४९-५०	व्यय के मद	बजट अनुमान १९४८-४९	समाधित बजट १९४८-४९	बजट
यूनियन उद्धारन कर	११४१.२३	१२२१.६६	१२१४.०४	आय पर सीधी माँगें	१११८.३२	१०९८.४०	१२३६.७३
क. पॉरेशन कर के अति-	१३२७.२३	१३०७.०९	१३६६.२२	सिचार्ज	४०४.४४	४११.४६	४४४.१६
रिक्त अन्य आयों पर कर				ऋण सेवायें	८७४.४६	८२३.३७	१३२६.९३
सम्पत्ति शुल्क	३६.६२	३६.६२	३६.६२	नागरिक प्रवासन	४९८४.०२	४९१८.१६	६२४७.७६
रेलों के किराये पर कर	१८४.७९	२०४.३०	२०४.३०	नागरिक निर्माण कार्य	४७९.४८	४११.६०	४४०.९७
मालगुजारी	२११२.४९	१८४१.४९	२११७.०३	विजली	३०८.८९	३२०.०९	१०१.७४
राज्य थाकवारी कर	४०४.४०	४३१.२३	४४१.७३	विविध	९३३.२४	१००७.८३	१२६०.१८
स्टाम्प	२९०.००	३१४.००	३४४.००	असाधारण मद	६४१.४४	८७७.३७	८८४.८२
अगल	४८२.३३	४१४.४४	४२१.२१				

विवरण	१९८२-८३	१९८३-८४	१९८४-८५	१९८५-८६
रजिस्ट्री	५३.३०	७१.०५	६५.३८	
गाड़ियों पर कर	१३५.००	१७०.००	२०६.००	
विधवा कर	—	—	६६५.००	
खाना पर कर	१३०३.१८	१५२६.८५	८०७.५३	
मिठाई (बाजारिक माल)	२४१.५०	२३८.७२	२७४.७३	
पूजा सेवामें	७२.१६	८५.०२	३३३.८१	
नागरिक प्रसाधन	१६१८.०१	१६६४.८५	१८८८.४८	
नागरिक निर्माण कार्य	२५६.७३	१६७.३८	२०३.३२	
विजरी	१०७.८५	८२.५३	—	
निमित्त	२७०.२२	३१७.११	३०१.३५	
राजपूत वीरेंद्र का अनुदान	००.२७	००.७३	००.२३	
नागरिक विकास योजनाएं	३८३.६७	३४४.५८	३१८.५६	
आदि				
प्रशासनिक भवन	२८२.८५	३७८.३४	५२६.२३	
योग	१०८२२.८२	११३३१.५४	११६६०.७७	११७७६.३५

लगाने पड़ते हैं। पर नये करों से कम और अनिश्चित आय होने के कारण उनको सदा ही केन्द्र की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है और यदि सहायता नहीं मिलती तो बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। प्रायः सब राज्य सरकारों के आय व्यय के मद एक से हैं पर कुछ राज्यों में दूसरों से एक दो कम या अधिक होते हैं। यह बात बनाने के पश्चात् हम उत्तर प्रदेश के आय-व्यय के मदों की बात लिखेंगे।

आय के मद—(१) यूनिजन उत्पादन कर, (२) कार्पोरेशन कर के अतिरिक्त अन्य आय कर, (३) सम्पत्ति शुल्क, (४) रेलों के विराये पर कर, (५) मालगुजारी, (६) आवकारी, (७) स्टाम्प, (८) जंगल, (९) रजिस्ट्री, (१०) मोटर कर, (११) मनोरंजन, बिजली तथा आय कर, (१२) सिंचाई, (१३) सूद, (१४) नागरिक निर्माण कार्य, (१५) नागरिक शासन, इनमें न्याय, जेल पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि और सहकारिता, उद्योग धंधे आदि सम्मिलित हैं, (१६) विविध, (१७) केन्द्रीय सरकार से सहायता, (१८) स्टेशनरी और छपाई, असाधारण प्राप्ति।

व्यय की मदें—(१) कर प्राप्ति का व्यय, (२) सिंचाई, (३) सूद, (४) नागरिक शासन, न्याय, जेल, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि, सहकारिता, उद्योग-धंधे आदि सम्मिलित हैं, (५) नागरिक निर्माण कार्य, (६) बिजली की योजनायें (७) विविध अकाल निर्माण पेन्शन, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, (८) राशनिंग व नियन्त्रण योजनायें, असाधारण मद।

आय के मदों का विवरण—

मालगुजारी— यह राज्य सरकारों की आय का एक मुख्य मद है। १९४०-४१ में उस मद से कुल आय का लगभग ५५ प्रतिशत प्राप्त हुआ। परन्तु घटते-घटते आजकल यह कुल का लगभग २० प्रतिशत रह गया है। १९३६-४० में इस मद से ६०५ करोड़ रुपया प्राप्त हुआ और १९५५-५६ में लगभग २१ करोड़। इस मद की आय बन्दोबस्त के समय ही जो ३०-४० वर्ष में बदला जाता है, बदली जा सकती है।

आय कर में एक अच्छी कर पद्धति के कई गुण पाये जाते हैं। जैसे, यह निश्चित है क्योंकि बन्दोबस्त ३०-४० वर्ष में एक बार बदला जाता है। यह सुविधाजनक है। क्योंकि यह फसल कटने के पीछे वसूल की जाती है। इसके वसूल करने का खर्च भी अल्प नहीं है। परन्तु इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि यह वेलोच है। हमारी आय ३०-४० वर्ष से पहले बढ़ाई नहीं जा सकती। इसके अतिरिक्त इस कर के वसूल करते समय यह ध्यान नहीं रखा जाता कि भूमि पर कौनसी फसल उत्पन्न की गई है तथा किसान की आर्थिक स्थिति क्या है।

कृषि आय कर— उत्तर प्रदेश में कृषि आय कर १९४-४६ से लगाया गया है। यह कर ३००० रु० की आय तक नहीं लगाया जाता। इसके ऊपर यह स्लैब पद्धति पर लगाया जाता है। यह कर उन्हीं किसानों पर लगाया जाता है जिनकी भूमि ५० एकर से अधिक है। इस स्रोत से अभी तक कोई विशेष आय नहीं होती।

आबकारी—राज्य सरकारों का अफीम, शराब तथा अन्य मादक चीजों के उत्पादन पर एकाधिकार है। उत्पादकों से कर और बेचने वालों से लाइसेंस फीस ली जाती है। परन्तु जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से उन्होंने मद्य-निषेध करना आरम्भ कर दिया है। इसी कारण इस मद की आमदनी घट रही है। बम्बई तथा मद्रास में जहाँ पूरे तौर पर मद्य-निषेध हो गया है इस मद की आय प्रायः समाप्त हो गई है।

मद्य निषेध की नीति (Policy of Prohibition)—आजकल बहुत से राज्यों ने मद्य निषेध की नीति को अपनाया है। परन्तु इस नीति की बहुत से आदमी बड़ी आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि इसके कारण राज्यों की आय घट जायेगी परन्तु मद्य पीने वालों को कोई लाभ न होगा क्योंकि वे छिपे-छिपे पीते रहेंगे। उनको रोकने के लिये सरकार को पुलिस रखनी पड़ेगी जिसके कारण राज्यों का खर्च और बढ़ जायगा।

परन्तु इस नीति से बहुत लाभ हुआ है तथा आगे होने की आशा है। बखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'स्वतन्त्रता का दसवाँ वर्ष' नामक पुस्तक में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आलोचक चाहे जो कुछ भी कहें परन्तु यह बात अवश्य है कि पीने वाले भी अब पहले से कम पीते हैं, इससे गरीब आदमियों को विशेषतः लाभ हुआ है क्योंकि वे अब कम शराब पीते हैं। इनसे इन परिवारों में पहले से अधिक प्रसन्नता पाई जाती है तथा बच्चों को शराब पीने की आदत कम पड़ेगी। शराब के कम पीने के कारण विलासिता भी अवश्य कम हो जायेगी। इस प्रकार इस समय चाहे राज्यों को थोड़ी हानि हो जाय परन्तु आगे चल कर सारे देश को इससे लाभ होगा।

स्टाम्प, जगल, मोटर कर, तथा रजिस्ट्री—सरकार को इन सब मदों से भी बहुत सी आय प्राप्त होती है। स्टाम्प में खर्चों पर कर लगाये गये टिकट तथा पोर्ट फीस सम्मिलित है। जगलों से लकड़ी बेचकर तथा पशुओं को चराने पर आय प्राप्त होती है। मोटर कर में, मोटर चलाने के लाइसेंस की फीस होती है। सिचाई में नहरों तथा ट्यूब वेल की आय आती है। रजिस्ट्री में मकानों तथा जमीनों की बेचते समय जो रजिस्ट्री करानी पड़ती है उसकी आय है।

नागरिक शासन—इसमें न्यायालयों, जेल, पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, दृष्टि, सहायता तथा उद्योग धन्यों से जो आय प्राप्त होती है वह सम्मिलित है।

मनोरंजन कर—यह सिनेमा, थियेटर, घुड़दौड़ आदि के टिकटों पर लगता है।

बिजली कर—यह युद्ध के पश्चात् लगाया गया है। आजकल यह राज्य सरकारों की आय का एक मुख्य स्रोत है। यह कर विलासिता तथा आराम देने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं पर यह प्रायः नहीं लगाया जाता है। आजकल बपटा बिजली कीजों पर केन्द्र बिजली पर लगाकर राज्यों में बाँट देता है।

बिक्री कर के दोष

बिक्री कर में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं —

(१) यह एक प्रतिगामी कर है और इसका भार छोटी छोटी आय वाले व्यक्तियों पर पड़ता है।

(२) इस कर में लोगों की कर देने की योग्यता का विचार नहीं किया जाता।

(३) इसमें अर्जित व अर्जाजित आय में कोई भेद नहीं किया जाता।

(४) यह घर सेवाओं तथा लोकोपयोगी सेवाओं पर नहीं लगाया जाता। यदि यह उन पर भी लगाया जाता तो उसका अधिक भार अमीर लोगों पर पड़ता क्योंकि इन चीजों का उपभोग अधिकतर वही करते हैं। परन्तु कर प्रणाली ज्ञान आयोग ने इसका खंडन प्रशासन की कठिनाइयों के कारण किया है।

(५) बहुत सी दशाओं में दोहरा कर लग सकता है। जैसे ई घन पर लगाया गया कर एक बार तो ई घन खरीदते समय देना पड़ता है और दूसरे उस समय देना पड़ता है जब कि कोई वह वस्तु जिसके तैयार करने में वह ई घन काम में आता है। यदि समस्त बिक्री पर कर लगाया जाता है तो एक ही वस्तु पर कई बार कर लग जाता है।

(६) इस कर की व्यवस्था करनी बड़ी कठिन है क्योंकि यह कर खरीदार से वसूल किया जाता है। दूकानदार को हर खरीदार का हिसाब रखना पड़ता है।

(७) इस कर को एकत्र करने का खर्च बहुत अधिक होता है।

(८) इस कर से बचने में दूकानदार बहुधा सफल हो जाते हैं।

(९) कभी-कभी इसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि यह कर मोटर के तेल पर लगाया जाता है तो इससे मोटर मातायात में बड़ी बाधा आती है।

इन सब दोषों के होते हुये भी यह कर कई बातों के कारण लगाया जाता है—

(१) इस कर से पर्याप्त आय प्राप्त होती है। (२) इसकी व्यवस्था करने में सरकार को कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। (३) इस कर का भार खरीदार को अधिक महसूस नहीं होता क्योंकि वह कर को मूल्य का एक अंग समझता है।

(४) सरकार के बढ़ते हुये खर्चों के कारण बहुत से देशों में इसको लगाया जाता है।

आय कर—यह कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। उसका कुछ भाग केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को, जिल्लिय आयोगों के निर्णय के अनुसार देती है।

व्यय के मद

कर प्राप्ति व्यय—यह व्यय भिन्न-भिन्न करों को प्राप्त करने के लिये करना पड़ता है।

सिचाई—सरकार को नहरों, कुएँ, तालाब आदि बनवाने में जो खर्च करना पड़ता है वह इस मद में आता है।

सूच—यह सूद राज्य सरकारों की जनता तथा केन्द्रीय सरकार से लिये हुये ऋण पर देना पड़ता है।

नागरिक प्रशासन—इस मद में पुलिस, जेल, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि सहकारिता आदि का खर्च आता है। राज्य सरकारों को देश में शान्ति रखने के लिए पुलिस तथा जेलों का प्रबन्ध करना पड़ता है। लोगों के झगड़ों का फैसला करने के लिए न्यायालय खोलने पड़ते हैं। इन मदों पर सरकार को बहुत धन व्यय करना पड़ता है। इनके साथ इस मद के अन्तर्गत गवर्नर, मन्त्रियों तथा धारा सभा का भी खर्च आता है।

इस मद के अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा, कृषि सहकारिता, आदि भी आते हैं। इन सब के ऊपर राष्ट्र के लोगों का जीवन निर्भर होता है। अंग्रेजों के शासन काल में इस मद पर बहुत कम व्यय होता था। परन्तु अब से अपनी सरकार बनी है तब से वह इन मदों पर अधिकाधिक खर्च करती जा रही है। पर अभी तक इन मदों पर व्यय आवश्यकता से बहुत कम है। इसका कारण यह है कि राज्य सरकारों के पास जो आय के मद हैं उनसे आय आवश्यकता के अनुसार नहीं बढ़ती। इसी कारण इस बात की आवश्यकता है कि वह नये नये आमदनी के मद खोजें या केन्द्रीय सरकार उनको ऐसे आमदनी के मद सौंपे जो आवश्यकतानुसार बढ़ सकें।

पंचवर्षीय योजना की अर्थ-व्यवस्था

प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कुल २३३१ करोड़ रु० खर्च होने की आशा थी। परन्तु वास्तव में इस पर १९४७ करोड़ रुपये खर्च हो सके। प्रारम्भ के कुछ वर्षों में खर्च की गति बड़ी धीमी थी परन्तु धीरे-धीरे इसको बढ़ाया गया। जैसे १९५१-५२ में यह खर्च २५९ करोड़ था तथा १९५२-५३, १९५३-५४, १९५४-५५ तथा १९५५-५६ में यह खर्च क्रमशः २७३ करोड़ रु०, ३४० करोड़ रु०, ४७५ करोड़ रु० तथा ६०० करोड़ रु० था। इस सब धन को विदेशी सहायता, सार्वजनिक ऋण, अल्प आय वालों को बचत करने का प्रोत्साहन देकर तथा हीनार्थ प्रवर्धन (Deficit Financing) से पूरा किया गया। इसमें से २३५ करोड़ रुपये अल्प बचत से, २०४ करोड़ रु० विदेशी सहायता से, ४०० करोड़ रु० हीनार्थ प्रवर्धन के रूप में, १४० ए० करोड़ पाँड पावने में से और सेप करो तथा अन्य ढंगों से प्राप्त किया गया।

दूसरी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में ४८०० करोड़ रु० खर्च होने की आशा है। इसमें से २४०० करोड़ रु० तो करो, ऋणों तथा अन्य आयों से प्राप्त किये जायेंगे। ८०० करोड़ रु० की सहायता विदेशों से मिलने की आशा की गई है परन्तु अभी हाल ही की वित्तीय मन्त्री की विदेश यात्रा से यह साफ पता चलता है कि इतनी विदेशी सहायता प्राप्त न हो सकेगी। इस कारण आजकल यह प्रयत्न किया जा रहा है कि विदेशी वित्तिय की अधिकाधिक बचत की जाय। २०० करोड़ रु०

पौड पावने से लिए जायेंगे और १२०० करोड़ रु० के नोट छाप कर अर्थात् हीनाथ प्रबन्धन से प्राप्त किये जायेंगे। फिर भी ४०० करोड़ रु० की कमी रह जायगी जो कि अन्य राष्ट्रीय साधनों से पूरी की जायगी।



Q. 97. What are the existing financial relations between the States and the Central Government in India ? Are State revenues adequate to meet their needs ? Suggest some remedies

प्रश्न ९७—भारत में वर्तमान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में किस प्रकार के आर्थिक सम्बन्ध हैं ? क्या राज्यों की आय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है ? इसको सुधारने के उपाय बताइये।

उत्तर—भारतवर्ष में १९१६ के मॉण्टफोर्ड सुधारों से पहले प्रान्तों को अपनी आर्थिक आवश्यकतायें पूरी करने के लिये केन्द्र के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। प्रान्तीय सरकारें कोई भी योजना उस समय तक कार्यान्वित नहीं कर सकती थी जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार से मंजूर न हो जाय। १९१६ के सुधारों के पश्चात् प्रान्तों को आर्थिक दृष्टि से कुछ स्वतन्त्रता मिली। उनको आय तथा व्यय के कुछ विषय मिल गये। परन्तु आय के साधनों में खेती की मालगुजारी, वन, स्टाम्प आदि सम्मिलित थे जिनसे आय अस्थायी सी रहती थी। इसके विपरीत व्यय के विषयों में खेती, उद्योग धन्धे, शिक्षा, सब्जें आदि सम्मिलित थे जिन पर बहुत धन व्यय करने की आवश्यकता पड़ती थी। इस कारण प्रान्तीय सरकारें कोई विशेष कार्य न कर सकीं।

१९३५ के भारत सरकार एक्ट के अनुसार प्रान्तों को स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई। अब वे जनता की चुनी हुई धारा सभाओं द्वारा कर लगा सकते थे तथा अपनी इच्छानुसार उनको खर्च कर सकते थे। इस एक्ट के अनुसार केन्द्र तथा प्रान्तों में आय के साधन साफ तौर पर बँट गये। कुछ विषय तो ऐसे थे जो केन्द्र को मिल गये। उनमें आयात निर्यात कर, सिक्के बनाने का लाभ, नमक आदि सम्मिलित थे। कुछ मद प्रान्तों को दे दिये गये। उनमें मालगुजारी की आय पर कर, मादक वस्तुओं पर उत्पात कर, वन, बिजली कर, मनोरंजन कर आदि सम्मिलित थे। आय-कर प्रान्तों तथा केन्द्र दोनों में बँटता था।

इतना करने के साथ साथ यह बात भी विचारी गई कि इस प्रकार के प्रबन्ध के कारण कुछ प्रान्तों को भारी घाटे का सामना करना पड़ेगा। इस कारण सर ओटो नीमियर को इस बात की खोज करने के लिये नियुक्त किया गया कि वह कोई ऐसा ढंग बतायें जिससे प्रान्तीय सरकारों को कार्य करने में कठिनाई न उठानी पड़े। ओटो नीमियर ने अप्रलिखित सुझाव दिये—

(१) बंगाल, बिहार, आसाम आदि को जो केन्द्रीय सरकार का १९३६ के पहले का ऋण देना था उसको माफ कर दिया जाये ।

(२) जूट उगाने वाले प्रान्तों को जूट कर का ६२½ प्रतिशत दिया जावे ।

(३) प्रान्तों को उपर्युक्त सहायता के अतिरिक्त कुछ सहायता रुपये में भी दी जाय जिससे कि बजट का घाटा पूरा हो सके । यह सहायता इस प्रकार थी— बंगाल को ७५ लाख रुपए, बिहार को २५ लाख रुपए, उड़ीसा को ५० लाख रुपए, मध्य प्रदेश को १५ लाख रुपए, आसाम को ४५ लाख रुपए तथा उत्तर प्रदेश को २५ लाख रुपए ।

(४) इस प्रकार की अस्याई सहायता देने के अतिरिक्त प्रान्तीय सरकारों को स्याई सहायता देने का सुझाव भी दिया गया । यह सहायता आय-कर (Income Tax) का ५० प्रतिशत होनी चाहिए । मोटो नीमियर ने भिन्न प्रान्तों में इस घन को बाँटने का निम्नलिखित ढङ्ग बताया—मद्रास को १५ प्रतिशत, बम्बई को २० प्रतिशत, बंगाल को २० प्रतिशत, उत्तर प्रदेश को १५ प्रतिशत, सीमा प्रान्त को १ प्रतिशत तथा सिन्ध में से प्रत्येक को २ प्रतिशत ।

केन्द्रीय सरकार को अधिक सकट से बचने के लिए यह सुझाव भी दिया गया कि केन्द्र को प्रान्तीय सरकारों के हिस्से को उस समय तक उनको नहीं देना चाहिए जब तक कि केन्द्र की आय कर का भाग तथा केन्द्र की रेलों से होने वाली आमदनी दोनों मिलाकर १३ करोड़ रुपए से अधिक न हो जायें । यह कार्य केन्द्र को ५ वर्ष तक करना चाहिए । अगले ५ वर्ष में केन्द्र को थोड़ा-थोड़ा करके प्रान्तों का भाग सोटाना चाहिए ।

प्रान्तों को स्वशासन देने के पूर्व यह आशा की जाती थी कि प्रान्तों को प्रारम्भ में आय-कर में से कुछ भी न मिलेगा । पर रेलों की आय बढ़ जाने के कारण प्रान्तों को आय-कर का अपना भाग पहले ही वर्ष में मिल गया । इधर कुछ ही समय पश्चात् युद्ध छिड़ गया । इस कारण केन्द्रीय सरकार को कानून में बदल करनी पड़ी जिससे कि वह १९३९-४०, १९४०-४१ तथा १९४१-४२ में प्रान्तीय सरकारों के आय-कर के भाग में से प्रनिवर्ष ४½ करोड़ रुपए रख सके । वही बात अगले तीन वर्षों में भी चली । १९४५-४६ में केन्द्र ने ३½ करोड़ तथा १९४७-४८ में ३ करोड़ रुपए रखे ।

देश के विभाजन के कारण सिन्ध तथा उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त हमारे देश से निकल गए तथा पंजाब व बंगाल का विभाजन हो गया । इस कारण प्रान्तों में आय-कर बाँटने की व्यवस्था में परिवर्तन करना आवश्यक हो गया । नई योजना १९४८ में घोषित की गई और इसमें १९४७-४८ तथा १९४८-४९ में काम लिया गया । इस योजना के अनुसार आय-कर निम्नलिखित ढंग से बाँटा गया—

बम्बई २१ प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल १२ प्रतिशत, मद्रास १८ प्रतिशत, संयुक्त प्रान्त १६ प्रतिशत, बिहार १३ प्रतिशत, पूर्वी पंजाब ५ प्रतिशत, मध्य प्रदेश तथा बरार ६ प्रतिशत, आसाम तथा उड़ीसा में से प्रत्येक को ३ प्रतिशत ।

इस योजना के अनुसार छूट उगाने वाले प्रान्तों को छूट निर्यात कर का भाग ६२½ प्रतिशत से घटा कर २० प्रतिशत किया गया। केवल आसाम व उड़ीसा को आर्थिक सहायता प्रदान की गई।

१९४८ की योजना से प्रान्तों में बड़ा असन्तोष था। इस कारण श्री देशमुख को इस पर विचार करने के लिए नियुक्त किया गया। देशमुख ने जो निर्णय दिया उसको १९४०-४१ तथा ४१-४२ में लागू किया गया। इस निर्णय के अनुसार राज्यों का आय-कर का भाग इस प्रकार बदल दिया गया—

बम्बई २१ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश १८ प्रतिशत, मद्रास १७½ प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल १३½ प्रतिशत, बिहार १२½ प्रतिशत, मध्य प्रदेश ६ प्रतिशत, पूर्वी पञ्जाब ५½ प्रतिशत, आसाम व उड़ीसा में से प्रत्येक ३ प्रतिशत।

छूट उगाने वाले प्रान्तों को कुछ समय तक आर्थिक सहायता देने का भी प्रबन्ध किया गया। यह पश्चिमी बंगाल के लिए १९५ लाख रुपए, आसाम के लिए ५ लाख रुपए थी।

१९५१ में प्रथम वित्त आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग के अनुसार राज्यों को आय-कर का ५० के स्थान पर ५५ प्रतिशत भाग मिलने लगा। इस घन का बँटवारा राज्यों में जनसंख्या तथा आय के स्रोत के अनुसार किया गया—जन-संख्या के अनुसार ६६ तथा आय के स्रोत के अनुसार ३। इसके अतिरिक्त राज्यों को सम्बाङ्ग, दिघासलाई, वनस्त्राति घी द्वारा प्राप्त किये गये उत्पादन कर का ४० प्रतिशत जनसंख्या के हिसाब से बाँटा गया। छूट उगाने वाले राज्यों को छूट निर्यात कर में से निम्नलिखित ढग से सहायता दी गई—

पश्चिमी बंगाल १५० लाख रुपए, आसाम ७५ लाख रुपए, बिहार ७५ लाख रुपए, उड़ीसा १५ लाख रुपए।

इसके अतिरिक्त कुछ निम्नलिखित राज्यों को शिक्षा आदि का प्रसार करने के लिए सहायक अनुदान दिए गए।

आय-कर का बँटवारा निम्नलिखित ढग से किया गया—

बम्बई १७½ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश १५ ७५ प्रतिशत, मद्रास १५ २५ प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल ११ २५ प्रतिशत, बिहार ६ ७५ प्रतिशत, मध्य प्रदेश ५ २५ प्रतिशत, हैदराबाद ४ ५० प्रतिशत, उड़ीसा ३ ५ प्रतिशत, राजस्थान १ ५ प्रतिशत, पञ्जाब ३ २५ प्रतिशत, ट्रावनकोर कोचीर २ ५ प्रतिशत, आसाम २ ५ प्रतिशत, मैसूर २ २५ प्रतिशत, मध्य भारत १ ७५ प्रतिशत, सोराष्ट्र १ प्रतिशत, पेप्पू ० ७५ प्रतिशत।

इस आयोग की सिफारिशों की निम्नलिखित आलोचनाएँ की गई हैं—

(१) आय-कर को आय के स्रोत के अनुसार बाँटना चाहिए।

(२) उत्पादन कर को उपयोग के अनुसार न बाँट कर आय के स्रोत के अनुसार बाँटना चाहिये ।

(३) सहायक अनुदानों के कारण राज्यों की केन्द्र पर निर्भर रहना पड़ेगा और यह बात सघानीय सिद्धान्त के विरुद्ध है ।

(४) वास्तविक सघीय शासन में आय के ऐसे मद जिनका केन्द्र तथा राज्यों में बँटवारा होता है कम से कम होने चाहिये परन्तु उनको बढ़ा दिया गया है ।

नवम्बर १९५७ ई० में द्वितीय वित्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है । यह रिपोर्ट सरकार ने मान ली है और उस पर सीधे ही कार्य किया जायगा ।

इस आयोग ने सिफारिश की है कि आय-कर का ६० प्रतिशत राज्यों में बाँटा जाय । राज्यों में बँटवारे का आधार जनसंख्या तथा कर के एकत्र करने का स्थान होगा । कुल बाँटे जाने वाले कर का ६० प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर बाँटा जायगा तथा शेष १० प्रतिशत कर के एकत्र करने के आधार पर ।

इसके अतिरिक्त राज्यों को यूनिफन उत्पादन कर में से भी कुछ भाग दिया जायगा । प्रथम वित्तीय आयोग ने दिवासलाई, वनस्पति पी, तम्बाकू से प्राप्त होने वाली वास्तविक आय का ४० प्रतिशत राज्यों में जनसंख्या के आधार पर बाँटने की सिफारिश की थी । परन्तु द्वितीय आयोग ने उपर्युक्त तीन चीजों की वास्तविक आय के अतिरिक्त कहूँ, चाय, चीनी, कागज, वनस्पति गैर-जहूरी तेल से प्राप्त होने वाली वास्तविक आय को भी बाँटने की सिफारिश की है । परन्तु इन सब चीजों से प्राप्त होने वाली आय का केवल २५ प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर बाँटने की सिफारिश की गई है ।

सहायक अनुदान के विषय में आयोग ने सिफारिश की है कि यह पश्चिमी बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा में उतनी ही मात्रा में दिये जायें जितने कि ये प्रथम वित्तीय आयोग की सिफारिश के अनुसार दिए जाते थे । परन्तु अभी हाल ही में बिहार का कुछ भाग बंगाल को मिल जाने के कारण बिहार के सहायक अनुदान को २५६ लाख घटाकर उतने ही अधिक सहायक अनुदान को पश्चिमी बंगाल को दिया जाय । ये अनुदान १९६० ई० तक दिये जायेंगे ।

इनके अतिरिक्त निक्षेपण (Devolution) की योजना के अनुसार प्रथम वित्तीय आयोग ने कुछ निश्चित सहायता राज्यों को देने की सिफारिश की थी । यह सिफारिश सरकार ने मान ली थी । इसके अतिरिक्त यह भी सिफारिश की गई थी कि बिहार, हैदराबाद, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पेंडू, पंजाब तथा राजस्थान में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार के लिये १९५६-५७ तक ६ करोड़ रु० की सहायता दी जाय । द्वितीय आयोग ने इस प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की है । परन्तु इसने १४ राज्यों में से ११ राज्यों को पर्याप्त सहायता देने की सिफारिश की है ।

आयोग की इन तीनों सिफारिशों को हम एक तालिका के रूप में इस प्रकार रख सकते हैं ।

राज्यों का नाम	आय कर का भाग ६ प्रतिशत	यूनियन उत्पादन कर का भाग २५ प्रतिशत	विधान की धारा २७३ के अन्तर्गत सहायक अनुदान (लाख रुपये)
आन्ध्र प्रदेश	८.१२	६.३८	—
आसाम	२.४४	३.४६	७५.००
बिहार	६.६४	१०.५७	७२.३१
बम्बई	१५.६७	१२.१७	—
केरल	३.६४	३.८४	—
मध्य प्रदेश	६.७२	७.४६	—
मद्रास	८.४०	७.५६	—
मैसूर	५.१४	६.५२	—
उड़ीसा	३.७३	४.४६	१५.००
पंजाब	४.२४	४.५६	—
राजस्थान	४.०६	४.७१	—
उत्तर प्रदेश	१६.३६	१५.६४	—
पश्चिमी बंगाल	१०.०८	७.५६	१५२.६६
जम्मू काश्मीर	१.१३	१.७५	—

सम्पत्ति कर (Estate Duty) के विषय में आयोग ने सिफारिश की है कि ३१ मार्च १९५७ तक उसी योजना से काम लिया जाय जो कि पहले से चल रही है । उसके पश्चात् कुल कर में से १ प्रतिशत केन्द्र के लिये बचाकर शेष को राज्यों में बाँटा जाय । बाँटते समय कुल आय को चल व अचल सम्पत्ति की आय अलग-अलग करनी चाहिये । इसमें से अचल सम्पत्ति की आय उसकी स्थिति के आधार पर बाँटी जाय तथा चल सम्पत्ति की आय जनसंख्या के आधार पर बाँटी जाय ।

रेल भाड़े पर कर की कुल वास्तविक आय में से ३ प्रतिशत केन्द्र के लिए बचा कर शेष को प्रत्येक राज्य में स्थित रेल की लम्बाई के आधार पर बाँटा जाय ।

आयोग ने इस बात की भी जाँच की कि राज्यों को बिक्री कर से, चाहे वह किसी भी रूप में लगाया जाय, मिल के बने कपड़े चीनी तथा तम्बाकू से ३२ करोड़ रुपये की आय प्राप्त होती है । क्योंकि अब केन्द्र इन सब चीजों पर से बिक्री कर समाप्त करके उत्पादन कर लगाने वाला है इस कारण आयोग ने सिफारिश की है कि पहले राज्यों को इन तीनों चीजों की वास्तविक आय में से वह धन दिया जाय जिसकी उनकी बिक्री-कर समाप्त करने से हानि होगी । यह धन देने के पश्चात् जो

इन तीनों सिफारिशों को निम्नलिखित तालिका में दिखाया गया है—

राज्यों का नाम	विधान की धारा २७५ (१) के अनुसार दिये गये सहायक अनुदान (लाख रुपये में)	सम्पत्ति कर का भाग ६६%*	रेल भाड़े पर कर का भाग ६६.७५%
आन्ध्र प्रदेश	४००	८७६	८८६
आसाम	४०५*	२५३	२७१
बिहार	३८०*	१०८६	६३६
बम्बई	—	१३५२	१६२८
केरल	१७५	३७६	१८१
मध्य प्रदेश	३००	७३०	८३१
मद्रास	—	८४०	६४६
मैसूर	६००	५४३	४४५
उड़ीसा	३३५*	४१०	१७८
पंजाब	२२५	४५२	८११
राजस्थान	२५०	४४७	६७७
सत्तर प्रदेश	—	१७७१	१८७६
पश्चिमी बंगाल	३२५*	७३७	६३१
जम्मू काश्मीर	३००	१२४	—

* १९६०—६१ तथा १९६१—६२ में आसाम को ४५० लाख, बिहार को ४२५ लाख, उड़ीसा को ३५० लाख तथा पश्चिमी बंगाल को ४७५ लाख रुपये मिलेगा।

* अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त दूसरी सम्पत्तियों के लिए यह लागू होता है।

कुछ पन बचे उसको अशत जनसंख्या के आधार पर और अशत इन चीजों के समयोग के आधार पर बाँटा जाय। इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर आयोग ने बचे हुए धन को बाँटने का ढंग भी बताया है। आयोग ने सिफारिश की है कि इन तीनों चीजों से प्राप्त आय में से १ प्रतिशत केन्द्र रखे। १३ प्रतिशत जम्मू व काश्मीर को दिया जाय और शेष को राज्यों में बाँटा जाय। आयोग ने इस सम्बन्ध में जो सिफारिश की है उसको अग्रलिखित तालिका में दिया गया है।

आयोग ने राज्यों के ऋण के विषय में भी विचार किया है। आयोग ने सिफारिश की है कि बिना ब्याज के ऋण में कोई हेर-फेर न किया जाय। शरणाधिकियों को दिये गये ऋण के विषय में आयोग ने कहा है कि १ अप्रैल १९५७ से राज्य सरकारें केन्द्र को केवल वही धन दें जो कि शरणाधिकियों से मूलधन तथा ब्याज के रूप में प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त पिछला शेष भी उनको चुकाना होगा। इसके

राज्य का नाम	आय जो कि तीनो धीजों पर बिक्री कर समाप्त करने के कारण राज्यों को देने का आश्वासन दिया गया है	शेष का बँटवारा ६७.७५%
आन्ध्र प्रदेश	२३५ लाख रुपये	७.८१
आसाम	८५ "	२.७३
बिहार	१३०	१०.०४
बम्बई	६६०	१७.५२
केरल	६५	३.१५
मध्य प्रदेश	१५५	७.१६
मद्रास	२८५	७.७४
मैसूर	१००	५.१३
उड़ीसा	८५	३.२०
पंजाब	१७५	५.७१
राजस्थान	६०	४.३२
उत्तर प्रदेश	५७५	१७.१८
पश्चिमी बंगाल	२८०	८.३१
जम्मू व काश्मीर	—	वास्तविक आय का १.३%

अतिरिक्त ऋण को जिस पर व्याज की दर ३ या ३ से अधिक है, दो ऋणों में बदला जाय और उस पर ३ प्रतिशत व्याज लिया जाय। इनमें से एक ऋण वह होगा जो उन ऋणों से मिला कर बनेगा जिनके चुकाने की अवधि २० वर्ष या उससे कम है। यह ऋण १५ वर्ष में चुकाया जाय। शेष ऋणों को ३० वर्ष में चुकाया जाय। आयोग ने उस ऋण के लिए भी जिस पर व्याज की दर ३ प्रतिशत से कम है इसी प्रकार दो ऋणों में बदलने की सिफारिश की है। इन पर व्याज की दर २.२ प्रतिशत होगी।

आयोग का कहना है कि १९५६-५७ तक के पिछले पाँच वर्षों में केंद्र ने राज्यों को ६३ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से दिया है। उनकी सिफारिशों के फलस्वरूप राज्यों को १४० करोड़ रु० प्रतिवर्ष मिलेंगे। यह इसलिए किया गया है कि राज्यों को पंचवर्षीय योजना के लिये अधिक धन की आवश्यकता है। आयोग का विश्वास है कि उनकी इन सिफारिशों के कारण राज्यों को अपने बजट के सन्तुलन में सहायता प्राप्त होगी।

आलोचनाएँ—यद्यपि आयोग ने इस बात का प्रयत्न किया है कि छोटी सावधानी से राज्य अपने बजट का सन्तुलन कर सकें तो भी आयोग की सिफारिशों के विरुद्ध कुछ आलोचनाएँ की जाती हैं। आलोचना करने वाले, राज्य बंगाल व बम्बई हैं

क्योंकि कल कारखानों के स्थित होने व इन राज्यों में बन्दरगाह स्थित होने के कारण सबसे अधिक आय-कर इन राज्यों में ही एवज होता है। इन राज्यों का कहना है कि आय-कर का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर न करके उसके एकत्र करने के स्थान के अनुसार किया जाना चाहिए। ऐसा न करने के कारण बम्बई, बंगाल, मद्रास राज्यों को हानि व उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश राज्यों को लाभ होगा।

बंगाल व बिहार का यह कहना है कि जूट निर्यात कर के स्थान पर उसको जो सहायक अनुदान मिलेगा वह १९६० ई० में समाप्त हो जायगा। यह अनुचित है। इसको स्थायी रूप से दिया जाना चाहिए।

पश्चिमी बंगाल का यह भी कहना है कि उनको केन्द्र से जो सहायता मिलने वाली है उसमें चालू बजट के घाटे को पूरा करने की ओर ही ध्यान दिया गया है। यह अनुचित है क्योंकि इस राज्य को बहुत सा ऋण जमींदारी को समाप्त करने के कारण भी देना शेष है। आयोग को इसका भी ध्यान रखना चाहिए था।

पश्चिमी बंगाल का यह भी कहना है कि विधान की धारा २७५ के अन्तर्गत दिये जाने वाले सहायक अनुदान में धारणाधिकारियों के आने के कारण जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं उनका कोई ध्यान नहीं रखा गया। इस राज्य को १९६०-६१ व १९६१-६२ में ३२५ मिलियन रुपये के बदले ४७५ मिलियन रुपये मिलने चाहिये।

पश्चिमी बंगाल तथा अन्य राज्यों का यह भी कहना है कि कुल यूनियन उत्पादन कर को ५० प्रतिशत राज्यों में बाँटा जाना चाहिये। कुछ राज्यों का यह भी कहना है कि वह उत्पादन-कर जो कि केन्द्र तथा राज्यों में बाँटा जायगा उसको जनसंख्या के आधार पर बाँटना अनुचित है।

नये विधान में केन्द्रों तथा राज्यों में आय व्यय के मदों को उही प्रकार विभाजित किया गया है कि जिस प्रकार कि १९३५ के भारत एक्ट में। हाँ केन्द्रीय सरकार ने अब कहीं-कहीं अपनी कर लगाने की शक्ति को अधिक बढ़ा दिया है। जूट निर्यात कर अब केन्द्र को ही मिलेगा। जूट उगाने वाले राज्यों को केवल आर्थिक सहायता मिलेगी। राज्य पट्टे के समान ऋण ले सकते हैं।

भारत सरकार ने कमीशन की सब सिफारिशों को मान लिया है तथा उसके लिए आवश्यक कार्यवाही भी की जा चुकी है। परन्तु सरकार ने कमीशन की राज्यों के ऋण सम्बन्धी सिफारिश को नहीं माना है क्योंकि ऐसा करने से भारत सरकार राज्य को योजना अथवा उसके बाहर के ऋण न दे सकेगी। सरकार ने कमीशन की इस सिफारिश को भी नहीं माना है कि सब प्रकार के ऋणों के लिये व्याज की दर समान हो।

राज्यों की आय का प्रश्न—१९३५ के भारत सरकार एक्ट तथा नये विधान के अनुसार राज्यों को जो आय के मद दिए गये हैं उनमें मालगुजारी, मादक पदार्थों पर कर, जंगलार, स्टाम्प, रजिस्ट्री, बिक्री कर, धुपि आय-कर, मनोरंजन कर आदि

सम्मिलित हैं। इनमें मालगुजारी से राज्यों की सबसे अधिक आय प्राप्त होती है। पर मालगुजारी उन राज्यों में जहाँ पर स्थायी बन्दोबस्त है, बिल्कुल नहीं बढ़ाई जा सकती। उन राज्यों में भी जहाँ अस्थायी बन्दोबस्त है यह आय ३०-४० वर्ष पीछे बढ़ाई जा सकती है। दूसरे करो तथा मदो से बहुत कम आमदनी होती है। कुछ वर्षों से सभी राज्यों में बिक्री कर लगाया गया है। उनसे राज्यों की आय कुछ बढ़ी तो है पर वह बहुत अधिक नहीं बढ़ी। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यों के पास आय के जो मद हैं उनसे आवश्यकतानुसार आय बढ़ने की सम्भावना नहीं है।

इसके विपरीत राज्यों की व्यय के जो मद रीपे गए हैं उनमें प्रायः सभी ऐसे हैं जिन पर किसी राष्ट्र का जीवन निर्भर रहता है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग धंधे, सहकारिया आदि। इन सभी दिशाओं में हमारा देश सप्ताह के सभी देशों से पीछे है। इन सबकी उन्नति करने के लिये सैकड़ों करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यही नहीं, राज्य सरकारों ने जमींदारी उम्मूलन तथा मद्य निषेध का कार्य भी अपने ऊपर लिया है। जिन पर बहुत घन व्यय होगा। पर जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, राज्य सरकारों के पास इन सब चीजों पर खर्च करने की बहुत कम धन है। इसी कारण हमें यह आशा नहीं दिखाई पड़ती कि निकट भविष्य में राज्य सरकारें देश के लोगों का अधिक उत्थान कर सकेंगी। हमारे विचार में राज्यों की आय बढ़ाने के लिए निम्नलिखित बातें करनी चाहियें।

(१) राज्य सरकारों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे आय-कर पर १० व १५ प्रतिशत सरचार्ज लगा सकें।

(२) राज्यों को कृषि आय-कर लगाना चाहिए।

(३) राज्यों को अपनी मोटरों तथा उद्योग-धंधे चलाने चाहियें जिससे कि उनकी आय बढ जाय।

भारत का सार्वजनिक ऋण

Q. 98. What is the nature and extent of India's public debt as it stands at present ?

प्रश्न ९८—बताइये कि आजकल भारत का सार्वजनिक ऋण कितना तथा कैसा है ?

उत्तर—द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने पर इस देश के सार्वजनिक ऋण का बहुत बड़ा भाग उत्पादक (Productive) था। यह ऋण रेलों, डाकखानों-तार, नहरों आदि में लगा हुआ था। इस ऋण का कुछ भाग स्टर्लिङ्ग में तथा कुछ रुपये में था। १९१७-१९ में यह ऋण इस प्रकार था—७३६.६४ करोड़ अथवा ६१.१२ प्रतिशत रुपए में तथा ४६९.१२ करोड़ अथवा ३८.८ प्रतिशत स्टर्लिङ्ग में। इस ऋण में से ७८.४ प्रतिशत उत्पादक तथा केवल १९.२ प्रतिशत अनुत्पादक था तथा शेष प्रतिभूतियों के रूप में लगा हुआ था।

द्वितीय महायुद्ध में सरकार का खर्च बहुत बढ़ गया। यह खर्च सरकार ने कर, ऋण तथा मुद्रा-स्फीति द्वारा चलाया। युद्ध काल में सरकार ने छ बर्ष के डिफेंस बॉन्ड, दसवर्षीय डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट तथा बिना व्याज के बॉन्ड चलाये। इसके अतिरिक्त सामान्य सरकारी नौकरों के लिये डिफेंस सेविंग बैंक एकाउंट की भी स्थापना की गई। इस प्रकार रुपये ऋण में वृद्धि होती चली गई। मार्च १९४६ में यह बढ़कर १९३६ ९५ करोड़ रुपये हो गया।

३

इसके विपरीत स्टलिन्स ऋण में दिनों दिन बमी होती चली गई। युद्ध के बीच भारत का व्यापारिक सन्तुलन उसके पक्ष में रहा। इसके अतिरिक्त भारत ने इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों को भी बहुत सा भाल भेजा। इस सबके बदले भारत को स्टलिन्स दिया गया। ऐसा करने के कारण स्टलिन्स की मात्रा दिनोंदिन बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि १९४६ में १३३ लाख पाँड की स्टलिन्स भारत के पक्ष में हो गई। इसी बीच सरकार ने स्टलिन्स ऋण को बहुत से समझौतों द्वारा कम किया। ऐसा करते-करते युद्धकाल का प्राप सभी स्टलिन्स ऋण चुका दिया गया। जो थोड़ा ऋण बचा वह कुछ बातों के कारण नहीं चुकाया जा सका। १९५५-५६ में यह ऋण केवल २३.२८ करोड़ था तथा १९५६-५७ के बजट का अनुमान २२.२६ करोड़ २० था। १९५८-५९ के संशोधित बजट के अनुसार यह ऋण ३०.७९ करोड़ रुपये था परन्तु १९५९ ६० के बजट के अनुसार इसकी मात्रा ७१.४४ करोड़ २० होगी।

सार्वजनिक ऋण की वर्तमान स्थिति

भारतव्य के सार्वजनिक ऋण की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है—

रुपया ऋण—मार्च १९३९ ई० में यह ऋण ७०.९६६ करोड़ रुपये था। मार्च १९४६ में यह बढ़कर १९३६ ९५ करोड़ २० हो गया। युद्ध के पश्चात् भी बहुत सी बातों के कारण इस में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है यहाँ तक कि ३१ मार्च १९५९ तक यह ४५९३ करोड़ २० हो गया।

अल्पकाल ऋण (Floating Debt)—हमारे देश में युद्ध काल में बहुत सा घन राजकोष विपत्रों (Treasury Bills) से भी एकत्र किया गया। १९३९ से १९४३ तक ये निरन्तर बढ़ते रहे। १९३९ में यह ऋण ४६ ३० करोड़ करोड़ २० था जो कि कुल ऋण का ६५ प्रतिशत था परन्तु १९४३ में यह २६४ ७० २० हो गया, जो कि कुल का २१.९ प्रतिशत था। २० दिसम्बर १९४९ ई० से राजकोष विपत्रों का जानता का बचना बन्द कर दिया गया परन्तु ९ सितम्बर १९५२ से उनको फिर बेचना आरम्भ कर दिया गया है। १९५८ ई० में राजकोष विपत्र २६५ १२ करोड़ २० के थे।

राजकोष विपत्रों के अनिरिक्त अल्पकाल ऋण मार्गोपाय अधिन (Ways and Means Advances) के द्वारा भी लिया जाता है। यह ऋण रिजर्व बैंक से दिन प्रतिदिन होने वाले व्यय के लिये लिया जाता है। इसकी अवधि ३ मास से ६ मास तक होती है।

अल्प वचत्ते—सरकार ने युद्ध काल में कुछ साधनों वाले लोगों से ऋण लेने के लिये कई योजनाएँ चलाईं। उसने १९४० ई० में दस वर्षीय डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जारी किये। १९४१ ई० में पोस्ट आफिस डिफेंस सेविंग बैंक योजना चालू की गई। १९४३ ई० में १२ वर्षीय नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट योजना चालू की गई। अभी हाल ही में सरकार ने १० वर्षीय योजना सर्टिफिकेट तथा ऋण जारी किये हैं। १९५५-५६ में इस प्रकार का ऋण ५०५ ७० करोड़ रुपये या परन्तु १९५८-५९ में वह बढ़ कर ६९५ २२ करोड़ २० हो गया।

इसके अतिरिक्त अन्ध ऋण की मात्रा १९५८-५९ में ४२२.३७ करोड़ रुपये थी इस ऋण में प्राविडेंट फंड डाक बीमा, आदि सम्मिलित हैं।

विदेशी ऋण—इनके अतिरिक्त १९५८ में हमारा विदेशी ऋण २११.०२ करोड़ २० या इस में हमारा डालर ऋण १५१.८५ करोड़ रुपये या। भविष्य में डालर ऋण के बढ़ने की धीर भी संभावना है क्योंकि पंचवर्षीय योजना के लिये हम बहुत सी मशीनें तथा अन्य सामान अमेरिका से भेगा रहे हैं।

इस प्रकार १९५८-५९ में भारत सरकार का यह ऋण जिस पर उसको व्याज देना था, ४९६४ करोड़ रुपये या इसमें से ४५९३ करोड़ आन्तरिक या शेष राया बाह्य था।

भारतवर्ष में आजकल पंचवर्षीय योजना के चलने के कारण बहुत धन की आवश्यकता है। इसलिये आजकल सरकार को बहुत सा ऋण लेना पड़ रहा है। इस कारण भविष्य में हमारे ऋण का कर बढ़ने वाला है। परन्तु इससे भय की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारा अधिकतर ऋण उत्पादक कार्यों के लिए है और ऐसा ऋण कभी भी चिन्ता का विषय नहीं होता।



स्थानीय सस्थाओं की आय व व्यय के मद

Q 99 Discuss the main sources of income and expenditure of the Municipal and District Boards in India. How would you increase their revenue resources without increasing the burden on the overtaxed sections of the urban and rural population?

प्रश्न ९९—भारत में नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों की आय व व्यय के मुख्य मद बताइये। आप नगर व ग्राम की करों से लदी जनता का भार बिना उनकी आय बढ़ाये कैसे बढ़ावेंगे?

उत्तर—हमारे देश में नगरपालिकाओं की आय के निम्नलिखित मद हैं—

(१) सम्पत्ति कर (Taxes on Property)—नगरपालिकाएँ मकानों तथा भूमि की स्थिति पर कर लगाती हैं। युद्ध से पूर्व इस मद से बम्बई में कुल आय का ८२ प्रतिशत, मद्रास में ४७ प्रतिशत, आसाम में ७८ प्रतिशत तथा बिहार उड़ीसा में ७७ प्रतिशत प्राप्त होता था।

(२) व्यापार, पेशे, कार्यों आदि पर कर (Taxes on Trades, Professions Callings etc.)—यह कर प्रायः सभी जगह लगाया जाता है परन्तु मद्रास, मध्य प्रदेश तथा बंगाल के अतिरिक्त यह कहीं भी महत्वपूर्ण नहीं है।

(३) व्यक्तियों पर कर अथवा हैसियत कर (Taxes on Persons or Haisyat Tax)—यह कर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तथा सम्पत्ति अथवा हैसियत पर लगाया जाता है। यह कर लगाने समय व्यक्ति की आय तथा उसके सामाजिक स्तर को ध्यान में रखा जाता है।

(४) मल वाहन, रोशनी तथा अग्नि कर (Conservancy, lighting and fire Taxes)—वास्तव में इसको कर न कहकर दर (Rate) कहना चाहिये क्योंकि यह कर नगरपालिका अपनी सेवा के बदले लोगों से दसूल करती है। इसलिये यह निश्चित करना बड़ा कठिन है कि नगरपालिका ने किस व्यक्ति की कितनी सेवा की है इसलिये यह कर व्यक्ति की सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के अनुसार लगाया जाता है।

(५) घुड़ों, सीमा कर तथा मार्ग शुल्क (Ocires, Terminal Tax and Toll Tax)—यह भारतवर्ष की नगरपालिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण कर है। यह बहुत पुराने समय से चलता चला आ रहा है। जब नगरपालिकाओं की सीमा में बाहर से कोई खाने पीने अथवा दूसरे उपभोग की वस्तु लाई जाती है, तो उस पर मूल्य के अनुसार अथवा सवारी के अनुसार कर लिया जाता है। इसी को चुंगी सीमा कर अथवा मार्ग शुल्क कहते हैं।

इस कर के विरुद्ध लोग बड़ी बड़ी आलोचनाएँ करते हैं। उनका कहना है कि व्यापार में यह बड़ी बाधा उपस्थित करता है। चुंगी की वापसी के कारण बहुत व्यभिचार फैलता है। इसके अतिरिक्त इस कर का भार गरीबों पर अधिक पड़ता है। सर जोशिया स्टामन ने चुंगी के विषय में कहा है—‘मेरे विचार में सैद्धान्तिक दृष्टि से तथा अनुभव के आधार पर कोई भी देश उन्नतिशील नहीं हो सकता जो कि किसी भी प्रकार चुंगी पर निर्भर रहता है जिसमें सभी अवगुण हैं।’

(६) व्यापारिक कार्यों से आय (Income from Commercial undertakings)—बहुत सी नगरपालिकाएँ अपन सन में लोगों को पानी, बिजली गैस आदि प्रदान करती हैं तथा बहुत से स्थानों पर वे अपनी दुकानें बसाईखान आदि बनवा देती हैं। इन सबसे उनको आय प्राप्त होती है।

(७) सहायक अनुदान (Grant in aid)—नगरपालिकाओं को राज्य सरकारों से भी कई प्रकार की सहायता प्राप्त होती है जैसे शिक्षा, चिकित्सा, सहायता, यातायात के साधनों की उन्नति के लिये सहायता। यह सहायता आवर्ती अनुदान (Recurring grant) तथा सम वरद्ध अनुदान (Block Grant) के रूप में दी जाती है।

(८) विविध कर (Miscellaneous Taxes)—इन सब के अतिरिक्त नगर-

पालिकायें बाजार कर, पशुओं की रजिस्ट्री का कर, नोकर कर, घोड़ी, इक्का, बाइसिकलों आदि पर कर लगाकर भी आय प्राप्त करती हैं।

नगरपालिकाओं के व्यय के मद

नगरपालिकायें निम्नलिखित कामों पर धन खर्च करती हैं—

(१) मल वाहन (Conservancy)—नगर की सड़कों की सफाई करना, कूड़ा-करकट नगर के बाहर फेंकवाना, नातियों की सफाई कराना, पाखाना नगर के बाहर पहुँचाना आदि नगरपालिकाओं के ये मुख्य कार्य हैं और इन बातों पर ही उनका सबसे अधिक धन खर्च होता है।

(२) स्वास्थ्य सेवार्थ (Health Services)—इसके पश्चात् नगरपालिकाओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवार्थें भी महत्वपूर्ण हैं, नगरपालिकायें नगर में हस्पतालों का प्रबन्ध करती हैं, बच्चों के चेचक के टीके लगवाती हैं। बरसात से पहले तथा उसके बीच कुओं में ताल दबायें डालकर उनकी सफाई कराती हैं। इसके अतिरिक्त वे एक-एक स्वास्थ्य उपकरण भी रखती हैं जो देखता है कि नगर में कोई चीज ऐसी न बिके जिससे रोग फैलने का भय रहता है। इस प्रकार वे रोग को रोकने के लिये पूरा प्रयत्न करती हैं।

(३) शिक्षा (Education)—हमारे देश में नगरपालिकाओं के ऊपर यह भार है कि वे प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क दें। प्रारम्भिक शिक्षा के अतिरिक्त कुछ नगरपालिकायें माध्यम शिक्षा का भी प्रबन्ध करती हैं।

(४) विविध व्यय (Miscellaneous Expenditure)—इन कामों के अतिरिक्त नगरपालिकायें अपने क्षेत्र में सड़कें, इमारतें, कलाईखाने व खेलने के मैदान आदि भी बनवाती हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नगरपालिकाओं के जिम्मे बहुत सी आवश्यक सेवार्थें हैं जिन पर बहुत सा धन खर्च करने की आवश्यकता है। परन्तु हमारी नगरपालिकाओं की प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की औसत आय कुछ ही रुपये है। इतनी कम आय से वे अधिक कार्य नहीं कर सकती। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि उनको आय के ऐसे साधन सौंपे जायें जिससे कि आय बढ़ जाये और वे अधिक कार्य करने लगें।

जिला बोर्डों की आय और व्यय

आय—

जिला बोर्डों की आय निम्नलिखित साधनों से प्राप्त होती है—

(१) भूमि पर उपकर (Land cess)—जिला बोर्डों की आय का मुख्य साधन भूमि पर उपकर है। इसके द्वारा उनकी ६७ से ६६ प्रतिशत तक आय प्राप्त होती है। इस कर को मालगुजारी के साथ वसूल किया जाता है। इन कर को जमींदारों से वसूल किया जाता है। परन्तु कुछ राज्यों में जमींदार इसकी किसानों से वसूल कर लेते हैं।

(२) सम्पत्ति तथा परिस्थिति कर (Tax Property and circumstances) इस कर को हैसियत कर भी कहते हैं। यह कर मनुष्य की कुल आय पर लगाया जाता है। परन्तु १९३५ ई० के विधान के अनुसार सिवाय उन जिला बोर्डों को जो इस कर को प्रांतीय स्वशासन के पहले ही लगा रहे थे, कर लगाने का अधिकार नहीं है। यह कर उन लोगों से लिया जाता है जो गाँवों में रहते हैं। इस कर में छोटी आय वाले आदमी कर से मुक्त रहते हैं। इस कर की दर ४ पाई प्रति रुपये से अधिक नहीं हो सकती।

(३) मार्ग शुल्क—(Tolls)—जिला बोर्ड अपने क्षेत्र में पड़ने वाली नदियों के घाटों का ठेका देकर मार्ग शुल्क वसूल करते हैं।

(४) काजी हौस (Cattle Pounds)—काजी हौस में आवारा फिरने वाले पशुओं को बन्द कर दिया जाता है और उनका मालिक पशुओं को कर देकर छुड़ा सकता है। इस प्रकार जिला बोर्डों को कुछ आय प्राप्त हो जाती है।

(५) शुल्क (Fees)—जिला बोर्ड गाँवों में प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिये स्कूल भी खोलत हैं इन स्कूलों में बच्चों से फीस ली जाती है।

(६) किराया (Rent)—जिला बोर्डों की कुछ आय सराय के किराये से भी वसूल हो जाती है। इनको किराये की आय दूसरी प्रकार की इमारतों से भी होती है।

(७) मेले (Fairs)—जिन जिला बोर्डों के क्षेत्रों में मेले लगते हैं उनको उन मेलों से भी आय प्राप्त होती है। मेरठ जिले में गङ्गमुखेश्वर पर गंगा स्नान का मेला तथा मेरठ नगर में नौचन्दी का मेला प्रमुख हैं जिन से जिला बोर्डों को आय प्राप्त होती है।

सहायक अनुदान (Grants-in-aid)—जिला बोर्डों को राज्य सरकारों से भी बहुत सी आय सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। १९३६-४२ में उत्तर प्रदेश में यह आय कुल की ४० प्रतिशत थी।

व्यय—

शिक्षा—जिला बोर्डों का सबसे अधिक धन शिक्षा पर खर्च होता है। यह केवल प्रारम्भिक शिक्षा ही देते हैं। शिक्षा के लिये इनको राज्य सरकार से भी सहायता मिलती है।

(२) सड़कें तथा इमारतों पर खर्च—इस मद पर इनका लगभग ३ प्रतिशत धन खर्च होता है। परन्तु यह धन बहुत कम है। वास्तव में इनके अधिकार में इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि वे उसमें अपने थोड़े से साधनों से सड़कें आदि बनवा ही नहीं सकते।

(३) हस्तशिल्प तथा सफाई—जिला बोर्ड स्थान-स्थान पर हस्तशिल्प रखते हैं जिनमें गाँव के लोगों को मुफ्त दवा दी जाती है इसके अतिरिक्त ये गाँवों में चंचक के टीके भी लगवाते हैं।

(४) विविध ध्यय—इन सबके अतिरिक्त उनको अपने कर्मचारियों, दण्डियों के हस्ततालो, मेलो, नुमाइशों आदि पर भी बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जिला बोर्डों की आय तो बहुत कम है परन्तु उनके अधिकार में व्यय के जो मज हैं उन पर बहुत धन खर्च करने की आवश्यकता है। उनकी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का औसत केवल ८ आने ही है। इतनी कम आय से वे कैसे अधिक कार्य कर सकते हैं। इसलिये इस बात की आवश्यकता है कि उनकी आय के कुछ नये साधन दिये जायें जिससे कि वे अपना कार्य कर सकें।

स्थानीय सस्थाओं की आर्थिक स्थिति पर दृष्टि—

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में स्थापित सस्थाओं के जिम्मे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कार्य रखे गये हैं परन्तु इन कार्यों पर खर्च करने के लिये इनके पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। साइमन कमिशन ने इनकी आय के विषय में कहा था, सब प्रकार की स्थानीय दरों, नगर तथा ग्राम, से १६२७-२८२५ लाख (२३ million) पौड की आय प्राप्त हुई, जो कि उस वर्ष में केवल लन्दन काउन्टी काउंसिल की दरो की आय से कुछ ही अधिक है।

भारतीय कर जाँच समिति के अनुसार उनकी आयको बिना लोगों का कर-भार बढ़ाए निम्नलिखित ढंग से बढ़ा सकते हैं।

(१) मालगुजारी को उचित बना दिया जाय जिससे कि इन सस्थाओं को ऊँची दर पर भूमि उपकर (Land Cess) लगाने का अवसर मिल जाय।

(२) प्रांतीय सरकारों द्वारा एकत्र किए गये भूमि के किराये तथा गैर कृषि भूमि की बढ़ी हुई आय में से स्थानीय सस्थाओं को कुछ भाग दिया जाय।

(३) नगरपालिकाओं को विज्ञापनों पर कर लगाने का अधिकार दिया जाय।

(४) मोटर पर से आयात कर को घटाया जाय जिससे कि प्रांतीय सरकारें उन पर कर लगा सकें तथा उसकी स्थानीय सस्थाओं में बाँट सकें।

(५) प्रांतीय सरकारें इनको अधिक आर्थिक सहायता दें।

बम्बई तथा उत्तर प्रदेश की स्थानीय स्वशासन जाँच समितियों ने इन सुझावों का अनुमोदन किया तथा उत्तर प्रदेश की समिति ने कुछ और भी सुझाव दिये।

(६) प्रांतीय कोर्ट फीस का कुछ भाग इनको दिया जाय।

इनके अतिरिक्त ये सस्थायें अपनी आय लोगों को बिजली, पानी, गैस आदि देकर तथा अपनी मोटर आदि चला कर बढ़ा सकती हैं।

१९४६ में नियुक्त स्थानीय वित्तीय जाँच समिति तथा १९५३ ई० में नियुक्त कर जाँच आयोग ने स्थानीय सस्थाओं के वित्त के विषय में जाँच की। इनमें से स्थानीय वित्तीय जाँच समिति ने सुझाव दिया है कि रेल, समुद्र तथा हवाई जहाज से ले जाने वाले माल (Terminal Taxes) तथा यूनिवर्सलिस्ट के ८९वें मद के अंतर्गत रेल भाड़े तथा किराये पर लगाये गये कर स्थानीय सस्थाओं के लिये सुरक्षित

रहने चाहियें । इसने यह भी सुझाव दिया है कि भूमि, इमारतों, खानों के अधिकारों, स्थानीय सस्थाओं के क्षेत्र में आने जाने वाले माल, बिजली की बिक्री व उपभोग, अखबार, के अतिरिक्त दूसरे विज्ञापनों, सड़क तथा पानी से ले जाने वाले माल व यात्रियों, गाड़ियों, पशुओं, पालतू, जानवरों, पेशों, विलासिताओं आदि पर कर तथा विधान की सातवीं तालिका में राज्यों के लिये निश्चित भाग शुल्क तथा प्रति व्यक्ति कर स्थानीय सस्थाओं के काम आने चाहियें ।

कर जर्चि आयोग का मत है कि राज्यों की वर्तमान प्रवृत्ति जिसके कारण वे स्थानीय सस्थाओं के कर लगाने के अधिकारों में हस्तक्षेप करती हैं, बड़ी खराब है तथा उसको समाप्त करना चाहिये और कुछ कर केवल स्थानीय सस्थाओं के लिये सुरक्षित रहने चाहियें । आयोग का मत है कि इसके लिए विधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है । राज्य सरकारों को चाहिये कि वे स्वयं ही हस्तक्षेप करना छोड़ दें तथा स्थानीय सस्थाओं को उन करों को लगाने का प्रोत्साहन दें जो उनके लिये निश्चित किए हुए हैं । आयोग यह बात भी पसन्द नहीं करता कि राज्य व स्थानीय सस्थायें आपस में कर का बँटवारा करें । आयोग का मत है कि विशेष कामों के लिए सहायक अनुदान देना तथा अच्छे स्तर का काम करने के लिये सहायता देना अधिक उचित है ।

—————

आर्थिक योजना तथा राष्ट्रीय आय

Q 100. Describe the chief features of the first Five Year Plan. On what factors does its final success depend ?

प्रश्न १००—पंचवर्षीय योजना की मुख्य बातें बताइये। इसकी अन्तिम सफलता किन बातों पर निर्भर है ?

द्वितीय महायुद्ध में भारत की आर्थिक उन्नति के लिए बहुत सी योजनाएँ देश के सामने रखी गईं जिनमें बम्बई योजना, गांधी योजना, जन योजना मुख्य हैं। परन्तु इन योजनाओं में कोई भी ऐसी नहीं थी जो देश के सब पहलुओं पर दृष्टि डालती तथा जिसमें देश के सब प्रकार के वर्तमान साधनों को ध्यान में रखते हुए एक उचित ध्येय सामने रखा गया हो। इस कारण उनमें से किसी को कार्यान्वित न किया जा सका। मार्च सन् १९५० ई० में एक राष्ट्रीय योजना आयोग (National Planning Commission) की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष हमारे प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू थे। इस आयोग ने जोलाई १९५१ ई० में पाँच वर्ष के समय (१९५१ से १९५६ तक) के लिए एक योजना की रूप-रेखा पेश की। यह १७९३ करोड़ रु० की थी। इस रूप-रेखा को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं ने देखा तथा उस पर अपनी आलोचना की। इन सब आलोचनाओं को ध्यान में रखकर दिसम्बर १९५२ ई० में अन्तिम योजना को लोक-सभा में पेश किया गया।

यह योजना तीन भागों में बाँटी गई है—पहले भाग में बताया गया है कि एक पिछड़ी हुई अर्थ-व्यवस्था को किस प्रकार उन्नत किया जा सकता है तथा उस अन्तिम ध्येय का भी वर्णन किया गया है जिसके लिए राष्ट्र को अपनी शक्ति लगानी चाहिए। दूसरे भाग में योजना की व्यवस्था तथा सार्वजनिक सहयोग का वर्णन है। तीसरे भाग में उन्नति के विभिन्न प्रोग्राम दिये गये हैं। इनको तीन बड़े खण्डों में बाँटा गया है—(अ) कृषि, सिंचाई तथा सामुहिक विकास, (आ) उद्योग तथा याता-यात, (इ) सामाजिक सेवार्थ तथा रोजगार।

उद्देश्य—योजना आयोग के अनुसार इस योजना का उद्देश्य उन्नति के मार्ग को खोलना है जिससे कि देश के लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा हो जाए और उनकी अच्छा जीवन बिताने के लिये अवसर प्राप्त हो जाए। इस योजना में देश के सब प्रकार के साधनों (भौतिक तथा मनुष्य सम्बन्धी) को काम में लाने के ऊपर दृष्टि रखी गई है जिससे कि देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की अधिक उत्पत्ति हो सके और

घन-वितरण की असमानता दूर हो सके। योजना में बताया गया है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये हमको जल्दी नहीं करनी चाहिए वरन् सोच-समझ कर धीरे-धीरे काम करना चाहिए।

इस योजना में राज्य तथा जनता के लिये कार्य क्षेत्र निश्चित किये गये हैं। राज्य का कार्य पूँजी का निर्माण करना, उत्पादन की गई पद्धति को प्रोत्साहन देने तथा चालू करने की सुविधा देना तथा समाज में उत्पादन शक्तियों तथा वर्ग सम्बन्धों को एक सूत्र में बाँधना है। जनता को भी कार्य करने का अवसर मिलना आवश्यक है परन्तु उसको पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं छोड़ा जा सकता। वेनी यद्यपि व्यक्ति स्वयं करते हैं परन्तु सरकार का कर्तव्य है कि वह सिंचाई, शक्ति, सड़क व यातायात का प्रवन्ध करे। इससे अतिरिक्त सरकार को पत्तल के बेचने तथा टैक्सीकल सलाह देने में भी सहायता करनी चाहिये। इसी प्रकार उद्योगों को यद्यपि निजी पूँजी द्वारा चलाया जा सकता है तो भी सरकार को बहुत से क्षेत्रों में इनकी सहायता करनी पड़ेगी।

योजना आयोग का सुझाव है कि नियोजन अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy) के लिए यह आवश्यक है कि मूल्यों तथा साक्ष पर नियन्त्रण किया जाय।

योजना में इस बात की सिफारिश की गई है कि घन वितरण की असमानता को दूर किया जाय। ऐसा तभी प्राप्त किया जा सकता है जबकि पूँजीपतियों को अत्यधिक लाभ न देने दिया जाय तथा मृत्यु कर तथा बढेमान आय कर लगाए जायें।

इस योजना में कुछ चीजों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें कृषि, सिंचाई, शक्ति आदि सम्मिलित हैं। इस प्राथमिकता का कारण यह है कि जब तक अनाज व फल्ले माल की उत्पत्ति नहीं बढ़ेगी और उसमें पर्याप्त मात्रा में बचत नहीं होगी तब तक दूसरे क्षेत्रों में उत्पत्ति सम्भव नहीं हो सकती।

इस योजना में अधिकतर साधन सिंचाई, शक्ति तथा यातायात पर खर्च हो जायेंगे। इस कारण उद्योगों की उन्नति के लिये निजी पूँजी पर निर्भर रहना पड़ेगा। हाँ कुछ आधारभूत उद्योगों को उन्नत करने की जिम्मेदारी सरकार पर रहेगी। इन उद्योगों में लोहे तथा इस्पात, भारी रासायनिक बिजली के सामान आदि के उद्योग हैं।

व्यय की रूप-रेखा—

योजना में निम्नलिखित ढग से खर्च करने का प्रोग्राम है—

	करोड़ रुपये	कुल व्यय का प्रतिशत
कृषि व सामूहिक विकास	३६१	१०.५
सिंचाई	१६८	५.१
बहु-उद्देश्य सिंचाई व शक्ति योजनायें	२६६	१२.६
शक्ति	१२७	६.१

यातायात व संचाद-वाहन	४६७	२४००
उद्योग	१७३	८४
सामाजिक सेवायें	३४०	१६४
पुननिवास	८५	४१
अन्य	५२	२५
	<hr/>	<hr/>
	२०६६	१०००

देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए योजना पेश करने के पश्चात् यह आवश्यक समझा गया कि उसका कुछ प्रबन्ध किया जाय। इस कारण इस समस्या के लिये योजना में इधर-उधर कुछ वृद्धि कर दी गई है। इस प्रकार अन्त में यह योजना २३३१ करोड़ रुपये की हो गई।

इस योजना का खर्च निम्नलिखित ढंग से किया जाना था—

	करोड़ रु०
केन्द्रीय सरकार (रेलो सहित)	१२४१
राज्य भाग अ	६१०
भाग ब	१७३
भाग स	३२
जम्मू तथा काश्मीर	१३

२०६६

यह खर्च विभिन्न मदों पर निम्नलिखित ढंग से किया जाना था—

	करोड़ रुपये			
	केन्द्र	भाग 'अ'	भाग 'ब'	भाग 'स'
कृषि तथा सामूहिक विकास	१८६३	१२७३	३७६	८७
सिंचाई तथा शक्ति	२६५६	२०६१	८५१	३५
यातायात तथा संचादवाहन	४०६५	५६६	१७४	८८
उद्योग	१४६७	१७६	७१	०५
सामाजिक सेवायें तथा पुननिवास	१६१४	१६२३	२८६	१०४
विविध	४०७	१००	०७	

१२४०५ ६१०१ १७३२ ३१६

योजना का धन सम्बन्धी आधार—उपयुक्त धन को निम्नलिखित ढंग से प्राप्त किया जाना था—

	केन्द्रीय सरकार	राज्य (जम्मू काश्मीर सहित)	करोड़ रु० में योग
विकास पर धन व्यय	१२४१	८२८	२०६६

बजट सम्बन्धी साधन—

(१) चालू आय (Current revenues)	३३०	४०८	७३८
(२) पूँजी कृत (Capital) आय रक्षित कोष (Reserve) में से निकाला हुआ धन छोड़ कर ।	३६६	१२४	५२०
(३) राज्यों को प्राप्त केन्द्रीय सहायता ।	—२२६	२२६	—
	४६७	७६१	१२५८
बाह्य साधन जो प्राप्त हो चुके हैं	१५६	—	१५६
योग	६५३	७६१	१४१४

इस प्रकार ६५५ करोड़ रुपये की कमी पड़ती है जिसको कि विदेशों से सहायता, आन्तरिक करो, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबन्धन (Deficit Financing) द्वारा प्राप्त किया जायेगा ।

परन्तु वास्तव में इस योजना पर केवल १६६० करोड़ रु० खर्च किया गया जो कि अन्तिम ध्येय बिन्दु से १७ प्रतिशत कम है । इस धन में से २५६ करोड़ १६५१-५२ में, १७३ करोड़ १६५२-५३ में, ३४० करोड़ १६५३-५४ में ४७६ करोड़ १६५४-५५ में तथा ६१२ करोड़ १६५५-५६ में खर्च किया गया । यह सब धन निम्नलिखित ढग से प्राप्त किया गया—

	करोड़ रुपये में
(१) आय के साधनों से	७५२
(२) जनता से ऋण	२०५
(३) अल्प बचत	३०४
(४) अन्य जो पूँजी कृत है	६१
(५) विदेशी सहायता	१८८
(६) हीनार्थ-प्रबन्धन	४२०
योग	१६६०

योजना में निश्चित किये गये लक्ष्य—इस योजना से हमको अप्रतिष्ठित वस्तुओं व सेवाओं के प्राप्त होने की आशा है—

	१९५०-५१	१९५१-५६ तक वृद्धि (योजना विन्दु)	१९५१-५६ मासिक	१९५०-५१ की अपेक्षा १९५१-५६ में वृद्धि.	योजना विन्दु की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि
(१) कृषि					
खाद पदार्थ (लाख टन)	५४०	७६	६४६	+१०६	१४३०
बपास (लाख गैठ)	२६७	१२६	४००	+१०३	८२
बूट (लाख गैठ)	३३०	२०६	४२०	+६०	४३
गन्ना (लाख टन)	५६२	७०	५८६	+२४	३४
तिलहन (रस लाख टन)	५०५	४०	५६६	+५६	११६
(२) सिंचाई तथा शक्ति					
सिंचाई (लाख एकड़)	५१००	१६७०	६४००	+१४०	७१
विद्युत शक्ति (स्थापित शक्ति लाख किलोवाट)	२३	१३	३४	+११	८४
(३) उद्योग					
तैयार इस्पात (लाख टन)	६८	६७	१२८	+३०	४५

करना लोहा (लाय टन)	१५.७	१२.७	१७.६	१७.६	१७
सीमेंट (लाय टन)	२६.६	२१.१	४५.६	४५.६	६०.०
लाइन (हजार टन)	४६.०	४०.०	४६.०	४६.०	६०
रेल के इन्जन (संख्या)	३	१७०	१७०	१७०	१०५
मिल का बपटा (लाय गज)	३७१२०	६२०	६२०	५१०२०	१५१०
लुट का बना माल (हजार टन)	२२५	३७६	३७६	३०५५	६१
वाइसिकल (हजार)	६७	४३३	४३३	५१३	६६
(४) यातायात					
जहाज (लाय G. R. T.)	३६	२.२	४.८	४.८	४१
राष्ट्रीय सड़कें (हजार मील)	१२.३	०.६	०.६	१२.६	१००.०
राज्य सड़कें (हजार मील में) एकको	६७५	—	—	१२१.६	—
(५) स्वास्थ्य					
बच्ची	१५१.०	—	—	१६५.१	—
हस्पताल के विस्तर	११३	१२	१२	१३६ (१६५४ ५५५ में)	—
दवाई लागे तथा हस्पताल (संख्या)	२६००	१४००	१४००	६२०६	—

योजना का आय तथा रोजगार पर प्रभाव—

१९५०-५१ ई० में हमारी राष्ट्रीय आय ८८५० करोड़ थी। योजना के अन्त में यह बढ़कर १०४८० करोड़ रुपये हो गई। इस प्रकार इसमें १८४% की वृद्धि हो गई। इस बीच प्रति व्यक्ति आय २४६ रु० से बढ़कर २७४ रु० हो गई। इस प्रकार इसमें ८ प्रतिशत वृद्धि हो गई।

रोजगार के सम्बन्ध में योजना में बताया गया है कि भारतवर्ष में बेरोजगारी की इतनी समस्या नहीं है जितनी कि कम समय के लिए रोजगार मिलने की है। जैसे-जैसे योजना के ऊपर खर्च होता जायगा वैसे-वैसे रोजगार के साधन बढ़ते जायेंगे। इसके अतिरिक्त योजना के कारण जितनी पूंजी एकत्र होगी उससे दूसरी योजना में रोजगार के साधन खुलेंगे।

व्यवस्था तथा सहयोग—

योजना में बताया गया है कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह मालूम करे कि लोगों की आवश्यक जरूरतें क्या हैं और उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त देश में प्रशिक्षित लोगों की कमी के कारण सरकार का यह भी कर्तव्य हो जाता है कि वह लोगों को ध्यानपूर्वक देखें कि उनको कहाँ लगाया जा सकता है। देश में अपनी जिम्मेदारी को निभाने तथा लोगों की आशाओं को पूरा करने के लिये बहुत से शासन सम्बन्धी सुधार करने पड़ेंगे। इन सुधारों का उद्देश्य शासन में सच्चाई, कार्य-कुशलता, मितव्ययिता तथा जन सहयोग प्राप्त करना है। इस योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि योजना को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिये पग-पग पर जनता के सहयोग की आवश्यकता है।

योजना के अन्तर्गत आर्थिक नीति—

इस योजना की आर्थिक नीतियों को निम्नलिखित ढंग से बता सकते हैं—

(१) योजना का ढंग—भारत में योजना प्रजातान्त्रिक ढंग से चलनी चाहिए। ऐसा ढंग अपनाने में यद्यपि कुछ कठिनाइयाँ आती हैं तो भी राष्ट्र के लोगों की उत्पन्न करने की सुप्त-शक्ति का उपयोग करके लिये यही एक सबसे अच्छा ढंग है।

(२) खाद्यान्न नीति—देश में उस समय तक नियन्त्रण रहे जब तक कि खाद्यान्न उत्पत्ति ७६ लाख टन न हो जाय। प्रारम्भ से ही नियन्त्रण न रखने से मूल्य स्तर ऊँचा हो जायगा जिसके कारण सब प्रकार का खर्च बढ़ेगा तथा योजना के चलाने में बड़ी बाधा उत्पन्न होगी।

(३) मूल्य नीति—मूल्य नीति का उद्देश्य यह है कि सापेक्षित (Relative) मूल्य ढाँचा इस प्रकार का हो जिससे कि योजना में निर्दिष्ट किये गये लक्ष्य को पूरा करने के लिये उसमें साधन लगाए जा सकें। इस फल को प्राप्त करने के लिये आर्थिक तथा भौतिक नियन्त्रण की आवश्यकता है। योजना के प्रारम्भ में द्रव्य आय

उत्पादन की अपेक्षा अधिक वेग से बढ़ती है जिसके कारण मुद्रा-स्फीति का डर है । इस डर के लिए मुद्रा तथा साख नीति के हथियार को अपनाना आवश्यक है ।

(४) प्राथमिकता—इस योजना में (जैसा पहले बताया जा चुका है) कृषि जिसमें सिंचाई तथा शक्ति सम्मिलित हैं प्राथमिकता दी गई है ।

(५) भूमि सम्बन्धी नीति—इस योजना में इस बात की सिफारिश की गई कि उच्चतर सीमा निश्चित कर दी जाय, बड़े खेत वालों को सहायता दी जाय । छोटे छोटे तथा बीच वाले किसानों में सहकारी ढंग को प्रोत्साहन दिया जाय ।

(६) विदेशी पूँजी—विदेशी पूँजी का स्वागत किया जाय । इस पूँजी को उन नये स्थानों पर लगाया जाय जहाँ विशेष अनुभव तथा टेक्नीकल योग्यता की आवश्यकता है ।

(७) कुटीर उद्योग—कुटीर उद्योगों में सहकारिता को प्रोत्साहन दिया जाय । इन उद्योगों की सहायता उनके लिये उत्पादन के क्षेत्रों को निश्चित करके अच्छे माल को देकर तथा अनुसंधान (Research), बिक्री और प्रशिक्षण (Training) सम्बन्धी संस्थाएँ स्थापित करनी चाहियें ।

(८) श्रम नीति—श्रमिक झगड़े मध्यस्थता (Arbitration) से सुलझाने चाहियें । मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाने के लिये विशेष प्रकार के बोर्डों का निर्माण करना चाहिये ।

(९) व्यापारिक नीति—व्यापारिक नीति का उद्देश्य यह होना चाहिये कि निर्यात कर स्तर ऊँचा रहे । भुगतान आधिक्य (Balance of Payments) की कमी देश के विदेशी विनिमय के साधनों के अन्दर ही रहे । आयात और निर्यात में सम्मिलित की जाने वाली वस्तुएँ देश की अर्थ तथा मूल्य नीतियों को ध्यान में रख कर सम्मिलित करनी चाहियें तथा नीति निरन्तर चलनी चाहिए ।

आलोचनात्मक निरूपण (Critical estimate)—

पंचवर्षीय योजना एक यथार्थ योजना है । इसमें देश की प्रायः सभी प्रकार की समस्याओं का विचार किया गया है । इस योजना में कृषि, सिंचाई, यातायात आदि की प्राथमिकता देकर देश की वास्तविक समस्या को ध्यान में रखा गया है । बिना इनके उन्नत दूरे देश की किसी प्रकार की भी उन्नति सम्भव नहीं थी । उद्योग-धन्धों में विशेषतः आधारभूत उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया है । कुटीर उद्योगों की भी प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया गया है । देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिये १७५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । इस बात का भी प्रयत्न किया गया है कि निजी उद्योगों को बढ़ान का अवसर मिले । इसके अतिरिक्त इस योजना को प्रजातान्त्रिक ढंग से चलाना इस बात का सबूत है कि सरकार देश के सभी विचारधारा के लोगों को इस योजना में हाथ बढ़ाते देखना चाहती है । इस योजना में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि बिना जनता के सहयोग के अधिक सफलता होने की आशा नहीं है ।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी योजना की अन्तिम सफलता निम्न-
वातों पर निर्भर है—

- (१) देश में पर्याप्त मात्रा में पूँजी हो तथा वचत भी पर्याप्त हो ।
- (२) देश के लोग योजना को सफल करने में पूरा-पूरा सहयोग दें ।
- (३) सरकारी कर्मचारी जो इस योजना के कार्य में लगे हुए हैं, वे सच्चाई व ईमानदारी से काम करें ।
- (४) राज्य सरकारें इसकी सफलता के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न करें ।
- (५) विदेशी सहायता पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो ।
- (६) कृषि उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हो ।
- (७) देश में एक उचित मूल्य-स्तर कायम हो सके ।

Q. 101. Discuss the outline of the Second Five Year Plan.

प्रश्न १०१—द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना की रूप-रेखा का वर्णन कीजिये ।

पहली पञ्चवर्षीय योजना मार्च १९५६ ई० में समाप्त हुई । इस योजना से एक ऐसा आधार तैयार हुआ जिस पर एक ठोस और सर्वांगीण अर्थ-व्यवस्था और विविधतापूर्ण प्रगति की इमारत खड़ी की जा सके । इस योजना के फलस्वरूप कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, मूल्य उचित स्तर पर है और वैदेशिक अर्थ-सम्बन्ध भी मजबूत हैं । सभी महत्त्वपूर्ण लक्ष्यों को पूर्ण किया जा चुका है । केवल इस्पात के एक नये कारखाने, बिजली के बड़े कारखाने खोलने की जो व्यवस्था थी, उसमें आंशिक प्रगति हुई और शिक्षा, ग्रामोद्योग तथा लघु, उद्योगों में भी सीमित प्रगति ही हो सकी है । योजना की अवधि में राष्ट्रीय आय में अनुमानतः १८ प्रतिशत वृद्धि हुई । आशा केवल ११ प्रतिशत बढ़ने की थी । इस योजना के कारण देश में आशा का वायुमण्डल फैल गया ।

द्वितीय योजना के लक्ष्य—

इस योजना के चार लक्ष्य हैं—(१) आय तथा सम्पत्ति की विषमताओं को दूर करना तथा आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण, (२) रोजगार सम्बन्धी सुविधा के क्षेत्र का विस्तार, (३) औद्योगीकरण की गति को तेज करना तथा मूल और भारी उद्योगों का अधिकाधिक विकास, (४) राष्ट्रीय आय तथा जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करना ।

इस योजना के द्वारा यह प्रयत्न किया जाएगा कि इस देश में समाजवादी जनतन्त्र की स्थापना हो । समाजवादी रूप देश की आर्थिक नीति का उद्देश्य माना जा चुका है । इस उद्देश्य की प्राप्ति पर हमारे रहन-सहन का स्तर ऊँचा होगा,

हमारे अवसरो में वृद्धि होगी तथा हम में यह विश्वास उत्पन्न होगा कि देश के सर्वोत्तम प्रयासों में हमारा योग है और यह हमारे कल्याण के लिये हो रहा है।

योजना का आकार व रूप—

इस योजना पर कुल ७२०० करोड़ रुपया खर्च होगा जिसमें से ४८०० करोड़

रुपये सरकार तथा २४०० करोड़ निजी उद्योगपति खर्च करेंगे। इस प्रकार यह प्रथम योजना में सरकार व उद्योगपतियों का भाग ५०, ५० प्रतिशत था वहीं दूसरी योजना में क्रमशः ६१ व ३९ प्रतिशत है।

सरकार इस धन को निम्नलिखित ढंग से खर्च करेगी—

(१) खेती, सामुदायिक योजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (खेती पर ३४१ करोड़ रु० सामुदायिक योजना पर व राष्ट्रीय विस्तार सेवा पर २०० करोड़ रु०)	५६८ करोड़ रु०	११.८%
(२) सिंचाई और बिजली (सिंचाई व बांध रोकने पर ४८६ करोड़ रु० तथा बिजली पर ४२७ करोड़ रु०)	९१३ "	१९ "
(३) उद्योग तथा खानों (बड़े उद्योगों और खानों पर ६६० करोड़ रु० व कुटीर उद्योगों पर २०० करोड़ रु०)	८६० "	१८.५ "
(४) यातायात व संचारवाहन (रेलो पर ६०० करोड़ रु०, सिडको पर २६३ करोड़ रु०, जहाजों, बन्दरगाहों व आंतरिक जल, यातायात पर ६६ करोड़ रु० व डाक व तार, हवाई जहाज, आदि पर ११६ करोड़ रु०)	१३८५ "	२८.६ "
(५) सामाजिक सेवाओं, मकानों तथा पुनर्वास पर २३६ करोड़ रु० व शिक्षा पर ३०७ करोड़ रु०, स्वास्थ्य, पानी व सफाई पर २७४ करोड़ रु०, श्रम व श्रम हितकारी कार्य पिछड़ी व अछूत जातियों की उन्नति पर १२० करोड़ रु० पुनर्वास पर ६० करोड़ रु०)	६४५ "	१६.७ "
(६) विविध	६६ "	२.१ "

योग	४८००	१००.०
-----	------	-------

सरकार इस योजना के लिये निम्नलिखित ढग से धन प्राप्त करेगी—

(१) चालू बचत	३५० करोड़ रुपये
(२) अतिरिक्त कर	४५० „
(३) रेलें	१५० „
(४) प्रोविडेंट फण्ड आदि	२५० „
(५) जनता से ऋण तथा अल्प बचत	१२०० „

२४०० करोड़ रुपये

घाटा—यह निम्नलिखित साधनों से पूरा किया जायगा—

(६) विदेशी सहायता	५००
(७) हितार्थ प्रबन्धन (Deficit Financing)	१२००
(८) शेष जो आन्तरिक व बाह्य साधनों से पूरा किया जायगा	४००

२४००

योजना में कहा गया है कि यदि मदिरा निषेध आदि सामाजिक कार्य करने हैं तो उससे आय की कमी होगी। इस कारण अतिरिक्त आय के साधनों को ढुंढना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मुद्रा स्फीति को कम करने के लिये और अधिक करों को लगाना पड़ेगा। ५०० करोड़ रुपये छोटी बचतों से प्राप्त करने के लिये सरकार देश के हर नागरिक से अपील करेगी कि वह योजना को सफल बनाने में अपना कुछ न कुछ हाथ बँटाये।

हीनार्थ प्रबन्धन—योजना में १२०० करोड़ रुपये के हीनार्थ का प्रबन्ध किया गया है जिसमें से २०० करोड़ रुपये पौंड पावने में से निकाल कर शेष १००० करोड़ रुपये के नोट छापे जायेंगे। नोट छापने में सावधानी से काम लेना पड़ेगा जिससे कि मूल्य स्तर में वृद्धि न हो तथा बड़ा हुआ धन सट्टेबाजों के हाथ में पड़कर योजना की सफलता में बाधा न डाले। इसी कारण रिजर्व बैंक को दूसरे व्यापारिक बैंकों पर नियन्त्रण करने की और अधिक शक्ति दी गई है।

कंट्रोल—यदि आवश्यक हुआ तो मूल्यों पर कंट्रोल भी लगाये जा सकते हैं। परन्तु ऐसा करने में यह सावधानी करनी पड़ेगी कि उनके कारण उत्पादन में कमी न हो। इसके अतिरिक्त गल्ले व दूसरी आवश्यक चीजों को स्टॉक किया जायगा जिससे कि वह मूल्य स्तर को अधिक बढ़ने से रोके।

अतिरिक्त कर—योजना में अधिक कर प्राप्त करने के लिये सम्पत्ति कर, नजराना-कर तथा पूंजी लाभ कर लगाने का सुझाव दिया गया है।

विदेशी सहायता—५०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता इस प्रकार प्राप्त की जायगी—

६४ करोड़ पिछले भूजूर किये हुये जो काम में न लाये जा सके । ६३ करोड़ मिललाई इस्पात के कारखाने के लिये रूस द्वारा उधार दिये जायेंगे परन्तु इससे २० करोड़ रुपये लौटाने पड़ेंगे जिससे ४३ करोड़ इस साधन से प्राप्त होंगे । ६३ करोड़ रुपये ब्रिटिश सरकार व बैंकी द्वारा दुर्गापुर के इस्पात के कारखाने के लिये दिये जायेंगे । इस प्रकार ६३० करोड़ रुपये की सहायता का प्रबन्ध करना पड़ेगा । आशा है कि निजी-उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व बैंक तथा दूसरे साधनों से १०० करोड़ रुपये प्राप्त हो जायेंगे । यदि विदेशी सहायता आवश्यकता से कम प्राप्त हुई तो हमें अपने साधनों को बढ़ाना पड़ेगा ।

योजना के कुछ ध्येय बिन्दु—योजना में अतिरिक्त गल्ले के उत्पादन का ध्येय १५ प्रतिशत, कपास का ३१ प्रतिशत, गन्ने का २२ प्रतिशत, तेल निकालने वाले बीजों का २७ प्रतिशत तथा जूट का २५ प्रतिशत रखा गया है । परन्तु इससे अधिक उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिये । खनिज पदार्थों का उत्पादन भी बढ़ाया जायगा । इसमें कोयले के उत्पादन का विशेष उल्लेख किया गया है । दक्षिणी भारत में ४५ मिलियन टन का एक लिग्नाइट (Lignite) का कारखाना लगाया जायगा जिससे २११,००० नलोवाट बिजली भी उत्पन्न की जा सकेगी । खाद बनाने की दो नई फैक्टरी भी लगाई जायेंगी । इससे अतिरिक्त बहुत सा घन पानी के जहाजों, हवाई जहाजों, रेडियो, तार, टेलीफोन आदि पर भी खर्च किया जायगा । आशा की जाती है कि १९३१ ई० तक ११ वर्ष की आयु तक वाले ६३ प्रतिशत बच्चों व ११ साल से १४ साल तक की आयु वाले २२.५ प्रतिशत बच्चों के लिये शिक्षा का प्रबन्ध किया जा सकेगा । इन्जीनियरिंग की शिक्षा देने के लिये ६ कालिज और खोले जायेंगे । ऊँची शिक्षा देने के लिये कालिजों की संख्या बढ़ाई जायगी । डाक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य सहायकों (Health Assistants) की संख्या में क्रमशः १८, ४१ व ७५ प्रतिशत की वृद्धि की जायगी । ४ करोड़ रुपये घरेलू योजना के लिये भी रखे गये हैं ।

भारत की विभिन्न योजनाओं में इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि खेती पर से जनसंख्या का भार कम हो । इस प्रकार १९७५-७६ तक खेती पर निर्भर रहने वाले केवल ६० प्रतिशत रह जायेंगे ।

यह भी प्रयत्न किया जायगा कि दक्षिणी-पूर्वी एशिया व अफ्रीका के देशों से अपने व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाये जायें तथा आपस में एक दूसरे से लाभ उठाने का प्रयत्न किया जाय ।

यह भी प्रयत्न किया जायेगा कि देश के सभी भागों की आर्थिक उन्नति समान हो । इस कारण उद्योगों के विकेन्द्रीकरण का प्रयत्न किया जायगा तथा उद्योगों की विभिन्न भागों में चालू किया जायगा ।

प्राथमिकता में बदल—जहाँ पहली योजना में खेती के उद्योग को बढ़ाने तथा उन्नत करने का प्रयत्न किया गया वहाँ दूसरी योजना में उद्योगों की उन्नति पर

विशेष ध्यान दिया जायगा। उद्योगों में भी ८६१ करोड़ रुपये में से ६६१ करोड़ रुपये बड़े पैमाने के उद्योगों व खानों पर खर्च किये जायेंगे। उद्योगों के साथ रेलों का विकास भी करना आवश्यक है। प्रथम योजना में उद्योगों, खानों व रेलों पर कुल का ३ खर्च किया गया परन्तु इस योजना में इसको बढ़ाकर आधा कर दिया गया है। प्रथम योजना में औद्योगिक विकास के लिए जितनी रकम मंजूर की गई थी उससे कम खर्च हुआ। इसलिए दूसरी योजना में औद्योगिक उन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया है।

यद्यपि खाद्य तथा अन्य आवश्यक कच्चे मालों की कमी दूर हो चुकी है, पर देश की बढ़ती हुई आबादी की समस्या को ध्यान में रखते हुये इस योजना में खेती की पैदावार बढ़ाने पर उचित ध्यान दिया गया है। सिंचाई, अच्छे बीज और खाद पहुँचाने, पशुपालन और खेती के तरीकों में सुधार आदि के कार्यक्रमों को पुरा करने के साथ साथ दूसरी योजना में देहातों का पुनर्गठन करने तथा राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों को युक्ति सगत प्राथमिकता दी गई है।

४८०० करोड़ रुपये के कुल खर्च में से २५५६ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा २२४१ करोड़ रुपये राज्यों द्वारा खर्च किये जायेंगे। सामाजिक क्षेत्र के कुल ४८०० करोड़ रुपये के खर्च में ३८०० करोड़ रुपये तो नयी विकास सम्पत्ति पर तथा १००० रुपये चालू उन्नति की योजनाओं पर खर्च होंगे।

निजी क्षेत्र में खर्च का अनुमान इस प्रकार है—

(१) समूहित उद्योग व खानें	५७५ करोड़ रुपये
(२) चाय आदि के बाग	
ब्रिजली, मातायात (रेलो को छोड़कर)	१२५ " "
(३) निर्माण (Construction)	१००० " "
(४) खेती व कुटीर उद्योग	३०० " "
(५) स्टॉक	४०० " "
कुल	२४००

राष्ट्रीय आय—

इस योजना के फलस्वरूप हमारी राष्ट्रीय आय जो [१६५५-५६ में १०८०० करोड़ रुपये थी वह बढ़कर १६६०-६१ में १३४८० करोड़ रुपये हो जायेगी। इस प्रकार उसमें १५ प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी। इस प्रकार हमारी प्रति व्यक्ति आय २८१ रु० से बढ़कर ३३० रुपये हो जायेगी।

रोजगार में वृद्धि—

आशा की जाती है कि इसके फलस्वरूप ८० लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। यह भी प्रयत्न किया जायेगा कि कम रोजगार मिलने की समस्या को भी हल किया जाय।

योजना की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें—

दूसरी योजना के द्राष्ट में कहा गया है कि योजना की सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर होगी—

(१) कृषि उत्पादन में पर्याप्त उत्पत्ति,

(२) घरेलू बचतों में निरन्तर वृद्धि,

(३) विदेशी विनिमय की कमी को पूरा करने के लिए विदेशी सहायता,

(४) एक ऐसा मूल्य स्तर कायम रखना जिसमें अधिक परिवर्तन न हो तथा जो उत्पादकों व उपभोक्ताओं दोनों के लिये न्याय संगत हो,

(५) व्यवस्था की कार्य कुशलता और विशेषतः वे साधन जो प्रथम योजना में निर्माण किये गये हैं तथा दूसरी योजना में निर्माण किये जायेंगे, उनका उचित उपयोग करना ।

योजना के खर्च में किए गए हेर-फेर—

जिस समय दूसरी योजना बनाई गई थी उस समय विभिन्न मदों पर खर्च का जो अनुमान लगाया गया था उसमें आगे चलकर कुछ बातों के कारण हेर फेर करना पड़ा । परन्तु सांवेजनिक क्षेत्र के खर्च का अनुमान वही ४८०० करोड़ रुपए रहा ।

अभी हाल ही में राष्ट्रीय विकास काउन्सिल (National Development Council) ने सुझाव दिया है कि ४८०० करोड़ रुपए के खर्च को दो भागों में बांटना चाहिए । भाग 'अ' में वे सब योजनायें सम्मिलित होंगी जो महत्वपूर्ण हैं और जिनका सम्भव है की उत्पादन बढ़ाना तथा उन योजनाओं को पूरा करना है जो पूरी होने के समीप हैं । इन योजनाओं पर खर्च का अनुमान ४१०० करोड़ रुपए होगा । भाग 'ब' में शेष योजनायें सम्मिलित होंगी और उनपर केवल ३०० रुपए खर्च होगा । काउन्सिल का कहना है कि हमारे वर्तमान साधनों का खर्च ४२६० करोड़ रुपए है । इस प्रकार २४० करोड़ रुपए की कमी रहेगी । योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि इस घन को अतिरिक्त करो, ऋणों, अल्प बचतों तथा खर्च में कमी करके पूरा किया जाय । भाग 'ब' में सम्मिलित योजनाओं को अभी पूरा किया जायेगा जबकि उनके लिए साधन उपलब्ध होंगे । इस प्रकार विभिन्न मदों पर खर्च का जो अनुमान लगाया गया है वह अगले पृष्ठ की तालिका से पता चल सकता है ।

योजना की प्रगति पर विचार—

अप्रैल १९५६ और अगस्त १९५७ ई० के बीच थोक मूल्यों में १४ प्रतिशत वृद्धि हो गई । उसके पश्चात् उनमें कुछ कमी हो गई परन्तु अब भी वे १०६-१०७ हैं । अप्रैल १९५६ से मार्च १९५८ तक हमारे विदेशी विनिमय के साधनों में ८२१ करोड़ रुपए की कमी रही । उसको कम करने के लिये बहुत से पग उठाये गये । परन्तु फिर भी विदेशी विनिमय का सकट बना हुआ है ।

मद	प्रारम्भिक अनुमान	कुल का प्रतिशत	कुछ योजनाओं का मूल्य बढ़ने से ४८०० करोड़ रु० के खर्च में हेर फेर	कुल का प्रतिशत	वर्तमान साधनों के अनुसार खर्च में परिवर्तन	कुल का प्रतिशत
	करोड़ रु०		करोड़ रु०		करोड़ रु०	
(१) खेती तथा सामुदायिक विकास	५६८	११.८	५६८	११.८	५१०	११.३
(२) सिंचाई तथा शक्ति	६१३	१२.०	८६०	१७.६	८२०	१८.२
(३) ग्राम तथा छोटे उद्योग	२००	४.२	२००	४.२	१६०	३.६
(४) उद्योग तथा खनिज	६६०	१४.४	८८०	१८.४	७६०	१७.५
(५) यातायात तथा संचार वाहन	१३८५	२८.६	१३४५	२८.०	१३४०	२८.८
(६) सामाजिक सेवाएँ	६४५	१६.७	८६३	१८.०	८१०	१८.०
(७) विविध	६६	१.०	८४	१.७	७०	१.६
योग	४८००	१००.०	४८००	१००.०	४५००	९३.०

पहले तीन वर्षों में २४६६ करोड़ रुपए खर्च किये गये। यह योजना के कुल खर्च का १० प्रतिशत के लगभग है। पहले तीन वर्षों में २४६६ रुपए निम्नलिखित साधनों से प्राप्त हुये —

	करोड़ रुपए में
आय से बचत	४२८
रेलो से	१२६
जनता से ऋण	४४१
अल्प बचतें	२११
दीर्घकालीन ऋण व पूंजी प्राप्ति	—८० (Minus 80)
विदेशी सहायता	४५८
हीनार्थ प्रबन्धन	८८२

योग २४६६

योजनाकाल के दो वर्षों में यह खर्च इस प्रकार होन की आशा है—

आय से बचत	३२२ करोड़ रुपए
रेलो से	१२४ "
जनता से ऋण (वास्तविक)	२७७ "
अल्प बचतें	१७३ "
दीर्घकालीन ऋण व विविध	

पूर्वी प्राप्ति
विदेशी सहायता
हीनार्थ प्रबन्धन

६	”
६४२	”
२१०	”
<hr/>	
१७५४	”

इस प्रकार यह आशा की जाती है कि अगले दो वर्षों में केन्द्र व राज्य १७५४ करोड़ रुपये प्रदान कर सकेंगे। परन्तु ४५०० करोड़ रुपए का खर्च पूरा करने के लिये २०३४ करोड़ रुपए की आवश्यकता है। इस प्रकार लगभग २८० करोड़ रुपए की कमी रहेगी। इसमें से १६८ करोड़ रुपए केन्द्र में तथा ८२ करोड़ रुपए राज्यों में कमी होगी।

इस कमी को ध्यान में रखते हुए नवम्बर १९५८ में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने निश्चय किया कि (१) राज्य को गल्ले में थोक व्यापार करना चाहिए। (२) ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को फिर से बनाने के लिए ग्रामीण सहकारी समितियों पर जोर देना चाहिये। (३) केन्द्र तथा राज्यों को प्रयत्न करना चाहिए कि वे निर्माण कार्य में निमित्तव्ययिता से काम लें तथा अतिरिक्त साधन प्राप्त करने का प्रयत्न करें। (४) मई १९५८ में निश्चित किये हुए खर्च के ४५०० करोड़ रुपए के प्रोग्राम को कायम रखें।

हीनार्थ-प्रबन्धन—अभी तक विदेशी साधनों में जो कमी होती थी वह विदेशी विनिमय के साधनों से पूरी कर ली जाती थी। परन्तु क्योंकि अब हमारे विदेशी विनिमय के साधन २०० करोड़ रुपए से भी कम रह गये हैं इस कारण अब हम उनको और नहीं घटा सकते। अगले दो वर्षों में हम आशा करते हैं कि प्रत्येक वर्ष १०० करोड़ रुपए के नोट छापे जायेंगे। परन्तु इसको जितना भी हो सके कम करना चाहिए। परन्तु यह तभी हो सकता है जब कि हमारे देश में गल्ले का उत्पादन बड़े। मार्च १९५६ तक हमको ३५० मिलियन डालर का वचन दिया गया है। परन्तु अगले दो वर्षों में हमकी ६५० मिलियन डालर की सहायता चाहिए।

द्वितीय योजना के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के टेक्निकल मिशन के विचार—

मिशन इस योजना की मोटी रूप-रेखा से सहमत है परन्तु उसने इस योजना को ‘बहुत कुछ उत्कृष्ट आकांक्षा वाली’ बताया है। उसने सरकार से कहा कि हीनार्थ प्रबन्धन करने में बड़ी सावधानी से काम लेना चाहिए तथा मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये अधिक गल्ले का स्टॉक करना चाहिए।

मिशन ने बताया है कि देश की यातायात की हालत बहुत खराब है और सिफारिश की है कि इस समस्या को रेल, सड़क, तटीय जहाजरानी तथा आन्तरिक जल मार्ग उभर करके सुलझाना चाहिए।

मिशन ने कहा है कि सूती उद्योग तथा हाथ-करघा के बीच में जो समझौता किया गया है, वह नहीं चल सकेगा इससे निर्यात करने में बाधा पड़ सकती है।

मिशन ने कहा है कि विदेशी विनिमय कमाने के लिये अधिक सूती कपड़ा, द्रव्य, फसलें आदि विदेशों को निर्यात करनी चाहियें। उसका यह भी कहना है कि निजी पूंजी को योजना में सहयोग देने का अवसर देना चाहिये। उसका यह भी सुझाव है कि विदेशी पूंजी व योग्यता को प्राप्त करने के लिये खूब प्रयत्न करना चाहिए।

मिशन यह भी कहता है विभिन्न योजनाओं पर किये गए खर्च के आँकड़े बहुत पुराने हो गये हैं। उनको ठीक करना चाहिए जिससे कि खर्च की गड़बड़ दूर की जा सके।

मिशन ने सुझाव दिया है कि सरकार को रेलों के भाड़े की दर, बिजली दर तथा बन्दरगाहों पर खर्च की दर बढ़ाकर अधिक आय प्राप्त करनी चाहिए।

मिशन का कहना है कि कुटीर उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय आय में सतनी वृद्धि न हो सकेगी जितनी कि योजना में बताई गई है।

मिशन ने यह भी कहा कि उपयोग की वस्तुयें पैदा करने के लिये फैक्टरी तथा गैर फैक्टरी उत्पत्ति का जो बँटवारा किया गया है वह ठीक नहीं है क्योंकि गैर फैक्टरी उत्पत्ति पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता।

मिशन ने आगे कहा है कि योजना में निर्यात बढ़ाने के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार उद्योगों की प्रतियोगी शक्ति को बढ़ाने के लिये कोई विचार ध्यान नहीं दे रही है।

Q 102 What in your opinion, is going to be the outline of the Third Five Year Plan ?

प्रश्न १०२—आप के विचार में तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप-रेखा क्या होने वाली है ?

द्वितीय योजना अभी दो वर्षों में समाप्त होने वाली है। परन्तु अभी से तृतीय पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा तैयार होनी आरम्भ हो गई है। आशा है कि यह १९५६ के अन्त तक बन कर तैयार हो जायगी।

तीसरी योजना की रूप रेखा का आधार पहली दो योजनायें ही होंगी। इस योजना में हमारा ध्येय निम्नलिखित होगा —

(१) राष्ट्रीय आय का स्तरान्तरण लोगों की आर्थिक, सामाजिक तथा समुदनी उन्नति करना।

(२) रोजगार के अवसर बढ़ाना।

(३) द्रुत गति से औद्योगीकरण करना।

(४) आय तथा धन की असमानता को कम करना।

पहली दो योजनाओं में हम ने कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में उन्नति की है परन्तु कुछ दिशाओं में हमको निराशा का मुँह साकना पड़ा है। उदाहरण के लिये

इन योजनाओं को सफल बनाने में जनता का इतना सहयोग प्राप्त नहीं हुआ जितना कि आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त इन दोनों योजनाओं में रोजगार की समस्या सुलझ नहीं पाई। योजनाओं को सफल बनाने के लिए लोगों में जितने उत्साह तथा कठिन परिश्रम की आवश्यकता है, वह भी दिखाई नहीं पड़ता। इन दोनों योजनाओं में भौतिक साधनों पर जोर न देकर आर्थिक साधनों पर जोर दिया गया है।

इसी कारण तीसरी योजना की रूप रेखा तैयार करते समय हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। दूसरी योजना में हमने जो अनुभव प्राप्त किये उनके आधार पर ही हमें तीसरी योजना की इमारत खड़ी करनी चाहिए। अभी तक इस योजना के विषय में जो चर्चा चल रही है उनके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यह योजना लगभग ११,००० करोड़ रुपये की होगी। इसमें से लगभग ८५०० करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में तथा शेष २५०० करोड़ रुपये निजी क्षेत्र में खर्च होंगे। परन्तु पहली और दूसरी योजनाओं का अनुभव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इतना धन आयेगा कहाँ से। श्री ए० डी० गोरवाला ने अपने एक लेख में बताया है कि तीसरी योजनाकाल में हमको ३००० करोड़ रुपये से अधिक विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हो सकती। इसमें से लगभग ७२० करोड़ रुपये व्याज आदि देने में समाप्त हो जायेंगे। इस प्रकार वास्तविक विदेशी सहायता लगभग २२८० करोड़ रुपये होगी। ऐसा अनुमान है कि देश के भीतरी साधनों से २८०० करोड़ रुपये प्राप्त हो सकेंगे। इस प्रकार हमारे कुल साधनों का अनुमान लगभग ५०८० करोड़ रुपये है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के खर्च का अनुमान ८५०८ करोड़ रुपये है। इस प्रकार $८५०८ - ५०८० = ३४२८$ करोड़ रुपये की खाई होगी। इस खाई को यदि हीनार्थ प्रबन्धन द्वारा पाटा गया तो देश के अन्दर मूल्य-स्तर बहुत अधिक ऊँचा हो जायगा। इसी कारण श्री गोरवाला का मत है कि तीसरी योजना केवल ५०८० करोड़ रुपये की होनी चाहिए। परन्तु दूसरे बहुत से आर्थिकों का मत इससे भिन्न मालूम पड़ता है। उनका मत है कि तीसरी योजना का आकार बड़ा होना चाहिए। इसके लिये वे भिन्न-भिन्न साधन बताते हैं।

तीसरी योजना की विचारधारा का आधार समाज का समाजवादी ढाँचा खड़ा करना होगा। परन्तु गरीबी का तो समाजीकरण हो नहीं सकता। इसी कारण तीसरी योजना में औद्योगिक विकास को तेजी से बढ़ाना होगा। परन्तु इसके साथ ही साथ हमें अपनी खेती की उन्नति की ओर भी पूरा ध्यान देना होगा। हमको न केवल खेती की उपज ही बढ़ानी होगी वरन् यह भी देखना होगा कि खेती पर निर्भर रहने वाले लोगों की संख्या न बढ़ने पाये। इसी कारण इस बात की आवश्यकता है कि गाँवों में कुटीर उद्योगों को उत्पन्न किया जाय तथा इस बढ़ती हुई जनसंख्या को इन उद्योगों में लगाया जाय। इन उद्योगों को उत्पन्न करने के लिए गाँवों की बिजली प्रदान करनी पड़ेगी तथा इन उद्योगों को मिल उद्योगों की प्रतियोगिता से बचना पड़ेगा।

समाज के अन्दर समाजवाद का ढाँचा खड़ा करने के लिये हम को गाँवों में सहकारी समितियों तथा ग्राम पंचायतों को उन्नत करना पड़ेगा। भविष्य में हमको चाहिए कि सहकारी समिति को ही ग्राम की समस्त दौड़ धूप का केन्द्र बनाये। यदि उत्पादन तथा उपभोग के क्षेत्र में सहकारी समितियाँ स्थापित हो गईं तो हमको पूँजी निर्माण करने में भी बड़ी सहायता मिलेगी।

समाज के अन्दर बराबरी लाने तथा सब को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिये यह आवश्यक होगा कि तीसरी योजना में बिना खेती के मजदूरों तथा नीचे मध्य वर्ग की ओर ध्यान दिया जाय। बिना खेती के मजदूरों की हालत भूमि सुधारों, उन्नत खेती करने के ढंगों, कुटीर-उद्योगों आदि से सुधर सकती है। परन्तु नीची मध्य श्रेणी की हालत उन्नत करने के लिये हम को उनके लिये रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने पड़ेंगे। परन्तु अधिक रोजगार बढ़ाने के लिये इस बात की आवश्यकता होगी कि देश की आर्थिक उन्नति हो तथा हमारे देश में विद्या के ढंग को उन्नत किया जाय। आजकल यह अनुभव किया जा रहा है कि हमारी शिक्षा पद्धति का सम्बन्ध हमारी उन्नतिशील अथ व्यवस्था से हो। यह आवश्यक है कि शिक्षित वर्ग को बेरोजगारी का मुँह न ताकना पड़े। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि हमारी शिक्षा पद्धति कम महँगी हो। यह भी आवश्यक है कि गाँव के लोगों में गाँव में रहने के प्रति कोई ग्लानि उत्पन्न न हो।

साधनों का गतिचलन—

इतनी बड़ी योजना के लिये साधनों को कैसे चालना दी जाय, यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकतन्त्र शासन में तो इस प्रश्न का हल कोई कठिन नहीं है परन्तु प्रजातन्त्र में इस प्रश्न को हल करना थोड़ा कठिन है। हमारे देश में अभी तक मनुष्य-शक्ति को काम में लाने के लिये बहुत कम प्रयत्न किया गया है। हमारे देश में जन-संख्या १३ से २ प्रतिशत तक बढ़ती है। इसीलिये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि तीसरी योजना पर १०,००० करोड़ रु० खर्च करके भी हम १२०,००,००० आदमियों को रोजगार प्रदान कर सकेंगे। परन्तु बेकारों की संख्या तीसरी योजना के प्रारम्भ में जहाँ ७० लाख होगी वहाँ वह तीसरी योजना के अन्त में ६० लाख हो जायगी। इसी कारण श्री मुलजारीलाल नन्दा ने कहा है कि हमारे लिये इस बात की आशा करना वास्तविकता न होगी कि तीसरी योजना २ करोड़ १० लाख आदमियों को रोजगार प्रदान कर सकेगी। इसीलिये मैं अनुभव करता हूँ कि हम देश में रोजगार के कुछ ऐसे नये साधन ढूँढ़ जहाँ पर कि वे लोग जो साधारण ढंग से काम पर न लगाये जा सकें उनको किसी उत्पादक काम में लगाया जा सके। यह एक बहुत बड़ा काम है जिसको पूरा करना हमारे लिये बहुत ही आवश्यक है।

साधारण बेरोजगारी के अतिरिक्त कृषि क्षेत्रों की बेरोजगारी एक अलग सिर दर्द पैदा कर रही है। वर्तमान भारत में २ करोड़ लोग कृषि क्षेत्र में बेकार

हैं। इन सब के लिये भी काम की व्यवस्था करना बड़ा आवश्यक है जिससे कि अल्प व्यय में ये खप सकें।

मनुष्य शक्ति को काम में लाने के अतिरिक्त हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम देश में प्राप्त सभी साधनों का उपयोग करें। पहली दोनो योजनाओं में केवल शहरों से प्राप्त आय पर ही ध्यान दिया गया था। परन्तु हमारे देश की कुल आय का लगभग ५० प्रतिशत गाँवों में जाता है। यह आवश्यक है कि इस धन का उपयोग किया जाय। डा० के० एम० राज, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स का सुझाव है कि भारत के ५ लाख गाँवों में ४ हजार करोड़ रु० की नयी बीमा पालिसियाँ देवनी कोई अवास्तविक लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। यदि इतनी रकम की पालिसियाँ जारी की जा सकें, तो देश को प्रीमियम द्वारा प्रतिवर्ष २०० करोड़ रु० की बचत होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत में उपभोग वस्तुओं पर जितना खर्च होता है उसमें से गाँवों में प्रायः ६ प्रतिशत और शहरों प्रायः ४ प्रतिशत विभिन्न प्रकार के पारिवारिक समारोहों में खर्च हो जाता है। यह असम्भव नहीं है कि इस तरह के खर्च को घटा कर आधा कर दिया जाय। इस प्रकार छोटी छोटी बचतों से बहुत वृद्धि हो जायगी। उन्होंने यह भी कहा है कि नाज के थोक व्यापार से सरकार को थोड़ा लाभ हो सकता है परन्तु इस साधन पर बहुत निर्भर रहना बुद्धिमान नहीं होगी। इतना ही काफी है कि सरकार थोक व्यापार द्वारा नाज की कीमतों को स्थिर कर सके। कृषि की कीमतों को स्थिर करने के लिये न केवल यह आवश्यक कि सरकार खरब खरीद और बिक्री का काम अपने हाथ में ले, वरन् नाज आदि को बड़े-बड़े गोदामों में भरने की भी बहुत आवश्यकता है।

डा० राज ने यह भी कहा है कि शहरी क्षेत्रों में भी करो में और वृद्धि करने की अभी गुंजायश है। खास तौर से ६ हजार रु० से २५ हजार रु० प्रतिवर्ष की आय के स्तर में वृद्धि की जा सकती है। इस वर्ग के लोग प्रत्यक्ष करों के रूप में कुल जितनी रकम देते हैं वह इस वर्ग के दूसरे देशों के लोगों की अपेक्षा बहुत कम है।

श्री सद्दीक अली का सुझाव है कि राजकीय उद्योगों जैसे रेलों आदि की ठीक व्यवस्था करने से भी बहुत आय बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि लोगों को कर बचाने से रोक कर हम अपनी आय को ५० से ७५ करोड़ रु० वार्षिक से बढ़ा सकते हैं।

कुछ आँकड़े—

ऐसा अनुमान लगाया गया है कि प्रति व्यक्ति १५ औंस चावल, आटा और ३ औंस दाल की खपत के हिसाब से १९६५-६६ तक १० करोड़ टन गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा उत्पादकों द्वारा अधिक उपयोग निर्यात